वार्षिक रिपोर्ट 1999 – 2000

एन सी ई आर टी

वार्षिक रिपोर्ट 1999 - 2000

एन सी ई आर टी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

नवंबर 2000
कार्तिक 1922
PD 5H MK, NSY

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा नाथ ग्राफिक्स, 1/21, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली 110 016 द्वारा लेजर टाइपसैट होकर जे.जे. ऑफसैट प्रिंटर्स, 7, प्रिंटिंग प्रेस एरिया, वज़ीरपुर, दिल्ली 110 035 द्वारा मुद्रित।

आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन सी ई आर टी) डा. मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और परिषद् के अध्यक्ष के प्रति उनके परामर्श और मार्गदर्शन के लिए आभारी है। परिषद् विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक सुधार के कार्यक्रमों में गहन रुचि लेने और समर्थन प्रदान करने के लिए अपने सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति, कार्यक्रम सलाहकार समिति और अन्य कार्यक्रम कार्यविधि समितियों के विशिष्ट सदस्यों के प्रति कृतज्ञ है।

परिषद् उन विशेषज्ञों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इसकी विभिन्न समितियों में कार्य किया तथा अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की है। वे सभी राज्य शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय सहित सभी संगठन और संस्थान भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने शिक्षा में भागीदारी के उद्देश्य की भावना से परिषद् को सहयोग देकर उसके कार्यकलापों को कार्यान्वित करने में पूरी सहायता की है।

एन सी ई आर टी यूनेस्को, यूनिसेफ, यू एन डी पी, यू एन एफ पी ए, विश्व बैंक आदि के प्रति भी सम्मान व्यक्त करती है जिन्होंने अपने प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान किया। परिषद् अपने सभी स्तर के स्टाफ के सदस्यों के प्रति भी आभार प्रकट करती है, जिनके सहयोग और कर्त्तव्यनिष्ठा के बिना कार्यक्रम का कार्यान्वयन असंभव था। परिषद् उन हजारों अध्यापकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और ऐसे अनेक व्यक्तियों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती है जिन्होंने परिषद् के 1999-2000 के प्रकाशनों और कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए परिषद् के विभिन्न संघटकों को पत्र भेजे और निरंतर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा के सतत स्रोत बने।

इस रिपोर्ट का प्रारूप योजना, कार्यक्रम, अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रभाग के डा. जे.पी. मित्तल, रीडर ने संकाय सदस्यों और कार्यालय के स्टाफ की सहायता से तैयार किया है। इसका प्रकाशन कार्य प्रकाशन प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा संपन्न हुआ है। इन सभी के बहुमूल्य सहयोग से इस रिपोर्ट को यह स्वरूप प्राप्त हुआ है।

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

मोनोग्राम में परस्पर आवेष्टित हंस,
एन.सी.ई.आर.टी. के कार्य के तीनों पहलुओं
के एकीकरण के प्रतीक हैं
अर्थात् (i) अनुसंधान और विकास
(ii) प्रशिक्षण तथा (iii) विस्तार और प्रसार।
यह डिज़ाइन, कर्नाटक के रायचूर ज़िले
में मस्के के निकट हुई खुदाई से प्राप्त
ईसा पूर्व तीसरी सदी के अशोक युगीन भग्नावशेष
के आधार पर बनाया गया है।

'विद्ययाऽमृतमश्नुते' आदर्श वाक्य ईशावास्य
उपनिषद् से लिया गया है जिसका अर्थ है–
विद्या से अमरत्व मिलता है।

विषय सूची

गांधी जी का जन्तर

तुम्हें एक जन्तर देता हूं । जब भी तुम्हें सन्देह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ :

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा । क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा ? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है ?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

मो॰ क॰ गांधी

विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था होने के नाते परिषद् अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों और अनुसंधान के लिए सहायता तथा शैक्षिक अनुसंधान पद्धति संबंधी प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.) के विभिन्न विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आई.ई.), केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) विद्यालयी शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान कार्य करते हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) विद्यालयी शिक्षा का शीर्षस्थ संसाधन संस्थान है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा विद्यालयी शिक्षा से संबंधित शैक्षिक मसलों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और परामर्श देने के लिए की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

परिषद् अपने निम्नलिखित घटकों के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है:

1. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.), नई दिल्ली
2. केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.), नई दिल्ली
3. पंडित सुन्दरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.), भोपाल
4. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आई.ई.), अजमेर
5. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आई.ई.), भोपाल
6. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आई.ई.), भुवनेश्वर
7. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आई.ई.), मैसूर
8. उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एन.ई.आर.आई.ई.), शिलांग
9. राज्यों में स्थित क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.)

नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान अपने विभिन्न विभागों, प्रभागों के माध्यम से पाठ्यचर्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित शोध और विकास कार्य करता है, आद्य-पाठ्यचर्यात्मक और पूरक अनुदेशी सामग्री तैयार करता है, विद्यालयी शिक्षा से संबंधित आंकड़ा-आधार विकसित करता है तथा विद्यालय-पूर्व, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास के लिए प्रायोगिक और नवाचारी कार्य करता है। एन.आई.ई. केंद्र द्वारा प्रायोजित विद्यालय सुधार योजनाओं के कार्यान्वयन से संबद्ध प्रमुख संसाधन व्यक्तियों और अध्यापक-शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण भी आयोजित करता है। एन.आई.ई. के विभागों के शैक्षिक कार्यक्षेत्र नीचे दिए गए हैं:

सी.आई.ई.टी.

केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) भी नई दिल्ली में ही स्थित है। यह शैक्षिक माध्यमों से संबंधित अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, उत्पादन और विस्तार के कार्यक्रम करता है तथा राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों (एस.आई.ई.टीज़.) को अकादमिक तथा तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है।



वार्षिक महासभा की बैठक।

एन.आई.ई. के विभाग और उनके शैक्षिक कार्यक्षेत्र

विभाग/प्रभाग	*शैक्षिक कार्यक्षेत्र*
विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा विभाग (डी.पी.एस.ई.ई.)	विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा संबंधी विषय और समस्याओं पर शोध कार्य और आदर्श शिक्षण-अधिगम सामग्री का विकास कार्य तथा ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के एक भाग के रूप में अध्यापक शिक्षा और विस्तार विभाग के साथ मिलकर राष्ट्रीय संसाधन समूह, अध्यापक-प्रशिक्षण, शिक्षण और पाठ्यचर्या संबंधी कार्य।
अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षण विभाग (डी.ई.एन.एफ.ए.एस.)	गैर नामांकित और विद्यालय-त्यागी बच्चों से संबंधित मुद्दों और समस्याओं सहित अनौपचारिक शिक्षा व वैकल्पिक शिक्षण के आद्य-मॉडलों के लिए अनुसंधान और उनका विकास, अनौ. शि., वैकल्पिक शिक्षण के लिए खुला विद्यालय संबंधी अध्ययन, अनुदेशी सामग्री और अनौ. शि. के कार्मिकों के प्रशिक्षण की कार्यनीतियों का निर्धारण।
विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (डी.ई.जी.एस.एन.)	अनुसूचित जातियों/जनजातियों (अ.जा./अ.ज.जा.), अल्पसंख्यकों, विकलांगों और अन्य विशेष ज़रूरतमंद समूहों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे और समस्याएँ।
महिला अध्ययन विभाग (डी.डब्ल्यू.एस.)	बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे और समस्याएँ तथा संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यकलाप।
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एम.)	विज्ञान और गणित शिक्षा के मुद्दे और समस्याएँ तथा आद्य-पाठ्यचर्या और अनुदेशी सामग्री पर अनुसंधान और विकास कार्य तथा विज्ञान उपकरणों के डिज़ाइन और विकास का कार्य।
अध्यापक शिक्षा और विस्तार विभाग (डी.टी.ई.ई.)	राज्य/क्षेत्र के अध्यापक शिक्षा संस्थानों की क्षमता के विकास के कार्यक्रम और अध्यापक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना को शैक्षिक समर्थन, विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ संयुक्त रूप से प्रशिक्षण, शिक्षाशास्त्र और पाठ्यचर्या पर राष्ट्रीय संसाधन समूह का कार्य करना, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के साथ समन्वयन तथा विस्तार शिक्षा से संबंधित विषय।
सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एस.एच.)	सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा संबंधी मुद्दे और समस्याएँ, आद्य-पाठ्यचर्या और अनुदेशी सामग्री पर अनुसंधान और विकास कार्य, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन.पी.ई.पी.) के एक भाग के रूप में जनसंख्या शिक्षा के कार्यक्रम।

शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग (डी.ई.पी.एफ.ई.)	शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और दार्शनिक आधारों से संबंधित अध्ययन, तुलनात्मक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा के लिए उनके निहितार्थ।
शैक्षिक मापन और मूल्यांकन विभाग (डी.ई.एम.ई.)	विद्यालयी शिक्षा से संबंधित मापन व मूल्यांकन, परीक्षा सुधार सहित संतत और सम्यक् शिक्षा पर अनुसंधान और विकास कार्यकलाप।
मापन, मूल्यांकन, सर्वेक्षण और आंकड़ा प्रक्रियन विभाग (डी.ई.एस.डी.पी.)	आवधिक मूल विषयी शैक्षिक अध्ययन जिसमें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण भी शामिल है।
शैक्षिक अनुसंधान और नीतिगत संदर्श विभाग (डी.ई.आर.पी.पी.)	शिक्षा में नीतिगत अनुसंधान को बढ़ावा देना, 'विचार बैंक' को कारगर बनाने के लिए संबंधित कार्यकलाप आयोजित करना, विद्यालयी शिक्षा में अनुसंधान और नवाचारी अध्ययन शुरू करना, समन्वयन करना और प्रायोजित करना तथा एरिक सचिवालय का कार्य करना।
कंप्यूटर शिक्षा और तकनीकी सहायता विभाग (डी.सी.ई.टी.ए.)	कंप्यूटर शिक्षा संबंधी विषय और समस्याएँ तथा आधुनिक तकनीकी सहायता/बहुमाध्यम शिक्षा समर्थन में अनुसंधान और विकास तथा कंप्यूटर संसाधन केंद्र के कार्य।
योजना, प्रोग्रामिंग, अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रभाग (पी.पी.एम.ई.डी.)	एन.सी.ई.आर.टी. के घटकों को कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में समन्वय करना, कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना, लक्ष्य समूह द्वारा कार्यक्रमों की उपयोगिता का मूल्यांकन करना तथा कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग (आई.आर.डी.)	अन्य देशों में शैक्षिक संस्थानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समन्वयन करना और राष्ट्रीय विकास समूह (एन.डी.जी.) के लिए शैक्षिक सचिवालय के रूप में कार्य करना।
प्रकाशन प्रभाग (पी.डी.)	विद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकों, अनुदेशी और पूरक सामग्रियों, पत्रिकाओं और अनुसंधान मोनोग्राफों का प्रकाशन कार्य।
पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना प्रभाग (डी.एल.डी.आई.)	शैक्षिक सूचनाओं का प्रलेखन और पुस्तकालय सुविधाएँ प्रदान करना।

पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.

पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) भोपाल में स्थित है। यह संस्थान विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य आयोजित करता है।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आई.ईज़.) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में स्थित हैं। ये संस्थान राज्य और ज़िला स्तर के अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों को विद्यालयी शिक्षा संबंधी सेवाकालीन प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करते

हैं। ये संस्थान एक सीमा तक विज्ञान और गणित तथा मानविकी के अध्यापन के लिए विद्यालय के अध्यापकों तथा प्रारंभिक अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए अध्यापक-शिक्षकों को सेवापूर्व वृत्तिक प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। आर.आई.ईज़ अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की शैक्षिक आवश्यकताओं (सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षा) को पूरा करते हैं। ये विद्यालयी शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के लिए क्षेत्रीय संसाधन संस्थान के रूप में भूमिका निभाते हैं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की नीतियों के कार्यान्वयन में अपेक्षित सहायता देते हैं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन में सहायता करते हैं। अजमेर स्थित क्षे.शि.सं. दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों और संघ शासित राज्य चंडीगढ़ की अध्यापक शिक्षा और अन्य संबंधित शैक्षिक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। क्षे.शि.सं., भोपाल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं- गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य और संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की व्यवस्था क्षे.शि.सं., भुवनेश्वर द्वारा की जाती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य और संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी क्षे.शि.सं., मैसूर में शामिल हैं। उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिलांग में एक नया क्षे. शि.सं. (एन.ई.आर.आई.ई.) स्थापित किया गया। इन राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं और प्रचालन की प्रक्रिया में इस संस्थान को क्षे.शि.सं., भुवनेश्वर के अंतर्गत शामिल रखना जारी है।

क्षेत्रीय कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. के अधिकतर क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। ये राज्यों में विद्यालयी शिक्षा की समस्याओं और मुद्दों पर शिक्षा विभागों और अन्य संबद्ध संस्थाओं के साथ शैक्षिक संबंध स्थापित करते हैं तथा राज्यों को परिषदों की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

कार्यक्रम और गतिविधियाँ

एन.सी.ई.आर.टी. निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का संचालन करती है:

अनुसंधान

विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था होने के नाते परिषद् अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों और अनुसंधान के लिए सहायता तथा शैक्षिक अनुसंधान पद्धति संबंधी प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.) के विभिन्न विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) और पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) विद्यालयी शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान कार्य करते हैं।

परिषद् अपने घटकों में अनुसंधान कार्य करने के अतिरिक्त अन्य संस्थानों एवं संगठनों को वित्तीय सहायता तथा अकादमिक परामर्श के द्वारा उनके अनुसंधान कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करती है। पीएच.डी. शोध प्रबंधों के प्रकाशन हेतु परिषद् द्वारा विद्वानों को सहायता प्रदान की जाती है। परिषद् विद्यालयी शिक्षा संबंधी अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान अध्येतावृत्तियाँ भी प्रदान करती है, ताकि विकास, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों के लिए शोध का मज़बूत आधार तैयार किया जा सके और सुदक्ष शोधकर्ताओं का कार्यदल विकसित हो सके।

परिषद् देश में शैक्षिक अनुसंधानों का आयोजन भी करती है। परिषद् में आंकड़ों के भंडारण, संसाधन एवं उन्हें पुन: प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर सुविधाएँ हैं। यह अंतर्देशीय अनुसंधान परियोजना कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अभिकरणों से सहयोग करती है।

विकास

विद्यालयी शिक्षा के विकास संबंधी कार्यकलाप परिषद् के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। परिषद् के विकास संबंधी

मुख्य कार्यों में शामिल हैं: विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या एवं अनुदेशी सामग्री तैयार करना और बच्चों तथा समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें नवीन रूप देना। परिषद् के नवाचार संबंधी विकास के कार्यकलापों में विद्यालय-पूर्व शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायीकरण और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या और अनुदेशी सामग्री का विकास भी सम्मिलित है। इसके अलावा शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जनसंख्या शिक्षा और विकलांगों तथा विशेष वर्गों की शिक्षा के विकास के लिए अपेक्षित कार्य किए जाते हैं।

प्रशिक्षण

परिषद् का एक प्रमुख कार्य पूर्व-प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर तथा व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, मार्गदर्शन और परामर्श तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में भी अध्यापकों को सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ईज़.) के सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में विषयवस्तु और शिक्षण विधि का एकीकरण, वास्तविक कक्षा व्यवस्था में दीर्घकालीन प्रशिक्षु अध्यापक, और समुदाय कार्यों में छात्र/छात्राओं की प्रतिभागिता जैसी नवीन विशेषताओं को भी शामिल किया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, राज्यों तथा राज्य स्तरीय संस्थाओं के प्रमुख कार्मिकों और अध्यापक शिक्षकों तथा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्य भी करते हैं।

विस्तार

एन.सी.ई.आर.टी. व्यापक शैक्षिक विस्तार कार्यक्रम संचालित करती है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान तथा राज्यों में स्थित क्षेत्रीय सलाहकारों के कार्यालय विभिन्न प्रकार से कार्यरत हैं। परिषद् राज्यों के विभिन्न संगठनों तथा संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य करती है और विभिन्न कार्मिक वर्गों, अध्यापकों, अध्यापक-प्रशिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों, प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों, पाठ्यपुस्तक लेखकों आदि को सहायता प्रदान करने के लिए विस्तार सेवा विभागों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापक प्रशिक्षण केंद्रों के साथ व्यापक रूप से कार्य करती है।

विस्तार कार्यों के अंतर्गत नियमित रूप से सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ एवं प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि जहाँ विशेष समस्याएँ हैं तथा जिनके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है, वहाँ तक संबंधित शिक्षाकर्मी पहुँच सकें। परिषद् विकलांगों और समाज के सुविधावंचित वर्गों की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है। देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रकाशन और प्रसार

परिषद् कक्षा 1 से 12 तक के विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करती है। यह अभ्यास पुस्तिकाएँ, अध्यापक निर्देशिकाएँ, पूरक पाठमालाएँ, अनुसंधान रिपोर्ट आदि भी प्रकाशित करती है। इसके अतिरिक्त यह अध्यापक प्रशिक्षकों, अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों तथा सेवारत अध्यापकों के लिए उपयोगी शिक्षा सामग्री भी प्रकाशित करती है। निरंतर शोध और विकास कार्य से तैयार अनुदेशी सामग्री राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न संगठनों के लिए एक आदर्श सामग्री के रूप में होती है। यह सामग्री राज्य स्तरीय संगठनों को अपने यहाँ प्रयोग करने एवं/या अनुकूलन हेतु उपलब्ध कराई जाती है। ये पाठ्यपुस्तकें अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित की जाती हैं।

शैक्षिक सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए परिषद् छह पत्रिकाएँ प्रकाशित करती है। *दि प्राइमरी टीचर* अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में प्रकाशित की जाती है और इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की कक्षा में सीधे उपयोग के लिए सार्थक एवं उपयुक्त सामग्री प्रदान करना है। *स्कूल साइंस* विज्ञान शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के लिए एक खुला मंच प्रदान करती है। *जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन* समकालीन शैक्षिक विषयों पर चर्चा के माध्यम से शिक्षा में मौलिक और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। *इंडियन एजुकेशनल रिव्यू* में शोध

लेख होते हैं और यह शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं को एक मंच प्रदान करती है। *भारतीय आधुनिक शिक्षा* हिंदी में प्रकाशित की जाती है तथा समकालीन विषयों पर शिक्षा में आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने तथा शैक्षिक समस्याओं और व्यवहारों को प्रसारित करने के उद्देश्य से एक व्यापक मंच प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त परिषद् की समाचार-पत्रिका *एन.सी.ई.आर.टी. न्यूज़लैटर* हर मास अंग्रेज़ी और हिंदी में प्रकाशित की जाती है। इसका हिंदी संस्करण *शैक्षिक दर्पण* के नाम से निकलता है।

आदान-प्रदान कार्यक्रम

एन.सी.ई.आर.टी. विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन तथा विकासशील देशों के कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए यूनेस्को, यूनिसेफ, यू.एन.डी.पी., यू.एन.एफ.पी.ए. और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर कार्य करती है। यह एपिड के सहयोगी केंद्रों में से एक है। यह शैक्षिक नवाचार के लिए राष्ट्रीय विकास दल (एन.डी.जी.) के सचिवालय के रूप में कार्य करती है। परिषद् विकासशील देशों के शैक्षिक कार्यकर्ताओं के लिए संबद्ध कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं में भागीदारी के माध्यम से प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करती है।

परिषद् विद्यालयी शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार तथा अन्य राष्ट्रों के बीच निर्धारित द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य अभिकरण के रूप में कार्य करती है। इस क्षेत्र में परिषद् भारतीय आवश्यकताओं से संबद्ध विशिष्ट शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अन्य देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजती है तथा अन्य देशों के विद्वानों के लिए प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों की व्यवस्था करती है। अन्य देशों के साथ शैक्षिक सामग्री का आदान-प्रदान भी किया जाता है। इसके अलावा दूसरे देशों व संगठनों के अनुरोध पर परिषद् अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, बैठकों, परिसंवादों आदि में भाग लेने के लिए अपने संकाय सदस्यों को भेजती है।

सांगठनिक संरचना

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री परिषद् के महानिकाय के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री इस निकाय के सदस्य होते हैं। इस निकाय के अन्य सदस्य हैं: विश्वविद्यालय अुनदान आयोग के अध्यक्ष, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग के सचिव, चार विश्वविद्यालयों के उपकुलपति (प्रत्येक क्षेत्र से एक), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निदेशक, श्रम मंत्रालय के प्रशिक्षण और रोज़गार निदेशालय के प्रशिक्षण निदेशक, योजना आयोग के शिक्षा प्रभाग का एक प्रतिनिधि, परिषद् की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य (जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं हैं) तथा भारत सरकार द्वारा नामित अधिकतम 6 अन्य व्यक्ति (जिनमें कम से कम 4 सदस्य विद्यालयों के अध्यापक हों)। सचिव, एन.सी.ई. आर.टी. इस महानिकाय के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं।

कार्यकारिणी समिति परिषद् का मुख्य शासी निकाय है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इसके अध्यक्ष (पदेन) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उपमंत्री उपाध्यक्ष (पदेन) हैं। कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्य हैं: भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के सचिव, निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी., विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, विद्यालयी शिक्षा में रुचि रखने वाले चार शिक्षाशास्त्री (जिनमें दो विद्यालय अध्यापक हों), संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी., परिषद् संकाय के तीन सदस्य (जिनमें से कम से कम दो प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष स्तर के होने चाहिए), मा.सं.वि.मं. का एक प्रतिनिधि और वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि (जो एन.सी.ई.आर.टी. का वित्तीय सलाहकार हो)। सचिव, एन.सी.ई.आर.टी. कार्यकारिणी समिति का संयोजक होता है। कार्यकारी समिति के कार्यों में निम्नलिखित समितियाँ सहायता करती हैं:

1. वित्त समिति
2. स्थापना समिति
3. भवन एवं निर्माण समिति
4. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की प्रबंध समितियाँ
5. केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का सलाहकार बोर्ड
6. पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान का सलाहकार बोर्ड

7. एन.आई.ई. की अकादमिक समिति
8. एन.आई.ई. के विभागों के सलाहकार बोर्ड
9. कार्यक्रम सलाहकार समिति
10. शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति

परिषद् मुख्यालय में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. परिषद् सचिवालय
2. लेखा शाखा

परिषद् में पाँच वरिष्ठ पदाधिकारियों निदेशक, संयुक्त निदेशक (परिषद्), संयुक्त निदेशक, सी.आई.ई.टी., संयुक्त निदेशक, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. और सचिव की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान इन पदों को जिन अधिकारियों ने संभाला वे हैं:

एन.सी.ई.आर.टी. के वरिष्ठ पदाधिकारी

निदेशक	**प्रो. जे.एस. राजपूत (14.7.1999 से)** **प्रो. ए.के. शर्मा (30.6.1999 तक)**
संयुक्त निदेशक	**प्रो. ए.एन. माहेश्वरी (8.11.1999 तक)**
संयुक्त निदेशक (सी.आई.ई.टी.)	**प्रो. पी.के. भट्टाचार्य**
संयुक्त निदेशक (पी.एस.एस.सी. आई.वी.ई.)	**प्रो. एस. जेड. हैदर (3.3.2000 से)** **प्रो. ए.के. मिश्रा (1.6.1999 तक)**
सचिव	**श्रीमती सोनाली कुमार, आई.ए.एस. (24.11.1999 से)** **श्री बिमल जुल्का, आई.ए.एस. (23.11.1999 तक)**

अन्य कार्यों के साथ-साथ शैक्षिक कार्यों में निदेशक की सहायतार्थ तीन संकायाध्यक्ष हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित ने यह पद संभाला :

एन.सी.ई.आर.टी. के संकायाध्यक्ष

डीन (अनुसंधान):	**प्रो. ए. एन. माहेश्वरी (8.11.1999 तक)**
डीन (अकादमिक):	**प्रो. ए.के. मिश्रा (2.6.1999 से)** **प्रो. अर्जुन देव (1.6.1999 तक)**
डीन (समन्वय):	**प्रो. एम.एस. खापर्डे**

डीन (अकादमिक) एन.आई.ई. के विभागों के कार्य का समन्वय करते हैं, डीन (अनुसंधान) अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करते हैं और शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) के कार्य को देखते हैं तथा डीन (समन्वय) विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के सेवा/उत्पादन कार्यकलापों का समन्वय करते हैं।

कार्यक्रमों का नियोजन और अनुवीक्षण

एन.सी.ई.आर.टी. के घटक अपने कार्यक्रमों के निरूपण में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) के प्रावधानों और राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की अपेक्षित सहायता को ध्यान में रखते हैं। राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान मुख्य रूप से राज्य समन्वय समिति (एस.सी.सी.) की कार्यप्रणाली के माध्यम से की जाती है। यह समिति एन.सी.ई.आर.टी. के संकाय और राज्य शिक्षा विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच परस्पर अनुक्रिया के लिए एक मंच प्रदान करती है। इस समिति के अध्यक्ष शिक्षा सचिव होते हैं और सदस्य-संयोजक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ईज़.) के प्राचार्य होते हैं।

राज्यों की जिन शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान की जाती है उन पर आर.आई.ईज़. की प्रबंध समितियाँ (एम.सी.) विचार करती हैं। इनमें से अनेक शैक्षिक आवश्यकताओं को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अपने स्तर पर पूरा कर देते हैं। जिन शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए एन.सी.ई.आर.टी. के घटकों की सहायता अपेक्षित होती है उन्हें संबंधित घटकों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। एन.आई.ई. के विभागों के शैक्षिक कार्यक्रमों का संसाधन संबंधित विभागों की विभागीय सलाहकार समितियाँ (डी.ए.बी.) करती हैं और उसके बाद एन.आई.ई. की अकादमिक समिति (ए.सी.) उस पर विचार करती है। सी.आई.ई.टी. के कार्यक्रम शिक्षा प्रणाली के अनुसार मीडिया पर आधारित हैं। इसके कार्यक्रमों का संसाधन संस्थान का सलाहकार बोर्ड (आई.ए.बी.) करता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) के कार्यक्रमों का संसाधन उसके संस्थान का सलाहकार बोर्ड (आई.ए.बी.) करता है। एन.सी.ई.आर.टी. के घटकों और अन्य संस्थानों/

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्यों के शिक्षाधिकारियों के संपर्क, केंद्रीय शैक्षिक संगठनों (सी.ए.बी.ई., के.वी.एस., एन.वी.एस., सी.बी.एस.ई. आदि) द्वारा मांगी गई सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों के अकादमिक कार्यक्रमों को संसाधित किया जाता है और तदोपरांत संस्थान की शैक्षिक समिति (ए.सी.) इन पर विचार करती है।

केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का सलाहकार बोर्ड (आई.ए.बी.) परिषद् के घटकों और एस.आई.ई.टीज. की आवश्यकताओं के आधार पर इस संस्थान के कार्यक्रमों को शिक्षा प्रणाली के लिए अपेक्षित संचार माध्यम सहायता संसाधित करता है।

केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (सी.आई.वी.ई.) के कार्यक्रम उस संस्था में सलाहकार बोर्ड द्वारा संसाधित किए जाते हैं।

परिषद् के शैक्षिक सलाहकार राज्यों के शिक्षा अधिकारियों से परामर्श करके राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करते हैं जिनको राज्य समन्वय समितियों द्वारा संसाधित किया जाता है। इसके बाद इन संसाधित आवश्यकताओं को क्षेत्रीय समन्वय समितियाँ संसाधित करती हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की प्रबंध समितियाँ (एम.सी.) उनके अकादमिक कार्यक्रमों को संसाधित करती हैं।

परिषद् के घटकों तथा विश्वविद्यालयों के विभागों और स्वयंसेवी संगठनों सहित दूसरे संगठनों या संस्थानों द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रमों पर शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति विचार करती है।

ए.सी., आई.ए.बी., एम.सी. और एरिक द्वारा भेजे गए कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति व कमियों आदि की जांच के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति की एक उपसमिति कार्यक्रमों की छानबीन करती है।

कार्यक्रम सलाहकार समिति की उप-समिति की छानबीन के बाद परिषद् की कार्यक्रम सलाहकार समिति (पी.ए.सी.) कार्यक्रमों पर विचार करती है।

पी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों को अंततः परिषद् की कार्यकारिणी समिति (ई.सी.) द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

पी.ए.सी. और कार्यकारिणी समिति (ई.सी.) द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम परिषद् के घटकों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं

कार्यक्रम के कार्यान्वियन की प्रगति का अनुवीक्षण प्रतिमाह घटक/ विभाग के अध्यक्ष द्वारा और निदेशक की अध्यक्षता में गठित अनुवीक्षण समिति द्वारा किया जाता है।

शिक्षा प्रणाली में विद्यालयी शिक्षा के गुणात्मक सुधार की दृष्टि से कार्यक्रमों के परिणामों के व्यापक प्रसार के लिए उनका मूल्यांकन घटक/ विभाग या पी.पी.एम.ई.डी. द्वारा किया जाता है।

परिषद् के स्तर पर राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं, राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय विकासक्रमों को प्रतिबिंबित करते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों के निरूपण, विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण, अंतिम उत्पादों/परिणामों का मूल्यांकन तथा शिक्षा प्रणाली के सुधार में उनकी उपयोगिता से संबंधित कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने वाला चार्ट।

संगठनों द्वारा प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रमों पर शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) विचार करती है। शैक्षिक समितियों, संस्थान सलाहकार बोर्डों, आर.आई.ईज़. की प्रबंध समितियों और शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति द्वारा भेजे गए कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति और कमियों आदि की जांच के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति की उप समिति उनकी छानबीन करती है।

विभिन्न कार्यक्रमों की समितियों द्वारा संसाधित और संस्तुत कार्यक्रमों पर अंतिम रूप से कार्यक्रम सलाहकार समिति (पी.ए.सी.) विचार करती है। इसके साथ ही एन.सी.ई.आर.टी. की कार्यकारिणी समिति को पी.ए.सी. यह भी सिफारिश करती है कि किन विषयों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, विस्तार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा देश में विद्यालयी शिक्षा को उन्नत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के सर्वोत्तम माध्यम कौन से होंगे। पी.ए.सी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्राप्त किए गए कार्यक्रमों पर भी विचार करती है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान 22 मार्च 2000 को कार्यक्रम सलाहकार समिति (पी.ए.सी.) की बैठक हुई और इसमें विभिन्न सलाहकार बोर्डों/समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया।

अनुवीक्षण और कार्यक्रम कार्यान्वयन

कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने का दायित्व मुख्यत: एन.सी.ई.आर.टी. के प्रत्येक घटक/विभाग के अध्यक्ष पर ही होता है। एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक/संयुक्त निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय स्थित घटकों/विभागों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हैं।

परिषद् के विभिन्न घटकों के कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया परिषद् और राज्यों का एक सहयोगमूलक संयुक्त प्रयास है। एन.सी.ई.आर.टी. के लगभग सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अकादमिक सदस्यों व शिक्षा कर्मियों तथा व्यावसायिकों को विभिन्न स्तरों पर शामिल किया जाता है अर्थात् कार्यक्रम की योजना से लेकर परिणामों के व्यापक संचरण तक में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया से एन.सी.ई.आर.टी. संकाय सदस्यों को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ सहयोग व प्रतिबद्धता से कार्य करने का अवसर मिलता है।

एन.सी.ई.आर.टी. के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों के संबंध में सूचना एन.सी.ई.आर.टी. कार्यक्रम 'एन.सी.ई.आर.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कैलेण्डर' तथा 'एन.सी.ई.आर.टी. की वार्षिक रिपोर्ट' आदि प्रलेखों के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित की जाती है।

रिपोर्ट और विवरणिका

एन.सी.ई.आर.टी. विभिन्न प्रयोजनों से अपने कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की आवधिक रिपोर्टें तथा विवरणिकाएं तैयार करती है। इस दौरान निम्नलिखित रिपोर्टें तथा विवरणिकाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) को भेजी गईं:

- प्रमुख गतिविधियों और महत्वपूर्ण घटनाओं की मासिक रिपोर्ट
- प्रमुख गतिविधियों और महत्वपूर्ण घटनाओं का मासिक सारांश
- मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए मुख्य घटनाओं की रिपोर्ट
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट
- राष्ट्रीय एकता परिषद् की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई की त्रैमासिक रिपोर्ट
- पी.ओ.ए.-92 के कार्यान्वयन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
- सांप्रदायिकता को समाप्त करने तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु किए गए कार्यों की त्रैमासिक कार्रवाई रिपोर्ट
- शिक्षा विभाग (मा.सं.वि. मंत्रालय) के लिए वार्षिक रिपोर्ट हेतु मसौदा सामग्री
- बजट निष्पादन।

प्रशासन

31 मार्च, 2000 को एन.सी.ई.आर.टी. के संस्वीकृत स्टाफ की संवर्गवार स्थिति परिशिष्ट II में दी गई है।

वित्त

एन.सी.ई.आर.टी. की वर्ष 1999-2000 से संबंधित वार्षिक प्राप्ति और भुगतान लेखा संबंधी सूचना परिशिष्ट III में दी गई है।

विद्यालयी शिक्षा में एन सी ई आर टी के योगदान का सिंहावलोकन

शिक्षा की दूर-दूर तक पहुंच और विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को साकार रूप प्रदान करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. अपने विभिन्न संघटकों के माध्यम से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार तथा शैक्षिक सूचनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. ने विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों को नया रूप दिया तथा उनकी प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन किया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में वर्षों से प्रयासरत है। अपने उद्देश्यों को साकार रूप प्रदान करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. अपने विभिन्न संघटकों के माध्यम से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार तथा शैक्षिक सूचनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करती है। परिषद् के संघटकों में नई दिल्ली स्थित परिषद् मुख्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.) के विभिन्न विभागों तथा केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) के अतिरिक्त भोपाल स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) तथा अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर व शिलांग स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एवं विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थित लगभग एक दर्जन क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं।

वर्ष 1999-2000 के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. ने विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय सरोकारों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों को नया रूप दिया तथा उनकी प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन किया है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों को आरम्भ/नियोजित किया गया:

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना
- यूनेस्को का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (आई.सी.एस.एन.ई.) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र
- राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा संसाधन केन्द्र
- अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम
- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में मार्गदर्शन और परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- राष्ट्रीय कंप्यूटर विस्तार शिक्षा केन्द्र

विद्यालयी शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) पर आधारित कार्रवाई योजना (पी.ए.ओ.) के कार्यान्वयन की गति को त्वरित किया गया। ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के कार्यान्वयन में शामिल राज्यों और ज़िला स्तर की एजेंसियों को शैक्षिक सहायता और परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की गईं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्यालयी शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। पाँचवां शैक्षिक अनुसंधान सर्वेक्षण खंड दो तथा छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण जारी किए गए। रिपोर्ट के इस अध्याय में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ईज़.) द्वारा दिए गए राज्य स्तरीय योगदान सहित एन.सी.ई.आर.टी. के संघटकों/विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण, विहंगावलोकन प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रमों और कार्यकलापों का विस्तृत विवरण विषय संबंधी विभिन्न अध्यायों में दिया गया है।

शैशवकालीन शिक्षा

एन.सी.ई.आर.टी. विद्यालय-पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के संगत संसाधन सामग्री के विकास, प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों के संचालन, तथा अनुसंधान अध्ययन के माध्यम से शैशवकालीन शिक्षा (ई.सी.ई.) के क्षेत्र में शैक्षिक सहयोग व महत्वपूर्ण आगतें प्रदान कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का समन्वयन कर रही है। आई.सी.डी.एस. के विद्यालय-पूर्व शिक्षा घटकों और इसके प्रति समुदाय के दृष्टिकोण तथा इसकी उपयोगिता के विस्तार की अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस अध्ययन के प्राप्त निष्कर्षों के संकेत इस प्रकार मिलते हैं:

(1) अपर्याप्त सुविधाएं, (2) उपयुक्त पाठ्यचर्या का विकास नहीं हुआ, (3)विद्यालय-पूर्व तथा प्राथमिक विद्यालय के बीच संबंधों में कमी और (4) अभिभावकों का अत्यधिक सकारात्मक दृष्टिकोण। खिलौना निर्माण प्रतियोगिता की पुरस्कृत प्रविष्टियों पर आधारित एक पुस्तक 'इज़ी टु मेक ट्वाइज़ एंड गेम्स' शीर्षक से तैयार की गई। ई.सी.सी.ई. के कार्मिकों तथा अभिभावकों के लिए ई.सी.ई. बच्चों की प्रगति के लिए अनुवीक्षण दिशा-निर्देशों पर एक प्रलेख तथा ई.सी.ई. के क्षेत्र में अभिभावकों की जागृति के लिए छह पोस्टर तैयार किए गए। छह राज्यों के डाइटों/एस.सी.ई.आर.टीज़. के राज्य स्तरीय प्रमुख कार्मिकों के लिए ई.सी.ई. में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालय-पूर्व शिक्षा में लद्दाख पहाड़ी परिषद् के 60 शैक्षिक अधिकारियों को अभिविन्यासित किया गया।

प्राथमिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यू.ई.ई.) के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रयास

किए गए। राष्ट्रीय प्रलेखन एकक में विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित अतिरिक्त सूचना को एकत्र करने, संकलित करने, प्रलेखबद्ध करने तथा इसका प्रचार-प्रसार करने का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न राज्यों की पाठ्यपुस्तकों और रोचक अधिगम सामग्री को विश्लेषण के लिए एकत्र कर लिया गया है। 'ग्लिंप्सेज' और 'आभास' नामक त्रैमासिक पत्रिकाएं विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा में विकास पर अद्यतन सूचनाएँ प्रदान करती हैं।

अन्य त्रैमासिक पत्रिकाओं, अंग्रेज़ी में 'दि प्राइमरी टीचर' तथा हिंदी में 'प्राइमरी शिक्षक' का नियमित प्रकाशन, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों और अध्यापक प्रशिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा के नवाचारों और विचारों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मीडिया की ज़रूरतों को पूरा करता है। विभिन्न विषयों पर आरंभ किए गए निम्नलिखित अनुसंधान लगभग पूरे हो चुके हैं:

(1) कक्षा-प्रक्रिया का अध्ययन: प्राइमरी स्तर पर बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन से संबंधित शिक्षकों की अभिवृत्तियों/अपेक्षाओं पर केन्द्रित, (2) बच्चों की बोधात्मक अवस्थिति की तुलना में चयनित संकल्पनाओं/दक्षताओं के अर्जन का प्रयोगसिद्ध अध्ययन, (3) कामकाजी बच्चों को विद्यालयों की मुख्यधारा में लाने के लिए एम.वी.फाउंडेशन के अनुभवों का केस अध्ययन और (4) पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यचर्या-बोझ का एक अध्ययन। विद्यालयी पाठ्यचर्या में अबोधात्मक घटकों को पढ़ाने के लिए कक्षा शिक्षण में रंगमंच/नाटक तकनीक को अपनाने के लिए एक विद्यालय-रंगमंच मुहिम आरंभ की गई। गणित के अधिगम में कठिनाइयों के निदान के लिए परीक्षण सामग्री का एक डाटा-बैंक विकसित किया गया और अध्यापकों के लिए निदानात्मक परीक्षण पर एक पुस्तिका तैयार की गई। बच्चों में अनुभवजन्य मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 'आओ मिलकर गाएं' पुस्तक का संशोधित संस्करण निकाला गया और एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से शिक्षकों और बच्चों के लिए पाँच अंतर्राज्यीय शिविर लगाए गए। केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय बोर्डों के संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया और तिब्बती विद्यालयों का अध्ययन किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रीय योगदान इस प्रकार हैं:

कक्षा एक और दो के लिए क्रियाकलाप आधारित शिक्षण पर अनुदेशी सामग्री का विकास, प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन, अध्यायों और पाठ्य-कविताओं के रूप में 60 श्रव्य कार्यक्रमों का विकास। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों से संबद्ध प्रायोगिक स्कूलों ने कार्रवाई अनुसंधान प्रविधि के रूप में सक्षमता आधारित अध्यापन जारी रखे। अध्यापकों को बहुविध स्थितियों, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण, स्वास्थ्य आदतों, शारीरिक शिक्षा और योग में प्रशिक्षित किया गया।

ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को समर्थन

ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) का उद्देश्य उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण है। आधार-रेखा और मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण संचालित किया गया और 'स्टूडेन्ट्स अचीवमेन्ट अण्डर एम.ए.एस. अप्रेज़ल इन फेज़-II स्टेट्स' शीर्षक से एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया गया। इस दस्तावेज़ में मध्यावधि सुधारों के संकेतक दिए गए हैं तथा डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत कार्यक्रमों की भावी योजना बनाने के लिए सूचक दिए गए हैं। डी.पी.ई.पी. की समन्वय समिति द्वारा कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिगम कठिनाइयों की पहचान के लिए प्राथमिक स्तर के गणित में निदानात्मक परीक्षण सामग्री का एक डाटा बैंक तैयार किया गया। कक्षा-प्रेक्षणों, अध्यापकों, अभिभावकों और प्रशिक्षणार्थियों के गहन साक्षात्कारों के द्वारा कक्षा-प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर चार अनुसंधान अध्ययन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ईज़.) द्वारा पूरे किए जा रहे हैं:

(1) कक्षा प्रक्रियाएँ और भारतीय विद्यालय सुधारकों/महान शिक्षाविदों/भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा के शैक्षिक-दर्शन पर आधारित शिक्षण प्रदान करने वाले प्राथमिक विद्यालयों की संस्थानिक संरचना

(2) प्राथमिक अध्यापकों की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण सामग्री की सार्थकता

(3) प्राथमिक शिक्षा पर ई.सी.सी.ई. का प्रभाव

(4) आंध्र प्रदेश के डी.पी.ई.पी. ज़िलों में प्रभावी और अप्रभावी विद्यालय शिक्षा समितियों और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के नामांकन, अवधारण और उपलब्धि पर उनके प्रभाव का अध्ययन।

'प्राथमिक स्तर पर विद्यालयी प्रभावकारिता में अनुसंधान' विषय पर पाँचवीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 14 से 16 जुलाई 1999 तक आयोजित की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की पूर्व तैयारी के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं। पाँचवीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए पत्रों और संगोष्ठी की कार्रवाइयों का प्रलेखन भी शामिल किया। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में डी.पी.ई.पी. के अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पहचान की गई। उड़ीसा के गजपति ज़िले में जनजातीय बच्चों द्वारा गणित-अधिगम का एक केस अध्ययन भी किया गया।

अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण

इस क्षेत्र में निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए गए : (1) भारत में उच्च प्राथमिक स्तर पर एन.एफ.ई. की स्थिति, (2) अनौपचारिक शिक्षा तथा वैकल्पिक शिक्षण के क्षेत्र में एस.सी.ई.आर.टी. की स्थिति, (3) प्राथमिक स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में हिन्दी के पठन-पाठन में आने वाली कठिनाइयाँ और (4) बिहार, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में एन.एफ.ई. कार्यक्रम की प्रभाविता तथा रिपोर्ट लेखन का कार्य प्रगति पर है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की ज़रूरतों के विशेष संदर्भ में एस.सी.ई.आर.टी./एस.आर.सी. के अनौपचारिक शिक्षा संसाधन व्यक्तियों को अनौ. शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण के विविध पहलुओं की जानकारी दी गई। बिहार और दक्षिणी राज्यों की स्वयंसेवी संस्थाओं के अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए विषयवस्तु आधारित दो अभिविन्यास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों के लिए परामर्शकारी सेवा का विस्तार किया गया। अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए राज्यों के अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण संस्थानों के निदेशकों का वार्षिक सम्मेलन और नवाचारी और प्रायोगिक परियोजनाओं पर स्वयंसेवी संगठनों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। मा.सं. वि.मं. के अनुदान हेतु विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत 40 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया और कुछ गैर-सरकारी संगठनों के नवाचारी कार्यक्रमों के अध्ययन हेतु क्षेत्र अध्ययन आयोजित किए गए।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक शिक्षा

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में पढ़ा रहे गैर-आदिवासी शिक्षकों के आदिवासी भाषा प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गई। इस सामग्री का उद्देश्य कक्षा में पठन-पाठन प्रक्रिया और अध्यापक-छात्र सहभागिता को अर्थपूर्ण बनाना और एक आदिवासी भाषा में प्रवाह विकसित करना है। 'सरकार द्वारा पोषित मकतबों/मदरसों की वर्तमान पाठ्यचर्या का विश्लेषण' शीर्षक का अध्ययन पूरा हो चुका है और इसकी प्रारूप-रिपोर्ट तैयार की गई। अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) के शैक्षिक विकास के उद्देश्य से चलाई गई केंद्र पोषित योजनाओं से उनके हितों का कितना विकास हुआ, इसके मूल्यांकन के लिए नमूना सर्वेक्षण किया गया।

अल्पसंख्यकों के लिए चलाए गए संस्थानों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करने, मदरसों का आधुनिकीकरण करने के लिए सुझाव आमन्त्रित करने और परियोजनाओं के लिए विज्ञान पुस्तकें और विज्ञान किट आदि के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विभिन्न मदरसा बोर्डों की एक कार्यशाला आयोजित की गई।

विकलांग बच्चों की शिक्षा

बधिर बच्चों के भाषा-विकास के लिए पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षकों की सहायता हेतु एक पुस्तिका तैयार की गई। प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पद्धति में बधिर बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हिंदी भाषा की पाठ्यचर्या में अनुकूलन और समायोजन किया गया। आकलित आवश्यकताओं के आधार पर कमज़ोर दृष्टि वाले बच्चों को मुख्यधारा के परिवेश में एकीकृत करने के लिए प्राथमिक अध्यापकों हेतु संदर्शिका का हिंदी संस्करण तैयार किया गया। एकीकृत पद्धति में प्राथमिक विद्यालयों के दृष्टिहीन बच्चों के गणित पाठ्यचर्या के कार्यसंपादन हेतु एक पुस्तिका विकसित की जा रही है। विकलांग बच्चों का सामान्य

विद्यालयों में एकीकरण के क्षेत्र में डी.पी.ई.पी. राज्यों के आई.ई.डी. समन्वयकों, विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों, विद्यालयों और संस्थानों आदि को अकादमिक सहायता प्रदान की गई। भारत-आस्ट्रेलिया क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के लिए अध्यापकों को तैयार करने हेतु संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए। भारत और एशिया-प्रशांत क्षेत्रों में समावेशी पद्धति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के सहयोग से 'अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्ट शिक्षा केन्द्र' (आई.सी.एस.एन.ई.) स्थापित किया गया। आई.ई.डी.सी. के मूल्यांकन के लिए सामान्य शिक्षा पद्धति, अध्यापकों और बच्चों पर एकीकृत शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन प्रगति पर है।

बालिका शिक्षा

एन.सी.ई.आर.टी. महिलाओं की शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में सार्क के क्रियाकलापों के 'नोडल केन्द्र' के रूप में कार्य करती है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करती है। ग्रामीण बालिकाओं के नामांकन, प्रतिधारण और संप्राप्ति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए 'माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं को प्रदान की जा रही भोजन व आवास की सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण' की केंद्रीय योजना का मूल्यांकन किया गया। इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक पाया गया। म.प्र. प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण पर प्रोत्साहन योजना से पता चला कि वितरित सामानों की गुणवत्ता और व्याप्ति में सुधार की आवश्यकता है। (1) दूरवर्ती क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, (2) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में भोपाल की बेगमों की भूमिका, (3) बालिकाओं के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद का स्तर, (4) दिल्ली के स्कूलों में लैंगिक परिप्रेक्ष्य से विद्यालयी प्रयास आदि अध्ययन प्रगति पर हैं। महिलाओं की शिक्षा और विकास की पद्धति पर नवां छह-सप्ताही कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक प्रशिक्षण संदर्शिका तैयार की गई। इस कार्यक्रम में बारह राज्यों से 27 संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया।

सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा

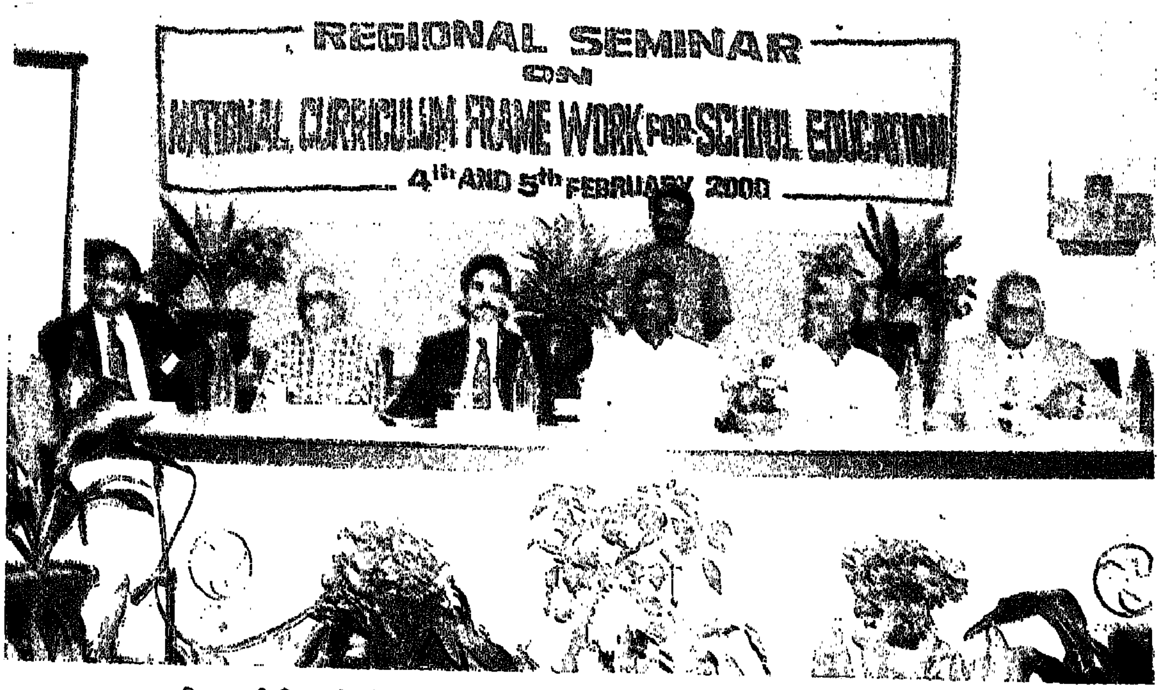
(1) कक्षा पाँच की समाप्ति पर अरुणाचल प्रदेश के विद्यार्थियों द्वारा हिन्दी भाषा में ग्रहण की गई भाषिक दक्षता, (2) उच्चतर विद्यालयों के विद्यार्थियों में मानचित्र को समझने की क्षमता और उपयोग का सर्वेक्षण, (3) हिन्दी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं (एस.आई.एल.) के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योजना के कार्यान्वयन की अवस्थिति से संबंधित अध्ययन पूरे कर लिये गए हैं और रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। एन.सी.ई.आर.टी. की सामाजिक विज्ञान और भाषा की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए एक परियोजना शुरू की गई। इस वर्ष तैयार की गई/संशोधित पाठ्यपुस्तकों में शामिल हैं-कक्षा आठ और दस के लिए भूगोल की नई/संशोधित पाठ्यपुस्तकें, कक्षा ग्यारह और बारह के लिए अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकें, कक्षा दस के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, कक्षा छह से आठ के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक का हिंदी संस्करण, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी व्याकरण और रचना, कक्षा दस के लिए हिंदी 'बी' कोर्स की पाठ्यपुस्तक और नई शृंखला में कक्षा एक के लिए अंग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तक।

व्यापार-अध्ययन और लेखाशास्त्र के पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया। विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए सचित्र हिंदी शब्दकोश और 'एन्सिएन्ट स्टोरीज़ रिटोल्ड' और 'वी आर वन' दो पूरक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए समाजशास्त्र की एक पाठ्यपुस्तक, 'उर्दू साहित्य का इतिहास', 'मानवाधिकार- एक स्रोत ग्रंथ' का उर्दू संस्करण और संस्कृत-विशेषज्ञ समूह द्वारा बनायी गई योजनाएं प्रारम्भ की गईं। 'इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इन्डिपेंडेंस : विज़ुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स' का हिंदी संस्करण छप रहा है। (1) आधुनिक भारत में उर्दू-शिक्षण- समस्याएँ और निदानात्मक मानदण्ड, (2) आज का सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य और कबीर और (3) संस्कृति शिक्षण के तरीकों का सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों ने अनेक प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए और प्रशिक्षण सामग्री तथा शिक्षण-कौशल में संदर्शिकाएँ विकसित कीं।

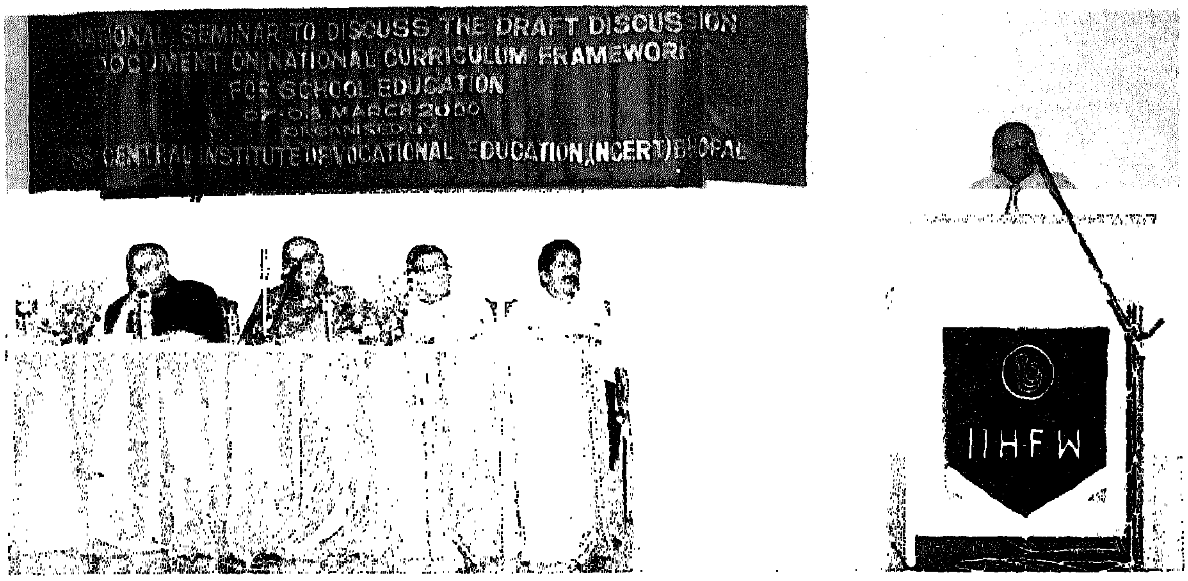
विज्ञान और गणित शिक्षा

पाठ्यचर्या के पुनर्नवीकरण को प्राथमिकता देते हुए पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ पाठ्यचर्या के विविध पक्षों पर विद्यालयी पद्धति जिसमें अध्यापक, अध्यापक-प्रशिक्षक और प्रशासक भी शामिल हैं, से पाठ्यचर्या 'फीडबैक' इकट्ठा किया गया। प्रयोगशाला उन्मुख कार्यक्रमों के अंतर्गत एन.सी.ई.आर.टी. ने कक्षा ग्यारह-बारह के लिए रसायन विज्ञान के प्रायोगिक पाठ्यक्रम के लिए वर्कशीट, +2 स्तर के लिए जीव विज्ञान की वर्कशीट, रसायन विज्ञान में सेमी-माइक्रो तकनीक को अपनाते हुए नवाचारी प्रयोगों और गणित प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशाला-संदर्शिका तैयार की। (1) 'मोल कॉन्सेप्ट एण्ड केमिकल स्टोकियोमेट्री', (2) 'केमिकल काइनेटिक्स', (3) 'केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स और (4) 'सम बेसिक कान्सेप्ट्स इन इनओर्गेनिक कमेस्ट्री', ये चार माड्यूल प्रबुद्ध विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए तैयार किए गए। +2 स्तर के लिए गणित में एक 'प्राब्लम बुक' और जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के लिए 'परीक्षण सामग्री' (टेस्ट आइटम्स) भी विकसित की गईं। 'पढ़ें और सीखें' योजना के अंतर्गत विज्ञान के कई नए शीर्षकों पर नई पुस्तकों के लेखन का कार्य प्रारंभ किया गया। 'हमारा अद्‌भुत वायुमंडल अब मैला क्यों', 'सौर ऊर्जा', 'मौसम-क्या, क्यों और कैसा', 'ग्लिम्प्सेज़ ऑफ प्लान्ट्स लाइफ' भाग-1 तथा भाग-2, 'बालू बोले अपनी बात', पुस्तकें छपने हेतु भेजी गईं। इनमें से प्रथम तीन पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं और दो प्रकाशन के क्रम में हैं। छह अन्य पुस्तकें लिखी जा रही हैं। 'रसायन विज्ञान के कुछ रोचक विषय' परियोजना के अंतर्गत 'एलॉय' पर एक माड्यूल विकसित किया गया।

पर्यावरणीय शिक्षा में राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्तियों का अभिविन्यास किया गया। सिक्किम राज्य के माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए गणित में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रसायन विज्ञान में शिक्षकों के अभिविन्यास के लिए सहकारी-अधिगम कार्यनीति का एक मॉडल विकसित किया गया और उसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। 27 नवम्बर से 3 दिसम्बर 1999 को राजकोट में गुजरात सरकार के सहयोग से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विषय पर बच्चों के लिए 26वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, 1999 आयोजित की गई। 'विज्ञान के मॉडल की संरचना और कार्य-व्यवहार' नामक एक पुस्तिका, प्रदर्श-सूची इत्यादि प्रकाशित और वितरित की गईं। राज्य स्तर के लिए विज्ञान प्रतियोगिता का केन्द्रीय विषय 'जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी' था। ये प्रदर्शनियाँ 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय



विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी।



विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिचर्चा दस्तावेज़ के प्रारूप पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी।

समिति और परमाणु ऊर्जा विद्यालयों द्वारा आयोजित की गईं। उनके संगठनों को सहायता के रूप में एन.सी.ई.आर.टी. ने 16 लाख रुपए प्रदान किए।

विज्ञान शिक्षा का स्तर-अध्ययन दो चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में भारत में विज्ञान शिक्षा के कार्यालयी स्तर की आधार सामग्री प्राप्त हुई जिसमें विद्यालयी ढाँचा, सुविधाओं और विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रमों की तुलना को शामिल किया गया। द्वितीय चरण में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की विज्ञान पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया गया। यह अध्ययन बताता है कि 80 प्रतिशत बल केवल ज्ञान पर दिया गया है।

शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को विज्ञान तथा गणित के विभिन्न पक्षों से जुड़े उनके अवबोधनों, अनुभवों और नवाचारों को प्रचार-प्रसार करने हेतु मंच प्रदान करने के लिए 'स्कूल साइंस' नामक त्रैमासिक पत्रिका लगातार निकाली जा रही है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

संकाय सदस्यों के परामर्श, प्रतिष्ठित वक्ताओं से परस्पर विचार-विमर्श और विभिन्न सैद्धान्तिक और शोध सामग्रियों के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर एक परिचर्चा दस्तावेज़ तैयार किया गया। इस परिचर्चा दस्तावेज़ पर विचार-विमर्श करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. ने क्षेत्रीय संगोष्ठियाँ, व्यावसायिक क्षेत्रों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, एन.ओ.एस., नीपा, इग्नू आदि केन्द्रीय संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं जैसे- अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक (ए.आई.पी.टी.ई.), कला, संस्कृति और शिक्षा स्थायीकरण समाज, गाँधी शांति प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सभी बोर्ड अध्यक्षों के सम्मेलन के लिए संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की और राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के अनेक संगठनों, प्रशिक्षित शिक्षाविदों और समाज के सभी वर्गों के विचार/सुझाव भी प्राप्त किए। प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन.पी.ई.पी.) के चौथे चरण को एक नए नाम 'विद्यालयों में जनसंख्या और शिक्षा विकास' के अंतर्गत आरम्भ किया गया। इस परियोजना को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), राष्ट्रीय मुक्त



पूर्व निदेशक प्रो ए.के. शर्मा जनसंख्या शिक्षा की पोस्टर प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरित करते हुए।

विद्यालय (एन.ओ.एस.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) और नवोदय विद्यालय समिति (एन.वी.एस.) द्वारा भी क्रियान्वित किया जा रहा है। विद्यालयों में किशोरावस्था शिक्षण पर आधार सामग्री का एक पैकेज प्रकाशित किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर ने खुर्दा, बलसोर और कोरापत जिलों की मानव जनसंख्या का पी.क्यू.एल. के मानकों पर एक स्तर अध्ययन किया और अध्यापक-शिक्षकों के लिए पुर्नावधारण जनसंख्या शिक्षा पर एक सहक्रियात्मक संगोष्ठी आयोजित की।

13 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 21 परियोजना कार्मिकों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए विद्यालयों में जनसंख्या और शिक्षा विकास पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केरल राज्य में अन्तर्राज्यीय शैक्षिक दौरे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

किशोर पुनरोत्पादक स्वास्थ्य पर एक आधार बिन्दु (बेन्चमार्क) सर्वेक्षण किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने अध्यापक-प्रशिक्षकों के लिए पुर्नावधारण जनसंख्या शिक्षा और किशोर शिक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। परियोजना क्रियाकलाप के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण पाँच अंतर्क्षेत्रीय समन्वय समिति की बैठकों द्वारा राज्य स्तर पर भी और मा.सं.वि.मं., एम.एच.ओ.एफ.डब्ल्यू. तथा यू.एन.एफ.पी.ए. में किया गया। प्रगति के पुनरीक्षण और कार्ययोजना तथा बजट अनुमान तैयार करने के लिए परियोजना प्रगति पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की गईं।

अंतर्राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन '21वीं सदी के लिए निर्णय : चयन और उत्तरदायित्व' विषय पर किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों द्वारा 'जनसंख्या शिक्षा सप्ताह' और 'विश्व जनसंख्या दिवस' मनाया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। 'भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण में महिलाओं का सशक्तीकरण ही सहायक होगा' विषय पर एक राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। जनसंख्या शिक्षा बुलेटिन के दो अंक प्रकाशित किए गए और उनका प्रचार-प्रसार किया गया। डी.एल.डी.आई. के जनसंख्या शिक्षा केन्द्र में जनसंख्या शिक्षा पर सामग्री इकट्ठा करने और उसके प्रचार-प्रसार का कार्य जारी रखा। साथ ही किशोर पुनरोत्पादक स्वास्थ्य और लैंगिक स्वास्थ्य पर एक मूल संदर्भ ग्रंथ सूची विकसित की और उसका प्रचार-प्रसार किया गया।

शैक्षिक मनोविज्ञान

(1) विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण और दैनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय स्तर की विज्ञान पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण, (2) मीराम्बिका में शिक्षण : एक केस अध्ययन, (3) भारत में शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान प्रवृत्तियां और मौलिकता, (4) स्थिति और विकास के निर्माण में परामर्शदाता (प्रथम चरण), (5) सामाजिक मानदण्डों के प्रति किशोरों के दृष्टिकोण का एक अध्ययन, (6) परामर्शदाता-प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्य निष्पादन और सेवा निष्पादन के लिए चुनाव प्रक्रिया की भावी संभावना, (7) भारत में मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुसंधान : एक गहन अध्ययन और (8) भारत में प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा की शैक्षिक मनोविज्ञान पाठ्यचर्या का आलोचनात्मक अध्ययन पर अध्ययन पूरे किए गए। 'कक्षा ग्यारह के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन' तथा परामर्शदाता निर्माण : स्थिति एवं विकास (द्वितीय चरण) पर अध्ययन प्रगति पर है। लोकप्रिय मनोविज्ञान शृंखला के अंतर्गत 14 पुस्तिकाओं, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान में पाठ्यचर्या, परामर्श केस प्रबंधन पर प्रायोगिक संदर्शिका और कक्षा में

अध्यापकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों पर संसाधन सामग्री, +2 स्तर पर मनोविज्ञान पाठ्यचर्या, डाइट कार्मिकों के लिए अध्यापन अधिगम मनोविज्ञान में संवर्द्धन पाठ्यक्रम के स्व अधिगम मॉड्यूलों को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मूल्य, मनोवृत्ति और रुचि मापन पर लगभग 60 भारतीय परीक्षणों की एक पुस्तिका प्रकाशन के लिए तैयार है।

मार्गदर्शन और परामर्श में नौ महीने के एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 13 राज्यों से 31 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। सी.बी.एस.ई. से संबद्ध विद्यालयों में +2 स्तर पर मनोविज्ञान पढ़ाने वाले विद्यालयी अध्यापकों के लिए मनोविज्ञान में एक संवर्द्धन पाठ्यक्रम और राज्य स्तरीय प्रशिक्षित मार्गदर्शन कर्मिकों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किया गया। एन.आई.ई., सी.आई.ई.टी. और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में मूल्य शिक्षा पर विस्तृत ग्रंथ-सूची तैयार की जा रही है। मूल्य शिक्षा पर एक संसाधन केन्द्र स्थापित किया गया है जो मूल्यों की सामग्री के लिए राष्ट्रीय भण्डार सदन का कार्य करेगा। इस केन्द्र में मूल्य शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार का साहित्य शामिल किया गया है। मार्गदर्शन और परामर्श में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण पुस्तकालय में लगभग 25 भारतीय परीक्षण शामिल करके उसे समृद्ध किया गया। कैरियर सूचना केन्द्र तथा मार्गदर्शन प्रयोगशाला ने मार्गदर्शन और परामर्श के पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों तथा संकाय की आवश्यकताओं की पूर्ति की। शैक्षिक मनोविज्ञान और परामर्श के क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों को परामर्श सेवाएँ और अनुसंधान सहायता उपलब्ध कराई गई।

परीक्षा सुधार

पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.सी.ई., पश्चिम बंगाल और नागालैण्ड बोर्डों के उच्च माध्यमिक परिणामों के विश्लेषण से पता चला कि छात्रों की तुलना में छात्राओं का प्रतिशत बेहतर रहा। विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत अन्य बोर्डों की अपेक्षा आई.सी.एस.सी.ई. का, विज्ञान विषयों में अन्य बोर्डों की तुलना में गोवा बोर्ड का, अन्य विज्ञान विषयों की अपेक्षा जीव विज्ञान का उच्च था। आन्तरिक और बाह्य परीक्षा अंकों के अध्ययन से यह संकेत मिला कि बोर्ड-पूर्व परीक्षा और बोर्ड परीक्षा परिणामों के बीच एक सार्थक सह-संबंध था। उच्च माध्यमिक स्तर के लिए रसायन विज्ञान में प्रायोगिक कार्यपुस्तिका और रसायन प्रयोग कार्य के मूल्यांकन के लिए एक योजना विकसित की गई। कक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया को मज़बूत बनाने के लिए कक्षा चार के लिए पर्यावरणीय अध्ययन (सामाजिक अध्ययन) में परीक्षण सामग्री का एक 'पूल' तैयार किया गया। 'ग्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानिए' को ध्यान में रखते हुए एक सुनिश्चित तरीके से 'विद्यालयों में ग्रेडिंग' शीर्षक से एक दस्तावेज़ विकसित किया गया और उसे विस्तृत रूप से प्रचारित किया गया। विभिन्न विद्यालयी विषयों में संतुलित प्रश्न-पत्र विकसित करने के लिए जम्मू-कश्मीर और कर्नाटक बोर्डों के प्रश्नकों/परीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। गोवा के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उत्तम प्रश्न और एक 'आइटम बैंक' बनाने की तकनीकों से अवगत कराया गया। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों को सतत् और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा और तकनीक में अभिमुख किया गया। गुजरात और मेघालय से आइटम लेखकों को राज्य स्तरीय एन.टी.एस. परीक्षा के लिए मानसिक योग्यता परीक्षण (एम.ए.टी.) के लिए आइटम लेखन में अभिविन्यासित किया गया। विद्यालयी शिक्षा के राज्य बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन में अंकों के स्थान पर ग्रेड से जुड़े मुद्दों, विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन रूपरेखा का विकास आदि पर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज

इस योजना का उद्देश्य है- कक्षा दस की समाप्ति पर प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता देना ताकि वे आगे अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। 1999-2000 के दौरान 70 अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों सहित 750 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं। पुरस्कार के लिए चयन दो स्तरों पर किया गया। प्रथम स्तर पर राज्यों द्वारा लिखित परीक्षाओं के आधार पर चयन किया गया। दूसरे स्तर पर चयन का कार्य एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया गया।

1999-2000 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत कुल 4710 पुरस्कार विजेताओं को छात्रवृत्ति के रूप में 1.25 करोड़ रुपया वितरित किया गया।

अध्यापक शिक्षा

निम्नलिखित पर अध्ययन किए गए- (1) प्राथमिक अध्यापकों की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के संदर्भ में उनकी शिक्षण-प्रभाविता, (2) महाराष्ट्र में स्मार्ट-पी.टी. के अंतर्गत अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता का मूल्यांकन, (3) विज्ञान शिक्षण के सृजनात्मक उपागम, (4) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण का व्यावहारिक अध्ययन, (5) दिल्ली की स्वायत्तशासी एस.सी.ई.आर.टी. का केस अध्ययन, (6) डाइटों की योजनाओं का कार्यान्वयन और (7) एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई. का स्तर। निम्नलिखित का विकास प्रगति पर है- (1) 'भारत में अध्यापक शिक्षा के पचास वर्ष' पर एक दस्तावेज़, (2) अध्यापक मूल्यांकन के लिए प्रतिभागितामूलक तथा डाटा-बेस व्यवस्था के लिए रूपरेखा, (3) भारतीय शिक्षा पर एक विश्वकोश। इग्नू के सहयोग से प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए स्व-अधिगम सामग्री तैयार की गई है।

भारत सरकार के शिक्षा तथा दूरसंचार विभाग, यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.) की सहायता से मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों में, कंप्यूटर की सहायता से दो तरफा आडियो तथा दो तरफा वीडियो व्यवस्था का प्रयोग करते हुए, अनुक्रियात्मक दूरदर्शन के माध्यम से सेवाकालीन अध्यापकों के प्रशिक्षण (आई.पी.टी.टी.-आई.टी.वी.) के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई. के संकाय के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम तथा डाइट के संकाय के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। एस.सी.ई.आर.टीज़./एस.आई.ईज़. के निदेशकों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भारतीय शिक्षा में अद्यतन विकास के संदर्भ में एस.सी.ई.आर.टी. की बदलती भूमिकाओं तथा आपसी हितों के सरोकारों को साझा करने पर विचार-विमर्श किया गया। अध्यापक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा में नवाचारी अभ्यास और कार्य पद्धतियों की योजना के अंतर्गत 71 लेख प्राप्त हुए। इनमें से 27 लेख राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए जिनमें 19 लेख प्राथमिक अध्यापक शिक्षा स्तर तथा 8 लेख माध्यमिक अध्यापक शिक्षा स्तर के थे। ये पुरस्कार एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रदान किए गए।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों (आर.आई.ईज़.) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर ने चार-वर्षीय बी.एससी. बी.एड./बी.एससी.एड. समेकित पाठ्यक्रम जारी रखा। विज्ञान और मानविकी में एक दो-वर्षीय बी.एड. (माध्यमिक) पाठ्यक्रम विकसित किया गया और 1999-2000 सत्र से शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की पूर्व तैयारी के रूप में प्राथमिक स्तर पर विद्यालय प्रभाविता के संबंध में अनुसंधानों पर क्षेत्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित कीं। नीपा/मा.सं.वि.मं. की ओर से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों द्वारा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओबी) योजना का राष्ट्रीय मूल्यांकन भी किया गया। 2000-2001 से आरंभ किए जाने वाले मार्गदर्शन और परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ने विज्ञान में ब्लूप्रिंट रूपरेखा व प्रश्नपत्रों, हिंदी व व्यावसायिक लेखाशास्त्र पढ़ाने के लिए अध्यापक संदर्शिका, रसायनशास्त्र में विषयवस्तु संवर्द्धन सामग्री, गणित में प्रशिक्षण सामग्री, बीजगणित में कठिन क्षेत्रों की पहचान के लिए अंतरावर्तिता सामग्री और कक्षा 1 तथा 2 में हिंदी और गणित के लिए तथा व्यावसायिक लेखाशास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए कार्यकलाप आधारित अनुदेशी सामग्री का विकास किया। डाइट संकाय और एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई. संकाय के लिए हिंदी, पर्यावरण 1 और 2 तथा गणित का कार्यकलाप आधारित शिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण के आयोजन, शैक्षिक सर्वेक्षणों के संचालन, सेवाकालीन कार्यक्रमों के मूल्यांकन और उच्च अनुदेशी विधियों तथा कार्यक्रम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, सहकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, एस.आई.ई. संकाय, पर्यवेक्षण से जुड़े कर्मियों को शैक्षिक पर्यवेक्षण, योजना और मूल्यांकन आदि में प्रशिक्षित किया गया। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को विद्यालयी विषयों

के शिक्षण, बहुश्रेणी स्थिति में स्व-अधिगम क्रियाकलापों के प्रयोग और विज्ञान किट के प्रयोग का भी सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने (1) डाइट संकाय के लिए विशेष शिक्षा, (2) आदिवासी विद्यालय शिक्षकों के लिए लेखाशास्त्र शिक्षण, (3) अंग्रेज़ी अध्यापकों के लिए मौखिक परीक्षण और (4) उर्दू अध्यापकों के लिए उर्दू शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया। अनुदेशी सामग्री के रूप में (1) ई.सी.ई. के लिए नमूना क्रियाकलाप योजना, (2) शैक्षिक प्रक्रिया से लैंगिक असमानता को समाप्त करने की कार्यनीतियां, (3) पर्यावरण पर आधारित नवाचारी सामग्री और (4) +2 स्तर पर इतिहास के मानक प्रश्नपत्र विकसित किए गए। डाइट संकाय और मुख्य संसाधन व्यक्तियों के लिए (1) माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, (2) जनसंख्या शिक्षा, (3) अंग्रेज़ी भाषा में नवाचारी शिक्षण विधियां, (4) विकलांगों की एकीकृत शिक्षा, (5) भूगोल की मूलभूत दक्षताएं और (6) कम्प्यूटर साक्षरता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। नवोदय विद्यालयों में अर्थशास्त्र, भूगोल, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान और केंद्रीय विद्यालयों में इतिहास, भूगोल, हिंदी व गणित के स्नातकोत्तर अध्यापकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रभर में एक महीने तक 'वन्देमातरम्' नामक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर ने आदिवासी प्राथमिक विद्यालयों और कम विकृति के विकलांगों के लिए पाठ्यचर्या संपादन, पर्यावरणीय अध्ययनों (विज्ञान) में अधिगम क्रियाकलाप बैंक, कक्षा 3 और 4 के लिए बंगाली स्व-अधिगम सामग्री की समस्याओं के समाधान की कार्यनीतियों का विकास किया। इसी क्रम में संस्थान ने हिंदी और उड़िया में परीक्षण, परामर्श और मार्गदर्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए पाठ्यक्रम और 5 वर्षीय बी.ए.बी.एड./बी.एससी. बी.एड. पाठ्यक्रमों और अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए एम.एड. कार्यक्रम का पुन: प्रतिपादन किया। डाइट/एससीईआरटी संकाय और मुख्य संसाधन व्यक्तियों के लिए सतत् और व्यापक मूल्यांकन, हिंदी शिक्षण-अधिगम निष्कर्षों के मूल्यांकन की कार्यनीतियों, पाठ्यपुस्तक लेखन, आई.ई.डी.सी. शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विद्यालयी विषयों के अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया गया। इंटर्नशिप शिक्षण पर प्रधानाध्यापकों और सहकारी विद्यालयों के अध्यापकों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। उत्तर-पूर्वी राज्यों में पी.एम.ओ.एस.टी. के क्रियान्वयन हेतु संसाधन व्यक्तियों का अभिविन्यास किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र और जीव विज्ञान के प्रश्न बैंक, माध्यमिक स्तर पर गणित और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स पर माड्यूल्स विकसित किए। गणित की अध्यापक पुस्तिका, पर्यावरणीय अध्ययन-2 में क्रियाकलाप आधारित अनुदेशी सामग्री, अंग्रेज़ी, तमिल और तेलुगू शिक्षण के आडियो कैसेट भी विकसित किए गए। कम्प्यूटर अनुप्रयोग पर डाइट/एस.सी.ई.आर.टी. के मुख्य स्तर के व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विषयगत और शिक्षाशास्त्री दक्षताओं के विकास के लिए स्नातकोत्तर शिक्षकों और इंटरमीडिएट कालेज के प्रवक्ताओं के सेवाकालीन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग ने (1) मिज़ोरम के पाठ्यपुस्तक लेखकों, (2) सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए असम के एस.सी.ई.आर.टी./डाइट संकाय सदस्यों और (3) सॉप्ट के संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम (सॉप्ट)

एन.सी.ई.आर.टी. ने विभिन्न राज्यों में सॉप्ट कार्यक्रमों को शैक्षिक सहयोग और अनुवीक्षण प्रदान करने की अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना जारी रखा। क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थानों और क्षेत्र सलाहकारों ने सॉप्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया और अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक सहयोग तथा मार्गदर्शन प्रदान किया। इस वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.80 लाख अध्यापक प्रशिक्षित किए गए। इस योजना के प्रारंभ 1993-94 से अब तक लगभग 12.5 लाख अध्यापक प्रशिक्षित हो चुके हैं।

शैक्षिक दूरदर्शन

एन.सी.ई.आर.टी. ने छोटे बच्चों के लिए आकाशवाणी के 195 स्टेशनों से प्रसारित होने वाले एक साप्ताहिक श्रव्य प्रसारण 'उमंग', प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए डी.डी.-1 पर उपलब्ध शैक्षिक दूरदर्शन सेवा के अंतर्गत 'तरंग' तथा शैक्षिक उपग्रह चैनल 'ज्ञान दर्शन' (26 जनवरी 2000) से विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण को प्रसारण-सामग्री प्रदान करनी जारी रखी। इसके अतिरिक्त 'एक्सप्लोरिंग दि यूनिवर्स', 'स्पेस साइंस एंड एक्सप्लोरिंग एक्सप्लोरेशन्स', 'दि लिविंग प्लेनेट-अर्थ' (सभी माध्यमिक स्तर), 'एनवायरनमेंट', 'क्रियेटिव मूवमेंट्स एंड म्यूज़िकल इन्स्ट्रूमेंट्स', 'वाटर एंड लाइफ' (प्राथमिक स्तर), 'वाटर मोशन', 'सेरीकल्चर एंड ड्रिप इरिगेशन', 'बिज़नेस एंड कॉमर्स', 'समाधान', 'परफोर्मिंग आर्ट्स', 'दिवास्वप्न' आदि विभिन्न शृंखलाओं के अन्तर्गत लगभग 85 शैक्षिक दूरदर्शन आलेखों की रूपरेखा भी तैयार की गई।

दृश्य कार्यक्रमों के लिए आरेखीय संपादन, नई गुणवत्ता वाले जनित्र का संचालन और व्यावहारिक चालन, स्टूडियो कैमरों-डी.एक्स.सी.-डी. 3 ओ.पी. का सिद्धान्त, व्यावहारिक संचालन व रख-रखाव और संपादन उपकरण डी.एफ.एस. 500 पी.वी.एफ. 500 पी.वी.डब्ल्यू 800 पी. में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तर-पूर्व राज्यों और उड़ीसा के डाइटों के शैक्षिक प्रौद्योगिकीय संकाय और एस.आई.ई.टी. कर्मियों को क्रमश: शैक्षिक प्रौद्योगिकी और बहु संचार में प्रशिक्षित किया गया। एस.सी.ई.आर.टी., मणिपुर के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग में एक तीन-सप्ताही अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

विभिन्न विश्वविद्यालयों/विद्यालयों के संचार विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों और वीडियोग्राफी में स्नातक के विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण से जोड़ा गया और राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के स्नातक विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए अपनी परियोजना के एक अंग के रूप में बहुसंचार पैकेज पर एनीमेशन से सम्बद्ध हैं। सी.आई.ई.टी. ने सात एस.आई.ई.टीज़. के क्रियाकलापों के संचालन में सहयोग और शैक्षिक तथा संचार-उत्पादन की गतिविधियों में मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को भी परामर्श और सहयोग प्रदान किया गया।

संचार अनुसंधान और मूल्यांकन गतिविधियों में शामिल हैं- (1) बच्चों के पत्रों के विश्लेषण पर आधारित 'पत्रों के उत्तर' मासिक कार्यक्रम, (2) ग्रेड-4 स्तर पर मापन अवधारणा के शिक्षण के लिए अंतर्क्रियात्मक दृश्य कार्यक्रम का अध्ययन, (3) विभिन्न विषय क्षेत्रों में कम्प्यूटर सहायक अधिगम- एक बड़ा विश्लेषण और (4) 'शैक्षिक मीडिया की प्रभाविता- एक सर्वेक्षण' नामक एक मीडिया अनुसंधान समीक्षा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के एस.आई.ई.टीज़. और राजस्थान के ई.टी. सेल के सहयोग से भारत सरकार की शैक्षिक तकनीकी योजना का एक प्रभाव अध्ययन प्रगति पर है। एन.सी.ई.आर.टी. की कक्षा-6 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों पर एक अंत:क्रियात्मक बहुसंचार-सी डी-आर. ओ.एम. (पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए) विकसित किया गया है।

सी.आई.ई.टी. ने जापान, यू.एस.ए. और जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक दृश्य-श्रव्य उत्सवों में भाग लिया और अपने 'रोज़ बदलता कैसे चांद' (दि चेंजिंग मून) के लिए एन.एच.के. टोक्यो में 'दि मायडा' पुरस्कार जीता। कठपुतलियों द्वारा कहानी कहने पर आधारित एक दूसरा कार्यक्रम 'म्यूनिख', जर्मनी में वीडियो बार के लिए चयनित हुआ।

कंप्यूटर शिक्षा और प्रौद्योगिकीय सहायता

एन.सी.ई.आर.टी. में कंप्यूटर शिक्षा और संबंधित अनुसंधान तथा आधुनिक तकनीकी सहायता/मीडिया के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एन.सी.ई.आर.टी. ने सूचना प्रौद्योगिकी के आत्मसातीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निवेश प्रदान किया। संघटक इकाइयों की हार्डवेयर प्रणाली, समुचित साफ्टवेयर और इंटरनेट सम्बद्धता प्रदान की गई। आई.टी. दक्षताओं में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एन.सी.ई.आर.टी. का वेबसाइट विद्यालयी शिक्षा के लिए समर्पित प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। सेवाकालीन अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु बहुमाध्यम प्रयोगशाला विकसित की गई है। इसमें राष्ट्रीय कंप्यूटर - विस्तार शिक्षा केन्द्र में परिवर्धित प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किए गए जिसमें आई.टी. आधारित अधिगम सामग्री का

विकासशील संग्रह है। सूचना प्रौद्योगिकी और विद्यालयी प्रक्रिया पर एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई। एन.सी.ई.आर.टी. ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय हेतु स्मार्ट विद्यालयों के लिए ब्लू प्रिंट और एन.सी.ई.आर.टी. कर्मचारियों और अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक स्व-अधिगम माड्यूल विकसित किए। एन.सी.ई.आर.टी. ने कंप्यूटर के प्रयोग और बहुमाध्यम साफ्टवेयर के विकास पर स्टाफ के लिए अनेक, और केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली के विद्यालय अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

एन.सी.ई.आर.टी. ने 1999-2000 के दौरान 100 प्राइमरी विज्ञान किट, 30 मिनी टूल किट व मिडिल विद्यालयों के लिए 265 एकीकृत विज्ञान किट बनाए और राज्यों के प्राथमिक विद्यालयों में 300 प्राइमरी विज्ञान किट व 72 मिनी टूल किट की आपूर्ति की। उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए धारा विद्युत हेतु लागत-प्रभावी प्रयोगशाला क्रियाकलापों के लिए लागत प्रभावी शिक्षण साधनों के एक सेट का परीक्षण दिल्ली के विद्यालयों में किया जा रहा है।

व्यावसायिक शिक्षा

कंप्यूटर सहायता प्राप्त आरेखन और पांडुलेखन (ड्राइंग और ड्राफ्टिंग), कम लागत की आवास-व्यवस्था और समुदाय आधारित पुनर्वास पर तीन नई दक्षता आधारित व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यचर्याओं का विकास किया गया और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 6 पाठ्यचर्याओं का विकास किया गया। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श पर एक पुस्तिका, स्वास्थ्य और पैरा-चिकित्सा, गृह विज्ञान के क्षेत्रों में व्यावसायिक पाठ्यचर्या के साथ पर्यावरणीय घटकों का एकीकृत परिशिष्ट और व्यावसायिक योग्यता प्रणाली के अंतर्गत बड़ी संख्या में उद्यान विज्ञान, कीट पालन और अभियांत्रिकी पर बड़ी संख्या में लघु माड्यूल विकसित किए गए। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की 15 अनुदेशी सामग्रियों की पांडुलिपि और 9 पूर्व व्यावसायिक माड्यूल विकसित किए गए हैं जो मुद्रणाधीन हैं।

अध्यापक प्रशिक्षण के बारह कार्यक्रम निम्नलिखित क्षेत्रों में आयोजित किए गए-क्रय और भंडारण, घरेलू बिजली उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव, उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना (पी.टी.सी.), कंप्यूटर यूनिक्स प्रणाली प्रशासन, कम्प्यूटर तकनीक, व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श, उद्यमिता विकास, जिसमें आदिवासी, विकलांग, अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक संस्थानों में कार्यरत 285 अध्यापकों के लिए जेनेटिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में व्यावसायिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 संसाधन पदाधिकारियों को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया। नवसाक्षर आदिवासी/ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए एक 25-दिवसीय साधन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। व्यावसायिक शिक्षा के क्रियान्वयन में अवधारणागत स्पष्टता लाने के बारे में राज्य कर्मचारियों के लिए आठ अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अलावा यात्रा और पर्यटन प्रबंधन व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए छह राष्ट्रीय परिसंवादों/गोष्ठियों का आयोजन किया गया। 'शिक्षा का व्यावसायीकरण : नई सहस्राब्दि के लिए परिप्रेक्ष्य' विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

सर्वोत्तम व्यावसायिक संस्थान, सर्वोत्तम व्यावसायिक अध्यापक और सर्वोत्तम विद्यालय-उद्योग संयोजन को व्यावसायिक शिक्षा उन्नयन के लिए पुरस्कार (प्रत्येक राज्य को एक) दिए गए। उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रत्येक राज्य को दो सर्वोत्तम उपार्जितकर्ता पुरस्कार दिए गए। प्रकाशनों की दो प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं। इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन और क्वार्टर्ली बुलेटिन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन प्रत्येक के दो संयुक्त अंक प्रकाशित किए गए और शेष अंक मुद्रणाधीन हैं। व्यावसायिक शिक्षा की शोध परियोजनाएँ जो प्रगति पर हैं, उनमें शामिल हैं- (1) निश्चित राज्यों में सामान्य आधार पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन का तुलनात्मक

अध्ययन, (2) राज्यों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का बेंचमार्क सर्वेक्षण, (3) भारत में व्यापार और वाणिज्य आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के व्यावसायिक शिक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों का स्तर अध्ययन, (4) शहरी और ग्रामीण समाजों में लड़कियों की जीविका आकांक्षा बनाम व्यावसायिक शिक्षा, (5) माध्यमिक व्यावसायिक विद्यालयों में विद्यालय-उद्योग के बीच संबंध की स्थापना-क्रियात्मक अनुसंधान, (6) चुने हुए राज्यों में व्यावसायिक पाठ्यचर्या और अनुदेशी सामग्री की गुणवत्ता और मानदंड का तुलनात्मक मूल्यांकन, (7) कृषि में व्यावसायिक पठन-पाठन की स्थिति और प्रभाविता का तुलनात्मक अध्ययन, (8) महाराष्ट्र के कुछ व्यावसायिक संस्थानों के विद्यालय उद्योग संयोजन का केस अध्ययन, (9) पंजाब के व्यावसायिक विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन पर कार्य प्रशिक्षण का प्रभाव, (10) महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर गृहविज्ञान व्यावसायिक पाठ्यक्रम की सार्थकता और (11) 10+2 स्तर के विद्यार्थियों में व्यावसायिक दक्षता के विकास में अध्यापक व्यवस्था की भूमिका। बिहार के गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रम की क्षमता और कमज़ोरी के मूल्यांकन के लिए सी.ए.एस. के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का अध्ययन किया जा रहा है।

विशेष व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और अनुदेशी सामग्री का सुधार और विकास के लिए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और असम राज्यों को परामर्श दिया जा रहा है।

शैक्षिक अनुसंधान और नवाचारों को उन्नयन

अनेक संघटकों में अनुसंधान करने के अतिरिक्त एन.सी.ई.आर.टी. बाहरी संस्थाओं/संगठनों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) द्वारा समर्थित 13 परियोजनाएँ पूरी की गईं। एरिक के अंतर्गत 56 अनुसंधान परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। एरिक के सहयोग से एक पीएच.डी. का शोध प्रबंध प्रकाशित हुआ। वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त अनुसंधान प्रस्तावों की स्वीकृति और नीतिगत मामालों के पुनरीक्षण के लिए एरिक की एक बैठक आयोजित की गई। विद्यालयी शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान नवाचारों और अन्य विकासों का 'जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन', 'भारतीय आधुनिक शिक्षा', और 'इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू' के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया।

1800 से अधिक सारांशों से युक्त और 38 क्षेत्रों में वर्गीकृत शैक्षिक अनुसंधान के पांचवें सर्वेक्षण के दूसरे खंड को अंतिम रूप दिया गया। शैक्षिक अनुसंधान के अगले सर्वेक्षण जिसकी अवधि 1993 से 1997 है, में सर्वेक्षण के अध्ययनों को पूरा होने और उनके व्यापक प्रचार-प्रसार के बीच समय के अंतराल को न्यूनतम करने के लिए नई प्रविधियाँ अपनाई जा रही हैं। 'इंडियन एजुकेशनल एब्सट्रेक्ट्स' (आई.ई.ए.) नामक छमाही अनुसंधान पत्रिका का प्रकाशन जारी रहा। आई.ई.ए. का एक संयुक्तांक (खण्ड 7 और 8), जिसमें 201 सार-संक्षेप हैं, को अंतिम रूप दिया गया। यह अंक मुद्रणाधीन है। डाइट और एस.सी.ई.आर.टी. संकाय के लिए अनुसंधान पद्धति पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एन.आई.ई. व्याख्यान माला के अंतर्गत ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों के व्याख्यान आयोजित किए गए।

पी.ई.ओ. को आर्थिक सहायता

शिक्षा के उन्नयन के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने के क्रम में कुछ व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों (पी.ई.ओ.) को विस्तार क्रियाकलाप/पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु आर्थिक मदद दी गई।

शैक्षिक सर्वेक्षण

छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की मुख्य रिपोर्ट मुद्रित रूप में आ चुकी है। इसमें निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए गए हैं- (1) प्राथमिक स्तर पर एकल आयुवार नामांकन का अनुमान, (2) प्राथमिक स्तर पर शाला त्याग और गतिरोध : उ.प्र. के दो चयनित ज़िलों का नमूना अध्ययन, (3) विद्यालय शिक्षा की वृद्धि : एक ग्राफिकीय प्रस्तुतीकरण और (4) प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का मूल्यांकन और पुनरीक्षण। छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के प्रचार-प्रसार की कार्यनीतियों का विकास नामक परियोजना पूर्णता के स्तर पर है। परिमाणात्मक अनुसंधान पद्धति पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय सेवाएं

राज्यों में स्थित एन.सी.ई.आर.टी. के क्षेत्रीय सलाहकारों ने एन.सी.ई.आर.टी. के विभिन्न संघटकों, मा.सं.वि. मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभागों आदि के द्वारा किए गए कार्यक्रमों और कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए निरंतर संपर्क जारी रखे। आर.आई.ई. के विस्तार शिक्षा विभागों ने राज्य समन्वय समितियों (एस.सी.सीज़.) के माध्यम से राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान की जिनके लिए एन.सी.ई.आर.टी. के संघटकों से सहायता अपेक्षित है।

एन.सी.ई.आर.टी. के क्षेत्र सलाहकारों ने राज्य शिक्षा विभागों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए अध्यापकों के चयन, पाठ्यचर्या और अनुदेशी सामग्री के विकास, कार्मिकों के प्रशिक्षण और नीति निर्धारण आदि कार्यों में सहयोग दिया। मा.सं.वि.मं. को भी निम्नलिखित प्रसंगों में मदद की गई : (1) राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण, (2) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा जमा किए गए अनौपचारिक शिक्षा प्रस्तावों का स्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन, (3) संयुक्त मूल्यांकन दल के माध्यम से स्वयंसेवी संगठनों के कार्यरत अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के कार्यों का मूल्यांकन और (5) नीपा, मा.सं.वि.मं. परियोजना ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का मूल्यांकन।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विद्यालयी शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में एन.सी.ई.आर.टी. द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों (सी.ई.पी.) की एक प्रमुख एजेंसी के रूप में निरंतर कार्यरत रही है। वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार द्वारा सीरिया, ग्रीस, कुवैत, कम्बोडिया और फ्रांस से द्विपक्षीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त रिपोर्टों, सामग्री, प्रलेख आदि को एन.सी.ई.आर.टी. स्थित पुस्तकालय प्रलेखन व सूचना प्रभाग के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र में रखा गया। एन.सी.ई.आर.टी. के कई संकाय सदस्यों को अन्य देशों में उन देशों या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु भेजा गया। एन.सी.ई.आर.टी. संकाय सदस्यों ने भारत में आए कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों/शिक्षाविदों और अध्यापकों से विचार-विमर्श किया।

पुस्तकालय और प्रलेखन

एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय में स्थित परिषद् का पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना प्रभाग एन.आई.ई. परिसर, नई दिल्ली में एन.सी.ई.आर.टी. के विभिन्न घटकों के अनुसंधान और विकास के कार्यकलापों में सहायता देता है। एन.सी.ई.आर.टी. के दूसरे घटक भी अपने परिसर में पुस्तकालय बनाए हुए हैं। वर्षों से यहां शिक्षाशास्त्रियों, अध्यापक शिक्षकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों आदि के लिए शिक्षा और संबंधित विषयों पर पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का समृद्ध संग्रह है। यह पुस्तकालय कार्यदिवसों में लगातार सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक और शनिवार तथा रविवार को 9 बजे से शाम 5.00 बजे तक खुला रहता है। राजपत्रित अवकाशों पर यह बंद रहता है। 31 मार्च 2000 को इस पुस्तकालय में कुल 30,160 पुस्तकें और पत्रिकाएँ थीं।

हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन

एन.सी.ई.आर.टी. के संघटकों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के क्रम में अनेक कदम उठाए गए हैं। मुख्यालय में अवर श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों और अनुभाग अधिकारियों के लिए तीन हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा लेने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। 14 से 28 सितंबर 1999 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि में टिप्पण/प्रारूपण, निबंध लेखन, टंकण, अनुवाद, वाद-विवाद, कविता और आशुलिपि की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., सी.आई.ई.टी. और आर.आई.ईज़. ने भी हिंदी सप्ताह और हिंदी के प्रोत्साहन हेतु कई प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए। विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। एन.सी.ई.आर.टी. के विभिन्न घटकों के प्रशासनिक प्रलेखों और कागज़-पत्रों के हिंदी अनुवाद संबंधी सहायता हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की जाती रही।

कार्यक्रम नियोजन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन

एन.सी.ई.आर.टी. के विभिन्न संघटकों/विभागाध्यक्षों ने अपने-अपने विभाग के संकाय सदस्यों द्वारा किए जा रहे

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण जारी रखा। संघटकों के कार्यक्रमों की समीक्षा परिषद् के निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा, एन.सी.ई.आर.टी. के नियोजन, कार्यान्वयन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रभाग के माध्यम से की गई। परिषद् के विभिन्न संघटकों के कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन की समस्त प्रक्रिया एन.सी.ई.आर.टी. और राज्यों के सामूहिक प्रयास के अन्तर्गत चल रही है। एन.सी.ई.आर.टी. के रा.शि.सं. के विभागों के कार्यक्रमों को उसके विभागीय सलाहकार बोर्डों (डी.ए.बी.) और अकादमिक समितियों (ए.सी.), सी.आई.ई.टी. और पी.एस.एस.सी. आई.वी.ई. के कार्यक्रमों को अपने संस्थान सलाहकार बोर्डों (आई.ए.बी.) और आर.आई.ईज़. के कार्यक्रमों को अपनी प्रबन्धन समितियों (एम.सीज़.) की प्रक्रिया के दौर से गुज़रना पड़ा। कार्यक्रम सलाहकार समिति (पी.ए.सी.) द्वारा कार्यक्रमों पर अनुमोदनार्थ विचार करने से पहले कार्यकारिणी समिति ने उन पर अन्तिम संस्तुति की। एन.सी.ई.आर.टी. कार्यक्रमों और क्रियाकलाप की प्रगति की आवधिक रिपोर्टों और विवरणों को मा.सं.वि.मं. को निरन्तर भेजती रही है।

प्रकाशन

एन.सी.ई.आर.टी. ने विद्यालयी शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, अनुपूरक पुस्तकों, अध्यापक संदर्शिकाओं, व्यावसायिक शिक्षा में अनुकरणीय अनुदेशी सामग्री, अनुसंधान रिपोर्ट/प्रबंध और शैक्षिक पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य निरंतर जारी रखा। इस वर्ष के दौरान 319 प्रकाशन सामने आए। पत्रिकाओं के प्रकाशन की स्थिति इस प्रकार है–

- इंडियन एजुकेशनल रिव्यू — 3 अंक
- जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन — 6 अंक
- स्कूल साइंस — 11 अंक
- दि प्राइमरी टीचर — 4 अंक
- प्राइमरी शिक्षक — 5 अंक
- भारतीय आधुनिक शिक्षा — 5 अंक
- इंडियन एजुकेशनल एब्सट्रेक्ट्स — 1 अंक

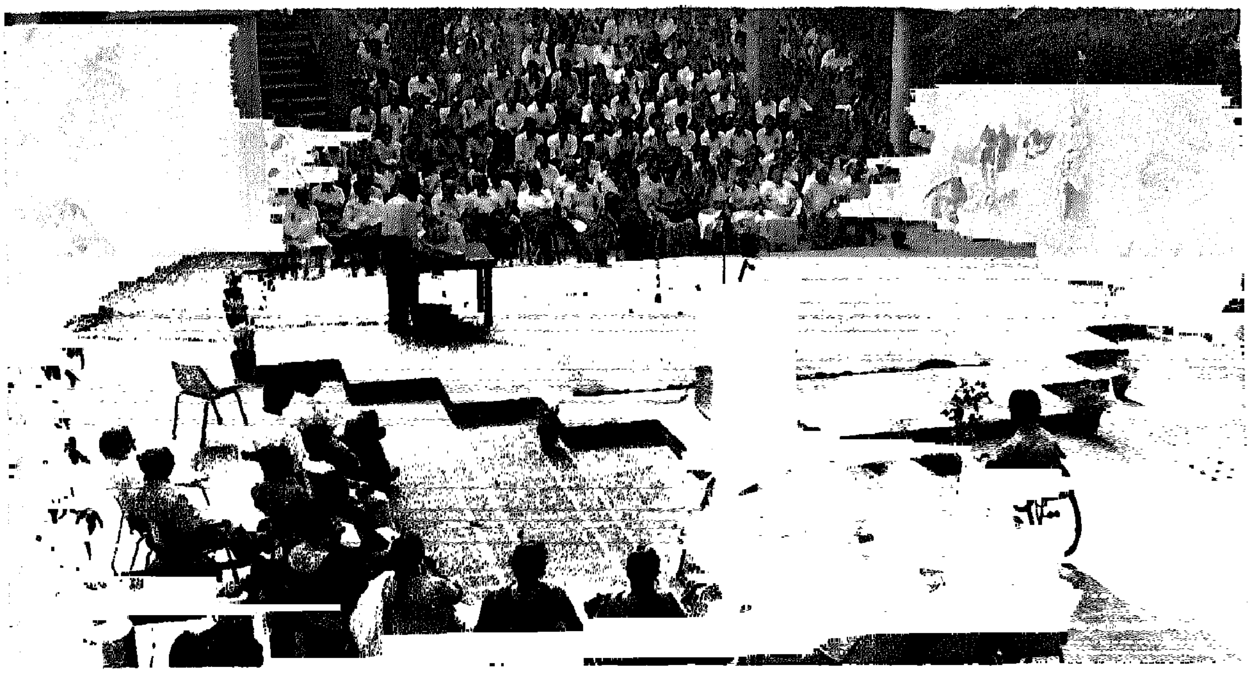
एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशनों की बिक्री देश भर में फैले थोक एजेंटों के माध्यम से की गयी। उर्दू प्रकाशनों की बिक्री और वितरण का कार्य उर्दू अकादमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से किया गया। एन.सी.ई.आर.टी. का प्रकाशन प्रभाग सीधे विद्यालयों और व्यक्तियों को एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों आदि की आपूर्ति करता रहा। इस वर्ष प्रकाशित अनेक पुस्तकें अनुमोदित डाक सूची के अनुसार डाक द्वारा भिजवाई गईं। प्रकाशनों की बिक्री से कुल 41.41 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। बड़ी संख्या में संस्थानों और अनुसंधानकर्ताओं द्वारा भेजी गई मांगों के आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. के मूल्यरहित प्रकाशनों की आपूर्ति की गई। परिषद् के प्रकाशन प्रभाग के क्षेत्रीय उत्पादन-सह-वितरण केन्द्रों– सुखचर (पश्चिम बंगाल) और बेंगलूर ने परिषद् के प्रकाशनों की बिक्री और वितरण का कार्य अपने-अपने क्षेत्रों जैसे पूर्वी और दक्षिणी में अनवरत जारी रखा। उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों की मांगों की आपूर्ति एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा की गई।

सूचनाओं के प्रचार-प्रसार से संबंधित कार्य के एक भाग के रूप में प्रकाशन प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी. ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया:

1. दिल्ली पुस्तक मेला, अगस्त 1999
2. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी राजकोट, नवंबर-दिसंबर 1999
3. हैदराबाद पुस्तक मेला, दिसंबर 1999
4. राष्ट्रीय पुस्तक मेला, भोपाल, नवंबर 1999
5. कलकत्ता पुस्तक मेला, जनवरी-फरवरी 2000
6. विश्व पुस्तक मेला, दिल्ली, फरवरी 2000

कल्याण कार्यकलाप

कर्मचारियों की पात्रता और स्थिति के अनुसार विभिन्न वर्ग के क्वार्टरों का आबंटन किया गया। वर्ष 1999-2000 के दौरान 23 नए आबंटन और 16 परिवर्तन मांग पर आबंटित किए गए। पप्पन कलाँ में 135 से अधिक स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। एन.सी.ई.आर.टी. के सभी कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बचत जीवन बीमा योजना लागू है। परिपक्वता/निकासी दावे के 86 मामलों और मृत्यु दावे के 16 मामलों को अंतिम व्यवस्थापन हेतु भारतीय



एन.सी.ई.आर.टी. का 39वां स्थापना दिवस।

जीवन बीमा निगम को भेजा गया। भारतीय जीवन बीमा निगम से कुछ दावों के अलावा सभी दावों का भुगतान प्राप्त हुआ और जी.एस.एल.आई.एस. के अंतर्गत पूर्व सदस्यों और दिवंगत सदस्यों के नामितियों को प्रदान किया गया। एक हज़ार दो सौ नियमित वेतनभोगी और दो सौ पचास पेंशनभोगी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा सुविधा का लाभ ले रहे हैं। वे कर्मचारी जो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा क्षेत्राधिकार से बाहर हैं वे ए.एम.ए. के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। एन.सी.ई.आर.टी. के 40 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतीक उपहार प्रदान किए गए। 1 सितम्बर 1999 को एन.सी.ई.आर.टी. के स्थापना-दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

एन.सी.ई.आर.टी. में स्वतंत्रता-दिवस और नव वर्ष दिवस मनाया गया तथा बच्चों को मिठाइयाँ और कर्मचारियों को चाय/नाश्ता दिया गया। कार्यालय समय के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की गई। शारीरिक बीमारियों पर डा. एस.सी.एस. सेंगर, चेयरमैन, अन्तर्राष्ट्रीय ओषधिशास्त्री और परामर्शी चिकित्सक की पांच वार्ताएँ विभिन्न समूह के कर्मचारियों के लिए आयोजित की गईं। सफाईवालों और अन्य कर्मचारियों के लिए साक्षरता कक्षाएँ लगाई गईं।

3 शैशवकालीन शिक्षा

शैशवकालीन शिक्षा (ई.सी.ई.) के दोहरे लाभ–बच्चे के विकास पर पड़ने वाले इसके प्रत्यक्ष प्रभाव तथा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यू.ई.ई.) में इसके योगदान–को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय विशेषज्ञता का विकास करने तथा इस क्षेत्र में कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ विद्यालय-पूर्व तथा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए शैक्षिक और मनोरंजक मूल्यजन्य सस्ते व प्रभावकारी अनौपचारिक साधनों की खोज और विकास को ई.सी.ई. परियोजना में प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है। विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर और बच्चों तथा अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में समुचित अध्ययन–शिक्षण सामग्री तैयार करके क्षमता विकास का कार्य किया जा रहा है।

शैशवकालीन शिक्षा (ई.सी.ई.) के दोहरे लाभ–बच्चे के विकास पर पड़ने वाले इसके प्रत्यक्ष प्रभाव तथा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यू.ई.ई.) में इसके योगदान–को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय विशेषज्ञता का विकास करने तथा इस क्षेत्र में कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ विद्यालय-पूर्व तथा प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए शैक्षिक और मनोरंजक मूल्यजन्य सस्ते व प्रभावकारी अनौपचारिक साधनों की खोज और विकास को ई.सी.ई. परियोजना में प्रमुख स्थान दिया जाता रहा है। विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर और बच्चों तथा अध्यापकों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में समुचित अध्ययन शिक्षण सामग्री तैयार करके क्षमता विकास का कार्य किया जा रहा है। विद्यालय-पूर्व शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार, संगत संसाधन सामग्री के विकास, प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों के आयोजन तथा अनुसंधान अध्ययन आदि के माध्यम से एन.सी.ई.आर.टी. महत्वपूर्ण समर्थनकारी व अकादमिक सहयोग प्रदान कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को सहायताप्राप्त परियोजनाओं का समन्वयन कर रही है।

अनुसंधान

शैशवकालीन शिक्षा (ई.सी.ई.) परियोजना

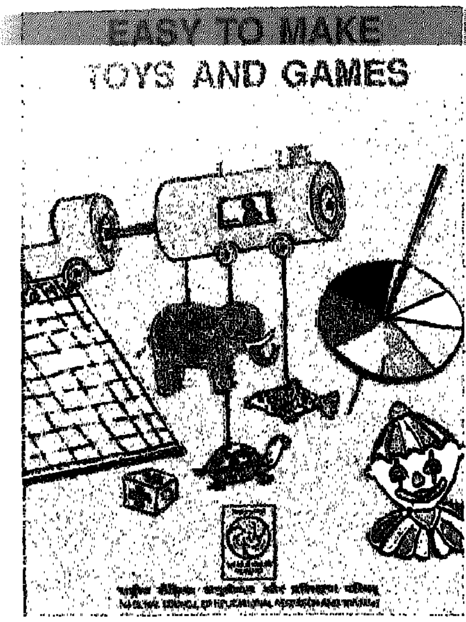
पिछले पाँच वर्षों की यूनिसेफ सहायताप्राप्त ई.सी.ई. परियोजना, जिसमें 10 राज्यों को शामिल किया गया था, की एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसका प्रथम प्रारूप तैयार है। 12 राज्यों में, ई.सी.ई. परियोजनाओं के समन्वयकों की एक समीक्षा बैठक में विभिन्न राज्यों द्वारा की गई प्रागति की समीक्षा की गई।

विकास

खिलौना बनाने की प्रतियोगिता की विजेता प्रविष्टियों पर आधारित 'ईज़ी टु मेक टॉयज़ एंड गेम्स' नामक एक पुस्तक तैयार की गई जो प्रकाशनाधीन है।

प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय प्रमुख कार्यकताओं हेतु शैशवकालीन शिक्षा के अन्तर्गत 6 राज्यों के डी.आई.ई.टीज़./एस.सी.ई.आर.टीज़. से 44 कार्मिकों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।



खेलों के विकास व खिलौनों के निर्माण पर प्रकाशित पुस्तक।

लद्दाख पर्वतीय परिषद् के शैक्षिक अधिकारियों के लिए वार्षिक अभिविन्यास/प्रशिक्षण के अन्तर्गत विद्यालयों में कार्यरत 60 व्यक्तियों, ब्लाक और जिला स्तर के शैक्षिक अधिकारियों को विद्यालय पूर्व शिक्षा में पूर्वाभिमुख किया गया।

विस्तार

ई.सी.ई. परियोजना समन्वयन के अंतगर्त बिहार, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में 2000-01 के लिए वार्षिक योजनाओं के विकास और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ई.सी.ई. कार्मिकों के लिए योजना प्रशिक्षण में अकादमिक समर्थन प्रदान किया गया।

शैशवकालीन शिक्षा में क्षेत्रीय सहायता

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने शारीरिक और गतिकी (मोटर), सामाजिक और भावनात्मक, सर्जनात्मक, बोधात्मक भाषा और संज्ञानात्मक विकास में मध्य प्रदेश के एस.सी.ई.आर.टी. और डी.आई.ई.टी. के लिए शैशवकालीन शिक्षा हेतु प्रतिदर्शी कार्यकलाप योजना का विकास किया और उसे अन्तिम रूप दिया।

1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- रिपोर्ट ऑन 'स्टडी ऑफ प्री-स्कूल एजुकेशन कंपोनेन्ट ऑफ आई.सी.डी.एस. एंड इट्स परसेप्शन एंड एक्सटेंट ऑफ यूटिलाइज़ेशन बाई दि कम्युनिटी' (अनुलिपि)।

4 प्राथमिक शिक्षा

भारत में विद्यालयी स्तर के लिए पाठ्यचर्या योजना में मूल्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यों को सिखाया नहीं जा सकता। इसे विद्यालयी बच्चे तभी सीख सकते हैं, जब वे इकट्ठे रहें। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, एन.सी.ई.आर.टी. ने बच्चों में अनुभवजन्य मूल्य शिक्षा को उन्नत करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया। माननीय मा.सं.वि. मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने दिसंबर, 99 में इस कार्यक्रम का उद्घाटन 'आओ मिलकर गाएँ' पुस्तक के संशोधित संस्करण के विमोचन से किया।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यू.ई.ई.) की व्यापक रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है। पाठ्यचर्या समीक्षा, विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण, प्रासंगिक व महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और अनुसंधान अध्ययनों व पत्रिकाओं आदि के द्वारा विचारों, अनुभवों और समाचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुसंधान

कक्षा-प्रक्रिया का अध्ययन : प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन के संबंध में अध्यापकों की अभिवृत्ति/अपेक्षाओं पर केंद्रित

इस अध्ययन का उद्देश्य बच्चों की अपेक्षाओं के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का आकलन करना है। इसके संबंध में दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के प्रदर्शन के द्वारा सूचना प्राप्त करने की अपेक्षा की गई। इसके लिए गुणात्मक अनुसंधान कार्यप्रणाली को अपनाया गया जिसमें कक्षा-प्रक्रिया का विस्तृत प्रेक्षण तथा चुनिंदा केस अध्ययन विद्यालयों में निर्धारित कक्षाओं के अध्यापन-अधिगम से जुड़े अध्यापकों का अनिर्देशित साक्षात्कार किया गया। अपेक्षित क्षेत्रीय अध्ययन पूरा हो चुका है और विश्लेषण किया जा रहा है।

ग्रेड-3 के बच्चों की बोधात्मक अवस्थिति की तुलना में चयनित संकल्पनाओं/दक्षताओं के अर्जन का एक प्रयोगसिद्ध अध्ययन

पाठ्यचर्या के क्षेत्र में यह एक अन्वेषणात्मक अध्ययन है। अनुसंधान का प्रश्न है, क्या बच्चे के लिए कठिन सक्षमताओं को हासिल करना इसलिए कठिन है क्योंकि ये बच्चों की बोधात्मक अवस्थिति से ऊपर है या कोई अन्य कारण है जैसे परीक्षाओं की भाषा, कक्षा में अपर्याप्त प्रतिपादन। कठिन सक्षमताओं की पहचान करने के लिए एक प्रारंभिक अध्ययन के परिणामों हेतु एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा एक मार्गदर्शी अध्ययन किया गया जिसके अन्तर्गत वर्तमान अध्ययन में इन सक्षमताओं को हासिल करने पर बच्चों के टेस्ट हेतु एक मापदंड संदर्भ परीक्षण बनाया गया। यह टेस्ट लिखित और मौखिक प्रपत्र के रूप में था। बच्चे की बोधात्मक अवस्थिति की पहचान के लिए एक बोधात्मक कार्य के साथ-साथ ग्वालियर के चुनिंदा विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का एक उपलब्धि टेस्ट भी लिया गया। आधार सामग्री का विश्लेषण किया जा रहा है।

कामकाजी बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में लाने में एम.वी. फाउंडेशन के अनुभवों का केस अध्ययन

प्रारंभिक शिक्षा में नवाचारी पद्धतियों के प्रलेख के अध्ययनों की एक श्रृंखला के अन्तर्गत, वर्ष 1999-2000 के लिए आन्ध्र प्रदेश के ज़िला रंगारेड्डी में एम.वी. फाउंडेशन के कार्यों को लिया गया। एम.वी. फाउंडेशन का उद्देश्य विद्यालय से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सामान्य विद्यालयों में बनाए रखना है। इस अध्ययन का उद्देश्य उनके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनके प्रयासों और पुनरावृत्ति की प्रभावकारिता को प्रलेखित करना है। विद्यालय प्रेक्षणों और बच्चों, अध्यापकों व अभिभावकों के साक्षात्कारों पर आधारित एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार हो चुकी है।

पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यचर्या बोझ का एक अध्ययन

स्थिति के त्वरित मूल्यांकन के लिए पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम बोझ का एक अध्ययन किया गया। 25 विद्यालयों से सूचना एकत्र की गई जिसमें पाँच विद्यालय हरियाणा के और शेष दिल्ली के थे। नमूने में सभी प्रकार के विद्यालयी प्रबन्धनों के विद्यालयों को शामिल किया गया। इस अध्ययन के परिणामों को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित पाठ्यचर्या रूपरेखा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में शामिल किया गया। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

विकास

विद्यालय रंगमंच गतिविधि

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा अधिगम विशेषकर विद्यालय पाठ्यचर्या के अबोधात्मक घटकों को पढ़ाने के लिए रंगमंच/नाटक प्रविधियों को अपनाना था। इस

कार्यक्रम को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संकाय सदस्यों और शिक्षा समूह में रंगमंच से जुड़े कुछ व्यक्तियों के सहयोग से आरंभ किया गया। दिल्ली से विभिन्न प्रबन्धनों के अन्तर्गत पाँच विद्यालयों के अध्यापकों के एक समूह को एक कार्यगोष्ठी में आमंत्रित किया गया। इस कार्यगोष्ठी में प्रतिभागियों को कक्षा में नाटक के द्वारा पढ़ाने के लिए सुग्राही बनाया गया। विभिन्न विषयों के शिक्षण के संदर्भ में विद्यालय में इसकी गतिविधियों और कक्षा अध्यापक द्वारा इसके विकास का आदान-प्रदान किया गया।

प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित में निदानात्मक परीक्षण

इस कार्यक्रम में अधिगम कठिनाइयों के निदान के प्रयोगार्थ जाँच-विषयों का एक आधार आँकड़ा बैंक विकसित किया गया। तीन राज्यों में इसका परीक्षण किया गया और आधार-सामग्री का विश्लेषण बच्चों की सम्भावित अधिगम कठिनाइयों को समझने के लिए किया गया। अध्यापकों के प्रयोगार्थ अनुभव पर आधारित निदानात्मक जाँच सहित निदानात्मक परीक्षण की एक पुस्तिका तैयार की गई। आगे, व्यावहारिक निदानात्मक उपाय के प्रचार-प्रसार के प्रयास किए गए।

बच्चों में अनुभवजन्य मूल्य शिक्षा को उन्नत करना

भारत में विद्यालयी स्तर के लिए पाठ्यचर्या योजना में मूल्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मूल्यों को सिखाया नहीं जा सकता। इसे विद्यालयी बच्चे तभी सीख सकते हैं, जब वे इकट्ठे रहें। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, एन.सी.ई. आर.टी. ने बच्चों में अनुभवजन्य मूल्य शिक्षा को उन्नत करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया। माननीय मा.सं.वि. मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने दिसंबर, 1999 में इस कार्यक्रम का उद्घाटन 'आओ मिलकर गाएँ' पुस्तक के संशोधित संस्करण के विमोचन से किया। इस परियोजना में बच्चों और अध्यापकों के लिए अन्तर्राज्यीय शिविर, सामुदायिक गायन व राष्ट्रीय एकता, मूल्य शिक्षा तथा अंतर-सांस्कृतिक अभिव्यक्तिकरण को उन्नत करने के लिए अध्यापक शिविरों का आयोजन किया गया। एस.सी.ई. आर.टीज़. के सहयोग से बच्चों के लिए अध्यापकों के साथ पाँच अन्तर्राज्यीय शिविर आयोजित किए गए।

प्रशिक्षण

केंद्रीय तिब्बती विद्यालय बोर्ड के अनुरोध पर संसाधन व्यक्तियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। संकाय सदस्यों के एक दल ने इस प्रशिक्षण का अनुकरण उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में स्थित तिब्बती विद्यालय के अध्ययन में किया।



माननीय मा.सं. वि.मं. डा. मुरली मनोहर जोशी 'आओ मिलकर गाएँ' पुस्तक का विमोचन करते हुए।

विस्तार

पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आंकड़ा बैंक

पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रलेखन एकक (एन.डी.यू.) के अन्तर्गत सामग्री सूचना का संकलन, वर्गीकरण नियमित रूप में किया गया और सरल आकलन के लिए कंप्यूटर में फीड किया गया। 1999-2000 में विश्लेषण के लिए विभिन्न राज्यों की पाठ्यपुस्तकें और रोचक अधिगम सामग्री एकत्र की गईं। एक विषय-सूची एवं विवरणिका निकाली जा रही है जिसमें एन.डी.यू. के संबंध में सूचना दी गई है।

समाचार पत्रिकाएँ–'ग्लिम्प्सेज़' और 'आभास'

दोनों समाचार पत्रिकाएँ (अंग्रेज़ी में 'ग्लिम्प्सेज़' और हिंदी में 'आभास') त्रैमासिक हैं और हर वर्ष जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च में नियमित प्रकाशित होती हैं। समाचार पत्रिका 'ग्लिंप्सेज़' की लगभग 2000 प्रतियों और 'आभास' की 1000 प्रतियों का प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों/व्यक्तियों में नियमित रूप से प्रचार-प्रसार किया गया। ग्लिंप्सेज़ समाचार पत्रिका का सितंबर, 1999 का अंक निकाला जा चुका है और इसका प्रचार-प्रसार संबंधित एजेंसियों को किया गया। दोनों समाचार पत्रिकाओं के दिसंबर 1999 अंक और 'आभास' का सितंबर 1999 अंक प्रकाशनाधीन है और मार्च अंक की पाण्डुलिपि तैयार की जा रही है।

पत्रिकाएँ

दो त्रैमासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित करना– अंग्रेज़ी में 'दि प्राइमरी टीचर' और हिंदी में 'प्राइमरी शिक्षक' एन.सी.ई.आर.टी. के नियमित और निरंतर कार्यकलाप हैं। ये पत्रिकाएँ प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के बारे में विचारों और समाचारों के आदान-प्रदान का एक खुला मंच प्रदान करती हैं और मुख्य रूप से प्राथमिक कक्षाओं में कार्यरत अध्यापकों तथा अध्यापक प्रशिक्षकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं।

'प्राइमरी शिक्षक' के तीन अंक अप्रैल 1999, जुलाई 1999 और अक्टूबर 1999 पहले प्रकाशित हो चुके हैं। चौथा अंक जनवरी 2000 मुद्रणाधीन है। 'प्राइमरी टीचर' के भी दो अंक (अप्रैल 1999 एवं जुलाई 1999) प्रकाशित हो चुके हैं, एवं बाकी के दो अंक मुद्रणाधीन हैं।

प्राथमिक शिक्षा में क्षेत्रीय निवेश

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ने शिक्षण आधारित कार्यकलाप के अन्तर्गत हिन्दी और गणित में कक्षा 1 और 2 के लिए अनुदेशी सामग्री तैयार की और उत्तर प्रदेश के एक चुनिंदा ब्लाक के अध्यापकों को प्रशिक्षण भी दिया ताकि अधिगम-अध्यापक प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाया जाए। हरियाणा के बहुश्रेणी स्थिति के अध्यापकों को स्वत: अधिगम कार्यकलापों के प्रयोग में प्रशिक्षित किया और कक्षा के लिए अपेक्षित सामग्री प्रदान की।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर ने प्राइमरी विद्यालयों में छात्रों की उपलब्धि पर प्रभाव डालने वाले घटकों का अध्ययन किया और विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम के संबंध में एक मॉडल विकसित किया। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को स्वास्थ्य आदतों, शारीरिक शिक्षा और योग पर अभिमुख भी किया गया।

1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- शिक्षा के पहले कदम : प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की ओर, भाग I
- 'प्राइमरी ईयर्स टुवर्ड्स करीकुलम फ्रेम वर्क पार्ट-2
- लैट अस सिंग टुगैदर (संगीत स्वरलिपि सहित, संगीत स्वरलिपि रहित)
- प्रमोटिंग एक्सपिरिएन्शल वेल्यू एजुकेशन (हिंदी और अंग्रेज़ी)
- पत्रिका 'दि प्राइमरी टीचर' - त्रैमासिक 1999-2000 के सभी अंक
- पत्रिका 'प्राइमरी शिक्षक' - त्रैमासिक 1999-2000 के सभी अंक
- त्रैमासिक समाचार पत्रिका 'ग्लिंप्सेज़' 1999-2000 के सभी अंक
- हिन्दी में त्रैमासिक समाचार पत्रिका - 'आभास' 1999-2000 के सभी अंक।

अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मुख्यतः अनुभवों के आदान-प्रदान और कार्यप्रणालियाँ विकसित करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली में 27-28 मार्च 2000 को अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण में राज्य संस्थानों के निदेशकों का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया।

एन.सी.ई.आर.टी.

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को पूरा करने के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में एन.सी.ई.आर.टी. संसाधनों के विकास, अध्यापन-अधिगम सामग्री के विकास और वैकल्पिक शिक्षण हेतु कार्यनीतियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए क्षेत्रीय विषयवस्तु आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य स्तरीय संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों का एक मजबूत संसाधन आधार तैयार करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण में स्थितिपरक अध्ययन के संबंध में शोधकार्य, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावकारिता और नवाचारी परियोजना के मूल्यांकन को भी लिया गया है। एन.सी.ई.आर.टी. विभिन्न सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों को परामर्श और संसाधन सहायता प्रदान करती है। वर्ष 1999-2000 में किए गए कार्यक्रमों के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

अनुसंधान

उच्च प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति

इस अध्ययन से यह प्रकट हुआ कि छह राज्यों/सं.शा. प्रदेश जैसे आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, उड़ीसा और चंडीगढ़ तथा बहुत थोड़े से स्वयंसेवी संगठनों में उच्च प्राथमिक स्तर पर एन.एफ.ई. कार्यक्रम का कार्यान्वयन हुआ है। कार्यक्रम के कम कार्यान्वयन का मुख्य कारण योग्य और प्रशिक्षित अनुदेशकों की अनुपलब्धता, अभिभावक-असमर्थन और एन.एफ.ई. बच्चों के लिए पाठ्यक्रम की अनुपयुक्तता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया। रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण के क्षेत्र में एस.सी.ई.आर.टीज़. की स्थिति

अध्ययन से ये संकेत मिले हैं कि केवल नौ राज्यों- आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/राज्य शिक्षा संस्थान अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए सामग्री विकास, प्रशिक्षण और अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन में शामिल थे। रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और राज्य एजेन्सियों और अन्य संगठनों को भेज दी गई है।



अनौपचारिक शिक्षा का एक परिदृश्य : आनंददायी अधिगम।

प्राथमिक स्तर के अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों पर हिंदी के अध्यापन अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ

यह अध्ययन दिल्ली और हरियाणा में किया गया। प्राथमिक स्तर पर हिंदी के अध्यापन अधिगम में आने वाली कठिनाइयों की पहचान की गई और सुधारात्मक कार्यप्रणाली के सुझाव दिए गए। आंकड़ा आधार के विश्लेषण और रिपोर्ट का कार्य चल रहा है।

बिहार, हरियाणा और राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा की प्रभावकारिता

यह अध्ययन बिहार और राजस्थान के सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों दोनों और हरियाणा में तीन गैर सरकारी संगठनों द्वारा एन.एफ.ई. कार्यक्रमों के कार्यान्वियन तक सीमित था। प्रभावकारिता के अध्ययन को अवसंरचना, प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या, अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण, कार्यक्रम मूल्यांकन और अध्येता उपलब्धि को ध्यान में रखकर किया गया। आँकड़ों का विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन का कार्य किया जा रहा है।

मूल्यांकन

एन.सी.ई.आर.टी. ने प्रयोगात्मक और नवाचारी कार्यक्रमों पर केंद्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत मा.सं.वि. मंत्रालय में अनुदान के लिए संगठनों द्वारा प्रेषित 40 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया और कुछ गैर सरकारी संगठनों के नवाचारी कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए कई क्षेत्र अध्ययन किए। मा.सं.वि. मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई गई नवाचारी परियोजनाओं के अध्ययन के लिए क्षेत्रों के दौरे किए गए जैसे बिहार और उड़ीसा में 'फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल्स सोसायटी', मुंबई में विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए 'प्रथम', ऋषि घाटी शिक्षा केंद्र, मदनपाल्ले, आन्ध्र प्रदेश। ये दौरे उनके उपग्रह विद्यालयों में बहुश्रेणी और बहुस्तरीय अध्यापन की कार्यप्रणाली के अध्ययन हेतु किए गए। इन दौरों की रिपोर्टों को मा.सं.वि. मंत्रालय को भेजा गया।

प्रशिक्षण

स्वयंसेवी संगठनों के अनौपचारिक शिक्षा कार्यकर्ताओं का अभिविन्यास

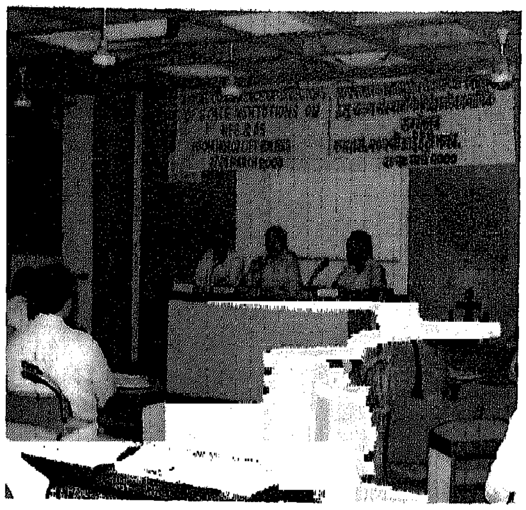
दक्षिणी राज्यों के 26 और बिहार के स्वयंसेवी संगठनों के 35 वरिष्ठ अनौपचारिक शिक्षा कार्यकर्ताओं के लिए दो विषय-वस्तु आधारित पांच-दिवसीय क्षेत्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम क्रमशः बैंगलूर और नीमडीह में आयोजित किए गए। प्रतिभागियों को अनौपचारिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं जिनमें एन.एफ.ई. केंद्रों का अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण, न्यूनतम अधिगम स्तर, अध्यापन अधिगम कार्यप्रणालियां और अध्येताओं की उपलब्धि का मूल्यांकन आदि शामिल था, की जानकारी दी गई।

एस.सी.ई.आर.टीज़./एस.आई.ईज़./एस.आर.सीज़./डी.आई.ई.टीज़. के प्रमुख एन.एफ.ई. कार्यकर्ताओं का अभिविन्यास

पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों के एस.सी.ई.आर.टीज़./एस.आई.ईज़./एस.आर.सीज़./डी.आई.ई.टीज़. में डी.आर.यूज़. के 24 प्रमुख अनौपचारिक शिक्षाकर्मियों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम 21-25 फरवरी, 2000 को एस.सी.ई.आर.टी., कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अभिविन्यास कार्यक्रम में शामिल प्रमुख पहलू इस प्रकार थे: नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों की भूमिका; विभिन्न सरकारी अभिकरणों में अनुभवों को साझा करना; ज़िला, ब्लाक और गाँव स्तर पर क्षमता निर्माण; शिक्षण कार्यप्रणाली, अध्यापन अधिगम सामग्री का विश्लेषण और छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन।

विस्तार

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए मुख्यतः अनुभवों के आदान-प्रदान और कार्यप्रणालियां विकसित करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली में 27-28 मार्च 2000 को अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण में राज्य संस्थानों के निदेशकों का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। 23-24 मार्च को एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली में स्वयंसेवी संगठनों की नवाचारी और प्रयोगात्मक परियोजनाओं के अनुभवों को



अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण के राज्य संस्थानों के निदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।

साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी इन उद्देश्यों से आयोजित की गई- (क) एन.जी.ओ. द्वारा नवाचारों और प्रयोगों को प्रलेखित करना और (ख) विद्यालय प्रणाली में इन नवाचारों को मुख्यधारा में लाने के लिए कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली विकसित करना है। इस कार्यगोष्ठी में पन्द्रह स्वयंसेवी संगठनों ने भाग लिया और नवाचार तथा प्रायोगिक परियोजनाओं पर अपने अनुभव प्रस्तुत किए। 'एन.एफ.ई. इन एक्शन' शीर्षक के अन्तर्गत एन.जी.ओ.- लोक सेवा आयतन, नीमडीह, बिहार द्वारा संचालित एन.एफ.ई. केंद्रों से एन.एफ.ई. अध्येताओं और अनुदेशकों ने 23 जून 1999 को एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली में नृत्य/नाटक के ज़रिए पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं/शीर्षकों से अधिगम प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। एन.सी.ई. आर.टी. में संगठनात्मक स्तरीय कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के अतिरिक्त विभिन्न सरकारी और स्वयंसेवी संगठनों को परामर्श और संसाधन सहायता प्रदान की गई।

1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- एस.सी.ई.आर.टी./एस.आर.सी. के अनौपचारिक शिक्षा के संकाय सदस्यों और अनौपचारिक शिक्षा व वैकल्पिक शिक्षण के संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट (फोटोप्रति)।
- दक्षिणी राज्यों से गैर सरकारी संगठनों के वरिष्ठ एन.एफ.ई. कार्यकर्ताओं के लिए विषय-वस्तु आधारित क्षेत्रीय अभिविन्यास कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की शिक्षा

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में आदिवासी भाषाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण पैकेज विकसित करने का कार्यक्रम आदिवासी भाषा में धाराप्रवाहिता को विकसित करने और कक्षा में पढ़ाने तथा अध्यापक-छात्र अन्योन्यक्रिया को अर्थपूर्ण बनाने पर केंद्रित है। इस प्रशिक्षण पैकेज में मनोवृत्तिक बदलावों के लिए अपनाईं जाने वाली कार्यप्रणालियों और संप्रेषण की प्रासंगिकता व व्यावहारिक विषय क्षेत्रों के संदर्भ में मज़बूत सांस्कृतिक घटकों को सम्मिलित किया गया है। इसका उड़ीसा राज्य के डी.पी.ई.पी. ज़िलों में व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है।

एनसीईआरटी

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण (यू.ई.ई.) की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के उद्देश्य से एन.सी.ई.आर.टी. विशेष आवश्यकताओं वाले समूहों, जैसे- अनुसूचित जातियों (एस.सी.), अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) और अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दे रही है। इस क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में संचालित कार्यक्रमों के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

गैर-आदिवासी अध्यापकों के लिए आदिवासी भाषा का प्रशिक्षण पैकेज

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में आदिवासी भाषाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण पैकेज विकसित करने का कार्यक्रम आदिवासी भाषा में धाराप्रवाहिता को विकसित करने और कक्षा में पढ़ाने तथा अध्यापक-छात्र अन्योन्यक्रिया को अर्थपूर्ण बनाने पर केंद्रित है। इस प्रशिक्षण पैकेज में मनोवृत्तिक बदलावों के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणालियों और संप्रेषण की प्रासंगिकता व व्यावहारिक विषय क्षेत्रों के संदर्भ में मज़बूत सांस्कृतिक घटकों को सम्मिलित किया गया है। इसका उड़ीसा राज्य के डी.पी.ई.पी. ज़िलों में व्यापक रूप से प्रयोग किया गया है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

मकतबों/मदरसों में मौजूदा पाठ्यचर्या का विश्लेषण

इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी सहायताप्राप्त मकतबों/मदरसों की मौजूदा पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का अध्ययन और विश्लेषण करना और अन्तरालों की पहचान करके उनकी पाठ्यचर्या को संशोधित करने का सुझाव देना है। इस अध्ययन में आंकड़े एकत्र करने के लिए तीन राज्यों- केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। इन राज्यों से विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों सहित विभिन्न प्रकार के उत्तर देने वालों से सूचना एकत्र करने के लिए एक प्रश्नावली बनाई गई। इस प्रकार से एकत्र किए गए आंकड़ों का कक्षा 5 तक पढ़ाए जाने वाले विषयों, वित्तीय सहायता के स्रोतों, संबंधों, अनुदेश के माध्यम, अध्यापकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, अध्यापकों की योग्यताओं और परीक्षा की शर्तों को ध्यान में रखकर विश्लेषण किया गया।

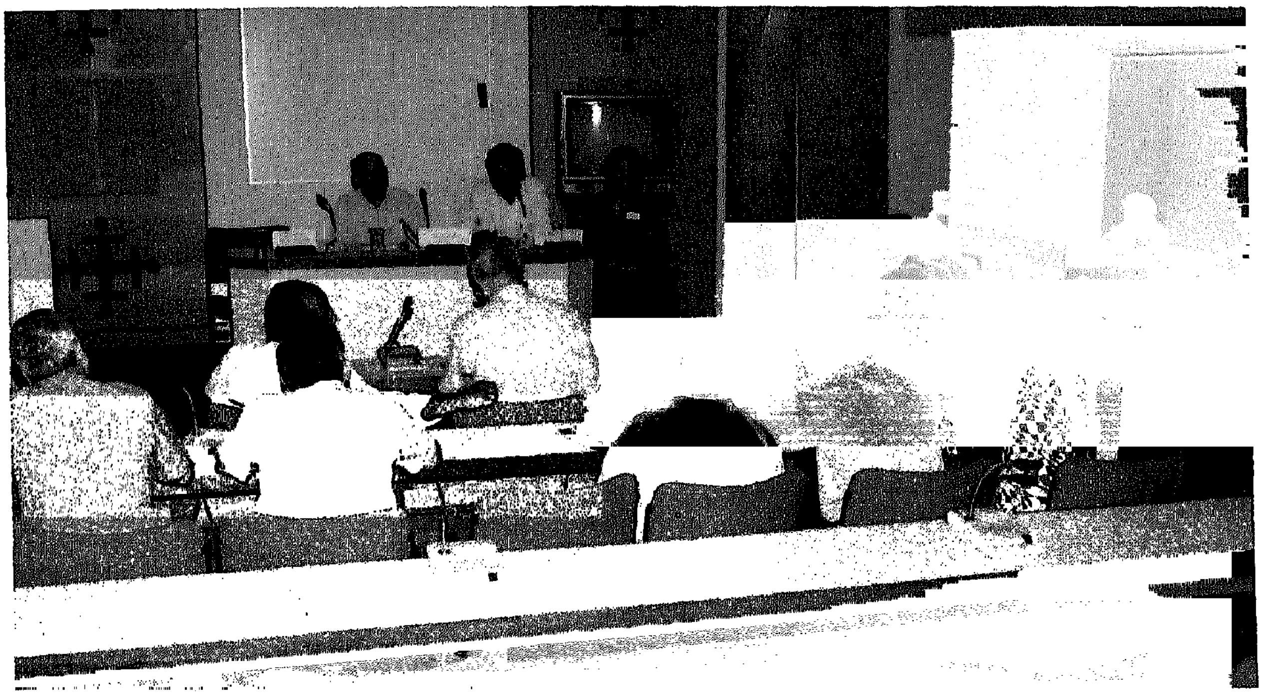
इसके अतिरिक्त, इन संस्थानों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों के संबंध में सूचना के साथ-साथ अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर भी सूचना एकत्र की गई। इस सूचना का विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया गया।

अल्पसंख्यकों (मुस्लिमों) के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त शैक्षिक लाभ

शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास पर आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अल्पसंख्यक (मुस्लिम) किस हद तक लाभान्वित हुए, इसका आकलन करने के लिए एक नमूना सर्वेक्षण किया गया। तीन राज्यों और शैक्षिक प्रबंधकों, अध्यापकों और विद्यार्थियों से सूचना एकत्र करने के लिए चार साधनों को तैयार किया गया। समुदाय सदस्यों से सूचना और विचार एकत्र करने के लिए एक लघु साक्षात्कार-सारणी भी तैयार की गई। विस्तृत सूचना को एक कार्यशाला में अन्तिम रूप दिया गया जिसमें अल्पसंख्यकों, अनुसंधान कार्यप्रणाली और व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों ने भाग लिया। तीन राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से ध्यानपूर्वक प्राप्त किए गए प्रतिनिधि नमूनों की पहचान की गई और उन्हें वर्तमान अध्ययन में शामिल किया जाएगा। इस अध्ययन की उपलब्धियाँ संभवत: अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अधिकार देने के लिए विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की उपयोगिता की जानकारी प्रदान कर सकती हैं।

विस्तार

एन.सी.ई.आर.टी. उत्तर प्रदेश और बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए चलाए गए संगठनों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान भी करती है और डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन और विज्ञान की पुस्तकें तथा विज्ञान किट प्रदान करके मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सुझाव मांगती है।



मदरसों के आधुनिकीकरण पर आयोजित कार्यशाला।

राज्यों और स्वयंसेवी अभिकरणों में संसाधन विकास

2-3 फरवरी, 2000 को एक दो-दिवसीय कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागी राज्य शै.अ. और प्र. परिषदों को वर्ष 2000-2001 में लिए गए कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने में सहायता दी गई। राज्य शै.अ. और प्र.प. के संकाय सदस्यों में क्षमता निर्माण के लिए समसामयिक मुद्दों पर आधारित दो परियोजना लेखों के प्रस्तुतीकरण और प्रतिभागियों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की गई। राज्य स्तर पर कार्यरत इन संगठनों द्वारा लिए गए इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित वर्ष के दौरान अकादमिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मदरसों का आधुनिकीकरण

एन.सी.ई.आर.टी. ने राज्यों में स्थित विभिन्न मदरसों के बोर्ड के आधुनिकीकरण हेतु सुझाव आमन्त्रित करने और परियोजना के लिए उन्हें मार्गदर्शन तथा विज्ञान पुस्तकें और विज्ञान किट प्रदान करने के लिए 22-23 जून को एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया।

अनु.जा./अनु.ज.जा. और अल्पसंख्यकों में क्षेत्रीय सहायता

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर द्वारा 'अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डेवलपमेन्ट डिसएबिलिटीज़-ए मल्टीडिसिप्लिनरी एप्रोच' पर एक कार्यगोष्ठी आयोजित की गई। क्षे.शि.सं., भुवनेश्वर ने उड़ीसा के आदिवासी बच्चों के विज्ञान सीखने पर मनोसामाजिक घटकों की पहचान की। आदिवासी प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्यचर्या आदान-प्रदान से संबंधित समस्याओं का हल निकालने के लिए कार्यप्रणालियाँ विकसित की गईं और आदिवासी हाई स्कूलों के अध्यापकों का अंग्रेज़ी भाषा शिक्षा और विज्ञान में अभिविन्यास किया।

7 विकलांग बच्चों की शिक्षा

यूनेस्को की सहायता से एन.सी.ई.आर.टी. में भारत सरकार के तत्वावधान में 'विशेष आवश्यकताओं की शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र' स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस केंद्र का मुख्य ध्येय होगा– भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक समावेशित व्यवस्था में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों तक शिक्षा के अधिक से अधिक अवसरों को पहुंचाना। इसके लक्ष्यों, दृष्टिकोण, उद्देश्यों और कार्रवाई योजना पर दस्तावेज़ विकसित किया गया है जो आगामी कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश प्रदान करेगा।

एन.सी.ई.आर.टी.

एनसी ई आर टी शारीरिक और बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं: क्षमता विकास, विशेष समूहों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा की सुलभता में सुधार और इस क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और दूसरे संस्थानों में नेटवर्क का विकास। एन.सी.ई.आर.टी. ने 'विकलांगता अधिनियम 1995' के कार्यान्वयन के लिए प्रयास किया और नियमित विद्यालयों में विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम आरंभ किए। इस क्षेत्र में 1999-2000 के दौरान आयोजित कार्यक्रमों और गतिविधियों के मुख्य बिन्दु नीचे दिए गए हैं:

अनुसंधान

'विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा' योजना का मूल्यांकन

1974 में केंद्र प्रायोजित एक योजना के तहत सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आई.ई.डी.सी.) आरंभ की गई। इस योजना को प्रत्येक पाँच वर्षों में संशोधित किया जाता है। आई.ई.डी.सी. योजना का मूल्यांकन-अध्ययन विकलांग बच्चों की शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा के प्रभाव के अध्ययन का प्रयास है। क्षेत्र अन्वेषकों के लिए अनुसंधान साधनों (टूल्स) के प्रयोगार्थ प्रशिक्षण देने हेतु दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन अनुसंधान साधनों को अध्ययन के अन्तर्गत राज्यों के आई.ई.डी.सी. प्रकोष्ठ में अध्यापकों, अभिभावकों, बच्चों और कार्यरत व्यक्तियों के लिए नमूने के रूप में पहले विकसित किया गया था। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं और इनका विश्लेषण किया जा रहा है।

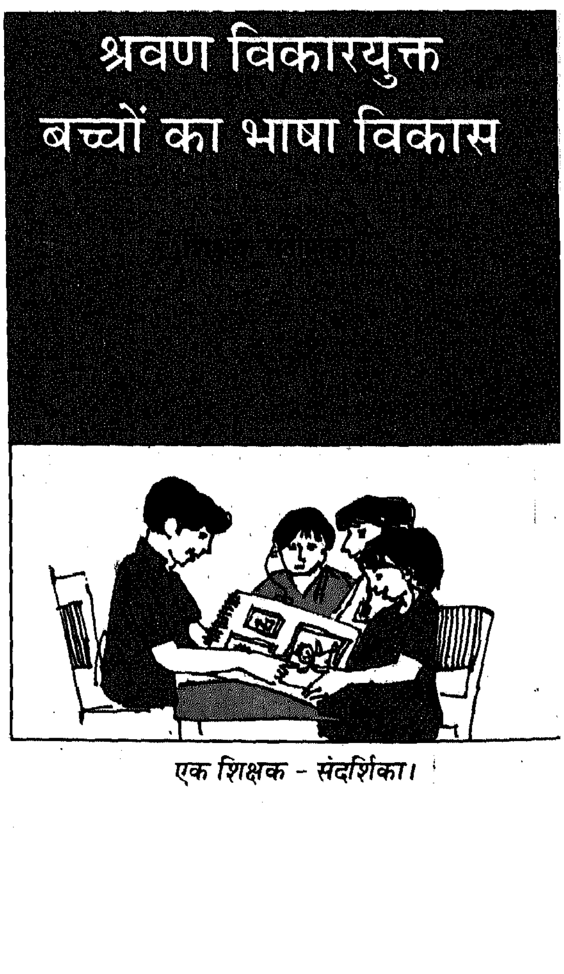
विकास

श्रवण विकारयुक्त बच्चों का भाषा विकास : एक अध्यापक पुस्तिका

यह पुस्तिका पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर श्रवण विकारयुक्त बच्चों को शिक्षण देने वाले अध्यापकों के लिए बनाई गई। इस पुस्तिका में श्रवण विकारयुक्त बच्चों के कक्षा-1 में प्रवेश से पूर्व 'विद्यालय-पूर्व प्रारंभिक पाठ्यचर्या', दी गई है। अध्यापकों को मंद श्रवण विकारयुक्त बच्चों, अत्यधिक विकारयुक्त बच्चों, जिन्होंने 3-4 वर्ष के व्यवधान के बाद नियमित विद्यालयों में प्रवेश किया है और जिनके विद्यालय आने से पहले व्यवधान नहीं पड़ा है, की भाषा के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। कक्षा 1 और 2 में भाषा शिक्षण में अनुकूलन और समायोजन पर शिक्षण कार्यप्रणालियों और मूल्यांकन प्रक्रिया आदि पर चर्चा भी की गई।

श्रवण विकारयुक्त बच्चों के लिए हिंदी भाषा पाठ्यचर्या

प्राथमिक स्तर पर एकीकृत व्यवस्था में श्रवण विकारयुक्त बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंदी भाषा पाठ्यचर्या में अनुकूलन और समायोजन इस उद्देश्य से किया गया ताकि श्रवण विकारयुक्त बच्चों को एकीकृत विद्यालयों में हिंदी भाषा को ग्रहण करने योग्य बनाया जाए। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षण कार्यप्रणालियों का संशोधन करके कक्षा 3, 4 और 5 में श्रवण विकारयुक्त बच्चों के लिए हिंदी में न्यूनतम सक्षमता स्तर की पहचान करना है। कक्षा 3, 4, 5 में श्रवण विकारयुक्त



एक शिक्षक - संदर्शिका।

बच्चों की उपलब्धियों के स्तर के संबंध में एकत्र आकड़ों पर चर्चा करने के लिए तीन कार्यशालाएं क्रमशः इन कक्षाओं के लिए आयोजित की गईं। अध्यापकों की कठिनाइयों पर भी चर्चा की गई। इन कक्षाओं में हिंदी शिक्षण में न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल.) को अनुकूल बनाया गया और पाठ्यचर्या शिक्षण कार्यप्रणालियों में अनुकूलन और समायोजन के लिए दिशानिर्देश का प्रारूप बनाया गया तथा नमूना अध्यापन-अधिगम सामग्री तैयार की गई।

कमज़ोर दृष्टि वाले बच्चे : प्राथमिक-विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक संदर्शिका

अंग्रेज़ी में पूर्व प्रकाशित इस संदर्शिका ने अध्यापकों को कमज़ोर दृष्टि वाले बच्चों की आवश्यकताओं और उपलब्ध सेवाओं के साथ काम चलाने के लिए अभिमुख किया। यह अध्यापकों को पढ़ने, लिखने, सुनने, मनो-सामाजिक विकास क्षेत्र आदि पर कमज़ोर दृष्टि वाले बच्चों के प्रभाव को समझने में मदद करती है। यह संदर्शिका कमज़ोर दृष्टि वाले बच्चों की उपलब्धि को बढ़ाने के अन्तिम लक्ष्य के साथ-साथ उनकी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार करने में सहयोग प्रदान करेगी। इसका हिंदी रूपान्तर मुद्रणाधीन है।

एकीकृत व्यवस्था में प्राथमिक विद्यालय के दृष्टिहीन बच्चों के लिए गणित पाठ्यचर्या पढ़ाने के लिए पुस्तिका

इस परियोजना के अन्तर्गत उन क्षेत्रों की पहचान की गई जिन्हें दृष्टिहीन बच्चों के लिए गणित पाठ्यचर्या में अनुकूलन/संशोधन की आवश्यकता है। यह पुस्तिका पहचाने गए क्षेत्रों के साथ-साथ उपयुक्त अनुदेशी पद्धतियों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसे कार्यशाला के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। इस पुस्तिका में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए दिशानिर्देश होंगे कि दृष्टिहीन बच्चों को अन्य बच्चों के साथ एकीकृत करके एक अंतर्विष्ट कक्षा में कैसे पढ़ाया जा सकता है।

प्रशिक्षण

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की एकीकृत शिक्षा पर भारत-आस्ट्रेलिया क्षमता निर्माण कार्यक्रम

भारत-आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तत्वावधान में एन.सी.ई.आर.टी. ने 19-21 मई, 1999 को उत्तरी क्षेत्र में स्थित राज्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला इस दृष्टि से आयोजित की कि इन राज्यों में ऐसे संसाधन व्यक्ति तैयार किए जाएं जो अंतर्विष्ट शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार कर सकें। कार्यशाला में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, गुजरात और केरल के नामितों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में शामिल संसाधन व्यक्ति एन.सी.ई.आर. टी. संकाय, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया के संकाय सदस्य और वे संसाधन अध्यापक थे जिन्हें उन्होंने इस प्रयोजन के लिए विशेष रूपरेखा तैयार करके छह-सप्ताह के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले प्रशिक्षित किया था।

विस्तार

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का पुनरीक्षण

विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना की एक पुनरीक्षण कार्यशाला, समाज की बदलती आवश्यकताओं और स्थिति के अनुसार योजना बनाने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. के तत्वावधान में मा.सं.वि.मं. द्वारा आयोजित की गई। इस योजना को 1974 से आरम्भ किया गया और प्रत्येक पांच वर्ष में इसका पुनरीक्षण किया गया। राज्यों के सचिवों, एस.सी.ई.आर.टीज़. के निदेशकों और राज्य शिक्षा संस्थानों, आई.ई.डी. समन्वयकों और गैर-सरकारी संगठनों, जिन्हें समावेश और एकीकरण का सफल अभ्यास है, ने अपने अनुभवों को साझा किया और 'पी.डब्ल्यू. अधिनियम 1995' के अनुकूल बाधाओं और समाधानों की पहचान की। राज्यों ने योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं को बताया और बाधाओं को दूर करने के लिए दिए गए सुझावों को अंतिम संस्तुतियों के लिए एकत्र किया जिन्हें क्षमता निर्माण के मुख्य विषयों और सेवा प्रदान करने और प्रशासनिक मुद्दों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रभावशाली योजना को विकसित करने में योगदान मिलेगा।

समावेशित शिक्षा पर कार्यशाला

यूनेस्को के सहयोग से एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व वचनबद्धताओं का समर्थन करने और आगे वास्तविक कार्यान्वयन हेतु देश की एक राजनीतिक इच्छाशक्ति को रूपान्तरित करने में सहायता करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मुक्त शिक्षा और जहां तक सम्भव हो सामान्य विद्यालयों में एकीकरण को सुलभ बनाने के लिए परिवर्तन के साथ-साथ लोगों को प्रत्येक बच्चे के अधिकार के संबंध में जानकारी देना है। इस कार्यशाला में आई.ई.डी. समन्वयकों और सामान्य विद्यालय में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का शिक्षा-पोषण करने वाले गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया। इसमें संकल्पनात्मक मुद्दे, शिक्षा की सुलभता, बाधाएं और कठिनाइयां, शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय व व्यवस्था से संबंधित सरोकार, पद्धति और क्षमता-निर्माण, नीतिगत योजना और प्रशासन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। शिक्षा को उन्नत करने के लिए समावेशित शिक्षा पद्धति के लिए कार्यप्रणालियां और दिशानिर्देश बनाए गए। इससे प्रतिभागियों को अपने संस्थानों और राज्यों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों को कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई योजना की अभिकल्पना करने और कार्यान्वियन में मदद मिली।

अध्यापन-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) पर प्रदर्शनी एवं कार्यशाला

एन.सी.ई.आर.टी. के तत्वावधान में आर.सी.आई. द्वारा एक प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का आयोजन अध्यापकों को अध्यापन-अधिगम सामग्री की पहचान कराने और उन्हें अच्छे साधनों, जिन्हें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों पर प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सके, के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया। इस प्रदर्शनी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा में कार्यरत विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिभागियों को उनके द्वारा बनाई गई सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए आमन्त्रित किया गया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपने दीर्घकालीन अनुभवों पर भी विचार-विमर्श किया। बच्चों का ध्यान केन्द्रित करने, बच्चों की समस्याओं को हल करने, सभी क्षेत्रों में उनके विकास को प्रेरित करने, कौशलों की प्राप्ति और स्वत: अनुवीक्षण के लिए बच्चों का उत्साह बढ़ा सकने वाली नवाचारी सामग्री के विकास के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए।

कार्यशाला के उपरान्त विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा अपनाई जा सकने वाली पत्रिकाओं की पहचान की गई। नवाचारी अध्यापकों के लिए उनकी रुचि को बढ़ाने और शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए। प्रतिभागी संस्थानों में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री की पहचान की गई।

राज्यों और स्वयंसेवी अभिकरणों को संसाधन सहायता

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए राज्यों और स्वयंसेवी संस्थानों हेतु संसाधन सहायता निर्मित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। बिहार, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, गंगटोक, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर के प्रतिभागियों ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा के कार्यक्रम के निष्पादन, उपलब्धियों और कार्यान्वियन की समस्याओं को प्रस्तुत किया। इस कार्यशाला ने विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा में कार्यरत विभिन्न एस.सी.ई.आर.टीज़./एस.आई.ईज़. और स्वयंसेवी संगठनों में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया। सत्र आई.ई.डी. समन्वयकों को ज़िला/ब्लाक/समूह स्तर पर विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा के कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें नियोजन, आयोजन, प्रबन्धन और अनुवीक्षण में सक्षम बनाने हेतु आयोजित किया गया।

विशेष आवश्यकताओं की शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

यूनेस्को की सहायता से एन.सी.ई.आर.टी. में भारत सरकार के तत्वावधान में 'विशेष आवश्यकताओं की शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केंद्र' स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस केंद्र का मुख्य ध्येय होगा – भारत और एशिया प्रशान्त क्षेत्र में एक समावेशित व्यवस्था में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों तक शिक्षा

के अधिक से अधिक अवसरों को पहुंचाना है। यह केंद्र औपचारिक तथा अनौपचारिक विद्यालयों और शिक्षण के अन्य वैकल्पिक रूपों को जिन्हें नवाचारी, प्रायोगिक और क्रियात्मक अनुसंधान सूचित कर सकेगा तथा क्षमता-निर्माण एवं सहायता देकर सभी बच्चों के लिए गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। केंद्र, क्षेत्र में एकीकरण और परस्पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। यह समावेशित शिक्षा के क्षेत्र में कार्य को सुलभ बनाने के लिए प्रबन्धन सूचना व्यवस्था (एम.आई.एस.) भी विकसित करेगा। यह सदस्य देशों और अन्य देशों को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता के सुधार के लिए परामर्श प्रदान करेगा। इसके लक्ष्यों, दृष्टिकोण, उद्देश्यों और कार्रवाई योजना पर दस्तावेज़ विकसित किया गया है जो आगामी कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश प्रदान करेगा।

परामर्श

सार्क क्षेत्र के राज्य-विभागों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों, विद्यालयों और व्यक्तियों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण कार्यनीतियों की आवश्यकताओं और विकास के संबंध में परामर्श प्रदान किया गया। विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अनुदेशी प्रणालियों के नियोजन और प्रबन्धन के लिए अध्यापक-सहायता प्रदान की गई।

विकलांग बच्चों के लिए क्षेत्रीय निवेश

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने आई.ई.डी.सी. के क्षेत्र में राज्यों के एस.सी.ई.आर.टीज़. और एस.आई.ईज़. को मज़बूत बनाने के लिए विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए एक पाँच-दिवसीय शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया और डी.आई.ई.टीज़. के अध्यापक-प्रशिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण पैकेज भी विकसित किया।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर ने मामूली विकलांग बच्चों की शैक्षिक बाधाओं की पहचान और उनके निदान के लिए एक कार्यनीति विकसित की। आई.ई.डी.सी. में राज्य स्तरीय संसाधन व्यक्तियों का अभिविन्यास किया गया

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर ने 'अर्ली आइडेन्टीफिकेशन एण्ड इन्टरवेन्शन ऑफ डेवलपमेन्ट डिसएबिलिटीज़-ए मल्टीडिसिप्लीनरी एप्रोच' पर एक कार्यशाला आयोजित की।

1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- समावेशित शिक्षा पर यूनेस्को-एन.सी.ई.आर.टी. कार्यशाला रिपोर्ट (फोटोप्रति)
- श्रवण विकारयुक्त बच्चों का भाषा विकास।

एन सी ई आर टी नीति निर्माण, पाठ्यचर्या संपादन और अध्यापक शिक्षा के माध्यम से बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके कार्यक्षेत्र में एक समर्थ आंकड़ा आधार, लैंगिक भेदभाव को दूर करके पाठ्यचर्याओं की पुनर्संरचना, सभी शैक्षिक कार्मिकों का लैंगिक सुग्राहीकरण, अध्यापक और अध्यापक-प्रशिक्षकों हेतु पुस्तिका विकास, पीढ़ी जागरूकता, बालिका शिक्षा और विकास का समर्थन, अभिभावकों और समुदायों में अभिवृत्तिक परिवर्तन और इन सबसे ऊपर विद्यालयों में बालिकाओं के प्रति मैत्रीपूर्ण वातावरण शामिल हैं।

एन सी ई आर टी

एन सी ई आर टी नीति निर्माण, पाठ्यचर्या संपादन और अध्यापक शिक्षा के माध्यम से बालिका शिक्षा और महिला सशक्तीकरण की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके कार्यक्षेत्र में एक समर्थ आंकड़ा आधार, लैंगिक भेदभाव को दूर करके पाठ्यचर्याओं की पुनर्संरचना, सभी शैक्षिक कार्मिकों का लैंगिक सुग्राहीकरण, अध्यापक और अध्यापक-प्रशिक्षकों हेतु पुस्तिका विकास, पीढ़ी जागरूकता, बालिका शिक्षा और विकास का समर्थन, अभिभावकों और समुदायों में अभिवृत्तिक परिवर्तन और इन सबसे ऊपर विद्यालयों में बालिकाओं के प्रति मैत्रीपूर्ण वातावरण शामिल हैं। इस क्षेत्र में 1999-2000 के दौरान आयोजित कार्यक्रम और कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

अनुसंधान

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्राओं के लिए आवास और छात्रावास की सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की केंद्रीय योजना का मूल्यांकन

इस अध्ययन में 12 राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित 50 छात्रावासों को सम्मिलित किया गया। यह अध्ययन मूलत: गुणवत्ता पर आधारित है और इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत साक्षात्कार सूचियों, एक प्रेक्षण जाँच-सूची और छात्रावास सहवासियों के साथ परस्पर व्यक्तिगत बातचीत और चर्चा के द्वारा छात्रावास सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया। इस मूल्यांकन को प्रभावकारी बनाने के लिए योजना आगतों, प्रक्रियाओं और परिणामों की पहचान और विश्लेषण करते समय स्थिति, विद्यार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि के प्रासंगिक घटकों का अध्ययन किया गया।

यह जानकर संतोष हुआ कि कुछ अपेक्षाओं के साथ छात्रावास ग्रामीण और दूरगामी क्षेत्रों तथा अन्य सुविधाहीन वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित बालिकाओं को लाभ पहुँचा रहे थे। योजना में बालिका नामांकन, प्रतिधारण और संप्राप्ति, प्रतिरूप, आत्मविश्वास, नेतृत्व योग्यता और संप्रेषण कुशलता वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया। यह योजना माध्यमिकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब समूहों और पिछड़े समुदायों के अभिभावकों को प्रेरित करने और बालिकाओं को आकर्षित करने में लाभदायक है। छात्रावास सहवासियों की शैक्षिक और व्यावसायिक महत्वाकांक्षाएं उच्च थीं। प्रबंधकगणों, वार्डन और बालिका छात्रावासियों की लैंगिक भूमिका परिप्रेक्ष्य बहुत समतावादी पाया गया।

प्राथमिक विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण पर प्रोत्साहन के प्रभाव का मूल्यांकन

यह अध्ययन मध्य प्रदेश के दो विकास खंडों-अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रधान धार ज़िले के धार खंड और अनुसूचित जाति जनसंख्या केंद्रिक राजगढ़ ज़िले के राजगढ़ खंड में किया गया। इस अध्ययन की मुख्य उपलब्धि यह है कि प्रोत्साहनों का नामांकन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है किन्तु इसका सकारात्मक प्रभाव उपस्थिति और संप्राप्ति पर नहीं है। दोनों चुने गए विकास खंडों में यूनिफार्म और पाठ्यपुस्तकें पर्याप्त मात्रा में नहीं पाई गईं। सिले-सिलाए यूनिफार्म और पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति घटिया किस्म की थी। अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि वितरित माल की गुणवत्ता में सुधार करने की गुंजाइश है और जहाँ तक पाठ्यपुस्तकों और लेखन सामग्री का संबंध है, उन्हें व्यापक रूप से सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

दूरस्थ क्षेत्रों, द्वीप-समूहों, रेगिस्तानों, पर्वतीय क्षेत्रों और वन क्षेत्रों में बालिका शिक्षा, बालिका शिक्षा को उन्नत करने में भोपाल की बेगमों की भूमिका, बालिकाओं की खेलों और शारीरिक शिक्षा की अवस्थिति और दिल्ली के विद्यालयों में लैंगिक परिप्रेक्ष्य से विद्यालय पद्धतियाँ आदि अध्ययन प्रगति पर हैं।

प्रशिक्षण

'महिला शिक्षा की प्रणाली और विकास' पर छह-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेष वार्षिक गतिविधि है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की कार्यप्रणाली उच्च सहभागिता और अन्योन्यक्रिया पर आधारित है। इसमें सभी प्रतिभागियों से एक स्थिति-लेख लाना अपेक्षित है जिसकी रूपरेखा पहले दी जाती है। आगे वे संकाय पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करते हैं और उनकी अवस्थिति रिपोर्ट संवर्धित और अलंकृत करके एन.सी.ई.आर.टी. और नीपा और अन्य संसाधन केंद्रों में प्रयोग की जाती है। महिला शिक्षा पर विकास कार्यप्रणाली पर नौवां प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 10 जनवरी से

20 फरवरी तक आयोजित किया गया जिसमें 12 राज्यों से 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में राज्य शिक्षा विभाग, एस.सी.ई.आर.टीज़., एस.आई.ईज़., डी.आई.ई.टीज़., विश्वविद्यालय और एन.सी.ई.आर.टी. के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आई.ईज़.) सम्मिलित हुए।

पाठ्यक्रम की संरचना और शीर्षकों की विस्तृत रूपरेखा और विषयवस्तु को विस्तारपूर्वक बताने के लिए एक प्रशिक्षण संदर्शिका तैयार की गई। यह कार्यक्रम शीर्ष स्तर के कार्मिकों को महिला शिक्षा और विकास की कार्यप्रणाली में प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु तैयार करने के लिए बनाया गया। इस कार्यक्रम में उन्हें इन विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया : (क) महिला अध्ययनों और अन्य सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्यों के ज़रिए महिलाओं से संबंधित विषयों की समझ (ख) तुलनात्मक परिप्रेक्ष्यों में महिलाओं की शिक्षा और अवस्थिति की जानकारी (ग) बालिका शिक्षा और विकास के मनो-सामाजिक आयामों की समझ, एकत्रीकरण के कौशल, आँकड़ों की जाँच और विश्लेषण तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्रवाई परियोजनाओं का निरूपण।

विस्तार

बालिका और सह शिक्षा पर उपलब्ध अद्यतन आंकड़े सामाजिक और जनसांख्यिकी संकेतकों को मिलाकर विश्लेषित किए गए और बालिका शिक्षा पर एक तथ्य लेख (एक ग्राफिक प्रस्तुतीकरण) प्रकाशित किया गया। 'सबके लिए शिक्षा' की रूपरेखा में जोमटियन अवधि के उपरान्त प्रगति की समीक्षा के क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बालिका शिक्षा पर एक अनुसंधान आधारित पेपर प्रस्तुत किया गया। नीपा में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा बैठक में एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसंधान विकास, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यकलापों के माध्यम से महिला समानता के लिए शिक्षा पर कृतसंकल्प एन.पी.ई. के कार्यान्वयन में वास्तविक भूमिका पर प्रस्तुतीकरण किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग और महिला और बाल विकास विभाग द्वारा राज्यों को संसाधन सहायता प्रदान की गई।

बालिका शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय निवेश

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने मध्य प्रदेश में 'शैक्षिक प्रक्रियाओं में लैंगिक भेदभाव को दूर करने की कार्यपद्धतियों का विकास' पर एक चार-दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति भेदभाव और उन्हें अधिकारवंचित करने के मुख्य कारणों की पहचान की गई और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए।

1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- इवेल्यूएशन स्कीम फॉर स्ट्रेंग्थनिंग ऑफ बोर्डिंग एण्ड होस्टल फेसिलिटीज़ फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ सेकेण्डरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स (फोटोप्रति)
- शिक्षा लहर, यूनेस्को इन्नोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट ऑन प्रोमोशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स इन रूरल हरियाणा (1992-98)
- एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया-ए फेक्टशीट
- ट्वन्टी फाइव इयर्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन एट दि एन.सी.ई.आर.टी. (1974-1999) (फोटो प्रति)
- एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया : एन असेसमेंट (मुद्रणाधीन)
- बालिका शिक्षा में ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग एक दिशा (फोटोप्रति)
- नाइन्थ ट्रेनिंग कोर्स ऑन मैथडोलोजी ऑफ वुमेन्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (जनवरी 10 से 20 फरवरी 2000)

1. इन्फोरमेशन ब्रॉशर (फोटोप्रति)
2. रिसोर्स मैनुअल (फोटोप्रति)
3. रिपोर्ट (फोटोप्रति)।

१ विज्ञान और गणित शिक्षा

एन सी ई आर टी अपने अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और विस्तार संबंधी कार्यकलापों के द्वारा विज्ञान और गणित की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर और पोषणीय प्रयास कर रही है। इसके विकासात्मक मुख्य कार्यकलापों में छात्रों और अध्यापकों के लिए गणित और विज्ञान शिक्षा में आदर्श पाठ्यचर्या सामग्री, विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों के लिए विज्ञान व गणित में पाठ्यचर्या और गणित व विज्ञान के विभिन्न विषयों में मूल पाठ्यसामग्री और अनुदेशी सामग्री का विकास करना समाहित है।

एन सी ई आर टी अपने अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और विस्तार संबंधी कार्यकलापों के द्वारा विज्ञान और गणित की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर और पोषणीय प्रयास कर रही है। इस क्षेत्र में विकास के प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं- (1) छात्रों और अध्यापकों के लिए गणित और विज्ञान शिक्षा में आदर्श पाठ्यचर्या सामग्री का विकास करना, (2) विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों के लिए विज्ञान और गणित में पाठ्यचर्या का विकास करना और (3) गणित और विज्ञान के विभिन्न विषयों में मूल पाठ्यसामग्री और अनुदेशी सामग्री का विकास करना। समस्त पाठ्यचर्या में पर्यावरण शिक्षा के तत्व शामिल किए जाते हैं।

नई विधियों और प्रौद्योगिकी के साथ अध्यापन अधिगम की कार्यनीतियों के प्रयोग संचालित किए जाते हैं। विज्ञान और गणित की संकल्पनाओं के प्रभावी अध्यापन अधिगम के लिए कार्यकलाप उन्मुख तीन विमितीय (थ्री डाईमेंशनल मॉडलों) और प्रयोगशाला कौशलों की रूपरेखा बनाई जाती है और उनका विकास किया जाता है। प्रतिभाशाली छात्रों के प्रतिभा पोषण के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाते हैं। प्रतिभा पोषण कार्यक्रमों के संचालन के लिए विभिन्न विषयों में विकसित अध्ययन संदर्शिकाओं और चुनौतीपूर्ण समस्याओं का प्रयोग किया जा रहा है। मंदगति के विद्यार्थियों के लिए निदानात्मक परीक्षण और उपचारी सामग्री विकसित की जाती है। गणित और विज्ञान शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों में शामिल हैं – रुचिकर पठन सामग्री, पूरक पुस्तकों के विकास द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाना, विद्यालयेत्तर गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए विज्ञान प्रदर्शनी और त्रैमासिक पत्रिका 'स्कूल साइंस' के ज़रिए वैज्ञानिक नवाचारों की संकल्पनाओं आदि का प्रचार-प्रसार करना। विभिन्न स्तरों के संसाधन व्यक्तियों को इस क्षेत्र के नए और नवाचारी विकास के बारे में सरल और सुबोध तरीके से अभिमुख किया जाता है। 1999-2000 में इस क्षेत्र में किए गए कार्यक्रमों और कार्यकलापों का महत्वपूर्ण विवरण इस प्रकार है:

अनुसंधान

विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या का नवीकरण

विद्यालयी शिक्षा के समग्र ढाँचे की प्रासंगिकता की दृष्टि से एन.सी.ई.आर.टी. ने पाठ्यचर्या नवीकरण के कार्य को वरीयता दी। प्रश्नावली, विद्यार्थियों और अध्यापकों के वैयक्तिक संपर्क, कक्षा शिक्षण के माध्यम से पाठ्यचर्या के विभिन्न पक्षों पर विद्यालय-प्रणाली (अध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षकों और प्रशासकों) से फीडबैक इकट्ठा किया गया। फीडबैक पर अन्तिम निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए वर्तमान में प्रश्नावलियों का विश्लेषण किया जा रहा है।

भारत में विज्ञान शिक्षा की स्थिति

अध्ययन के प्रथम चरण में विद्यालयी ढाँचा, विज्ञान प्रयोगशाला, अध्यापक की योग्यता, सेवाकालीन प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तकें और अन्य पाठ्यचर्यात्मक सामग्री जैसी विज्ञान शिक्षण की सुविधाओं के साथ भारत विज्ञान शिक्षा के कार्यालयी स्तर का मूल्यांकन किया गया। इसने विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रमों की तुलना भी प्रदान की।

अध्ययन के दूसरे चरण में इकाइयों की संकल्पना आलोचनात्मक सोच का विकास, प्रक्रिया कौशल का विकास और विज्ञान की सामाजिक प्रासंगिकता की प्राप्ति आदि को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न राज्यों के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की विज्ञान पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन किया गया। यह पाया गया कि सभी पुस्तकों में 80 प्रतिशत से अधिक बल केवल ज्ञान पर ही दिया गया।

विकास

विज्ञान और गणित में मूल्यांकन सामग्री

शिक्षकों को पाठ्यपुस्तक की हर इकाई में विद्यार्थियों की संप्राप्ति का मूल्यांकन करने योग्य बनाने के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की कक्षाओं की जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के लिए परीक्षण-सामग्री का विकास किया गया। ये सामग्री विद्यार्थियों के आत्म-मूल्यांकन, उनकी उपलब्धियों में सुधार और समस्या समाधान की योग्यता में भी सहायक होंगी।

सभी तरह की समस्याओं को समाहित करते हुए +2 स्तर पर कक्षा ग्यारह के लिए गणित में एक निर्मेय-पुस्तक विकसित की गई। इस निर्मेय-पुस्तक में विस्तृत और लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी हैं जो कि पाठ्यपुस्तकों में नहीं हैं। इसमें चुनौतीपूर्ण प्रश्न भी हैं जिन्हें हल करने के लिए मेधावी विद्यार्थी अभ्यास कर सकते हैं।

रसायन विज्ञान की अवधारणाओं के विकास के लिए मॉड्यूलों का विकास

एन.सी.ई.आर.टी. वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मेधावी छात्रों और अध्यापकों के लिए रसायन विज्ञान के उन क्षेत्रों में, मॉड्यूल संसाधन सामग्री विकसित कर रही है जो या तो अमूर्त और कठिन है, या अवधारणागत/विषयगत रूप में मेधावी छात्रों के लिए बोधगम्य नहीं है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन मॉड्यूल पहले ही विकसित किए जा चुके हैं और इस वर्ष 'मोल कॉन्सेप्ट एण्ड केमिकल स्टोइकियोमेट्री', 'केमिकल काइनेटिक्स', 'केमिकल थर्मोडाइनामिक्स' तथा 'सम बेसिक कान्सेप्ट्स इन इनआर्गेनिक केमिस्ट्री' पर चार मॉड्यूल विकसित किए गए। इन माड्यूलों में न केवल रासायनिक अवधारणाओं को ही व्यापक रूप से शामिल किया गया है बल्कि इन क्षेत्रों में अधिगम अध्यापन में उचित उपागम और अद्यतन प्रवृत्तियाँ भी दी गई हैं। इन माड्यूलों में आवश्यकतानुसार प्रासंगिक प्रश्न भी दिए गए हैं। एक अन्य कार्यक्रम 'सम इन्टरेस्टिंग टॉपिक्स इन केमेस्ट्री' में पर्यावरण से संबंधित कुछ मॉड्यल पहले से ही विकसित हैं और इस वर्ष इस शृंखला में 'एलॉय' पर एक माड्यूल शामिल किया गया।

विज्ञान और गणित को लोकप्रिय बनाना

एन.सी.ई.आर.टी. ने अपनी परियोजना 'पढ़ें और सीखें' के अंतर्गत विज्ञान और गणित के नए और व्यावहारिक क्षेत्रों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए विज्ञान में 35 से अधिक पुस्तकों का विकास किया। इनमें से अधिकतर पुस्तकें देश के नामी वैज्ञानिकों के सहयोग से मूलरूप से हिंदी में लिखी गई हैं। 1999-2000 के दौरान ये तीन पुस्तकें मुद्रित हुईं-

(1) हमारा अद्भुत वायुमंडल अब मैला क्यों?

(2) सौर ऊर्जा

(3) मौसम-क्या, क्यों और कैसा?

बालू बोले अपनी बात और ग्लिम्पसेज़ ऑफ प्लान्ट लाइफ पार्ट-1 और 2 (अंग्रेज़ी) प्रेस में हैं और छह पुस्तकें लिखी जा रही हैं-

(1) साहा एण्ड हिज फार्मूला

(2) रिमोट सेन्सिंग

(3) पेट्रोकेमिकल्स

(4) प्लान्ट्स-ए नेचुरल लैबोरेटरी फॉर सिन्थेसिस ऑफ केमिकल कम्पाउंड्स

(5) अर्थक्वेक्स, और

(6) फिंगर प्रिंटिंग

प्रयोगशाला अभिमुख कार्यक्रम

रसायन विज्ञान में कक्षा ग्यारह और बारह के लिए कार्य पत्रक को अन्तिम रूप दिया गया और ये विद्यालयों में परीक्षण हेतु तैयार हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि ये कार्य पत्रक विद्यार्थियों का अन्वेषण में मार्गदर्शन करेंगे, प्रायोगिक नोटबुक का कार्य करेंगे और प्रायोगिक कार्यकलापों के विविध पक्षों के प्रति समझ के मूल्यांकन में सहायक होंगे।

+2 स्तर पर विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने और उन्हें स्वतंत्र प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए जीवविज्ञान में कार्य पत्रक विकसित किए गए। ये कार्य पत्रक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के मूल्यांकन में भी सहायक होंगे। वर्तमान परिस्थिति में यदि आवश्यक हुआ तो विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और निदानात्मक कार्यक्रमों की व्यवस्था में अध्यापक अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में होगा।

सेमीमाइक्रो तकनीक को अपनाकर विभिन्न नवाचारी अभ्यासों का निर्माण और प्रदर्शन रसायन प्रयोगों में समाहित करने के उद्देश्य से किया गया। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(अ) एस्टीमेटिंग हार्डनेस ऑफ वाटर क्वान्टिटेटिवली

(ब) स्टडी ऑफ फूड एडल्ट्रेशन

इन प्रयोगों को आगे विद्यालयों में प्रयोग किया जाएगा और यदि उपयुक्त पाए गए तो उच्च माध्यमिक स्तर के

रासायनिक प्रयोगों में उन्हें सम्मिलित किया जाएगा।

एन.सी.ई.आर.टी. ने गणित प्रयोगशाला के लिए एक पुस्तिका विकसित की जिसमें उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित गतिविधियाँ निहित हैं। नियम पुस्तिका में शामिल गतिविधियाँ/मॉडल्स विद्यार्थियों को गणित के कठिन और गूढ़ प्रत्ययों को समझने में सहायता करेंगे। एक अध्यापक अपने स्कूल में ऐसे ही मॉडल्स/गतिविधियों का निर्माण और विकास कर सकता है और गणित के अध्यापन में इन गतिविधियों का उपयोग कर सकता है।

प्रशिक्षण

रसायन विज्ञान के स्नातकोत्तर अध्यापकों के लिए सहकारी अधिगम कार्यनीति

रसायन विज्ञान के सेवाकालीन स्नातकोत्तर अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक सहकारी अधिगम कार्यनीति विकसित की गई और सफलतापूर्वक क्रियान्वित की गई। इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल थीं– (1) प्रत्येक मॉड्यूल के लिए निर्धारित कुल समय का 25-35 प्रतिशत का व्याख्यान, (2) स्वाध्याय, (3) समकक्ष-समूहों के साथ विचार-विमर्श, (4) उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं की समस्याओं की रूपरेखा बनाना और (5) अन्ततः दो उप-समूहों में विचार विमर्श। इस कार्यनीति में सहकारिक और प्रतिस्पर्द्धात्मक दोनों स्थितियाँ प्रदान की गईं। अध्यापकों ने स्वाध्याय में सहकारिक और प्रतिस्पर्द्धात्मकता के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया और अन्तिम विचार-विमर्श सत्र में समकक्ष समूहों के साथ विचार-विमर्श किया। सहकारी अधिगम के लिए विकसित मॉड्यूलों को शिक्षकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर परिष्कृत किया गया।

पर्यावरणीय शिक्षा में राज्यों के संसाधन व्यक्तियों का अभिविन्यास

राज्यों के संसाधन व्यक्तियों को पर्यावरणीय शिक्षा के विकास और तरीकों तथा उसकी अवधारणाओं के अन्य विषयों से एकीकरण से अवगत कराने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा में एक पाँच-दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान कुछ क्रियाकलापों का विकास किया।

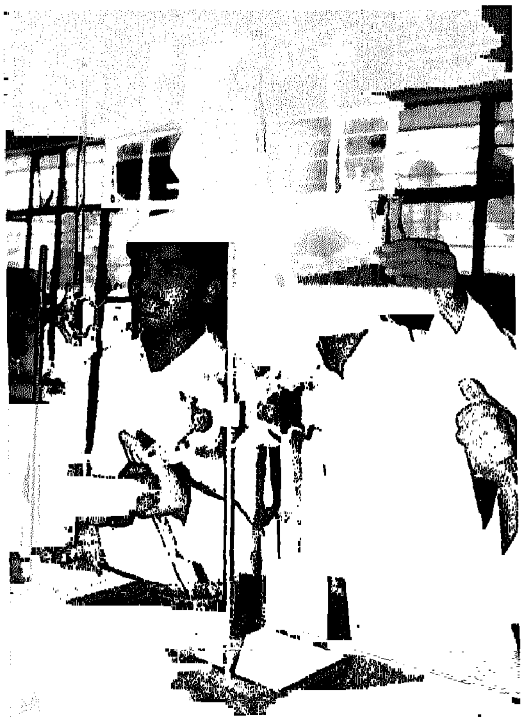
सिक्किम राज्य के गणित अध्यापकों का प्रशिक्षण

सिक्किम राज्य के माध्यमिक शिक्षकों के लिए गंगटोक में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गणित के कठिन और गूढ़ क्षेत्रों की पहचान की गई और अध्यापकों का ध्यान मुख्य रूप से इन्हीं से संबंधित समस्याओं के समाधान पर केंद्रित किया गया। अध्यापकों को माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या पर आधारित गणित के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित संसाधन सामग्री भी प्रदान की गई।

विस्तार

बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी

एन.सी.ई.आर.टी. और गुजरात सरकार के सहयोग से 27 नवंबर से 3 दिसंबर 1999 तक राजकोट (गुजरात) में बच्चों के लिए 26वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 1999 आयोजित की गयी। 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण' प्रदर्शनी की केंद्रीय विषयवस्तु थी। प्रदर्शित वस्तुओं को 6 उपविषयों 'खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य और पौष्टिकता', 'ऊर्जा', 'प्रौद्योगिकी और पर्यावरण', 'उद्योग और पर्यावरण सुरक्षा', 'यातायात और संचार' और 'प्रौद्योगिकीय सामग्री' के समूह में बांटा गया था। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों के प्रदर्श (राज्य स्तर पर चयनित) प्रदर्शनी में सम्मिलित किए गए थे। इस विज्ञान प्रदर्शनी में 67 ग्रामीण विद्यालयों सहित लगभग 160 विद्यालय और 400 अध्यापक तथा छात्र सम्मिलित हुए। गुजरात सरकार के लगभग 40 विद्यालयों (राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए विद्यालयों के अलावा) ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लिया। एन.सी.ई.आर.टी. ने भी अपना स्टॉल लगाया था। प्रदर्शनी के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए फोल्डर (अंग्रेज़ी/हिंदी/गुजराती) छापे गए थे। इनमें विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करने के उद्देश्यों और प्रयोजनों के साथ-साथ प्रदर्शों की सूची भी दी गयी थी। दर्शकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और सहभागियों में मुफ्त वितरण के लिए 'प्रदर्शों की सूची' (अंग्रेज़ी/हिंदी दोनों में) और 'विज्ञान मॉडलों का ढाँचा और कार्यविधि' भी प्रकाशित किए गए।





राजकोट में आयोजित बच्चों के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 1999 में कार्यरत प्रतिभागी विद्यार्थी।

राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियाँ

राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियाँ राज्य और संघीय क्षेत्रों में ज़िला और क्षेत्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन हैं। बच्चों के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता 1999-2000 का केंद्रीय विषय था- 'जीवन की चुनौतियाँ : विज्ञान और प्रौद्योगिकी'। इसी तरह उप-विषय थे- (1) खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य और पोषण, (2) उद्योग, (3) यातायात और संचार, (4) ऊर्जा और (5) पर्यावरण। केंद्रीय विषय और उपविषयों पर मॉडल तैयार करने और उनके मूल्यांकन के मानदंड निर्धारित करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. ने राज्यों को अपेक्षित शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान किया। बच्चों के लिए 27वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 2000 में सहभागिता के निर्धारण हेतु विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त सर्वोत्तम प्रदर्शों के आलेखों की अंतिम छानबीन की गयी। 30 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और परमाणु ऊर्जा विद्यालयों में 1999-2000 के दौरान बच्चों के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनियाँ आयोजित की गईं। इन राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु परिषद् ने रु. 16.60 लाख की सहायता प्रदान की।

विद्यालय विज्ञान पत्रिका

विज्ञान और गणित शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अवगमों, अनुभवों, नवाचारों और शोध निष्कर्षों के प्रचार-प्रसार के लिए अध्यापकों, शोधकर्ताओं, पाठ्यचर्या निर्माताओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी 'स्कूल साइंस' नामक त्रैमासिक पत्रिका एक मंच प्रदान करती है। विज्ञान और गणित शिक्षण में अद्यतन विकास, वस्तुगत समृद्धि और नवाचारी अभ्यासों से संबंधित विविध प्रकार की पठन सामग्रियां इस पत्रिका में समाहित हैं। 'विज्ञान समाचार' और 'पुस्तक समीक्षा' इस पत्रिका का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। पत्रिका के सदस्य के रूप में ख्यात वैज्ञानिकों के एक 'सम्पादकीय सलाहकार समिति' द्वारा पत्रिका के संपूर्ण विकास और वितरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

संसाधन सहायता

सी.बी.एस.ई., एस.सी.ई.आर.टी., डाइट, डी.ए.वी. विद्यालय प्रबंधन/सी.टी.एस.ए. और कुछ पब्लिक स्कूलों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों और विद्यालय शिक्षकों (सरकारी विद्यालयों, पब्लिक स्कूलों,

केंद्रीय विद्यालयों, दिल्ली प्रशासन) के चयन में संसाधन सहायता प्रदान की गई।

विज्ञान और गणित में क्षेत्रीय सहायता

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों पर जम्मू-कश्मीर के शिक्षकों को गणित शिक्षण और दिल्ली के संसाधन व्यक्तियों को उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान किट के प्रयोग के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। जम्मू और कश्मीर के लिए माध्यमिक स्तर पर गणित में प्रशिक्षण सामग्री, राजस्थान के लिए उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान के चुने हुए शीर्षकों पर मॉड्यूलर रूप में विषयवस्तु संवर्द्धित सामग्री तथा हरियाणा के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बीजगणित के चिह्नित कठिन क्षेत्र पर अंतरावर्तीय-सामग्री विकसित की गई।

कक्षा एक के लिए 'कॉम्पीटेंसी बेस्ड मैथेमेटिक्स' शीर्षक से एक पुस्तक निर्मित, मुद्रित और वितरित की गई। इसका परीक्षण किया जा रहा है।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर ने माध्यमिक स्तर के सेवाकालीन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अवधारणा केंद्रित-अधिगम और भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान में प्रयोगों पर विज्ञान शिक्षण में विषयवस्तु संवर्धन-कार्यक्रम आयोजित किया। जनजातीय हाई-स्कूलों में विज्ञान में शिक्षकों के अभिविन्यास कम सुविधाप्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के तरीके और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के गणित-शिक्षण पर विषयवस्तु-संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर ने 'आन्ध्र प्रदेश सोशल वेल्फेयर रेज़िडेन्सियल इन्स्टीट्यूशन्स सोसाइटी' के अनुरोध पर विषयवस्तु और शिक्षाशास्त्रीय सामर्थ्य विकसित करने के लिए इंटरमीडिएट विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के क्षेत्रों में प्राध्यापकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसने उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए प्रश्न बैंक, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान प्रक्रिया की दक्षताओं के मूल्यांकन के लिए प्रारूप पद्धति और माध्यमिक के लिए गणित तथा उच्च माध्यमिक के लिए अंग्रेज़ी में आधार पाठ्यक्रम पर एक मॉड्यूल विकसित किया।

इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्यावरणीय अध्ययनों (विज्ञान) में एक अधिगम गतिविधि बैंक और कक्षा तीन तथा चार के लिए बांग्ला भाषा में स्वाधिगम सामग्री तैयार की।

1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- ए मॉडल नरचरेन्स प्रोग्राम इन फिज़िक्स फॉर दि टैलेन्टेड स्टूडेन्ट्स (अनुलिपि)
- लेबोरेटरी मैनुअल इन मैथेमेटिक्स फॉर अपर प्राइमरी, सेकेण्डरी एण्ड सीनियर सेकेण्डरी स्टेज-II (अनुलिपि)
- एनालिसिस ऑफ मैथेमेटिक्स सिलेबाय फॉर सेकेण्डरी स्टेज ऑफ डिफरेन्ट स्टेट्स (अनुलिपि)
- डेवलपमेन्ट ऑफ डायगनॉस्टिक टेस्ट एण्ड रेमिडियल मेटीरियल्स ऑन ए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री (कान्ग्रुएन्ट फिगर्स) फॉर स्लो लर्नर्स ऑफ अपर प्राइमरी स्टेज एण्ड टु स्टडी दि इफेक्टिवनेस ऑफ दि रेमेडियल मेटीरियल्स (अनुलिपि)
- सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमेस्ट्री - ए मॉड्यूल ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म (अनुलिपि)
- चैलेन्जिंग प्राबलम्स इन केमेस्ट्री फॉर क्लासेज़ XI और XII (अनुलिपि)
- डेवलपमेन्ट ऑफ ए मॉडल कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी फॉर टीचर ओरिएंटेशन इन केमेस्ट्री (अनुलिपि)
- स्टेटस ऑफ साइंस एजुकेशन इन इण्डिया (अनुलिपि)
- 'एलॉज़' अण्डर दि प्रोजेक्ट 'सम इन्टरेस्टिंग टॉपिक्स इन केमिस्ट्री: डेवलपमेन्ट ऑफ मॉड्यूल्स (अनुलिपि)
- हमारा अद्भुत वायुमण्डल अब मैला क्यों?
- मौसम-क्या, क्यों और कैसा
- सौर ऊर्जा

लिस्ट ऑफ एक्ज़ीबिट्स ऑफ 26th जवाहरलाल नेहरू साइंस एक्जीबिशन फॉर चिल्ड्रेन

- स्ट्रक्चर एण्ड वर्किंग ऑफ साइंस मॉड्यूल्स
- स्कूल साइंस क्वार्टरली जर्नल
- वर्कशीट इन केमेस्ट्री फॉर प्रेक्टिकल कोर्स–क्लास XI और XII (अनुलिपि)
- डिज़ाइन एंड ट्राइआउट ऑफ इन्नोवेटिव एक्सरसाइजेज़ फॉर देयर इन्क्ल्यूजन इन केमेस्ट्री प्रेक्टिकल्स: ए रिपोर्ट (अनुलिपि)
- प्रॉबलम बुक इन मैथेमेटिक्स फॉर क्लास XI (टंकित)
- ए सप्लीमेन्ट टू मैथमेटिक्स फॉर क्लास XI
- कक्षा XI की जीव विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग II
- कम्यूनिकेटिंग साइन्स थ्रू ग्राफ्स (अनुलिपि)।

सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा

एन सी ई आर टी के सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा के कार्यक्रम पाठ्यचर्या, सेवारत अध्यापकों व अध्यापक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों को विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अनुसंधान, विकास, अनुदेशी सामग्री और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में परामर्शकारी/शैक्षिक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित रहे हैं।

एन सी ई आर टी के सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा के कार्यक्रम पाठ्यचर्या, सेवारत अध्यापकों व अध्यापक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों को विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अनुसंधान, विकास, अनुदेशी सामग्री और प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों में परामर्शकारी/शैक्षिक सहायता प्रदान करने पर केंद्रित रहे हैं। इनमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं: (1) भाषा (हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेज़ी), (2) सामाजिक विज्ञान (भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिकशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र), (3) वाणिज्य, (4) कला शिक्षा और (5) जनसंख्या शिक्षा। इसके अलावा एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन, मानवाधिकार शिक्षा और उपभोक्ता शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से संलग्न रही है।

अनुसंधान

अरुणाचल प्रदेश में कक्षा 5 की शिक्षा समाप्ति के बाद छात्रों द्वारा अर्जित हिंदी भाषा क्षमता और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों में मानचित्र कौशलों की समझ के सर्वेक्षण पर परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। मा.सं.वि. मंत्रालय के लिए हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए योजना के कार्यान्वयन की अवस्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। एन.सी.ई.आर.टी. की सामाजिक विज्ञान और भाषा पाठ्यपुस्तकों में लिंग, धर्म और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विषयों को बिंबित करने के तरीकों के अध्ययन के मूल्यांकन के लिए एक परियोजना शुरू की गई।

विकास

एन.सी.ई.आर.टी. ने पाठ्यचर्या के क्षेत्र में अपना कार्य जारी रखा और छात्रों तथा अध्यापकों से प्राप्त पुनर्निवेशन और मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यपुस्तकों के नए/ संशोधित संस्करण तैयार किए। सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8 और 10 की भूगोल की पाठ्यपुस्तकें, कक्षा 9 और 11 के लिए अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तकें, कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें, कक्षा 5 से 8 तक के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के हिंदी रूपान्तरण के नए/संशोधित संस्करण निकाले गए। भाषा में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 'हिंदी व्याकरण और रचना', कक्षा 10 के लिए हिंदी 'बी' पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तकें और अंग्रेज़ी भाषा पाठ्यपुस्तकों की नई शृंखला के लिए कक्षा 1 की अंग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तक तैयार की गई। वाणिज्य में, व्यापार अध्ययन और लेखाशास्त्र में पाठ्य विवरणों को व्यापार और उद्योग, लेखा प्रक्रिया और सूचना प्रौद्योगिकी में हाल में हुए विकासों को ध्यान में रखकर संशोधित किया गया। उच्चतर माध्यमिक के लिए समाजशास्त्र में नई पाठ्यपुस्तकों की तैयारी आरंभ की गई है।

नए सिरे से उर्दू साहित्य का इतिहास तैयार करने के लिए परियोजना प्रारंभ की गयी। संस्कृत में विशेषज्ञ समूह की एक बैठक में नए कार्यक्रमों और योजनाओं का निरूपण किया गया जो आरंभ हो चुकी हैं। इसमें संस्कृत साहित्य में प्रतिबिंबित विज्ञान और शिक्षा पर पुस्तकों की शृंखला, प्रवेशकों के लिए विद्यार्थी संस्कृत शब्दकोश, संस्कृत शिक्षण कार्य पद्धति के सुधार पर कार्यक्रम और संस्कृत में एक प्रशिक्षण पैकेज का विकास शामिल है। विद्यालयी छात्रों के लिए एक दृष्यन्त हिन्दी शब्दकोश प्रकाशन के लिए भेजा गया।

'पढ़ें और सीखें' परियोजना के अन्तर्गत 'एंशयन्ट स्टोरीज़ रीटोल्ड' और 'वी आर वन' नामक दो पूरक पाठमालाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इस परियोजना में और अधिक पुस्तकें तैयार की जा रही हैं, जिनमें एक पंडित मदन मोहन मालवीय पर है। 'इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेन्डेन्स–विजुअल्स एंड डाक्युमेंट्स' का हिंदी रूपान्तरण प्रकाशन के लिए तैयार है और 'ह्यूमन राइट्स–ए सोर्स बुक' के उर्दू रूपान्तरण की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है।

विस्तार

'आधुनिक भारत में उर्दू शिक्षण–समस्याएं और सुधारात्मक उपाय' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। बाल साहित्य में 19 भाषाओं (अष्टम अनुसूची की सभी भाषाओं और अंग्रेज़ी) में दो वर्षों में एक बार आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के अन्तर्गत 30वीं बाल साहित्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता के परिणाम घोषित किए गए। इस पुरस्कार के लिए तीस पुस्तकें/पाण्डुलिपियां चयनित की गईं।

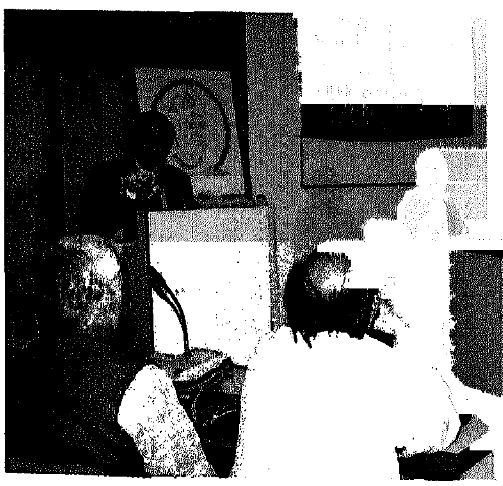


'आधुनिक भारत में उर्दू शिक्षण' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी।

'आज का सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य और कबीर' पर एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के लेखों और कार्यविधियों को प्रकाशित करने के लिए संपादन कार्य किया जा रहा है।

देश के विभिन्न भागों में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध स्वतंत्रता और एकता के गीतों के एक संग्रह का संकलन किया गया। इन गीतों को मुद्रित किया जाएगा और इनके ऑडियो कैसेट बनाए जाएंगे।

सभी स्तरों पर संस्कृत शिक्षण के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए संस्कृत के माध्यम से संस्कृत शिक्षण के विशेष संदर्भ के साथ संस्कृत की शिक्षण पद्धति के सुधार पर एक तीन-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई।



'आज का सामाजिक - सांस्कृतिक परिदृश्य और कबीर' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन-सत्र।

सामाजिक विज्ञान और मानविकी में क्षेत्रीय निवेश

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ने उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में हरियाणा के अध्यापकों की कठिनाइयों के समाधान के लिए एक अध्यापक संदर्शिका की रूपरेखा तैयार की। दिल्ली के अध्यापकों के लिए माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के एक भाग के रूप में अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए अनुदेशी सामग्री भी विकसित की गई।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने (1) गोवा राज्य के लिए भूगोल शिक्षण के अनिवार्य कौशलों पर एक नियम पुस्तिका, (2) मध्य प्रदेश के लिए +2 के लिए इतिहास के मॉडल प्रश्न पत्रों पर एक पैकेज, (3) लेखाशास्त्र में प्रशिक्षण सामग्री, अध्यापक संदर्शिका के दो पैकेज और वाणिज्य में परियोजना प्रस्ताव, (4) माध्यमिक स्तर पर अंग्रेज़ी अध्यापकों के लिए मौखिक परीक्षण पर दिशानिर्देश

और (5) गोवा में मराठी और कोंकणी माध्यम वाले विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर अंग्रेज़ी भाषा में नवाचारी अध्यापन अधिगम पद्धतियों में एक नियम पुस्तिका और प्राथमिक स्तर पर उर्दू शिक्षण पद्धति में एक प्रशिक्षण पैकेज विकसित किया। महाराष्ट्र में माध्यमिक स्तर पर मराठी शिक्षण का एक अवस्थिति सर्वेक्षण भी आयोजित किया गया और सामग्री के विकास के लिए कुछ समस्याओं की पहचान की गई।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर ने जनजातीय हाई स्कूलों के अध्यापकों के लिए सामाजिक विज्ञान और अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कठिन बिन्दुओं की पहचान, माध्यमिक विद्यालयों के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विषयवस्तु एवं प्रणाली का संवर्द्धन कार्यक्रम और संबंधित प्रशिक्षण प्रणाली व विषयवस्तु एवं प्रणाली, माध्यमिक-विद्यालय के अध्यापकों के लिए भौतिक भूगोल के शिक्षण पर संवर्द्धन कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक लेखकों के लिए प्रशिक्षण और कार्यशाला, हिंदी शिक्षण में डी.आई.ई. टी. संकाय के अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए।

1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- रिपोर्ट ऑफ दि रिव्यू कमेटी ऑन सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम ऑफ फाइनेंसियल असिस्टेंस फॉर एपाइंटमेंट ऑफ माडर्न इंडियन लेंग्वेजिज़ टीचर्स (प्रेफेरेबली साउथ इंडियन लेंग्वेजिज़) इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स (फोटोप्रति)
- मैपबुक फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेन्ट्स फॉर ट्राई-आउट
- ए सलेक्टिड एन्नोटेटिड बिबिलियोग्राफी ऑन स्कूल एजुकेशन (1981-99) (अनुलिपि)
- अरुणाचल प्रदेश की पाँचवीं कक्षा के छात्रों द्वारा हिंदी भाषा में अर्जित दक्षता संप्राप्ति मूल्यांकन-एक अध्ययन (वर्ड प्रोसेस्ड)
- सम आस्पेक्ट्स ऑफ अपर प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया-स्टेटस स्टडी (1998) (मुद्रणाधीन)
- फाइनेलाइज़ेशन ऑफ प्रोजेक्ट डाक्युमेंट्स ऑफ सब-कान्ट्रेक्टिंग एजेन्सीज़ (एन.सी.टी.ई., एन.वी.एस., सी.बी.एस.ई. एण्ड एन.ओ.एस.) (अनुलिपि)।

बोर्डों, अध्यापकों और सामान्य जनता के हित में ग्रेडिंग जैसे तकनीकी विषय को यथासंभव आसान बनाने के लिए 'विद्यालयों में ग्रेडिंग' नामक दस्तावेज़ विकसित किया गया। यह दस्तावेज़ वास्तव में 'ग्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानिए' को स्पष्ट करता है।

एन सी ई आर टी परीक्षा सुधार के क्षेत्र में मापन और मूल्यांकन से संबंधित अनेक कार्यकलापों में संलग्न है। इस क्षेत्र के कार्यक्रम खासतौर से संसाधन व्यक्तियों, प्रश्नपत्र निर्माताओं और परीक्षकों के प्रशिक्षण, अवधारणात्मक और नमूना सामग्री के विकास, अनुसंधान आयोजन और संवृद्धि, परामर्शकारी सेवाओं की उपलब्धता और शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र में शोधन गृह कार्यकलापों पर केंद्रित हैं। 1999-2000 की अवधि में परीक्षा सुधार के क्षेत्र में किए गए कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :

अनुसंधान

बोर्ड के उच्चतर माध्यमिक परीक्षाफल का विश्लेषण

इस पायलट अध्ययन के अंतर्गत आठ बोर्डों- पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई., पश्चिम बंगाल और नागालैंड- के परीक्षा-परिणामों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण से पता चलता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक था, अन्य बोर्डों की अपेक्षा आई.सी.एस.ई. में उत्तीर्ण प्रतिशत उच्चतर था, विज्ञान विषयों में गोवा बोर्ड के विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत अन्य बोर्डों की तुलना में अधिक था और सभी बोर्डों में विज्ञान के अन्य विषयों की तुलना में जीव विज्ञान में विद्यार्थियों ने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। सी.बी.एस.ई. में लगभग 56 प्रतिशत और नागालैंड में मात्र 6% अभ्यर्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए थे।

आंतरिक और बाह्य परीक्षा प्राप्तांकों के मध्य संबंध

दिल्ली राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के 18 उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालयों से कुल 215 विज्ञान विद्यार्थियों का एक नमूना इस्तेमाल किया गया। उपलब्धियों से संकेत मिलता है कि बोर्डपूर्व और बोर्ड परीक्षा परिणामों के मध्य एक सार्थक सहसंबंध है, विज्ञान और गणित में बोर्डपूर्व और बोर्ड परीक्षाओं दोनों के प्राप्तांक में लड़कियों और लड़कों के बीच अभिव्यंजक अंतर नहीं था लेकिन गणित की बोर्ड परीक्षा में औसत प्राप्तांक में सार्थक अन्तर था। विज्ञान, गणित और अंग्रेज़ी में ग्रामीण और शहरी परीक्षार्थियों के बीच बोर्डपूर्व और बोर्ड परीक्षा के औसत प्राप्तांकों में महत्वपूर्ण अन्तर नहीं था।

विकास

विद्यालयों में ग्रेडिंग

बोर्डों, अध्यापकों और सामान्य जनता के हित में ग्रेडिंग जैसे तकनीकी विषय को यथासंभव आसान बनाने के लिए 'विद्यालयों में ग्रेडिंग' नामक दस्तावेज़ विकसित किया गया। यह दस्तावेज़ वास्तव में 'ग्रेडिंग के बारे में सब कुछ जानिए' को स्पष्ट करता है।

कक्षा चार के लिए पर्यावरणीय अध्ययन (सामाजिक अध्ययन) में परीक्षण इकाई

कक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया को मज़बूत करने और अच्छे प्रश्नों को तैयार करने में शिक्षकों की कठिनाइयों को समाप्त करने के क्रम में एन.सी.ई.आर.टी. ने कक्षा चार के लिए पर्यावरणीय अध्ययन (सामाजिक अध्ययन) में एक प्रश्न भंडार विकसित, परिष्कृत और निश्चित किया। प्राथमिक विद्यालयों में व्यापक पैमाने पर वितरण के लिए इसे मुद्रित रूप में लाया जाएगा।

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर रसायन विज्ञान के प्रयोगात्मक मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकन पद्धति का विकास

रसायन-प्रयोगशाला कार्यों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में रसायन प्रयोगों में प्रचलित मूल्यांकन पद्धति का विश्लेषण किया गया। विद्यालय शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर के लिए प्रयोग-कार्य पुस्तिका विकसित, परिष्कृत और निश्चित की गई और रसायन प्रयोग कार्यों की एक मूल्यांकन पद्धति विकसित की गई। ग्राह्य और अनुकूल बनाने के लिए यह पद्धति विद्यालयी शिक्षा के बोर्डों को प्रचारित-प्रसारित की जाएगी।

प्रशिक्षण

प्रश्न-पत्र निर्माताओं का प्रशिक्षण

जम्मू और कश्मीर विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 68 प्रश्न-पत्र निर्माताओं/परीक्षकों को अंग्रेज़ी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में संतुलित प्रश्न-पत्रों के निर्माण के लिए श्रीनगर में एक पाँच-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला में मूल्यांकन और निर्मित प्रश्न-पत्रों पर प्रत्ययात्मक सामग्री से युक्त कार्यक्रमों की एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस पर विचार-विमर्श किया गया।

संतुलित प्रश्न-पत्रों के निर्माण हेतु 'कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा और परीक्षा बोर्ड' के 50 प्रश्न-पत्र निर्माताओं के लिए एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को मूल्यांकन के प्रत्यय और परीक्षण की विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया गया। उन्होंने अंग्रेज़ी, हिंदी, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन के विषयों का संतुलित प्रश्न-पत्र तैयार किया। एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई और प्रतिभागियों के बीच परिचालित की गई।

आइटम बैंक निर्मित करने हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण

गोवा राज्य के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को अच्छे प्रश्न बनाने और आइटम बैंक तैयार करने की तकनीक से अवगत कराया गया। अंग्रेज़ी, अर्थशास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषयों के लगभग 60 अध्यापकों ने इस कार्यशाला में भागीदारी की और कार्यशाला के दौरान हर विषय में लगभग 500 प्रश्न तैयार किए। गोवा के शिक्षकों के प्रयोग के लिए इन प्रश्नों की जाँच कर अन्तिम रूप दिया जाएगा और आइटम बैंक के रूप में संकलित किया जाएगा।

सतत् और व्यापक मूल्यांकन में केंद्रीय विद्यालय के अध्यापकों का प्रशिक्षण

दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय विद्यालयों के 28 अध्यापकों को सतत् और व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई.) की अवधारणा और तकनीक में अभिमुख किया गया। अवधारणा, निदान और उपचार, गैर-शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और छात्र विकास के विभिन्न पहलुओं के मूल्यांकन के लिए उपकरण का विकास जैसे सी.सी.ई. के विभिन्न आयामों की उन्हें जानकारी दी गई। यह आशा की जाती है कि ये अध्यापक अपने विद्यालयों के अन्य अध्यापकों में संसाधन समूह के रूप में कार्य करके इस प्रशिक्षण को प्रचारित कर सकेंगे।

मानसिक योग्यता परीक्षण (एम.ए.टी.) के लिए लेखन आइटमों में प्रशिक्षण

राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए गुजरात और मेघालय राज्यों के आइटम लेखकों को मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए लेखन आइटम में प्रशिक्षित करने के लिए दो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन दोनों कार्यशालाओं में प्रतिभागियों ने मानसिक क्रियाकलापों के मूल्यांकन हेतु बड़ी संख्या में आइटमों का विकास किया। ये आइटम पुनरीक्षित और परिष्कृत किए जाएंगे और मैट के लिए आइटम पूल विकसित करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे।

विस्तार

राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों के एक दो-दिवसीय सम्मेलन में विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें अंकों के स्थान पर ग्रेड देने और एक राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन के निर्माण के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्पूर्ण देश के प्रमुख



राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्षों का दो दिवसीय सम्मेलन।

शिक्षाशास्त्री और मा.सं.वि. मंत्रालय के अधिकारियों के अतिरिक्त 28 राज्य बोर्डों के अध्यक्षों और संसाधित अधिकारियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। पाठ्यचर्या रूपरेखा पर प्रतिभागियों के प्रेक्षण रूपरेखा के दस्तावेज़ में समाहित किए जाएंगे। प्रतिभागी इस बात पर सहमत थे कि ग्रेडिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के पूर्व सी.ओ.बी. एस.ई. अपने साझेदारों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित कर सकता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन की स्थापना के संबंध में प्रतिभागियों की राय थी कि एन.सी.ई.आर.टी. इस प्रस्ताव पर कार्य कर सकती है और एन.ई.ओ. के विशिष्ट लक्ष्यों, उद्देश्यों और ढाँचे के संदर्भ निष्कर्ष पर पहुँच सकती है।

परीक्षा सुधार में क्षेत्रीय निवेश

आर.आई.ई., अजमेर ने राजस्थान की डाइट के प्रयोग के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान विषय में आदर्श

ब्ल्यू प्रिन्ट्स और प्रश्न-पत्रों की रूपरेखा तैयार की। ये हरियाणा के माध्यमिक स्तर के लिए भी तैयार किए गए जिसके संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षित थे।

आर.आई.ई., भोपाल ने उच्च माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित में प्रश्न-पत्र निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण पैकेज विकसित किया।

आर.आई.ई., भुवनेश्वर ने हिंदी और उड़िया में भाषा दक्षता परीक्षण का विकास और मानकीकरण किया और अधिगम निष्कर्षों के मूल्यांकन के लिए उभरते हुए तरीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

1999-2000 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- ग्रेडिंग इन स्कूल्स
- इग्जामिनेशन रिफार्म बुलेटिन वाल्यूम II नंबर 2
- टेस्ट आइटम्स इन इन्वायरनमेन्टल स्टडीज़ (सोशल स्टडीज़) फार क्लास IV (फोटोप्रति)
- एनालिसिस ऑफ सीनियर सेकेण्डरी रिज़ल्ट्स ऑफ बोर्ड्स – ए पायलट स्टडी (फोटोप्रति)
- ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्टरनल एण्ड एक्सटरनल इग्जामिनेशन स्कोर्स ऑफ सीनियर सेकेण्डरी स्टूडेन्ट्स इन डेल्ही (फोटोप्रति)
- ए स्कीम ऑफ केमिस्ट्री प्रेक्टिकल फार सीनियर सेकेण्डरी लेवेल (फोटोप्रति)
- एनालिसिस ऑफ स्टूडेन्ट्स परफॉरमेन्स ऑफ डिफरेन्ट सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस इन एन.टी.एस. (फोटोप्रति)
- एन एप्रैज़ल ऑफ एन.टी.एस. इग्जामिनेशन, 1999 (फोटोप्रति)।

राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है जोकि मूल्यों की सामग्रियों के राष्ट्रीय निधि सदन के रूप में कार्य करेगा। मूल्य-परिवर्तन, मूल्यों का शिक्षण व अधिगम, जनजाति समाजों के मूल्य, मूल्यों की भारतीय अवधारणा, विभिन्न धर्मों में मूल्य का शिक्षण इत्यादि सरीखा शिक्षा में मूल्यों से संबंधित विभिन्न प्रकार का साहित्य इसमें शामिल है।

शैक्षिक मनोविज्ञान, परामर्श और मार्गदर्शन के क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के द्वारा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना परिषद् के मुख्य सरोकारों में से एक है। इस क्षेत्र के कार्यक्रमों के परिणामों का विद्यालयी छात्रों के शैक्षिक विकास पर ही नहीं बल्कि उनके चहुंमुखी विकास तथा प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों पर उनके सामाजिक, भावात्मक एवं जीवनवृत्तिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ कार्यक्रम मुख्य रूप से अध्यापकों और अध्यापक शिक्षकों को सशक्त और सक्षम बनाने और इसके परिणामस्वरूप अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए तैयार किए जाते हैं। परामर्श और मार्गदर्शन के कार्य क्षेत्र में एक मुख्य संस्था होने के नाते एन.सी.ई.आर.टी. विद्यालयी छात्रों, अध्यापकों और समुदायों को अपनी सेवाएँ प्रदान करने में राज्य स्तर के अभिकरणों की सहायता करती रही है। राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा संसाधन केन्द्र के रूप में जानी जाने वाली एन.सी.ई.आर.टी. ने दो कार्यक्रम आरम्भ किए हैं– प्रकाशित कार्यों की विस्तृत संदर्भ ग्रंथ-सूची और संस्थाओं को मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में सूचना उपलब्ध कराना।

अनुसंधान

कक्षा 11 के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की मनोविज्ञान की पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन : एक पायलट अध्ययन

पुनरीक्षकों, अध्यापकों और शिक्षकों के लिए मूल्यांकन के आधारों को तैयार करने हेतु संबंधित साहित्य का पुनरीक्षण किया गया। पुनरीक्षकों के लिए विकसित अलग-अलग मूल्यांकन प्रारूपों को अन्तिम रूप दिया गया। संकाय-सदस्यों के सुझावों को शामिल किया गया। दिल्ली के उन विद्यालयों के अध्यापकों और छात्रों से आंकड़ा एकत्र किया गया, जहाँ मनोविज्ञान एक विद्यालयी विषय के रूप में पढ़ाया जाता है।

परामर्शदाता निर्माण : स्थिति एवं विकास (फेज़ II)

अध्ययन का उद्देश्य प्रभावशाली परामर्शदाताओं के केस-अध्ययन को तैयार करना है। साक्षात्कार के द्वारा ऐसे 15 परामर्शदाताओं से आंकड़ा एकत्रित किया गया। केस-वृत्तों को मार्गदर्शन कार्मिकों और अन्य इच्छुक शैक्षिक प्रशासकों और अध्यापकों के प्रयोगार्थ प्रकाशन के लिए तैयार किया जाएगा।

सामाजिक मानदण्ड के प्रति किशोरों के दृष्टिकोण पर एक अध्ययन

अनुसंधान की यह योजना किशोरों के दृष्टिकोणों और व्यवहारों के प्रति माता-पिता के मानदंडों और अपेक्षाओं की प्रकृति तथा इन अपेक्षाओं के प्रति किशोरों के दृष्टिकोणों का अध्ययन करने के लिए बनाई गयी। प्रश्नावलियों और साक्षात्कारों की सहायता से आंकड़ा इकट्ठा किया गया। माता-पिता की अपेक्षाओं और किशोरों की अपेक्षाओं के बीच अंतर्विरोध देखने, यदि कोई हो, तो उसे देखने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर माता-पिता के लिए कुछ निश्चित दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं ताकि वे किशोरों के विकास में वृद्धि के लिए उनके अंतर्द्वंद्वों और तनावों को कम करने का प्रयास कर सकें।

विज्ञान की प्रकृति, मनोवृत्ति, विज्ञान के प्रति मूल्य और दैनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में माध्यमिक विद्यालय स्तर की विज्ञान पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण

इस परियोजना के अंतर्गत एन.सी.ई.आर.टी. के माध्यमिक स्तर की विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का विज्ञान की प्रकृति, उसके प्रति मनोवृत्ति व मूल्य और दैनिक जीवन के लिए उसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में विश्लेषण किया गया। यह विश्लेषण मौजूदा विश्लेषण योजना की सहायता से किया गया, जिसे इस अध्ययन के लिए अनुकूलित किया गया। इसके परिणामों पर चर्चा की गई और पाठ्यपुस्तकों के विकास के लिए मार्गदर्शिका तैयार की गई। अनुलिपि रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

भारत में शैक्षिक मनोविज्ञान की अनुसंधान प्रवृत्तियाँ एवं मौलिकता : दैनिक पत्र-पत्रिकाओं और रिपोर्टों का विश्लेषण

इस अध्ययन का उद्देश्य पिछले पन्द्रह वर्षों में भारत में शैक्षिक मनोविज्ञान में अनुसंधान-प्रवृत्तियों का पता लगाना और संरचनात्मक विशेषताओं, लेखकीय मानदंड, विधि और विषयों के केंद्र-बिंदु तथा शैक्षिक मनोविज्ञान में संस्थानों के योगदान के संदर्भ में विश्लेषण करने के लिए पत्र-

पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों और अनुसंधान रिपोर्टों की जाँच पड़ताल करना था। इस अध्ययन के अंतर्गत विश्लेषण के लिए 641 आलेख (पूर्ण पाठ्यसामग्री) एकत्र किए गए। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

परामर्शदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्य- निष्पादन और सेवाकार्य-निष्पादन के लिए चयन प्रक्रिया की भावी संभावना का अध्ययन

इस परियोजना का उद्देश्य परामर्शदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्य-निष्पादन और सेवाकार्य-निष्पादन के लिए चयन प्रक्रिया की भावी संभावना का निर्धारण करना था। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित परामर्शदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन में एक लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और आत्म अभिव्यक्ति की तकनीक अपनाई जाती है। इस तकनीक के परिणामों के साथ उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और सेवाकार्य निष्पादनों का सह-संबंध स्थापित किया गया। इस अध्ययन में गुणात्मक आंकड़ा विश्लेषण सहित सह-संबंधनात्मक विश्लेषण से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उनसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए उम्मीदवारों की मौजूदा चयन-प्रक्रिया हेतु प्रयोग की जा रही परीक्षाओं और साक्षात्कार की तकनीक की पुष्टि होती है। अनुलिपि रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

भारत में प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की शैक्षिक मनोविज्ञान पाठ्यचर्या का आलोचनात्मक अध्ययन

देश भर में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान के 31 पाठ्यक्रमों के राष्ट्रीय सर्वेक्षण की अनुलिपि रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। यह रिपोर्ट दो भागों में है। पहला भाग सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों से संबंधित है और दूसरा भाग पाठ्यक्रम प्रकृति के आनुभविक विश्लेषण, संरचना और पाठ्यचर्या की योजना में निहित विषयवस्तु, नीतियों और प्रयासों तथा शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक-प्रशिक्षकों के अवबोधन से संबंधित है। इस रिपोर्ट को संशोधित करने के लिए इसे एन.सी.टी.ई. और एस.सी.ई.आर.टी. को उनके अपने पाठ्यक्रमों में प्रयोग करने के लिए भेजा गया।

मीरांबिका में शिक्षा : एक केस अध्ययन

अध्ययन का उद्देश्य मीरांबिका सरीखे एक ऐसे विद्यालय में शिक्षण कार्यविधि का परीक्षण करना है, जोकि श्री अरविन्द के मुक्त विकास दर्शन पर आधारित है। मीरांबिका में 8 महीने तक तीन अन्वेषकों द्वारा गहन प्रतिभागी प्रेक्षण किया गया। नृजातीय पद्धति का अनुसरण करते हुए मीरांबिका का एक आन्तरिक केस अध्ययन किया गया। त्रिविध पद्धति अर्थात् प्रेक्षण, साक्षात्कार और प्रश्नावलियों के प्रयोग से विद्यालय में 3 अन्वेषकों के प्रेक्षणों की अंतर्वैधता में सहायता मिली।

यह अध्ययन विद्यालयों में संगठनात्मक गतिकी, विकेन्द्रित योजना, विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास, बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप बाल-केन्द्रित पाठ्यक्रम और पठन-पाठन की परियोजना पद्धति पर प्रकाश डालता है। इस अध्ययन की उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. की अध्यक्षता में संबंधित विद्यालयों के सदस्यों के सम्मुख किया गया। मुख्य उपलब्धियों की रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई।

परामर्शदाता निर्माण : स्थिति एवं विकास (फेज़ I)

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं का अनुवर्तन करना है। परामर्शदाताओं की प्रभविष्णुता पर परामर्शदाताओं, प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सूचना प्राप्त की गई। प्रभविष्णुता के मूल्यांकन के मानदण्ड पर कुछ परामर्शदाता प्रभावी पाए गए जिनकी पहचान की गई। निष्कर्षों से परामर्शदाताओं के अवबोधन का संकेत मिलता है।

परामर्शदाता अपनी भूमिका के निर्वाह में अंतर्विरोधों का सामना कर रहे हैं क्योंकि कार्यों की मांग उनकी अवबोधन-भूमिका के अनुरूप नहीं है। नियोक्ताओं, विद्यालय के प्रभारी और विद्यार्थियों में परामर्शदाताओं के कार्यों के प्रति समझदारी का अभाव है। परियोजना से संबंधित कार्य पूरा हो चुका है और रिपोर्ट को लगभग अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

भारत में मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुसंधान : एक गहन अध्ययन

इस परियोजना का उद्देश्य मार्गदर्शन और परामर्श में भारतीय अनुसंधानों का सूक्ष्म और स्थूल विश्लेषण करना है। पत्र-

पत्रिकाओं और विभिन्न आयामों पर उपलब्ध प्रलेखों से लगभग 500 अनुसंधानों की पहचान का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आगे के अनुसंधान की योजना में और व्यावसायिक प्रयास के लिए व्यावहारिक देशी आदर्श के विकसित निष्कर्ष उपयोगी हैं।

विकास

लोकप्रिय मनोविज्ञान शृंखला

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापकों और अभिभावकों के लिए ऐसी पुस्तिकाओं का विकास करना है जिनसे बच्चों के अधिगम और विकास की समझ में वृद्धि हो सके। इस शृंखला के अंतर्गत 14 पुस्तिकाएँ पहले ही तैयार कर ली गई थीं । एक कार्यशाला में विशेषज्ञों ने इन सभी 14 पुस्तिकाओं का पुनरीक्षण किया और पाण्डुलिपि में संशोधन के लिए अपने प्रेक्षण, मत और सुझाव दिए। पुनरीक्षकों के सुझावों के आधार पर इन पुस्तिकाओं को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

'डाइट कार्मिकों के लिए अध्यापन-अधिगम के मनोविज्ञान में संवर्द्धन पाठ्यक्रम' के स्व-अधिगम माड्यूल : संसाधन सामग्री का विकास

32 स्व-अधिगम माड्यूल विकसित और पुनरीक्षित किए गए। पुनरीक्षणकर्ताओं के सुझावों को समाहित करने के बाद ये माड्यूल 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 1999 और 10 से 12 जनवरी 2000 को संपादन-मंडल के सदस्यों के सम्मुख रखे गए। संपादन-मंडल के सदस्यों ने इन सभी 32 माड्यूलों का संपादन किया। सदस्यों ने कुछ माड्यूलों में संशोधन का सुझाव दिया। संशोधित माड्यूल संपादन-मंडल के एक सदस्य के पास भेजा गया है। माड्यल के अन्तिम रूप को मुद्रित किया जाएगा।

प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान में पाठ्यचर्या

एन.सी.ई.आर.टी. शैक्षिक मनोविज्ञान में पाठ्यक्रम ढाँचे के निर्माण की प्रक्रिया में है जो कम सैद्धान्तिक, कार्यात्मक, यथार्थोन्मुख और देशी होगा। यह विषयवस्तु के निर्माण, एकीकृत सिद्धान्त और व्यवहार, प्रस्तावित क्षेत्रों और तरीकों, उपयुक्त अधिगम पद्धतियों के निर्णय में पाठ्यचर्या निर्माताओं के लिए सुनिश्चित मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा। अब तक जो कार्य किए गए, वे निम्न हैं- साहित्य का गहन पुनरीक्षण, प्रशिक्षण में छूटे हुए पहलुओं के बारे में सेवाकालीन अध्यापकों के बोध के लिए ऐसे पाठ्यक्रम में मूलत: क्या होना चाहिए-विषय पर विशेषज्ञों के विचार आदि। पाठ्यचर्या के विकास के लिए मुद्दों और रूपात्मकता पर विचार-विमर्श करने के लिए संचालन समिति की बैठक की गई। बाद में विचार-विमर्श के लिए एक आधार पत्र तैयार किया गया। विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों की शोध अंतर्दृष्टि और अनुभवों की पहचान के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई और प्रकाशन के लिए एक लेख तैयार किया गया।

परामर्शकारी केस प्रबंधन : व्यावहारिक संदर्शिका का विकास

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा चलाए जा रहे परामर्शकारी डिप्लोमा के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार व सफलतापूर्वक चलाए जा रहे परामर्शकारी केस-अध्ययनों पर एक केस-पुस्तिका तैयार करने का प्रयास है।

एन.सी.ई.आर.टी. में उपलब्ध पाँच सौ केस-रिकार्डों में से 20 केसों की पहचान कर ली गई है। प्रकाशन के लिए इन केस-अध्ययनों का संपादन, संशोधन और पुनरावलोकन किया जा चुका है। केस-अध्ययनों के पुनरीक्षण और कुछ सैद्धान्तिक अध्यायों के लिए पुनरीक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। यह केस-पुस्तिका पुनरीक्षकों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को समाहित करने के बाद अन्तिम प्रारूप की प्रक्रिया में है।

कक्षा में अध्यापकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न : संसाधन सामग्री का विकास

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अध्यापन-साधन के रूप में प्रश्न पूछने की भूमिका का पता लगाना और अध्यापकों के लिए प्रश्न पूछने पर संसाधन सामग्री विकसित करना है। प्रश्नों से संबंधित अनुसंधानों की प्रवृत्तियों को जानने के लिए भारतीय और विदेशी दोनों पत्र-पत्रिकाओं में अनुसंधानों का पुनरीक्षण किया गया। अध्यापकों के प्रश्नों की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए कक्षाओं के छोटे नमूने का खोजपरक अध्ययन किया गया। अध्यापकों के उपयोग के

लिए प्रश्नों के बारे में शिक्षक प्रशिक्षकों के विचारों से संबंधित आंकड़ा विकसित किया गया। यह विस्तार से बताता है कि प्रश्न कैसे और क्यों हों। यह मार्ग निर्देशन करता है और बताता है कि कक्षा-प्रश्नों की संरचना कैसी हो। प्रश्न पूछने के विभिन्न आयामों से संबंधित अनुकरणीय सामग्री विकसित की गई है। एक प्रबन्ध के रूप में लाने के लिए सामग्री को शीघ्रता से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

+2 स्तर पर मनोविज्ञान पाठ्यचर्या

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है +2 स्तर पर वर्तमान मनोविज्ञान की पाठ्यचर्या का परीक्षण करना और इस स्तर पर मनोविज्ञान के स्थिति प्रपत्र का विकास करना।

पूरे देश के विभिन्न राज्य बोर्डों में +2 स्तर पर लागू मनोविज्ञान की पाठ्यचर्या के विश्लेषण का कार्य किया गया। मनोविज्ञान के विद्यालय अध्यापकों और छात्रों के एक प्रतिदर्श के माध्यम से आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्य किया गया। स्थिति पत्र तैयार किया जाएगा जिसके बाद +2 स्तर पर मनोविज्ञान की अनुकरणीय पाठ्यचर्या विकसित होगी।

मूल्य, मनोवृत्ति और रुचियों की पुस्तिका

यह पुस्तिका मूल्य, रुचि और मनोवृत्ति के क्षेत्र में आलोचनात्मक पुनरीक्षण के लगभग 60 परीक्षणों से युक्त है। विभाग द्वारा तैयार की गई ऐसी पुस्तिकाओं की शृंखला में यह तीसरी है। अन्तिम रूप दिए जाने के बाद यह पाण्डुलिपि प्रेस में भेजने हेतु तैयार है।

प्रशिक्षण

+ 2 स्तर पर विद्यालयी शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान में संवर्धन पाठ्यक्रम

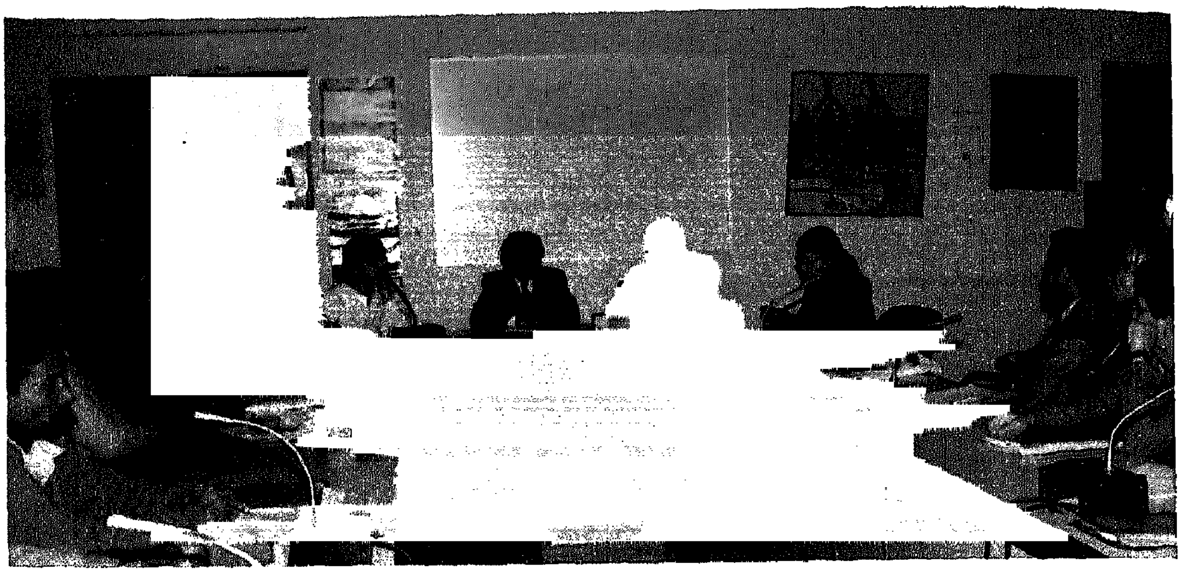
इस पाठ्यक्रम की विषयवस्तु आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण और 22 से 23 सितम्बर 1999 में आयोजित कार्यशाला के आधार पर तैयार की गई थी। दिल्ली और संबद्ध राज्यों में सी.बी.एस.ई. से संबद्ध विद्यालयों के +2 के स्तर पर मनोविज्ञान पढ़ा रहे 20 विद्यालयी शिक्षकों के लिए नई दिल्ली में 27 मार्च से 1 अप्रैल 2000 तक संवर्द्धन पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था– इस क्षेत्र में हुए नवीन विकासों, मनोविज्ञान में देशीकरण के महत्व, अधिक प्रभावी शिक्षण तकनीकों की खोज, मनोविज्ञान में भविष्य में जीविकोपार्जन के विभिन्न आयामों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना।

मार्गदर्शन और परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम

नौ महीने के इस स्नातकोत्तर डिप्लोमा का उद्देश्य है– केन्द्र, राज्य और स्कूल स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं में व्यावसायिक परामर्शदाता तैयार करना। 1999-2000 सत्र के दौरान कुल 31 प्रशिक्षणार्थी-3 राज्यों से, 1 केन्या से और 2 तिब्बत से प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में गहन सिद्धान्त और व्यवहार कार्य के साथ-साथ विद्यालय में सप्ताह में एक बार का अभ्यास भी शामिल है। प्रशिक्षणार्थी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को संचालित करता है। विद्यार्थियों को जीविका हेतु परामर्श देता है और विद्यालयों में जीविका सम्मेलन आयोजित करता है। कार्यशालाएँ आयोजित करके विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यान के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान में वृद्धि की जाती है। इसी तरह का एक पाँच- दिवसीय कार्यक्रम जीवन विज्ञान अकादमी, महरौली, नई दिल्ली में ध्यान और योग पर होता है। इसके अलावा मार्गदर्शन और परामर्श के क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न संस्थाओं और अभिकरणों के कार्यों से परिचित कराने के लिए स्थानीय और शैक्षिक यात्राएँ भी आयोजित की गईं।

राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मार्गदर्शन कर्मियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

राज्य/ज़िला स्तर पर मार्गदर्शन और परामर्शकारी सेवाओं के संगठनों के लिए ज़िम्मेदार कर्मियों को अद्यतन जानकारी देना इस पाँच दिवसीय पाठ्यक्रम का उद्देश्य था। स्टेट ब्यूरो ऑफ गाइडेन्स एण्ड काउन्सलिंग और राज्य स्तर की दूसरी एजेन्सियों द्वारा किए गए एक आवश्यकता सर्वेक्षण के आधार पर तीन पाठ्यक्रम तैयार किए गए। मानसिक स्वास्थ्य, एड्स, ड्रग्स, परिवार-परामर्श, सामाजिक कौशल



राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मार्गदर्शन कर्मियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का समापन-सत्र।

इत्यादि क्षेत्रों में कार्य कर रहे विशेषज्ञों के द्वारा विचार-विमर्श किया गया। पूरे भारत से 36 प्रतिभागियों ने जिनमें से अधिकांश व्यावसायिक प्रशिक्षित परामर्शदाता थे, 10 से 14 जनवरी 2000 तक इस पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया।

मार्गदर्शन और परामर्श में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय व सार्क तथा एशिया-अफ्रीका के अन्य पड़ोसी देशों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श के क्षेत्र में एन.सी.ई.आर.टी. ने एक कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया। विभिन्न दूतावासों के कर्मियों से व्यक्तिगत विचार-विमर्श के द्वारा, विभिन्न सेवार्थी देशों को लिखकर व साहित्य का सर्वेक्षण कर और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ अनेक बैठकें कर इस प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन किया गया। सर्वेक्षण संकेत देता है कि इन विकासशील देशों में प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता थी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व प्रासंगिक मुद्दों की संख्या का पता लगाने के लिए सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से विचार-विमर्श करके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या के विकास की तैयारी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के क्रम में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण लाइब्रेरी

इस परीक्षण लाइब्रेरी में विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप लगभग 2000 भारतीय और विदेशी परीक्षण हैं। इस न्यासी में ये परीक्षण नमूने के रूप में रखे गए हैं। दर्शकों के अनुरोध पर लाइब्रेरी सुविधाओं में विस्तार किया गया। लगभग 25 नए परीक्षण लाइब्रेरी में शामिल किए गए।

कैरियर सूचना कक्ष

मार्गदर्शन प्रयोगशाला के एक अंग के रूप में कैरियर सूचना कक्ष देश में विभिन्न स्रोतों से एकत्रित जीविका संबंधी सूचना सामग्री रखते हैं। यह सामग्री प्रशिक्षणार्थियों, मार्गदर्शन और परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संकायों के साथ-साथ मार्गदर्शन और परामर्श के विभिन्न क्षेत्रों के दूसरे कार्यक्रमों के लिए भी उपयोगी है।

वर्ष के दौरान जीविका और व्यवसाय के अपनाए गए विभिन्न मार्गों पर अद्यतन प्रकाशित सामग्री और वीडियो कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए कई संगठनों से पत्राचार किया गया। जीविका से संबंधित विषयों पर लोगों को वैयक्तिक रूप से अथवा पत्राचार के द्वारा कुछ सलाह दी गई।

मार्गदर्शन प्रयोगशाला

मार्गदर्शन प्रयोगशाला के लिए सामग्री को एकत्र करने और उसके विकास का कार्यक्रम जारी है। विशेष रूप से

मार्गदर्शन और परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संकाय और प्रशिक्षणार्थियों ने सामग्री और प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की गई अन्य सुविधाओं का उपयोग किया।

मूल्य शिक्षा पर विस्तृत ग्रंथ-सूची

परियोजना का उद्देश्य भारत में मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों को संकलित करना है। इसमें विस्तृत क्षेत्रों को समाहित करने के लिए एन.आई.ई., सी.आई.ई.टी. सहित चारों क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों–अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में नोडल-केन्द्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केन्द्र से दो संकाय सदस्य परियोजना पर कार्य कर रहे हैं। उद्धरण और संकलन के लिए प्रारूप विकसित करने हेतु, विभिन्न उपलब्ध प्रारूपों के आधार पर साहित्य पुनरीक्षण कर लिया गया है। परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संकलन के लिए दिशा निर्देश भी विकसित किए गए।

उद्धरण और संकलन के लिए प्रारूप को अन्तिम रूप प्रदान करने हेतु 22 से 23 मार्च 2000 को एक नोडल-संकाय की बैठक आयोजित की गई। देश के विस्तृत क्षेत्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तरीका खोज लिया गया है। यह 14 महीने की परियोजना है। आशा की जाती है कि मूल्य शिक्षा पर किए गए कार्यों की संकलित ग्रंथ सूची को मुद्रित और साथ ही साथ आडियो-वीडियो मीडिया रूप में भी तैयार किया जाएगा।

मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं की नेटवर्किंग

इस परियोजना का उद्देश्य मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों की पहचान करना और इन संगठनों पर आधारित एक आँकड़ा विकसित करना है। इन संगठनों से संपर्क भविष्य की कार्रवाइयों से संबंधित कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति और सूचनाओं के विनिमय के लिए अवसर प्रदान करेंगे। एक उभय मंच पर सूचनाओं का आदान-प्रदान मूल्य-उन्मुख शिक्षा के लिए सहयोगी प्रयासों हेतु माहौल तैयार करेगा। 250 संगठनों के पते इकट्ठे किए जा चुके हैं। उनसे सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इन संगठनों के संपर्क में रहकर उनकी गतिविधियों की एक निर्देशिका विकसित करना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय मूल्य-शिक्षा संसाधन केन्द्र

राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है जोकि मूल्यों की सामग्रियों के राष्ट्रीय निधि सदन के रूप में कार्य करेगा। मूल्य-परिवर्तन, मूल्यों का शिक्षण व अधिगम, जनजाति समाजों के मूल्य, मूल्यों की भारतीय अवधारणा, विभिन्न धर्मों में मूल्य का शिक्षण इत्यादि सरीखा शिक्षा में मूल्यों से संबंधित विभिन्न प्रकार का साहित्य इसमें शामिल है।

परामर्श

एन.सी.ई.आर.टी. ने शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में परामर्श और संसाधन सहयोग तथा डी.आर.डी.ओ., रक्षा मंत्रालय, यू.जी.सी., विश्वविद्यालयों, विद्यालयों तथा एन.जी.ओ. जैसे विभिन्न संगठनों को दिशा निर्देश और परामर्श प्रदान किया। कुछ संकाय सदस्यों ने विम्हैंस (वी.आई.एम.एच.ए.एन.एस.) द्वारा 'रोल्स एण्ड फंक्शन्स ऑफ प्रोफेशनल काउन्सलर्स' पर आयोजित संगोष्ठी 'एक्सप्रेशन्स-99' में भी भाग लिया। सी.आई.ई.टी., एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा दूरदर्शन पर 'समाधान' कार्यक्रम के अंतर्गत 'आत्मविश्वास निर्माण' पर एक वार्ता प्रसारित की गई।

शैक्षिक मनोविज्ञान में क्षेत्रीय निवेश

मार्गदर्शन और परामर्श में स्नातकोत्तर डिलोमा के लिए एक पाठ्यक्रम भी विकसित किया गया।

1999-2000 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- स्कूलिंग इन मीरांबिका- ए केस स्टडी (अनुलिपि)
- फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन इन मीरांबिका- ए केस स्टडी
- ऐस्थेटिक्स इन एजुकेशन: ए साइकोलाजी करिक्युलम इन एलीमेंटरी टीचर एजुकेशन
- ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलाजी करिक्युलम इन एलीमेंटरी टीचर एजुकेशन (अनुलिपि)।

कार्य-प्रभाविता बढ़ाने में स्वायत्तता के प्रभाव का पता लगाने के लिए दिल्ली की स्वायत्त एस.सी.ई.आर.टी. का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि स्वायत्तशासी स्तर ने संस्था के कार्यों के सम्यक और व्यवस्थित संचालन में सुविधा प्रदान की। संस्थान के स्वायत्तशासी स्तर प्राप्त करने के पश्चात एस.सी.ई.आर.टी. के कार्य के क्षेत्रों में विस्तार हुआ। आर्थिक सहायता में वृद्धि ने एस.सी.ई.आर.टी. को विस्तृत सुविधाओं और संसाधनों के साथ कार्य करने के लिए प्रारम्भिक पहल का आत्मविश्वास दिया तथा दृष्टिकोण और कार्य की स्वतन्त्रता के साथ मानव और सामग्री दोनों में उच्च गुणवत्तायुक्त संसाधनों की प्राप्ति के योग्य बनाया।

विद्यालयी शिक्षा के सुधार में अध्यापक शिक्षा एक पाठ्यचर्यात्मक निवेश है। इस क्षेत्र के कार्यक्रम और कार्यकलाप सामान्यतया ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) और प्राथमिक अध्यापकों के विशेष अभिविन्यास के लिए सॉप्ट के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित राज्यों में क्षमता विकसित करने, अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जैसे ज़िला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), अध्यापक शिक्षा के कालेज (सी.टी.ई.), शिक्षा के उच्च अध्ययन संस्थानों (आई.ए.एस.ई.) तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों को शैक्षिक समर्थन देने पर केंद्रित हैं। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए, एन.सी.ई.आर.टी. के मुख्य घटक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.) के अंतर्गत अध्यापक शिक्षा और विस्तार विभाग (डी.टी.ई.ई.), नई दिल्ली और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान- अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूर और शिलांग अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार संबंधी कार्यों में संलग्न हैं। 1999-2000 के दौरान अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

अनुसंधान

प्राथमिक अध्यापकों की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं के संबंध में उनकी अध्यापन प्रभविष्णुता

अध्यापक प्रभविष्णुता और अध्यापकों की शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं के मध्य संबंध की पहचान और विभिन्न शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यताओं की संहतियों से अध्यापक प्रभविष्णुता की तुलना इस अध्ययन का उद्देश्य है। अध्ययन के लिए विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले दिल्ली नगर निगम के 249 प्राथमिक विद्यालय अध्यापकों को बानगी के तौर पर चुना गया। अध्ययन के लिए तैयार किए गए उपकरणों में (1) प्रधानाध्यापक अवबोधन सूची, (2) अध्यापक की स्व-अवबोधन सूची, (3) हिंदी, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन-1 (समाज अध्ययन) और (3) विज्ञान में उपलब्धि पत्र समाविष्ट किए गए। शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं पर आधारित अध्यापकों के 10 समूह बनाए गए।

यह अध्ययन उद्घाटित करता है कि विभिन्न शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं वाले शिक्षक जैसा कि उनके प्रधानाध्यापकों द्वारा और उनके अवबोधन से निर्णित हुआ, प्रभविष्णुता में एक दूसरे से भिन्न हैं, यद्यपि बहुत अर्थ पूर्ण रूप में नहीं। वे अध्यापक जो योग्यताओं की अन्य संहति रखते हैं उनकी अपेक्षा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमाधारी स्नातक, विज्ञान शिक्षक और बी.एड. की डिग्री वाले विज्ञान के स्नातकोत्तर शिक्षक उच्च स्व-अवबोधन रखते हैं।

यह अध्ययन यह भी उद्घाटित करता है कि अध्यापकों का वस्तुज्ञान विज्ञान और गणित में उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यताओं के अनुरूप भिन्न-भिन्न था। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए बी.एससी./बी.टी.सी./ई.टी.ई. अध्यापक अधिक प्रभावी पाए गए।

महाराष्ट्र में स्मार्ट-पी.टी. के अन्तर्गत शिक्षक-प्रशिक्षण की गुणवत्ता का निर्धारण

अध्ययन का उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के 'स्टेटवाइड मैसिव एण्ड रिगरस ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी टीचर्स' (स्मार्ट-पी.टी.) के अंतर्गत विभिन्न निवेशों की उपयुक्तता की जाँच करना और प्रतिभागियों की दक्षता तथा ज्ञान-प्राप्ति के संदर्भ में इसकी गुणवत्ता का अध्ययन करना था। यह अध्ययन यह भी उद्घाटित करता है कि निरीक्षित चार प्रशिक्षण केन्द्रों के पास श्यामपट, शौचालय, व्याख्यान कक्ष, तकनीकी सामग्री और अधिगम सामग्री की समय पर उपलब्धता जैसी सुविधाएँ पहले दिन ही पर्याप्त थीं, यद्यपि पुस्तकालय की सुविधा अपर्याप्त थी। प्रशिक्षण के दौरान लिंग, संस्था, निवास-स्थान इत्यादि पर ध्यान दिए बिना अध्यापकों ने सार्थक ज्ञानोपलब्धि की।

स्वायत्तशासी एस.सी.ई.आर.टी., दिल्ली का केस अध्ययन

कार्य-प्रभाविता बढ़ाने में स्वायत्तता के प्रभाव का पता लगाने के लिए दिल्ली की स्वायत्त एस.सी.ई.आर.टी. का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि स्वायत्तशासी स्तर ने संस्था के कार्यों के सम्यक और व्यवस्थित संचालन में सुविधा प्रदान की। संस्थान के स्वायत्तशासी स्तर प्राप्त करने के पश्चात एस.सी.ई.आर.टी. के कार्य के क्षेत्रों में विस्तार हुआ। आर्थिक सहायता में

वृद्धि ने एस.सी.ई.आर.टी. को विस्तृत सुविधाओं और संसाधनों के साथ कार्य करने के लिए प्रारम्भिक पहल, दृष्टिकोण और कार्य की स्वतन्त्रता के साथ मानव और सामग्री दोनों में उच्च गुणवत्तायुक्त संसाधनों की प्राप्ति के योग्य बनाया। यद्यपि एस.सी.ई.आर.टी. के संकाय सदस्य अब भी नौकरी से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनके उपयुक्त निदान की आवश्यकता है।

एस.सी.ई.आर.टीज़./एस.आई.ईज़. की स्थिति

विभागीय ढाँचा, भौतिक सुविधाएँ, स्टाफ विवरण, कार्य योजना और कार्यान्वयन के संदर्भ में एस.सी.ई.आर.टीज़./ एस.आई.ईज़. की मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए यह अध्ययन किया गया। इस अध्ययन का दूसरा उद्देश्य इन संस्थानों के सुचारू रूप से कार्यकलापों के संचालन में बाधा डालने वाले कारकों की जानकारी करना और बाधाओं को निष्प्रभावित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने का सुझाव देना था। आंकड़ा इकट्ठा और विश्लेषित कर लिया गया है। मसौदा रिपोर्ट तैयार होने के क्रम में है।

डाइट की योजना का कार्य-संचालन : एक सर्वेक्षण

डाइट को अपनी भूमिका प्रभावकारी ढंग से निभाने में मदद के उद्देश्य से अपेक्षित कदम के सुझाव देने की दृष्टि से स्थिति और कार्यकलापों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन जारी है। 156 डाइट और 2203 शिक्षक-प्रशिक्षकों से आंकड़ा प्राप्त हुआ। आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई। सर्वेक्षण से पता चला कि विभिन्न राज्यों में सेवा-पूर्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विभिन्न नाम थे। यह देखा गया कि अधिकांश डाइट में सभी सात शाखाएँ जो मूल घटक हैं, सुचारू रूप से कार्यरत नहीं थीं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में पद रिक्त थे, यद्यपि शिक्षक-प्रशिक्षक पर्याप्त योग्यता की स्थिति में थे। इन शिक्षक-प्रशिक्षकों को उनके व्यावसायिक विकास के लिए अनवरत निवेश जैसे प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता है। डाइट ने अपनी कार्यक्रम सलाहकार समिति बनाई है और 'एक्शन रिसर्च' के लिए प्रयोग क्षेत्रों की पहचान कर ली है।

विज्ञान-शिक्षण के रचनात्मक उपागम

इस परियोजना में प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान की रचनात्मक उपयोगिता की जानकारी के लिए अध्यापकों को विद्यालय आधारित प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए जो प्रक्रियाएँ अपनायी गईं, वे थीं- वास्तविक कक्षा अधिगम स्थिति का प्रेक्षण, रचनात्मकता के प्रयोग द्वारा अध्यापकों का अध्यापन कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, शिक्षकों को इसका प्रदर्शन और कक्षा शिक्षण पर प्रशिक्षण के प्रभाव का अध्ययन।

अध्ययन से यह पता चलता है कि इस विधि से प्रशिक्षित अध्यापकों को उपलब्ध कराकर हमारे स्कूलों में रचनात्मकता को आसानी से कार्यान्वित किया जा सकता है। अध्यापकों को बताया गया कि वे विद्यार्थियों के साथ उनके पाठ विस्तार, क्रियाकलापों में उनकी मदद और अपने निष्कर्षों तक पहुँचने में इस अवधारणा का उपयोग करें। अध्यापक इस बात से सहमत थे कि रचनात्मकता के साथ शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को प्रेरित करता है, शिक्षक को पूरी विषयवस्तु समझने में मदद मिलती है और कक्षा के अधिगम वातावरण में वृद्धि करता है। यह उपागम शिक्षकों से कुछ नई अपेक्षा रखता है, जैसे- विषयवस्तु का सम्यक ज्ञान और शिक्षा शास्त्री दक्षताओं का विकास। यह विद्यार्थियों की रटकर सीखने की आदत को कम करता है।

अध्यापक मूल्यांकन की सहभागिता और आंकड़ा आधारित प्रणाली का ढाँचा

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उत्तरदायी मानकों को बल प्रदान के लिए एन.सी.ई.आर.टी. ने शिक्षक मूल्यांकन के लिए सहयोगी और आंकड़ा आधारित प्रणाली का ढाँचा विकसित किया। इस ढाँचे में अध्यापक का आत्म-मूल्यांकन और प्रत्येक अध्यापक के शैक्षिक और सह-पाठ्यचर्यात्मक गतिविधियों तथा योगदानों के बारे में एकत्रित आंकड़े के आधार पर प्रधानाचार्य के मूल्यांकन को भी शामिल किया जाता है। इस ढाँचे के अंतर्गत यह भी सुझाव है कि एक मूल्यांकन साक्षात्कार भी इसमें शामिल किया जाए ताकि जिस अध्यापक का मूल्यांकन किया जा रहा है उसे अपने महत्वपूर्ण योगदानों को प्रस्तुत करने का मौका मिल सके। प्रयोगात्मक तौर पर इसे चार प्रायोगिक

स्कूलों और तीन जवाहर नवोदय विद्यालयों में लागू करने का प्रयास किया गया। जिन स्कूलों में यह प्रयोग किया गया उन्होंने इस ढाँचे के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण : एक व्यावहारिक अध्ययन

इस अध्ययन का उद्देश्य क्षेत्र में मौजूदा मानव शक्ति और शिक्षक शिक्षा से जुड़ी हुई आधारभूत सुविधाओं का पता लगाना तथा इन राज्यों में सेवाकालीन प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के आयोजन की विशिष्ट आवश्यकताओं का पता लगाना है।

इस अध्ययन के लिए प्रश्नावलियों, उत्तर-पूर्वी राज्यों के क्षेत्र-दौरों और अन्य दूसरे स्रोतों से आंकड़ा इकट्ठा किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि खराब यातायात, प्रतिभागी के लिए आवासीय सुविधा की कमी, आधारभूत सुविधाओं की कमी, जैसे-सभागार, दृश्य-श्रव्य सामग्री और पठन सामग्री इत्यादि समस्याओं के कारण इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या कम रही। आर्थिक बंधनों और विभिन्न विषय क्षेत्रों के असक्षम संसाधन व्यक्तियों ने भी सेवाकालीन प्रशिक्षण की गुणवत्ता को प्रभावित किया। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए किए गए इस अध्ययन ने निम्नलिखित आवश्यकताओं पर बल दिया: (1) संदर्भ संस्थानों में खर्च के अधिक उदार नियमों के साथ आधारभूत सुविधाओं में संवर्द्धन हेतु विशेष योजना, (2) लक्ष्य समूह, प्रशिक्षण तकनीक, आवश्यकता-निर्धारण, प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या और अवधि इत्यादि को स्पष्ट करती हुई माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों के लिए विशेष अभिविन्यास योजना (एस.ओ.एस.एस.टी.)।

विकास

भारत में अध्यापक शिक्षा के पचास वर्ष : मूल्यांकन और भावी परिप्रेक्ष्य

अध्यापक शिक्षा के विकास की प्रवृत्ति और मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से इस परियोजना अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: (1) सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रकारों और स्तरों के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करना, (2) सेवारत शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करना, (3) आज़ादी के बाद शुरू किए गए नवाचारी कार्यक्रमों और कार्यान्वित कार्यक्रमों की समीक्षा करना, (4) अध्यापक शिक्षा के पुनर्गठन की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत स्थापित अध्यापक शिक्षा संस्थानों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना और (5) अध्यापक शिक्षा के विकास में विभिन्न संस्थानों और संगठनों की भूमिकाओं की समीक्षा करना। अध्यापक शिक्षा के एकीकृत विषयों सहित विभिन्न आयामों को लेकर 11 अध्यायों के विषयों की अंतिम रूप से पहचान की गई। विशेषज्ञ दल और एन.सी.ई.आर.टी. से चुनिंदा लेखकों की पहचान कर ली गई है। अध्याय लिखने का कार्य प्रगति पर है जो अंतिम प्रलेखन और प्रकाशन के लिए संपादित किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए स्व-अधिगम सामग्री

इग्नू ने प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक सेवाकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए स्व-अधिगम अनुदेशी सामग्री का विकास कर लिया गया है। इस अनुदेशी सामग्री में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा विकास और कार्य व्यवहार, जैसे-बड़े आकार की कक्षाओं में अध्यापन, सहकारी अधिगम विधियाँ, बाल-केन्द्रित और क्रियाकलाप आधारित खेल विधि शामिल हैं। इस सामग्री में सतत व्यापक मूल्यांकन के माड्यूल्स, पाठयोजना, अधिगम का मनोविज्ञान आदि भी शामिल हैं। आरंभ में यह डिप्लोमा कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों, जहाँ अधिकांश संख्या में अप्रशिक्षित अध्यापक हैं, के सेवारत अध्यापकों के लिए दूरवर्ती शिक्षा माध्यम के रूप में शुरू किया जाएगा।

भारतीय शिक्षा का विश्वकोश

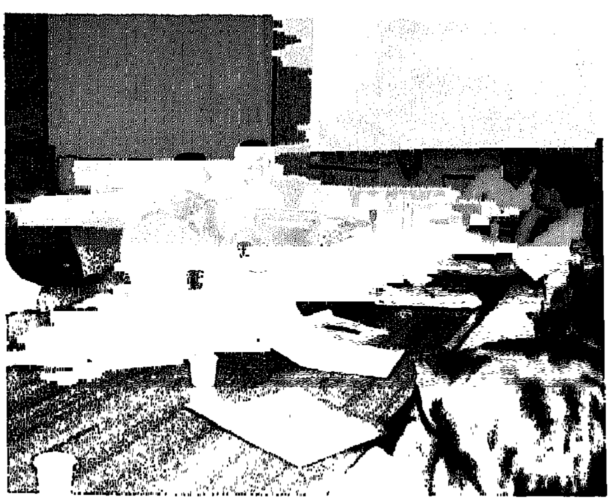
एन.सी.ई.आर.टी. भारतीय शिक्षा के विश्वकोश निर्माण की परियोजना पर कार्य कर रही है, जोकि भारतीय शिक्षा के सभी कालों, सभी स्तरों और सभी दृष्टिकोणों से जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों के लिए ज्ञान और सूचना का एकमात्र

स्रोत होगा। इसमें पाँच तरह की प्रविष्टियाँ शामिल हैं: (1) शैक्षिक विषयवस्तु, (2) शैक्षिक संस्थाएँ, संगठन आदि, (3) शैक्षिक परियोजनाएँ और योजनाएँ, (4) विभिन्न राज्यों में शिक्षा की प्रणाली और (5) शिक्षा की स्पष्ट भारतीय अवधारणा। लगभग 450 प्रविष्टियों के साथ संभावित लेखकों की पहचान कर ली गई है जो विभिन्न प्रविष्टियों पर उच्च व्यावसायिक और विद्वत्तापूर्ण आलेख तैयार कर सकें। सलाहकार समूह की चार बैठकों में लेखकों के नाम और प्रविष्टियों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लिया गया है। लेखकों की पहचान का काम प्रगति पर है।

प्रशिक्षण

डाइट-संकाय का प्रशिक्षण

एन.सी.ई.आर.टी. विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके डाइट के प्रिंसिपल और संकाय सदस्यों की क्षमता का निर्माण कर रही है। इस क्रम में प्रशिक्षण की रूपरेखा और अनुदेशी अधिगम माड्यूल का विकास कर लिया गया है। इस कार्यक्रम में योजना और प्रबन्धन, सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीक का उपयोग, शिक्षार्थी केन्द्रित उपागम इत्यादि सहित प्रशिक्षण में विभिन्न क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है। अनुदेशी सामग्री का क्षेत्र परीक्षण और माड्यूलों का अन्तिम पुनरीक्षण किया गया। एन.आई.ई. परिसर, नई दिल्ली में 27 से 31 दिसम्बर 1999 को डाइट के प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पाँच राज्यों- दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के 25 प्रधानाचार्यों ने प्रतिभागिता की। डाइट की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत सभी संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के क्रम में एक कार्य योजना तैयार की गई। 27 मार्च से 3 अप्रैल 2000 तक डाइट के संकाय के प्रशिक्षण हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 18 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।



जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय-सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

आई.ए.एस.ईज़. के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा में अनुसंधान उन्नयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुसंधान के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के क्रम में 29 मार्च से 1 अप्रैल 2000 तक एन.आई.ई. परिसर, नई दिल्ली में प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान का उन्नयन विषय पर एन.सी.ई.आर.टी. ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली के 27 प्रधानाचार्यों और संस्थाओं के अध्यक्षों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्राथमिक शिक्षा के उभरते हुए सूक्ष्मतर सरोकारों और प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन में अनुसंधान की आवश्यकता पर प्रतिभागियों ने विचार-विमर्श किया। प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों जैसे-प्रवेश-प्रक्रिया, सेवा-पूर्व शिक्षा का पाठ्यक्रम, स्थानबद्ध कार्यक्रम और मूल्यांकन आदि संभावित अनुसंधान विषयवस्तुओं पर विचार-विमर्श हुआ और अनेक अनुसंधान प्रस्ताव विकसित किए गए।

अनुक्रियात्मक टेलीविजन (आई.पी.टी.टी. : आई.टी.वी) के माध्यम से सेवारत प्राथमिक अध्यापकों का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के अन्तर्गत देश भर में प्रशिक्षण साफ्टवेयर के रूप में प्रयोग के पहले इसे मार्गदर्शी परियोजना के रूप में प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण साफ्टवेयर का पूर्व परीक्षण मध्य प्रदेश और गुजरात में किया जा रहा है। इस परियोजना का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन एन.सी.ई.आर.टी. कर रही है। इस परियोजना के सहयोगी संगठन जैसे शिक्षा विभाग और इसके स्वायत्त संगठन, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, यूनेस्को और अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ को विशेष

ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय मुख्य अभिकरण हैं– एस.सी.ई.आर.टी., मध्य प्रदेश और जी.सी.ई.आर.टी., गुजरात। एन.सी.ई.आर.टी. अकादमिक समर्थन देने के अलावा परियोजना का समन्वयन, निगरानी और मूल्यांकन का कार्य भी देख रही है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात के छह ज़िले और 62 प्रखंड तथा मध्य प्रदेश के 10 ज़िले और 124 प्रखंड हैं। इसके लिए 20 अधिगम केन्द्र हैं। इनमें 12 केन्द्र मध्य प्रदेश में हैं और 6 गुजरात में हैं। इस परियोजना के लाभार्थी हैं– अध्यापक, अध्यापक प्रशिक्षक और शिक्षा पर्यवेक्षक। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुँच के लिए ज़िलों और प्रखण्डों का चयन कर लिया गया है। अनुक्रियात्मक गुणवत्ता में सुधार के लिए कम्प्यूटर समर्थन प्रणाली के तहत इस प्रौद्योगिकी के दो तरफा आडियो और वीडियो माध्यम प्रयोग किए जाते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. ने भी अपने संस्थान में डिजीटल अपलिंग अर्थ स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि प्राथमिक स्तर के अधिकांश अध्यापक प्रशिक्षक सीधे प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लाभार्थियों में शमिल हैं–एस.सी.ई.आर.टी. और डाइट के संकाय, वी.ई.सी., अध्यापक और विद्यालय शिक्षा से संबद्ध अन्य कार्मिक। एन.सी.ई.आर.टी. ने अध्यापकों के लिए स्व–अधिगम मुद्रित सामग्री का निर्माण किया है।

एस.सी.ई.आर.टी. संकाय के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम

एन.सी.ई.आर.टी. ने एन.आई.ई. परिसर, नई दिल्ली में 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर 1999 तक एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई. संकाय के लिए एक पाँच–दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। उत्तर–पूर्व और पश्चिमी राज्यों के 14 एस.सी.ई.आर.टीज़./एस.आई.ईज़. के 30 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा और अध्यापक शिक्षा से संबंधित उभरती प्रवृत्तियों और मुद्दों के बारे में भागीदारों को अवगत कराना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनुदेशी सामग्री में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के विषय, प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के सरोकार और मुद्दे, पाठ्यचर्या और अनुदेशी सामग्री का विकास, योजना, आयोजन, निगरानी और सेवाकालीन शिक्षा–प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान की तकनीकें और कक्षा–शिक्षण में उनके निहितार्थ सम्मिलित हैं।

विस्तार

एस.सी.ई.आर.टीज़. और एस.आई.ईज़. के निदेशकों का सम्मेलन

एस.सी.ई.आर.टीज़./एस.आई.ईज़. के निदेशकों का एक सम्मेलन 7–8 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, केरल, हरियाणा, कर्नाटक, नागालैण्ड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के 17 एस.सी.ई.आर.टीज़./एस.आई.ईज़. ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवों और विचारों का आदान–प्रदान करना था। सम्मेलन में विभिन्न एस.सी.ई.आर.टीज़. की महत्वपूर्ण उपलब्धियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर भी विचार–विमर्श किया गया। एन.आई.ई. के विभिन्न विभागों ने विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के पारस्परिक रुचि के सरोकारों पर एस.सी.ई.आर.टीज़./एस.आई.ईज़. के निदेशकों से विचार–विनिमय किया।

विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, अनुभवजन्य मूल्य शिक्षा, एन.सी.ई.आर.टी. और एस.सी.ई. आर.टीज़. के पारस्परिक संबंधों का सुदृढ़ीकरण, केंद्र पोषित योजना अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना के साथ डाइट, सी.टी.ई. व आई.ए.एस.ई. का परिचालन और एस.ओ.पी.टी. आदि पारस्परिक रुचि के सरोकारों पर विभिन्न सत्रों में गहन विचार–विमर्श हुआ। एस.सी.ई.आर.टीज़. के निदेशकों ने तीन समूहों में कार्य किया और एन.सी.ई.आर.टीज़. तथा एस.सी.ई.आर.टीज़. के बीच संबंध सूत्र को मज़बूत बनाने, डाइट, एस.आई.ईज़. और सी.टी.ईज़. में सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, डाइट, सी.टी.ईज़. और आई.ए.एस.ईज़. के संबंध सूत्र आदि पर अपनी संस्तुतियां दीं। इस सम्मेलन की संस्तुतियां या सिफारिशें विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए दीर्घकालीन निहितार्थ रखेंगी।

अध्यापक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा में नवाचार–अखिल भारतीय प्रतियोगिता

अध्यापक प्रशिक्षकों और विद्यालयी अध्यापकों में नव प्रयोगों, अनुसंधानों और नवाचारी कार्य व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. प्रतिवर्ष दो अखिल भारतीय प्रतियोगिताएँ आयोजित करती है। अध्यापक शिक्षा में नवाचार और विद्यालयी शिक्षा में नवाचार नामक इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य है– अध्यापक प्रशिक्षकों और विद्यालय के शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना। इस योजना में शिक्षक-प्रशिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों से नवाचारी आलेख आमंत्रित किए जाते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. पुरस्कार के लिए इन आलेखों का मूल्यांकन विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा किया जाता है। चयनित अध्यापक प्रशिक्षकों को नकद पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर की पहचान के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। एन.सी.ई.आर.टी. इन चयनित अध्यापकों को उनके नवाचारों पर विचार-विमर्श करने और इन नवाचारों की उपयोगिता का क्षेत्र परीक्षण करने का अवसर प्रदान करती है।

पिछले वर्ष के दौरान 15 राज्यों से 71 आलेख प्राप्त हुए। इनमें से एन.सी.ई.आर.टी. पुरस्कार के लिए 27 आलेख- प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा से 19 और माध्यमिक अध्यापक शिक्षा से 8-चुने गए। एन.आई.ई., नई दिल्ली में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में चयनित अध्यापकों ने अपने नवाचारी विचारों पर विचार-विमर्श के लिए प्रतिभागिता की। नवंबर 1999 में अध्यापक प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिए गए।

1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग-स्टेटस ऑफ देयर ऑपरेशनलाइज़ेशन
- इन्स्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेज़ एंड क्लासरूम मैनेजमेंट इन लार्ज साइज्ड क्लासेज़ एट प्राइमरी स्टेज (फोटो प्रति)
- इन्नोवेटिव एक्सपेरिमेन्ट्स एंड प्रैक्टिसेज़ इन एलिमेंटरी टीचर एजुकेशन (पुरस्कृत आलेख 1998-99) (फोटोप्रति)
- इन्नोवेटिव एक्सपेरिमेन्ट्स एंड प्रैक्टिसेज़ इन सेकन्डरी टीचर एजुकेशन (पुरस्कृत आलेख 1998-99) (फोटोप्रति)
- ऑल इंडिया कम्पटीशन ऑन इन्नोवेशंस फॉर सेकेंडरी/सीनियर सेकेंडरी (एस.एस.ई.) टीचर्स 1998-99
- ए स्टडी ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन हरियाणा एंड मध्य प्रदेश (फोटोप्रति)
- एस.सी.ई.आर.टी., दिल्ली-ए केस स्टडी
- पार्टीसिपेटरी एंड डाटाबेस्ड सिस्टम ऑफ टीचर एप्रेज़ल : ए फ्रेमवर्क (फोटोप्रति)
- इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ सेकेंडरी एंड सीनि. सेकेंडरी टीचर्स ऑफ नार्थ-ईस्टर्न रीजन: ए फीज़िबिल्टी स्टडी (फोटोप्रति)
- टीचिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन रिलेशन टु देयर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस (फोटोप्रति)
- ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ सॉप्ट प्रोग्राम इन लखनऊ एंड उन्नाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश
- सर्वे ऑफ इन्नोवेशंस इन टीचर एजुकेशन।

अध्यापक शिक्षा को क्षेत्र स्तरीय योगदान

सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रमुख सरोकारों में सेवापूर्व नवाचारी अध्यापक शिक्षा का विकास और संचालन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत एन.सी.ई.आर.टी.के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में विज्ञान शिक्षा में चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम और प्रारंभिक शिक्षा में विशेषीकरण के साथ एक वर्ष का एम.एड. पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। 1999-2000 के दौरान विज्ञान और मानविकी में प्रायोगिक आधार पर एक नया द्विवर्षीय बी.एड. सेकेंडरी कोर्स प्रारम्भ किया गया। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के विभिन्न सेवापूर्व पाठ्यक्रमों में कुल 1589 छात्र नामांकित किए गए। इस चार वर्षीय एकीकृत बी.एससी.बी.एड/बी.एससी.एड. पाठ्यक्रम का मुख्य ज़ोर गुणवत्ता जैसे-विषययुक्त की सम्यक जानकारी युक्त प्रक्रिया, शिक्षाशास्त्र और सहपाठ्यचर्यात्मक क्रियाकलापों से युक्त अच्छे अध्यापक तैयार करना है। शिक्षक शिक्षा में

एक वर्षीय एम.एड. बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा और अनुसंधान आधारित निवेशों से जुड़े सरोकारों पर पर्याप्त ज़ोर देता है। इस पाठ्यक्रम में शिक्षक समुदाय के बुनियादी शिक्षा के विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कई प्रकार के अनुसंधान अध्ययन किए गए। मार्गदर्शन और परामर्श में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा की रूपरेखा तैयार की गयी है जिसे अगले सत्र से शुरू किया जाएगा।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ने डाइट और एस.सी.ई.आर.टी./एस.आई.ई. के संकाय सदस्यों के लिए निम्नलिखित विषयों पर पांच कार्यक्रम आयोजित किए: (1) हिन्दी, गणित और पर्यावरण अध्ययन 1 और 2 के विषय क्षेत्रों में कार्यकलाप आधारित शिक्षण, (2) सेवाकालीन कार्यक्रमों का आयोजन, (3) शैक्षिक सर्वेक्षणों का संचालन, (4) सेवाकालीन कार्यक्रमों का मूल्यांकन और (5) उच्च अनुदेशी कार्यनीतियाँ और कार्यक्रम प्रबन्धन।

निम्नांकित को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया: (1) संस्था के स्तर पर प्रभावी योजना और विद्यालय के कार्यकलापों की निगरानी पर चण्डीगढ़ के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, (2) प्रशिक्षण-सामग्री के निर्माण के बाद शिक्षक और उनके विद्यालयी निष्पादन के मूल्यांकन पर चण्डीगढ़ के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और एस.आई.ई. के संकाय, (3) विद्यालयों की प्रभावशाली निगरानी के लिए प्राथमिक स्तर पर विषयवस्तु और तरीकों के शिक्षण पर उत्तर प्रदेश के निगरानी कार्यकर्ता। विस्तार भाषण, प्रधानाध्यापकों का अभिविन्यास/सहयोग करने वाले विद्यालयों के अध्यापक जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने अध्यापकों, अध्यापक शिक्षकों, विद्यार्थियों और उन सभी लोगों के लिए जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, 'ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेज़' शीर्षक सामग्री विकसित की।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने डाइट संकाय और मुख्य संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया- (1) माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, (2) जनसंख्या शिक्षा, (3) माध्यमिक स्तर पर अंग्रेज़ी भाषा शिक्षण के नवाचारी तरीके, (4) विकलांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा, (5) माध्यमिक स्तर पर भूगोल (समाज विज्ञान) की मूलभूत दक्षताएँ और (6) कम्प्यूटर साक्षरता।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ने नवोदय विद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए निम्नलिखित दो सेवाकालीन अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित किए: (1) अर्थशास्त्र, भूगोल, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तथा (2) हिन्दी, वाणिज्य व इतिहास। इसके साथ केन्द्रीय विद्यालय के स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए भी इतिहास, भूगोल, हिन्दी और गणित में अभिविन्यास पाठ्यक्रम संचालित किए गए।

संस्थान ने निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित की: (1) विशेष शिक्षा, (2) लेखा शास्त्र-शिक्षण, (3) माध्यमिक स्तर पर मौखिक परीक्षण, (4) प्राथमिक स्तर पर उर्दू शिक्षा की शिक्षण-विधियाँ। विभिन्न आवश्यक क्षेत्रों में अनुदेशी सामग्री का विकास किया गया जैसे (1) मध्य प्रदेश में शैशवकालीन शिक्षा के लिए नमूना क्रियाकलाप योजना, (2) मध्य प्रदेश में शिक्षा प्रक्रिया में लैंगिक-पूर्वाग्रह को दूर करने के तरीके, (3) पर्यावरण आधारित नवाचारी सामग्री और (4) मध्य प्रदेश के लिए +2 पर इतिहास का आदर्श प्रश्न-पत्र।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर ने एस.सी.ई.आर.टी. कर्मियों, डाइट और सी.टी.ईज़. के शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए कार्यात्मक अनुसंधान प्रणालियों पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। एन.सी.टी.ई. के मार्गदर्शन पर शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए पाँच वर्षीय बी.ए., बी.एड/बी.एससी. बी.एड. और एम.एड. कार्यक्रम पुनर्निर्मित किए गए।

संस्थान ने सहयोग करने वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों का 'स्थानबद्ध शिक्षण' पर, डाइट और एस.सी.ई.आर.टी. के संकाय सदस्यों का सतत और व्यापक मूल्यांकन पर सम्मेलन आयोजित किया। इसके साथ संस्थान ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-प्रशिक्षकों के लिए शैक्षिक तकनीक पर अभिविन्यास कार्यक्रम और कम

लागत की शैक्षिक सामग्री के उत्पादन/विकास पर कार्यशाला भी आयोजित की। संस्थान ने पाठ्यचर्या में संस्कृति, परंपरा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तरीकों की पहचान के लिए कार्यशाला आयोजित की और उत्तर पूर्वी राज्यों में पी.एम.ओ.एस.टी. के क्रियान्वयन के लिए सत्रह संसाधन व्यक्तियों का पाँच-दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर ने एरिक की दो परियोजनाओं पर कार्य किया: (1) प्रारंभिक शिक्षक-प्रशिक्षकों में उपलब्ध दक्षता और अपेक्षित दक्षताओं की पहचान के लिए 'डेवलपमेन्ट ऑफ ए प्रोफाइल ऑफ काम्पीटेन्सीज़ एवेलेबल एण्ड ट्रेनिंग डिज़ाइन फॉर दि टीचर एजुकेटर्स एट दि एलिमेंटरी लेवेल' और (2) शिक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्रियान्वयन परिणामों के उद्देश्य से 'ए स्टडी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्पेसलाइज़ेशंस ऑफर्ड बाई दि इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचर एजुकेशन ऑप्टिड हेड बाई स्टूडेंट टीचर एण्ड रिक्वायर्ड बाई दि प्राइमरी एण्ड सेकेण्डरी स्कूल्स इन दि साउथर्न रिजन' अध्ययन का कार्य प्रगति पर है। संस्थान ने केरल और आंध्र प्रदेश के एस.सी.ई. आर.टीज़., डाइटों, सी.टी.ईज़., आई.एस.एस.ईज़. और डी.पी.ई.पी. में कार्यरत संसाधन व्यक्तियों के लिए कम्प्यूटर अनुप्रयोगों पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कक्षा दस के लिए गणित की अध्यापक पुस्तिका और पर्यावरणीय अध्ययन में क्रियाकलाप आधारित अनुदेशी सामग्री तैयार की गई।

दक्षिणी राज्यों में पाठ्यचर्या/पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण और पुनर्संरचना, डाइट संकाय के लिए कार्यात्मक अनुसंधान और नवोदय विद्यालय के गणित के स्नातकोत्तर शिक्षकों को विषयवस्तु और तरीकों में प्रशिक्षण के लिए अकादमिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

एन.सी.टी.ई. पाठ्यचर्यात्मक ढाँचे के मुख्य बिन्दुओं से शिक्षक-प्रशिक्षकों/प्रशासकों को परिचित कराने के लिए मैसूर विश्वविद्यालय के सहयोग से दो वर्षीय बी.एड. (माध्यमिक) पाठ्यक्रम के लिए 'ऑपरेशनलाइज़ेशन ऑफ एन.सी.टी.ई. करीकुलम फ्रेमवर्क' पर सेमिनार आयोजित किया गया।

एन.सी.ई.आर.टी. के क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश के आवासीय संस्थानों के विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर 'पर्यावरण का प्रभाव' पर अध्ययन किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की।

उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग

उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग ने 'इम्पैक्ट स्टडी ऑफ सॉफ्ट प्रोग्राम' अध्ययन प्रारंभ किया जो पूर्ण होने की प्रक्रिया में है। असम के डाइट और एस.सी.ई.आर.टी. संकाय सदस्य सतत और व्यापक मूल्यांकन में प्रशिक्षित किए गए। एस.सी.ई.आर.टी./डाइट संकाय सदस्यों के साथ मिज़ोरम के विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अकादमिक अधिकारियों के लिए 'मिज़ोरम के पाठ्यपुस्तक लेखकों के लिए प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला' का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने कक्षा 8 तक के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यपुस्तक लेखन के मार्गनिर्देशों को विकसित किया। संस्थान ने वर्ष 1999 के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय शिक्षकों की राज्य स्तरीय चयन समिति तथा क्षेत्रीय समिति, नवोदय विद्यालय, शिलांग के अनुबंध/पार्ट टाइम आधार पर पीजीटी/टीजीटी के चयन में मदद की।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ने मा.सं.वि.म./नीपा की ओर से ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के राष्ट्रीय मूल्यांकन का कार्य किया। डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी की प्रस्तावना के रूप में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर में एक क्षेत्रीय गोष्ठी विद्यालय की प्रभविष्णुता पर आयोजित की गई।

प्रायोगिक विद्यालय

प्रायोगिक विद्यालय आर.आई.ईज़. के अभिन्न अंग हैं। ये संस्थान की प्रयोगशालाएँ हैं जहाँ विद्यालय शिक्षा और अध्यापक शिक्षा के नवाचारी प्रयोगों का परीक्षण किया जाता है। आर.आई.ईज़. के सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित अध्यापक विद्यार्थी इन विद्यालयों में व्यावहारिक प्रशिक्षण का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले चार वर्षों से डी.एम. विद्यालयों के प्राथमिक स्तर के अध्यापक क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत दक्षता

वर्ष 1999-2000 के दौरान क्षे.शि. संस्थानों में पाठ्यक्रमानुसार नामांकन

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अजमेर	भोपाल	भुवनेश्वर	मैसूर
1.	बी.एससी.बी.एड.				
	1 वर्ष	82	78	86	82
	2 वर्ष	74	78	85	62
	3 वर्ष	69	80	76	64
	4 वर्ष	59	72	87	49
2.	बी.एड. (माध्यमिक)	40	32	40	40
	विज्ञान				
	मानविकी	40	44	39	40
3.	एम.एड. (प्रारंभिक)	17	11	32	31
	कुल	381	395	445	368

वर्ष 1999-2000 के दौरान क्षे.शि.सं. के परीक्षा परिणाम
उत्तीर्ण प्रतिशत

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	अजमेर	भोपाल	भुवनेश्वर	मैसूर
1.	बी.एससी. बी.एड./ बी.एससी. एड.				
	1 वर्ष	93	92	91	
	2 वर्ष	96	100	97	
	3 वर्ष	100	94	93	
	4 वर्ष	100	100	97	89
2.	एम.एड. (प्रारंभिक)	100	94	86	100

आधारित शिक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। वे बच्चों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं, कक्षा कक्ष आंकड़ों के आधार पर शिक्षण और कार्यनीतियों की योजना बनाते हैं। डी.एम. विद्यालय, सी.बी.एस.ई., नई दिल्ली से संबद्ध हैं और कक्षा 1 से 12 तक अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। ये विद्यालय मार्गदर्शन और परामर्शकारी सेवाएँ भी प्रदान करते हैं और इनमें +2 स्तर पर अलग प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं।

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

क्षे.शि.सं., अजमेर

- कंडक्टिंग ऑन एजुकेशनल सर्वे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल (फोटोप्रति)
- इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शंस इन वोकेशनल एकाउन्टेंसी (फोटोप्रति)

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रायोगिक विद्यालयों में कक्षानुसार नामांकन

कक्षा	अजमेर	भोपाल	भुवनेश्वर	मैसूर
1	30	68	64	68
2	34	68	79	69
3	32	70	77	70
4	34	67	78	70
5	35	68	78	70
6	63	88	112	70
7	58	66	117	70
8	39	65	122	64
9	65	67	125	70
10	51	61	121	67
11	58	55	55	35
12	69	57	95	39
कुल	568	800	1123	762

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रायोगिक विद्यालयों के परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण प्रतिशत

कक्षा	अजमेर	भोपाल	भुवनेश्वर	मैसूर
10	81	93	98	92
12 (विज्ञान)	78	85	97	94
12 (कला)	80	100	97	–
12 (वाणिज्य)	100	84	96	–
12 (व्यावसायिक)	67	92	100	–
12 (मानविकी)	–	–	–	83

- हिन्दी शिक्षण संदर्शिका (फोटोप्रति)
- ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कन्टेन्ट एनरिचमेंट इन एकाउन्टेंसी (+2 अध्यापकों के लिए शैक्षिक धारा) (फोटोप्रति)
- उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय में मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण हेतु नील पत्र प्रश्न पत्र की रूपरेखा निर्माण संदर्भ सामग्री (फोटोप्रति)
- डिज़ाइनिंग ए शॉर्ट टर्म इनसर्विस प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स फॉर सेकण्डरी क्लासिस एंड डेवलपिंग रेलीवेन्ट इंस्ट्रक्शनल मेटीरियल्स (फोटोप्रति)
- ट्रेनिंग ऑफ हैड मास्टर्स इन इफैक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एकाडिमिक फंक्शनिंग इन प्राइमरी स्कूल्स (फोटोप्रति)
- वर्क एक्सपीरियंस/एस.यू.पी.डब्ल्यू. एक्टीविटीज़ (फोटोप्रति)
- डेवेलपमेन्ट ऑफ ट्रेनिंग पैकेज फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट एण्ड सेटिंग ऑफ क्वेसचन पेपर फॉर के.आर.पीज़. इन साइंस एट सेकण्डरी स्टेज ऑफ हरियाणा स्टेट (फोटोप्रति)

- डेवेलपमेन्ट ऑफ कन्टेन्ट एनरिचमेन्ट पैकेज एंड ट्रेनिंग ऑफ के.आर.पीज़. इन कैमिस्ट्री एट +2 लेवल फॉर राजस्थान स्टेट (फोटोप्रति)
- ज्यॉग्राफी ट्रेनिंग ऑफ के.आर.पीज़. इन टीचिंग सोशल साइंसेज़ एट अपर प्राइमरी लेवल (फोटोप्रति)
- बीजगणित शिक्षण एक अभिनव उपागम (फोटोप्रति)
- ट्रेनिंग ऑफ एस.आई.ई. परसोनल ऑन इवैल्युएशन ऑफ इनसर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम (फोटोप्रति)
- मैथेमेटिक्स एट सीनियर सेकण्डरी लेवल (फोटोप्रति)
- क्रियापरक शिक्षण प्रशिक्षण मंजूषा हिंदी गणित कक्षा 1 और 2 (फोटोप्रति)
- ट्रेनिंग पैकेज फॉर सोशल साइंस टीचर्स (ज्यॉग्राफी) (फोटोप्रति)
- ट्रेनिंग पैकेज ऑन डायगनोस्टिक टेस्टिंग इन साइंस एंड मैथेमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल (फोटोप्रति)
- ट्रेनिंग पैकेज फॉर कन्टिन्यूवस इवैल्युएशन एंड वर्क एक्सपीरिएंस फॉर प्राइमरी स्कूल (फोटोप्रति)

क्षे.शि.सं., भोपाल

- डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग पैकेज फॉर डी.आई.ई.टी. फैकल्टी इन दि एरिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन (हिन्दी) (फोटोप्रति)
- इनसर्विस ट्रेनिंग मैटीरियल्स एंड टीचर्स गाइड इन बुक कीपिंग एंड एकाउन्टेंसी फॉर +2 लेवल (हिन्दी) (फोटोप्रति)
- ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दि टीचर्स ऑफ इन्टीग्रेटिड एजुकेशन स्कूल्स इन स्पेशल एजुकेशन (फोटोप्रति)
- ओरियन्टेशन ऑफ की रिसोर्स परसन्स ऑफ गुजरात स्टेट इन सांइस एट सेकण्डरी लेवल (फोटोप्रति)
- ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पॉपुलेशन एजुकेशन फॉर दि डी.आई.ई.टी. परसोनल ऑफ गुजरात स्टेट (फोटोप्रति)
- ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर रिसोर्स परसन्स इन इंटीग्रेटिड एजुकेशन फॉर दि डिसएबल्ड चिल्ड्रन (फोटोप्रति)
- ओरियंटेशन ऑफ की रिसोर्स परसन्स ऑफ गोवा इन एसेंशियल स्किल्स ऑफ ज्यॉग्राफी एट सेकण्डरी लेवल (फोटोप्रति)
- डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइन्स फॉर ओरल टीचिंग फॉर नॉलिज (इंग्लिश) टीचर्स एट सेकण्डरी लेवल (फोटोप्रति)
- आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम्स फॉर प्रोजेक्ट वर्क एंड डेवेलपमेंट ऑफ प्रीपोज़ल इन कामर्स एट दि सीनियर सेकण्डरी लेवल (फोटोप्रति)
- ट्रेनिंग पैकेज इन टीचिंग स्ट्रेटजीस ऑफ उर्दू फॉर टीचर्स एट प्राइमरी लेवल (फोटोप्रति)
- मॉडल क्वेसचन पेपर्स इन हिस्ट्री एट +2 लेवल (फोटोप्रति)
- डेवलपमेन्ट ऑफ स्ट्रेटजीस टु रिमूव जैन्डर बायस इन एजुकेशनल प्रोसेसिस इन प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन इन मध्य प्रदेश (फोटोप्रति)
- हैंडबुक ऑन यूज़ ऑफ कम्प्यूटर फॉर डी आई ई टी फैकल्टी (फोटोप्रति)
- डेवलपमेन्ट ऑफ ट्रेनिंग पैकेज ऑन पेपर सेटिंग इन कैमिस्ट्री ऑफ सीनियर सेकण्डरी लेवल (फोटोप्रति)
- इनवायरनमेन्ट बेस्ड इन्नोवेटिव मैटीरियल-ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजिस (फोटोप्रति)
- डेवलपमेन्ट ऑफ ट्रेनिंग पैकेज ऑन पेपर सेटिंग इन बॉयोलोजी एट सीनियर सेकण्डरी लेवल (फोटोप्रति)
- टूल्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ ब्लॉक रिसोर्स सेन्टर्स एंड क्लस्टर रिसोर्स सेन्टर्स टु डी.पी.ई.पी. डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र (फोटोप्रति)
- टीचर्स ट्रेनिंग पैकेज ऑफ डायगनोस्टिक टेस्टिंग इन मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी क्लासिस (फोटोप्रति)

क्षे.शि.सं., भुवनेश्वर

- डेवलपमेन्ट ऑफ ट्रेनिंग मेथोडोलोजी ऑन कान्सेप्ट सेन्टर्ड टीचिंग एंड एक्विज़िशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेसीफिक स्किल्स इन बॉयोलोजी एट + लेवल (डी टी पी)
- डेवलपमेन्ट ऑफ ए ट्रेनिंग मैथोडोलोजी ऑन कान्सेप्ट सेन्टर्ड टीचिंग एंड एक्विजिशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स इन बॉयोलोजी एट +2 लेवल (फेस I: आइडेंटिफिकेशन) (डी.टी.पी.)
- डेवलपमेन्ट ऑफ रिमीडियल मैटीरियल्स इन मैथेमेटिक्स बेस्ड इन दि एनालिसिस ऑफ कॉमन एरर्स कमिटिड बाई स्टूडेन्ट्स इन दि हायर सेकण्डरी मैथेमेटिक्स इग्ज़ैमिनेशन कंडक्टिड बाई सी.एच. एस.ई. (उड़ीसा) (डी.टी.पी.)

- न्यू डाइमेन्शन ऑफ साइंस करीकुलम इन ऑपरेशनल एप्रोच
- रिव्यू ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्टबुक्स ऑफ क्लासिस-1 एंड 2 ऑफ उड़ीसा एंड डेवलपमेंट ऑफ इग्ज़ेमप्लर मैटीरियल्स (डी टी पी)
- डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज़ ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन इन मैथेमेटिक्स (डी टी पी)
- डायग्नोस्टिक टैस्टिंग एंड रिमीडियल पैकेज इन मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी क्लासिस (डीटीपी)
- इफैक्ट्स ऑफ मास्टरी लर्निंग स्ट्रेटजी ऑन अटेनमेन्ट ऑफ सलेक्टिड कॉमपिटेन्सीज़ इन मैथेमेटिक्स ऑफ क्लासिस 1 और 2 (डी.टी.पी.)
- ओरियन्टेशन ऑफ स्टेट लेवल रिसोर्स पर्सस इन आई.ई.डी.सी. स्कीम फॉर वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा (डी.टी.पी.)
- इफैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पैडागोजिकल रीन्यूअल इन दि कानटेक्स्ट ऑफ डी.पी.ई.पी. इंटरवेन्शन्स ऑफ कांपीटेन्स ऑफ प्राइमरी टीचर्स ऑफ उड़ीसा (डी.टी.पी.)
- डेवलपमेन्ट ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग मैटीरियल्स फॉर प्राइमरी टीचर्स ऑफ उड़ीसा (डी.टी.पी.)
- रिव्यू ऑफ दि बुक, इनटाइटल्ड आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया, समीक्षा
- बिहार के ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का प्राथमिक विद्यालय में हिन्दी शिक्षण सम्बन्धी अभिज्ञान (फोटोप्रति)
- ओरियन्टेशन ऑफ फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ डी.आई.ई.टीज़. लोकेटिड इन बिहार ऑन टीचिंग ऑफ हिन्दी इन प्राइमरी स्कूल्स (डी.टी.पी.)
- डेवलपमेन्ट ऑफ स्ट्रेटजीज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रिमीडिएशन ऑफ एजुकेशनल बेरियर्स ऑफ माइल्ड डिसएबल्ड चिल्ड्रेन इन डी.पी.ई.पी. डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा (डी.टी.पी.)
- एनालिसिस ऑफ साइंस टेक्स्टबुक्स ऑफ उड़ीसा स्टेट फॉर क्लासिस 6, 7 एंड 8 टु आइडेंटिफाई हार्ड कानसेप्ट्स फॉर डेवलपिंग मैटीरियल्स फॉर कान्सेप्ट सेन्टर्ड टीचिंग एंड इनकल्केशन ऑफ साइंटिफिक स्किल्स रिलेटिड टु साइंस अमंग लर्नर्स (डी.टी.पी.)

क्षे.शि.सं., मैसूर

- ट्रेनिंग पैकेज फॉर टीचर एजुकेशन : मल्टी-लेवल टीचिंग इन मल्टी-ग्रेड स्कूल्स (कम्प्यूटर प्रिंट)
- मैनुअल ऑफ लैबोरेट्री एक्सरसाइज़ इन बॉयोलोजी फॉर हायर सेकण्डरी क्लासिस इन पांडिचेरी (कम्प्यूटर प्रिंट)
- ट्रेनिंग ऑफ टीचर एजुकेटर्स इन हैल्थ एंड फिज़ीकल एजुकेशन (कम्प्यूटर प्रिंट)
- ए रिपोर्ट ऑन दि ओरियन्टेशन प्रोग्राम इन एडोलसेन्स एजुकेशन फॉर दि फैकल्टीज़ ऑफ डी.आई.एल.ई.टीज़. एंड सी.टी.ई. ऑफ कर्नाटक एंड केरल (कम्प्यूटर प्रिंट)
- ओरियन्टेशन प्रोग्राम फॉर दि पी.जी.टीज़. इन मैथेमेटिक्स ऑफ नवोदय विद्यालय समिति, न्यू दिल्ली (कम्प्यूटर प्रिंट)
- एनरिचमेन्ट मैटीरियल्स इन मैथेमेटिक्स फॉर सीनियर सैकण्डरी टीचर्स (कम्प्यूटर प्रिंट)
- रिपोर्ट ऑफ पापुलेशन एजुकेशन वीक (कम्प्यूटर प्रिंट)
- ब्रिज कोर्स मैटीरियल्स इन मैथेमेटिक्स फॉर सेकण्डरी स्कूल टीचर्स ऑफ केरल प्रोमोटिड फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल्स (कम्प्यूटर प्रिंट)
- डेवलपमेंट ऑफ क्वेसचन बैंक इन बायोलोजी एट हायर सेकंडरी लेवल ऑफ साउदर्न रीजन (कम्प्यूटर प्रिंट)
- डेवलपमेन्ट ऑफ क्वेसचन बैंक इन फिज़िक्स एट हायर सेकण्डरी लेवल ऑफ साउदर्न रीजन (कम्प्यूटर प्रिंट)
- डेवलपमेन्ट ऑफ डिसआर्डर्स, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इन्टरवेन्शन (मल्टी-डिसीप्लीनेरी अप्रोच) (कम्प्यूटर प्रिंट)
- डेवलपमेन्ट ऑफ ए डिज़ाइन एंड टूल्स फॉर रिसर्च स्टडी ऑन अवेयरनेस एंड एटीच्यूड टु एडोलसन्स एजुकेशन अमंग डी.एम.एस. स्टूडेन्ट्स (कम्प्यूटर प्रिंट)

उत्तर-पूर्वी क्षे.शि.सं., शिलांग

- पर्सपैक्टिव्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन दि नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स (साइक्लोस्टाइल)
- एनुअल रिपोर्ट – अप्रैल 1998–मार्च 1999 (फोटोप्रति)।

विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करना एन.सी.ई.आर.टी. का एक प्रमुख सरोकार रहा है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस. सी.आई.वी.ई.), भोपाल एन.सी.ई.आर.टी. का एक घटक है और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का केन्द्र भी है, जिसका संचालन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और व्यावसायिक शिक्षा की संयुक्त परिषद् की तकनीकी शाखा के रूप में व्यावसायिक शिक्षा और कार्यानुभव कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में सलाह और मदद प्रदान करता है।

विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा में सुधार करना एन.सी.ई.आर.टी. का एक प्रमुख सरोकार रहा है। पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.), भोपाल एन.सी.ई.आर.टी. का एक घटक है और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का केन्द्र भी है, जिसका संचालन यूनेस्को द्वारा किया जाता है। पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को अनुसंधान और विकास तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। यह केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और व्यावसायिक शिक्षा की संयुक्त परिषद् की तकनीकी शाखा के रूप में व्यावसायिक शिक्षा और कार्यानुभव कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में सलाह और मदद प्रदान करता है। पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. व्यावसायिक शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक प्रणाली में पाठ्यचर्या विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मार्गदर्शन, सूचनाओं का प्रचार-प्रसार, विस्तार, अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन तथा परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। यह कार्यक्रमों की गुणवत्ता के मानदंड को ध्यान में रखते हुए प्रमाणपत्रों की समतुल्यता स्थापित करने एवं व्यावसायिक संस्थानों तथा कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने, संबंधित और अन्य संगठनों के स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर व्यावसायिक सूचना प्रणाली और सेवाओं के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ावा देने तथा सूचनाओं के प्रभावशाली प्रसार को सुगम बनाने तथा व्यावसायिक शिक्षा व मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं का सतत् ध्यान रखते हुए कार्य करता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए मुख्य कार्यक्रम/क्रियाकलाप निम्नलिखित हैं:

अनुसंधान

व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में आयोजित निम्नांकित परियोजना अध्ययन जारी हैं:

- कुछ राज्यों में सामान्य बेसिक पाठ्यक्रमों के कार्यान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन
- राज्यों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का निर्देश चिह्न (बेंचमार्क) सर्वेक्षण
- भारत में व्यापार और वाणिज्य आधारित पाठ्यक्रमों के व्यावसायिक शिक्षा के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की स्थिति का अध्ययन
- ग्रामीण तथा नगरीय समाजों में लड़कियों की वृत्तिक आकांक्षाएं और व्यावसायिक शिक्षा
- माध्यमिक व्यावसायिक विद्यालयों में विद्यालय उद्योग संयोजन की स्थापना–क्रियात्मक अनुसंधान
- चुनिंदा राज्यों में व्यावसायिक पाठ्यचर्या और अनुदेशी सामग्री के मानदण्ड और गुणवत्ता का तुलनात्मक अध्ययन
- कृषि में व्यावसायिक अध्यापन अधिगम की स्थिति और प्रभाविता का तुलनात्मक अध्ययन
- महाराष्ट्र के कुछ व्यावसायिक संस्थानों के विद्यालय-उद्योग संयोजन पर केस अध्ययन
- पंजाब में व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के कार्यनिष्पादन पर (ओ.जे.टी.) का प्रभाव
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में गृह विज्ञान के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का महत्व
- 10+2 स्तर के विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशलों के विकास में अध्यापक की भूमिका

विकास

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या का विकास और संशोधन

वनस्पति उपज और प्रबन्धन की पाठ्यचर्या, सामान्य स्वागती, कार्यालय प्रबन्धन, आशुलिपि, मत्स्य पालन, बीज उत्पादन और नेत्र तकनीशियन पाठ्यक्रमों में संशोधन किए गए। कंप्यूटर की सहायता से आरेखण और पांडुलेखन, कम लागत के आवास, समुदाय पर आधारित पुनर्वासन (समुदाय पुनर्वासन सहायक) पर नवीन पाठ्यचर्या और (1) स्वास्थ्य और पैरा-चिकित्सा, (2) गृह विज्ञान के व्यावसायिक पाठ्यचर्या सहित पर्यावरणजन्य घटकों के एकीकरण पर पाठ्यचर्या के एक परिशिष्ट का विकास किया गया। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों

के छात्रों हेतु व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श पर एक पुस्तिका का विकास किया गया। पाइलट-अध्ययन के पश्चात् इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा।

राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता (एन.वी.क्यू.) प्रणाली का विकास

राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली के अंतर्गत बड़ी संख्या में उद्यान विज्ञान, रेशम उत्पादन और विद्युत अभियांत्रिकी में लघु माड्यूल पाठ्यक्रमों का विकास किया गया और फसल उत्पाद एवं भवन रख-रखाव के अंतर्गत विकसित माड्यूलों की समीक्षा की गई।

व्यावसायिक और पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अनुदेशी सामग्री का विकास

व्यावसायिक शिक्षा पर अनुदेशी सामग्री की पंद्रह पांडुलिपियाँ जिनमें अधिकांश कक्षा 11 और 12 की पाठ्यपुस्तकें तथा पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा पर नौ पांडुलिपियों का विकास किया गया। ये सभी प्रकाशनाधीन हैं।

प्रशिक्षण

मुख्य कार्यकर्ताओं के लिए अल्पावधि का प्रशिक्षण

मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, उड़ीसा, दिल्ली तथा जम्मू और कश्मीर के 10 मुख्य कार्यकर्ताओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित संकल्पनात्मक स्पष्टीकरण हेतु अल्पावधि का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यावसायिक विद्यालयों के अनुशिक्षण में सुधार के लिए बारह अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किए गए: क्रय और भण्डारण, घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण, केरल के विद्यालयों में उत्पादन सहित प्रशिक्षण केन्द्रों (पी.टी.सी.) की स्थापना, कम्प्यूटर यूनिक्स प्रणाली प्रशासन, कम्प्यूटर तकनीक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श, उद्यम विकास, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात के जनजातीय कल्याण विभाग के अध्यापकों हेतु व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श, विकलांगों के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रशिक्षक/अध्यापकों हेतु उद्यम विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थानों के अध्यापकों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों में कुल 285 अध्यापक प्रशिक्षित हुए।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के अनुरोध पर विभिन्न राज्यों के केन्द्रीय विद्यालयों के 19 कार्यानुभव अध्यापकों हेतु जातिगत व्यावसायिक पाठ्यक्रम पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

नवसाक्षर जनजातीय/ग्रामीण महिलाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण

केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान (सी.आई.ए.ई.), भोपाल के सहयोग से नवसाक्षर जनजातीय/ग्रामीण महिलाओं हेतु 25 दिन का व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इनमें से 10 प्रतिभागियों के एक समूह को ट्रेक्टर ऑपरेशन, देखभाल और अनुरक्षण तथा बॉयोगैस प्लांट अनुरक्षण नामक दो क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। अन्य 15 प्रतिभागियों ने भी गृह और कृषि कचरे के उपयोग तथा बॉयोगैस प्लांट अनुरक्षण के दो क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

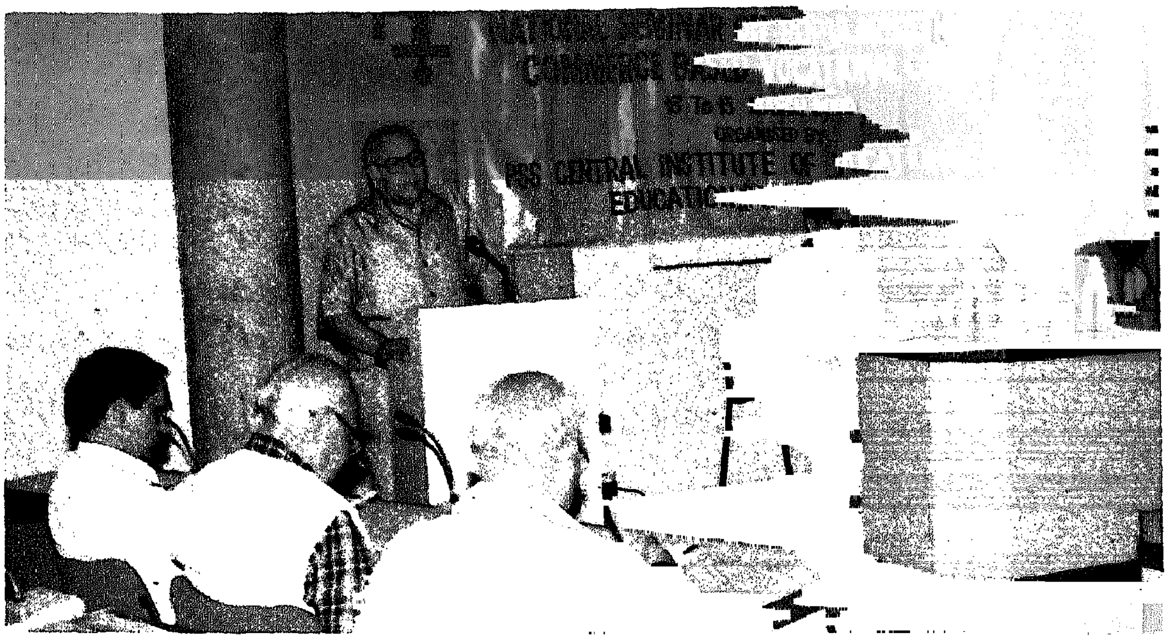
अभिविन्यास कार्यक्रम

वर्ष के दौरान आठ अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें से दो आंध्र प्रदेश और दिल्ली के मुख्य कार्यकर्ताओं हेतु व्यावसायिक शिक्षा पर, एक उत्तर-पूर्व राज्यों हेतु व्यावसायिक मार्गदर्शन और परामर्श पर, एक-एक गैर सरकारी संगठनों और अल्संख्यक वर्ग की शिक्षा और अ.जा./अ.ज.जा. के मुख्य कार्यकर्ताओं से संबंधित संस्थानों तथा हरियाणा और आंध्र प्रदेश के राज्यों के व्यवसाय और वाणिज्य के अध्यापकों हेतु दो अभिविन्यास कार्यक्रम थे।

विस्तार

राष्ट्रीय संगोष्ठी/राष्ट्रीय सम्मेलन/राष्ट्रीय बैठकें

(1) मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन और सुअर पालन, (2) अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, (3) व्यापार



वाणिज्य आधारित व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी।

और वाणिज्य से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रम और (4) यात्रा और पर्यटन प्रबन्धन। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए छह राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ/बैठकें आयोजित की गईं। एक-एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा : परिचर्चा दस्तावेज़ प्रारूप और वी.ई.पी. की स्थिति के मूल्यांकन पर विचार-विमर्श करने हेतु आयोजित की गई। सिओल में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कांग्रेस की प्रस्तावना के रूप में भारतीय परिप्रेक्ष्य में नई सहस्राब्दि के लिए व्यावसायिक शिक्षा नीति के स्तर के निर्धारण हेतु 'शिक्षा का व्यावसायीकरण : नई सहस्राब्दि के लिए परिप्रेक्ष्य' विषय पर आई.आई.टी., नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार

व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यावसायिक शिक्षा के प्रति समर्पित व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने और अन्य व्यक्तियों के बीच उनकी प्रतिष्ठित पहचान के लिए पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. हर साल पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित करती है। यह कार्यक्रम 5 जुलाई को संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम 17-11-1999 को तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण (टी.टी.टी.आई.) के सम्मेलन कक्ष, भोपाल में हुआ। इस अवसर पर निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए:

- सर्वोत्तम उपार्जनकर्ता पुरस्कार (प्रत्येक राज्य से दो-राज्य में उच्चतर माध्यमिक व्यावसायिक शिक्षा के परीक्षाफल के आधार पर)



प्रो. एम.एस. सोढा पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. का सर्वोत्तम उपार्जनकर्ता पुरस्कार प्रदान करते हुए।

- सर्वोत्तम व्यावसायिक अध्यापक पुरस्कार (प्रत्येक राज्य से एक)
- सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार (प्रत्येक राज्य में से एक संस्थान, जो +2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है)
- सर्वोत्तम विद्यालय उद्योग संयोजन पुरस्कार (प्रत्येक राज्य के लिए एक विद्यालय और उद्योग को भी दिया गया)।

पुरस्कृत व्यक्तियों को स्मृति चिह्न और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। छात्रों और अध्यापकों को नकद पुरस्कार भी दिए गए। यह अनुभव किया गया कि ये पुरस्कार देश में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के गुणात्मक विस्तार में योगदान देंगे।

इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन

संस्थान ने अर्द्धवार्षिक पत्रिका का 'इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन' नामक शीर्षक से प्रकाशन प्रारंभ किया है। यह पत्रिका व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को शोध आलेखों, लेखों, समीक्षा और सार लेखन के लिए मंच प्रदान करती है। समीक्षाधीन वर्ष में एक संयुक्त अंक का प्रकाशन हो चुका है और दूसरा संयुक्त अंक प्रकाशनाधीन है।

व्यावसायिक शिक्षा का त्रैमासिक बुलेटिन

संस्थान में व्यावसायिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए एक त्रैमासिक बुलेटिन-'व्यावसायिक शिक्षा' का प्रकाशन करती है। बुलेटिन की प्रतियाँ राज्य के मुख्य कार्यकर्ताओं सहित देश के 4000 विद्यालयों को भेजी जाती हैं। इस वर्ष बुलेटिन के दो अंकों का संयुक्त रूप से प्रकाशन किया गया और दो अंकों (हिन्दी/अंग्रेज़ी अनुवाद) का एक अन्य संयुक्त अंक प्रकाशनाधीन है।

प्रकाशनों की प्रदर्शनियाँ

व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के व्यापक प्रचार के लिए, प्रत्येक वर्ष पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. अपने प्रकाशनों की प्रदर्शनी आयोजित करती है। इस वर्ष प्रकाशनों की दो प्रदर्शनियाँ, एक पी.एस.एस.सी. आई.वी.ई. पुरस्कार समारोह के अवसर पर, टी.टी.टी.आई., भोपाल में और दूसरी राष्ट्रीय सम्मेलन आई.आई.टी., दिल्ली में आयोजित की गईं। संस्थान द्वारा मुख्य कार्यकताओं के कार्यक्रम के अल्पकालीन प्रशिक्षण के दौरान भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

गैर-सरकारी संगठनों का मूल्यांकन

मा.सं.वि. मंत्रालय के संयुक्त मूल्यांकन दल के रूप में, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. ने केन्द्रीय रूप से आयोजित योजना के अंतर्गत नवाचारी व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए मा.सं.वि. मंत्रालय से वित्तीय सहायताप्राप्त बिहार, विशेषकर पटना और वैशाली ज़िलों के गैर-सरकारी संगठनों का मूल्यांकन किया और मा.सं.वि. मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की। मा.सं.वि. मंत्रालय से वित्तीय सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रस्तावों का भी मूल्यांकन किया और मंत्रालय द्वारा अनुदान-सहायता हेतु उनकी उपयुक्तता पर अपने मत मा.सं.वि. मंत्रालय को प्रस्तुत किए।

अन्य क्रियाकलाप

वी.ई.पी. के प्रोत्साहन हेतु राज्य के मुख्य कार्यकर्ताओं से गहन विचार-विमर्श

हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्यों ने शिक्षा मंत्री, राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श करने के लिए दौरा किया। उन्होंने पी.एस.एस.सी. आई.वी.ई. की भूमिका और कार्य, देश में वी.ई.पी. की वर्तमान स्थिति और संबंधित राज्यों की कार्यान्वयन समस्याओं पर वार्तालाप किया।

राज्यों को परामर्शकारी सेवाएँ

संस्थान विचार-विमर्श और दौरों के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर राज्यों/सं.शा. प्रदेशों के लिए परामर्शकारी सेवाएँ उपलब्ध कराता है:

- मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के सलाहकार के साथ बैठक में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने की संभावना की खोज।

- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पर समिति का गठन।
- मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के राज्यों ने सामान्य आधार पाठ्यक्रम (जी.एफ.सी.) के पाठ्यविवरण/पाठ्यचर्या के विकास में सहायता की। असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्, गुवाहाटी कृषि, व्यापार व वाणिज्य, अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी और गृह विज्ञान आदि क्षेत्रों के 8 पाठ्यक्रमों में परिशोधन कर रहा है।
- मध्य प्रदेश सरकार को व्यावसायिक शिक्षा पर उनकी समिति और मिडिल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षण आरम्भ करने की अन्वेषी सम्भावना पर परामर्श भी प्रदान किया।

व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय स्तर का योगदान

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य शीर्षस्थ व्यक्तियों को गृह विज्ञान, कृषि, वाणिज्य और विज्ञान के क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर पर कार्यानुभव/एस.यू.पी.डब्ल्यू. क्रियाकलापों को प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षित किया और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक लेखाशास्त्र की अध्यापन कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का विकास किया।

वर्ष 1999-2000 में प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- क्वार्टर्ली बुलेटिन - वोकेशनल एजुकेशन, खंड-5, अंक 3 और 4 (संयुक्त अंक)
- क्वार्टर्ली बुलेटिन-वोकेशनल एजुकेशन, खंड-6, अंक 1 और 2 (संयुक्त अंक) (मुद्रणाधीन)
- इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, खंड 2, सं. 2 और खंड 3, सं. 1 (संयुक्त अंक)
- इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, खंड 3, सं. 2 और खंड 4, सं. 1 (संयुक्त अंक) (मुद्रणाधीन)
- वोकेशनलाइज़ेशन ऑफ एजुकेशन : पर्सपैक्टिव्स फॉर दि न्यू मिलेनियम- दि चैलेंज

व्यावसायिक पाठ्यचर्या

- कंपीटेंसी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन फूड प्रिज़र्वेशन एंड प्रोसेसिंग (हिन्दी)
- कंपीटेंसी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन इन्शयोरेंस
- कंपीटेंसी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन टैक्सेशन प्रैक्टिस
- गाइडलाइन्स ऑन इस्टैबलिशमेन्ट ऑफ प्रोडक्शन-कम-ट्रेनिंग सेन्टर्स इन दि स्कूल्स रनिंग 10+2 वोकेशनल सेन्टर्स (हिन्दी)
- कंपीटेंसी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन एक्स-रे टैक्नीशियन
- कंपीटेंसी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन मैडिकल लैबोरेट्री टैक्नीशियन
- कंपीटेंसी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन पर्चेज़िंग एंड स्टोर कीपिंग (मुद्रणाधीन)
- कंपीटेंसी बेस्ड वोकेशनल सर्विस करीकुलम ऑन ट्रांसपोर्ट सर्विस मैनेजमेंट (मुद्रणाधीन)
- कंपीटेन्सी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन ट्रेवल एंड टूरिज़्म टैक्नीक (मुद्रणाधीन)
- कंपीटेन्सी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन कमर्शियल गारमेन्ट डिज़ाइनिंग एंड मार्केटिंग (हिन्दी) (मुद्रणाधीन)
- कंपीटेन्सी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन डेयरी टैक्नोलोजी (हिन्दी) (मुद्रणाधीन)
- कंपीटेन्सी बेस्ड वोकेशनल करीकुलम ऑन फिश प्रोसेसिंग टैक्नोलोजी (मुद्रणाधीन)
- लिस्ट ऑफ नॉन-फार्मल एंड फार्मल वोकेशनल कोर्सेज़

अनुदेशी सामग्री

व्यावसायिक शिक्षा

- डेयरी एनीमल मैनेजमेन्ट टैक्स्टबुक कक्षा 11
- फ्रूट प्रोडक्शन टैक्स्टबुक कक्षा 12
- कमर्शियल क्लोथिंग टैक्स्टबुक कक्षा 11
- बेसिक बेकरी टैक्स्टबुक कक्षा 11

- फूड प्रिज़र्वेशन टैक्नीक्स टैक्स्टबुक कक्षा 11 (फोटोप्रति)
- फूड पैकेजिंग टैक्स्टबुक कक्षा 11 (फोटोप्रति)
- एलीमेन्ट्स ऑफ सेल्समैनशिप टैक्स्टबुक कक्षा 11 (फोटोप्रति)
- एलीमेन्ट्स ऑफ मार्केटिंग टैक्स्टबुक कक्षा 11 (फोटोप्रति)
- पब्लिक हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैल्थ स्टैटिस्टिक्स टैक्स्टबुक कक्षा 12 (फोटोप्रति)
- जनरल सेरिकल्चर टैक्स्टबुक कक्षा 11 (फोटोप्रति)
- मॅलबेरि कल्टीवेशन टैक्स्टबुक कक्षा 11 (फोटोप्रति)
- सिल्क वोर्म-सिल्क प्रोडक्शन टैक्नोलोजी टैक्स्टबुक कक्षा 12 (फोटोप्रति)
- सिल्क वोर्म-रिअरिंग टैक्स्टबुक कक्षा 12 (फोटोप्रति)
- एगरी बिज़नेस टैक्स्टबुक कक्षा 12(फोटोप्रति)
- एगरी बिज़नेस प्रैक्टिकल कक्षा 12 (फोटोप्रति)
- मैनुफेक्चर मैटीरियल एंड टैक्नोलोजी टैक्स्टबुक कक्षा 12 (फोटोप्रति)

पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा

- बॉयो-फर्टिलाइज़र (फोटोप्रति)
- मिल्क कन्फेक्शनरी (फोटोप्रति)
- शुगर कन्फेक्शनरी (फोटोप्रति)
- प्रेपरेशन ऑफ ब्रेड एंड अदर यीस्ट लीवंड प्रोडक्ट्स (फोटोप्रति)
- प्रेपरेशन ऑफ बिस्किट्स एंड कुकीज़ (फोटोप्रति)
- प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़िंग कैमिकल्स (फोटोप्रति)
- प्रिज़र्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाई ड्राईंग एंड डीहाइड्रेशन (फोटोप्रति)
- प्रिज़र्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़िंग शुगर (फोटोप्रति)
- प्रिज़र्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़िंग साल्ट, विनेगर एंड ऑयल (फोटोप्रति)
- इंस्ट्रक्शनल मैटीरियल्स ऑन सेरीकल्चर फॉर न्यू-लिटरेट्स (प्रकाशनाधीन)।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य सरोकार आवश्यकताओं का मूल्यांकन, लक्ष्य समूह की रूपरेखा तैयार करना, श्रव्य व दृश्य कार्यक्रमों और अध्यापन सहायक सामग्री की रूपरेखा व विकास, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाओं जैसे आलेख लेखन, मीडिया कार्यक्रमों का निर्माण और तकनीकी प्रचालन में राज्य स्तरीय कार्मिकों का प्रशिक्षण है। यह घटक अनुसंधान और मूल्यांकन, प्रलेखन और प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित क्रियाकलापों को प्रारंभ करने के साथ-साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों और विकास में विभिन्न संगठनों को परामर्श देता है। मीडिया संसाधनों के कंप्यूटर डाटाबेस, अन्योन्यक्रिया संबंधी मल्टीमीडिया सहित श्रव्य और दृश्य कार्यक्रमों के विकास के लिए नई तकनीकों के साथ परीक्षण करता है।

एन सी ई आर टी के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है- विद्यालय स्तर पर देश में शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली के विकास के साथ-साथ शिक्षा में सुधार और प्रसार हेतु विशेषकर जन संचार माध्यम द्वारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक शीर्षस्थ संस्थान के रूप में केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्य सरोकार आवश्यकताओं का मूल्यांकन, लक्ष्य समूह की रूपरेखा तैयार करना, श्रव्य और दृश्य कार्यक्रमों और अध्यापन सहायक सामग्री की रूपरेखा व विकास, शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाओं जैसे आलेख लेखन, मीडिया कार्यक्रमों का निर्माण और तकनीकी प्रचालन में राज्य स्तरीय कार्मिकों का प्रशिक्षण है। यह घटक अनुसंधान और मूल्यांकन, प्रलेखन और प्रचार-प्रसार से सम्बन्धित क्रियाकलापों को प्रारंभ करने के साथ-साथ शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों और विकास में विभिन्न संगठनों को परामर्श देता है। मीडिया संसाधनों के कंप्यूटर डाटाबेस, अन्योन्यक्रिया संबंधी मल्टीमीडिया सहित श्रव्य और दृश्य कार्यक्रमों के विकास के लिए नई तकनीकों के साथ परीक्षण करता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इस क्षेत्र में प्रारम्भ किए गए मुख्य कार्यक्रम और कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम

संस्थान में कक्षा 11 के छात्रों के लिए गणित की श्रृंखला, कला और हस्तकला शिक्षा जिसमें कला का प्रदर्शन, व्यावसायिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, मल्टीग्रेड अध्यापन, खेल-कूद, नवाचारी अध्यापक सृजनात्मक गतिविधियाँ और सांगीतिक वाद्ययंत्रों तथा मानवाधिकारों, बाल अधिकारों और शैशवकालीन शिक्षा में प्रसारण हेतु संस्थागत रूप में 181 ई.टी.वी. कार्यक्रमों का निर्माण किया गया। अन्य महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं 'एक्सप्लोरिंग दि यूनिवर्स' और 'स्पेस साइंस' का निर्माण हो रहा है। 'हेमिस फैस्टीवल' पर एक कार्यक्रम और 'फ्रीडम फाइटर' श्रृंखला संपूर्ण होने वाली है।

आलेख डिज़ाइन

आलेखों का विकास, मीडिया कार्यक्रमों के शीघ्रता से निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस वर्ष विभिन्न श्रृंखलाओं के अन्तर्गत तैयार किए गए ई.टी.वी. आलेख इस प्रकार हैं: 'एक्सप्लोरिंग दि यूनीवर्स' (माध्यमिक स्तर) के अंतर्गत ग्यारह, 'स्पेस साइंस और एक्सप्लोरेशन्स' (माध्यमिक स्तर) के अंतर्गत तीन, दि 'लिविंग प्लानेट-अर्थ' (माध्यमिक स्तर) के अंतर्गत दो, 'एनवायरनमेंट'



एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्मित बच्चों के एक कार्यक्रम में सुविख्यात वैज्ञानिक प्रो. यशपाल।

के अन्तर्गत दो, 'क्रिएटिव मूवमैंट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स' के अन्तर्गत ग्यारह, 'वाटर एंड लाइफ' (प्राथमिक स्तर) शृंखला के अंतर्गत नौ, 'वाटर मोशन' पर तीन, 'ज्योग्राफी सीरीज़' के अन्तर्गत दो, 'होम साइंस' के क्षेत्र में पाँच, 'सेरीकल्चर एंड ड्रिप इरीगेशन' (कृषि विज्ञान) में छह, व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों हेतु व्यवसाय और वाणिज्य क्षेत्र में छह और अध्यापकों की समस्याओं पर प्रतिष्ठित अध्यापक प्रशिक्षकों की चर्चा पर आधारित 'समाधान' शृंखला के अंतर्गत नौ, 'एक-एक कदम आगे' नामक शीर्षक के अंतर्गत गिजुभाई वधेका का 'दिवास्वप्न' पर बारह और 'परफोर्मिंग आर्ट्स' व 'म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स' पर चार-चार आलेखों के प्रारूप तैयार किए गए।

ई.टी.वी. और श्रव्य कार्यक्रमों का प्रसारण

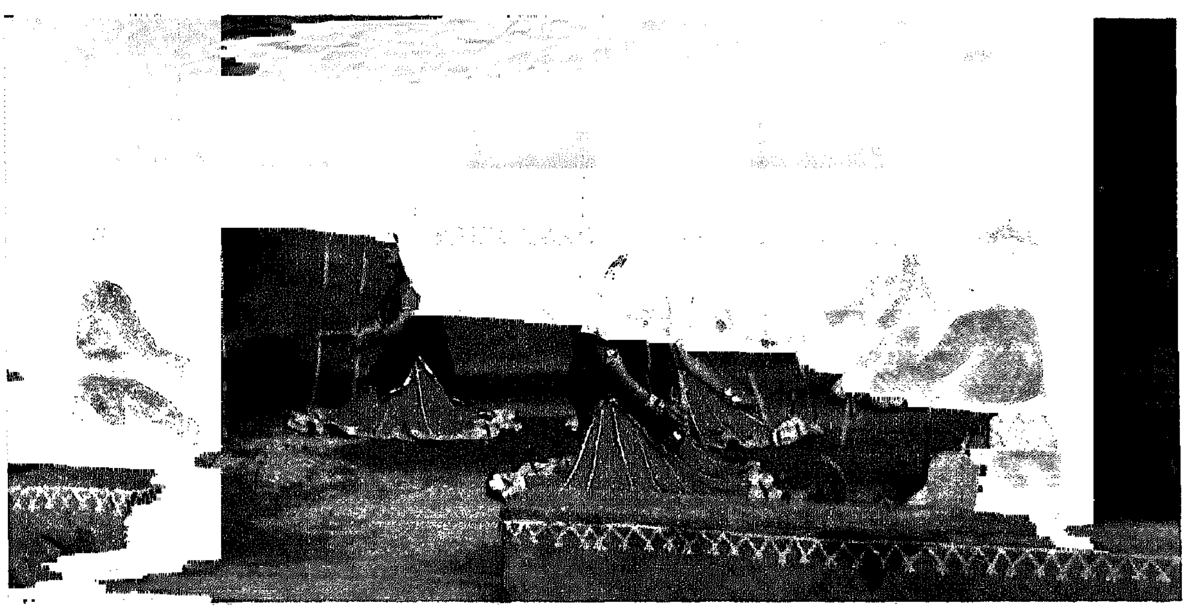
तरंग

सी.आई.ई.टी. माध्यमिक और प्राथमिक स्तर पर छात्रों और अध्यापकों हेतु डी.डी.-1 पर 'तरंग' नामक शीर्षक से एक घंटा और 15 मिनट की शैक्षिक दूरदर्शन सेवा प्रदान कर रही है। विभिन्न वर्गों के लिए टेलीविजन प्रसारण का समय इस प्रकार है:

प्रसारण समय	लक्ष्य समूह
05.45 प्रातः से 06.00 प्रातः	अध्यापक (सप्ताह में सात दिन)
10.00 प्रातः से 10.30 प्रातः	माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक छात्र
10.30 प्रातः से 11.00 प्रातः	प्राथमिक विद्यालयी छात्र

ज्ञान दर्शन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माननीय मंत्रियों द्वारा 26 जनवरी, 2000 को उपग्रह शैक्षिक चैनल 'ज्ञान दर्शन' का परीक्षण प्रसारण किया गया। सी.आई.ई.टी. (एन.सी.ई.आर.टी.) ज्ञान दर्शन के परिचालन में सहभागी है और विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में ई.टी.वी. कार्यक्रमों हेतु एक नोडल एजेंसी है। संस्थान इस शैक्षिक चैनल पर चार घंटों के प्रसारण में से प्रतिदिन 6.30 सायं से 8.00 सायं तक डेढ़ घंटे की अवधि के लिए ई.टी.वी. कार्यक्रमों हेतु सॉफ्टवेयर का योगदान देता है। कुछ ही महीनों में इस चैनल से कार्यक्रमों का प्रसारण संभवतः बढ़ा कर 16 घंटे कर दिया जाएगा, ऐसी योजना बनाई जा रही है।



शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम।

उमंग

सी.आई.ई.टी. (एन.सी.ई.आर.टी.) 'उमंग' शीर्षक से आकाशवाणी पर श्रव्य कार्यक्रमों के लिए 10 मिनट के एक साप्ताहिक स्लॉट को पोषित कर रही है जो 195 आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होता है जबकि गत वर्ष में यह कार्यक्रम 10 आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित होता था। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आकाशवाणी के साथ एम.ओ.यू. को वर्ष 1999 से और आगे बढ़ाकर वर्ष 2001 तक कर दिया गया है। इस वर्ष संस्थान ने प्रसारण और गैर-प्रसारण दोनों के लिए 'राग रस बरसे' की शृंखला के अंतर्गत छोटे बच्चों/अध्यापकों हेतु राग/संगीत के अध्यापन पर 20 कार्यक्रमों सहित 61 श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण किया। निर्माण के क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण कार्य, एक संयुक्त प्रयास के रूप में मा.सं.वि. मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हेतु मिडिल विद्यालय बच्चों के लिए संस्कृत के अध्यापन पर कार्यक्रमों की शृंखला और 'उमंग' शीर्षक के अंतर्गत प्रसारण के लिए श्रव्य कार्यक्रमों के 16 आलेखों का निर्माण है।

प्रशिक्षण और संयोजन

सी.आई.ई.टी. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं विशेषकर आलेखों की रूपरेखा, निर्माण और निर्माणोत्तर तकनीकों (एनीमेशन और ग्राफिक्स, कैमरा प्रचालन और स्टूडियो प्रकाश, संपादन इत्यादि), स्टूडियो से संबंधित कार्य और प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान व्यावसायिक संस्थानों के छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण भी देता है।

सी.आई.ई.टी. ने इस वर्ष दृश्य कार्यक्रमों हेतु अन्-रैखिक संपादन, नवीन विशेषतायुक्त जेनेरेटर के प्रचालन और व्यावहारिक प्रयोग तथा डी एक्स सी-डी 30 पी स्टूडियो कैमरों और डी एफ एस 500 पी वी एफ 500 पी वी डब्ल्यू 800 पी संपादकीय उपकरणों के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक प्रचालन तथा अनुरक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

सी.आई.ई.टी. ने पूर्वोत्तर राज्यों और उड़ीसा को डी.आई.ई.टी. के प्रौद्योगिकी संकाय के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी में 2 सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एस.आई.ई.टी. के कार्मिकों के लिए मल्टीमीडिया पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एस.सी.ई.आर.टी., मणिपुर के लिए ई.टी. और उसके लक्ष्यार्थ पर 3 सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया।

विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से संचार विभाग के स्नातकोत्तर छात्रों और वीडियोग्राफी के स्नातक छात्रों को उनके व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु संयोजित किया गया। राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के स्नातक छात्र सी.आई.ई.टी. के मल्टीमीडिया पैकेज पर एनीमेशन कार्य में सम्मिलित हुए। उन्होंने इस कार्य को इंटर्नशिप के लिए अपनी परियोजनाओं के एक भाग के रूप में लिया।

एस.आई.ई.टी.-सी.आई.ई.टी. समन्वय

क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, देश में सात एस.आई.ई.टीज़. के क्रियाकलापों में समन्वय और मार्गनिर्देशन से संबंधित है। सी.आई.ई.टी.-एस.आई.ई.टीज़. समन्वय समिति की बैठक 14 और 16 मार्च, 2000 को हुई जिसमें सात एस.आई.ई.टीज़. के निदेशकों, उत्पादन प्रभारी, अभियांत्रिकी प्रभारी और संपादकों ने भाग लिया। प्रत्येक एस.आई.ई.टी. ने उपकरण और मानवशक्ति के विवरण की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपायों पर विचार-विमर्श किया।

विस्तार कार्यकलाप

सी.आई.ई.टी. जापान की वीडियो लाइब्रेरी हेतु दक्षिण-पूर्व एशिया का केन्द्र है और सभी एन.एच.के. पुरस्कृत कार्यक्रमों के यू-मेटिक/बैटाकॉम कैसट प्राप्त करता है। संस्थान ने जापान, अमेरिका और जर्मनी में हुए अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक दृश्य समारोहों में भाग लिया तथा इसके ई.टी.वी. कार्यक्रमों में से एक 'रोज़ बदलता कैसे चाँद' (दि चेंजिंग मून) ने एन.एच.के. टोकियो समारोह में 'दि मायडा' पुरस्कार प्राप्त किया। यह शैक्षिक टी.वी. निर्माण में अपने नवीन दृष्टिकोण के लिए शैक्षिक दृश्य कार्यक्रमों की एक सुप्रसिद्ध प्रतियोगिता है। कठपुतलियों द्वारा कही गई कहानी पर आधारित एक अन्य कार्यक्रम को म्यूनिख, जर्मनी में 'वीडियो बार' के लिए चुना गया।

राजकोट, गुजरात में आयोजित 26वीं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में फोटोग्राफी और वीडियो कवरेज प्रदान की गई। 'बडिंग साइंटिस्ट्स' नामक शीर्षक से ई.टी.वी. कार्यक्रम की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई जो चालू वर्ष सहित विभिन्न राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित प्रदर्शों पर आधारित है। चालू वर्ष की प्रदर्शनी में ई.टी.वी. कार्यक्रम निर्मित किया गया जिसका प्रसारण गुजराती और हिंदी दोनों में किया गया।

सह-संस्थानों जैसे राष्ट्रीय खुला विद्यालय और राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के क्रियाकलापों में परामर्श और सहायता उपलब्ध कराई गई। संस्थान ने मूल्य शिक्षा के श्रव्य और दृश्य कार्यक्रमों की सटिप्पण ग्रंथ सूची तैयार करने हेतु शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग को सहयोग दिया।

संस्थान ने दृश्य कार्यक्रम का एक वृहत डाटाबेस विकसित किया है जिसमें सभी तकनीकी विवरण, स्थिर दृश्यों का एक सेट और एक मिनट की शो रील संचित है। सूचना की पुन: प्राप्ति की प्रक्रिया विभिन्न संभावित प्रयोगकर्ताओं जैसे ई.टी.वी. लाइब्रेरी स्टाफ, मीडिया संसाधन प्रभाग, निर्माताओं और शिक्षाविदों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गई। मुद्रण/मल्टीमीडिया फॉर्मेट और प्रकाशनों का समस्त डाटाबेस सी.आई.ई.टी. के बेवसाइट पर है।

मीडिया अनुसंधान और मूल्यांकन

सी.आई.ई.टी. ने डी.डी.-1 और आकाशवाणी से 'तरंग' और 'उमंग' की प्रसारण सेवा का अनुवीक्षण जारी रखा। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी, 2000 से 'ज्ञान दर्शन' नामक शैक्षिक चैनल से प्रसारित कार्यक्रमों का अनुवीक्षण कर रही है। अन्य क्रियाकलापों में सम्मिलित हैं: (1) 'पत्रों के उत्तर' नामक शीर्षक से मासिक कार्यक्रम, जो पत्रों द्वारा बच्चों से उत्तरों के विश्लेषण पर आधारित है, (2) छठे श्रेणी स्तर पर मापन संकल्पना के अध्यापन हेतु दृश्य कार्यक्रमों की अन्योन्यक्रिया का अध्ययन, (3) विभिन्न विषयी क्षेत्रों के अन्तर्गत कम्प्यूटर सहायक अधिगम-एक अधि-विश्लेषक, (4) मीडिया अनुसंधान की समीक्षा शीर्षक-शैक्षिक मीडिया की प्रभावकारिता : एक अनुसंधान सर्वेक्षण।

विशेष परियोजनाएँ

भारत सरकार की शैक्षिक तकनीकी योजना का प्रभाव-अध्ययन

संस्थान द्वारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के राज्यों में चार राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से भारत सरकार की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का प्रभाव-अध्ययन किया गया। प्रायोगिक अध्ययन का उद्देश्य पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्येत्तर क्षेत्रों (सामान्य जागरूकता, जीवन को बल देने वाले कौशल और मूल्य अंतर्निवेशन) में बच्चों की उपलब्धियों पर शैक्षिक टी.वी. और रेडियो सह कैसट प्लेयर (आर.सी.सी.पी.) के प्रभावों का मूल्यांकन करना है एवं इन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता और उपयोगिता पर कार्यकर्ताओं, व्यापक स्तर पर अभिभावक और समाज के ज्ञान को भी जानना है। अपेक्षित अनुसंधान साधन तैयार कर लिए गए हैं और पूर्व-परीक्षण पूर्ण हो गए हैं। अनुवीक्षण सहित आंकड़े और अवलोकन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विश्लेषण हेतु कंप्यूटर में डाल दी गई है।

मल्टीमीडिया सी.डी. आर.ओ.एम. का विकास

कक्षा 6 के विज्ञान हेतु अन्योन्यक्रिया मल्टीमीडिया सी.डी. आर.ओ.एम. (कोर्सवेयर) विकसित किया, जो एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। इसे सी.आई.ई.टी. परिसर में मल्टीमीडिया केन्द्र के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत किया गया। नए मीडिया के इस सर्वप्रथम प्रकाशन को एस.सी.ई.आर.टीज़. अनेक डाइटों, के.वि.सं. इत्यादि द्वारा बखूबी स्वीकार किया गया तथा इसकी और अधिक प्रतिलिपियों के लिए अनुरोध आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की सी.डी. के तेलुगू रूपान्तरण को निकालने की योजना है।

वेबसाइट का सृजन

सी.आई.ई.टी. ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना को, डालने के लिए वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सी.आई.ई.टी. डॉट एन.आई.सी. का सृजन किया है। यह अनेक अन्वेक्षण यंत्रों के साथ पंजीबद्ध है, अन्य संबंधित साइट से संबद्ध है और इसमें कार्यक्रमों विशेषकर ई.टी.वी.

कार्यक्रमों के संबंध में निरंतर अद्यतन सूचना होती है। इस साइट को शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर पूर्ण रूप से विकसित करने और इसमें प्रशिक्षण तथा कान्फ्रेंसिंग के घटकों को समाविष्ट करने का विचार है।

ई.टी.वी. कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार

ग्राफिक्स में एनीमेशन सम्मिलित करके ई.टी.वी. निर्माण की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न ई.टी.वी. कार्यक्रमों हेतु शीर्षकों से लेकर अचल चित्रों तक 2-डी. एनीमेशन, 3-डी. एनीमेशन और सेल एनीमेशन परियोजनाएं प्रारम्भ की गईं। पाँच छात्रों ने सी.आई.ई.टी. के साथ अपनी डिप्लोमा परियोजनाओं पर कार्य किया, जिसमें से दो सेल एनीमेशन परियोजनाएँ थीं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत उन्होंने अपने कार्य के लिए विभिन्न स्तरों पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जिसमें टेस्टिंग, कंपोज़िंग, स्पेशल इफेक्ट्स सम्मिलित हैं। अन्य परियोजनाओं में चित्रों और एनीमेशन के छोटे-छोटे सेक्शनों को सम्मिलित किया गया। वीडियो डाउनलोड कार्ड प्रणाली की सहायता से छाया-चित्रण से चित्रों को स्थानांतरण किया गया और दीवार पर चित्रों और एनीमेशन परियोजना को सीधे वीडियो टेप पर पहुंचाया गया जिससे गुणवत्ता की मात्रा में पर्याप्त सुधार हुआ है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षेत्रीय योगदान

क्षे.शि.सं., भोपाल द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की डी.आई.ई.टी. संकाय के लिए कंप्यूटर साक्षरता पर 10-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके ई.टी. प्रकोष्ठ ने सभी सुविधाएं और परामर्श उपलब्ध कराए।

क्षे.शि.सं., भुवनेश्वर ने प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया।

क्षे.शि.सं., मैसूर ने कर्नाटक के कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए 60 श्रवण कार्यक्रम, कक्षा 3 और 4 के बच्चों के लिए तमिल में 10 श्रवण कैसट विकसित किए। संस्थान ने अंग्रेज़ी में श्रवण कैसटों के विकास के लिए आलेख लेखन प्रारंभ किया और तमिल भाषा में सक्षमता आधारित श्रवण कार्यक्रम प्रारंभ किए। कंप्यूटर अनुप्रयोग प्रयोगशाला की अवसंरचना सुविधा में कुछ अतिरिक्त मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के साथ वृद्धि की गई है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- ऐस्थेटिक एंड टैक्नीकल आस्पैक्ट्स ऑफ साउंड (टंकित)
- ए स्टडी ऑफ दि इंटरएक्टिव वीडियो प्रोग्राम फॉर टीचिंग ऑफ मेजरमेन्ट कान्सैप्ट एट सिक्स्थ ग्रेड लेवल (अनुलिपि)
- कंप्यूटर एसिस्टिड लर्निंग विदिन डिफ्रिंग सब्जैक्ट एरियाज़ (अनुलिपि)
- एफैक्टिवनैस ऑफ एजुकेशनल मीडिया: ए सर्वे ऑफ रिसर्च (अनुलिपि)
- मैथेमेटिक्स टीचिंग एड्स एट दि मिडल एंड हाई स्कूल लेवल
- समाधान एक पहल (अनुलिपि)
- गिजुभाई वधेका के 'दिवास्वप्न' से प्रेरित 'एक-एक कदम आगे' (अनुलिपि)
- डिज़ाइन एंड डेवेलपमेंट ऑफ ई.टी.वी. स्क्रिप्ट्स वोकेशनल एजुकेशन-5, समाधन-9, परफोर्मिंग आर्ट्स-4, म्युज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स-4 और दिवास्वप्न-12 (टंकित)
- डिज़ाइन एंड डेवेलपमेंट ऑफ 5 ई.टी.वी. स्क्रिप्ट्स ऑन सेरीकल्चर (वोकेशनल एजुकेशन) (फोटोप्रति)
- कोर्सवेयर (इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया) ऑन साइंस फॉर क्लास 6 (सी.डी. आर.ओ.एम.) ओरियंटेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स थ्रू ऑडियो कान्फ्रेंसिंग (वर्ड प्रोसेस्ड)।

कंप्यूटर शिक्षा और प्रौद्योगिकी सहायता

विद्यालयों के लिए मल्टीमीडिया अधिगम सामग्रियों का विकास और सेवाकालीन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए इंटेल एशिया इलैक्ट्रोनिक्स के सहयोग से एक मल्टीमीडिया प्रयोगशाला विकसित की गई है। अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता देने हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास किया गया। प्रारंभ से ही प्रयोगशाला क्रियाकलापों का सक्रिय केन्द्र बन गई है। आई.टी. आधारित अधिगम सामग्रियों के बढ़ते हुए संग्रह के साथ ही प्रयोगशाला कम्प्यूटर विस्तार शिक्षा हेतु राष्ट्रीय केन्द्र में परिवर्धित हो गई है। साथ ही स्मार्ट विद्यालयों हेतु रूपरेखा विकसित की गई और मा.सं.वि. मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। यह दस्तावेज़ क्लास 2000, भारत सरकार के नवीन विद्यालय कंप्यूटिंग कार्यक्रम, के अंतर्गत प्रारंभ किए गए स्मार्ट विद्यालयों हेतु आधार बनाता है।

एनसी ई आर टी ने अपने कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी को आत्मसात कर उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एन.सी.ई.आर.टी. के सभी संघटकों में कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रणाली और उचित साफ्टवेयर की स्थापना के लिए चुनाव, परीक्षण एवं उपलब्धता के लिए विस्तृत एवं अपूर्व प्रयत्न किए गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि एन.सी.ई.आर.टी. के विभिन्न संघटकों/विभागों में आई.टी. और सूचना सुविधाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब एन.आई.ई. परिसर के प्रत्येक विभाग इंटरनेट से संबद्ध हैं। वर्ष के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. अधिकारियों/कर्मचारियों में विभिन्न आई.टी. कौशलों को विकसित करने हेतु अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे कि वे उपलब्ध आई.टी. सुविधाओं का सर्वोत्तम प्रयोग कर सकें।

एन.सी.ई.आर.टी. के नवीन वेबसाइट की स्थापना की गई है, जो उपयोगी सूचना और घोषणाएँ उपलब्ध करवाता है और वह अत्यन्त सक्रिय रूप से विस्तृत, समृद्ध एवं नवीन हो रहा है। कोई भी एचटीटीपी://डब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू. एनसीईआरटी. एनआईसी. आईएन पर पहुंच सकता है। यह साइट मुख्य रूप से विद्यालयी शिक्षा में कार्य करने जा रही है। वर्ष 1989–98 के दौरान त्रैमासिक पत्रिका 'स्कूल साइंस' के सभी चालीस अंक कम्पैक्ट डिस्क पर चुनिंदा अनुसंधान और प्रिंटिंग सुविधाओं सहित उपलब्ध किए गए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों हेतु विज्ञान किटों का उत्पादन, विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण, और टी.टी.आईज़. से छात्रों द्वारा कार्यशाला में अल्प अध्ययन दौरे प्रौद्योगिकीय सहायता के क्षेत्र में प्रमुख कार्यकलाप रहे।

कम्प्यूटर विस्तार शिक्षा राष्ट्रीय केन्द्र

विद्यालयों के लिए मल्टीमीडिया अधिगम सामग्रियों का विकास और सेवाकालीन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए इंटेल एशिया इलैक्ट्रोनिक्स के सहयोग से एक मल्टीमीडिया प्रयोगशाला विकसित की गई है। अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता देने हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास किया गया। प्रारंभ से ही प्रयोगशाला क्रियाकलापों का सक्रिय केन्द्र बन गई है। आई.टी. आधारित अधिगम सामग्रियों के बढ़ते हुए संग्रह के साथ ही प्रयोगशाला कम्प्यूटर विस्तार शिक्षा हेतु राष्ट्रीय केन्द्र में परिवर्धित हो गई है।

दिनांक 16–17 फरवरी, 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी और विद्यालयी प्रक्रिया पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री महाराज कृष्ण काव, शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। संगोष्ठी की कार्रवाई प्रकाशनाधीन है। वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए रचनात्मक प्रयोगशाला क्रियाकलापों का विकास करने हेतु एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।



सूचना प्रौद्योगिकी और विद्यालयी प्रक्रिया पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी।

विकास

कम्प्यूटर शिक्षा

स्मार्ट विद्यालयों हेतु रूपरेखा विकसित की गई और मा.सं.वि. मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। यह दस्तावेज़ क्लास 2000, भारत सरकार के नवीन विद्यालय कंप्यूटिंग कार्यक्रम, के अंतर्गत प्रारंभ किए गए स्मार्ट विद्यालयों हेतु आधार बनाता है। वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस मैनेजमेन्ट सिस्टम, स्प्रेडशीट, वेब डिज़ाइन, डेस्क टॉप पब्लिशिंग पर अनुलिपि

प्रशिक्षण मॉड्यूलों, अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और एन.सी.ई.आर.टी. के अधिकारियों/ कर्मचारियों के स्वयं प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए कंप्यूटर संबंधित प्रस्तुति विकसित की गई।

विद्यालयों के लिए कोर्सवेयर का विकास भी प्रगति पर है। यह आने वाले महीनों में पूर्ण हो जाएगा।

प्रौद्योगिकीय सहायता

प्राथमिक विद्यालयों के लिए तीन सौ प्राथमिक विज्ञान किट और सत्तर छोटे टूल किट राज्यों की माँग पर उन्हें पहुंचाए गए। माध्यमिक विद्यालयों हेतु एक सौ प्राथमिक विज्ञान किट, तीस छोटे टूल किट और दो सौ पैंसठ एकीकृत विज्ञान किट निर्मित किए गए। ये प्रेक्षण हेतु तैयार हैं।

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लिए धारा विद्युत हेतु लागत-प्रभावी प्रयोगशाला क्रियाकलाप के लिए लागत-प्रभावी प्रौद्योगिकीय सहायता का छात्र निर्माण पर्चा और अध्यापक सूचना पर्चा सहित दिल्ली के अनेक विद्यालयों में परीक्षण किया गया।

प्रौद्योगिकीय सहायता के अंतर्गत टी.टी.आई. के नौ प्रशिक्षुओं को उनके अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया। टी.टी.आई. के छात्रों हेतु पन्द्रह-पन्द्रह दिनों के दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जोकि अर्द्ध स्वचालित इंजैक्टिंग मोल्ड मशीन के प्रयोग के बारे में थे।

प्रशिक्षण और विस्तार

आई.टी. समृद्ध वातावरण में आधुनिकता का सामना करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। इन कार्यक्रमों में विंडोज़ प्लेटफॉर्म, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, वेब डिज़ाइनिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर कार्य शामिल हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों और दिल्ली के अनेक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए पंद्रह दिन के कार्यक्रम का संचालन किया गया। इस कार्यक्रम में मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया द्वारा कम्प्यूटर प्रयोग सिखाया गया।

कंप्यूटर शिक्षा में क्षेत्रीय निवेश

क्षे.शि.सं., मैसूर में कम्प्यूटर अनुप्रयोग लैब की अवसंरचना सुविधा में कुछ अतिरिक्त मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के साथ वृद्धि की गई है। पूर्व और सेवाकालीन दोनों कार्यक्रमों की आवश्यकता को यह लैब पूरा करती है। संस्थान परिसर के अंदर कंप्यूटरों के नेटवर्क का स्थानीय क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। संस्थान की लाइब्रेरी ने कुछ महत्वपूर्ण सी.डी.-आर.ओ.एम. जैसे वर्ल्ड एटलस, वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया, साइंस एनसाइक्लोपीडिया आदि उपलब्ध कराए हैं। लाइब्रेरी में संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा छात्रों के लिए इंटरनेट अनुसंधान सेवा प्रस्तुत की गई है। यह 'मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क' (एम.वाई. एल.आई.बी.एन.ई.टी.) परियोजना द्वारा प्रायोजित एन.आई.एस.एस.ए.टी. में सदस्य के रूप में नामांकित हैं और सभी क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- आई.टी. लिटरेसी मॉड्यूल्स, विंडोज़ 98, वर्ड 2000, एक्सेल 2000, एक्सेस 2000, पॉवर पॉइन्ट 2000, वेब पेज डिज़ाइनिंग एंड डी.टी.पी. (अनुलिपि)
- स्मार्ट स्कूल्स : ए ब्लूप्रिंट (अनुलिपि)
- प्रोसीडिंग्स ऑफ दि नेशनल सेमीनार ऑन इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी एंड दि स्कूलिंग प्रोसेस (प्रेस में)।

विशेष कार्यक्रम

ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) वर्ष 1994 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की सुलभता और प्रतिधारण में सुधार, अधिगम संप्राप्ति में संवृद्धि और सामाजिक व लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए विद्यालय त्याग की दर में कमी लाने में राज्य सरकारों का सहयोग करना है। डी.पी.ई.पी. का उद्देश्य मात्र प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण ही नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार का भी सार्वजनीकरण है। इस कार्यकम में कक्षाओं में विद्यार्थी-केंद्रित और क्रियाकलाप आधारित शिक्षण-अधिगम की शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि स्थापित करने पर ज़ोर दिया गया है।

(क) ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) वर्ष 1994 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा की सुलभता और प्रतिधारण में सुधार, अधिगम संप्राप्ति में संवृद्धि और सामाजिक व लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए विद्यालय त्याग की दर में कमी लाने में राज्य सरकारों का सहयोग करना है। डी.पी.ई.पी. का उद्देश्य मात्र प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण ही नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार का भी सार्वजनीकरण है। इस कार्यकम में कक्षाओं में विद्यार्थी-केंद्रित और क्रियाकलाप आधारित शिक्षण- अधिगम की शिक्षाशास्त्रीय दृष्टि स्थापित करने पर ज़ोर दिया गया है।

देश भर में डी.पी.ई.पी. कार्यक्रमों और कार्यकलापों में योगदान देने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. में निम्नलिखित संसाधन समूहों की स्थापना की गई है-

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संसाधन समूह (एन.सी.आर.जी.)
- राष्ट्रीय अनुसंधान संसाधन समूह (एन.आर.आर.जी.)
- राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन समूह (एन.टी.आर.जी.)

अक्टूबर 1996 में शिक्षा विभाग के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.), राज्य परियोजना निदेशकों के कार्यालयों, एड.सिल. इत्यादि के बीच संपर्क स्थापित करने के अलावा एन.आई.ई. और आर.आई.ईज़. स्तर पर, जहाँ कि डी.पी.ई.पी. कार्य प्रगति पर है, एन.सी.आर.जी., एन.आर.आर.जी. और एन.टी.आर.जी. की गतिविधियों के समन्वयन और नियंत्रण तथा राज्य परियोजना निदेशकों, एड.सिल. इत्यादि बाहरी साधनों से संपर्क करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. में डी.पी.ई.पी. केन्द्रिक संसाधन समूह (डी.पी.ई.पी.सी.आर.जी.) गठित किया गया।

आधार रेखा और मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण

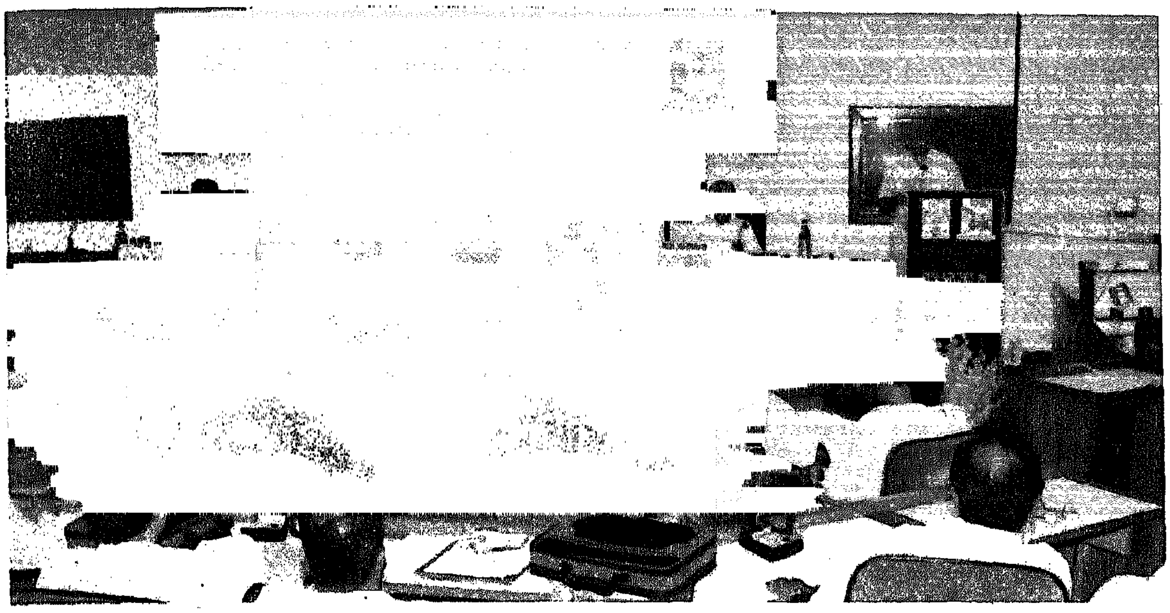
डी.पी.ई.पी. केन्द्रिक संसाधन दल के महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक था- आधार रेखा निर्धारण सर्वेक्षण (बी.ए.एस.) और मध्यावधि निर्धारण सर्वेक्षण (एम.ए.एस.) का संचालन। समूह ने बी.ए.एस. और एम.ए.एस. के संचालन के लिए अनुसंधान की रूपरेखा के विकास और अनुसंधान उपकरणों में संशोधन के कार्य शुरू किए। प्रशिक्षण और विस्तार के स्तर पर, राजस्थान के दस विस्तृत ज़िलों में आधार रेखा निर्धारण सर्वेक्षण के संचालन के लिए मुख्य प्रशिक्षकों के लिए एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर में एक सात-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में फैले कम से कम 17 ज़िलों में मध्यावधि निर्धारण सर्वेक्षण संचालित किया गया।

चरण II के राज्यों में संचालित मध्यावधि निर्धारण सर्वेक्षण की अन्तिम रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया और विद्यार्थियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। 'स्टूडेन्ट्स अचीवमेन्ट अण्डर एम.ए.एस. अप्रैज़ल इन फेज II स्टेट्स' शीर्षक से एक दस्तावेज़ प्रकाशित किया गया। इस दस्तोवज़ में मध्यावधि सुधार के संकेतक दिए गए हैं जो डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत भावी योजना निर्माण के कार्य बिन्दु स्थापित करते हैं। डी.पी.ई.पी. की समन्वय समिति द्वारा डी.पी.ई.पी. की गतिविधियों की प्रगति का पुनरीक्षण किया गया। डी.पी.ई.पी. चरण I की एम.ए.एस. रिपोर्ट के आधार पर गणित और भाषा दोनों के लिए अधिगम के कठिन बिन्दुओं की पहचान की गई और इन समस्याओं के समाधान हेतु कदम उठाने के लिए चरण I के सात डी.पी.ई.पी. राज्यों को भेजा गया। दस राज्यों के 76 ज़िलों के लिए मध्यावधि निर्धारण सर्वेक्षण (एम.ए.एस.) प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

डी.पी.ई.पी. के तत्वावधान में एन.सी.ई.आर.टी. 1995 से विद्यालयी प्रभविष्णुता पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करती रही। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयी प्रभविष्णुता से संबंधित अनुसंधानों पर पाँचवीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 14-16 जुलाई को आयोजित की गई। संगोष्ठी में मुख्य बल रहा- शोध, खास तौर से प्राथमिक स्तर पर विद्यालयी प्रभविष्णुता के लिए अन्तर्वर्ती कार्यनीतियों के प्रभाव पर।

अप्रैल-मई 1999 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रस्तावना के रूप में एन.सी.ई.आर.टी. ने अपने शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थानों में तीन क्षेत्रीय संगोष्ठियाँ- भोपाल, भुवनेश्वर और मैसूर प्रत्येक में एक-एक आयोजित की। क्षेत्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत करने के लिए भारतीय सहयोगियों की 171 प्रविष्टियों में से 59 प्रपत्र छाँटे गए। अन्ततः पूरे देश से 14



प्राथमिक स्तर पर विद्यालय प्रभविष्णुता में अनुसंधान पर आयोजित पांचवीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।

आलेख अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत करने के लिए चुने गए। 10 विदेशी सहयोगियों के आलेखों में से आठ आलेख चुने गए। ये आलेख ईरान, जापान, नीदरलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और युगांडा से थे। इनके अलावा डी.पी.ई.पी. ब्यूरो, एम.एच. आर.डी., नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई कुछ प्रस्तुतियों का चुनाव संगोष्ठी में प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया। 'समुदाय की भागीदारी और विद्यालय की प्रभविष्णुता' पर एक समूह-वार्तालाप के अलावा संगोष्ठी में 27 प्रस्तुतियाँ की गईं।

संगोष्ठी में विद्यालयी प्रभविष्णुता के विविध आयामों पर चर्चा की गई और इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के उद्देश्य की संप्राप्ति के हमारे प्रयासों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की गई।

संगोष्ठी में प्रस्तुत किए गए पत्रों का प्रलेखन और संगोष्ठी की कार्रवाइयाँ पाँचवीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट में शामिल हैं। बुनियादी स्तर पर गुणवत्ता शिक्षा के संकेतकों पर दिसम्बर 2000 में आयोजित की जाने वाली 66वीं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगोष्ठी की तैयारी की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा पर अनुसंधान अध्ययन

एन.सी.ई.आर.टी. क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों सहित अपने संघटकों के माध्यम से डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन करती रही है। 1999-2000 के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. के घटकों द्वारा डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत निम्नलिखित चार परियोजनाएं प्रारंभ की गईं:

1. स्टडी ऑफ क्लासरूम प्रोसेस एण्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स प्रोवाइडिंग स्कूलिंग बेस्ड ऑन एजुकेशनल फिलासफी ऑफ इन्डियन स्कूल रिफोरमर्स/ग्रेट एजुकेटर्स/इण्डियन सोशियो-कल्चरल ट्रेडिशन
2. इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग पैकेज ऑन कान्टीनुउस एण्ड काम्प्रीहेन्सिव इवैल्युएशन ओवर दि इवैल्युएशन प्रेक्टिसेज़ ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स
3. इम्पैक्ट ऑफ ई.सी.सी.ई. ऑन प्राइमरी स्कूलिंग
4. स्टडी ऑफ इफेक्टिवनेस एण्ड इनइफेक्टिव स्कूल एजुकेशन कमेटीज़ (एस.ई.सीज़.) एण्ड देयर इम्पैक्ट ऑन इनरोल्मेन्ट, रिटेन्शन एण्ड एचीवमेन्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन इन डी.पी.ई.पी. डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश।

प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित में निदानात्मक परीक्षण

अधिगम समस्याओं के निदान के लिए कार्यक्रम में परीक्षण सामग्रियों का एक डाटा बैंक विकसित किया गया। तीन राज्यों में परीक्षण आयोजित किए और बच्चों के अधिगम की

संभावित कठिनाइयों को समझने के लिए आंकड़े का विश्लेषण किया गया। शिक्षकों के प्रयोग के लिए अनुभव पर आधारित निदानात्मक परीक्षणों के परीक्षण के लिए एक पुस्तिका तैयार की गई। निदानात्मक उपचार के उपायों का प्रचार-प्रसार करने के लिए प्रयास जारी हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने प्राथमिक कक्षाओं में गणित के निदानात्मक परीक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास किया।

कक्षा-प्रक्रियाएँ : तुलनात्मक केस अध्ययन

यह अध्ययन एन.सी.ई.आर.टी. के डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर, भोपाल और मैसूर के संकाय-सहयोग से किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की कक्षा-प्रक्रियाओं में एक आधार बिन्दु का विकास था। अध्ययन में अकादमिक वर्ष के दौरान किए गये विस्तृत कक्षा-सर्वेक्षण में शिक्षकों, अध्यापकों और प्रशिक्षणार्थियों के साक्षात्कार सहित गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया।

यह अध्ययन सात राज्यों- आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सितम्बर 1998 में शुरू किया गया। डी.पी.ई.पी. के बारहवें संयुक्त पुनरीक्षण मिशन के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सदस्यों के साथ साझा करने के लिए विभिन्न राज्यों की सूचनाओं पर आधारित एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान करने का कार्य जारी है।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर ने तमिलनाडु के एम.एल.एल. आधारित कक्षा चार स्तर के पर्यावरण अध्ययन-1 पाठ्यक्रम के लिए सहायक सामग्री विकसित की और प्राथमिक अध्यापकों की आवश्यक दक्षताओं के विकास के लिए परिणामोन्मुख परीक्षण सामग्री विकसित की।

आदिवासी बच्चों द्वारा गणित का अधिगम : एक केस अध्ययन (उड़ीसा का गजपति ज़िला)

अध्ययन में मूल रूप से यह जानने और उसका प्रलेखन करने का प्रयास किया गया कि आदिवासी अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार के गणित का उपयोग करते हैं। इस उद्देश्य के लिए गजपति ज़िले के सौरा आदिवासी समुदाय का चयन किया गया। शुरू में समुदाय के मानव शास्त्री और सामाजिक लक्ष्यों का दस्तावेज़ तैयार करने के लिए सर्वेक्षण संचालित किया गया। अध्ययन के अगले दो दौरों में सौरा की संख्या-गणना पद्धति, बाजार लेन-देन पद्धति आदि से संबंधित दस्तावेज़ तैयार किए गए। यह पाया गया कि गृह-निर्माण से लेकर कृषि से संबंधित छोटे उपकरण बनाने में सौरा जनजाति अलग प्रकार के गणित का प्रयोग करती है। रिपोर्ट का पहला प्रारूप तैयार है। रिपोर्ट जनजातीय क्षेत्रों में गणित की विद्यालयी पाठ्यचर्या में संशोधन के लिए कुछ अन्तर्वर्ती सुझाव देती है। इनमें कुछ सुझाव निम्न है:

1) गणित के प्रश्न जनजातियों के दैनिक जीवन की वास्तविक स्थितियों को प्रदर्शित करने वाले होने चाहिए, न कि परिकल्पनात्मक गणितीय प्रश्न।
2) प्राथमिक स्तर पर जनजातीय बच्चों के गणित शिक्षण के लिए जनजातीय अंक पद्धति को आरंभ किया जाना चाहिए।
3) गणित की पाठ्यपुस्तकों में 'गुणा' और 'भाग' की जगह 'जोड़' और 'घटाना' जैसी एल्गोरिदम्स पर ज़ोर होना चाहिए।

कार्यात्मक अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण

हिमाचल प्रदेश के 25 डी.पी.ई.पी. कर्मचारियों के लिए कार्यात्मक अनुसंधान पद्धति में एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

उत्तर प्रदेश और बिहार में अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान

यह परियोजना डी.पी.ई.पी. राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं की जाँच करने के विशिष्ट उद्देश्य से लागू की गई। संस्थाओं, विद्यार्थियों और अध्यापकों के बारे में अधिक जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक प्रखंडों से आंकड़ा इकट्ठा किया गया। विभिन्न आयामों से युक्त इस अध्ययन में संस्थाओं के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएँ शामिल हैं। आँकड़ों का विश्लेषण किया गया और प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विकलांगों की एकीकृत शिक्षा

राज्य की योजनाओं के विकास के लिए राज्य सलाहकार समिति का सदस्य होने के नाते एन.सी.ई.आर.टी. ने केरल और उत्तर प्रदेश में एन.जी.ओज़ द्वारा परियोजनाओं के चयन, पुनरीक्षण और अनुवीक्षण के लिए डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत आई.ई.डी.सी. के क्रियान्वयन हेतु संसाधन सामग्री प्रदान की। उड़ीसा के डी.पी.ई.पी. ज़िलों में कम विकलांग बच्चों की शैक्षिक बाधाओं की पहचान और उनके निदान के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर ने कार्यनीतियाँ विकसित कीं।

परामर्श

विभिन्न राज्यों द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण किया गया और राज्यों में इस कार्यक्रम के अनुवीक्षण के लिए ज़िम्मेदार पदाधिकारियों के उपयोग के लिए दूरवर्ती राज्यों में जनजातीय शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार की गई। डी.पी.ई.पी. राज्यों में जनजातीय शिक्षा के समन्वयकों की एक पुनरीक्षण बैठक करने की योजना है।

1999-2000 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

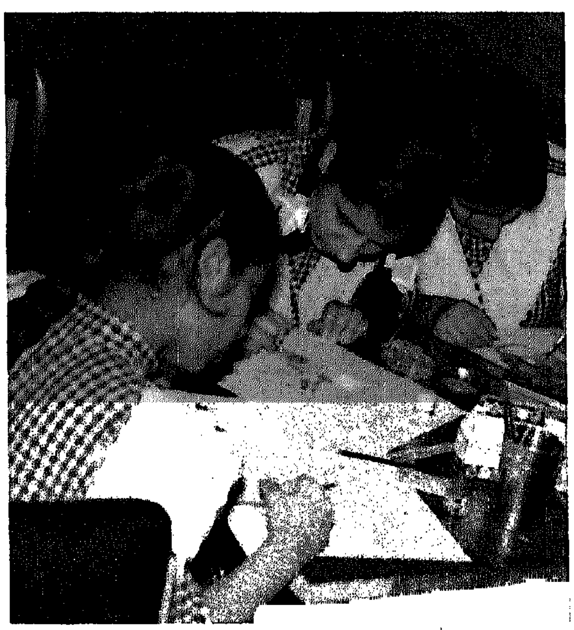
- लर्निंग आर्गनाइज़ेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एण्ड स्कूल इफेक्टिवनेस एट प्राइमरी स्टेज (प्रोसीडिंग्स ऑफ दि स्टडीज़ डिस्कस्ड एट दि 1998 इन्टरनेशनल सेमिनार)
- स्टडीज़ ऑन लर्निंग आर्गनाइज़ेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एण्ड स्कूल इफेक्टिवनेस एट प्राइमरी स्टेज (ए कम्पेन्डियम ऑफ स्टडीज़ प्रजेन्टेड इन दि 1998 इन्टरनेशनल सेमिनार)
- स्टूडेन्ट्स एचीवमेन्ट अण्डर एम.ए.एस. अप्रैज़ल इन फेज़-II स्टेट्स, अक्टूबर 1999 (फोटोप्रति)
- आइडेन्टीफिकेशन ऑफ हार्डस्पोट्स ऑफ लर्निंग इन लैंग्वेज़ एण्ड मैथमेटिक्स अण्डर एम.ए.एस. इन डी.पी.ई.पी. फेज़-I स्टेट्स, अक्टूबर 1999 (फोटोप्रति)
- रिसर्चेज़ इन स्कूल इफेक्टिवनेस एट प्राइमरी स्टेज (प्रोसीडिंग्स ऑफ दि स्टडीज़ डिस्कस्ड इन 1999 इन्टरनेशनल सेमिनार) फरवरी 2000
- डेवलपमेन्ट ऑफ़ स्ट्रेटजीज़ फॉर आइडेन्टीफिकेशन एण्ड रेमेडिएशन ऑफ एजुकेशनल बैरियर्स ऑफ माइल्ड डिसएबल्ड चिल्ड्रेन इन डी.पी.ई.पी. डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा, आर.आई.ई., भुवनेश्वर (डी.टी.पी.)
- इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ पेडागाजिकल रिनेवल इन दि कान्टेक्स्ट ऑफ डी.पी.ई.पी. इन्टरवेंशन्स आन कम्पीटेन्स ऑफ प्राइमरी टीचर्स ऑफ उड़ीसा, आर.आई.ई., भुवनेश्वर (डी.टी.पी.)।

(ख) राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एन.पी.ई.पी.), जोकि देश में अप्रैल 1980 में शुरू की गई, अपने चौथे चरण (1998-2000) जून 1998 से नए नाम- 'एन.पी.ई.पी.: विद्यालयों में जनसंख्या और विकास शिक्षा' के नाम से चलाई जा रही है। यह परियोजना 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के संबंधित राज्य जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठों और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एन.ओ.एस.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति जैसे राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 1999-2000 के दौरान परियोजना के अंतर्गत संचालित मुख्य गतिविधियाँ रहीं:

विकास

विद्यालयों में किशोरावस्था शिक्षण पर आधारभूत सामग्री के एक पैकेज का प्रकाशन किया गया। इस पैकेज



जनसंख्या शिक्षा में अंतर-विद्यालयी चित्रकला प्रतियोगिता के कुछ प्रतिभागी।

में निम्नांकित छह पुस्तिकाएं हैं: (1) प्रस्तावना, (2) किशोरावस्था शिक्षा की सामान्य रूपरेखा, (3) ज्ञान आधारित: किशोरावस्था शिक्षा, (4) किशोरावस्था शिक्षा : प्रश्न और उत्तर, (5) विद्यार्थियों के कार्यकलाप और (6) किशोरावस्था शिक्षा : वयस्कों की भूमिका। (1) विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष व्याख्यान और दृश्य-श्रव्य प्रदर्शन, (2) लम्बी दूरी की दौड़, (3) राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता 1999 और (4) अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयन पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए और राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों में वितरित किए गए। जनसंख्या शिक्षा पत्रिका के दो अंक प्रकाशित और प्रसारित किए गए। किशोरावस्था पुनरुत्पादक और लैंगिक स्वास्थ्य पर पी.ओ.पी.डी.ओ.सी., डी.एल.डी.आई. द्वारा एक संदर्भ ग्रंथसूची तैयार की गई और उसका प्रचार-प्रसार किया गया।

प्रशिक्षण

राज्य परियोजना कार्मिकों के लिए विद्यालयों में जनसंख्या और विकास शिक्षा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 13 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के 21 परियोजना कार्मिकों और दूसरे कार्यान्वयन अभिकरणों ने भाग लिया। केरल राज्य में अन्तर्राज्यीय शैक्षिक दौरे का एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 5 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 15 परियोजन कार्मिकों ने भाग लिया।

विस्तार

अप्रैल और सितंबर 1999 में यू.एन.एफ.पी.ए. पोषित एक कार्यक्रम-अन्तर्राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था- '21वीं सदी के लिए निर्णय : चयन और उत्तरदायित्व'। राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक समूह द्वारा हज़ारों प्रविष्टियों में से 15 विजेता - पांच वर्गों से प्रत्येक से तीन-तीन-चुनी गईं और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। शैक्षिक निर्णय के लिए पांचों आयु वर्गों की प्रत्येक प्रथम प्रविष्टि यू.एन.एफ.पी.ए. मुख्यालय न्यूयार्क भेज दी गई।

जुलाई-अक्टूबर 1999 के दौरान पाँच स्तरों-विद्यालय स्तर, ज़िला/मंडल स्तर, राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर- पर 'भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण में महिलाओं का सशक्तीकरण ही सहायक होगा' विषय पर एक राष्ट्रीय वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। राष्ट्रीय स्तर पर विषय के पक्ष और विपक्ष में तीन सर्वश्रेष्ठ टीमों और सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं को पुरस्कार दिया गया।

अनुसंधान और मूल्यांकन

जनसंख्या शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए यू.जी.सी., वयस्क शिक्षा निदेशालय और यू.एन.एफ.पी.ए. के सहयोग से एक कार्य योजना तैयार की गई। किशोरों के पुनरोत्पादक स्वास्थ्य पर आधारभूत सर्वेक्षण के लिए आंकड़ा इकट्ठा और संसाधित किया गया। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

परियोजना क्रियान्वयन का अनुवीक्षण

विद्यालय शिक्षा, वयस्क शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्रों में परियोजना के प्रभावशाली कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए पाँच अंतर्क्षेत्रीय समन्वय बैठकें की गईं। पुनरीक्षण की यह नई प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी शुरू की गई। एम.एच.आर.डी., एम.एच.ओ.एफ.ड़ब्ल्यू और यू.एन.एफ.पी.ए. की बैठकों में निश्चित अन्तरालों पर परियोजना क्रियान्वयन का पुनरीक्षण किया गया। 1999 के दौरान हुई प्रगति का पुनरीक्षण और 2000 के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा बजट का अनुमान करने के लिए नवम्बर-दिसम्बर 1999 में परियोजना प्रगति की दो पुनरीक्षण बैठकें आयोजित की गईं।

जनसंख्या शिक्षा में क्षेत्रीय स्तर पर योगदान

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर ने उत्तरी क्षेत्रों के शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए किशोरावस्था शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा के पुर्नविधारण रूपरेखा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। जनसंख्या शिक्षा सप्ताह के दौरान विद्यालयों में विविध क्रियाकलाप आयोजित किए गए। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रीभ्रूण हत्या और स्त्री शिशु मृत्यु के कारणों और इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों का एक अध्ययन पूर्ण किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल ने जनसंख्या शिक्षा अधिगम सामग्री (पापुलेशन लर्निंग मेटीरियल्स) विकसित की। मध्य प्रदेश के डाइटों की जनसंख्या शिक्षा प्रयोगशालाओं में उत्पादित सामग्री का पुनरीक्षण किया और उसे अन्तिम रूप प्रदान किया और मध्य प्रदेश तथा एस.सी.ई.आर.टी. व डाइटों में उसका प्रचार-प्रसार किया गया। किशोरावस्था शिक्षा (एडोल्सेन्स एजुकेशन) सामग्री उत्पादित और विकसित की गई। इसे अन्तिम रूप दिया गया और इसका प्रचार-प्रसार किया गया। किशोर पुनरोत्पादक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और अभिवृत्ति का एक अध्ययन किया जा रहा है। आँकड़ों के विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है। संस्थान ने विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या शिक्षा सप्ताह भी मनाया तथा विद्यालय के बच्चों के लिए अतिथि व्याख्यान, विद्यालयी और अंतर्विद्यालयी चित्रकला, कहानी लेखन और निबंध प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर ने भी विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या शिक्षा सप्ताह मनाया। इस दौरान विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए। उड़ीसा के खुर्दा, बलसोर और कोरापत ज़िलों के मानव जनसंख्या का पी.क्यू.एल. के मानकों पर एक स्तर अध्ययन किया गया। पूर्वी और पूर्वोत्तरीय क्षेत्रों के राज्यों/संघशासित प्रदेशों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यचर्या निर्माताओं और सामग्री विकसित करने वाले कर्मियों के लिए 'पुर्नविधारण जनसंख्या शिक्षा : एक सहक्रियात्मक संगोष्ठी' आयोजित की गई।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर और जनसंख्या शिक्षा सप्ताह के दौरान कई सह-पाठ्यचर्यात्मक क्रियाकलाप आयोजित किए। किशोरावस्था शिक्षा पर एक आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन किया गया। विद्यालयों में जनसंख्या और विकास शिक्षा पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया गया। कर्नाटक और केरल के डाइटों और सी.टी.ईज़. के संकायों के लिए किशोरावस्था शिक्षा पर एक सात-दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रायोगिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच किशोरावस्था शिक्षा के प्रति जागरूकता और अभिवृत्ति पर एक अध्ययन के लिए रूपरेखा और सामग्री विकसित की गई।

1999-2000 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

निम्नलिखित प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित और प्रचारित-प्रसारित किए गए :

- एडोल्सेन्स एजुकेशन इन स्कूल्स : ए पैकेज ऑफ बेसिक मेटिरियल्स
- पापुलेशन एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज़ (अनुलिपि)
- पापुलेशन एजुकेशन बुलेटिन (दो अंक)
- ए रिपोर्ट ऑन एनुअल प्रोजेक्ट प्रोग्रैस रिव्यू मीटिंग 1999 (अनुलिपि)
- पापुलेशन एजुकेशन रिसर्च इन इण्डिया (फोटोप्रति)
- पापुलेशन एजुकेशन स्कूल करीकुलम - ए रिपोर्ट ऑफ दि कन्टेन्ट एनालिसिस (प्रकाशनाधीन)
- रिपोर्ट ऑफ मिड-टर्म इवैल्युएशन ऑफ नेशनल पापुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट-थर्ड साइकिल (प्रकाशनाधीन)
- ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पापुलेशन एजुकेशन फॉर दि डाइट परसनेल ऑफ गुजरात स्टेट, आर.आई.ई., भोपाल (फोटोप्रति)
- ए रिपोर्ट ऑन दि ओरिएन्टेशन प्रोग्राम इन एडोल्सेन्स एजुकेशन फॉर दि फेकल्टीज़ ऑफ डाइट्स एण्ड सी टी.ईज़. ऑफ कर्नाटक एण्ड केरल (कम्प्यूटर प्रिन्ट)
- डेवलपमेन्ट ऑफ ए डिज़ाइन एण्ड टूल्स फॉर रिसर्च स्टडी ऑन अवेयरनेस एण्ड एटीट्यूड टु एडोल्सेन्स एजुकेशन एमंग डी.एम.एस. स्टूडेन्ट्स (कम्प्यूटर प्रिन्ट)।

(ग) प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की संप्राप्ति के तरीकों के एक भाग के रूप में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1993-94 में तैयार किया गया प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम (सॉप्ट) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। प्राथमिक विद्यालयों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रदान की गयी सामग्री के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों में दक्षता

का विकास करना और अधिगम के लिए बाल-केंद्रित पद्धति अपनाने के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित करना इस योजना के मुख्य बिंदु हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर (एम एल एल) पर राष्ट्रीय रिपोर्ट में निहित दक्षताओं के विकास पर भी यह अभिविन्यास कार्यक्रम आधारित है। सॉप्ट कार्यक्रम प्रतिवर्ष 4.5 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य से आरंभ किया गया था। एन.सी.ई.आर.टी. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी सौंपना चाह रही है। इस दिशा में एन.सी.ई.आर.टी. ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रयोगार्थ प्रशिक्षण की रूपरेखा, प्रशिक्षण पैकेज और दृश्य-श्रव्य सामग्री का विकास किया। तीन चरणों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया गया जिसमें एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा राज्य शिक्षा विभाग के संसाधन व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए। राज्य स्तर के संसाधन व्यक्तियों ने ज़िला स्तर पर प्रशिक्षण देकर संसाधन व्यक्ति तैयार किए। राज्यों में प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की ज़िम्मेदारी इन्हीं संसाधन व्यक्तियों को सौंपी गई।

सॉप्ट ने राज्य नोडल अभिकरणों जैसे असम, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निधि प्रदान की। कुछ राज्यों ने सॉप्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त निधि के अव्ययित शेष से किया।

विभिन्न राज्यों में आयोजित सॉप्ट कार्यक्रमों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करने और अनुवीक्षण की ज़िम्मेदारी एन.सी.ई.आर.टी. की है। सॉप्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्र सलाहकार ने अपने-अपने क्षेत्रों में सॉप्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण किया और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गहन अध्ययन भी आयोजित किए गए। इस वर्ष के दौरान सॉप्ट योजना के अंतर्गत लगभग 2.80 लाख अध्यापक प्रशिक्षित किए गए और 1993-94, जब से यह योजना प्रारंभ की गयी है, तब से मार्च 1999 तक लगभग 12.5 लाख अध्यापक प्रशिक्षित हो चुके हैं। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्य संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित किया गया।

(घ) विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की तैयारी

कार्रवाई योजना में 1992 और नौवीं योजना के दस्तावेज़ में दिए गए सुझावों के अनुपालन में परिषद् ने विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर कार्य प्रारंभ किया। इस दिशा में कार्य प्रारंभ करने के लिए सितंबर 1999 में निदेशक की अध्यक्षता में एन.आई.ई. के विभिन्न विभागों से 6 संकाय सदस्यों के 'पाठ्यचर्या समूह' का गठन किया गया।

विभागीय गोष्ठियां आयोजित कर परिषद् के प्रत्येक संकाय सदस्य से परामर्श लेकर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थाओं में गोष्ठी कर, खासतौर से आमंत्रित प्रतिष्ठित वक्ताओं से विचार-विमर्श कर और अनेक प्रकार की सैद्धान्तिक और शोध सामग्रियों का अध्ययन कर 'पाठ्यचर्या समूह' ने विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का परिचर्चा दस्तावेज़ तैयार किया।

जनवरी 2000 में परिचर्चा दस्तावेज़ का विमोचन किया गया और इस दस्तावेज़ को सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संगठनों, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों और अनेक लोगों के पास विचार और सुझाव हेतु भेजा गया। पाठ्यचर्या समूह ने क्षेत्रीय गोष्ठियों की एक श्रृंखला (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साथ हर क्षेत्र में एक गोष्ठी) और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की। केन्द्रीय संस्थाओं, जैसे- सी.बी.एस.ई., के.वी.एस.,एन.वी.एस., एन.ओ.एस. नीपा, इग्नू आदि के लिए भी एक राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी आयोजित की गई। विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के अनुरोध पर इस आशय के लिए आयोजित गोष्ठियों हेतु परिषद् ने उन्हें धन भी प्रदान किया। ये संगोष्ठियां अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, कला, संस्कृति और शिक्षा स्थायीकरण समाज (एस.पी.ए.सी.ई.), गांधी शांति प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद, गांधी शांति प्रतिष्ठान (नई तालीम के संस्थानों/अध्यापकों के लिए) ने आयोजित कीं।

इनके अतिरिक्त देश के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्षों के एक दो-दिवसीय सम्मेलन में इस दस्तावेज़ पर विचार-विमर्श किया गया।

विभिन्न गोष्ठियों और कार्यशालाओं की संस्तुतियों के आलोक में देश के विभिन्न भागों से प्राप्त पुनर्निवेशन के आधार पर दस्तावेज़ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आशा है अंतिम दस्तावेज़ जुलाई 2000 तक पूरा हो जाएगा।

प्रतिभा की पहचान और प्रोत्साहन

एन सी ई आर टी अपनी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन.टी.एस.) योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज. जाति के लिए 70 छात्रवृत्तियों सहित छात्रों को प्रतिवर्ष 750 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 10 के अंत में मेधावी छात्रों की पहचान करना और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सकें और अपनी रुचि के विषय में उन्नति करते हुए देश के विकास में सहायक हो सकें।

एनसी ई आर टी अपनी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन.टी.एस.) योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज. जाति के लिए 70 छात्रवृत्तियों सहित छात्रों को प्रतिवर्ष 750 छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कक्षा 10 के अंत में मेधावी छात्रों की पहचान करना और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सकें और अपनी रुचि के विषय में उन्नति करते हुए देश के विकास में सहायक हो सकें।

एन.टी.एस. के अंतर्गत पुरस्कार का चयन दो चरणों में किया जाता है। प्रथम चरण में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा प्रायः अक्टूबर और दिसम्बर के बीच लिखित

वर्ष 1999-2000 के दौरान दी गई एन.टी.एस. छात्रवृत्तियों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघीय क्षेत्र	आबंटित कोटा	परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या	पुरस्कृत छात्रवृत्तियों की संख्या (सामान्य वर्ग)	अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों को दी गई छात्रवृत्तियां	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	185	162	19	02	21
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	18	01	–	01
3.	असम	90	89	04	–	04
4.	बिहार	175	167	82	12	94
5.	दिल्ली	50	48	27	02	29
6.	गोवा	25	24	03	–	03
7.	गुजरात	170	129	07	–	07
8.	हरियाणा	55	55	25	01	26
9.	हिमाचल प्रदेश	35	35	04	01	05
10.	जम्मू और कश्मीर	25	23	–	–	–
11.	कर्नाटक	170	164	43	03	46
12.	केरल	185	181	26	03	29
13.	मध्य प्रदेश	205	196	35	06	41
14.	महाराष्ट्र	380	374	153	07	160
15.	मणिपुर	25	24	03	02	05
16.	मेघालय	25	22	–	–	–
17.	मिज़ोरम	25		(परीक्षा आयोजित नहीं हुई)		
18.	नागालैंड	25	25	01	02	03
19.	उड़ीसा	155	151	31	01	32
20.	पंजाब	85	85	26	02	28
21.	राजस्थान	105	99	42	05	47
22.	सिक्किम	25	23	–	01	01
23.	तमिलनाडु	255	237	37	03	40
24.	त्रिपुरा	25	21	02	01	03
25.	उत्तर प्रदेश	420	404	63	07	70
26.	पश्चिम बंगाल	250	229	38	07	45
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10	09	–	01	01
28.	चण्डीगढ़	10	10	08	–	08
29.	दादर और नगर हवेली	10	08	–	–	–
30.	दमन और दीव	10	(किसी भी छात्र को संस्तुत नहीं किया गया)			
31.	लक्षद्वीप	10	08	–	–	–
32.	पाण्डिचेरी	10	10	–	01	01
	कुल	3255	3030	680	49	750

परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है। इस परीक्षा के आधार पर निर्धारित संख्या में चुने छात्रों को एन.सी.ई.आर.टी. के अंतर्गत दूसरे स्तर की परीक्षा के लिए संस्तुत किया जाता है। द्वितीय स्तर की चयन परीक्षा में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों ही सम्मिलित हैं। एन.सी.ई.आर.टी. इन छात्रों को न केवल छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है, बल्कि देश के प्रमुख संस्थानों की सहायता और सहयोग से छात्रों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए उपयुक्त ग्रीष्मावकाश संस्थानों की व्यवस्था भी करती है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान पुरस्कृत कुल विद्यार्थियों की संख्या

+2 स्तर पर	1500
अवर स्नातक	
विज्ञान	165
सामाजिक विज्ञान	87
इंजीनियरिंग	2095
चिकित्सा	896
स्नातकोत्तर	
विज्ञान	17
सामाजिक विज्ञान	15
इंजीनियरिंग/एम.टैक.	02
चिकित्सा	–
प्रबन्धन	23
कुल	4710

वर्ष 1999-2000 के दौरान व्यय

1.	छात्रवृत्तियों का वितरण	रु. 1,25,00,000.00
2.	एन.टी.एस. परीक्षा का आयोजन	रु. 10,00,000.00
	कुल	1,35,00,000.00

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- एन अप्रेज़ल ऑफ नेशनल टैलंट सर्च एक्ज़ामिनेशन, 1999 (फोटो प्रतिलिपि)
- एनालिसिस ऑफ स्टूडेन्ड्स परफॉरमेन्स ऑफ डिफ्रेन्ट सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस इन नेशनल टैलंट सर्च स्कीम (फोटो प्रतिलिपि)।

19

शैक्षिक अनुसंधान

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अंतर्गत एन.सी.ई.आर.टी. शोध के राष्ट्रीय संघटकों का संचालन भी करती है। अनुसंधान में लगे एन.सी.ई.आर.टी. के संघटकों के अतिरिक्त परिषद् की एक स्थायी समिति के रूप में कार्यरत शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) विद्यालय और अध्यापक शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और उसे सहायता देन के लिए उत्प्रेरक का भी कार्य करती है।

विद्यालयी शिक्षा में अनुसंधान और गुणात्मक सुधार के लिए अनुसंधान पर आधारित नीतिगत परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देना एन.सी.ई.आर.टी. का महत्वपूर्ण सरोकार है। इस क्षेत्र के मुख्य कार्यों में शामिल हैं- (1) सांस्थानिक अनुसंधान क्षमता का विकास और सुदृढ़ीकरण, (2) शिक्षा, विशेषकर विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हुए पहलुओं पर अनुसंधान आधारित सूचना का प्रलेखन और (3) अनुसंधान निष्कर्षों और उनके पुनर्निर्देशन तथा शिक्षा प्रणाली पर उनके प्रभावों को शैक्षिक शोध से संबंधित कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए संप्रेषण के माध्यम उपलब्ध कराना। ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अंतर्गत एन.सी.ई.आर.टी. शोध के राष्ट्रीय संघटकों का संचालन भी करती है। अनुसंधान में लगे एन.सी.ई.आर.टी. के संघटकों के अतिरिक्त परिषद् की एक स्थायी समिति के रूप में कार्यरत शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) विद्यालय और अध्यापक शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और उसे सहायता देन के लिए उत्प्रेरक का भी कार्य करती है। एरिक के सदस्यों में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के शिक्षा तथा उससे संबद्ध विषयों के प्रख्यात अनुसंधानकर्ता तथा एस.आई.ईज़./एस.सी.ई.आर.टीज़. के प्रतिनिधि शामिल हैं।

शैक्षिक अनुसंधान और भारतीय शैक्षिक सार-संक्षेप का सर्वेक्षण

शैक्षिक अनुसंधान का सर्वेक्षण आयोजित करना एन.सी.ई.आर.टी. के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। शैक्षिक अनुसंधान के पांचवें सर्वेक्षण में, 1988 से 1992 तक की अवधि के लिए, भारतीय विश्वविद्यालयों के सर्वाधिक उत्कृष्ट पीएच.डी. और एम.फिल शोध प्रबंधों के सार-संक्षेप प्रस्तुत किए गए हैं। शैक्षिक अनुसंधान के पांचवें सर्वेक्षण के दूसरे भाग में शामिल 1800 सार-संक्षेपों को अंतिम रूप दिया गया।

अनुसंधान अध्ययन के पूरे होने और उसके प्रचार-प्रसार के मध्य के अंतराल को कम करने के लिए 1986 से एक अर्द्धवार्षिक अनुसंधान पत्रिका 'इंडियन एजुकेशनल एब्सट्रैक्ट्स' का प्रकाशन आरंभ किया गया है। 1999-2000 के दौरान 'इंडियन एजुकेशनल एब्सट्रैक्ट्स' (भाग 7 और 8) के एक संयुक्त अंक को जिसमें 201 सार-संक्षेप शामिल हैं, अंतिम रूप दिया गया। यह प्रकाशनाधीन है। इसके नौवें अंक का कार्य प्रगति पर है।

एरिक द्वारा सहायताप्राप्त अनुसंधान परियोजनाएँ

1999-2000 के दौरान एरिक द्वारा सहायताप्राप्त 13 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी हुईं और 47 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है।

वर्ष 1999-2000 में पूरी की गईं अनुसंधान परियोजनाएँ

(1) +2 स्तर पर भौतिकी के चुने हुए विषयों पर शिक्षणार्थियों की पूर्वधारणाओं और भ्रांतधारणाओं का अध्ययन

डा. एच.सी. जैन, आर.आई.ई., अजमेर

इस अध्ययन का उद्देश्य रहा : (1) +2 स्तर पर भौतिकी के चुने हुए विषयों पर विद्यार्थियों की पूर्वधारणा/भ्रांतधारणा/सहज सिद्धान्तों/सहजानुभूत विचारों की पहचान, (2) ऊपर पहचानी गई पूर्वधारणाओं के कारणों का निर्धारण, (3) भ्रांत अवधारणाएं समाप्त करने के लिए मानदंड सुझाना। विभिन्न केन्द्रों पर +2 स्तर के शिक्षणार्थियों के लिए बहुविकल्पी परीक्षण लागू किया गया और उनके द्वारा उल्लिखित कारणों को समझने के लिए समूह साक्षात्कार आयोजित किए गए। विभिन्न परीक्षणों के लिए नमूना प्रतिवर्ती 368 से 475 तक थे। उपलब्धियों से पता चला कि एक निश्चित विषय पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की गई थी और वास्तविक रूप में पढ़ने के बाद उन्होंने क्या स्पष्ट किया, दोनों के बीच सार्थक वैविध्य के प्रमाण मौजूद हैं। हम क्या पढ़ायें और क्या सीखा गया, इसके अंतराल को कम करने के लिए पी.आई. ने निम्नलिखित सहायक हो सकने वाले सुझाव दिए:

- वास्तविक संसार से जुड़ी हुई प्रासंगिक विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए।
- विद्यार्थियों में सोच-विचार के ढाँचे का अध्ययन और परिवर्तन किया जाना चाहिए।

- विद्यार्थियों को विज्ञान प्रक्रिया की दक्षताओं, खासतौर से आदर्शीकरणों और पूर्वानुमानों की पहचान से जुड़ी हुई योग्यता, सादृश व अधिगम की गुणात्मक व्याख्या और गणितीय परिणामों के विश्लेषण की आवश्यकता से परिचित कराना।
- भौतिकी के अध्यापकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का पुनर्नवीकरण करना चाहिए।

(2) हाईस्कूल स्तर पर बधिर बच्चों में पठन दक्षता विकास की कार्यनीति

डा. पी. विमला देवी, तिरुपति

इस अध्ययन के प्रमुख उद्‌देश्य थे- (1) कक्षा 9 में बधिर विद्यार्थियों के पठन स्तर की पहचान, (2) पठन स्तरों में अंतराल की पहचान, (3) कक्षा 9 में चार विद्यालय विषयों- तेलुगू, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन- को पढ़ रहे बधिर बच्चों के पठन स्तर में सुधार के तरीकों का विकास और (4) इन तरीकों की प्रभाविता का परीक्षण। इस अध्ययन की रूपरेखा सर्वेक्षण सह-प्रयोगात्मक है। बधिर विद्यार्थियों की शैक्षिक दक्षता के विकास पर उनके प्रभाव के लिए बारह परिवर्ती चुने गए। कक्षा 12 के 142 बधिर विद्यार्थियों पर नमूने के रूप में पठन बोध परीक्षण लागू किया गया। अध्ययन की उपलब्धियों से ज्ञात हुआ कि (1) लागू की गई नीतियों के माध्यम से प्रयोगात्मक समूह के विद्यार्थी पठन योग्यता के विकास में सक्षम थे जबकि नियंत्रित समूह ने कोई सुधार प्रदर्शित नहीं किया, (2) तेलुगू में पठन दक्षता का संपूर्ण विकास 13.71%, गणित में 35.9%, जीव विज्ञान में 29.19%, और समाज विज्ञान में यह 34.80% था, जो 0.01 स्तर पर अभिव्यंजक थे, (3) पारस्परिक अंतःसंबंधी सांचे से स्पष्ट था कि संप्राप्ति में संबंध था और पठन दक्षता योग्यता का श्रवण विकार की मात्रा से कोई संबंध नहीं था, (4) बधिर बच्चों में पठन दक्षता 39% से कम थी, (5) श्रवण विकार विद्यार्थियों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला एक बुनियादी घटक नहीं था। अध्ययन से पता चलता है कि महत्वपूर्ण पठन दक्षताओं, जैसे- पहचानना, संघटन, मिलाना, निष्कर्ष निकालना, निर्णय लेना और प्रयोग करना- का विकास कक्षा स्थितियों में निर्धारित पाठ्य से पाठ पढ़ाते समय प्रश्न पूछकर और निर्देश के माध्यम से किया जा सकता है। वास्तव में पठन दक्षताओं के विकास के लिए कक्षा में पढ़ाए गए सभी पाठों में इन दक्षताओं के विकास का अभ्यास करना है।

(3) मिडिल विद्यालयों के विज्ञान-शिक्षण में विज्ञान प्रौद्योगिकी सोसायटी (एस.टी.एस.) उपागम का विकास और चुने हुए विद्यालयों में इसकी प्रभाविता का परीक्षण

डा. ए.सी. बैनर्जी, प्रो. एवं अध्यक्ष
डी.ई.एन.एफ.ए.एस., एन.सी.ई.आर.टी.

(1) मिडिल विद्यालयों में विज्ञान-शिक्षण के एस.टी.एस. माड्यूल व परीक्षण, एस.टी.एस. उपागम का विकास व क्षेत्र परीक्षण और (2) अवधारणाओं के विविध क्षेत्रों में योग्यताओं का विकास, समस्या समाधान और निर्णय-निर्माण, रचनात्मक सोच और अभिवृत्ति के विकास में पारंपरिक उपागम की तुलना में एस.टी.एस. उपागम की प्रभविष्णुता का मूल्यांकन। तीन विद्यालयों से नौ अध्यापकों, प्रत्येक विद्यालय से तीन अध्यापक और 622 विद्यार्थियों (कक्षा छह, सात और आठ) से, एस.टी.एस. समूह के 305 विद्यार्थियों और पाठ्यपुस्तक समूह के 317 विद्यार्थियों से नमूना लिया गया। 14 एस.टी.एस. माड्यूल विकसित किए गए। इस अध्ययन के लिए प्री-पोस्ट कन्ट्रोल ग्रुप के साथ एक अर्द्ध-प्रयोगात्मक रूपरेखा अपनाई जा चुकी है। एस.टी.एस. कक्षाओं के विद्यार्थी प्रयोगात्मक समूहों के हैं जबकि पाठ्यपुस्तक कक्षाओं के विद्यार्थी नियंत्रण समूह के हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण में शामिल हैं- युग्मित और अयुग्मित टी-टेस्ट्स, एकमार्गीय एनोवा (ए.एन.ओ. वी.ए.) और बेनोफरीन बहुआयामी परीक्षण। इस अध्ययन से पता चला कि रचनात्मकता के क्षेत्रों में एस.टी.एस. और पाठ्यपुस्तक समूहों के विद्यार्थियों की योग्यताओं में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं था। अभिवृत्ति क्षेत्र के परिणाम प्रदर्शित करते हैं कि एक परियोजना विद्यालय में विज्ञान अध्यापकों और कक्षाओं के प्रति एस.टी. एस. उपागम ने प्रत्येक विद्यार्थी की अभिवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन किए। इस प्रकार प्राथमिक कक्षाओं में बेहतर समाधान और निर्णय-निर्माण की योग्यताओं के विकास में एस.टी.एस. उपागम विश्वसनीय है।

(4) आंध्र प्रदेश में आदिम चेन्चू जनजाति समूह में बच्चों की शिक्षा की समस्याएँ

डा. जी. ईश्वरैया, हैदराबाद

वर्तमान अध्ययन आंध्र प्रदेश में आदिम चेन्चू में बच्चों की शिक्षा की समस्याओं से संबंधित है। अध्ययन का उद्देश्य निम्न को विस्तार से जानना है: (1) पुरातनता, (2) अन्यत्रवासिता, निष्क्रियता और विद्यालय छोड़ना, (3) अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता-पिता की जागरूकता और अभिवृत्ति, (4) शिक्षा के लिए बच्चों की आकांक्षा, (5) चेन्चू विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों की अंतर्क्रिया और रुचि, (6) साक्षरता से जुड़े हुए सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक और प्रशासनिक कारक, (7) देशांतरण और शिक्षा, (8) चेन्चू बच्चों की शिक्षा पर जनजाति विकास कार्यक्रमों का प्रभाव और (9) बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए मानकों का सुझाव। वर्तमान अध्ययन के आंकड़े में 528 परिवार और 2212 जनसंख्या शामिल है, जो आंध्र प्रदेश के छह जिलों से चुने हुए हैं। अध्ययन के निष्कर्ष से पता चला कि (1) चेन्चू घरेलू पशु और मुर्गी पालन में रुचि रखते हैं और उन्हें अनवरत पशु-चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता है, (2) प्राइमरी स्तर पर सब मिलाकर उनकी उच्च साक्षरता दर 76.6%, कम नामांकन अनुपात नगण्य, शाला-त्याग और अनियमित उम्र में प्रवेश (अधिक उम्र और कम उम्र में), (3) लम्बी अवधि की विद्यालयी शिक्षा के प्रति अनिच्छा के कारण सातवीं कक्षा के बाद नामांकन में तेज़ी से गिरावट। पितृसत्ता समाज के कारण प्राय: सभी लड़कियाँ सातवीं कक्षा के बाद रोक दी जाती हैं, (4) कुछ विद्यार्थियों के लिए हिन्दी, गणित और विज्ञान जैसे विषय कठिन हैं, सरकारी खर्च पर विशेष कोचिंग की आवश्यकता है और (5) कक्षा प्रबंधन और अच्छा होना चाहिए। अध्यापक को प्रत्येक बच्चे पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

(5) बिहार में एकीकृत शिक्षा प्रणाली : विकलांग विद्यार्थियों के समायोजन का एक अध्ययन

डा. शशि प्रभा, पटना विश्वविद्यालय, पटना

वर्तमान अध्ययन का झुकाव एकीकृत शिक्षा प्रणाली का समग्रता में अध्ययन और मूल्यांकन की ओर है। अध्ययन का उद्देश्य है- (1) विकलांग विद्यार्थियों के पृष्ठभूमिगत लक्षणों, उनकी शैक्षिक और व्यावसायिक आकांक्षा के स्तरों की जाँच करना, (2) अध्यापकों और गैर-विकलांग विद्यार्थियों के साथ विकलांग विद्यार्थियों की प्रकृति और एकीकरण के तरीकों का मूल्यांकन, (3) विकलांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन और प्रदान की गई तथा उपलब्ध सुविधाओं के अन्तर को निश्चित करना, (4) एकीकरण की प्रक्रिया में विकलांग विद्यार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान और (5) विकलांग विद्यार्थियों में समायोजन की समस्याओं, जैसाकि उनके संसाधन शिक्षकों, माता-पिता और गैर-विकलांग विद्यार्थियों द्वारा अनुभव किया गया था, का अध्ययन। इस अध्ययन में 500 विकलांग बच्चे (70 दृष्टिहीन, 25 बधिर, 370 अस्थि विकलांग और 15 बहु-विकलांग) शामिल हैं। जांच के क्रम में यह पाया गया कि सरकार द्वारा दी गई सभी सुविधाओं को विद्यालय प्राप्त नहीं करते और विकलांग विद्यार्थियों के निर्दिष्ट नामांकन को 100 प्रतिशत सुनिश्चित नहीं करते। विकलांगों के प्रवेश की नीति में सुधार की आवश्यकता है। एकीकरण के विस्तार और एकीकरण की प्रक्रिया में सामने आने वाली समस्याओं के संदर्भ में यह पाया गया कि विकलांगों से उनके माता-पिता और अभिभावकों द्वारा लगाव और प्यार का व्यवहार किया जाता है और विद्यालयी जीवन में यह व्यवहार सामान्य संबंध बनाने में उनकी मदद करता है। अधिकतर विकलांग और गैर-विकलांग विद्यार्थी पुस्तकों के आदान-प्रदान और दूसरे कुछ अन्य क्रियाकलापों में एक दूसरे की मदद करते हैं लेकिन साथ-साथ मनोरंजक स्थानों के भ्रमण में अनिच्छुक रहते हैं। यह संकेतित करता है कि एक दूसरे का साथ देने में मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। अध्ययन ज़ोर देकर प्रदर्शित करता है कि शारीरिक-विकलांग विद्यार्थियों में सामाजिक अंतर्क्रिया और शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित समायोजन की समस्याओं की अपेक्षा भावनात्मक दवाब और तनाव ज़्यादा होता है। चूंकि वे विकलांग हैं, उनमें अध्ययन के प्रति पर्याप्त रुचि का अभाव होता है और उनमें से कुछ बोध में समस्या का सामना करते हैं। पी.आई. ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

(6) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में नवोदय विद्यालयों के कार्य और प्रबंधन का मूल्यांकन

डा. पी.पी. गोकुलनाथन, शिलांग

इस अध्ययन में जवाहर नवोदय विद्यालयों द्वारा क्षेत्र स्थिति में अपनायी जाने वाली कार्य पद्धति और प्रबंधन रणनीति के पुनरीक्षण का विचार है। अध्ययन के उद्देश्य हैं- (1) विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की गुणवत्ता के साथ-साथ अध्यापकों और विद्यार्थियों के संघटक का विश्लेषण करना, (2) जवाहर नवोदय विद्यालयों के कार्य और प्रबन्धन का अध्ययन करना, (3) विभिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की उपलब्धियों के स्तरों का पता लगाना, (4) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए विद्यालयों द्वारा की जा रही गतिविधियों का पता लगाना और (5) क्षेत्र में विद्यालयों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का अध्ययन। नमूने में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न भागों में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों से 75 अध्यापकों और 322 विद्यार्थियों को लिया गया है। अध्यापकों, विद्यार्थियों और प्रधानाध्यापकों के लिए बनाई गई प्रश्नावलियों द्वारा सूचना इकट्ठी की गई। निष्कर्षों में संक्षेप में निम्न शामिल हैं- उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय जवाहर नवोदय विद्यालयों के बारे में सूचना, क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालयों का प्रबंधन, आर्थिक प्रशासन, प्रदान की गई सुविधाएं, संबंधित कार्मिकों की स्थिति, विद्यार्थियों की सूचना, अकादमिक संगठन, विद्यार्थियों का प्रदर्शन, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में अनुभव की गई ताकतें और कमज़ोरियाँ, जवाहर नवोदय विद्यालयों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। अध्ययन में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जवाहर नवोदय विद्यालयों की योजना को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी शामिल हैं। इसमें 21वीं सदी के लिए दृष्टिकोण भी शामिल है।

(7) विद्यार्थियों से शिक्षक-प्रत्याशाएं और शिक्षण प्रक्रिया तथा विद्यार्थी-निष्कर्षों से उनके संबंध

डा. एन.सी. धोन्डियाल, अल्मोड़ा

यह अध्ययन निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है- (1) हाई स्कूल स्तर पर सेवाकालीन शिक्षकों में सामान्यीकृत शिक्षक-प्रत्याशाओं के समूह की मौजूदगी का सर्वेक्षण, (2) चयनित अध्यापक लक्षणों और उनकी सामान्यीकृत प्रत्याशाओं के बीच संयोजन का विश्लेषण, (3) कक्षा व्यवस्था में अलग-अलग अध्यापक-प्रत्याशाओं पर विचार करना और (4) उच्च और निम्न प्रत्याशा समूहों में विद्यार्थियों के नामांकन के द्वारा व्यक्त हुई अध्यापकों की सामान्यीकृत प्रत्याशाओं और उनकी अलग-अलग प्रत्याशाओं के बीच साहचर्य का विश्लेषण। नमूने में अल्मोड़ा ज़िले के यादृच्छिक रूप से चयनित 38 विद्यालयों के हाई स्कूल स्तर की कक्षाओं में पढ़ा रहे 335 अध्यापक शामिल हैं। अध्ययन से पता चला कि विद्यार्थी-निष्कर्षों के परिवर्त्यों जैसे- समायोजन, स्व-अवधारणा, प्रतिभा, शैक्षिक दुश्चिंता, अध्ययन से जुड़ाव और अकादमिक उपलब्धि अवबोधन पर अंक प्राप्ति में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था, जबकि अकादमिक उपलब्धि अभिप्रेरणा और अकादमिक उपलब्धि की संप्राप्ति में उच्च और निम्न अध्यापक प्रत्याशाओं वाले विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण अन्तर था। यह पाया गया कि अकादमिक उपलब्धि अभिप्रेरणा और वास्तविक अकादमिक उपलब्धि के संबंध में उन विद्यार्थियों ने जो उच्च शिक्षक-प्रत्याशा समूह में नामांकित थे, निम्न शिक्षक-प्रत्याशा समूह में नामांकित विद्यार्थियों की तुलना में उच्च औसत अंक प्राप्त किए। यह भी निष्कर्ष निकला कि वैयक्तिक विद्यार्थियों के बारे में प्रत्याशाओं के प्रतिपादन की प्रक्रिया में, विद्यार्थी के गुणों पर अध्यापक का अवबोधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(8) दृष्टिहीन बच्चों में मापन-संबंधी अवधारणाओं का विकास

डा. देबजानी सेनगुप्ता, कलकत्ता

इस अध्ययन का उद्देश्य है, दृष्टिहीन, आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चों, जैसाकि उनके दृष्टि प्रतिरूपों के आधार पर तुलना की गई, के मासिक व्यवहार की व्याख्या। इस अध्ययन में 6 से 12 वर्ष की आयुवर्ग के 160 पूर्ण दृष्टियुक्त, आंशिक दृष्टि और दृष्टिहीन बच्चों के नमूने लिए गए। आंकड़ा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्रियाँ हैं- व्यक्तिगत आंकड़ा प्रपत्र और वस्तु के विभिन्न गुणों जैसे दूरी, लम्बाई, क्षेत्र, घनत्व, द्रव्यमान और भार आदि के मापन में बच्चों की योग्यता के मूल्यांकन के लिए परीक्षणों की बैटरी। समय के अवबोधन और मापन में

बच्चों की दक्षता का भी परीक्षण किया गया। उपलब्धियों से पता चला कि दृष्टिहीन और आंशिक दृष्टि वाले बच्चे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापन के क्रम में दृष्टियुक्त बच्चों के बराबर थे लेकिन संरक्षण और पृथक मूल्यांकन में निश्चित रूप से पीछे रह गए। दृष्टिहीन बच्चों को आस-पास के वातावरण से समय का अनुमान लगाने में कठिनाई हुई। विद्यालयों और सुधार कार्यक्रमों के लिए निष्कर्षों के गंभीर निहितार्थ हैं क्योंकि दैनिक जीवन में दूरी, भार, समय आदि के मापन की क्षमता अत्यन्त आवश्यक है। रिपोर्ट में गतिविधियों के मापन में सहायक पाठ्यचर्या की एक बाह्य रूपरेखा भी सुझायी गई है।

(9) शिक्षार्थियों के सामने पारिवारिक समस्याएँ, सामाजिक - आर्थिक स्तर, साक्षरता केंद्रों में उपलब्ध भौतिक सुविधाएं, साक्षरता कार्यक्रम के संगठनात्मक और अनुदेशात्मक पहलू और पश्चिम बंगाल में महिला साक्षरता की उपलब्धि से उनके संबंध का आलोचनात्मक अध्ययन

डा. शर्मिष्ठा चक्रवर्ती, कलकत्ता

इस अध्ययन का उद्देश्य (1) साक्षरता कक्षाओं में शामिल होने के लिए महिला शिक्षार्थियों के सामने घर की समस्याएं और साक्षरता में उनकी उपलब्धि पर इसके प्रभाव का निर्णय, (2) साक्षरता केंद्रों पर उपलब्ध भौतिक सुविधाएं और महिला साक्षरता उपलब्धि से इनका संबंध, (3) शिक्षार्थी की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और यह शिक्षार्थियों की उपलब्धि को कैसे प्रभावित करती है, का निर्णय, (4) साक्षरता कार्यक्रम का संगठनात्मक पहलू और साक्षरता उपलब्धि से इसके संबंध का अध्ययन करना है। पश्चिम बंगाल के दो ज़िलों से साक्षरता उपलब्धि के अभिलिखित ढांचे के आधार पर 9-16 वय वर्ग के 302 महिला शिक्षार्थियों का नमूना इसमें समाविष्ट है। अधिकतर टूल्स संरचनागत और कुछ मुक्त थे। अध्ययन की उपलब्धियों से पता चला कि (1) अनुसूचित जाति शिक्षार्थियों का निष्पादन भाषा समस्या के कारण खराब था, (2) बीरभूम ज़िले के शिक्षार्थियों का प्रदर्शन दक्षिण चौबीस परगना ज़िले के शिक्षार्थियों की अपेक्षा महत्वपूर्ण रूप से अधिक था, (3) उपलब्धि परिवार के आर्थिक स्तर पर निर्भर नहीं थी, (4) साक्षरता में आय और उपलब्धि के बीच कमज़ोर आपसी संबंध था, (5) परिवार के शैक्षिक स्तर ने शिक्षार्थियों को प्रभावित किया, (6) साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु जिन स्थानों पर पर्यवेक्षक, ग्राम शिक्षा समिति और पंचायत सम्मिलित प्रयास कर रही थीं वहीं साक्षरता दर ऊंची (64.6%) थी, (7) जो महिला शिक्षार्थी गृह कार्य और बाहरी कार्य दोनों से जुड़ी हुई थीं, उनका प्रदर्शन केवल घरेलू क्रियाकलापों में लगी हुई महिलाओं से बेहतर था। इससे पता चलता है कि साक्षरता केंद्रों में महिला शिक्षार्थी नियमित अन्योन्यक्रिया का अवसर पा रही थीं।

(10) हिंदी और उड़िया में भाषा दक्षता परीक्षणों का विकास और उनका मानकीकरण

डा. ताप्ति दत्ता, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर

इस अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 7 तक में पढ़ रहे डिस्लैक्सिक बच्चों के निदान के लिए हिंदी और उड़िया में भाषिक दक्षता परीक्षणों का विकास और मानकीकरण तथा प्रायोगिक उपचार कार्यक्रम के लिए नियत सुझाव प्रदान करना है। नमूने के अंतर्गत कक्षा 1 से 7 तक के 700 विद्यार्थी, 350 हिन्दी माध्यम के और 350 उड़िया माध्यम के, जो पटना और भुवनेश्वर के 10 विभिन्न शहरी विद्यालयों से चुने गए, शामिल हैं। आंकड़े का विश्लेषण हिंदी और उड़िया दोनों के लिए शब्द डिकोडिंग और परिच्छेद बोध परीक्षणों से कार्यकारी नियमों की स्थापना के लिए किया गया। इन परीक्षणों में जिन विद्यार्थियों ने खराब प्रदर्शन किया, उनके लिए उपचारात्मक कार्यक्रम बनाया गया। पूर्व परीक्षण और परीक्षणोत्तर परिणाम की तुलना प्रदर्शित करती है कि जिन बच्चों ने उपचारात्मक कार्यक्रम में हिस्सा लिया उनके अंकों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई।

(11) उड़ीसा के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन

डा. बी.एन. पांडा, क्षे.शि.सं., भुवनेश्वर

सभी विद्यालयी विषयों में ग्रामीण, शहरी और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर की तुलना इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ शिक्षार्थी उपलब्धि पर

घर और विद्यालय से जुड़े हुए अध्यापक प्रभाव का भी अध्ययन किया गया। नमूने में 6 ज़िलों के 7 ब्लाकों के 64 विद्यालयों, 245 अध्यापकों और 882 विद्यार्थियों (478 लड़के और 404 लड़कियों) को शामिल किया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि अभिभावकों की शिक्षा और आय, घर पर भोजन की उपलब्धता शिक्षार्थी प्रदर्शन को बढ़ाने में अर्थपूर्ण हैं। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण, विद्यालय संसाधन और प्रोत्साहन योजनाएँ, विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाएँ संप्राप्ति की वृद्धि में बहुत प्रभावी हैं। शहरी क्षेत्रों में गणित की संप्राप्ति और जनजाति क्षेत्रों में भाषा उपलब्धि में अध्यापक की योग्यता के अलावा अध्यापक की गुणवत्ता संप्राप्ति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं रखती। प्रोत्साहन योजनाओं में, ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों में दोपहर के भोजन और छात्रवृत्तियों तथा जनजाति क्षेत्रों में मुफ्त पाठ्यपुस्तकों और मुफ्त यूनिफार्म (वर्दी) को संप्राप्ति की वृद्धि में बहुत ही प्रभावी पाया गया।

(12) प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के विशेष संदर्भ में उत्तर प्रदेश में बालिका प्रोत्साहन योजनाओं का प्रभाव

डा. जी.डी. भट्ट, दिल्ली

यह अध्ययन लड़कियों पर दोपहर के भोजन योजना के प्रभाव तक ही सीमित है। उ.प्र. में लड़कियों के लिए दूसरी प्रोत्साहन योजना नहीं है। इस अध्ययन का उद्देश्य निम्न बातों का अध्ययन करना रहा- (1) उ.प्र. सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दोपहर का भोजन क्या सभी समूह की बालिकाओं को उपलब्ध था, (2) प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन, उपस्थिति और विद्यालय में बने रहने पर क्या इस योजना का कोई सकारात्मक प्रभाव है, (3) लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता-पिता के मनोवृत्तिगत परिवर्तन में क्या इस योजना का प्रभाव है और (4) बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए दोपहर के भोजन की योजना के क्रियान्वयन में क्या कोई प्रशासनिक अड़चन है। अध्ययन की उपलब्धियों से पता चला कि उ.प्र. सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा दोपहर का भोजन सभी वर्गों की लड़कियों को उपलब्ध है और लड़कियों की शिक्षा के प्रति माता-पिता के मनोवृत्तिगत परिवर्तनों पर इसका सकारात्मक प्रभाव है। आंकड़े बताते हैं कि दोपहर के भोजन की योजना के लागू होने के बाद नमूना विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हुई है। अपेक्षित लक्ष्य समूह पर यू.ई.ई. क्रियान्वित करने में पी. आई. महसूस करता है कि राज्य के हर प्राथमिक विद्यालय में अन्य प्रोत्साहन योजनाएँ जैसे- मुफ्त यूनिफार्म, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और उपस्थिति छात्रवृत्ति योजनाएँ लागू की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मेधावी विद्यार्थियों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहनों को भी लागू करना चाहिए।

(13) बुद्धि की संस्कृति और प्रत्ययात्मकता

डा. ए.के. श्रीवास्तव, डी.ई.आर.पी.पी.
एन.सी.ई.आर.टी.

इस अध्ययन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बुद्धि की देशज धारणा की पहचान करना है। इस क्रम में निम्नलिखित प्रयास किए गए: (अ) देशज विचार की भारतीय विद्वत्ता और परम्पराओं को प्रमाण के रूप में प्रलेखित, विश्लेषित और प्रस्तुत करना, (ब) लोक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से बुद्धि के सामाजिक-सांस्कृतिक निर्माण का परीक्षण। एक द्विपक्षीय सैद्धान्तिक रणनीति अपनाई गई। प्रथम चरण में भगवद् गीता की शिक्षाओं, व्यवहारों को प्रभावित करने वाली संस्कृत सूक्तियों और हिन्दी लोकोक्तियों में निहित आम आदमियों के विचार और अनुभूतियों के विश्लेषण का प्रयास किया गया। द्वितीय चरण में एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन के रूप में आम आदमी की समझदारी और बुद्धि के प्रयोग का गहराई से अध्ययन किया गया। इसके लिए विविध आर्थिक-सांस्कृतिक संदर्भों, शिक्षा, उम्र और लिंग के चयनित 1885 भागीदारों को शामिल किया गया।

निष्कर्ष से यह भी प्रदर्शित हुआ कि भारतीय दृष्टि संज्ञानात्मक योग्यताओं की पहचान और उत्प्रेरक संज्ञानात्मक योग्यताओं के संदर्भित सार ढाँचे के अलावा प्रभावी घटकों को भी ध्यान में रखती है। बुद्धि के चार पहलुओं की पहचान की गई। ये हैं- संज्ञान, सामाजिक दक्षता, कार्य-प्रदर्शन और व्यक्तित्व। कुल मिलाकर, इस कार्य से बुद्धि की जो दृष्टि उभरी उसे 'समग्र' नाम दिया जा सकता है जिसमें पूर्णता, अंतर्संपर्क, अंतर्निर्भरता और पूरकता पर ज़ोर है। अध्ययन यूरो-अमेरिकन देशों के सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर विकसित मानदण्डों की बजाय अध्ययन में उल्लिखित बुद्धि की देशज धारणा पर आधारित बुद्धि के मानदण्डों के विकास का समर्थन करता है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी अनुसंधान अध्ययन

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	मुख्य अन्वेषक
1.	विभिन्न राज्यों में सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन	डा. डी.पी. सिंह पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
2.	माध्यमिक व्यावसायिक विद्यालयों में विद्यालय उद्योग संयोजन का स्थापना-कार्य अनुसंधान	डा. सौरभ प्रकाश पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
3.	भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर आधारित व्यापार और वाणिज्य में व्यावसायिक प्रवेश का स्थितिपरक अध्ययन	डा. ए. पालेनिवेल पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
4.	व्यावसायिक शिक्षा की तुलना में शहरी और ग्रामीण समाजों में लड़कियों की जीविका आकांक्षा	डा. (सुश्री) पूनम अग्रवाल पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
5.	दक्षिणी क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा के संस्थानों द्वारा प्रस्तावित, विद्यार्थी अध्यापकों द्वारा चयनित और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अपेक्षित विशेषज्ञता के विषयों का अध्ययन	डा. के डोरास्वामी आर.आई.ई., मैसूर
6.	राज्यों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का दिशा-निर्देश सर्वेक्षण	डा. (श्रीमती) के. माथुर पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
7.	उड़ीसा के जनजातीय बच्चों के विज्ञान अधिगम पर मनोवैज्ञानिक - सामाजिक घटकों के प्रभाव	डा. (श्रीमती) एम. महापात्र आर.आई.ई., भुवनेश्वर
8.	प्रारंभिक स्तर (कक्षा 6, 7,8) पर विज्ञान शिक्षण के एकीकृत पद्धति के नमूने का विकास	डा. एम.के. सत्पथी आर.आई.ई., भुवनेश्वर
9.	प्रारंभिक स्तर पर अध्यापक शिक्षकों के लिए शिक्षण रूपरेखा और उपलब्ध दक्षताओं की एक पार्श्विका का विकास	डा. वी.डी. भट्ट आर.आई.ई., मैसूर
10.	चयनित राज्यों में व्यावसायिक पाठ्यचर्या और अनुदेशी सामग्री की गुणवत्ता और मानक का तुलनात्मक मूल्यांकन	डा. जी. भार्गव पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
11.	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता की पहचान और पोषण- एक खोज	डा. अंजुम सीबिया डी.ई.पी.एफ.ई.

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	मुख्य अन्वेषक
12.	महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर गृह विज्ञान-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का महत्व	डा. पिंकी खन्ना पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
13.	10+2 स्तर के विद्यार्थियों में कौशलों के विकास में शिक्षक व्यवस्था की भूमिका	डा. वी.के. जैन पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
14.	महाराष्ट्र के व्यावसायिक संस्थानों में विद्यालय उद्योग संयोजन (एस.आई.एल.) का केस अध्ययन	डा. आस्फा एम. यासीन पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
15.	कृषि में व्यावसायिक पठन-पाठन के स्तर और प्रभविष्णुता का तुलनात्मक अध्ययन	डा. वी.एस.महरोत्रा पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
16.	पंजाब राज्य में रोज़गार प्रशिक्षण के कार्यान्वियन और व्यावसायिक विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का अध्ययन	डा. ब्रजवन्ती देवी पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. भोपाल
17.	विज्ञान-संप्राप्ति, संज्ञानात्मक-कौशल और विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में अवधारणा का प्रभाव	डा. मंजुला पी. राव आर.आई.ई., मैसूर
	एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रायोजित अध्ययन	
18.	शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों के अध्ययन और गृह-कार्य व्यवहार के संवर्धन से संबद्ध माता-पिता प्रशिक्षण तकनीकों का व्यवहारगत विश्लेषण और परिष्करण	डा. एस.एस. कौशिक वाराणसी
19.	वाराणसी में जूनियर हाई स्कूल के विद्यार्थियों के वैज्ञानिक-स्वभाव का अध्ययन	प्रो. वी.के. दूबे वाराणसी
20.	भारत में विद्यालय शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए नवाचारी संस्थान और उनके कार्यक्रम	प्रो. मोहम्मद मियां नई दिल्ली
21.	शिक्षा महाविद्यालयों में प्रशिक्षण निष्कर्षों पर मुख्य सांस्थानिक और अनुदेशिक परिवर्त्यों के प्रभाव का अध्ययन	डा. अरुण कुमार गुप्ता जम्मू
22.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किशोरों में नशीली दवाओं के सेवन की व्यक्तित्व-पार्श्विका और स्वभावगत अति संवेदनशीलता के परिष्कार के द्वारा मद्य-व्यसन को दूर करने के लिए निश्चित हस्तक्षेपकारी तकनीकों का प्रयोग	डा. एस. बैनर्जी वाराणसी
23.	विशेष शिक्षा अध्यापकों के प्रदर्शन की भूमिका	डा. जी.एल. रेड्डी कणयकुडी

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	मुख्य अन्वेषक
24.	अध्यापिकाओं में उत्प्रेरणा का कम होना	डा. (श्रीमती) एन. मिश्रा लखनऊ
25.	उत्तर प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान की शिक्षा में स्थानीय संसाधनों का प्रभाव	डा. जी.एस. पालीवाल गढ़वाल, (यू.पी.)
26.	महिला महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रों के प्रयोग की वृत्ति-परिपक्वता सूची का विकास	डा. (श्रीमती) ए. शुक्ला लखनऊ
27.	ग्रामीण समुदाय के लिए महिला शिक्षा कार्यक्रमों में महिला स्वास्थ्य कार्मिकों की भागीदारी की संभावना का अध्ययन	डा. (श्रीमती) पी. माथुर दिल्ली
28.	छह से आठ वय: वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर घरेलू पर्यावरण का प्रभाव	डा. सुधा भोगले बंगलौर
29.	अध्यापकों के उत्प्रेरणात्मक संलक्षणों पर कार्य अनुभव का प्रभाव	डा. उमा रंगन हैदराबाद
30.	दृष्टिहीन बच्चों के लिए हस्तकार्य की आवश्यकता	डा एम. इतिएरा दिल्ली
31.	आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों के प्रकार्यों का अध्ययन	डा. पी.एस. रेड्डी तिरुपति
32.	शैशवकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का मूल्यांकन और परिप्रेक्ष्यों की सुझाव योजनाएं	डा. एस.पी. मल्होत्रा कुरुक्षेत्र
33.	उड़ीसा में अलौकिक सदृशमूलक भाषा की खोज: इसके भाषा वैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और शैक्षिक निहितार्थ	डा. नंदिता बाबू भुवनेश्वर
34.	प्राथमिक स्तर के बच्चों में पठन संबंधी अक्षमता और संज्ञानात्मक सूचना प्रक्रिया	डा. एम.के. पाणी उड़ीसा
35.	विद्यालयी बच्चों में शैक्षिक कार्य निष्पादन के एकीकृत मध्यस्थता के प्रभाव का अध्ययन	डा. अर्चना डोगरा नई दिल्ली
36.	बोर्ड परीक्षा में छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति का मूल्यांकन और सोलो-टेक्सोनामी का तुलनात्मक अध्ययन	डा. रंजीत बसु कलकत्ता
37.	परंपरागत समाज में गणितीय अवधारणाओं की पहचान पर आधारित गणित में शिक्षण कार्य प्रणाली का विकास	डा. एन.सी. घोष कलकत्ता
38.	ग्रामीण क्षेत्रों में चुनिंदा भौतिकीय अवधारणाओं के प्रदर्शनात्मक शिक्षण के प्रभावकारी मॉडलों का विकास	डा. जी.एस. रॉय कटक

क्रम संख्या	अध्ययन का शीर्षक	मुख्य अन्वेषक
39.	कक्षा आठ में दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी के अधिगम और परीक्षण के संदर्भ में कंप्यूटर द्वारा भाषा-अधिगम की प्रभविष्णुता	डा. एन. बालसुब्रमण्यन कोयम्बटूर
40.	दृष्टिहीन छात्रों हेतु भौतिकी और जीव विज्ञान पर शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करने का प्रयास	डा. देबाशीष पॉल पश्चिम बंगाल
41.	शिक्षण की कार्यनीतियाँ, अध्यापकों का जुड़ाव और विद्यालय संप्राप्ति	डा. (सुश्री) बी.एस. रेड्डी हैदराबाद
42.	सूचना प्रक्रियन माध्यम द्वारा भौतिकी की कठिनाइयों को हल करने की योग्यता का विकास	डा. एस. मोहन करायकुडी
43.	बच्चों में भाषा अक्षमता को कम करने के लिए अनेक उपचारात्मक कार्यनीतियों की तुलना	डा. (श्रीमती) तेहल कोहली चण्डीगढ़
44.	जनजातीय और गैर-जनजातीय किशोरों की व्यावसायिक आकांक्षा, मूल्य और सामाजिक-आर्थिक स्तर के मध्य संबंध	श्रीमती एस कुमावत उदयपुर
45.	किशोरावस्था में आत्महत्या उद्‌भावना की मनोवृत्तियाँ	प्रो. वी.वी. उपमन्यु चण्डीगढ़
46.	विद्यालयी शहरी-गरीब बच्चों की समस्याएँ (बालिकाओं के विशेष संदर्भ में)	डा. एस.के. पन्त इलाहाबाद

प्रकाशन अनुदान

एरिक एन.सी.ई.आर.टी. की आंशिक सहायता से प्रकाशित पीएच.डी. शोध प्रबंध

शीर्षक	लेखक का नाम
कन्ज़र्वेशन ऑफ सब्सटेंसेज़ एमंग स्कूल चिल्ड्रेन	डा. प्रभा शुक्ला रायपुर

पी.ई.ओज़. को आर्थिक सहायता

शिक्षा के सुधार के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु 'व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों (पी.ई.ओज़.) को सहायता योजना' के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्येक संगठन को उसके सम्मुख लिखित विस्तार/प्रकाशन संबंधी गतिविधियों के लिए दस हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई:

संगठन	कार्यक्रम/क्रियाकलाप
भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	26-31 दिसम्बर 1999 को 33वीं इंडियन सोशल साइंसेज़ कांग्रेस का आयोजन
भारतीय गणित अध्यापक संघ (ए.एम.टी.आई.) चेन्नई	'जूनियर मैथेमेटीशियन' के हिंदी रूपान्तरण का प्रकाशन
गणित शिक्षण उन्नयन संघ कलकत्ता	'इंडियन जर्नल ऑफ मैथेमेटिक्स टीचिंग' का प्रकाशन

एरिक गोष्ठी

अनुसंधान परियोजनाओं की आर्थिक सहायता और अनुसंधान से जुड़े हुए दूसरे मामलों पर विचार करने के लिए एरिक की 31वीं बैठक एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली में 11-3-2000 को आयोजित की गई।

अनुसंधान पर एरिक द्वारा प्रायोजित संगोष्ठी

एरिक द्वारा वित्तीय सहायताप्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति तथा अनुवीक्षण के लिए छठी और सातवीं संगोष्ठी 27 से 29 मई 1999 को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल और 8 से 9 दिसम्बर 1999 को एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली में आयोजित की गई।

विशेषज्ञ समूह गोष्ठियाँ

उपर्युक्त गोष्ठियों जैसे 27-29 मई 1999 को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल और 8-9 दिसम्बर 1999 को एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली, के अलावा नए अनुसंधान प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह गोष्ठियाँ भी आयोजित की गईं।

अनुसंधान पत्रिकाएँ

शैक्षिक अनुसंधान पर एन.सी.ई.आर.टी. ने तीन पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं, जिनके नाम हैं- (1) जर्नल ऑफ इण्डियन एजुकेशन, (2) भारतीय आधुनिक शिक्षा, (3) इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू। 'इण्डियन एजुकेशनल रिव्यू' एक अर्द्धवार्षिक पत्रिका है जिसमें अनुसंधान पर्चे समाहित रहते हैं। 'जर्नल ऑफ इण्डियन एजुकेशन' और 'भारतीय आधुनिक शिक्षा' अंग्रेज़ी और हिन्दी की त्रैमासिक पत्रिकाएँ हैं। इन दोनों पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य है- नवाचारी विचारों के प्रस्तुतीकरण द्वारा अध्यापकों, अध्यापक प्रशिक्षकों, शैक्षिक प्रशासकों और शोधकर्ताओं को फलदायी और अनवरत अंत:क्रिया के लिए एक खुला मंच प्रदान करना। शिक्षा की नवीनतम प्रगति से पाठकों को परिचित कराकर ये पत्रिकाएं विद्यालयी शिक्षा के सभी पहलुओं में नई सोच का विकास करती हैं।

प्रशिक्षण

डाइट और एस.सी.ई.आर.टी. संकाय के लिए अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण कार्यक्रम

विभाग ने एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली में 27 मार्च से 7 अप्रैल 2000 तक उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुल 24 डाइट और एस.सी.ई.आर.टी. संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अनुसंधान पद्धति के विभिन्न घटकों पर बातचीत करने के साथ-साथ प्रतिभागियों ने बारह अनुसंधान प्रस्तावों का विकास किया जिसे वे अपने कार्य स्थल पर ले जा सकते हैं।

एन.आई.ई. व्याख्यानमाला

एन.आई.ई. व्याख्यानमाला के अंतर्गत 10 और 11 अगस्त 1999 को एक प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री प्रो. आर.एच. दवे ने निम्नलिखित विषयों पर भाषण दिया-

1. एन.सी.ई.आर.टी. के सम्मुख कार्य
2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता के संदर्भ में पाठ्यचर्या विकास
3. विद्यालयी शिक्षा में मूल्यांकन और निर्धारण : उभरती प्रवृत्तियाँ
4. विद्यालयी शिक्षा में अनुसंधान : उभरती संभावनाएँ

शैक्षिक सर्वेक्षण

जनगणना और नमूने के आधार पर शैक्षिक सर्वेक्षण संचालित करना एन.सी.ई.आर.टी. का एक महत्वपूर्ण कार्य है। वर्ष के दौरान निम्नलिखित शीर्षकों की परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। 'प्राथमिक स्तर पर एक आयु-वर्ग के नामांकन का अनुमान', 'प्राथमिक स्तर पर निष्क्रियता और शाला-त्याग-उत्तर प्रदेश के दो चयनित ज़िलों में नमूना अध्ययन', 'विद्यालयी शिक्षा का वर्धन : एक आलेखीय प्रस्तुतीकरण', 'प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए प्रोत्साहनकारी योजनाओं का मूल्यांकन और पुनरीक्षण' तथा उपकरणों के निर्माण, आकड़ों के एकत्रीकरण तथा विश्लेषण और आंकड़ों के प्रचार-प्रसार की रणनीति पर विचार-विमर्श करने हेतु 6 अक्टूबर 1999 को एक गोष्ठी आयोजित की गई। 7वीं ए.आई.एस.एस.ई. के लिए आंकड़ों को सारणीबद्ध करने हेतु रणनीति के बारे में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई।

छठी ए.आई.ई.एस. की योजना और संचालन में ज़िला शिक्षा अधिकारियों और दूसरे अधिकारियों तथा राज्यों के उन अधिकारियों को जिनके लिए नीपा में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, एक अभिविन्यास प्रदान किया गया। 'शैक्षिक

सांख्यिकी (विद्यालय शिक्षा) भाग-1 का विश्वकोश' परियोजना पर कार्य शुरू किया जा चुका है।

कंप्यूटर संसाधन केन्द्र

एस.पी.एस.एस. का प्रयोग करते हुए मात्रात्मक अनुसंधान तरीकों में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम-20 दिसम्बर 1999 से 7 जनवरी 2000 और 21 मार्च 2000 से 7 अप्रैल 2000 तक संचालित किए गए। एन.आई.ई. के विभिन्न अनुसंधानों, परिषद् की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज (एन.टी.एस.) योजना के परिणामों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर के प्रायोगिक विद्यालय में कक्षा-1 में प्रवेश के आंकड़ों को संसाधित करने का काम जारी है।

सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, योजना आयोग और भारतीय सामाजिक विज्ञान और अनुसंधान परिषद् को, शैक्षिक सांख्यिकी पर उनकी समितियों के लिए, सलाह प्रदान की गई। एन.आई.ई. विभागों के संकाय को उनकी परियोजनाओं के लिए विश्लेषण योजना और अनुसंधान की रूपरेखा विकसित करने में सहयेाग किया गया।

वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें और अन्य सामग्री

- सिक्स्थ ऑल इण्डिया एजुकेशनल सर्वे-मेन रिपोर्ट
- स्कूल एजुकेशन इन इण्डिया - ए ब्रोशर
- स्टेट पालिसिज़ ऑन इन्सेन्टिव स्कीम्स इन प्राइमरी स्कूल्स एण्ड देयर कन्ट्रीब्यूशन टु गर्ल्स पार्टिसिपेशन (प्रकाशनाधीन)
- ट्रेनिंग प्रोग्राम इन रिसर्च मैथडोलाजी फॉर डाइट एण्ड एस.सी.ई.आर.टी. फेकल्टी (अनुलिपि)।

20 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत सरकार के द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों से शैक्षिक सामग्री/सूचनाएँ जैसे पाठ्यपुस्तकें, अध्यापक निर्देशिकाएँ और पूरक पुस्तकें भेजीं और प्राप्त की गईं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में सहमति से पाठ्यचर्या क्षेत्रों में विशेषज्ञों के दौरों की अदला-बदली की गई। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त सामग्री को एन.सी.ई.आर.टी. के पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना प्रभाग (डी.एल.डी. आई.) के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र में प्रदर्शित किया गया।

एन सी ई आर टी विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों (सी.ई.पीज़.) के प्रबंधनों को कार्यान्वित करने वाली भारत सरकार की एक एजेंसी की तरह कार्य करती है। एन.सी.ई.आर.टी. विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को/एपिड/यू.एन.डी.पी. इत्यादि द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को भी लागू करती है और विचारों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए विदेशी शिष्टमंडलों और विशेषज्ञों हेतु कार्यक्रम आयोजित करती है। वह यूनेस्को, यू.एन.डी.पी., यूनीसेफ आदि के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, विचारविमर्श बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में प्रतिभागिता के लिए अपने संकाय सदस्यों को प्रायोजित करती है। एन.सी.ई.आर.टी., अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के लिए अल्पावधि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करती है। यह विभिन्न देशों, संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भारत में विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सूचनाएं भी उपलब्ध कराती है।

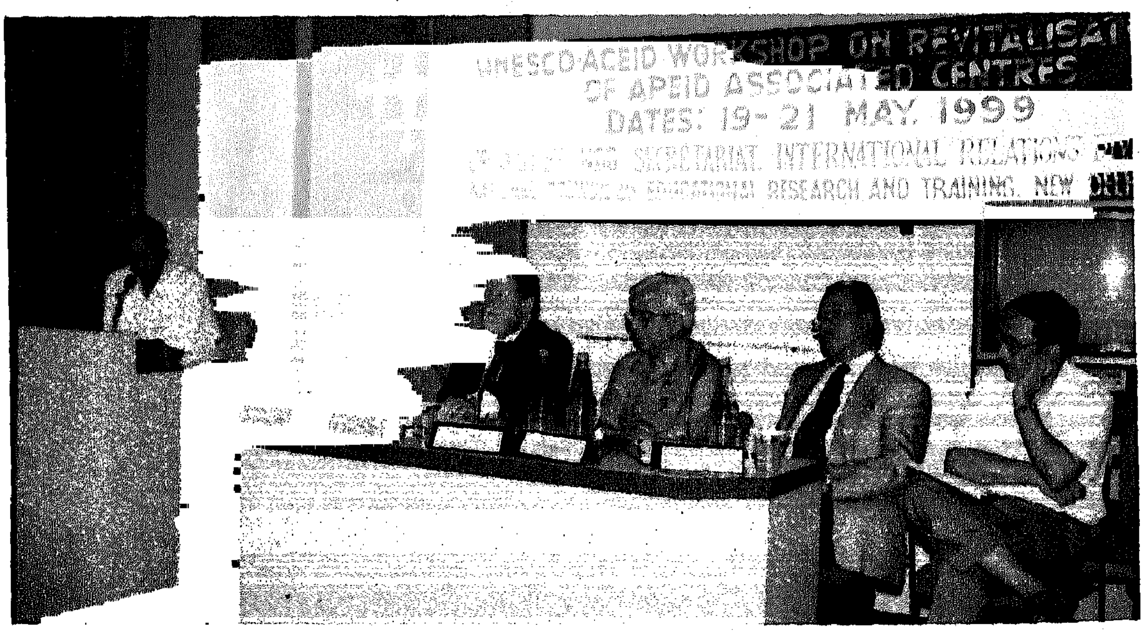
द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत सरकार के द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों से शैक्षिक सामग्री/सूचनाएँ जैसे पाठ्यपुस्तकें, अध्यापक निर्देशिकाएँ और पूरक पुस्तकें भेजीं और प्राप्त की गईं। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों में सहमति से पाठ्यचर्या क्षेत्रों में विशेषज्ञों के दौरों की अदला-बदली की गई। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त सामग्री को एन.सी.ई.आर.टी. के पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना प्रभाग (डी.एल.डी. आई.) के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र में प्रदर्शित किया गया। वर्ष 1999-2000 के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भारत सरकार सहित सीरिया, ग्रीस, कुवैत, कम्बोडिया और फ्रांस द्वारा निष्पादित किया गया।

एन.सी.ई.आर.टी. में विदेशी आगन्तुक

वर्ष 1999-2000 के दौरान विभिन्न देशों के निम्नलिखित शिक्षाविद्/विशेषज्ञ/शिष्टमंडल एन.सी.ई. आर.टी. पधारे :

- यू.के. से डा. मैरी हेरिस ने 13 जुलाई, 1999 को जेन्डर एंड मैथेमेटिक्स के क्षेत्र में तथा महिला अध्ययन विभाग के साथ प्राथमिक गणित अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर माड्यूल के मसौदे पर चर्चा करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया।
- प्रो. ई.आई. ब्राडकिन, प्रोफेसर (इतिहास), कनैक्टीकट कॉलेज, न्यू लंदन, इंग्लैंड ने 1 सितम्बर, 1999 को



अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग के तत्वावधान में एपिड से संबद्ध केंद्रों के पुनःस्फूर्तिकरण पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन-सत्र।

प्रायोगिक विद्यालय, क्षे.शि.सं. मैसूर और कनैक्टीकट कॉलेज, न्यू लंदन के मध्य छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम के संबंध में क्षे.शि.सं., मैसूर का दौरा किया। उन्होंने संस्थान और विद्यालय के सदस्यों के साथ बातचीत की और छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम के संबंध में विचार-विमर्श किया।

इंटरनेशनल रिसर्च फांउडेशन फॉर ओपन लर्निंग, इंग्लैण्ड के डा. हिलेरी पेर्राटन ने 8 सितंबर, 1999 को एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया। निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. ने उन्हें एन.आई.ई. विभागों सहित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की भूमिका और कार्यों के संबंध में संक्षिप्त विवरण दिया।

श्री क्लावर यीसा, निदेशक (योजना), शिक्षा मंत्रालय, रावांडा के नेतृत्व में दो सदस्यों के शिष्टमंडल ने 16 सितम्बर, 1999 को एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया और निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. के साथ शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यनीति तथा परिषद् के मुख्य कार्यक्रमों और क्रियाकलापों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने विज्ञान और गणित किटों के प्रदर्शन के संबंध में डी.सी.ई.टी.ए. का भी दौरा किया।

क्यूशू यूनिवर्सिटी और किन्की यूनिवर्सिटी, जापान के प्रो. हीरोनाका काजूहीको, प्रोफेसर एमरीटस ने 16 सितम्बर, 1999 को एन.सी.ई.आर.टी. की संरचना और कार्यों के संबंध में जानने के लिए एन.सी.ई. आर.टी. के क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता का दौरा किया।

18 नवम्बर, 1999 को श्रीलंका का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के संयुक्त निदेशक और विभागीय वरिष्ठ सदस्यों ने शिष्टमंडल का स्वागत किया। शिष्टमंडल के सदस्यों और एन.आई.ई. विभागों के वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने पाठ्यचर्या के क्षेत्र में अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया। शिष्टमंडल ने एन.सी.ई.आर.टी. का भी दौरान किया। उन्हें उसकी भूमिका और कार्यों का भी संक्षिप्त विवरण दिया गया।

14 दिसम्बर, 1999 को बांग्लादेश का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल एन.सी.ई.आर.टी. आया। डीन (अकादमिक) और डी.टी.ई.ई., डी.ई.एस. और डी.पी., डी.ई.एस.एस.एच., डी.ई.एस.एम. और सी.आई.ई.टी. के अध्यक्षों ने शिष्टमंडल का स्वागत किया। शिष्टमंडल और एन.आई.ई. विभागों के वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने भारत में पाठ्यचर्या की योजना और प्रबन्ध, अध्यापक प्रशिक्षण और अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया। शिष्टमंडल ने सी.आई.ई.टी. का भी दौरा किया और इसके कार्यों को समझने के लिए सी.आई.ई.टी. के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ विचार -विमर्श किया।

- 22 दिसम्बर, 1999 को तीन सदस्यों के एरीटरीन शिष्टमंडल ने एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया। अध्यक्ष, आई.आर. प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी. ने शिष्टमंडल का स्वागत किया और एन.सी.ई.आर.टी. के सभी संघटकों के कार्यों और क्रियाकलापों के बारे में बताया। शिष्टमंडल ने सी.आई.ई.टी. का भी दौरा किया और उसके कार्यों और ढांचे को समझने के लिए सी.आई.ई.टी. के वरिष्ठ संकाय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया।
- 23 दिसम्बर, 1999 को शिक्षा सचिव के नेतृत्व में नेपाल से उच्च स्तरीय शिष्टमंडल एन.सी.ई.आर.टी. आया। निदेशक, संयुक्त निदेशक सहित एन.आई.ई. विभागों के वरिष्ठ संकाय सदस्यों ने शिष्टमंडल का स्वागत किया और विभिन्न शैक्षिक पहलुओं पर चर्चा की। शिष्टमंडल ने प्रकाशन प्रभाग और सी.आई.ई.टी. का भी दौरा किया तथा उनके समक्ष तकनीकी सुविधाओं, ई.टी.वी. कार्यक्रमों इत्यादि का प्रदर्शन किया गया।
- डा. हॉवर्ड ए. हूसोक, हारवर्ड यूनिवर्सिटी, यू.एस.ए. ने 10 जनवरी, 2000 को एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया और ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पर संकाय सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया।
- डा. बेट्टी कॉलिस, प्रोफेसर (टेली-लर्निंग), शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय, सैन्टर फॉर टेलीमैटिक्स एंड इनफोर्मेशन टैक्नोलोजी (सी.टी. आई.टी.), यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वंटे, नीदरलैण्ड ने 10 जनवरी, 2000 को एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया और भारत में शिक्षा प्रणाली पर विचार-विमर्श



जापान के विद्यार्थियों का परिषद्-दौरा।

किया तथा कक्षा 2000 और टेलीकान्फ्रेंसिंग प्रयोगों की सराहना की।

- श्री किल्ची ओयसू, यूनेस्को कार्यालय, बैंकाक, थाईलैण्ड ने 2 फरवरी, 2000 को 'भारत में विशेष आवश्यकता समूह' के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया। विशिष्ट अतिथि को एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति और 'अंतर्राष्ट्रीय विशेष आवश्यकता शिक्षा केन्द्र' को स्थापित करने में आगे की भूमिका के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई।
- नार्वे से बीजरोन लूसियस के नेतृत्व में 9 छात्रों और 2 संकाय सदस्यों के एक दल ने 14 से 17 फरवरी, 2000 तक यूनेस्को/ए.एस.पी. सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत क्षे.शि.सं., भुवनेश्वर का दौरा किया।
- प्रो. गजेन्द्र के. वर्मा (ई.सी.टी. परियोजना पर यू.के. समन्वयक) के नेतृत्व में मनचेस्टर यूनिवर्सिटी के सात सदस्यों (छह यूरोपीय देशों) के शिष्टमंडल ने 23 फरवरी 2000 को एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया और शिष्टमण्डल ने एन.सी.ई.आर.टी. और जे.एन.यू. स्थित केन्द्रीय विद्यालयों का भी दौरा किया। शिष्टमंडल ने डीन (समन्वय) और संकाय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श भी किया।
- नीपा में शैक्षिक योजना और प्रशासन के 16वें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा में भाग ले रहे 32 आगन्तुकों ने 2 मार्च 2000 को एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया और विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा, महिला शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पाठ्यपुस्तक शिक्षा के क्षेत्र में एन.सी.ई.आर.टी. के संकाय सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया। प्रतिभागियों ने सी.आई.ई.टी. का भी दौरा किया।
- बी.आर.ए.सी., बांग्लादेश से छह सदस्यों के शिक्षा अनुसंधान दल ने 8 मार्च 2000 को एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया और परिषद् द्वारा प्रारंभ किए गए अनुसंधान क्रियाकलापों पर चर्चा की।
- प्रो. ए. छिब्बर, इंटरनेशनल क्रिस्चियन यूनिवर्सिटी, जापान के नेतृत्व में जापान के दस छात्रों के एक दल ने 14 मार्च, 2000 को एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया। समूह ने डी.टी.ई.ई. के संकाय सदस्यों के साथ अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विचार-विमर्श किया।
- मंगोलिया के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने 29 मार्च, 2000 को एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया और डीन (अकादमिक) तथा संकाय सदस्यों के साथ शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
- डा. रूपर्ट मैकलीन, अध्यक्ष, ए.सी.ई.आई.डी., डा. इयान बिर्च, परामर्शदाता, यूनेस्को, बैंकाक और डा. हिरोशी ओम्यूरे, यूनेस्को के सहयोगी विशेषज्ञ, प्रो. मोएगिआडी, निदेशक, यूनेस्को कार्यालय, नई दिल्ली

ने मई, 1999 के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित 'यूनेस्को-एपिड वर्कशाप ऑन रिवाइटीलाइज़ेशन ऑफ दि एसोसिएटिड सेन्टर्स ऑफ एपिड' में तीन दिन भाग लिया। भारत के 21 केन्द्रों में से एपिड के 16 सहयोगी केन्द्रों ने बैठक में भाग लिया।

- फिनलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैण्ड के शैक्षिक विशेषज्ञों ने पूर्व-विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृति-विशिष्ट संदर्भ में अध्यापक-अधिगम का अवलोकन करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. का दौरा किया।
- कनाडा के अध्येता, डा. लेरी पोचनार ने ई.सी.सी.ई. क्रियाकलापों का अध्ययन करने के लिए एन.सी.ई. आर.टी. के क्रेच और आई.आई.टी. परिसर में पूर्व-विद्यालय का दौरा किया।
- बांग्लादेश के एक उच्च स्तरीय दल को अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण विभाग द्वारा अनौपचारिक और सतत शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया।

एन.सी.ई.आर.टी. के संकाय सदस्यों की अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

- डा. एस.एन. प्रसाद, प्रोफेसर (विज्ञान), क्षे.शि.सं., मैसूर ने यूनेस्को के लिए परामर्शदाता के रूप में मालदीव विद्यालयों में भौतिकी के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु 17-24 अप्रैल, 1999 तक मालदीव गणराज्य, माले का दौरा किया। उन्होंने 30 अध्यापकों के लिए एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास और कार्यान्वयन किया।
- प्रो. अरुण के. मिश्रा (तत्कालीन संयुक्त निदेशक), पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल ने यूनेस्को विशेषज्ञ के रूप में 26-30 अप्रैल, 1999 तक सिओल, कोरिया गणराज्य का दौरा किया तथा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में आलेख प्रस्तुत किया।
- प्रो. ऊषा नैयर, अध्यक्ष, डी.डब्ल्यू.एस. 'एनहांसिंग कैपेबिलिटीज़ फॉर कम्युनिटी रीवाइटेलाइज़िंग प्रैक्टिसिज़ इन एजुकेशनल डिवेलपमेन्ट' पर अंतर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस में भाग लेने के लिए 16-19 मई, 1999 तक कराची गईं। उन्होंने दो आलेख प्रस्तुत किए (1) शिक्षा लहर: रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को इन्नोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन रूरल एरियाज़ और (2) जैन्डर सेन्ज़ीटिव एप्रोच टु करीकुलम ट्रांसेक्शन एट दि एलीमेंटरी स्टेज।
- डा. वी. माधा सुरेश, प्रवक्ता (भूगोल) क्षे.शि.सं., मैसूर 'संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन के 'लॉ ऑफ दि सी : इट्स इम्पिलीमेंटेशन एंड एजंडा 21' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 31 मई से 27 अगस्त 1999 तक इंटरनेशनल ओशन इंस्टीट्यूट, डलहौज़ी यूनिवर्सिटी, हालीफैक्स, कनाडा गए।
- प्रो. अर्जुन देव, अध्यक्ष, डी.ई.एस.एस.एच. ने गैर तमिल-भारतीय भाषाओं से संबंधित परियोजना पर शिक्षा मंत्रालय, सिंगापुर के सहयोग से विचार-विमर्श के लिए 8 से 12 जून, 1999 तक सिंगापुर का दौरा किया।
- प्रो. आर.डी. शुक्ल, अध्यक्ष, डी.ई.एस.एम. ने डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आई.ओ.एस.टी.ई.) की 9वीं संगोष्ठी में 26 जून से 3 जुलाई 1999 तक भाग लिया। उन्होंने 'वैज्ञानिक साक्षरता और पर्यावरण जागरूकता हेतु भारत में विद्यालयी शिक्षा के 10 वर्षों तक विज्ञान पाठ्यचर्या' पर आलेख प्रस्तुत किया।
- डा. (श्रीमती) सरोज बी. यादव, रीडर, डी.ई.एस. एस.एच. ने 'एडोलसेन्ट रीप्रोडक्टिव हैल्थ' में प्रशिक्षण को सुसाध्य (मार्ग निर्देशन और परामर्श तथा वयस्क विकास में 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) बनाने हेतु 11-31 जुलाई 1999 तक दोमासी-मलावी का दौरा किया।
- डा. जी.सी. उपाध्याय, रीडर, डी.पी.एस.ई.ई. ने श्रीलंका में यूनीसेफ द्वारा प्रायोजित कार्यशाला 'एसेसिंग लर्निंग एचीवमेंट' में 19-23 जुलाई, 1999 तक भाग लिया।
- प्रो. ए.के. मिश्रा, डीन (अकादमिक) ने 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा के परिप्रेक्ष्य पर संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 29-30 जुलाई, 1999 तक काठमांडू (नेपाल) का दौरा किया।

- डा. जी.एल. अरोड़ा, अध्यक्ष, डी.टी.ई.ई. ने काठमांडू, नेपाल में दक्षिण एशिया प्रशिक्षण कार्यशाला के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने हेतु प्रारंभिक बैठक में 7–9 सितम्बर, 1999 तक भाग लिया।
- डा. कानन के. साधु, वरिष्ठ प्रवक्ता, डी.ई.एस.एस.एच. ने इंटरकन्ट्री विज़िट कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या शिक्षा, जिसमें किशोरावस्था पुनरुत्पादक स्वास्थ्य समिम्लत है, के क्षेत्र में अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए 10–20 सितंबर, 1999 तक कोलम्बो–श्रीलंका का दौरा किया।
- डा. ए.एन. माहेश्वरी, (तत्कालीन संयुक्त निदेशक) ने 'एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस' पर कार्यशाला में भाग लेने के लिए 13–17 सितम्बर, 1999 इचॉन, दक्षिण कोरिया गणराज्य का दौरा किया।
- 3 संकाय सदस्य डा. डी.जी. राव और डा. एस.पी. मिश्रा, वरिष्ठ प्रवक्ता तथा श्री पी.एन. मिश्रा, पी.जी.टी. एवं क्षे.शि.स. और डी.एम. विद्यालय, भुवनेश्वर के चार छात्रों के एक दल ने यूनेस्को/ए.एस.पी. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 13–28 सितम्बर, 1999 तक नीड्यरेड वीडरजेन्डो स्कोले, ओसलो, नार्वे का दौरा किया।
- डा. एस.सी. पांडे, रीडर, डी.ई.एस.एस.एच. ने 14–18 सितम्बर 1999 को लंदन में आयोजित छठे विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया।
- डा. (सुश्री) सरोज पांडे, रीडर, डी.टी.ई.ई. ने टोक्यो, जापान में 'टीचर एजुकेशन फॉर पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग' पर 27 सितम्बर से 8 अक्टूबर, 1999 तक क्षेत्रीय संगोष्ठी में भाग लिया।
- डा. (श्रीमती) अनीता जुल्का, रीडर, डी.ई.जी.एस.एन. ने युकोसूका कानागावा, जापान में विशेष शिक्षा पर नवीं क्षेत्रीय संगोष्ठी में 8–13 नवम्बर, 1999 तक भाग लिया।
- श्री बिमल जुल्का, आई.ए.एस., सचिव, एन.सी.ई.आर.टी. ने यू.के. में टैक्नीकल कोओपरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, 1999–2000, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्वीन एलीज़ेबेथ हाऊस में अध्येतावृत्ति के अंतर्गत 24 नवंबर 1999 से 15 जुलाई 2000 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- प्रो. उत्पल मलिक, अध्यक्ष, डी.सी.ई.टी.ए. ने विद्यालयों में आई.टी. प्रयोग के मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने के लिए 29 जनवरी से 6 फरवरी तक टोक्यो, जापान का दौरा किया। यह बैठक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑफ जापान तथा यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी।

21 हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा बहुत से कदम उठाए गए। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, निर्देशों और राजभाषा विषयों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा बहुत से उपाय किए गए।

एनसीईआरटी

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा बहुत से कदम उठाए गए। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों, निर्देशों और राजभाषा विषयों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी प्रकोष्ठ, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा बहुत से उपाय किए गए। एन.सी.ई.आर.टी. का प्रशासनिक और शैक्षिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना और प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसके कार्यकलापों का मुख्य केन्द्र है। इस उद्देश्य से हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा संकल्पनात्मक साहित्य तैयार किया गया, एन.सी.ई.आर.टी. के कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, भावी योजनाएं तैयार की गईं, एन.सी.ई.आर.टी. के विभिन्न संघटकों में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का निरीक्षण किया गया और त्रैमासिक प्रगति का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 1999-2000 के दौरान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

हिन्दी पखवाड़ा

1-14 सितम्बर, 1999 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस पखवाड़े के दौरान जो प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं वे थीं :

- हिन्दी अनुवाद प्रतियोगिता
- हिन्दी टिप्पण व प्रारूपण प्रतियोगिता
- हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता
- हिन्दी टंकण प्रतियोगिता
- हिन्दी कविता प्रतियोगिता
- हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिता

इन प्रतियोगिताओं में 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें 29 व्यक्तियों को विजयी घोषित किया गया। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पुरस्कृत विजेताओं को क्रमश: रु. 800, रु. 500 तथा रु. 300 की धनराशि के नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। समूह 'घ' के नवसाक्षर समूह हेतु एक हिन्दी लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और दो समूहों के छह कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में भी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी सप्ताह/पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिन्दी अनुवाद कार्य

परिषद् के विभिन्न संघटकों, विभागों/अनुभागों आदि से प्राप्त प्रशासनिक कागज़-पत्रों का अनुवाद करने में हिन्दी



हिंदी पखवाड़े के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए।

प्रकोष्ठ सहायता करता रहा है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिवेदनों जैसे कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञापन, प्रेस, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, प्रशासनिक व लेखा संबंधी अन्य रिपोर्ट आदि का हिन्दी अनुवाद किया गया।

कार्यान्वयन-बैठकों की मानीटरिंग (अनुवीक्षण)

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा देने और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 24 सितम्बर, 1999 को एन.सी.ई.आर.टी. मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों द्वारा भी अपने संस्थानों में इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की निगरानी और प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के अलावा हिन्दी प्रकोष्ठ ने परिषद् के विभिन्न विभागों/अनुभागों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग, आर.आई.ई./एफ.ए. अनुभाग और सी.आई.ई.टी. का निरीक्षण व दौरा किया गया तथा राजभाषा के प्रयोग से संबंधित उनकी कठिनाइयों के निराकरण के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए।

हिन्दी कार्यशाला

हिन्दी को बढ़ावा देने और एन.सी.ई.आर.टी. के अधिकारियों/कर्मचारियों में प्रवीणता का विकास करने के लिए मुख्यालय में अपर श्रेणी लिपिकों और उच्च श्रेणी लिपिकों तथा अनुभाग अधिकारियों के लिए पृथक-पृथक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

22 परिशिष्ट

- **परिशिष्ट I**
  एन सी ई आर टी की समितियाँ : 1999-2000
- **परिशिष्ट II**
  स्वीकृत स्टाफ की स्थिति (31 मार्च, 2000)
- **परिशिष्ट III**
  वर्ष 1999-2000 का प्राप्ति और भुगतान लेखा
- **परिशिष्ट IV**
  1999-2000 के दौरान निकाले गए प्रकाशन
- **परिशिष्ट V**
  एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के क्षेत्रीय उत्पादन व वितरण केन्द्र तथा थोक एजेंटों के नाम और पते

एन सी ई आर टी

एन सी ई आर टी की समितियाँ : वर्ष 1999-2000

- महासमिति
- कार्यकारिणी समिति
- वित्त समिति
- स्थापना समिति
- भवन एवं निर्माण समिति
- कार्यक्रम सलाहकार समिति
- शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति
- राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की अकादमिक समिति
- सी.आई.ई.टी. का संस्थान सलाहकार बोर्ड
- पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. का संस्थान सलाहकार बोर्ड
- आर.आई.ई., अजमेर की प्रबंध समिति
- आर.आई.ई., भोपाल की प्रबंध समिति
- आर.आई.ई., भुवनेश्वर की प्रबंध समिति
- आर.आई.ई., मैसूर की प्रबंध समिति
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति

महासमिति

1. मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय पदेन अध्यक्ष	1. डा. मुरली मनोहर जोशी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001
2. अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पदेन	2(i) प्रो. (कु.) अरमैती देसाई अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली 110002 (20.7.1999 तक)
	(ii) डा. हरि प्रताप गौतम अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह ज़फर मार्ग नई दिल्ली 110002 (22.7.1999 से)
3. सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) पदेन	3. श्री एम.के. काव सचिव, भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001
4. भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के नामित चार उप-कुलपति (प्रत्येक क्षेत्र से एक)	4. उप-कुलपति तेजपुर विश्वविद्यालय तेजपुर, सोनीतपुर असम 784001
	5. उप-कुलपति महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वड़ोदरा गुजरात 390002

5. प्रत्येक राज्य सरकार और विधान सभा से युक्त संघ शासित क्षेत्र का एक-एक प्रतिनिधि जो राज्य/संघ शासित क्षेत्र का शिक्षा मंत्री (अथवा उसका प्रतिनिधि) हो

6. उप-कुलपति
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
समर हिल, शिमला 171005

7. उप-कुलपति
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय
तिरुपति 517502
आंध्र प्रदेश

8. विद्यालय शिक्षा मंत्री
आंध्र प्रदेश सरकार
ए.पी. सचिवालय भवन
हैदराबाद 500022

9. विद्यालय शिक्षा मंत्री
अरुणाचल प्रदेश सरकार
ईटानगर 791111

10. विद्यालय शिक्षा मंत्री
असम सरकार, जनता भवन
दिसपुर (असम) 781006

11. विद्यालय शिक्षा मंत्री
बिहार सरकार
नया सचिवालय भवन
पटना 800015

12. विद्यालय शिक्षा मंत्री
गोवा सरकार, गोवा सचिवालय
पणजी 403001

13. विद्यालय शिक्षा मंत्री
गुजरात सरकार
ब्लाक नं. 1, सचिवालय
गांधी नगर 382010

14. विद्यालय शिक्षा मंत्री
हरियाणा सरकार
हरियाणा सिविल सचिवालय
चण्डीगढ़ 160001

15. विद्यालय शिक्षा मंत्री
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला 171002

16. विद्यालय शिक्षा मंत्री
जम्मू और कश्मीर सरकार
श्रीनगर 180001

17. विद्यालय शिक्षा मंत्री
कर्नाटक सरकार
विधान सौध
बैंगलूर 560001

18. विद्यालय शिक्षा मंत्री
केरल सरकार
अशोक नंथनकोडे
तिरुअनंतपुरम 695001

19. विद्यालय शिक्षा मंत्री
मध्य प्रदेश सरकार
भोपाल 462001

20. विद्यालय शिक्षा मंत्री
महाराष्ट्र सरकार
मंत्रालय मेन
मुंबई 400032

21. विद्यालय शिक्षा मंत्री
मणिपुर सरकार
मणिपुर सचिवालय
इंफाल 759001

22. विद्यालय शिक्षा मंत्री
मेघालय सरकार
मेघालय सचिवालय
शिलांग 793001

23. विद्यालय शिक्षा मंत्री
नागालैंड सरकार
कोहिमा 797001

24. विद्यालय शिक्षा मंत्री
मिज़ोरम सरकार
आइज़ोल 796001

25. विद्यालय शिक्षा मंत्री
उड़ीसा सरकार
उड़ीसा सचिवालय
भुवनेश्वर 751001

26. विद्यालय शिक्षा मंत्री
पंजाब सरकार
चण्डीगढ़ 160017

27. विद्यालय शिक्षा मंत्री
राजस्थान सरकार
सरकारी सचिवालय
जयपुर 302001

28. विद्यालय शिक्षा मंत्री
सिक्किम सरकार
सिक्किम सचिवालय
ताशिलिंग, गंगटोक 737101

29. विद्यालय शिक्षा मंत्री
तमिलनाडु सरकार
फोर्ट सेंट जॉर्ज
चेन्नई 500009

30. विद्यालय शिक्षा मंत्री
त्रिपुरा सरकार
सिविल सचिवालय
अगरतला 799001

31. विद्यालय शिक्षा मंत्री
पश्चिम बंगाल सरकार
राइटर्स बिल्डिंग
कलकत्ता 700001

32. विद्यालय शिक्षा मंत्री
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ 226001

33. विद्यालय शिक्षा मंत्री
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय
दिल्ली 110054

34. विद्यालय शिक्षा मंत्री
पांडिचेरी सरकार
विधान सभा सचिवालय
विक्टर सिमोनल स्ट्रीट
पांडिचेरी 605001

6. कार्यकारिणी समिति के वे सदस्य जो ऊपर दी गई सूची में सम्मिलित नहीं हैं

35. श्री जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल
शिक्षा राज्य मंत्री
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग)
शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001

36(i) प्रो. ए.के. शर्मा
निदेशक
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016
(30.6.99 तक)

(ii) प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत
निदेशक
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016
(14.7.99 से)

37. प्रो. जे.वी. नारलीकर
खगोलशास्त्र तथा खगोल भौतिकीय
अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र
पुणे विश्वविद्यालय
पुणे

38. प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
सी 2/10, सफदरजंग विकास क्षेत्र
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016
(13.7.99 तक)

39. श्रीमती विषलक्षी एच.
सहायक मिस्ट्रेस
सर्वोदय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय
जयानगर, शिमोगा ज़िला
कर्नाटक 577201

40. श्रीमती विभा पार्थसारथी
राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली 110003

41. प्रो. ए.एन. माहेश्वरी
संयुक्त निदेशक
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016
(8.11.99 तक)

42. डा. अरुण के. मिश्र
संयुक्त निदेशक
पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक
शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.,
एन.सी.ई.आर.टी.)
131, जोन-2, एम.पी. नगर
भोपाल 462011
(1.6.99 तक)

43. डा. पी.के. भट्टाचार्य
संयुक्त निदेशक
सी.आई.ई.टी.
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

44. डा. डी. के. भट्टाचारजी
प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भुवनेश्वर 750007

45. श्री एम. एम. झा
संयुक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा)
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001

46(i) श्री सुधीर नाथ
वित्तीय सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी.
शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली 110001
(मई 1999 तक)

(ii) श्री संजय नारायण
वित्तीय सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी.
शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001
(3.6.99 से)

7. (क) अध्यक्ष
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
नई दिल्ली
पदेन

47. श्री बी.पी. खंडेलवाल
अध्यक्ष
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2, कम्युनिटी सेंटर
प्रीत विहार, दिल्ली 110092

(ख) आयुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन
नई दिल्ली
पदेन

48. आयुक्त
केंद्रीय विद्यालय संगठन
18, इंस्टीट्यूशनल एरिया
शहीद जीत सिंह मार्ग
नई दिल्ली 110016

(ग) निदेशक
केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो
नई दिल्ली
पदेन

49. निदेशक
केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो
(डी.जी.एच.एस.)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोटला रोड
नई दिल्ली 110002

(घ) उपमहानिदेशक प्रभारी, कृषि शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली पदेन	50. उप महानिदेशक प्रभारी, कृषि शिक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि मंत्रालय डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड नई दिल्ली 110001
(ङ) निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और रोज़गार महानिदेशालय श्रम मंत्रालय नई दिल्ली पदेन	51. निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण और रोज़गार महानिदेशालय श्रम मंत्रालय श्रमशक्ति भवन नई दिल्ली 110001
(च) शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि योजना आयोग नई दिल्ली पदेन	52. शिक्षा सलाहकार योजना आयोग योजना भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली 110001
8. भारत सरकार द्वारा मनोनीत छह व्यक्ति (जिनमें कम से कम चार विद्यालयी अध्यापक हों)	53. श्री के. आर. सिद्दप्पा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डी/2 विद्यालय नगर दावणगेरे 577005 कर्नाटक
	54. श्री जे.एस. भण्डारी प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय पो.ओ. न्यू फारेस्ट देहरादून 248006 उत्तर प्रदेश
	55. श्री जी.बी. हेगाड़ी प्रधानाचार्य दिल्ली कन्नड़ व. मा. विद्यालय लोधी एस्टेट नई दिल्ली 110003

56. श्री ओ. रंगरेड्डी
प्रधानाचार्य
जवाहर नवोदय विद्यालय
वलसपल्ले, मदनपल्ले (पोस्ट)
चित्तूर ज़िला 517325
आंध्र प्रदेश

57. डा. एम.एन. कुलकर्णी
आई 302
अंसल लेक व्यू अपार्टमेंट
श्यामला हिल्स
भोपाल 462013

58. प्रो. जयालक्ष्मी
जया भवन
पोरूवाज़ी, पो.ओ. सस्तामकोट्टा
कोल्लम 690520
केरल

विशेष आमंत्रित

59. सचिव
भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद्
प्रगति हाउस, तीसरी मंज़िल
47, नेहरू प्लेस
नई दिल्ली 110019

संयोजक

60(i) श्री बिमल जुल्का
सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016
(23.11.1999 तक)

(ii) श्रीमती सोनाली कुमार
सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016
(24.11.1999 से)

कार्यकारिणी समिति

परिषद् के अध्यक्ष जो कार्यकारिणी के पदेन अध्यक्ष होंगे	1. डा. मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, एन.सी.ई.आर.टी. शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री जो कार्यकारिणी के पदेन उपाध्यक्ष होंगे	2. श्री जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल शिक्षा राज्य मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली 110001
परिषद् के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत शिक्षा उपमंत्री	......
परिषद् के निदेशक	3(i) प्रो. ए.के. शर्मा निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (30. 6. 1999 तक) (ii) प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (14. 7. 1999 से)
सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय पदेन	4. श्री एम.के. काव सचिव, भारत सरकार शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001
अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पदेन	5(i) प्रो. (कु.) अरमैती देसाई अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह ज़फर मार्ग नई दिल्ली 110002 (20. 7. 1999 तक)

(ii) डा. हरि प्रताप गौतम
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली 110002
(22.7.1999 से)

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत स्कूल शिक्षा में रुचि रखने वाले चार शिक्षाविद् (जिनमें से दो स्कूल के अध्यापक हों)

6(i) प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
सी-2/10, सफदरजंग विकास क्षेत्र
श्री अरविंद मार्ग
नई दिल्ली 110016
(13.7.1999 तक)

(ii) श्रीमती विषलक्षी एच.
सहायक मिस्ट्रेस
सर्वोदय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय
जयानगर
शिमोगा ज़िला
कर्नाटक 577201

(iii) श्रीमती विभा पार्थसारथी
अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली 110003

परिषद् के संयुक्त निदेशक

7. डा. ए.एन. माहेश्वरी
संयुक्त निदेशक
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016
(8.11.1999 तक)

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत परिषद् के संकाय के तीन सदस्य, जिनमें कम से कम दो सदस्य प्रोफसर तथा विभागाध्यक्षों के स्तर के हों

8(i) प्रो. अरुण के. मिश्र
संयुक्त निदेशक
पंडित सुंदरलाल शर्मा
केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
131, जोन-2
एम.पी. नगर, भोपाल 462011
(1.6.1999 तक)

(ii) प्रो. पी.के. भट्टाचार्य
संयुक्त निदेशक
केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

(iii) डा. डी.के. भट्टाचारजी
प्राचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भुवनेश्वर 750007

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	9. श्री एम.एम. झा संयुक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001
वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो परिषद् का वित्तीय सलाहकार होगा	10(i) श्री सुधीर नाथ वित्तीय सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी. शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 (मई 1999 तक) (ii) श्री संजय नारायण वित्तीय सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी. शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 (3.6.1999 से)
सचिव एन.सी.ई.आर.टी संयोजक	11(i) श्री बिमल जुल्का सचिव, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (23.11.1999 तक) (ii) श्रीमती सोनाली कुमार सचिव, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (24.11.1999 से)

वित्त समिति

निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. अध्यक्ष, पदेन	1(i) प्रो. ए.के. शर्मा निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (30.6.1999 तक)
	(ii) प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (14.7.1999 से)
वित्तीय सलाहकार पदेन	2(i) श्री सुधीर नाथ वित्तीय सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी. शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001 (मई 1999 तक)
	(ii) श्री संजय नारायण वित्तीय सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी. शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001 (3.6.1999 से)
संयुक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय पदेन	3(i) श्री एम.एम. झा संयुक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001

(ii) संयुक्त निदेशक
नीपा, एन.आई.ई. परिसर
नई दिल्ली 110016

(iii) डा. बी.पी. खंडेलवाल
अध्यक्ष
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केंद्र, 2 कम्युनिटी सेंटर
प्रीत विहार, दिल्ली 110092

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
सदस्य संयोजक

4(i) श्री बिमल जुल्का
सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016
(23.11.1999 तक)

(ii) श्रीमती सोनाली कुमार
सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016
(24.11.1999 से)

स्थापना समिति

निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. अध्यक्ष पदेन	1(i)	डा. ए.के. शर्मा निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (30.6.1999 तक)
	(ii)	प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (14.7.1999 से)
संयुक्त निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. पदेन	2.	प्रो. ए.एन. माहेश्वरी संयुक्त निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016
परिषद् के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का नामिती	3.	श्री एम.एम. झा संयुक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001
अध्यक्ष द्वारा मनोनीत चार शिक्षाविद् जिनमें से कम से कम एक वैज्ञानिक हो	4.	प्रो. सी.एल. आनन्द विज़िटिंग प्रोफेसर पंजाब विश्वविद्यालय एफ 87, विकास पुरी नई दिल्ली 110018
	5.	प्रो. पी. वेंकटरमय्या उपकुलपति कुवेम्पु विश्वविद्यालय, ज्ञान सहयाद्रि शंकरघट्टा, ज़िला शिमोगा 577115 (कर्नाटक)

6. डा. एस.एस. सालगांवकर
निदेशक
भारतीय शिक्षा संस्थान
128/2, जे.पी. नायक मार्ग
कोथरुड, पुणे 411029

7. कु. नरगिस पंचपकेसन
प्रोफेसर, केंद्रीय शिक्षा संस्थान
दिल्ली विश्वविद्यालय
33 छात्र मार्ग, दिल्ली 110007

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से एक प्रतिनिधि

8. प्रो. डी.के. भट्टाचारजी
प्राचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भुवनेश्वर 751007

अध्यक्ष द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (नई दिल्ली) से एक प्रतिनिधि

9. प्रो. (श्रीमती) ऊषा नायर
अध्यक्ष
महिला अध्ययन विभाग
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

परिषद् के शैक्षिक तथा गैर-शैक्षिक नियमित स्टाफ, प्रत्येक में से एक-एक प्रतिनिधि जिनका चयन परिशिष्ट में इस संबंध में निर्धारित वनियम के अनुसार किया गया हो

10. श्री विनोद चंद्र किमोथी
पी.जी.टी.
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
(शैक्षिक स्टाफ के प्रतिनिधि)

11. श्री वेद प्रकाश
सहायक कार्यक्रम समन्वयक
डी.ई.जी.एस.एन., एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016
(गैर-शैक्षिक स्टाफ के प्रतिनिधि)

वित्तीय सलाहकार
एन.सी.ई.आर.टी.

12(i) श्री सुधीर नाथ
वित्तीय सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी.
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली 110001
(मई 1999 तक)

(ii) श्री संजय नारायण
वित्तीय सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी.
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली 110001
(3.6.1999 से)

सचिव एन.सी.ई.आर.टी. संयोजक	13(i) श्री बिमल जुल्का सचिव एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (23.11.1999 तक)
	(ii) श्रीमती सोनाली कुमार सचिव एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (24.11.1999 से)

भवन एवं निर्माण समिति

निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. अध्यक्ष, पदेन	1(i)	प्रो. ए.के. शर्मा निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (30.6.1999 तक)
	(ii)	प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (14.7.1999 से)
संयुक्त निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. उपाध्यक्ष, पदेन	2.	प्रो. ए.एन. माहेश्वरी संयुक्त निदेशक एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (8.11.1999 तक)
मुख्य अभियंता सी.पी.डब्ल्यू.डी. या उनका प्रतिनिधि	3.	श्री वी.के. शर्मा अधीक्षक अभियंता, सी.पी.डब्ल्यू.डी. कमरा सं. 113, सेवा भवन आर.के. पुरम नई दिल्ली 110022
वित्त मंत्रालय (निर्माण) का एक प्रतिनिधि	4.	श्री डी.सी. भट्ट सहायक वित्त सलाहकार (निर्माण) शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली 110001
एन.सी.ई.आर.टी. का परामर्शदाता वास्तुकार	5.	श्री दीना नाथ वरिष्ठ वास्तुकार सी.पी.डब्ल्यू.डी., सेवा भवन आर.के. पुरम नई दिल्ली 110022

परिषद् के वित्तीय सलाहकार या उनका प्रतिनिधि	6(i) श्री सुधीर नाथ वित्तीय सलाहकार एन.सी.ई.आर.टी. शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001 (मई 1999 तक)
	(ii) श्री संजय नारायण वित्तीय सलाहकार एन.सी.ई.आर.टी. शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001 (3.6.1999 से)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	7. श्री एम.एम. झा संयुक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 110001
एक स्थायी सिविल इंजीनियर (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	8. श्री के.के. गुलाटी वास्तुकार व अभियन्ता सी-2 सी, पाकेट-2, फ्लैट सं. 9 जनकपुरी नई दिल्ली 110058
एक स्थायी विद्युत अभियंता (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	9. श्री एस.एन. गीरोत्रा आवासीय अभियंता (विद्युत) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हौजखास नई दिल्ली 110016

कार्यकारिणी समिति का एक सदस्य (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	10(i) प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् सी-2/10 सफदरजंग विकास क्षेत्र श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110016 (13. 7. 1999 तक) (ii) प्रो. पी.के. भट्टाचार्य संयुक्त निदेशक (सी.आई.ई.टी.) एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (12. 8. 1999 से)
सचिव एन.सी.ई.आर.टी. सदस्य-सचिव	11(i) श्री बिमल जुल्का सचिव एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (23. 11. 1999 तक) (ii) श्रीमती सोनाली कुमार सचिव एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली 110016 (24. 11. 1999 से)

कार्यक्रम सलाहकार समिति

1. निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. — *अध्यक्ष*
2. संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. — *उपाध्यक्ष*
3. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.)
4. संयुक्त निदेशक, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक
   शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.)
   भोपाल 462011

एन.सी.ई.आर.टी. से सदस्य

5. प्रो. आर.एल. फुटेला
   केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.)
   एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016
6. अध्यक्ष
   सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एस.एच.)
   एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016
7. प्रो. आर.के. दीक्षित
   सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एस.एच.)
   एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016
8. अध्यक्ष
   विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एम.)
   एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016
9. प्रो. हुकुम सिंह
   विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एम.)
   एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016
10. अध्यक्ष
    शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग (डी.ई.पी.एफ.ई.)
    एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016
11. डा. (श्रीमती) सुषमा गुलाटी
    शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग (डी.ई.पी.एफ.ई.)
    एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016
12. अध्यक्ष
    विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा विभाग (डी.पी.एस.ई.ई.)
    एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

13. प्रो. के.के. वशिष्ठ
विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा विभाग (डी.पी.एस.ई.ई.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

14. अध्यक्ष
अनौपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक शिक्षण विभाग (डी.ई.एन.एफ.ए.एस.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

15. डा. (श्रीमती) शुक्ला भट्टाचार्य
अनौपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक शिक्षण विभाग (डी.ई.एन.एफ.ए.एस.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

16. अध्यक्ष
शैक्षिक मापन और मूल्यांकन विभाग (डी.ई.एम.ई.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

17. डा. के.पी. गर्ग
रीडर, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन विभाग (डी.ई.एम.ई.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

18. अध्यक्ष
अध्यापक शिक्षा और विस्तार विभाग (डी.टी.ई.ई.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

19. प्रो. वी.के. रैना
अध्यापक शिक्षा और विस्तार विभाग (डी.टी.ई.ई.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

20. अध्यक्ष
महिला अध्ययन विभाग (डी.डब्ल्यू.एस.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

21. डा. (श्रीमती) गौरी श्रीवास्तव
रीडर, महिला अध्ययन विभाग (डी.डब्ल्यू.एस.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

22. अध्यक्ष
पुस्तकालय, प्रलेखन एवं सूचना प्रभाग (डी.एल.डी.आई.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

23. अध्यक्ष
प्रकाशन प्रभाग
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

24. अध्यक्ष
कंप्यूटर शिक्षा और प्रौद्योगिकीय सहायता विभाग (डी.सी.ई.टी.ए.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

25. डा. एच.ओ. गुप्ता
रीडर, कंप्यूटर शिक्षा और प्रौद्योगिकीय सहायता विभाग
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

26. अध्यक्ष
योजना, प्रोग्रामिंग, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.पी.एम.ई.डी.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

27. डा. जे.पी. मित्तल
रीडर, योजना, प्रोग्रामिंग, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.पी.एम.ई.डी.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

28. अध्यक्ष
विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (डी.ई.जी.एस.एन.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

29. प्रो. (सुश्री) के. शर्मा
विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (डी.ई.जी.एस.एन)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

30. अध्यक्ष
शैक्षिक अनुसंधान और नीतिगत संदर्श विभाग (डी.ई.आर.पी.पी.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

31. प्रो. सतवीर सिंह
सदस्य सचिव, एरिक
शैक्षिक अनुसंधान और नीतिगत संदर्श विभाग (डी.ई.आर.पी.पी.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

32. अध्यक्ष
शैक्षिक सर्वेक्षण और आँकड़ा प्रक्रियन विभाग (डी.ई.एस.डी.पी.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

33. श्री वी.के. जैन
रीडर, शैक्षिक सर्वेक्षण और आँकड़ा प्रक्रियन विभाग (डी.ई.एस.डी.पी.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

34. प्राचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर 305 004

35. डीन (अनुदेश)
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर 305004

36. प्राचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल 462013

37. डीन (अनुदेश)
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल 462013

38. प्राचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर 751007

39. डीन (अनुदेश)
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर 751007

40. प्राचार्य
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर 570006

41. डीन (अनुदेश)
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर 570006

42. विशेष कार्य अधिकारी
उत्तर पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग 793003

43. प्रो. ए.के. सचेती
पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.)
भोपाल 462013

अध्यक्ष एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित सदस्य

44. श्री आर. पी. सिंघल
डी 24, सी.सी. कालोनी
निकट राणा प्रताप बाग
दिल्ली 110007

45. डा. पुरुषोत्तम पटेल
प्रोफेसर अमेरीटस
गुजरात विद्यापीठ
आश्रम रोड
अहमदाबाद 380014

46. डा. मनमोहन सिंह
प्रोफेसर, उत्तर पूर्व पर्वतीय विश्वविद्यालय
शिलांग

47. डा. (श्रीमती) सुमन करींदकर
निदेशक, एस.आर.सी. भारतीय शिक्षा संस्थान
128/2, जे.पी. नायक पथ
कोथरुड, पुणे 491029

48. डा. सी. शेषाद्री
16, गंगोत्री लेआउट
I क्रॉस, II स्ट्रीट
मैसूर 570009

49. निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

50. निदेशक
महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
सदाशिव पेठ, पुणे 411030

51. निदेशक
सिक्किम राज्य शिक्षा संस्थान, गंगटोक 737107

52. निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
निशातगंज, लखनऊ 228007

53. निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
गुजरात, गांधी नगर 382021

विशेष आमन्त्रित

54. डीन (अकादमिक)
एन.सी.ई.आर.टी.

55. डीन (समन्वय)
एन.सी.ई.आर.टी.

56. मुख्य लेखाधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.

57 जन संपर्क अधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.

58. संयुक्त शिक्षा सलाहकार (ए) मा.सं.वि.म.
शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001

59. डा. जे.पी. मित्तल
रीडर, योजना, प्रोग्रामिंग, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी.पी.एम.ई.डी.)
एन.सी.ई.आर.टी.

60. सचिव *सदस्य-सचिव*
एन.सी.ई.आर.टी.

शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति

एन.सी.ई.आर.टी. से

डीन (अनुसंधान) — अध्यक्ष

डीन (अकादमिक)

डीन (समन्वय)

एन.सी.ई.आर.टी. के सभी घटकों के अध्यक्ष

1. संयुक्त निदेशक
   केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान
   एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016
2. संयुक्त निदेशक
   पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल
3. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर
4. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल
5. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर
6. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर
7. विशेष कार्य अधिकारी
   उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग

एन.आई.ई. के विभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित एस.सी.ई.आर.टीज़. के दो व्यक्ति

1. निदेशक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान
   और प्रशिक्षण परिषद्
   708 आर.डी., कामथेकर मार्ग
   सदाशिव पेठ
   पुणे 411030
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान
   और प्रशिक्षण परिषद्
   जे.बी.टी.सी. परिसर
   निशातगंज, लखनऊ 228007

विशेषज्ञ/शिक्षाविद/अनुसंधान अध्येता

अध्यक्ष, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों अथवा अन्य उपयुक्त एजेंसियों से नामित आठ व्यक्ति

1. प्रो. सुश्री वीना आर. मिस्त्री
   पूर्व प्रो. उप-कुलपति
   एम.एस. बड़ोदा विश्वविद्यालय
   बी-5 संख्या 3, सी.एस. पटेल एन्क्लेव
   प्रतापगंज, वड़ोदरा

2. डा. बी.पी. खण्डेलवाल
अध्यक्ष
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केंद्र, 2 सामुदायिक केंद्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली 110092

3. प्रो. सरोजिनी बी. शिन्त्री
प्राचार्य, सत्य साई शिक्षा सोसायटी
गृहविज्ञान संस्थान, बासवेश्वर भवन
धारवाड़ 580001

4. प्रो. के.डी. ब्रूटा
मनोविज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली 110007

5. प्रो. डी.के. सामन्त्रे
एन.1, 62-ए, आई.आर.सी. गांव
भुवनेश्वर 751 015

6. डा. (सुश्री) विनय भारद्वाज
968, विकास कुंज
नई दिल्ली 110018

7. डा. नीलम 'नीलकमल'
मार्फत डा. अजीत शरण
कलम बाग रोड
मुज़फ्फरपुर 842001

8. प्रो. शमीम हनफी
उर्दू विभाग
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
नई दिल्ली 110025

स्थाई/ विशेष आमंत्रित
(निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.
द्वारा नामित)

1. संयुक्त सचिव (विद्यालय)
शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली 110001

2. प्रो. वी.के. रैना
अध्यापक शिक्षा और विस्तार विभाग (डी.टी.ई.ई.)
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

3. प्रो. आर.एन. माथुर
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
(डी.ई.एस.एम.)
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

4. प्रो. (श्रीमती) एस. सिन्हा
सामाजिक विज्ञान और मानविकी
शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एस.एच.)
एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली 110016

5. प्रो. (श्रीमती) आशा भटनागर
शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा
आधार विभाग
(डी.ई.पी.एफ.ई.), एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

6. प्रो. ए.के. सचेती
पंडित सुन्दरलाल शर्मा
केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान
(पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.)
131, ज़ोन-II, एम.पी. नगर
भोपाल 462011

7. प्रो. एम. सेन गुप्ता
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, श्यामला हिल्स
भोपाल 462011

8. प्रो. के.के. वशिष्ठ
विद्यालय पूर्व और प्रारंभिक
शिक्षा विभाग (डी.पी.एस.ई.ई.)
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

संयोजक

9. प्रो. ए.एल.एन. शर्मा
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भुवनेश्वर 751007

10. प्रो. सतवीर सिंह
सदस्य सचिव (एरिक)
शैक्षिक अनुसंधान और नीतिगत संदर्श विभाग
(डी.ई.आर.पी.पी.)
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की अकादमिक समिति

आंतरिक सदस्य

1. डीन (अकादमिक), एन.सी.ई.आर.टी. — *अध्यक्ष*
2. अध्यक्ष, विद्यालय-पूर्व और प्रारम्भिक शिक्षा विभाग (डी.पी.एस.ई.ई.)
3. अध्यक्ष, अनौपचारिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण विभाग (डी.ई.एन.एफ.ए.एस.)
4. अध्यक्ष, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (डी.ई.जी.एस.एन.)
5. अध्यक्ष, महिला अध्ययन विभाग (डी.डब्ल्यू.एस.)
6. अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एस.एच.)
7. अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एम.)
8. अध्यक्ष, कंप्यूटर शिक्षा और प्रौद्योगिकीय सहायता विभाग (डी.सी.ई.टी.ए.)
9. अध्यक्ष, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन विभाग (डी.ई.एम.ई.)
10. अध्यक्ष, शैक्षिक सर्वेक्षण और आँकड़ा प्रक्रियन विभाग (डी.ई.एस.डी.पी.)
11. अध्यक्ष, अध्यापक शिक्षा और विस्तार विभाग (डी.टी.ई.ई.)
12. अध्यक्ष, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग (डी.ई.पी.एफ.ई.)
13. अध्यक्ष, शैक्षिक अनुसंधान और नीतिगत संदर्श विभाग (डी.ई.आर.पी.पी.)
14. अध्यक्ष, पुस्तकालय, प्रलेखन एवं सूचना प्रभाग (डी.एल.डी.आई.)

15. अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग
(आई.आर.डी.)

16. अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग (पी.डी.)

17. अध्यक्ष, योजना, प्रोग्रामिंग,अनुवीक्षण और मूल्यांकन प्रभाग
(पी.पी.एम.ई.डी.)

18. प्रो. आर.के. दीक्षित
सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग
(डी.ई.एस.एस.एच.)

19. प्रो. हुकुम सिंह
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग (डी.ई.एस.एम.)

20. डा. अवतार सिंह
शैक्षिक मापन और मूल्यांकन विभाग (डी.ई.एम.ई.)

21. प्रो. के.के. वशिष्ठ
विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक शिक्षा विभाग (डी.पी.एस.ई.ई.)

22. डा. (श्रीमती) सुषमा गुलाटी
शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग (डी.ई.पी.एफ.ई.)

23. डा. (श्रीमती) एन. सबरवाल
अध्यापक शिक्षा और विस्तार विभाग (डी.टी.ई.ई.)

बाहरी सदस्य

24. डा. डी.पी. पटनायक
बी-188, बारमुंडा, ड्यूप्लेक्स कालोनी, भुवनेश्वर 751003

25. डा. एस.सी. सर्मा
20-8/2-7, नया अयोध्या नगर, विजयवाड़ा-3 (आंध्र प्रदेश)

26. प्रो. एस.एन. सिंह
(1) 36/34, के-1, शक्ति नगर, कबीर नगर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
(2) मार्फत ग्लोब बुक सेंटर, लंका, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

27. डा. सीताराम जायसवाल
निदेशक, भारतीय शोध संस्थान, सरस्वती कुंज, निराला नगर
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

28. डा. एस.के. गुप्ता
बी-17, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली

सी.आई.ई.टी. का संस्थान सलाहकार बोर्ड

1. संयुक्त निदेशक — *अध्यक्ष*
   केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.)

2. प्रो. आर.एल. फुटेला
   सी.आई.ई.टी.

3. डा. एस.पी. बन्याल
   सी.आई.ई.टी.

4. डा. हरमेश लाल
   रीडर, सी.आई.ई.टी.

5. श्री एम. ब्रह्माजी
   अध्यक्ष, डी.पी.ओ.एम. प्रभाग, सी.आई.ई.टी.

6. एन.आई.ई. के सभी विभागों के अध्यक्ष

7. प्रो. लोकेश कौल
   डीन (अध्ययन) एवं अध्यक्ष
   शिक्षा विभाग
   हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला

8. श्री पूरन चंद
   संयुक्त आयुक्त (अकादमिक)
   केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई महरौली रोड
   नई दिल्ली

9. प्रो. ओ.एस. देवल
   ई-250, मयूर विहार, फेस II
   नई दिल्ली

10. प्रो. डी.पी. तिवारी
    16-ए मंदाकिनी एंक्लेव, अलकनन्दा परिसर
    नई दिल्ली 110019

11. प्रो. एन.के. अम्बष्ट
    अध्यक्ष
    राष्ट्रीय खुला विद्यालय
    बी-35, कैलाश कालोनी
    नई दिल्ली 110048

पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. का संस्थान सलाहकार बोर्ड

1. संयुक्त निदेशक *अध्यक्ष*
   पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.
   भोपाल

2. प्रो. ए.के.सचेती
   पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.
   भोपाल

3. प्रो. ए.पी.वर्मा
   पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.
   भोपाल

4. प्रो. डी.के. वैद
   पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल

5. प्रो. एन.के. अम्बष्ट
   अध्यक्ष, राष्ट्रीय खुला विद्यालय
   बी-35, कैलाश कालोनी
   नई दिल्ली 110048

6. अध्यक्ष
   राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
   सी-2/10, सफदरजंग विकास क्षेत्र, श्री अरविंद मार्ग
   नई दिल्ली 110016

7. प्रो. एस.वी. आर्य
   49, अलोक नगर, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश

8. श्री वी.डी. देशमुख
   निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा)
   व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय
   3, महापालिका मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं. 10036
   मुंबई 400001

9. डा. रवि प्रकाश
   ई-100/40, शिवाजी नगर
   भोपाल 462016

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर की प्रबंध समिति

1. उप-कुलपति — *अध्यक्ष*
एम.डी.एस. विश्वविद्यालय
अजमेर

2. प्राचार्य — *उपाध्यक्ष*
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
अजमेर

क्षेत्र में प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभागों का एक नामिती

3. श्रीमती विद्यावती
पी.ई.एस. (I)
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पंजाब
चंडीगढ़

4. निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा
चंडीगढ़

5. निदेशक
राज्य शिक्षा संस्थान
सेक्टर-32
चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़

6. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला 171001

7. श्री एन.एस. टोलिया
अवर शिक्षा निदेशक (विद्यालय)
शिक्षा निदेशालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय
दिल्ली 110054

8. डा. (श्रीमती) एन.बी. बछिवाल
प्राचार्य
आई.ए.एस.ई., मीराहाली रोड
अजमेर 305001

अध्यक्ष, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित दो विशेषज्ञ

9. श्रीमती एस. संधीर
   निदेशक
   एस.सी.ई.आर.टी., गुड़गांव
   हरियाणा

10. डा. शरद चन्द्र पुरोहित
    निदेशक
    एस.सी.ई.आर.टी.
    उदयपुर 313001

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के दो विभागाध्यक्ष

11. अध्यक्ष
    शिक्षा विभाग
    क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

12. अध्यक्ष
    विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
    क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. के एक नामिती

13. डीन (समन्वय)
    एन.सी.ई.आर.टी.
    नई दिल्ली 110016

उन विश्वविद्यालयों से अन्य सदस्य जिनसे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान संबद्ध हैं

14. प्रो. एम.एल. छीपा
    एम.डी.एस. विश्वविद्यालय
    अजमेर

15. प्रशासनिक अधिकारी — *सचिव*
    क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
    अजमेर

16. क्षेत्र के क्षेत्रीय सलाहकार — *विशेष आमंत्रित*

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल की प्रबंध समिति

1. उप–कुलपति *अध्यक्ष*
   बरकतुल्ला विश्वविद्यालय
   भोपाल

3. प्राचार्य *उपाध्यक्ष*
   क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
   भोपाल

क्षेत्र के प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभागों का एक नामिती

3. श्री सुमित बोस
   सचिव
   शिक्षा विभाग
   भोपाल

4. श्री एम.वी. जोशी
   निदेशक
   राज्य शिक्षा संस्थान
   गोवा

5. श्री आर.के. चौधरी
   निदेशक
   गुजरात एस.सी.ई.आर.टी.
   अहमदाबाद, गुजरात

6. निदेशक
   एस.सी.ई.आर.टी.
   पुणे, महाराष्ट्र

7. सचिव (शिक्षा)
   दादर और नगर हवेली
   संघ शासित क्षेत्र शिक्षा विभाग
   सिल्वासा

8. सहायक शिक्षा निदेशक
   संघ शासित क्षेत्र, दमन और दीव

अध्यक्ष, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित दो विशेषज्ञ

9. प्रो. वी.जी. भिडे
   पूर्व उप–कुलपति
   पुणे विश्वविद्यालय, भौतिकी विभाग
   पुणे 411 007

10. प्रो. (श्रीमती) स्नेहाबेन जोशी
प्रशासन और प्रबंधन विभाग
शिक्षा और मनोविज्ञान संकाय
एम.एस. विश्वविद्यालय, वड़ोदरा

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों के दो अध्यक्ष

11. अध्यक्ष
शिक्षा विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भोपाल

12. अध्यक्ष
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भोपाल

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. का एक नामिती

13. डीन (समन्वय)
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

उन विश्वविद्यालयों के अन्य सदस्य जिनसे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान संबद्ध है

14. डा. एच.के. गोस्वामी
प्रोफेसर (आनुवंशिक) एवं अध्यक्ष
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

15. डा. एस.के. कुलश्रेष्ठ
प्राचार्य
राजकीय हमीदिया महाविद्यालय
भोपाल

16. प्रशासनिक अधिकारी — *सचिव*
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भोपाल

17. क्षेत्र के क्षेत्रीय सलाहकार — *विशेष आमंत्रित*

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर की प्रबंध समिति

1. उप-कुलपति *अध्यक्ष*
   उत्कल विश्वविद्यालय
   भुवनेश्वर

2. प्राचार्य *उपाध्यक्ष*
   क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
   भुवनेश्वर

क्षेत्र में प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभागों का एक नामिती

3. श्री बी.सी. स्वेन
   संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग
   उड़ीसा सरकार, उड़ीसा सचिवालय
   भुवनेश्वर

4. श्री एस. सोम
   संयुक्त सचिव
   विद्यालय शिक्षा विभाग
   विकास भवन (पांचवां तल) सॉल्ट लेक
   कलकत्ता

5. निदेशक
   एस.सी.ई.आर.टी.
   महेन्द्रू, पटना
   बिहार

6. श्री एन. दास
   शिक्षा निदेशक
   ए. एंड एन. प्रशासन
   पोर्ट ब्लेयर

अध्यक्ष, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित दो विशेषज्ञ

7. प्रो. डी.एन. राय
   विश्व भारती
   शांतिनिकेतन
   ज़िला बीरभूम
   पश्चिम बंगाल

8. श्री परवन्त सामन्तराय
   35, मीना बाग
   नई दिल्ली 110011

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों से दो अध्यक्ष

9. अध्यक्ष
शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भुवनेश्वर

10. अध्यक्ष
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भुवनेश्वर

एन.सी.ई.आर.टी. का एक नामिती

11. डीन (समन्वय)
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

उन विश्वविद्यालयों से अन्य सदस्य जिनसे क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान संबद्ध है

12. डा. डी.सी. मिश्रा
सेवानिवृत्त डी.पी.आई.
जगन्नाथ लेन, बादामगढ़ी
कटक

13. प्रशासनिक अधिकारी — *सचिव*
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
भुवनेश्वर

14. क्षेत्र के क्षेत्रीय सलाहकार — *विशेष आमंत्रित*

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर की प्रबंध समिति

1. उप-कुलपति *अध्यक्ष*
मैसर विश्वविद्यालय
मैसूर

2. प्राचार्य *उपाध्यक्ष*
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
मैसूर

क्षेत्र में प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा विभागों का एक नामिती

3. श्री वी. कृष्णमाचार्युलु
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
आंध्र प्रदेश सरकार
आलिया भवन, लाल बहादुर स्टेडियम के सामने
हैदराबाद 500 001

4. निदेशक
डी.एस.ई.आर.टी.
बी.पी. वाडिया रोड
बसावनगुडी
बैंगलूर 560004

5. श्री के. जयकुमार
सरकार के सचिव
सामान्य शिक्षा विभाग
केरल सरकार
तिरुअनन्तपुरम 695001

6. निदेशक
डी.टी.ई.आर.टी.
कॉलेज रोड
चेन्नई 600006

7. श्री एस. हेमाचन्द्रन
सचिव (शिक्षा) एवं सह-शिक्षा निदेशक
पांडिचेरी सरकार
पांडिचेरी 605001

8. श्री पी.बी. मुथुकोया
शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निदेशालय
लक्षद्वीप प्रशासन
लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र
कवारत्ती (वाया) कोचिन

अध्यक्ष, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित दो विशेषज्ञ

9. डा. मल्लादी श्री रामामूर्ति
प्रो. एवं डीन
शिक्षा संकाय
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद

10. डा. जी. शिवरुद्रप्पा
पूर्व डीन
शिक्षा संकाय, कर्नाटक विश्वविद्यालय
वीरभद्र हाउसिंग बोर्ड कालोनी रोड
आर.टी. नगर, पो.ऑ. आदित्य नगर
बैंगलूर 560032

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नामित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों के दो अध्यक्ष

11. अध्यक्ष
शिक्षा विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
मैसूर

12. अध्यक्ष
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
मैसूर

निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी. का नामिती

13. डीन (समन्वय)
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

14. प्रशासनिक अधिकारी — *सचिव*
क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
मैसूर

15. क्षेत्र के क्षेत्रीय सलाहकार — *विशेष आमंत्रित*

(क) परिषद् मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति

1.	निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.	*अध्यक्ष*
2.	संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.	*उपाध्यक्ष*
3.	संयुक्त निदेशक, सी.आई.ई.टी.	
4.	सचिव, एन.सी.ई.आर.टी.	
5.	सभी विभागों/प्रभागों के अध्यक्ष	
6.	सभी उप सचिव	
7.	मुख्य लेखा अधिकारी	
8.	सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी	
9.	जन संपर्क अधिकारी	
10.	निदेशक, राजभाषा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली	
11.	निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	
12.	प्रोफेसर एवं प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ	*सदस्य सचिव*
13.	हिंदी अधिकारी	

(ख) परिषद् की राजभाषा कार्यान्वयन समिति

1.	निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.	*अध्यक्ष*
2.	संयुक्त निदेशक, एन.सी.ई.आर.टी.	*उपाध्यक्ष*
3.	संयुक्त निदेशक, सी.आई.ई.टी.	
4.	संयुक्त निदेशक, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.	
5.	सचिव, एन.सी.ई.आर.टी.	
6.	सभी विभागाध्यक्ष/प्रभागाध्यक्ष	
7.	सभी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्राचार्य	
8.	विशेष कार्य अधिकारी (ओ.एस.डी.) उत्तर-पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग	

9. सभी क्षेत्रीय सलाहकार
10. सभी उप सचिव
11. मुख्य लेखा अधिकारी
12. सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी
13. जन सम्पर्क अधिकारी
14. प्रोफेसर एवं प्रभारी, हिंदी प्रकोष्ठ — सदस्य सचिव
15. हिंदी अधिकारी

स्वीकृत स्टाफ की स्थिति

31.3.2000 को एन.सी.ई.आर.टी. में वर्गवार स्वीकृत स्टाफ की स्थिति

क्र.सं.	सूचना स्रोत	शैक्षिक संकाय			गैर-शैक्षिक (सचिवालयी)			गैर-शैक्षिक (तकनीकी)			ग्रुप डी	योग
		ए.	बी.	सी.	ए.	बी.	सी.	ए.	बी.	सी.		
1.	परिषद् मुख्यालय	199	01	02	23	200	291	45	47	146	285	1239
2.	सी.आई.ई.टी.	25	–	–	03	23	33	30	34	74	24	246
3.	आर.आई.ई., अजमेर	57	24	35	01	10	37	04	03	41	85	297
4.	आर.आई.ई., भोपाल	57	24	42	01	11	35	03	03	32	86	294
5.	आर.आई.ई., भुवनेश्वर	68	27	55	01	11	35	04	04	44	92	341
6.	आर.आई.ई., मैसूर	68	19	44	01	10	37	05	04	36	75	299
7.	आर.आई.ई., शिलांग	24	–	–	–	01	02	–	–	01	02	30
8.	क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय	25	–	–	–	26	17	–	–	13	26	107
9.	आर.पी.डी.सीज.	–	–	–	–	–	15	06	06	06	06	39
10.	पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल	35	–	–	04	05	12	05	01	15	05	82
	कुल	558	95	178	34	297	514	102	102	408	686	2974

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

वर्ष 1999-2000 का प्राप्ति और भुगतान लेखा

प्राप्तियां	राशि रु.	रु.	भुगतान	राशि रु.	रु.
आरंभिक बकाया			**बजट खर्च**		
नकद बकाया और बैंक में जमा	39,48,39,490		*अधिकारियों का वेतन*		
मार्गस्थ निधि	65,40,516	40,13,80,006	गैर-योजना	9,69,41,042	
			योजना	25,04,711	9,94,45,753
मानव संसाधन विकास मंत्रालय से			*प्रतिष्ठान वेतन*		
बजट खर्च के लिए प्राप्त अनुदान			गैर-योजना	11,67,32,993	
गैर-योजना	30,00,00,000		योजना	10,84,136	11,78,17,129
योजना	10,00,00,000	40,00,00,000			
विशेष परियोजनाओं से संबंधित			*भत्ते तथा मानदेय*		
अनुदान		8,65,55,628	गैर-योजना	14,12,12,968	
(अनुसूची 'एच')			योजना	22,71,458	14,34,84,426
			यात्रा भत्ता		
			गैर-योजना	33,10,053	
			योजना	2,25,204	35,35,257
परिषद् की प्राप्तियां					
(खंड 5)			*अन्य प्रभार*		
परिषद् भवनों का किराया	34,68,352		गैर-योजना	7,19,66,204	
ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	22,36,171		योजना	19,32,215	7,38,98,419
सावधि जमा पर ब्याज	1,45,33,058		*छात्रवृत्तियां और अध्येतावृत्तियां*		
भविष्य निधि निवेश			गैर-योजना	3,86,684	
पर ब्याज	3,46,12,911		योजना	46,773	4,33,457
अधिक भुगतान की वसूली	8,16,931		*कार्यक्रम*		
विज्ञान किटों की बिक्री	8,94,729		गैर-योजना	17,03,68,961	
शुल्क और प्रभार	51,36,175		योजना	3,73,19,026	20,76,87,987
पुस्तकों और पत्रिकाओं			*उपकरण और फर्नीचर*		
की बिक्री	41,41,18,343		गैर-योजना	83,25,541	
छुट्टी वेतन और			योजना	1,71,08,019	2,54,33,560
पेंशन अंशदान	11,05,265		*भूमि और भवन*		
सी.जी.एच.एस.	8,86,011		गैर-योजना	2,43,57,186	
(केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना)			योजना	3,37,00,635	5,80,57,821
विविध प्राप्तियां	1,04,28,003	48,82,35,949	*विशिष्ट परियोजनाओं से*		
			संबंधित भुगतान		
			(अनुसूची) 'एच'	28,41,70,886	28,41,70,886

विविध भुगतान (खंड 2)		
परिषद् भवन का किराया	31,51,858	
सी.जी.एच.एस.	33,58,659	
पेंशन अंशदान	3,72,767	
अंशदान भविष्य निधि ब्याज और परिषद् का अंश	19,96,163	
सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	3,69,09,008	
पेंशन और डी.सी.आर.जी.	11,09,57,742	
लेखा परीक्षा फीस	4,24,680	
विज्ञापन	24,48,559	
जमा लिंक बीमा योजना	5,25,588	
विविध/अदृष्ट	<u>4,19,621</u>	16,05,64,645

ऋण, जमा और प्रेषण

ऋण और अग्रिम (ब्याज सहित)		
खंड 4(3) (1)		
मोटर/स्कूटर	16,07,672	
अन्य वाहन (साइकिल)	1,09,828	
गृह निर्माण अग्रिम	30,70,527	
पंखा अग्रिम	22,298	
चक्रवात अग्रिम	<u>85,650</u>	48,95,975
खंड 4(3) (2) ब्याज रहित		
विभागीय अग्रिम खंड 4(5)		
स्थायी अग्रिम	20,085	
कार्यक्रम/विविध अग्रिम	<u>22,42,454</u>	22,62,539
ऋण खंड 4(1)		
सामान्य भविष्य निधि	10,01,49,755	
सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	<u>3,61,99,222</u>	13,63,48,977
सामान्य भविष्य निधि	(-) 17,33,984	
ब्याज और परिषद का अंश	<u>19,96,163</u>	2,62,179

ऋण और अग्रिम (ब्याज सहित)		
मोटरकार/स्कूटर	33,44,690	
अन्य वाहन (साइकिल)	1,15,500	
गृह निर्माण अग्रिम	47,23,199	
पंखा अग्रिम	24,000	
चक्रवात	<u>5,60,000</u>	87,67,389
विभागीय अग्रिम		
स्थायी अग्रिम	67,600	
कार्यक्रम/विविध अग्रिम	<u>26,07,920</u>	26,75,520
ऋण		
सामान्य भविष्य निधि		8,04,38,589
अंशदायी भविष्य निधि		17,02,190
भविष्य निधि		
दीर्घकालीन निवेश	5,23,54,118	
परिषद् से निवेश	<u>21,85,89,353</u>	27,09,43,471
अल्पकालीन		
बयाना राशि और प्रतिभूति जमा	43,32,006	
अवधान राशि	59,950	
अन्य	8,95,192	
अन्य जमा (विज्ञान किट)	<u>9,46,094</u>	62,33,242

निवेश			*प्रेषित धन*		
खंड 4(4)			सा.भ.नि./अं.भ.नि.	5,32,383	
भविष्य निधि			डाक जीवन बीमा/	5,03,712	
			जीवन बीमा निगम		
दीर्घकालीन निवेश	1,02,44,000		जी.एल.आई.एस.	28,76,604	
अल्पकालीन निवेश	20,46,41,653	21,48,85,653	आयकर	1,18,49,201	
			मृत्यु राहत निधि	3,85,962	
जमा					
खंड 4(2)			थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी	8,98,033	
बयाना राशि और प्रतिभूति जमा	14,76,351		विविध	34,52,066	
अवधान राशि	1,82,679		उपकार्यालय प्रेषण	36,54,42,734	
अन्य	12,67,302		प्रधानमंत्री राहत कोष	11,33,033	
अन्य जमा (विज्ञान किट)	2,68,645	31,94,977	आवधिक प्रेषण	30,98,07,574	
			बिक्रीकर	33,866	69,69,15,168
प्रेषित धन					
(खंड 4(7))			अंतशेष		
सा.भ.नि./अं.भ.नि.	5,44,639		रोकड़ बकाया	18,19,67,642	
डाक जीवन बीमा/जीवन			तथा बैंक में (अनुसूची 'सी')		
बीमा निगम	5,09,609		मार्गस्थ निधि	99,97,447	19,19,65,089
जी.एल.आई.एस.	26,60,369				
आयकर	1,17,29,608				
मृत्यु राहत निधि	2,30,851				
थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटी	8,95,548				
विविध	29,14,909				
उप कार्यालय प्रेषण	36,56,64,482				
आवधिक प्रेषण	30,98,07,574				
प्रधानमंत्री राहत कोष	11,39,161				
बिक्री कर	51,365	69,61,48,115			
कुल योग		**2,43,41,69,998**			**2,43,41,69,998**

मुख्य लेखा अधिकारी
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

सचिव
एन.सी.ई.आर.टी.
नई दिल्ली 110016

1999-2000 के दौरान निकाले गए प्रकाशन

शीर्षक

पहली कक्षा

- बाल भारती भाग-1
- अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग-1
- वर्कबुक फॉर लैट अस लर्न इंग्लिश बुक-I (एस एस)
- लैट अस लर्न मैथेमैटिक्स बुक-I

दूसरी कक्षा

- बाल भारती भाग-2
- अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग-2
- लैट अस लर्न इंग्लिश बुक-II (एस एस)
- वर्कबुक फॉर लैट अस लर्न इंग्लिश बुक-II (एस एस)
- लैट अस लर्न मैथेमैटिक्स बुक-II

तीसरी कक्षा

- बाल भारती भाग-3
- लैट अस लर्न इंग्लिश बुक-III (एस एस)
- वर्कबुक फॉर लैट अस लर्न इंग्लिश बुक-III (एस एस)
- लैट अस लर्न मैथेमैटिक्स बुक-III
- आओ गणित सीखें पुस्तक-III
- परिवेश अन्वेषण भाग-1 (विज्ञान)
- वी एण्ड अवर कंट्री (सोशल स्टडीज़)
- हम और हमारा देश
- एक्सप्लोरिंग एनवायरनमेंट बुक-I

चौथी कक्षा

- बाल भारती भाग-4 — दो संस्करण
- अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग-4
- इंग्लिश रीडर बुक-I (एस एस)
- वर्कबुक फॉर इंग्लिश रीडर बुक-I (एस एस)
- रीड फॉर प्लेजर-I — दो संस्करण
  (इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर फॉर क्लास-IV)
- लैट अस लर्न मैथेमैटिक्स बुक-IV

- हमारा देश भारत (सामाजिक अध्ययन)
- एक्सप्लोरिंग एनवायरनमेंट बुक-II (साइंस) दो संस्करण

पांचवीं कक्षा

- बाल भारती भाग-5
- अभ्यास पुस्तिका बाल भारती भाग-5
- स्वस्ति भाग-1 (संस्कृत पाठ्यपुस्तक)
- अभ्यास पुस्तिका स्वस्ति भाग-1
- इंग्लिश रीडर बुक-II (एस एस)
- रीड फॉर प्लेजर-II (इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर फॉर क्लास-V)
- लैट अस लर्न मैथेमैटिक्स बुक-V
- अवर कंट्री एंड दि वर्ल्ड (सोशल स्टडीज़)
- एक्सप्लोरिंग एनवायरनमेंट बुक-III (साइंस) दो संस्करण
- परिवेश अन्वेषण भाग-3 (विज्ञान)
- इंग्लिश वर्कबुक फॉर इंग्लिश रीडर-II

छठी कक्षा

- सरस भारती भाग-1
- संक्षिप्त रामायण (पूरक पठन की पुस्तक)
- नया जीवन (पूरक पठन की पुस्तक) भाग-1 दो संस्करण
- स्वस्ति भाग-2 (संस्कृत पाठ्यपुस्तक)
- अभ्यास पुस्तिका स्वस्ति भाग-2
- इंग्लिश रीडर बुक-III (एस एस)
- वर्कबुक फॉर इंग्लिश रीडर बुक-III (एस एस)
- रीड फॉर प्लेजर-III (इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर फॉर क्लास-VI)
- मैथेमैटिक्स बुक-I
- एन्शन्ट इंडिया (हिस्ट्री)
- प्राचीन भारत (इतिहास)
- लैंड्स एण्ड पीपुल पार्ट-I (ज्योग्राफी)
- देश और उनके निवासी भाग-1 (भूगोल)
- अवर सिविक लाइफ (सिविक्स)
- हमारा नागरिक जीवन (नागरिक शास्त्र)
- साइंस बुक-I
- विज्ञान पुस्तक-1
- हिन्दी व्याकरण और रचना (कक्षा 6-8)

सातवीं कक्षा

- सरस भारती भाग-2
- संक्षिप्त महाभारत — दो संस्करण
- स्वस्ति भाग-3 (संस्कृत पाठ्यपुस्तक)
- अभ्यास पुस्तिका स्वस्ति भाग-3
- इंग्लिश रीडर बुक-IV (एस एस)
- मैथेमैटिक्स बुक-II पार्ट-I
- गणित पुस्तक-2 भाग-1
- गणित पुस्तक-2 भाग-2
- हाउ वी गवर्न अवरसेल्व्स (सिविक्स)
- हम अपना शासन कैसे चलाते हैं (नागरिक शास्त्र)
- मेडिवल इंडिया (हिस्ट्री)
- मध्यकालीन भारत (इतिहास)
- साइंस बुक-II
- विज्ञान पुस्तक-2
- लैंड्स एण्ड पीपुल पार्ट-II (ज्योग्राफी)

आठवीं कक्षा

- सरस भारती भाग-3 (नई पुस्तक)
- सरस भारती भाग-3 (पुनर्मुद्रित संस्करण)
- संक्षिप्त बुद्ध चरित (पूरक पठन की पुस्तक) (नई पुस्तक)
- नया जीवन भाग-3 (पूरक पठन की पुस्तक) (नई पुस्तक) — दो संस्करण
- स्वस्ति भाग-4 (संस्कृत पाठ्यपुस्तक)
- अभ्यास पुस्तिका स्वस्ति भाग-4
- इंग्लिश रीडर बुक-V (एस एस)
- रीड फॉर प्लेजर-V (इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर फॉर क्लास-VIII)
- मैथेमैटिक्स बुक-III पार्ट-I
- मैथेमैटिक्स बुक-III पार्ट-II
- मॉडर्न इण्डिया (हिस्ट्री)
- साइंस बुक-III
- विज्ञान पुस्तक-3

नवीं कक्षा

- लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर-I इंग्लिश रीडर ('बी' कोर्स)
- लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर-I वर्कबुक टु इंग्लिश रीडर ('बी' कोर्स)
- लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर-I — दो संस्करण
- सप्लीमेंटरी रीडर ('बी' कोर्स)
- स्वाति भाग-1 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक 'अ' पाठ्यक्रम – पद्य)

- पराग भाग-1 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक 'अ' पाठ्यक्रम – गद्य)
- विज्ञान भाग-1
- विज्ञान (संयुक्त)
- मैथेमैटिक्स
- गणित भाग-1 (संयुक्त)
- अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट (ज्योग्राफी)
- पर्यावरण बोध (भूगोल)
- मानक हिन्दी व्याकरण और रचना (हिन्दी व्याकरण 'अ' पाठ्यक्रम, कक्षा 9-10)
- अवर इकोनोमी – एन इंट्रोडक्शन — दो संस्करण
- पूर्वा भाग-1 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक 'बी' पाठ्यक्रम) (नई पुस्तक) — दो संस्करण
- कथा कलश (हिन्दी 'बी' पाठ्यक्रम) नई पुस्तक
- दि स्टोरी ऑफ सिविलाइज़ेशन वाल्यूम-I
- सभ्यता की कहानी भाग-1

दसवीं कक्षा

- लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर-II इंग्लिश रीडर ('बी' कोर्स)
- लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर-II वर्कबुक टु इंग्लिश रीडर ('बी' कोर्स)
- लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर -II (सप्लीमेंट्री रीडर 'बी' कोर्स)
- स्वाति भाग-2 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक 'अ' पाठ्यक्रम-पद्य)
- पराग भाग-2 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक 'अ' पाठ्यक्रम-गद्य)
- मैथेमैटिक्स — दो संस्करण
- गणित (संयुक्त)
- इंडिया-इकॉनामिक ज्योग्राफी (ज्योग्राफी)
- भारत-आर्थिक भूगोल (भूगोल)
- सभ्यता की कहानी भाग-2 (इतिहास)
- इंडिया: कांस्टीट्यूशन एण्ड गवर्नमेंट
- भारत: संविधान और सरकार (कक्षा 9-10)
- दि स्टोरी ऑफ सिविलाइज़ेशन वाल्यूम-II

ग्यारहवीं कक्षा

- नीहारिका भाग-1 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक केंद्रिक-पद्य)
- पल्लव भाग-1 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक केंद्रिक-गद्य)
- मंदाकिनी भाग-1 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक वैकल्पिक-गद्य)
- साहित्य का स्वरूप
- आई एम दि पीपुल (इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर-कोर)
- स्टोरीज़, प्लेज़ एंड टेल्स ऑफ एडवेंचर (इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर-कोर) — दो संस्करण
- सरकार के अंग-राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक
- एन्शन्ट इंडिया (हिस्ट्री) नई पुस्तक

- प्राचीन भारत (इतिहास) नई पुस्तक
- प्रिंसीपल्स ऑफ ज्यॉग्राफी पार्ट-I
- भूगोल के सिद्धान्त भाग-1
- समाजशास्त्र: एक परिचय
- मेडिवल इंडिया (हिस्ट्री)
- एलीमेंट्री स्टेटिस्टिक्स (इकोनोमिक्स)
- अंडरस्टैंडिंग साइकोलोजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर
- व्यवसाय अध्ययन
- फिजिक्स पार्ट-I
- फिजिक्स पार्ट-II
- कैमिस्ट्री
- बायोलोजी
- इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनोमी
- ए सप्लीमेंट टु मैथेमैटिक्स-पार्ट बी (फॉर साइंस) (नई पुस्तक)
- ए सप्लीमेंट टू मैथेमैटिक्स-पार्ट सी (फॉर कामर्स एंड ह्यूमैनिटीज़) (नई पुस्तक)

बारहवीं कक्षा

- नीहारिका भाग-2 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक केंद्रिक-पद्य)
- पल्लव भाग-2 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक केंद्रिक-गद्य) — दो संस्करण
- प्रवाल भाग-2 (हिन्दी पाठ्यपुस्तक वैकल्पिक-गद्य)
- ए कोर्स इन रिटन इंग्लिश (कोर)
- दि वैब ऑफ अवर लाइफ (कोर)
- संस्कृत कविता कादम्बिनी — दो संस्करण
- बायोलोजी पार्ट-I — दो संस्करण
- बायोलोजी पार्ट-II
- कैमिस्ट्री
- रसायन विज्ञान भाग-1
- जीव विज्ञान भाग-1
- जीव विज्ञान भाग-2 (नई पुस्तक)
- मेजर कान्सेप्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस (पॉलिटिकल साइंस)
- इंडिया : ए जनरल ज्योग्राफी (ज्योग्राफी)
- इण्डिया-रिसोर्सेज़ एण्ड रिजनल डेवलपमेंट — दो संस्करण
- एकाउंटिंग बुक-I
- एकाउंटिंग बुक-II फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस
- नेशनल इनकम एकाउंटिंग
- एन इंट्रोडक्शन टु इकॉनोमिक थ्योरी
- आर्थिक सिद्धांत का परिचय
- इंडियन सोसाइटी
- साइकॉलोजी फॉर बैटर लिविंग

- सोशल चेंज
- कॉस्ट एकाउंटिंग
- मैथेमैटिक्स पार्ट-I
- मैथेमैटिक्स पार्ट-II
- गणित भाग-1 (नई पुस्तक)
- डेमोक्रेसी इन इंडिया (पॉलिटिकल साइंस)
- भारत में लोकतंत्र
- फिज़िक्स पार्ट-I
- फिज़िक्स पार्ट-II
- लेखाकरण भाग-2 (नई पुस्तक)
- ए सप्लीमेंट टु मैथेमैटिक्स (पार्ट-बी फॉर साइंस) (न्यू बुक)
- ए सप्लीमेंट टु मैथेमैटिक्स (पार्ट-सी फॉर कामर्स एंड ह्यूमेनिटीज़) (न्यू बुक)

उर्दू पाठ्यपुस्तकें

दूसरी कक्षा

- आओ हिसाब सीखें किताब-II
- उर्दू की नई किताब

तीसरी कक्षा

- हम और हमारा देश
- गिर्द-ओ-पेश का मुताला किताब-I
- उर्दू की नई किताब

चौथी कक्षा

- हमारा मुल्क हिन्दुस्तान
- गिर्द-ओ-पेश का मुताला किताब-II
- उर्दू की नई किताब

पाँचवीं कक्षा

- हमारा मुल्क और दुनिया
- गिर्द-ओ-पेश का मुताला किताब-III
- आओ हिसाब सीखें किताब-V हिस्सा-1
- उर्दू की नई किताब

छठी कक्षा

- साइंस किताब-I
- हमारी शहरी ज़िंदगी
- उर्दू की नई किताब

सातवीं कक्षा

- मुमालिक और उनके बाशिंदे हिस्सा-II
- उर्दू की नई किताब

आठवीं कक्षा

- उर्दू की नई किताब

नवीं कक्षा

- हमारी माईशत का एक नया तारुफ
- उर्दू की नई किताब

दसवीं कक्षा

- रियाजी (हिसाब) हिस्सा-I
- हिन्दुस्तान का माशी जुगराफ़िया
- उर्दू की नई किताब

ग्यारहवीं कक्षा

- उर्दू की नई किताब

बारहवीं कक्षा

- उर्दू की नई किताब

द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू के लिए पाठ्यपुस्तक

कक्षा-VI के लिए

- हमारी उर्दू की किताब हिस्सा-I (एल-2) (नई पुस्तक)

तृतीय भाषा के रूप में उर्दू के लिए पाठ्यपुस्तक

कक्षा-VII के लिए

- आओ उर्दू पढ़ें भाग-I (एल-III) (नई पुस्तक)

अरुणाचल प्रदेश के लिए पाठ्यपुस्तकें

- अरुण भारती भाग-1
- अभ्यास पुस्तिका अरुण भारती भाग-1
- अभ्यास पुस्तिका अरुण भारती भाग-2
- अरुण भारती भाग-3
- अभ्यास पुस्तिका अरुण भारती भाग-3
- अरुण भारती भाग-4
- अरुण भारती भाग-5

- न्यू डॉन रीडर-I फॉर क्लास-I
- वर्क बुक फॉर न्यू डॉन रीडर-II फॉर क्लास-II
- न्यू डॉन रीडर-III फॉर क्लास-III
- वर्क बुक फॉर न्यू डॉन रीडर-III फॉर क्लास-III

नवोदय विद्यालय के लिए पाठ्यपुस्तकें

छठी कक्षा

- माई फैमिली एंड फ्रेंड्स
- वर्कबुक फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स
- सप्लीमेंटरी रीडर फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स
- अभ्यास पुस्तिका-हमारी हिंदी भाग-1

सातवीं कक्षा

- माई स्माल वर्ल्ड
- वर्कबुक फॉर माई स्माल वर्ल्ड
- सप्लीमेंटरी रीडर फॉर माई स्माल वर्ल्ड
- अभ्यास पुस्तिका-हमारी हिंदी भाग-2

आठवीं कक्षा

- वर्कबुक फॉर दि वर्ल्ड अराउंड मी
- हमारी हिन्दी भाग-3
- अभ्यास पुस्तिका हमारी हिन्दी भाग-3

पश्चिम बंगाल के लिए पाठ्यपुस्तकें

- गद्य भारती — दो संस्करण
- काव्य भारती

शिक्षक संदर्शिकाएँ

- श्रवण विकारयुक्त बच्चों का भाषा विकास-शिक्षक संदर्शिका

पूरक पुस्तकें

- वी आर वन
- एन्शन्ट स्टोरीज़
- कंडक्टिंग यूथ्स पार्लियामेन्ट (रिवाइज़्ड एडीशन)
- जीवनोपयोगी सूक्ष्म मात्रिक तत्व
- साहस के धनी
- युवा ससद का संचालन (संशोधित संस्करण)

- आओ मिलकर गाएँ
- हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रमुख कंठ संगीतज्ञ
- सौर ऊर्जा और उसके उपयोग
- हमारा अद्‌भुत वायुमंडल अब मैला क्यों
- मौसम–क्या, क्यों और कैसा

व्यावसायिक पाठ्‌यक्रम की पाठ्‌यपुस्तकें

उद्यान विज्ञान

- फ्रूट प्रोडक्शन (प्रैक्टिकल मैनुअल फॉर क्लास XI)
- फ्रूट प्रोडक्शन (कक्षा 11 के लिए पाठ्‌यपुस्तक)

डेयरी उद्योग

- डेयरी एनीमल मैनेजमेंट क्लास XI
- फीड एंड फीडिंग ऑफ डेयरी एनीमल्स क्लास XI

कार्यालय प्रबन्धन

- टाइपराइटिंग पार्ट–I क्लास–XI

हस्तकला

- सॉफ्ट टॉयज़ क्लास IX–X

ग्रामीण अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी

- बिल्डिंग मेंटिनेंस –
  बिल्डिंग मैटीरियल प्रैक्टिस मैनुअल क्लास–XI पेपर–I
- बिल्डिंग मेंटिनेंस –
  बिल्डिंग मैटीरीयल–I (पाठ्‌यपुस्तक) क्लास–XI पेपर–I

अनुसंधान अध्ययन तथा मोनोग्राफ

- लर्निंग आर्गेनाइज़ेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड स्कूल एफैक्टिवनेस एट दि प्राइमरी स्टेज
- स्टडीज़ ऑन लर्निंग आर्गेनाइज़ेशन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड स्कूल एफैक्टिवनेस एट प्राइमरी स्टेज
- टीचिंग एड्स इन मैथेमैटिक्स फॉर मिडल एंड हाई स्कूल स्टूडेन्ट्स
- स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ साइंस मॉड्यूल्स
- एनुअल रिपोर्ट 1998–1999–एन.सी.ई.आर.टी
- वार्षिक रिपोर्ट 1998–1999–एन.सी.ई.आर.टी.
- एनुअल एकाउन्ट्स 1997–1998–एन.सी.ई.आर.टी.
- वार्षिक लेखा 1997–1998–एन.सी.ई.आर.टी.

- एक्ज़ामिनेशन रिफोर्म्स-ए बुलेटिन
- इंटरनेशनल रिसर्च सेमिनार ऑन इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एट एलीमेन्टरी स्टेज-फोल्डर
- जवाहर लाल नेहरू नेशनल साइंस एग्ज़ीबिशन 1999–लिस्ट ऑफ एग्ज़ीबिट्स
- जवाहर लाल नेहरू नेशनल साइंस एग्ज़ीबिशन 1999–फोल्डर (इंग्लिश)
- जवाहर लाल नेहरू नेशनल साइंस एग्ज़ीबिशन 1999–फोल्डर (हिन्दी)
- जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस एग्ज़ीबिशन 1999–फोल्डर (गुजराती)
- नेशनल सेमिनार ऑन इन्फरमेशन टैक्नोलोजी एंड दि स्कूलिंग प्रोसेस–फोल्डर
- स्कूल एजुकेशन इन इंडिया–फोल्डर (30.09.1998 तक)
- शिक्षा के पहले कदम : प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की ओर
- कॉमन स्कूल सिस्टम रेटरोस्पेक्ट एंड प्रोसपेक्ट
- शिक्षा लहर
- विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–परिचर्चा दस्तावेज़
- नेशनल करीकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन–ए डिस्कशन डॉक्युमेंट
- सिक्स्थ ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे–मेन रिपोर्ट
- ग्रेडिंग इन स्कूल्स
- एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन इंडिया

अनौपचारिक शिक्षा की पुस्तक

- मिलकर सीखें गणित भाग–4 क्लास–4

शैक्षिक पत्रिकाएँ

- दि प्राइमरी टीचर (चार अंक)
- प्राइमरी शिक्षक (पांच अंक)
- स्कूल साइंस (चार अंक)
- जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन (छह अंक)
- भारतीय आधुनिक शिक्षा (पांच अंक)
- इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (तीन अंक)
- इंडियन एजुकेशनल एब्स्ट्रेक्ट्स (जनवरी 1999) (एक अंक)
- ग्लिम्प्सेज़– ए क्वार्टर्ली जर्नल (चार अंक)
- आभास– त्रैमासिक पत्रिका (चार अंक)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए प्रकाशन

- फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटिज़न्स वाल्यूम–I
- फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटिज़न्स वाल्यूम–II
- नागरिकों के मूल कर्तव्य अंक–1

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के क्षेत्रीय उत्पादन व वितरण केन्द्र

क्रमांक	केन्द्रों के नाम	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1.	क्षेत्रीय उत्पादन एवं वितरण केन्द्र प्रकाशन प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी. मार्फत नवजीवन ट्रस्ट पो.ऑ. नवजीवन अहमदाबाद-380014 दूरभाष : 405446	गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गोवा
2.	क्षेत्रीय उत्पादन एवं वितरण केन्द्र प्रकाशन प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी. 108, 100 फीट रोड होस्कारेहल्ली एक्सटेंशन बनाशंकरी 3 स्टेज बैंगलूर-560085 दूरभाष : 6692740	तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिनीकाय और अमिन दीवी द्वीप समूह
3.	क्षेत्रीय उत्पादन एवं वितरण केन्द्र प्रकाशन प्रभाग, एन.सी.ई.आर.टी. 32, बी.टी. रोड सुखचर, 24 परगना कलकत्ता-743179 दूरभाष: 5530454	पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा उत्तर-पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशनों के थोक एजेन्टों के नाम और पते

आंध्र प्रदेश

1. मै. गुप्ता ब्रदर्स बुक्स
मेन रोड, 47-13-10/1 द्वारका नगर
विशाखापटनम-530016
फोन: 554454, 547580

2. मै. हिमालय बुक डिपो
5-7-561, दरगाह यूसुफैन रोड
नामपल्ली बाज़ार
हैदराबाद-500001
फोन: 214879, 4612145

3. मै. सैन्ट्रल बुक शॉप
5-9-186, चैपल रोड
हैदराबाद-500001
फोन (का.) 3202980
(नि.) 4530111

4. मै. श्रीनिवास पेपर एण्ड स्टेशनरी मार्ट
40-5-19/18 श्री वेंकटेश्वर निलयम्
मोंगलराजपुरम, रेवेन्यू कालोनी
विजयवाड़ा-520010 (आ.प्र.)
फोनः (08812) 25826, 21648

5. मै. ज्योति बुक डिपो
30-15-138, दाबागार्डन्स
विशाखापटनम-530020
फोन: 546020, 541201

6. मै. अशोक बुक सेन्टर
मेरिस स्टेली कॉलेज के सामने
विजयवाड़ा-520008
फोन: 476966, 472096

बिहार

7. मै. चिल्ड्रन बुक सेन्टर प्रा. लि.
मछुआ टोली
पटना-800004
फोन : (का.) 650362
(नि.) 220460, 655048

8. मै. गुप्ता पुस्तक एजेंसी
प्लाट नं. सी-1, सैक्टर-9
बोकारो स्टील सिटी-827009
फोन: (का.) 46637

9. मै. गया प्रसाद खंडेलवाल
खंडेलवाल चौक, मेन रोड
हज़ारीबाग
फोन: 2287

10. मै दुर्गा पुस्तक भण्डार
बांका बाजार, मोती झील
मुज़फ्फरपुर-842001

11. मै. झा न्यूज़ एण्ड बुक केन्द्र
रसूलपुर जिलानी
मझोलिया रोड
मुज़फ्फरपुर-842001
फोन: 242194

12. मै. प्रभात बुक डिपो
दीपक मार्किट, प्रथम तल
मोती झील
मुज़फ्फरपुर-842001

13. मै. प्रोग्रेसिव बुक सेन्टर
जिला स्कूल
पानी टंकी चौक रमना
मुज़फ्फरपुर-842001
फोन: 243852

14. मै. ज्ञान गंगा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
बोरिंग रोड
पटना-800013
फोन: 263011, 261956

15. मै पॉपुलर बुक स्टोर
पटना कॉलेज के सामने
पटना-800004
फोन (नि.) 54176

16. मै. सिन्हा ब्रदर्स
जहाज़ी कोठी के निकट
कदम कुआँ, मेन रोड
पटना–800003
फोन: (का.) 667342 (नि.) 665025

17. मै. वर्मा प्रेस (पी.एण्ड डी.)
प्रथम तल, गोपाल मार्किट
नया टोला
पटना–800004
फोन : (का.) 663465 (नि.) 673696

18. मै. पुस्तक मंदिर
पुस्तक पथ, अपर बाज़ार
रांची–834001
फोन: (का.) 203273, 313248

19. मै. पुस्तक सदन
रामा पथ, पूर्वी पुल
रांची–834001
फोन: (का.) 307515, 204364

20. मै. आइडियल बुक स्टोर
रतन टॉकीज़ के निकट
मेन रोड
रांची–834001
फोन: (का.) 311523
(नि.) 203629

21. मै श्री किताब घर
पुस्तक पथ, अपर बाज़ार
रांची–834001
फोन: 202714

22. मै. सुबोध ग्रंथमाला कार्यालय
पुस्तक पथ, अपर बाज़ार
रांची–834001

23. मै. भारती पुस्तक भण्डार
राम बाबू चौक
समस्तीपुर–848101

24. मै. ज्ञान भारती
कामधेनु कॉम्पलैक्स
जोरा फाटक रोड
धनबाद–820001
फोन: (का.) 302969, 307933

चंडीगढ़

25. मै. मनचंदा ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स
एस.सी.एफ. नं. 1, सैक्टर 19–सी
पो. बॉक्स नं. 705
चण्डीगढ़–160019
फोन: (का.) 775216, 775768, 775769
(नि.) 560499

26. मै. मनचंदा डिपार्टमेंटल स्टोर
एस.सी.एफ.नं. 2, सैक्टर 19–सी
चण्डीगढ़–160019
फोन: (का.) 775012

दिल्ली

27. मै. प्रकाश ब्रदर्स
46, भगत सिंह मार्किट
नई दिल्ली–110001
फोन: 3362615, 3362616

28. मै. जनता बुक डिपो प्रा. लि.
23, शहीद भगत सिंह मार्ग
नई दिल्ली–110001
फोन: 3363685, 3362985

29. मै. स्मिथ एण्ड स्पैन पब्लिकेशंस
8/7 ज्वाला हेड़ी मार्किट
पश्चिम विहार
नई दिल्ली–110063
फोन: 5575381, 5583302

30. मै. मलिक बुक सैलर्स एण्ड स्टेशनर्स
2157/टी–2, सत्यम सिनेमा के सामने
पश्चिमी पटेल नगर
नई दिल्ली–110008
फोन: 5706082

31. मै. अशोक पब्लिशिंग हाउस
ए-1/659, सैक्टर-6
मेन रोड, रोहिणी
नई दिल्ली-110085
फोन : 7048160

32. मै. सत्यम स्टेशनर्स
दुकान सं. 7
सी.एस.ई.नं.-6
सेक्टर-7 रोहिणी
नई दिल्ली-110085
फोन: 7053220, 784556

33. मै. मल्होत्रा बुक डिपो
17/39 बी, पुरानी मार्किट
तिलक नगर
नई दिल्ली-110018
फोन: 5439787, 5434956

34. मै. जी.बी.एस. पब्लिशर्स एण्ड
डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
एम.एस. हाउस
994/66 त्रिनगर
दिल्ली-110035
फोन: 7186836, 7195926

35. मै. जनता बुक डिपो
1521/2 वज़ीर नगर
पी.टी. कालेज के सामने
डिफेन्स कालोनी
नई दिल्ली-110003
फोन: (का.) 621791, 692352
(नि.) 6416656

36. मै. रोमिल पब्लिशर्स प्रा. लि.
ए.-18, गली सं. 10
पूर्वी आज़ाद नगर
दिल्ली-110051
फोन: (का.) 2436849, 2211154
(नि.) 2421652

37. मै. राज पुस्तक भण्डार
54, सेन्ट्रल मार्किट, लाजपत नगर
नई दिल्ली-110024
फोन: 6832627, 6849198

38. मै. चावला बुक डिपो
दुकान सं. 16
सैक्टर नं. 3, आर.के. पुरम
नई दिल्ली-110022
फोन 6174783, 6174501, 6184849, 6174900

39. मै. नीड प्रकाशन प्रा. लि.
219, जमरुदपुर
एन ब्लॉक के सामने
ग्रेटर कैलाश-I
नई दिल्ली-110048
फोन: 6443814, 6435460

40. मै. सचदेवा बुक डिपो
IX/6081, मेन रोड
गांधीनगर
दिल्ली-110031
फोन : (का.) 2200299
(नि.) 2415144, 2468756

41. मै. गोपीराम एण्ड सन्स (बुकसैलर)
2619/20, सी-3, न्यू मार्किट, नई सड़क
दिल्ली-110006
फोन: 3253351, 3250632

42. मै. गीता पब्लिशिंग हाउस
टी-565, प्रगति कॉम्पलैक्स
ईदगाह चौक
दिल्ली-110006
फोन: 7775482, 7522668

43. मै. विश्व भारती प्रकाशन
4071, नई सड़क
दिल्ली-110006
फोन: (का.) 2916973
(नि.) 6833079, 6916718

44. मै. दीपक स्टेशनर्स
709/1, जी.टी. रोड
कबूल नगर, शाहदरा
दिल्ली-110032
फोन: 2285327, 2280956

45. मै. संजय ब्रदर्स
2590, नई सड़क
दिल्ली-110006
फोन: 3261916

46. मै. शिवदास एण्ड सन्स
9665, इस्लाम गंज
लाइब्रेरी रोड, आज़ाद मार्किट
दिल्ली-110006
फोन: 7514886, 7777366, 3551616

47. मै. नेशनल बुक हाउस
8/18, कालकाजी एक्सटेंशन
नई दिल्ली-110019
फोन: 6232342, 6212711

48. मै. सुभाष ब्रदर्स
2606, नई सड़क
दिल्ली-110006
फोन: 3261011, 3283733

49. मै. राजेश पुस्तक भण्डार
4 ए/3, ज्वाला हेड़ी
पश्चिम विहार
नई दिल्ली-110063
फोन: 5580992, 5584826

50. मै. लाम्बा बुक डिपो
नं. 9, पुरानी मार्किट
तिलक नगर
नई दिल्ली-110018
फोन: 5190207, 5934577

51. मै. सचदेवा पुस्तक भण्डार
IX/6082-83, मेन रोड
गांधीनगर, थाने के पास
दिल्ली-110031
फोन: 2212172

गुजरात

52. मै. तुसार बुक डिपो
36-37, कैपिटल कमर्शियल सेन्टर
आश्रम रोड
अहमदाबाद-380009
फोन: 6587103, 6578741

53. मै. रॉयल स्टेशनर्स
सागर अपार्टमेंट
शॉप नं. 14
रामधाम के सामने, कालवाड़ रोड
राजकोट-360005
फोन: 582926

54. मै. शालिभद्र स्टेशनर्स
7, शान्ति सोसायटी
बॉम्बे गैराज के पीछे, शाही बाग
अहमदाबाद-380004
फोन: 5621748

हरियाणा

55. मै. फ्रेंड्स बुक सर्विस
दुकान सं. 68, 2 एच पार्क
एन.आई.टी.
फरीदाबाद-121001
फोन: 414292, 413040

56. मै. अरोड़ा ट्रेड लिंकर प्रा. लि.
(अग्रवाल धर्मशाला के सामने)
रेलवे रोड, करनाल-132001
फोन: (का.) 255805, 252205
(नि.) 255305

57. मै. भगवती पेपर मार्ट
पुरानी अनाज मण्डी
रोहतक-124001
फोन: (का.) 52184 (नि.) 56184

58. मै. शर्मा ब्रदर्स
बी.डी. हाई स्कूल के निकट
अम्बाला कैन्ट–133001
फोन: 640525

59. मै. चिल्ड्रन बुक डिपो
4329, बी.डी. वरिष्ठ माध्यमिक
विद्यालय के निकट
अम्बाला कैन्ट–133001
फोन: 642585

60. मै. दीपक बुक डिपो
4269, हॉस्पिटल रोड
अम्बाला कैन्ट–133001
फोन: (का.) 642076
(नि.) 641706, 640706

61. मै. द्वारका प्रसाद एण्ड सन्स
मोती बाज़ार
हिसार–125001
फोन: (का.) 31657 (नि.) 36122

62. मै. नरेश बुक डिपो
प्रताप चौक
रोहतक–124001
फोन (का.) 75889 (नि) 77052

63. मै. स्वामी किताब घर
कच्चा बेरी रोड
रोहतक–124001
फोन: (का.) 45879 (नि.) 46886

जम्मू और कश्मीर

64. मै. हरनाम दास एण्ड ब्रदर्स
पक्का डंगा
जम्मू तवी–180001
फोन: (का.) 542175
(नि.) 574428

65. मै. साहित्य संगम
कच्ची छावनी
जम्मू तवी – 180001
फोन: (का.) 549049 (नि.) 548729

66. मै. गुप्ता बुक सेन्टर
सम्राट होटल बस स्टैंड के निकट
जम्मू तवी–180001
फोन: (का.) 577046
(नि.) 534925

67. मै. जे.के. बुक हाउस
रेज़ीडेन्सी रोड
जम्मू तवी–180001
फोन: 573560

68. मै. अली मोहम्मद एण्ड सन्स
1, बडशाह होटल बिल्डिंग
लाल चौक
श्रीनगर–190001
फोन: (का.) 475973, 474539
(नि.) 474440

69. मै. अशोक बुक डिपो
पुरानी मंडी
जम्मू तवी–180001
फोन: 542261, 573014
(नि.) 547321, 543344

कर्नाटक

70. मै. हेमा स्टोर
नं. 1 तथा 2, बालाजी थिएटर कम्पलैक्स
वन्नरपेट, विवेक नगर
बैंगलूर–560047
फोन: 5575110

71. मै. भगवान कृष्णा ट्रेडर्स
नं. 25, मामुलपेट
बैंगलूर–560053
फोन: 2872774

72. मै. सुभाष पब्लिशिंग हाउस
नं. 116, 5 वां मेन, छठा क्रास
(राम मंदिर बस स्टॉप के निकट)
बैंगलूर–560053
फोन: 6507309

केरल

73. मै. एकेडेमिक बुक हाउस
पुलीमूदू जंक्शन
तिरुअनंतपुरम-695001
फोन (का.): 333349 (नि.) 331878

74. मै. टी.बी.एस. पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स
टी.बी.एस. बिल्डिंग, जी.एच. रोड
कालिकट-673001
फोन (का.): 720085, 720086, 721025
(नि.) 721160

75. मै. स्टर्लिंग ट्रेडिंग एण्ड एजेंसीज़
36/1079, जजिज़ एवेन्यू
वैदयार लेन, काल्लोर
कोच्चि-682017
फोन: 402624, 400531

76. मै. प्रोग्रेसिव करिकुलम मैनेजमेंट प्रा. लि.
अम्मनकोविल रोड
अरनाकुलम
कोच्चि-682035
फोन: 354047, 374058, 374258, 361824

77. मै. एकेडेमिक बुक हाउस
39/817, चितोर रोड
साउथ जंक्शन
अरनाकुलम-682016
फोन: 369613

78. मै. वी. पब्लिशर्स बुक स्टॉल
सी.एम.एस. कॉलेज रोड
कोट्टयम-686001
फोन: (का.) 567470, 567471, 568645
561472 (नि.) 301184

79. मै. विद्यार्थी बुक्स एंड लाबेड्स
सी.एम.एस. कालेज जंक्शन
कोट्टयम 686001
फोन : 561203, 567486

80. एच. एण्ड सी. स्टोर्स
पी.बी.नं. 1
कुन्नाकुलेम-680503
(थिरसुर जिला)
फोन (का.): 522243 (नि.) 522383

81. मै. एच. एंड सी. स्टोर्स
हाई रोड
थिरसुर-680001
फोन: (का.) 421462, 421467
(नि.) 336230

82. मै. एच. एण्ड सी. स्टोर्स
डी.एच. रोड
अरनाकुलम साउथ
कोच्चि-682016
फोन: 351563

मध्य प्रदेश

83. मै. पी.के. बुक्स एण्ड स्टेशनर्स
सदर बाज़ार कैन्ट
जबलपुर-482001
फोन: 320840

84. मै. सुशील प्रकाशन
212, खजूरी बाज़ार
इन्दौर-452002
फोन (का.): 535892, 282892
(नि.) 541901

85. मै. एम.पी. टेक्स्टबुक कार्पोरेशन
शिवाजी नगर
भोपाल-462011
फोन: 550727, 553094

86. मै. गुप्ता पब्लिशिंग हाउस
623, खजूरी बाजार, एम.जी.रोड
इन्दौर-452002
फोन: 454921, 454922

महाराष्ट्र

87. मै. ए.एच. व्हीलर एण्ड कं. लि.
25, आर.बी.एस.के. बोले रोड
दादर (पश्चिम)
मुंबई-400028
फोन: 4370612, 4370467

88. मै. एस. चांद एण्ड कं. लि.
3, गांधी सागर पूर्वी
नागपुर-440002
फोन: 723901

89. मै. कपूर स्टेशनरी मार्ट
दुकान सं. 42
आम्रपाली शापिंग आर्केड
वसन्त विहार, पोखरण रोड-2
थाणे (पं.)400601
फोन: 5330711, 5361053

उत्तर-पूर्वी राज्य

90. मै. बानी मंदिर
रानी बाड़ी, पान बाज़ार
गुवाहाटी-781001 (असम)
फोन: (का.) 520241
(नि.) 564488

91. मै. डोन्यी पोलो एन्टरप्राइज़ेज़
सी सैक्टर, ईटानगर-791111
अरुणाचल प्रदेश
फोन: 212769, 212389

92. मै. युनाइटेड पब्लिशर्स
मेन रोड, पान बाज़ार
गुवाहाटी-781001 (असम)
फोन (का.): 517059, (नि.) 546244

93. मै. न्यू कामर्शियल सेन्टर
थांगल बाज़ार
खोयाथोंग रोड
इम्फाल-795001 (मणिपुर)
फोन: (नि.) 225964

94. मै. पेपर एण्ड स्टेशनरी स्टोर्स
पाओन बाज़ार
इम्फाल-795001 (मणिपुर)
फोन: 221109

95. मै. लियानचुंगी बुक स्टोर्स
बड़ा बाजार
आइज़ोल-796001 (मिज़ोरम)
फोन: (का.) 329522
(नि.) 322855

96. मै. क्वालिटी स्टोर
नेशनल हाइवे
गंगटोक-737101 (सिक्किम)
फोन: 22992, 24358

उड़ीसा

97. मै. ज्ञान भारती
स्टेशन स्क्वेयर
50, खारावेलानगर, इकाई-3
भुवनेश्वर-751001
फोन: (का.) 508736
(नि.) 402664

पंजाब

98. मै. नीलम पब्लिशर्स
अद्दा टंडा
जालंधर-144008
फोन: (का.) 56899
(नि.) 57170

99. मै. मल्होत्रा बुक डिपो
रेलवे रोड
जालंधर शहर-144001
फोन: 57160, 58388, 59046

100. मै. हरबंस बुक डिपो
बुक्स मार्किट
लुधियाना
फोन: 726480, 720173

101. मै. सुमीत एजुकेशनल स्टोर्स
कॉलेज रोड
पठानकोट–145001
फोन: (का.) 21609
(नि.) 21809

102. मै. परवीन जनरल स्टोर
धोबी बाज़ार के पीछे
एस.एस.डी. मंदिर के सामने
भटिण्डा–151001
फोन: (का.) 256965 (नि.) 255965

103. मै. मित्तल बुक डिपो
मेन बाज़ार
मोंगा–142001
फोन: (का.) 21228 (नि.) 23151

104. मै. पेप्सू बुक डिपो
बुक्स मार्किट
पटियाला–147001
फोन (का.) 214696, 74578
(नि.) 214331, 74605

105. मै. देश राज एण्ड सन्स
अरना बरना बाज़ार
पटियाला–147001
फोन (का.) 216076, 304179
(नि.) 219172

राजस्थान

106. मै. एवरग्रीन बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स
बी–7, फतेह सिंह मार्किट
आर.एस. पोस्ट आफिस के निकट
रेलवे स्टेशन
जयपुर–302006
फोन (का.) 362395, 317234

107. मै. रमेश बुक डिपो
पब्लिशर्स एण्ड बुकसेलर्स
138, त्रिपोलिया बाज़ार
जयपुर–302003
फोन: (का.)606492 (नि.) 43314

108. मै. एस.वी. बुक कंपनी
5, रास्ता थाथेरन, चौड़ा रास्ता
जयपुर–302003
फोन: (का.)321819, 317889
(नि.)606062

109. मै. सैनिक स्टेशनरी स्टोर
शॉप नं. 4, सेन्ट्रल मार्किट
खेतड़ी नगर–333504
(ज़िला–झुनझुनु)
फोन: 20123

110. मै. भण्डारी स्टेशनर्स
गमानपुरा
कोटा–324007
फोन: 327576

111. मै. मनोहर बुक डिपो
रेलवे स्टेशन रोड के पास
सदर बाज़ार
जयपुर–302006
फोन: (का.) 202903, 376486
(नि.) 516056, 510211

तमिलनाडु

112. मै. न्यू सेन्चुरी बुक हाउस प्रा.लि.
136, अन्ना सलाई
चेन्नई–600002
फोन: 8549563, 8550664

113. मै. सेन्ट्रल बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स
6, रामनाथन स्ट्रीट
चेन्नई–600017
फोन: 4343336, 4342568

उत्तर प्रदेश

114. मै. आलोक प्रिंटर्स
14/188, हास्पिटल रोड
आगरा–282003
फोन: 364217, 261420

115. मै. एच.एम. पब्लिकेशन्स
12/62, सुई कटरा
हॉस्पिटल रोड
आगरा-282003
फोन (का.) 263495 (नि.) 312880

116. मै. सरस्वती बुक डिपो
नौलखा बाज़ार, ग्वालियर रोड
आगरा कैन्ट-282001
फोन: 267220

117. मै. साहित्य भंडार
50 चाहचांद
इलाहाबाद-211003
फोन: 400787, 402072

118. मै. शक्ति बुक एजेंसी
राजपुर चुंगी
आगरा-282001
फोन: 331233

119. मै. उत्तम पुस्तक भंडार
1, अखाड़ा बाज़ार
देहरादून-248001
फोन: (का.) 624820
(नि.) 625645

120. मै. कमल प्रकाशन
153, पक्की मोरी
गाज़ियाबाद
फोन: 748051

121. मै. नवयुग बुक डिपो
12, दिल्ली गेट
गाज़ियाबाद
फोन: (का.) 733389
(नि.) 718711

122. मै. युनाइटेड लाइब्रेरी एण्ड बुक स्टॉल
युनाइटेड सिनेमा कंपाउन्ड
सिनेमा रोड, गोलघर
गोरखपुर
फोन: 344841, 341797

123 मै. गौरव पुस्तक भण्डार
208, हरजिन्दर नगर
कानपुर-208010
फोन: 403525, 451333

124. मै. गौतम ब्रदर्स
39/18, मेस्टन रोड
कानपुर-208001
फोन: (का.)364601, 224194
(नि.) 256026

125. मै. आशा एजेन्सीज़
दुकान सं. 3, गनी मार्किट
177/23, गुईन रोड
अमीनाबाद, लखनऊ-226018
फोन: (का.) 221445, (नि.) 227036

126. मै. यूनिवर्सल बुक कंपनी
20, महात्मा गांधी मार्ग
इलाहाबाद-211001
फोन: 623467, 624953

127. मै. सरस्वती सदन
19, सुभाष मार्किट
बरेली
फोन: (का.) 474092
(नि.) 474042, 471142

128. मै. राजहंस पुस्तक भवन
सुभाष बाज़ार
मेरठ (उ.प्र.)
फोन: (का.) 516738, 641791

129. मै. अरुणोदय बुक सेन्टर
गुरु बाग
वाराणसी-221010
फोन: 320724, 361668

130. मै. गुप्ता जनरल ट्रेडिंग कंपनी
करणघंटा, बुलानाला
वाराणसी-221001
फोन: (का.) 353017, 354582
(नि.) 344802

131. मै. बनारस बुक कार्पोरेशन
यूनिवर्सिटी रोड, लंका
वाराणसी-221005
फोन: (का.) 311385 (नि.) 312316

132. मै. विद्यार्थी केन्द्र
डी-45/3, लक्सा रोड
वाराणसी-221010
फोन: (का.) 320730 (नि.) 320709

133. मै. नेशनल बुक हाउस
डिसपेन्सरी रोड
देहरादून-248001
फोन: 659430 (नि.) 621470

134. मै. चाचा बुक स्टोर
121, सदर बाज़ार
लखनऊ-226002
फोन: (0522) 480077, 481177

135. मै. शर्मा स्टेशनरी बुक एण्ड सेन्ट्रल स्टोर
श्रीनगर, आलमबाग
लखनऊ-226005
फोन: (का.) 456851 (नि.) 454229

136. मै. व्यापार सदन
177/25, महावीर मार्किट, गुईन रोड
लखनऊ-226002
फोन: 221771, 281423
(नि.) 373794

137. मै. माही बुक पैलेस
विजय नगर
शंकर आश्रम के सामने, पूर्वी कचहरी रोड
मेरठ
फोन: 641791, 645415

138. मै. नेशनल बुक डिपो
67, सुभाष बाजार
मेरठ
फोन: 27616

139. मै. कैम्ब्रिज बुक डिपो
सिविल लाइन्स
रुड़की-247667
फोन: (का.) 72341
(नि.) 73892

140. मै. सतीश प्रकाशन
गली नं. 1, प्लाट नं. 19
रविन्द्रपुरी
वाराणसी-221005
फोन: (का.) 315164
(नि.) 314193

141. मै. इलाहाबाद बुक सेन्टर
20, एम.जी. मार्ग, सिविल लाइन्स
इलाहाबाद-211001
फोन: 623468, 420936, 603159

पश्चिम बंगाल

142. मै. देव साहित्य कुटीर प्रा. लि.
21, झामपूकर लेन
कलकत्ता-700009
फोन: 3504294, 3504295, 3507887

अंडमान और निकोबार द्वीप

143. मै. अंडमान बुक सेन्टर
गोलघर, पो.बा. सं. 543
पोर्ट ब्लेयर-744103

and fifth-year programs, while continuing work in academic subjects, include courses in social affairs of Iraq, poultry-breeding, dairying, carpentry, and blacksmithing, principles of education and psychology, teaching methods, and practice teaching. In all these courses emphasis is upon the problems and needs of rural teachers of primary schools in Iraqi villages.

By a recent ruling students who have completed the fourth year are required to pass the public intermediate-school examinations before they can register for the fifth year. The professional courses are concentrated in the last two years; practice teaching is limited to the fifth year, beginning in a rural school connected with the college and ending with full-time practice in a village school during April. Methods instructors visit the student-teachers to appraise their work and give them assistance.

The staff of the College at Rustumiyah consists of the principal, who is a graduate of the old Higher Teachers College, and twenty-four instructors, of whom nineteen are graduates of the four-year course at the Higher Teachers College, four are graduates of Fuad I University in Cairo, and one is a graduate of the American University of Beirut. All graduates of the Higher Teachers College have had some professional training as prospective secondary-school teachers, but three of them—the teachers of psychology and education—are graduates of the Division of Education which existed at that College from 1937–42 and have had more intensive educational training.

Rustumiyah is situated on an extensive farm about 14 kilometers (8.7 miles) south of Baghdad on the Diyala River. Originally an experimental farm belonging to the Department of Agriculture, it was transferred in 1934 to the Ministry of Education. In addition to the original building which formerly housed the School of Agriculture (1928–30), there are now large dormitories with dining-rooms and an assembly hall, and extensive bungalows have been built to serve as classrooms. The College has a small library and large playing fields.

It was recently suggested by the Higher Committee on Studies and Curricula that the course for rural teachers should be lengthened to six years, with the first four years devoted to intermediate-school studies plus agricultural and hygiene classes and the upper two years devoted to studies of standard secondary and professional training. It was felt that such a plan for rural teachers would provide them with the equivalent of a secondary-school diploma and so open opportunities for the ambitious to pursue further study. At the same time it would attract a better type of student—the village boy who would like to attend a secondary school but is unable to do so because of lack of facilities in his village. The suggestion

was opposed on the grounds that its adoption would make the course unduly long at a time when the Ministry of Education is in great need of primary teachers and that it would raise the level of salaries beyond the capacity of the budget of the Ministry.

THE ELEMENTARY TEACHERS COLLEGE FOR WOMEN

The Elementary Teachers College for Women made its first appearance in 1934 in Diwaniyah, where an uncongenial environment brought its performance to an early end. It reopened as a branch of the Primary Teachers College for Women in Baghdad, but was later separated from that institution. It offers a course of four years to girl graduates of the primary school and is designed to prepare women teachers for rural primary schools. In its first three years this College follows the course of the intermediate schools except that it substitutes general-science courses for the separate science courses of the intermediate school. In the fourth year the program is as follows:

Subject	Periods per week
Psychology	2
General education and method	2
Practice teaching	3
Methods of teaching primary subjects	5
Arabic	6
English	4
Algebra	2
Geometry	2
History	2
Geography	2
Science	3
Drawing	1
Sewing	2
Singing and physical education	1
Total	37

It is apparent that the course of study is little adapted to the College's objective of fitting women to teach in the rural districts. It is a regular academic course combined with a few professional classes. As a result both types of instruction are weak and the curriculum is overcrowded, fourteen subjects being taught in one year.

The course is being lengthened to five years, and the students are to be required to pass the public intermediate-school examination before being admitted to the fourth year. The first graduating class to complete the new five-year program will be that of 1948.

At the time of the American Council Commission's visit (1945) the College had 212 students, almost all of them boarders at government expense. The attempt to admit only village girls is less successful than the similar policy in the rural-teachers colleges for men because there are fewer village schools for girls to supply candidates and because of the prejudice of parents against sending girls away from home. There is a staff of thirteen, including the principal and assistant principal. Of this number, five have had some professional training. The College is housed in a large quadrangle, one part of which is occupied by a practice school and a kindergarten.

The Education of Secondary-School Teachers

Teachers for intermediate and secondary schools are now educated at the Higher Teachers College, the three-year course at the Queen 'Aliyah Institute for women teachers, and at the Physical Education Institute.

THE HIGHER TEACHERS COLLEGE

The Higher Teachers College originated in evening classes which were opened for primary-school teachers in 1923 in order to prepare them to teach in secondary schools. This was later turned into a full-time boarding college giving a course of two years above the secondary school, divided into a literary and a scientific section. The College was abolished in 1931 as being of a low standard and having an inadequate staff. The need for secondary-school teachers made the Ministry of Education reopen the College in 1935, with a course of two years which was lengthened to three in 1937 and to four in 1939. In 1943 it was decided to add a preparatory year taught exclusively in English.[3] Women students were first admitted in 1937 and now constitute about one-third of the enrollment.

Buildings and grounds.—The Higher Teachers College is housed in two large, modern buildings on the northern outskirts of Baghdad with ample space for additional buildings, playgrounds, and gardens.

One building houses administrative offices, classrooms, and an assembly hall. The other houses the dormitory, the dining-room, reception rooms, the College library, and, until a special science building is erected, the physics and chemistry laboratories. Women students live in a rented house

[3] Word has recently been received that the preparatory year has been dropped and the program again reduced to four years. As no details of the new program were available, the description of the program as it was being executed and planned at the time of the visit of the American Council Commission has been maintained.

about a mile from the College. It is planned to build a special women's dormitory closer to the College.

Students.—In October 1945 when the American Council Commission visited the Higher Teachers College, there were four classes: preparatory, first, second, and fourth years. The fourth-year class was the last following the old four-year program. The remaining three classes were following the five-year program. Of the total registration of about 357 students it was expected that about 120 would be women, an increase of about 20 women students over the previous year. Students registered in the College were distributed as shown in Table 31.

TABLE 31

ENROLLMENT IN HIGHER TEACHERS COLLEGE, BAGHDAD, 1945–46

Year*	Literary	Social Studies	English	Chemistry —Biology	Physics—Mathematics	Total
Preparatory year....	...	...	...	...	...	130
1st year...........	17	19	12	20	14	82
2nd year...........	12	10	8	18	8	56
4th year...........	20	17	9	25	18	89
Total..........	...	...	...	...	...	357

* There was no third-year class in 1945–46 because of the change of length of course from four to five years.

Students are admitted on the basis of standing in the public secondary-school examination, distribution by provinces, health, and personal interview by the admission committee. Tuition, board and lodging, books, and medical care are free. Boarding students sign a contract with the Ministry, agreeing to serve the Ministry two years for every year spent at the College or pay 50 dinars ($200) for each year of study. Day students agree to teach one year for each year of study or forfeit 25 dinars ($100) per year of study.

Curriculum.—The distribution of subjects and periods is shown in Tables 32 and 33. The preparatory year has two parallel courses, the literary and the scientific. Both sections study the same courses in Arabic and English. However, in the English course students are grouped into A, B, and C sections, according to ability, each taking a course corresponding to its ability. Students wishing to become teachers of English must be members of section A or else stand very high in section B.

Preparatory students of the literary section take, in addition to English and Arabic, a three-period course in general mathematics and four-period courses in ancient history, modern history, and geography, whereas the scientific section concentrates on mathematics, physics, and chemistry. All

TABLE 32

PROGRAM OF STUDY OF THE HIGHER TEACHERS COLLEGE FOR ARABIC, ENGLISH, AND SOCIAL STUDIES SECTIONS, IRAQ, 1945

SUBJECT	HOURS PER WEEK																
	PREPARATORY YEAR (COMMON)	Arabic Section				English Section				Social Studies Section							
										1st Year	2nd Year	3rd Year Major			4th Year Major		
		1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year			Arab History	Modern History	Geography	Arab History	Modern History	Geography
Arabic	7	8	7	8	8	3	3	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
English	6	3	3	3	...	10*	10*	10*	8	5	...	...	...	...	...	...	...
Psychology	...	...	3	4	2	...	3	4	2	...	3	4	4	4	2	2	2
Education and practice teaching	...	...	5	4	7	...	5	4	7	...	5	4	4	4	7	7	7
Educational biology	...	3	...	...	...	3	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...	...
Hygiene	...	2	...	...	...	2	...	...	...	2	...	...	...	...	...	...	...
Ethics	...	...	...	...	1	...	...	...	1	...	...	...	...	...	1	1	1
General mathematics	3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Ancient history	4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	3	3	2	2	2
Modern history	4	...	...	...	...	...	...	...	...	4	5	...	6	...	...	6	...
Arabic history	...	4	4	...	...	...	...	...	...	4	5	6	...	...	6	...	...
Geography	4	2†	...	...	...	2‡	...	...	...	5	5	3†	3†	9§	...	...	6
French or Latin	...	3	3	3	3	3	3	3	3	...	...	...	...	...	...	...	...
Economics	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...
Government	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	2	...	...	...	...
Sociology	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3	3	3
Translation	...	...	...	...	...	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	28	25	25	22‖	21‖	24	25	24	21	23	23	22	22	22	21	21	21

* Including British history and institutions.
† Geography of the Arabic world.
‡ Geography of the British Commonwealth.
§ Includes three hours of geography of the Arabic world.
‖ Two three-hour courses in Syriac required in addition from students hoping to become candidates for fellowships abroad.

TABLE 33

PROGRAM OF STUDY OF THE HIGHER TEACHERS COLLEGE FOR CHEMISTRY-BIOLOGY AND PHYSICS-MATHEMATICS SECTIONS, IRAQ, 1945

Subject	Hours per Week											
	Preparatory Year (Common)	Chemistry-Biology Section						Physics-Mathematics Section				
		1st Year	2nd Year	3rd Year		4th Year		1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	
				Major		Major					Major	
				Chemistry	Biology	Chemistry	Biology				Mathematics	Physics
Arabic	7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
English	6	5	...	...	...	...	...	5	...	...	...	...
Psychology	...	...	3	4	4	2	2	...	3	4	2	2
Education and practice teaching	...	...	5	4	4	7	7	...	5	4	7	7
Educational biology	...	3	...	...	...	...	...	3	...	...	...	...
Ethics	...	...	...	...	...	1	1	...	...	...	1	1
Physics	4	4	...	...	...	...	...	4	7	7	...	7
Mathematics	7	3	...	...	...	...	...	6	6	6	6	3
Chemistry	4	5	6	10	4	12	...	5	...	...	...	...
Zoology	...	4	6	6 or	6	...	6	...	...	...	...	...
Botany	...	4	6	6	6	...	6	...	...	...	...	...
Biological theories	...	...	...	2	2	...	...	...	...	...	...	...
Anatomy, physiology, and hygiene	...	...	...	...	...	3	3	...	...	...	...	...
Mechanics (applied mathematics)	...	...	...	...	...	...	...	3	3	4	4	4
Hygiene	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...
Total	28	28	26	26	26	25	25	26	26	25	20	24

teaching is in English. The College regards the preparatory class as a means of discovering material unsuitable for higher training. Any student who fails in more than two subjects in this preparatory year is dropped. Between 18 and 25 percent in the class usually fails. A minimum grade of 60 in any subject and a general average of 65 are required. A student failing more than once at any time in his college career is dropped—unless he is a fourth-year student on the point of graduation, in which case he has another chance.

Having survived the preparatory course, the student may choose one of five parallel courses: Arabic, English, social studies, chemistry-biology, or physics-mathematics. All courses in every section are required. They have in common courses in English, educational psychology, education and practice teaching, educational biology, hygiene, and ethics. Only the courses in educational psychology and in education need be described briefly here.

In educational psychology students study a general course in psychology in the first year, a course in child and adolescent psychology in the second year, a course in mental and educational measurements in the third year, and a course in mental hygiene and behavior problems in the fourth. Studies in education include in the second year a general course in secondary education and visits to schools. In the third year courses in special methods and in the philosophy of education, based on Dewey's *Democracy and Education,* are given. Preliminary practice teaching consists of individual lessons given by the student-teachers in the presence of their fellow-students. These lessons are later discussed in class. In the fourth year the methods course is continued with three weeks of practice teaching in the demonstration school under the supervision of a training teacher. The instructors in methods are expected to visit the student-teachers about once a week. Early in April the student-teachers are assigned to the intermediate schools of Baghdad for an additional three weeks of practice teaching. During this period the student-teacher conducts two or three lessons a day by agreement with the subject teachers in the school. Specialized-methods courses are given in the teaching of four subjects: Arabic, English to foreigners, social studies, and science and mathematics.

In addition to the courses that are common to all and require a total of thirty-six hours out of the general total for four years' study of eighty-nine to one hundred and five hours (one hundred seventy-eight to two hundred ten semester hours), each section follows its own more or less specialized courses. In general, the first two years are intended for surveying the fields of study and the last two years for increased specialization in the field of the student's choice. Exceptions to this rule are the Arabic and English

sections, which require all students to take the same courses throughout.

The courses of the Arabic section are designed to give the student a specialist's knowledge of Arabic grammar and literature, sufficient familiarity with English language and literature to be at home in this language, and a basic knowledge of either French or Latin.

Courses of the English section are designed to produce a competent teacher of English. The curriculum stresses language and literature, but includes courses in British history and institutions and in the geography of the British Commonwealth. Here, as in the Arabic section, French or Latin is required, partly to deepen the student's understanding of the English language and partly to introduce him to a second Western literature. By direction of their English professors, most of the students elect Latin.

In the social-studies section, survey courses of college level are given in the first two years in Arabic history, modern European history, and geography, to provide the student with a basis for teaching these subjects in intermediate schools. In the last two years the student elects one of these subjects and takes advanced courses in it. All students are required to take two courses in ancient history—one an advanced course in the ancient history of Iraq (Babylonia and Assyria) and the other in that of Greece and Rome—one course in sociology, and one course in either government or economics.

In the chemistry-biology section the students take a general college course in physics in the preparatory and first years, and one general course in higher mathematics which includes the elementary concepts of the calculus needed in advanced chemical or biological work. The courses in chemistry, starting with the preparatory years, are designed to acquaint the student with inorganic and organic chemistry, with qualitative analysis and elements of physical chemistry. Survey courses in zoology and botany are given in the first two years. In the third year the student may specialize in chemistry or in biology. If he chooses chemistry, he studies quantitative volumetric and gravimetric analysis, industrial chemistry, and advanced physical chemistry; in addition, he studies either zoology or botany in his third year. If he chooses biology as his field of specialization, he studies theoretical biology, a course in anatomy, physiology, and hygiene, and has two years each of zoology and botany.

Students in the physics-mathematics section probably have the heaviest and hardest course in the College. All take four years of mechanics. They have a common program in physics and mathematics through the third year with only minor differentiation in the fourth. The courses in physics, beginning with the second year, cover the usual branches of the subject in detail and lead up to an ultimate course in the later discoveries concerning

the atom. Mathematics courses begin with elementary calculus, analytical geometry, and higher algebra, continue with advanced courses in these subjects, and end up with differential equations and interpolation in the fourth year.

Before graduation a student from any section must write two theses—one in the field of education or psychology, the other on a subject within the field of his specialization—and pass a comprehensive oral examination in both fields.

Equipment.—The fact that the Higher Teachers College was just getting re-established at the outbreak of World War II subjected it to delays and shortages in equipment. However, the government was rather generous in its budgetary allotment, and every attempt was made to equip it as well as possible.

Laboratories were started from nothing in the summer of 1937, only two years before the war. Large orders for equipment placed in England and various European countries gradually materialized, so that by 1941 the laboratories were supplied with essential, if not adequate, apparatus, chemicals, glassware, microscopes and slides, charts, and specimens. During the last year of the war the shortage of chemicals was felt, and the increase in number of students made the number of available microscopes inadequate. In 1945 the College was in great need of a workshop for repairing scientific apparatus and trained technicians to do the work.

For geography a good collection of Arabic, English, and German maps and globes has been brought together. Maps of Iraq of various scales have been supplied by the Iraqi Survey Department. There is a small geological collection, and a biological museum is contemplated.

The library grew from about 500 volues in 1937 to 9,252 in October 1945. About two-thirds of the books are in English; the rest, except for a few hundred in French and Turkish, are in Arabic. In spite of the difficulties of importing books in wartime, the library managed to add from 1,200 to 1,500 volumes to its collection yearly. The library has a fairly representative list of periodicals, but it was impossible during the war to get American magazines regularly, and there are many gaps in the files. Almost all the important Arabic periodicals are received and about 35 English and American periodicals. The Dewey Decimal system of classification is used. Work was proceeding in 1945 on a card catalog of authors, subjects, and titles.

Students make heavy use of library books for reference and assigned reading, but borrow few books for their own enjoyment.

Staff and administration.—In 1945–46 the staff of the Higher Teachers

College, consisting of the dean, professors, associate professors, assistant professors, instructors, lecturers, assistant instructors, and demonstrators, totaled forty. The faculty is drawn from Iraq, Lebanon, Egypt, England, and, in one instance, the United States. Professional qualifications are as follows:

Ph.D. or D.Litt. from the United States, England, or France	8
M.A. or M.S. from the United States, England, Egypt, or American University of Beirut	10
B.A. or B.Sc. from England or American University of Beirut	9
M.D.	1
Licence in Letters from Egypt	1
Licence in Law and old scholastic study of Arabic, Baghdad	1
Diploma of Dar al-'Ulum, Cairo	2
Diploma of Higher Teachers College, Egypt	1
Licence in Science or Letters, Higher Teachers College, Baghdad	7
Total	40

Difficulty in obtaining professors of scientific subjects from Egypt in 1944 and 1945 resulted in chairs of physics, chemistry, botany, and mathematics becoming vacant. Part-time lecturers, of whom there were fifteen in November 1945, were carrying on part of the work in these subjects.

The College is administered by a dean who is appointed by royal decree from among the professors of education at the College. He is responsible directly to the Minister of Education. He is assisted by an assistant dean for administrative affairs and an assistant dean for student affairs, both chosen from the College faculty and appointed by the Minister of Education upon their nomination by the dean.

The College faculty, or council of professors, composed of all members of the staff except the assistant instructors, is the body which controls the general policies of the institution and sets its curriculums. Its decisions are subject to the approval of the Minister, but actually the institution enjoys a considerable amount of autonomy. Each department constitutes a committee of all who teach in it under the chairmanship of the professor. One departmental committee may embrace more than one subject of the curriculum. The six committees—educaton, Arabic, English, social studies, chemistry-biology, and physics-mathematics—meet at the request of their chairmen to consider proposed modifications in the curriculum, contents of the courses, textbooks, progress of students, distribution of teaching loads, and plans for future development. The council of professors approves and coordinates all recommendations for curricular changes and must endorse all final marks before these can be given to the students. The teaching load

varies from six periods a week as a minimum for professors to twelve periods as a maximum for instructors.

Student life and activities.—Most of the men students and about half the women are boarders, their accommodations being in dormitories, for private rooms do not exist. A student committee, elected each term, looks after the physical arrangements, setting down the weekly menu, superintending the reception of provisions from the contractor, and supervising kitchen and dining-room. It has the power to reject any food supply that it considers unfit, and the contractor is obliged to replace it.

There are various student societies and clubs that hold regular meetings and receptions. Some societies, such as the Arab Culture Society, the English Society, the Social Science Society, the Science Society, and the Art Society, follow subject lines. The Mirth and Entertainment Society occasionally holds parties at which skits and comic plays are presented, and there is a more serious dramatic group. The Cooperative Society, established with capital collected from selling shares to students, maintains a shop on the campus, chiefly for selling tea, coffee, and other refreshments. At the end of each year profits are distributed to the students. Recently a Students' Union was started to coordinate the activities of students and societies and to represent student interests before the College administration. Its members are elected from the student body and serve on a committee with two faculty members who are appointed by the dean. The Students' Union developed plans for issuing a College magazine, the first numbers of which have already appeared. It is hoped that the Students' Union will so develop as to increase the measure of self-government enjoyed by the students.

The athletics program is limited by the nature of the College grounds, which are not yet well prepared for sports. However, soccer is played to some extent, and among indoor games basketball and volleyball, ping-pong, and badminton are popular. Competitions between classes and between individuals are common, and there are occasional intercollegiate competitions. Track and field sports occupy some of the students part of the year, and an annual field-day competition among the higher colleges has been held for the last five years.

THE QUEEN 'ALIYAH INSTITUTE FOR WOMEN TEACHERS

The reorganization of the Primary Teachers College for Women as the Queen 'Aliyah Institute in October 1945, which opened a three-year course for training intermediate-school teachers, was an attempt to overcome the shortage of women teachers for intermediate schools at a time when it was

difficult to get women teachers from Syria, Lebanon, and Egypt and when the number of women students at the Higher Teachers College was inadequate to meet the demand. It was hoped that the shorter, three-year course would attract girls who could not afford the five-year course of the Higher Teachers College and that its segregated character would appeal to conservative parents who distrusted coeducation.

In October 1945, 35 graduates of secondary schools had been admitted into the literary section and 26 into the scientific section. An additional 10 were on the waiting list. In order to speed up the process of graduation, 27 other students, who had had a year beyond secondary school, were advanced to form a second-year literary section of 16 and a second-year scientific section of 11. Thus, the total number of students was 88. The first graduation was expected in June 1947.

Table 34 shows the program of studies at the Institute:

TABLE 34

PROGRAM OF STUDIES, QUEEN 'ALIYAH INSTITUTE FOR WOMEN TEACHERS, IRAQ, 1945–46

Subjects	Hours per Week					
	Literary Section			Scientific Section		
	1st Year	2nd Year	3rd Year	1st Year	2nd Year	3rd Year
Arabic	7	7	7	5	3	2
English	5	4	3	3	3	...
Education (general)	2	...	...	2	...	...
Child and adolescent psychology	2	...	...	2	...	...
General method	...	4	...	...	4	...
Educational psychology	...	2	...	...	2	...
Special methods	...	...	4	...	...	4
Philosophy of education	...	...	4	...	...	4
History	6	6	3	...	...	...
Geography	4	4	3	...	...	...
Social science and civics	...	...	2	...	...	...
Hygiene and physiology	...	...	1	...	...	2
Mathematics	...	...	...	7	6	6
Chemistry	...	...	...	5	5	5
Physics	...	...	...	4	4	4
Biology (zoology and botany)	...	...	...	4	4	3
Total	26	27	27	32	31	30

The Institute is staffed largely by men, four of whom are full-time instructors. There are twenty part-time lecturers, drawn chiefly from the Higher Teachers College. The Institute is housed on the premises of the old Primary Teachers College for Women, whose principal became the director of the Institute. It is expected that arrangements will be made in the future to permit graduates of the Institute to finish their studies at the Higher Teachers College.

THE PHYSICAL EDUCATION INSTITUTE

The Physical Education Institute offers a one-year course to men interested in teaching physical education in intermediate or secondary schools or in supervising playground or sports programs. In 1945–46 there were 20 students, 18 of whom were graduates of the rural-teachers college and 2 were secondary-school graduates who were preparing to teach in Jewish schools. All were boarding students.

In 1945–46 a director, one full-time teacher, and four part-time teachers conducted the program, which provided instruction in Olympic games, rules, gymnastics, principles of teaching, wrestling and boxing, English, Arabic, administration, hygiene and first aid, extracurricular games, scouting, and small games. The weekly schedule provides for forty periods of theory and practical work. Equipment and play areas were ample for the needs of the number enrolled. The Institute is located near the public stadium, which is large enough for three football games to be played simultaneously. A large and well-constructed swimming pool is available for instruction and recreation.

Chapter 12

HIGHER EDUCATION AND EDUCATIONAL MISSIONS

THERE IS AS YET no university in Iraq. At least two attempts were made in 1943 and 1945 to incorporate the present colleges into a university, but neither attempt went beyond producing a draft charter and a draft law for the proposed university. Higher education as it now stands, therefore, is provided in separate colleges directed towards education for the professions. These are the Higher Teachers College, the Royal College of Medicine (with which is included the College of Pharmacy), the Law College, and the College of Engineering. To these must be added the three-year course of the Queen 'Aliyah Institute. No liberal-arts college existed at the time of the visit of the American Council Commission. The Higher Teachers College comes nearest to a liberal-arts college of the American type, combining academic and professional education as American colleges often do. There are, however, at least two important differences. The College is exclusively for the education of teachers; and, instead of a fluid elective system where individual courses may be combined in almost infinite alternatives, selection is limited to five parallel programs, the courses in which are almost all required.

The Higher Teachers College and the Queen 'Aliyah Institute have already been dealt with in the discussion of teacher education in the preceding chapter. The present chapter will describe the other colleges and educational missions abroad.

The Royal College of Medicine and Associated Schools

The Royal College of Medicine has associated with it under the same dean, the College of Pharmacy, the School of Nursing, and the School of Health Officials.

The Royal College of Medicine, established in Baghdad on the grounds of the Royal Hospital in 1927, provides the only medical training available in Iraq. The course is six years in length including one year of internship. New students are selected on the basis of the public secondary-school

examination results, geographical distribution, age, minority representation, personal interviews, medical examination, and a special oral and written examination in English.

Tuition is free to students who sign a contract to serve for a period of four years after graduation in the Department of Public Health or for a period of fifteen years with the army. However, all students are required to pay a fee of 4 dinars ($16) per year and to buy their own textbooks. A limited number of students pay their own tuition fees, amounting to about $160 a year, but even they may be required to practice in villages for a period of six years. Because of the dearth of medical service in villages and rural areas, proposed legislation would require all graduates to serve outside the cities for a definite period after graduation.

In 1945–46 the student body totaled 312 men and women, with 93 (including 19 repeating) in the first year, 43 in the second, 39 in the third, 41 each in the fourth and fifth, and 55 in the sixth. Students make their own living arrangements as the College has no boarding provisions. Classes and laboratories are held daily except on Friday, though part or all of Thursday afternoon is often free.

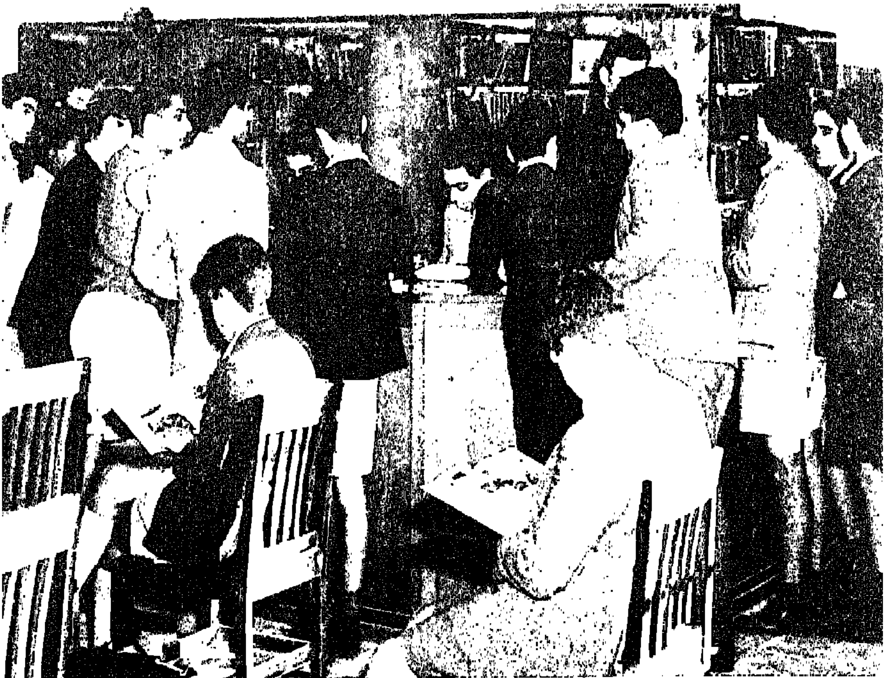
The first-year program consists of lectures and laboratory work in anatomy, chemistry, biology, and physics. Second-year students do theoretical and practical work in anatomy, physiology, and biochemistry and begin work in elementary clinics. The third year provides experience in the hospital wards and lectures and laboratory work in bacteriology, pathology, orthopedics, junior medicine, junior surgery, materia medica, and dispensing. The fourth year provides for continuation of work in wards, a study of sanitary administration, public health, obstetrics and gynecology, clinical therapeutics, skin diseases, senior medicine, senior surgery, and lectures and demonstrations in forensic medicine. Senior medicine and surgery are continued in the fifth year; approximately one-fourth of the student's time is spent in the wards, with children's diseases, mental diseases, ear, nose, and throat diseases, operative surgery, ophthalmology, radiology, anesthetics, and venereal diseases occupying the balance of his time. In the sixth year the student has lectures and practice in hematology and medical ethics, but most of his time is consumed by practical training with major emphasis on the medical and surgical services. The academic year of not less than thirty weeks is divided into three terms. Instruction is in English.

Administration of the College of Medicine is carried on, under the Ministry of Social Affairs, by the dean of the faculty, assisted by the board of studies and a council. The council includes the dean of the faculty of medicine as chairman, the director of the School of Pharmacy, and five





Above: A first grade in a village primary school, Za'faraniyah, Iraq
Below: The sixth grade in the same school. Note the small size of the class due to drop-outs





Above: The circulation desk of the library of Baghdad College at the end of the day, Baghdad, Iraq

Below: Snack-time at the kindergarten of the demonstration school of the Elementary Teachers College for Women, Baghdad, Iraq

professors of the medical college who are nominated by the board of studies and approved by the Minister of Social Affairs. Members of the faculty have received their medical training at universities and hospitals in England, Egypt, Turkey, Paris, and Beirut.

The College is housed in a modern building specially built for it with fairly extensive laboratories, dissection rooms, and lecture halls, large enough to accommodate 60 to 70 students in each of the six years. In addition, the College enjoys the extensive facilities of the teaching hospital on the grounds of which it is situated. This largest of Iraq's hospitals has 600 beds in large wards and semiprivate and private rooms, thus accommodating patients of all classes. As the hospital receives patients not only from the Baghdad area, but also from all parts of Iraq, students have a chance of seeing a very large and representative variety of cases and diseases. The hospital has a very large outpatient clinic occupying a two-story building and some annexes where more than 700,000 new cases are treated each year. Next to the College building is the large building housing the pathological and bacteriological institutes and the antirabic and vaccine-production institutes. On the same grounds is also the extensive X-ray building with facilities for both X-ray diagnosis and therapy, including fluoroscopy and radium therapy. All these facilities form part of the teaching facilities of the College.

THE COLLEGE OF PHARMACY

The College of Pharmacy, included for administrative purposes in the Royal College of Medicine, was established in 1936 and provides graduates of the secondary school with a four-year course leading to a Diploma of Pharmaceutical Chemist. In 1945–46 the enrollment was 98, with the four classes about equal in size. Upon graduation the student spends six months in practical work with a registered pharmacist and three months in a government dispensary. Students are admitted on the basis of a medical examination, public secondary-school examinations, personal interview, and geographical and minority distribution. Those who sign a contract to serve the Department of Health for four years after graduation are exempt from all fees except an instruction fee of 3 dinars ($12) yearly. Tuition fees for others are 33 dinars ($132) per year.

The College is administered by the dean assisted by a college board composed of permanent professors and lecturers. Members of the teaching staff are nominated by the dean, subject to the approval of the college board and confirmation by the Director General of Health.

The curriculum includes botany, general chemistry, business methods

and bookkeeping, physics, and zoology in the first year; analytical chemistry, pharmacy, pharmacognosy and pharmaceutical botany, inorganic materia medica, and organic chemistry in the second; organic pharmaceutical chemistry, biochemistry, pharmacy, organic materia medica, and pharmaceutical physiology in the third; and microscopic pharmacognosy, toxicology, inorganic pharmaceutical chemistry, pharmacy, bacteriology and parasitology, and hygiene and first aid in the fourth. There are fourteen hours of lectures and sixteen of laboratory per week in the first year, twelve of lectures and sixteen of laboratory in the second and third years, and ten of lectures and twenty-four of laboratory in the fourth. A student must not fall below the mark of 50 percent in any subject in the yearly final examinations or below 65 as an average. First-year students are allowed to repeat in the event of failure, but a second failure results in dismissal from the College. The nine-month practice period ends in oral and practical examinations which the student must pass, and he must also receive a favorable report from the supervisory pharmacist before he is granted his diploma and may work independently as a pharmacist.

The school of nursing

The School of Nursing is under the general administration of the dean of the College of Medicine, but has a principal as the immediate head. Instruction is in Arabic and English and is given by doctors associated with the College of Medicine or the Royal Hospital. It is a three-year course, and admission is limited to those who have an Intermediate-School Certificate or its equivalent. Applicants must be between eighteen and twenty-three years of age and are selected on the basis of their school records, public-examination results, and medical examinations. Students must sign a contract to work in a government hospital for four years upon graduation, but while they attend school all their expenses are paid and they receive an allowance of 1.5 dinars ($6.00) per month during the first year, 2 dinars ($8.00) during the second, and 2.5 dinars ($10) the third. A vacation of one month is granted during the period of July through September when no classes are held. Students are on duty in the Royal Hospital from seven to ten each morning and for two hours in the afternoon. Formal lectures are given daily from ten to twelve. A graduate may be released from the obligation to serve in a government hospital by paying 200 dinars ($800) to the government. In 1945–46 there were 33 girls enrolled in each the first and the third year classes and 20 in the second.

Subjects of instruction for the first year are anatomy and physiology, elementary science (including hygiene, sanitation, and bacteriology), food

values and invalid cooking, theoretical and practical nursing and first aid; for the second and third years, anatomy, physiology, elementary science, gynecology, surgery and medicine, and theoretical and practical nursing. Specialization in midwifery requires an additional year of study.

The School of Health Officials

The School of Health Officials was established to relieve the pressing need for medical service. Graduates of intermediate schools are enrolled in a two-year course, at the end of which they are given nine months of practical experience in a government dispensary or clinic. Thus trained, health officials may be assigned to assist medical officers or be sent to outlying villages to work under the supervision of a district medical officer. They are considered to be qualified in first aid, minor surgery, and diagnosis and treatment of common diseases. On independent duty they are placed in charge of government dispensaries where treatment is free. They are responsible for the collection and reporting of data on diseases and health conditions.

No tuition fees are charged, since the student agrees to work for four years in the government health service, but in the absence of boarding facilities the student must pay for all living expenses. His salary in his first appointment is eight dinars ($32) a month, but it has been recommended that this be increased to 10 dinars ($40) after one year of practice. In 1945–46 there were 28 students in the first-year class and 26 in the second. The second-year class of that year was the first for which completion of the nine-month practice training was required.

The first-year students study inorganic and organic chemistry, materia medica, public health, bacteriology, anatomy, internal diseases (general), surgery (general), nursing, and English. In the first half of the second year they study dispensing, medical accounting, public health, skin and venereal diseases, materia medica, dentistry, endemic diseases, the ear, nose, and throat, ophthalmology, internal diseases (special), surgery (special), English, and health laws. The second half of the year is spent in practical study in the various clinics of the hospital. Having fulfilled all requirements mentioned, the student receives the Certificate of Health Official. It has been recommended that this certificate should be rated with that of the secondary school for purposes of admission to the School of Pharmacy and the College of Medicine. It is assumed that the School of Health Officials will be discontinued when Iraq has sufficient fully qualified doctors to answer all needs. However, at the present time doctors avoid village practice because of the unsatisfactory living conditions

and the inability of the villagers to pay even nominal fees for private treatment.

The Law College

The Law College, located in Baghdad, serves the entire country. Its four-year course is open to men and women who hold the secondary-school certificate. The enrollment by class was in 1945–46: first year, 394; second year, 313; third year, 258; fourth year, 119. At that time the teaching staff consisted of twelve full-time members and eight part-time. Lack of classroom space necessitated parallel sessions in morning and afternoon. Fees of 15 dinars ($60) are charged all students except those who are certified to be poor or who maintain an average of 80 or higher in their marks. The high mark keeps the exemptions made on that basis at a minimum.

The first-year student takes three-hour courses in principles of law and history of Roman law, two-hour courses in constitutional law, criminal law, economics, and civil and religious law, and six hours of English a week. In the second year he takes four hours each of civil and religious law and of English, three each of economics and public international law, and two each of theory of obligations, administrative law, and criminal law. In the third year the number of weekly lectures is reduced to seventeen with six hours for Muhammadan civil law, three for public finance, and two each to theory of obligations, civil court procedure, commercial law, and criminal court procedure. In the fourth year two specializations are available, one to prepare lawyers and judges, the other to prepare local government administrators. The two groups have in common courses in Muhammadan law, land law, procedure of judgments, private international law, commercial law, Muhammadan jurisprudence, and application of criminal and civil law, totaling sixteen hours a week. The prospective judges take, in addition, two hours weekly in criminal investigation, two in legal medicine, and one in criminal psychology; the future administrators take one hour of administrative law, two of financial law, one in diplomacy, political science, and history of politics, and one in statistics.

The library, though well supplied with books in English, French, and Arabic, has yet to be organized for effective use, and it has been reported that few of the students are sufficiently well grounded in English and French to utilize the sources in these languages. The addition of a preparatory year to the course with instruction in English to overcome this deficiency has been suggested.

Students are selected on the basis of their standing in the public sec-

ondary-school examination, marks in English, geographical distribution, personal interview, and an entrance examination in English. Because of the large number of applicants from the city of Baghdad, it is sometimes necessary to limit admission to secondary-school graduates of the preceding year. The staff and the physical facilities, as well as the curriculum, are admittedly inadequate to meet the needs of the students now in attendance. It is anticipated that the establishment of a college of arts and sciences will relieve the pressure for admission to the Law College.

The College of Engineering

At the time of the American Council Commission's visit in the fall of 1945, the College of Engineering was in its second year of operation under a reorganized plan which had added a preparatory year to the old four-year course. There were 159 students, of whom 106 were boarders. Distribution by class was as follows: preparatory, 70; first-year college, 31; second-year, 6 (failures under the old plan); third-year, 33; fourth-year, 19. Only students who achieved an average grade of 70 or higher in mathematics and physics in the public secondary-school examinations may apply for admission. Final selection is made on the basis of medical examination, personal interview, proficiency in English, and geographical distribution.

The College is administered by a director under the general supervision of the Minister of Communications and Public Works. However, it is recognized that a governing body which includes professional engineers and also employers of engineers is desirable. Such a body would be more competent to evaluate a recent proposal to coordinate all technical education under a plan which would presumably improve trade training and at the same time open an opportunity for the more promising student to reach the College of Engineering and specialize in civil, mechanical, or electrical engineering. At present the College trains only civil engineers.

The curriculum provides for instruction in mathematics, English, physics, chemistry, descriptive geometry, machine drawing, and workshop in the preparatory year. Instruction throughout the College is mostly in English because most texts and references are in that language. The first-year program consists of mathematics, English, physics, descriptive geometry, machine drawing, mechanics, geology, surveying and workshop; the second year, mathematics, machine drawing, graphics, strength of materials, theory of structures, hydraulics, heat engines, theory of machines, electrical engineering, and surveying; the third, strength of materials, theory of structures, hydraulics, surveying, building construction, soil mechanics,

irrigation, railways, roads, and economics; the fourth, strength of materials, theory of structures, hydraulics, surveying, municipal engineering (water supply and sewage disposal), estimating (specifications and contracts), engineering law, and design (structures, irrigation works, and buildings). Lectures and practical work total from twenty-eight to thirty-two hours per week. This curriculum will be expanded when specialization in mechanical and electrical engineering is added.

No tuition or boarding fees are charged, but students sign a contract to work for a period of five years after graduation in the Department of Public Works. During this period of employment they are paid on the same scale as other government officials with similar preparation and experience.

Educational Missions

It was in 1921, just after the foundation of the national government and the accession of King Faysal I to the throne of Iraq, that the Ministry of Education proposed sending qualified students abroad to study. That year nine of the brighter boys were picked from the secondary schools, six of whom were sent to the American University of Beirut in Lebanon and three to England. Of these, two were to study medicine in England, one was later to study agriculture in the United States, and six were to prepare for high-school teaching. From the first, the idea of educational missions was to train specialists to meet Iraq's needs in the fields of health, education, and agriculture.

Needs multiplied until foreign educational missions were projected in no less than forty-six of the most diverse subjects. These included various sciences and subjects necessary to teaching, such as physics, chemistry, biology, mathematics, history, geography, Arabic, and English. Students were sent to study education, psychology, and kindergarten methods, chiefly in America. Agriculture was studied almost entirely in America. Students went abroad to study all types of engineering, surveying, architecture, the social sciences, modern business practice, astronomy, geology, meteorology, and law. The establishment of the Royal College of Medicine at Baghdad in 1927 almost stopped the movement of medical students to foreign universities, except for graduate study, but they continued to go abroad to study dentistry and veterinary science. They went on missions to study technical trades, archeology, Islamic art, physical education, printing, library science, and home economics. For the study of painting, sculpture, and music they were sent principally to France and Italy.

As the fields to be studied on mission became more numerous, so did the

number of students sent. The number of students supported wholly or almost wholly by the government rose from 9 in 1921 to 93 in 1928–29 and reached the peak figure of 238 in 1939–40. It declined because of World War II to 114 in 1943–44, but began to increase in 1945. Altogether more than 700 students have been sent abroad for study in the last quarter-century. The number of students who studied abroad at their own expense is at least as large.

Missions have been sent to eleven different countries, Lebanon receiving the most because of the popularity of the American University of Beirut. This University has not only prepared a large number of teachers for the Iraqi secondary schools; it has also served as a station for students going to America, to improve their English and prepare them for advanced study in the United States. After Lebanon, England receives the most, then Egypt, and in order, the United States, Switzerland, France, Germany, Sweden, Turkey, Italy, and India. World War II limited the missions for the most part to Lebanon and Egypt.

The first mission students returned to Iraq in 1926 and were absorbed by the secondary schools and the Primary Teachers College. Since then hundreds of students have returned. Most of them and most of the students who studied abroad at their own expense have gone into government posts where they are helping to fill a great need. At least 4 have attained cabinet rank, while many have become directors general of various departments and members of Parliament. The largest number have gone into teaching or administrative posts in the Ministry of Education. The next largest group are in technical posts in engineering or agriculture. Others are scattered throughout the ministries, having begun their careers as teachers and transferred from the Ministry of Education.

The budget for educational missions began in a modest way in 1921 and reached its highest peak of 62,000 dinars ($248,000) in 1938–39. It declined to 45,000 dinars ($180,000) in the war years, but is now expected to be increased. For a full-scholarship student the government pays nearly all his necessary expenses, including tuition fees, travel expenses to and from his place of study, an adequate monthly allowance for living expenses—varying from country to country—and an allowance for books and medical care. Any major medical treatment or surgery is also paid for by the government. A former government official sent on a mission receives, in addition to these benefits, one-third of his former salary to help support his family. In return for all this, the student signs a contract which commits him to serve the government one year for each year of study. In case of default or of failure to complete his studies, he must

reimburse the government for all expenditure in his behalf. This system allows many a bright but impoverished student to achieve a kind of education and career that unaided he could never have had.

Regulations govern the selection of students and other aspects of this program. The latest revision of the regulations was in 1942, and, according to these, a student to be eligible must be at least a secondary-school graduate with an average of no less than 66 in the public examination and of no less than 75 percent in the subject of his specialization; he must pass a medical examination and be interviewed by the selection committee, which looks into his credentials and into a confidential report from his former school principal. To qualify for postgraduate study abroad, a student must have attained first- or second-class honors in his undergraduate course.

The Council of Ministers determines the number of students to be sent every year and the fields to be studied, basing the decisions on statements of the various ministries and departments concerning their needs. With the growth of the various colleges in Iraq, more emphasis is being placed upon postgraduate study to prepare advanced specialists. In undergraduate work there is a good deal of concentration on the various branches of engineering and technology.

Chapter 13

PRIVATE AND FOREIGN SCHOOLS

Two TYPES of schools function outside the government system: private schools, which are owned and operated by Iraqi citizens, either individual or in association; and foreign schools, which are owned and operated by foreign individuals or groups. Since Iraqi parents are forbidden by law to send their children to foreign primary schools, there are no foreign schools below the intermediate level in Iraq, with the exception of 5 primary schools for Iranian boys. Table 35 presents enrollment figures for all types of primary and seconday schools in Iraq as of 1945–46.

Both private and foreign schools are obliged to conform to governmental regulations and to have governmental approval of housing, qualifications of teachers, curriculums, and textbooks. They must follow the government's courses of study for Arabic language and social studies, and teachers of these subjects are appointed by the Ministry of Education. Admission to the first and fourth years of secondary schools is conditional upon having passed the public primary- and intermediate-school examinations.

Curriculums for both private and foreign schools follow those of the government schools so that pupils will not be handicapped in the public examinations. Since all foreign secondary schools are American, English is emphasized, and in the last two years of the course some subjects are taught in that language. The private schools for Jews teach Hebrew language and literature in the primary sections and English and French language and literature in the secondary schools. The better students in the Jewish schools are prepared to take the examinations for French certificates, as are pupils in the schools which were founded as French missionary schools.

Private schools fall into three categories: private ventures, schools maintained by associations interested in raising the standard of national culture, and sectarian schools. The private ventures are conducted for profit and appeal especially to pupils who do not find places in the government schools. Associations that maintain schools are usually composed of citizens

TABLE 35

ENROLLMENT IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS IN IRAQ, CLASSIFIED ACCORDING TO CONTROL, 1945–46

Types of Schools	No. of Schools			Enrollment	
	Boys	Girls	Coeducational	Boys	Girls
Primary:					
Private	36	25	17	12,776*	7,977*
Foreign	5	...	...	917	...
Government					
Day	681	155	56	84,229†	27,458†
Evening	21	...	...	4,285	...
Total	743	180	73	102,207	35,435
Secondary:					
Private					
Intermediate only					
Day	8	6	...	885	584
Evening	4	...	...	356	...
Preparatory only					
Day	1	...	...	209	...
Evening	1	...	...	157	...
Complete					
Day	5	1	...	1,507	136
Evening	13	...	...	2,983	...
Total	32	7	...	6,097	720
Foreign:					
Intermediate only	2	...	...	114	...
Complete	2	1	...	582	127
Total	4	1	...	696	127
Government:					
Intermediate only	18	17	...	3,673	1,938
Preparatory only	3	2	...	1,114	380
Complete	15	3	...	4,697	608
Total	36	22	...	9,484	2,926
GRAND TOTAL	815	210	73	118,484	39,208

* Of these, 2,579 boys and 2,326 girls were in coeducational schools.
† Of these, 4,199 boys and 4,368 girls were in coeducational schools.

who are desirous of enlarging upon the educational provisions made by the government. Associations of this sort sprang up in the early twenties and continue to look after the cultural welfare of their members through the establishment of libraries, public lectures, discussion groups, and publications, in addition to schools. Such an association is the Tafayyud Society in Baghdad, which maintains kindergartens, primary schools, and a day and an evening secondary school in that city and has recently established intermediate schools in six towns in central Iraq. The Teachers Association in 1945 started evening secondary schools for boys in Baghdad,

Mosul, and Basrah and a day secondary school for girls in Baghdad.

The Jewish communities in Baghdad, Mosul, and Basrah are typical of associations primarily interested in the education and welfare of their own religious group. Both free and tuition schools of kindergarten, primary, and secondary level are administered by the community councils, and it is thought that nearly all Jewish children have a chance to become at least literate. In addition to full day and evening schools, which bear resemblance to government schools of equal level, these communities have workshops for poorer children. These provide training in sewing and crafts, and elementary work in reading, mathematics, and religious literature. In the early twenties these communities took over the administration of the Alliance Israelite Universelle schools, which now supply teachers for the communities. Teachers of such schools are paid by the local community. Other religious groups, such as the Assyrians, Syrian Orthodox, Syrian Catholics, Roman Catholics, Chaldeans, and Armenians, also maintain schools.

Iraq's only foreign primary schools are the 5 which provide instruction for Iranian boys from families of merchants and craftsmen who have long been residents of Iraq. These schools are located in Baghdad, Basrah, Karbala, and Najaf. There is also an intermediate Iranian school in Basrah.

All other foreign schools are controlled and financed by American agencies. Basrah has an intermediate school of this type, and Baghdad has 3 complete secondary schools, 2 for boys and 1 for girls.

The oldest of these schools is the American School for Boys in Basrah, founded by the Dutch Reform Mission early in this century. Its principal, Dr. John Van Ess, author of *Meet the Arab*,[1] has long been associated with education in Iraq, having served as its first Director of Education during the British occupation in 1915. This School provides education through the third year of the secondary course for poorer boys from Basrah and the surrounding villages. It stresses both high academic standards and the development of high moral character, and its graduates are in demand in business enterprises of the vicinity. The School opens its extensive play areas to poor boys who live near the school and provides one of its buildings for use as a recreation center by former students and their friends. Elementary instruction in the first four grades is provided for girls; both the girls school and the primary section of the school for boys are classified as private schools and have Iraqi citizens as their principals. More advanced instruction is offered girls on an informal basis through the Young Woman's Club.

[1] New York: John Day Co., 1943.

The American School for Boys in Baghdad was founded by the Dutch Reform Mission, but is at present under an independent board of trustees of which Lowell Thomas is president. Dr. and Mrs. Calvin K. Staudt, associated with the School since its founding a quarter of a century ago, have not only made it possible for boys to qualify for the Secondary-School Certificate examination, but have also done much to develop good character and good will among the diverse groups that attend the School. High standards are maintaned in the Arabic language, but special attention is given to strengthening oral and written English. Certain subjects, such as science, mathematics, and general history are taught in the last two years through the medium of English so that graduates will be better equipped to continue their education at the American University of Beirut or in Western universities. Pupils of the School are not under obligation to take the public Secondary-School Certificate examination in order to graduate. The School has a variety of student activities and organizations, which include Arabic and English dramatic societies, an international relations club, a chorus, assemblies, a brotherhood, sports field days and intramural athletic contests, oratorical contests, and Sunday evening religious services. Recently (1945) it became a member of the Near East Colleges Association, and is being developed into a college. A boys primary school is maintained under an Iraqi principal.

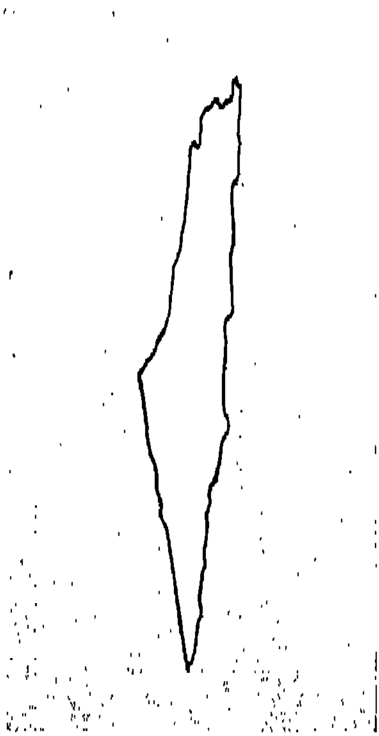
The American School for Girls was founded in Baghdad in 1925 by the United Mission of Mesopotamia. A six-year primary school, under an Iraqi principal, is followed by a five-year secondary school under the supervision of an American principal. The program of the School parallels the government program, and pupils regularly take the appropriate public examinations. Here, too, the use of the English language is stressed, and graduates are fitted for higher education in English and American institutions.

The most recently established American school in Iraq is the Baghdad College for Boys, founded by American Jesuits in 1932 and now under the supervision of Rev. Francis B. Sargeant, S.J. The aim of the school is to provide a good secondary education under Catholic auspices. Located at the northern edge of Baghdad, this school is housed in the most modern school buildings in all Iraq and has extensive play areas that are ample for athletic activities. It has boarding facilities, and in 1945–46 70 of the 418 boys enrolled were boarders. The fact that fees are comparatively high determines that most of the students will be of the upper middle class. The majority are from Christian families, but other religions are represented. The program follows the public-school program rather closely,

and the boys take the public certificate examinations. Instruction in mathematics and science and some other subjects is in English, but care is taken to cover the appropriate vocabularies in Arabic. An extensively equipped laboratory makes individual experiment possible in physics, chemistry, and biology. A large library circulates many books for collateral reading. Informal organizations include religious groups, the International Relations Club, various sports associations, a debating society, and a staff which publishes a school paper.

Another foreign agency which is making an important contribution to education in Iraq is the British Council. Institutes have been established in Baghdad, Basrah, Mosul, and Kirkuk in which young men and young women are given an opportunity to prepare for proficiency examinations in English as well as for the London matriculation and intermediate examinations. Classes are held in the mornings for women and in the late afternoons and evenings for men. Fees are nominal and the classes are popular. A model kindergarten has also been established in Baghdad which is attended largely by children of English-speaking parents. Clubs which have both social and educational aims have been established in the larger cities. Lecture series, musical evenings, and discussion programs are regularly scheduled for these clubs. Educational films are distributed to schools and organizations in Baghdad. Although not a responsibility of the British Council, the reading rooms established in the smaller towns and larger villages by the Public Relations Department of the British Embassy are much used. Current magazines in English and Arabic are regularly supplied to these reading rooms and a small library of selected titles is available. A radio is usually supplied also.

Part Three



PALESTINE

PALESTINE

Population: *1,887,214 (December 31, 1946).*

Area: *10,434 square miles.*

Form of government: *(At the time of the visit of the American Council Commission in 1946) Under mandate of Great Britain, governed by a High Commissioner appointed by the King of England.*

Principal occupations: *Agriculture, industry, commerce, finance, professions.*

Principal exports: *Citrus fruits, soap and edible oils, potash, bromine, knitted goods and apparel, artificial teeth, polished diamonds, kerosene, benzine, hides and skins, chocolate.*

Principal imports: *Industrial machinery, iron bars and rods, apparel, cotton goods, wool yarn, wood, fuel oil, seeds, animal feed, food products, cattle, sheep, goats.*

Monetary unit: *Palestinian pound* (£P) *equivalent to approximately $4.03.*

Chapter 14

ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF THE GOVERNMENT (ARAB) EDUCATIONAL SYSTEM

THERE ARE TWO public educational systems in Palestine, one for Arabs and one for Jews.[1] The Arab system is administered by the Government Department of Education, the Jewish by the Educational Committee of the Vaad Leumi (General Council of the Jewish Community in Palestine). In addition, there are numerous private schools for Arabs and for Jews.

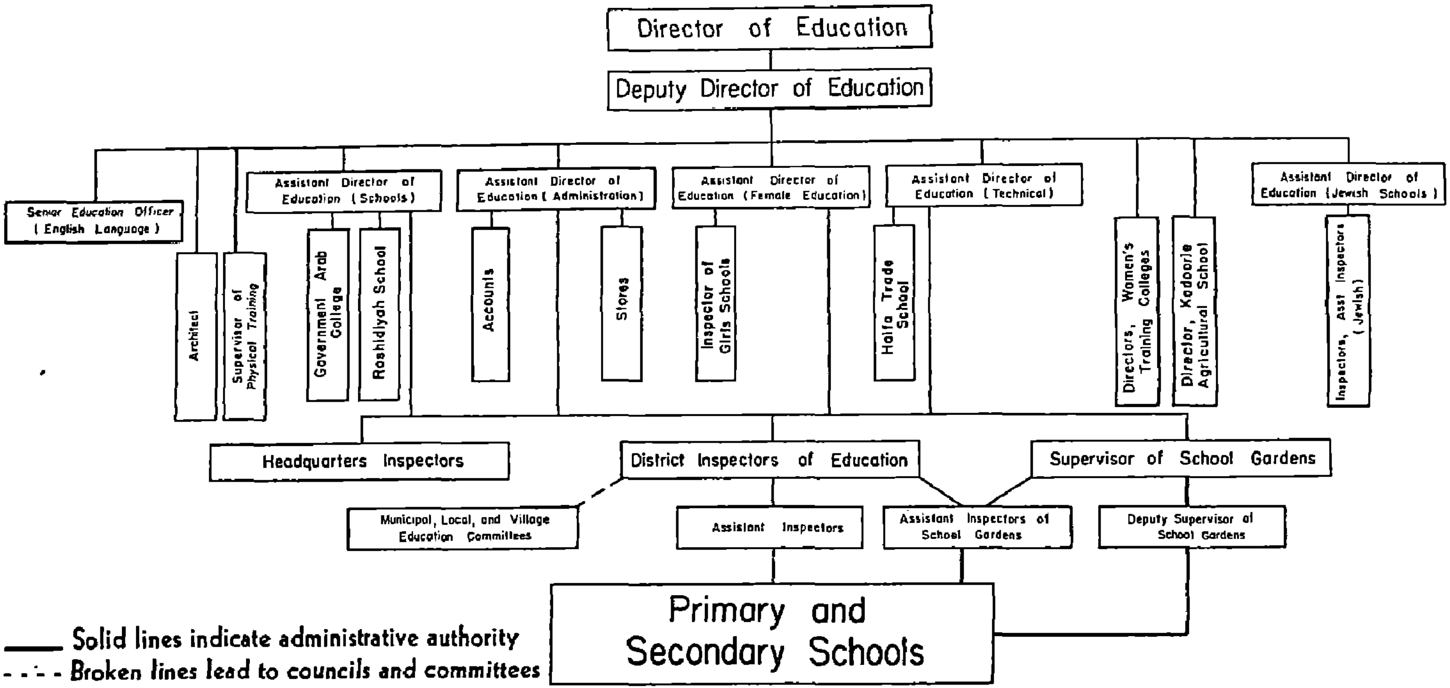
The two public systems have only slight contact with each other. The Government Department of Education has a legal right of registration of schools and of supervision over all schools that receive government assistance, including the Jewish public schools. It grants to the Jewish system an annual subsidy, most of which is given in a lump sum to the Vaad Leumi. The Government Department of Education includes on its staff a Jewish Assistant Director with Jewish inspectors who inspect Jewish schools and deal with matters pertaining to Jewish education; also the Department conducts public examinations which are open to students of Jewish as well as Arab schools, both public and private. In all other respects the two systems are separate, each following its own aims, plans, and methods. Therefore, they will be dealt with as separate systems in this report.

The organization of the Government Department of Education is shown in Chart V. At the head is a British Director of Education responsible to the Chief Secretary of the Palestine government. Powers pertaining to educational matters are strongly concentrated in the office of the Director, and the system is thoroughly centralized. Most of the funds for the Government system are derived from government revenues. Major lines of educational policy, appointment, promotion, and dismissal of teachers, sanctioning of new public schools, approval of textbooks, and the preparation and marking of secondary-school examinations are all decided

[1] The reader is reminded that this volume reports a survey made in 1946.

Chart V

PALESTINE: ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF THE GOVERNMENT (ARAB) DEPARTMENT OF EDUCATION, 1946



within the central office of the Government Department. Thus, the government system of public education (for Arabs) in Palestine is similar in its centralization to the public education systems of other Arabic-speaking countries. The Director of Education is assisted by a British Deputy Director and five assistant directors.

The Assistant Director of Education for Schools deals with professional and pedagogical questions and is responsible for the curriculum and textbooks; he is also director of the Government Arab College—the institution for training Arab men teachers—and has jurisdiction over the Rashidiyah School in Jerusalem, which is one of the two complete government secondary schools for boys (the other being the Amiriyah School in Jaffa[2]).

The Assistant Director of Education for Administration is responsible for the appointment, promotion, and dismissal of teachers, and for budgetary matters. He also has charge of accounts and stores, and must see that schools are adequately supplied with equipment and textbooks.

At the time of the visit of the American Council Commission in 1946, a British woman had been appointed Assistant Director of Education for Female Education, but had not taken up her duties. She was to be assisted by a woman inspector of girls schools.

The Assistant Director of Education for Technical Education, a British officer, serves also as director of the Haifa Technical School, the only government trade school in the country, and has charge of all prevocational education in elementary schools.

The Assistant Director of Education for Jewish Schools is assisted by seven Jewish inspectors who visit Jewish schools and report their findings. Neither the inspectors nor their superior may take any executive action with regard to Jewish schools—executive power resides with the educational authorities of the Vaad Leumi. The Jewish officials within the Department of Education have no concern with matters of Arab education, and no Arab officials interfere with matters of Jewish education.

There are three officials in addition to the assistant directors who report directly to the Director or Deputy Director of Education. These are the supervisor of physical training, the architect—for whom budgetary provision had been approved, though the office had not yet been filled in March 1946—and the senior education officer, who deals with all matters relating to the teaching of English—curriculum, textbooks, and methods.

The Director and Deputy Director of Education have additional respon-

[2] The Government Arab College maintains two upper classes of the secondary school, thus making three schools for Arabs with upper secondary classes.

sibilities in connection with three specific schools: the Teachers Training College for Women in Jerusalem, the Rural Training Center for Women at Ramallah, a few miles north of Jerusalem, and the Kadoorie Agricultural School at Tulkarm,[3] which is the only agricultural school for Arab students in the country and which also prepares teachers of agriculture for the rural schools of Arab Palestine.[4]

Next to the assistant directors and immediately attached to them according to field of specialization are the district inspectors of education, the supervisor of school gardens, and the headquarters inspectors.

Administration

District inspectors of education are actually administrators of provincial education. The six administrative districts of Palestine are grouped for educational purposes into four areas, each of which is administered by a district inspector. These educational districts are: the Jerusalem area, comprising the administrative district of Jerusalem, with headquarters at Jerusalem; the southern area, comprising the Southern and Lydda districts, with headquarters at Jaffa; the Samaria area, comprising the district of the same name, with headquarters in Nablus; and the Galilee area, comprising the districts of Haifa and Galilee, with headquarters in Haifa. Each district inspector has two assistant inspectors and an assistant inspector of school gardens. All four visit schools and classes and supervise instruction. All Arab public schools in Palestine (except those previously mentioned which are attached to a higher authority) come under the jurisdiction of the district inspectors of education. Certain matters beyond the jurisdiction of the district inspectors are referred to the central office; such matters include questions of appointment and promotion of teachers, opening of new schools or classes, admission of free pupils, most expenditures and supplies, and curriculum and textbooks. The district inspectors also act as liaison officers with municipal, local, and village councils with respect to educational affairs. The district inspector is usually an official member of the educational committees of these councils, but may delegate another person to attend meetings in his stead.

The supervisor of school gardens and his deputy have charge of the 238 school gardens which in January 1946 existed in the Arab rural schools. The supervisors lay down plans for expanding these gardens and

[3] There is also a Kadoorie Agricultural School for Jewish students at Mount Tabor (see p. 288).

[4] The teacher-training course was subsequently discontinued.

devise curriculums and approve textbooks for agricultural instruction in elementary and secondary rural schools. They keep in constant touch with the field, either personally or through assistant inspectors of school gardens.

Six headquarters inspectors, each specializing in one or more subjects, inspect the schools both administratively and professionally, recommending modifications in curriculum or textbooks in their respective fields. Each has certain administrative duties in the central office. Questions coming from district inspectors are referred first to the appropriate headquarters inspector, who may in certain instances take direct action and in others must refer the matter to higher authority.

Municipal and other local councils have been taking an increasing interest in education, and most of them now have educational committees formed in accordance with the provision of the Education Ordinance of 1933. Local authorities concentrate most of their efforts on the provision and maintenance of school buildings, but in numerous instances such councils have appointed teachers to schools in their localities at local expense, and a few municipalities have even established schools of their own. The municipality of Jaffa, the largest Arab city of Palestine, has its own school inspector. Ordinarily local authorities do not interfere in the professional aspects of their schools, as all Arab public schools follow the directives of the Department of Education.

Educational Finance

The Government Department of Education makes the major financial provision for the public-school system for Arabs and contributes to the support of the Jewish public-school system and to certain private schools. The budget allotment for education in the fiscal year 1945–46 was £P762,208[5] ($3,048,832), or 3.7 percent of the general budget of £P20,572,552 ($82,290,208). Table 36 shows the constant growth of the educational budget over a period of twenty-six years; it shows also that this has not kept pace with the growth of the total budget of Palestine. The government authorities do not deny that the lack of budgetary provision for education is perhaps the greatest obstacle to development of the Arab public-school system. Yearly about 8,000 applicants are refused admission to the elementary schools because of lack of places. In the upper elementary

[5] The rate of exchange of Palestinian pounds (£P) during World War II was established at $4.06. Since it varies slightly from time to time, $4 will be used in reducing Palestinian figures to approximate American dollars.

grades a rigid selection of pupils is practiced to save places for the younger pupils.[6]

The distribution of the educational budget between Arab and Jewish schools is roughly on the basis of three to one, which is approximately the ratio between the number of children of school age, five to fifteen years,

TABLE 36

RELATION OF EDUCATIONAL BUDGET TO TOTAL BUDGET, PALESTINE, 1920–21 TO 1945–46

Year	Total Budget: Palestinian Currency	Total Budget: American Dollars	Educational Budget: Palestinian Currency	Educational Budget: American Dollars	Percentage
1920–21.....	...	...	£E 78,000*	$ 312,000	...
1925–26.....	£E 2,040,332*	$ 8,161,328	£P 101,392*	405,568	4.96
1931........	£P 2,374,866	9,499,464	146,988	587,952	6.19
1935–36.....	4,236,202	16,944,808	221,087	884,348	5.22
1940–41.....	7,450,355	29,801,420	302,079	1,208,316	4.05
1941–42.....	7,463,602	29,854,408	385,204†	1,540,816	5.16
1942–43.....	10,253,283	41,013,132	458,322†	1,833,288	4.47
1943–44.....	14,819,250	59,277,000	652,157†	2,608,628	4.40
1944–45.....	18,196,594	72,786,376	711,916†	2,847,664	3.91
1945–46.....	20,572,522	82,290,088	1,037,208†	4,148,832‡	5.04

* £E means Egyptian pound. The Palestinian pound was not established until later.

† These figures include compensatory allowances for the wartime rise in the cost of living. In 1945–46 the compensatory [illegible] percent of the compensatory allowance of the total government budget, w[illegible] roximately $10,400,000). The actual educational budget for 1945–46 w[illegible]

‡ Estimated.

in the two communities. The division of the budget between the two school systems for 1944–45 is given below; figures include expenditures by the Departments of Public Works and Agriculture on schools.

Allocated to	Budget	
Administration and inspectorate (Arab and Jewish)	£P 44,229	($ 176,916)
Arab schools (including grants to private schools)	537,751	(2,151,004)
Jewish schools (including grants to private schools ..	157,935	(631,740)
Miscellaneous	2,487	(9,948)
Total	£P742,402	($2,969,608)

The Department of Education is not the sole support of even the Arab public-school system. Budgetary limitations on funds for village school buildings and for hiring new teachers have forced Arab villagers who

[6] Jerome Farrell, *Education in Palestine, General Survey 1936–45* (Jerusalem: 1945), pp. 3–4; Jibrail Katul, *Education in Palestine*, p. 11; Government of Palestine, *A Survey of Palestine*, prepared in December 1945 and January 1946 for the information of the Anglo-American Committee of Inquiry (Jerusalem: Government Printer, 1946), p. 641.

wanted new schools to raise funds for buildings and equipment and—in the event that the government did not provide sufficient teachers—the pay of teachers as well. From April 1941 to the end of August 1945 Arab villages raised £P325,120 ($1,300,480) for the expansion of their educational facilities. Of this sum, £P121,395 ($485,580) was spent on school buildings; during this period, the central government spent only £P23,720 ($94,880) on village school buildings. The government makes no provision for furniture for village schools, but contributes books and part of the teaching materials. Some of the larger municipalities levy local rates as authorized by the Education Ordinance and have built some of their schools and appointed their own teachers. In January 1946 there were 346 public-school teachers, among a total of 2,156, on the payrolls of village and town local authorities. In addition, some of the local authorities maintain, fully or in part, hostels for elementary- and secondary-school students.

Teachers salaries and promotions

A single salary scale prevails for all teachers and personnel of the nonclerical technical staff of the Department of Education, both men and women. Personnel with equal academic and professional qualifications receive equal pay.

Lowest on the scale are "supernumerary teachers." These teachers are uncertificated—they lack even the Secondary-School Certificate. They receive an initial salary of £P60 ($240) per annum, with an annual increment of £P6 until their annual salary is £P96 ($384). Such teachers cannot progress further unless they acquire higher qualifications.

The next category, grade four, is for teachers who have no university degree but who have at least a Secondary-School Certificate. The salary range is £P96–£P192 ($384–$768) with an annual increment of £P8. For teachers of Arabic, the initial salary varies from £P96 ($384) for those having only a Secondary-School Certificate to £P152 ($608) for graduates of Dar al-ʿUlum in Cairo. At certain points teachers are barred from further promotion unless they pass prescribed examinations or take up further study in approved institutions in Palestine or abroad. Teachers holding only a Secondary-School Certificate or a Palestine or London Matriculation Certificate, or their equivalent, reach the limit of £P104 ($416) annual salary. To progress beyond this point, they must pass the Teachers Lower Certificate examination, Part I, an examination in educational theory and practice. Graduates of the lower teacher-training institutions, which give professional training but are considered below the Secondary-School Certificate standard in subject training, stop at £P144 ($576) until they

take the Teachers Lower Certificate examination, Part II, a subject-matter examination, or make up any deficiencies they may have in certain subjects. Manual-arts teachers who are graduates of the Haifa Technical School or a similar school are also stopped at £P144 until they pass the Teachers Lower Certificate examination, Part I. Having passed these examinations, all these types of teachers may proceed unhindered to a maximum annual salary of £P192 ($768).

Between grade four and grade three—the latter, holders of the first university degree—is another type of teacher whose qualifications are higher than the Secondary-School Certificate but lower than the first university degree. This class includes graduates of the Government Arab College and the Teachers Training College for Women, both of which give professional and subject-matter training, the former two years and the latter one year above secondary school. Such teachers start at £P136 and £P120 ($544 and $480) respectively and stop at £P192 ($768) unless they pass certain parts of the Teachers Higher Certificate examination. Similarly Dar al-'Ulum graduates who start at £P152 ($608) may not progress beyond £P192 ($768) without passing the Teachers Higher Certificate examination.[7] All teachers are thus required to achieve the intermediate standard, equivalent to about two years of university study, and to reach a higher standard in educational theory and practice before entering the next grade, starting at £P200 ($800). Exceptions are made for graduates of the American University of Beirut, who start in grade four at £P140 ($560) and may proceed to grade three without examination, and for bearers of the Palestine Diploma of Arts and Sciences, who start at £P152 ($608).

Grade three is for all teachers who have fulfilled all the requirements of the Teachers Higher Certificate examination. They may or may not be university graduates. They begin at £P200 ($800) and, according to qualifications, work up at the rate of £P8 per annum to £P280 ($1,120), or at the rate of £P10 to £P300 ($1,200). Without acquiring a university degree they may not rise above £P300 per annum. This grade includes graduates from various foreign universities (with the exception of Oxford, Cambridge, and London), at £P224 ($896) per annum; they may be promoted to grade two without examination.

Grade two is limited to university graduates and bearers of the Palestine Diploma in Arts and Sciences. The lowest salary is £P300 a year. Annual increments are £P12, £P15, and £P20, with limits on annual salaries of

[7] For details of this examination, see pp. 234–35.

£P420, £P480, and £P500 ($2,000) respectively. For most teachers the limits of this grade represent the maximum which they may attain as teachers in Palestine. For graduates of Oxford, Cambridge, and London Universities the initial salary is usually £P336 ($1,344).

Grade one, with an initial salary of £P480 ($1,920), annual increments of £P20, and a maximum yearly salary of £P600 ($2,400) holds only teachers who have graduated from Oxford, Cambridge, or London Universities, and inspectors and assistant inspectors who are graduates of any recognized university. The maximum salary of £P600 a year is, at the present time, the highest pay available to any teacher in the Government school system of Palestine.

Above the numbered grades are four grades for higher officials of the Department of Education. The grade of Senior Education Officer, starting at £P600 with increments of £P25 a year to the maximum salary of £P800 ($3,200), is for district inspectors of education and for selected headquarters inspectors, the selection being made on the basis of efficiency and length of service in grade one. The grade of Assistant Director of Education, starting at £P800 with annual increments of £P25, has a maximum of £P1,000 ($4,000). The grade of Deputy Director of Education carries a fixed annual salary of £P1,000. The Director of Education has a fixed salary of £P1,350 ($5,400). The last two grades are reserved for British officials. All British officials receive in addition to regular pay an "expatriation allowance" ranging from £P100 a year for those of lower salary to £P200 for the Director of Education.

During the latter years of World War II compensatory allowances were added to the basic salaries of all government employees to cover rising war prices. The allowances were made in accordance with an ascending scale of six steps determined by the number of the employee's dependents and his basic salary if between £P2 and £P15. Thus, a porter with a monthly salary of £P2 ($8.00) received an additional minimum allowance of £P1.778 ($7.12) if unmarried, and a maximum of £P11.258 ($45) if married and the father of four or more children. An employee with a monthly basic salary of £P15 ($60) received an additional minimum allowance of £P9.480 ($37.92) if single and a maximum allowance of £P18.960 ($75.84) if married and the father or four or more children.

The salary scale for women teachers is the same as for men, but women are required to resign if they marry.

The following figures represent the distribution of teachers in the various levels for the year 1945–46:

Rank	No. of Teachers
Supernumerary teachers at £P60–£P96 ($240–$384)	266
Grade four at £P60–£P192 ($240–$768)	1,285
Grade three at £P200–£P300 ($800–$1,200)	219
Grade two at £P300–£P500 ($1,200–$2,000)	20
Grade one at £P480–£P600 ($1,920–$2,400)*	54

* Includes some inspectors and assistant inspectors.

PENSIONS AND RETIREMENT

Palestine has two forms of retirement compensation for government teachers—a pension system and a provident-fund system.

Under the pension system, certified teachers with approved efficiency records, occupying posts declared pensionable by the High Commissioner in Council, and in service on or before March 31, 1943, are eligible for participation in the pension plan after a probation period of three years. Teachers appointed after March 31, 1943, are not eligible unless their salaries are £P300 ($1,200) or more a year. Qualified teachers may be granted a pension after ten years of service. The amount of pension is calculated on the basis of one-sixtieth of his salary at retirement times the number of years in service. A teacher of thirty years' service is entitled to a pension equal to half his last annual salary. The pension allowance, however, may not exceed two-thirds the highest pensionable salary received by the teacher during his term of service.

Teachers appointed after March 31, 1943, whose salaries are not less than £P60 ($240) and no more than £P300 ($1,200) have the benefit of the provident fund. Under this system a teacher pays the treasurer 5 percent of his monthly salary, and the government pays an identical sum; this fund gathers interest at 3 percent. On leaving the service the teacher receives the amount standing to his credit.

At marriage or resignation, women who have taught five years or more are entitled, if occupying a pensionable office, to a gratuity of one-half month's salary for every six months of service up to a maximum of the equivalent of twelve months' pay.

Educational Legislation

Education in Palestine is subject to the Education Ordinance of 1933 and the regulations attached to it. The ordinance classifies public schools according to the principal language of instruction—into Arabic schools established by the government, and Hebrew schools declared public by the Director of Education in a special schedule attached to the law. The Director of Education is required to consult with any local authority or association

that maintains a school with regard to matters pertaining to the school. A nongovernment school must be registered at the Department of Education within a month after its opening, and a representative must be appointed to represent its interests to the Director. The Director of Health or any medical or sanitary officer authorized by him may visit the school, and, on the basis of his report, the Director of Education may require the manager of a school to effect repairs recommended by the sanitary officer. In case of default, the High Commissioner, after three months, may close the school. All schools except nonassisted schools are subject to government inspection, and nonassisted schools may be visited by Department of Education officials after reasonable notice. These schools are required to furnish visiting officials with information upon demand, but the officials have no authority to interfere with internal administration or curriculum of the schools.

No one is allowed to teach in a public or assisted school without a license procured by registering with the Department. The Director of Education may demand the dismissal of a teacher who has been convicted of bad morals or seditious teaching after inquiry by a judge. A school not properly registered or one conducted in a manner contrary to public morals and order or one that retains a teacher whose dismissal has been demanded by the Director of Education may be closed by the High Commissioner.

The ordinance provides for the establishment of local education authorities. Every municipal or other local council approved by the High Commissioner constitutes a local education authority, which establishes a committee of not more than thirteen members for a municipality or local-council area and of not more than seven members for a village. These committees are composed of three categories of members: (1) members of the municipal or local council; (2) some members drawn from the locality, and (3) an official of the central administration, the district inspector of education, and the headmaster of a public school in the area. The last two are Arabs for Arabic schools and Jews for Jewish schools. The local education authorities may impose an education tax, subject to the approval of the district commissioner, "which shall be a surcharge upon any rate, tax, tithe, or due assessed and collected by the government or the local authority under the terms of any law in force from time to time." If a local education authority fails to collect a rate adequate to maintain the schools, the High Commissioner has power to impose and collect a rate as if it were a government tax.

Local education authorities are charged to provide, at the request of the Director of Education, lands, school buildings, playgrounds, sanitary and hygienic conveniences, and other apparatus for schools. They may be re-

quired to provide free tuition, materials, and books for poor students, equipment and furniture for the school, and an adequate teaching staff, and to pay such teachers as are not pensionable government officials and also to pay the government treasurer the monthly 5 percent on such teachers' salaries to make up the required provident fund.

Local education authorities may make an agreement for the maintenance of a community (denominational) school. In this event a joint committee is formed of three members from the community and one from the local education authority to manage the school. The school is then considered a public school. The proprietors are responsible for the maintenance of school buildings and grounds; other expenses are provided for according to arrangements worked out between the local education authority and the Director of Education. Children of other denominations may be accepted up to a maximum of 25 percent to fill vacant places, subject to the consent of the committee on management of the school. No child may be required to attend religious instruction contrary to the desire of his father. Children of minority faiths may have religious instruction of their own at the expense of their communities.

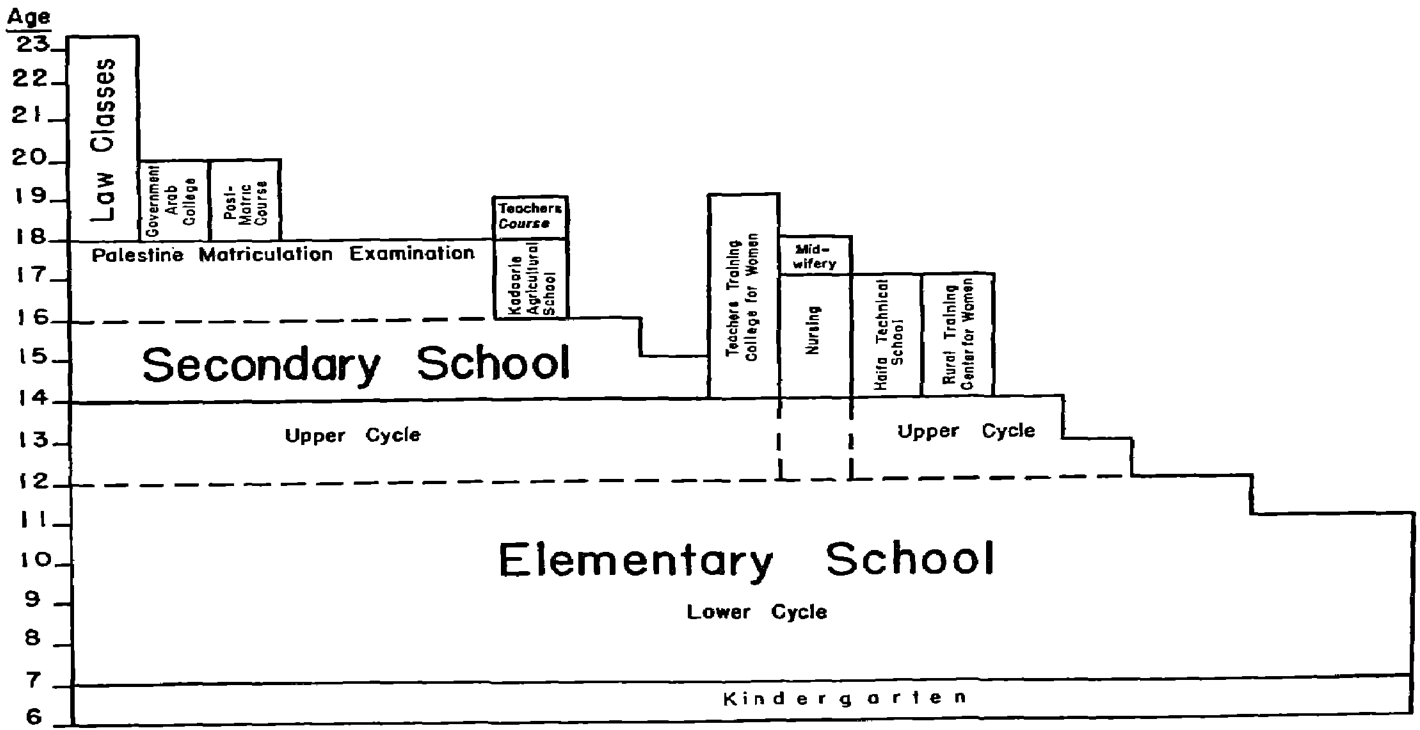
Any school managed by a registered public body or association other than a local education authority may, if recognized by the government, be registered as a public school. Certain conditions have to be met to obtain such recognition. It must be shown that the number of places in other public schools is inadequate; the medium of instruction must be one of the three official languages (English, Arabic, Hebrew) or Greek or Armenian; the syllabus must be approved by the Director of Education; the teachers' salary scale must not be lower than the minimum paid by the government; no teacher may be appointed or dismissed or punished with more than a reprimand without the approval of the Director of Education; the school must pay to the government the required provident-fund contribution for nonpensionable teachers; fees charged by the school must be approved by the Director of Education; finally, a number of free places must be provided. These provisions place the school largely under the authority of the Department of Education.

The Arab Educational Ladder

The Arab public-school system of Palestine forms a single, and quite simple ladder, shown in Chart VI. It rises from a kindergarten of one year (almost exclusively for girls) through an elementary school of seven years, a secondary school of four years, or, more frequently, of fewer years, 2 higher institutions for boys, and 2 schools for the training of women teach-

Chart VI

PALESTINE: THE GOVERNMENT (ARAB) SCHOOL SYSTEM, 1946



ers. Boys and girls attend separate elementary and secondary schools. The only professional education given other than teacher-training, is the five-year program of the Law Classes, which admit students from the secondary schools. The Kadoorie Agricultural School at Tulkarm admits boys from the second year of the secondary school, and the Haifa Technical School admits boys from the top class of the elementary school. Training for nurses is provided for both Arab and Jewish girls by government and mission hospitals. All of these schools will be described hereafter.

There are only three complete four-year public secondary schools for Arab boys in the country. There are thirteen schools having two secondary years, most of these being combined with some elementary grades (three of the thirteen are for girls). In addition, there are five elementary schools for boys which have added the first secondary-school class. Some of these one- and two-year schools offer courses in agriculture, including work in school gardens, along with the regular secondary program.

The two higher institutions for boys are the Arab College and the Rashidiyah School, both situated in Jerusalem. The Rashidiyah School is in fact a complete four-year secondary school with a two-year postmatriculation course of purely academic subjects. The Arab College combines academic subjects with professional education for teaching, and graduates are expected to teach in a government school. Upon completion of the course at either of these institutions, the student may present himself for the Palestine intermediate or the London University intermediate examination. This exhausts the opportunity of study within Palestine for Arab students. However, the superior student has a chance of being sent on scholarship to England if the need for teachers in the two colleges and the upper years of the secondary school is great.

Upon completion of elementary school, girls may enter one of the three two-year secondary schools situated in Jerusalem, Jaffa, and Nablus, or one of the two institutions for training teachers—the Teachers Training College for Women, in Jerusalem, or the Rural Training Center for Women, in Ramallah, for the training of rural teachers.

The public-school system for Arabs is essentially an elementary-school system to which are attached a few institutions designed to supply it with teachers. Of 82,775 students registered in 1946 in public schools conducted by the government or by local authorities under the supervision of the government, 80,901, or 97.8 percent, were in the kindergartens and elementary schools. The remaining 1,874 boys and girls, constituting 2.2 percent of the total, were distributed through all other types of schools:

secondary, teacher-training, agricultural, and technical, and the one two-year postmatriculation institution—Rashidiyah School.

In 1945–46 only 932 pupils, or 42 percent of the 2,211 pupils who had been registered in the seventh grade the previous year, were registered in the first secondary year or its equivalent. The remainder went to private schools or dropped out of school altogether—though a few may have been allowed to repeat the seventh grade.

Government Examinations

The Government Department of Education conducts five types of examinations: (1) the Palestine matriculation examination; (2) the Secondary-School Certificate examination; (3) the intermediate examination; (4) the Higher Certificate examination; and (5) the Diploma examination. In addition, the Department supervises examinations held in Palestine by the University of London and other British institutions. The Palestine Board of Higher Studies, formed in 1923, has charge of all these examinations. Its chairman is the Director of Education, and it is composed of representatives from the American School of Archaeology and various foreign educational institutions, government officials, and other persons interested in academic education in Palestine.

THE MATRICULATION EXAMINATION

The Palestine matriculation examination was first held in 1924 for 27 candidates, 9 of whom passed. It is held only once a year, beginning the first Monday in July. The candidate must be at least sixteen years old; he may be entered by a school or he may enter independently. Subjects are grouped into seven fields (common to the Secondary-School Certificate examination as well as the matriculation examination) as follows:

Group 1. Principal languages: English A, Arabic A, and Hebrew A. (The "A" indicates that the examination is designed for candidates whose mother-tongue is the language concerned and is the highest in standard of the language examinations.)

Group 2. Elementary mathematics.

Group 3. General history.

Group 4. Additional languages: Arabic and Hebrew are offered in three descending levels of difficulty, A-1, B-1, and B-2. English may be offered in two levels, A or B. Other languages which may be offered are Armenian (classical and modern), French, German, Italian, Latin, Greek (classical or classical and modern), and additional Hebrew.

Group 5. General physics. Additional physics, special physics in three parts (I: mechanics and hydrostatics; II: heat, light, and sound; III: electricity and magnetism), chemistry, botany, zoology, biology, geography, domestic science (for girls), and additional history.
Group 6. Religious knowledge: Jewish, Christian, and Muslim.
Group 7. Additional subject: physiology and hygiene.

The candidate must choose one subject in each group from 1 to 5, and a sixth subject in either group 4 or group 5. Each subject requires from one to three papers. He must satisfy the examiners in all six subjects. He is not allowed to choose the same language in groups 1 and 4 or to choose any subject in special physics if he has already chosen general or additional physics, or to choose biology if he has previously chosen botany or zoology. However, he may offer additional Hebrew if he has chosen Hebrew A from group 1 and either English or Arabic in group 4. Students may choose additional subjects from groups 6 and 7 to satisfy requirements of certain universities, but these do not count in the six required for the Matriculation Certificate. The names of these additional subjects will, however, be inscribed upon the certificate.

The examination may be taken in English, Arabic, or Hebrew, according to the candidate's choice of principal language in group 1. He is not obliged to choose his mother-tongue, but if he does he must achieve the highest standard. An Arab or a Hebrew candidate may offer a lower level if he can prove that Arabic or Hebrew is not his mother-tongue and that he studied in a school where some other language was the medium of instruction. All examinations except in modern languages, Latin, and Greek must be answered in the principal language. Modern languages are answered in their own medium. Biblical Hebrew and classical Arabic must be answered in the principal language chosen from group 1. Latin and classical Greek must be answered either in the principal language chosen or (if the candidate has chosen Arabic or Hebrew as his principal language) in English. Some practical work may be asked in the science examinations.

THE SECONDARY-SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION

The first Secondary-School Certificates were awarded in 1930. The examination for the certificate is conducted in much the same way as the matriculation examination except that the standard required is lower and the candidate has more freedom of choice. The student may choose his six subjects from any group, the only requirement being that he must take one in group 1. A candidate for this examination must not be more than

twenty years of age and must be presented by a school, with a statement from the school that he has studied courses in the language of instruction, in one other language, in history, in mathematics, and in at least one science.

Results of the 1945 examinations are shown in Table 37.

TABLE 37

RESULTS OF SECONDARY-SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION ACCORDING TO LANGUAGE MEDIUM, PALESTINE, 1945*

Medium	Number Taking Examinations	Passed Matriculation Examination		Passed School Certificate Examination		Failed	
		Number	Percentage	Number	Percentage	Number	Percentage
Arabic....	148	71	48.0	57	38	20	14.0
English...	81	34	42.0	34	42	13	16.0
Hebrew...	115	28	24.5	44	38	43	37.5

* Data supplied by the Department of Education.

The higher percentage of failure among candidates in the Hebrew medium is probably due to the lower age range of the candidates. As might be expected, since they are a highly selected group, the government school students make the highest record; students from nongovernment schools take second place, and unattached candidates have the poorest average. This is shown in Table 38.

TABLE 38

RESULTS OF SECONDARY-SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION ACCORDING TO TYPE OF SCHOOL, PALESTINE, 1944

Type of School	Number Taking Examinations	Passed Matriculation Examination	Passed School Certificate Examination	Failed	
				Number	Percentage
Government schools........	85	60	21	4	4.7
Nongovernment schools....	259	88	109	62	23.0
Unattached candidates.....	44	12	...	32	72.7

INTERMEDIATE EXAMINATIONS

The intermediate examination is the first part of the examinations for the Diploma in Arts and Sciences, granted by the Department of Education as the equivalent of the Bachelor of Arts degree. Candidates holding the Palestine Matriculation certificate or its equivalent may sit for the intermediate examination if they are registered in a school which provides postmatriculation studies or if they have previously attended such a school and are presented by its principal. The examination may be taken in any one of the three official languages of Palestine and is held at the same

time as the matriculation examination. Its subjects are in six groups. Group 1 contains English and either Arabic A or Hebrew A. Group 2 is history, which is divided into periods, each of which counts as a separate subject. Group 3 is history, philosophy, archeology, geography, and logic. Group 4 is pure and applied mathematics. Group 5 is classical and modern languages, including Armenian, Arabic B, and Hebrew B. Group 6 is physics, chemistry, biology, geology, and geography.

To pass, a candidate must satisfy the examiners in English and in either Arabic or Hebrew. If his mother-tongue is neither of the latter languages, he may substitute a modern language of Group 5. In addition, he must offer three other subjects, one being either history or mathematics, the other two to be chosen from any of the groups, though he is limited to two subjects in history. A student who offers two subjects in science and two in mathematics may be exempt from offering his mother-tongue. Aside from the languages, the choice is between a literary and scientific group of subjects. This organization is in line with the present division of courses at the Arab College and the Rashidiyah School.

The English examination consists of five papers; the Arabic examination, four; and the Hebrew examination, four. Examinations in all three are advanced in standard. History includes ancient history to Alexander, Greece and Rome, and Europe and the Near East from Constantine to 1500 A.D. Special episodes within these periods may be taken as separate subjects. The archeology of Palestine requires two papers. Pure mathematics includes two papers in advanced algebra, plane and solid geometry, and trigonometry as well as on coordinate geometry and elementary calculus. Applied mathematics includes two papers on statics, dynamics, and hydrostatics. Examinations in modern languages consist of two papers and an oral examination. General physics (not including mechanics) and chemistry require two papers each and inspection of the candidate's laboratory notebooks. For geography one paper in general and one in regional geography are required, and a third is devoted to mapwork. Candidates for the intermediate examination have been offered by the Arab College since 1941 and by the Rashidiyah School since 1944. As they are selected candidates, they usually all pass. Rashidiyah School prepares for the University of London intermediate also.

The Teachers Higher Certificate Examination

The Higher Certificate examination, based on the same syllabus as the intermediate examination, is less exacting. Additional subjects may be in-

cluded if application is made to the Board of Higher Studies early in the school year preceding that in which the examination is to be held. The examination is designed for candidates who have continued school after passing the matriculation examination and have taken studies of approximately intermediate-examination standard. Three subjects are required but with no particular grouping, and there are language tests in English and either Hebrew or Arabic. The language examinations are simpler than those of the intermediate examination, consisting of an essay and translation from English to the mother-tongue and vice versa. A candidate may offer up to five subjects in addition to the language tests.

This examination is in two parts: Part I, *a* and *b*, is in educational theory and practice, from which graduates of teacher-training colleges are exempted, but *c*, in the content of elementary- and secondary-school syllabuses, is required of all; Part II, a subject-matter examination of the University of London or Palestine intermediate-examination standard, is required of all except graduates of the Government Arab College of the class of 1943 or later.

Diploma examination

The Diploma examination, which is of the standard of an English Bachelor of Arts degree, was first held in 1929 and consists of subjects grouped under arts and under science. Only students who have passed the intermediate examination are allowed to sit for the Diploma examination. Candidates in arts must pass a six-paper examination in English and a similar one in Arabic or Hebrew. They must sit for two additional subjects if one is in the classics or for three if none is in the classics. Subjects included are as follows: general and special periods in history, archeology, and anthropology; history of political ideas; pedagogy; history of philosophy; languages (Arabic B, Hebrew B, French, German, and Armenian); and the classics, including classical history. Candidates offering in science must also satisfy the examiners in English and in either Arabic or Hebrew. If neither Arabic nor Hebrew is their mother-tongue, they may substitute either French or German. In addition, they offer three subjects, two of which must be chosen from the following: pure mathematics, applied mathematics, physics, chemistry, and biology. The third subject may be chosen from the foregoing or from astronomy, geology, geography, history of science, mathematics, and pedagogy.

The Diploma examination is held only upon application of a candidate, and very few candidates had applied in the period from 1929 to 1946.

EXAMINATIONS FOR FOREIGN INSTITUTIONS

The Department of Education, in addition to conducting its own examinations, supervises qualifying examinations held in Palestine by various British institutions, among which are London, Oxford, and Cambridge Universities, the London Association of Certified Accountants, Institute of Fire Engineers, Royal Aeronautical Society, and Institute of British Radio Engineers.

Expansion of the Arab Educational System

Table 39 represents an attempt to summarize statistically the development of the government public-school system for Arabs since the end of World War I. Beginning in 1919 with 171 schools, 408 teachers, and 10,662 students, it grew rapidly for a two-year period, adding 140 new schools, 231 teachers, and about 9,000 pupils. There followed a decade of relative stagnation, during which the number of schools remained virtually at a standstill—and in some years acually declined—the number of teachers increased very slowly, and the number of students was augmented by only about 500 a year. Lack of budgetary provision for educational expansion was largely responsible for this period of arrested development.

In 1933 the government, acting upon the recommendations of a committee of inquiry, laid down a five-year plan which was applied for only three years but which pushed the number of schools to 384 in 1935–36, the number of teachers to 1,148, and student registration to 42,765—an increase of about 18,000 over 1932. There followed another period of

TABLE 39

DEVELOPMENT OF THE ARAB PUBLIC-SCHOOL SYSTEM, PALESTINE, 1920–46

Year	Number of Schools	Number of Teachers	Enrollment		
			Boys	Girls	Total
1919–20	171	408	8,419	2,243	10,662
1920–21	244	525	13,656	2,786	16,442
1921–22	311	639	16,606	3,033	19,639
1925–26	314	687	16,146	3,591	19,737
1930–31	308	744	19,346	4,942	24,288
1931–32	305	783	19,658	5,179	24,837
1935–36	384	1,148	33,053	9,712	42,765
1938–39	395	1,312	39,702	10,318	50,020
1939–40	402	1,340	42,219	12,148	54,367
1940–41	403	1,364	42,244	12,314	56,558
1942–43	403	1,452	45,603	12,722	58,325
1943–44	458	1,729	50,450	14,340	64,790
1944–45	478	1,872	56,359	15,303	71,662
1945–46	504	2,156	65,828	16,947	82,775

stagnation, seven years in duration. The early years of this period, 1936–39, were marked by acute civil disturbances in Palestine; the final years were marked by World War II when expenditures on military operations made heavy inroads on Palestinian funds to the detriment of the social services. However, while school buildings remained numerically fixed, students kept increasing in number. The increase for this seven-year period was about 16,000. New rooms were added to existing schools at the expense of the local authorities, some new teachers were appointed, and classes were filled to more than capacity.

Naturally, this situation could not continue indefinitely, nor could the overwhelming demand of the Arab population for education be ignored. Accordingly, a new period of expansion set in and in the three years following 1943, 100 new schools were established, the number of teachers was increased by 700, and the number of pupils by about 24,000. However, the supply of educational facilities continues to fall far short of the ever-increasing demand motivated by the new Arab awakening. Recent years have witnessed a growing measure of participation in the educational effort by both local municipalities and the Arab populace in general. This participation manifests itself in the vigorous school-building activity carried on largely at the expense of the local authorities and supported by contributions from the people, in the collection of education taxes by a number of municipalities, and in the willingness of local authorities to finance new schools and pay additional teachers. In the last five years about 200 new schoolrooms were built and, in 1945–46, 346 teachers were being paid by the local authorities.

It is pertinent, at this point, to raise the question of what progress the public education system for Arabs has made toward its goal of universal education. There are about 300,000 boys and girls in Arab Palestine between the ages of five and fifteen. In 1945–46 there were about 119,000 children in kindergartens and elementary schools—private as well as public—in Arab Palestine, or approximately 40 percent of the children in the five- to fifteen-year age group.

However, if the hypothesis of the Government Department of Education that universal elementary education should be achieved through the five-year elementary school is accepted, the picture is brighter. It was estimated that on October 1, 1945, there were 156,098 Arab boys and girls in the six- to eleven-year age group. In November of the same year there were 71,663 boys and girls in the lower five grades of the public elementary school. Adding to this number the approximately 25,000 children in the corresponding grades of private schools, we find that about 96,000

Arab children, or about 62 percent of all children, in that age group were attending this basic school. Among the countries covered in this report, Palestine offers the second highest ratio between school attendance and school-age group, the highest being in Lebanon.

Table 40 shows the distribution of pupils by grades in the public schools

TABLE 40

DISTRIBUTION OF PUPILS BY GRADES, ARAB PUBLIC SCHOOLS, PALESTINE, 1944 AND 1945*

GRADES	ENROLLMENT, NOVEMBER 1944			ENROLLMENT, NOVEMBER 1945		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
Kindergarten	6	1,837	1,843	9	1,851	1,860
Elementary						
1	13,161	3,616	16,777	15,332	3,719	19,051
2	11,759	3,067	14,826	13,534	3,302	16,836
3	10,470	2,584	13,054	11,865	2,859	14,724
4	9,346	1,981	11,327	10,497	2,200	12,697
5	5,784	1,263	7,047	6,932	1,423	8,355
6	3,204	734	3,938	3,884	791	4,675
7	1,764	447	2,211	2,297	506	2,803
Secondary						
1	465	107	572	661	135	796
2	288	59	347	388	93	481
3	107	33	140	140	33	173
4	83	13	96	105	20	125
5	21	19	40	33	15	48
6	16	...	16	15	...	15
Technical	64	...	64	71	...	71
Agricultural	69	...	69	65	...	65
Total	56,607	15,760	72,367	65,828	16,947	82,775

* Data supplied by the Government Department of Education.

for the years 1944–45 and 1945–46. Comparison of the enrollment in classes in 1944 with that in the next classes in 1945 shows little elimination of pupils in the first four years of the elementary school. The sharp decline in numbers between the fourth and fifth grades is largely due to the fact that about half of the rural schools do not go beyond the fourth grade. Beginning with the sixth grade, the selective principle applied with increasing strictness brings registration almost to a vanishing point in the final year of postelementary education. It will be noticed that there was a gain in total registration of more than 10,000 in 1945–46.

Chapter 15

PUBLIC AND PRIVATE SCHOOLS FOR ARABS

PUBLIC KINDERGARTENS, found only in girls schools but admitting a few boys under six, give some instruction in reading and arithmetic, but emphasize helping the child to bridge the gap between home and school. The average age is six to seven years. However, some are as young as three and others as old as nine. Much attention is given to group games, stories, free play, and the development of personal habits of cleanliness. The aim of the kindergarten is the adjustment of the child to participation in a social group of his contemporaries. There were 1,860 children in the kindergartens of the Arab public-school system in 1944–45, only 9 of whom were boys.

Public Elementary Schools

The elementary school in Palestine has a seven-year course and in theory admits beginners who are seven years old. However, in practice, children from five to twelve are found in the first grade. Although most children enter directly from the home, some of the boys come from the *kuttabs* (native religious schools) and some of the girls from the kindergartens. The elementary school is divided into two stages or cycles.

The first stage consists of the first five grades in town schools and the first four grades in village schools. It would be incorrect to assume that villages have only four-grade schools, since almost half of the schools outside of the main towns have five or more grades. The elementary school in its lower five-year section is the vehicle with which the government hopes to stamp out illiteracy. Progress toward the realization of this goal is slow because of inadequate funds. This lower school is at present free, but economically incapable of admitting more than 60 percent of its applicants—a figure that does not take account of children in remote villages who do not apply because there is no school in their locality.[1] Out of

[1] Jerome Farrell, "Arab Public Education in Palestine," (Typewritten memorandum dated May 10, 1945); Farrell, *Education in Palestine, General Survey, 1936–45* (Jerusalem: 1945), p. 3.

79,141 children enrolled in public elementary schools in 1945–46, according to statistics supplied by the Government Department of Education, 71,663 were in the lower section. No selection is practiced in this section, admission to the first grade being strictly by priority of application. Every elementary-school principal is required to keep a register of rejected pupils for use in deciding subsequent priorities. As the demand for education is great and the number of places limited, the omission of tests of ability as a basis for admission has led to large classes in the lower stage. One repetition of a grade is permitted, but failures are not extensive. The authorities believe that, given adequate funds, a very near approach to universal elementary education based on the lower school could be achieved among the Arabs without compulsion.

In the higher section, which comprises the sixth and seventh grades, the limited number of places available requires a very strict selection of students. Statistics for November 1945 show 8,355 pupils in the fifth grade; the number drops abruptly to 4,675 in the sixth, and to 2,803 in the seventh, making a total of 7,478 in the higher section as against 71,663 in the lower. Promotion to the sixth grade is on the basis of merit and age. A pupil in the fifth grade of a town school or the fourth grade of a rural school who will be fourteen before the coming October and who is not eligible for promotion is automatically dropped. In the higher section, repetition of a grade is allowed only on grounds of prolonged illness or of age below the norm for the grade—indicating too rapid acceleration. Dismissal of the dullard and the idler is justified on the ground that in a system of limited facilities a repeater wastes public money by depriving a worthier child of a place in the school. Although repeaters may aggregate 12 to 18 percent of the enrollment in the lower classes in boys schools, they drop to from 3 to 6 percent in the sixth and seventh grades respectively, to 1 percent or less in the first two secondary years, and disappear altogether in the last two secondary years and the two postmatriculation classes. Repeaters among girls are even rarer than among boys.

A fee of £P1.5 (about $6.00) is charged in the sixth and seventh grades, but no competent pupil is barred from school because of inability to pay a fee. Pupils barred from the higher cycle because of low grades sometimes enter private schools, which charge higher tuition fees but practice little or no selection.

In rural Palestine an attempt is made to maintain a complete seven-grade elementary school in any strategically placed large village which is surrounded by small villages having schools of four or five grades. Better pupils from the smaller villages may then be admitted to the larger school.

ɔ their elementary education, boarding depart-
ıumber of large village or rural town schools.
ished prior to 1940, one of which, at Beer-
rs for Bedouin boys. Nine additional hostels
)40 and 1945. The hostels are small, the
n being 459 boys in 1945. Rented houses,
and former military quarters are utilized as
ι of the local school authorities. The hostels
ɔy contributions from the municipalities and
. Scholarships which include maintenance are
the Department.
at in 1945–46 there were 374 village schools
ıg grade distribution:

ion	No. of Schools
grade	2
'o grades	5
ree grades	26
ır grades	161
e grades	66
ε grades	31
ɔn grades	83
	374

ıere are 48 village schools maintained by local
ɜing the total to 422. There are also eleven
.ementary classes and one or two secondary
ıg the number of schools in rural areas with
l areas the principal emphasis is laid on the
Very few schools have less than four grades.
:h schools in 1945, 27 had been in existence
thus had not yet had a chance to develop a

ıntries studied in this report holds no public
.cluding their elementary schooling.

OF STUDY

ɔgram of studies is established by the Depart-
difications, subject to the approval of district
neet local needs in rural areas. Local programs
or absence of school gardens, workshops, and

teachers trained in special fields. The standard program of studies is given in Table 41. Two periods of theoretical and practical agriculture are added in the fourth and fifth grades and three in the sixth and seventh grades in schools that have school gardens.

TABLE 41

ELEMENTARY-SCHOOL PROGRAM OF STUDIES FOR ARABS, PALESTINE, 1945–46

Subjects	Periods* per Week						
	1st Grade	2nd Grade	3rd Grade	4th Grade	5th Grade	6th Grade	7th Grade
Arabic	14	11	12	8	8	8	8
English	...	...	...	8	8	8	8
Mathematics	5	5	5	5	5	6	6
Hygiene and nature study	...	3	3	2	2	2	2
Religion	5	5	5	4	4	3	3
History and geography	2	2	3	4	4	4	4
Manual training or domestic science	2	2	2	2	2	2	2
Drawing	2	2	2	1	1	1	1
Physical training	...	...	3	1	1	1	1
Total	30	30	35	35	35	35	35

* Periods are thirty minutes in length in first grade, forty-five in all others.

The first-grade course in the *Arabic language* proceeds in the usual form—reading from a simple book, conversation on familiar topics, the writing of characters of the alphabet and familiar words, and recitation of short easy pieces from the prescribed reader. Memorization of poetry and prose begins in the second grade (ten lines of each required), and *nashkh,* the most common script, is taught. Silent reading with comprehension tests is introduced in the third grade, memorization increased to at least thirty lines of poetry and twenty of prose, and *ruq'ah* script is added. The study of the fundamentals of grammar begins in the fourth year, formal grammar in the fifth. Memorization, dictation, and composition increase in difficulty through the fifth, sixth, and seventh grades. In the seventh grade special emphasis is placed upon syntax. Some fifty supplementary readers are prescribed for silent reading from the third through the seventh grades, but their use had to be curtailed during the war owing to the shortage of paper.

The *English language* is introduced in the fourth grade with a direct and conversational method. In the first half-year a conversational reader—either Morris, *An English Course for Foreign Children,*[2] Books I and II, or Bentwick, *English for Beginners,*[3] Parts I and II—is used, after which

[2] New York: Macmillan Co.

[3] New York: Longmans, Green & Co.

West's *New Method Reader I: Alternative Edition*[4] and supplementary books are studied. Pupils are expected to complete readers one through seven together with supplementary books in the elementary school. In the early stages Arabic equivalents of English words are used, but translation is avoided. The main objects in the teaching of English are ease of silent reading involving the acquisition of a large passive vocabulary; correctness, rather than ease, of written composition, and correctness of oral expression and pronunciation.[5] The style of handwriting taught is "cursive script," which in its early stages resembles print. At the beginning of the seventh grade and thereafter disjointed handwriting is not permitted.

Attention is given to instruction in grammar beginning in the second year of the study of English—fifth grade—but systematic and formal study of grammar is postponed until the fourth year when Tipping's *English Grammar for Beginners*[6] is studied.

Recitations of selections from prose and poetry are required beginning with the third year—sixth grade. Selections are taken from the readers and supplementary books. The supplementary books include simplified editions of *The Deerslayer, The Cloister and the Hearth, Quentin Durward* in the third year, and *King Solomon's Mines, Treasure Island, Ivanhoe,* and *Silas Marner* in the fourth year. Additional books are available in most schools for pupils who wish to carry on voluntary collateral reading. Much recitation and reading in unison are used to increase the amount of practice for each pupil. The classes are sometimes divided into paired groups with one pupil asking questions and the second giving the answers. Since this is done simultaneously in a number of groups in the classroom, a visitor may get the impression of great noise and confusion. The pupils seem to be less disturbed and to enjoy the activity.

The study of *mathematics* emphasizes logical form, accuracy, and neatness in all written number work. At the lower levels there is much practice in oral work, and practical demonstrations with familiar objects are employed. The content of the courses from first grade through fourth grade is similar to the conventional outline year by year as described for the Egyptian elementary program in chapter 2. However, while elementary mathematics ends with the fourth year in Egypt, there is a fifth grade in Palestine, in which work with fractions and decimals becomes more complex, and the pupils study square root, ratios as fractions, and give some attention to averages.

[4] New York: Longmans, Green & Co.

[5] *Instructions for the Teaching of English in Government (Arab) Elementary Schools* (Jerusalem: The Modern Press, 1944), p. 7.

[6] New York: Macmillan Co.

In the upper division of the elementary school, sixth-grade pupils study the metric system in detail, the English monetary system, simple equations and formulas, simple and compound proportion and proportional parts and averages, simple exercises on percentages, and simple interest. They are taught to use instruments and to develop geometric ideas inductively and by observation of carefully drawn figures. In the seventh grade the pupils study square root, profit and loss, commission, insurance, simple and compound interest, debit and credit accounts, bank discount, use of checks and bills, easy problems on stocks and shares, and a slightly more advanced kind of theoretical and demonstrative geometry.

Systematic study of *science* (hygiene, nature study, and elementary science) begins in the second grade, though even kindergarten children have their attention called to objects and living things in their environment. The course is designed to interest children in nature, arouse their curiosity, and develop their powers of observation and perception. Small museums are found in many schools. Through the second and third grades they are taught health habits and the importance of cleanliness, and study common domestic and wild animals, birds, and insects. They are introduced to elementary gardening in the third grade, and in the fourth grade emphasis is upon the importance of plants, animals, and minerals to the economic life of Palestine, and industries of the country are studied. In this grade the children learn more about anatomy and the functions of various parts of the body, simple first aid, and something about the safe handling of milk and food and the methods of obtaining pure water.

More formal study of the *biological sciences* begins in the fifth grade with the classification of animal and plant life and the study of types, and education in hygiene proceeds to an elementary study of the nervous system, how to combat common diseases (such as trachoma and malaria), methods of using disinfectants and antiseptics, etc.

The *physical sciences* are introduced in the sixth grade and continue in the seventh grade. More advanced subjects in hygiene and the biological sciences are also studied in the seventh grade, including the functions of the skin and kidneys, the effects of alcoholic beverages, the prevention and transmission of serious diseases, and advanced first aid.

The study of *religion* is similar in all Arab public schools, and covers memorization of the Koran, study of the life and teachings of the Prophet, and the required practices in prayer, fasting, and pilgrimages. Non-Muslim pupils are not required to attend classes in the Muslim religion; if a Christian teacher is available, Christian religious instruction is given. In schools with Christian majorities the situation is reversed. There are three

approved syllabuses of the Christian religion: nondenominational, Greek Orthodox, and Catholic. The last is a syllabus for the Latin (Roman) and Greek (Uniate) Catholics. Religious instruction in schools is given only by the schoolteachers. If no suitable teacher is available, arrangements are made for the pupils to attend classes elsewhere for instruction by a clergyman of the appropriate sect.

As far as possible, teaching of *history* and *geography* is coordinated in all grades. The work is organized in three cycles, the first including grades one and two; the second, the next three grades; and the third, the sixth and seventh grades. The content of the course is similar to standard outlines for the different levels, with the substitution of Palestine in the emphasis that is customarily given to the study of the native country. History and civics are correlated, with emphasis upon comparative government.

School gardening or *elementary agriculture* has become an important activity in both rural and town schools. In 1945 more than half the elementary schools had gardens, with a total acreage of 680. Boys get theoretical and practical training in making terraces and preparing ground for planting, cultivating, and harvesting cereals and vegetables. They learn pruning and grafting of fruit trees, and many schools have nurseries which supply other schools and neighboring farmers with small trees. Poultry-raising and beekeeping are included in the program of some schools. Each upper-grade pupil has a plot for which he takes complete responsibility. Other plots, particularly in schools with large gardens, are cared for by groups of pupils as communal activities. The pupils get experience also in raising flowers in plots arranged to improve the appearance of the schools.

Other standard subjects include courses in manual training and domestic science, drawing, and physical training, following the conventional pattern through the grades, making use of native materials with which to work, and organized with regard to the age and ability of pupils. (See description of similar courses in Egypt, chapter 2.) In physical training, the upper grades have formal drills with planned exercises, and sports days among groups of schools arouse great interest as culminating activities of the year's work.

School buildings and grounds

Construction of school buildings has been greatly retarded by lack of funds. Many elementary schools occupy former dwellings, and some are in buildings formerly used as military establishments or local government offices. New buildings that have been financed by the Department of Education are designed to permit expansion by the addition of wings or

stories. Such buildings are of stone, with floors and stairways of tile or cement. The standard classroom is about 24 feet 6 inches by 23 feet and is furnished with double benches and desks with hinged tops or an open shelf. The blackboard is painted plaster or wood. Playground space is usually small, and, as it is rarely paved or graveled, it is dusty in dry weather and very muddy during the rainy season. Most schools have developed attractive flower gardens, shrubs, rock gardens, and trees. Village schools for the most part have been constructed by funds raised locally. Those of more than one room are built as a row of rooms opening upon a south porch—a type of construction that makes future addition of rooms or wings relatively easy. Outside latrines are common. Running water is available in some schools and is used for irrigation in many of the school gardens. In other schools wells have been dug to insure a water supply for the school and its garden. Some schools are supplied with pumps.

Public Secondary Schools

As shown in Chart VI (page 229), secondary education in government schools for Arabs in its complete form consists of a four-year course above the elementary school with separate schools for boys and girls. However, there are only three complete public secondary schools for Arab boys in Palestine—the Arab College and Rashidiyah School, both in Jerusalem, and both also providing two years of postmatriculation work, and a school at Jaffa, which graduated its first regular four-year class in 1946. (The school at Jaffa had previously offered a two-year commercial course above the second year of secondary school.) There are 13 schools having two secondary years (3 of the 13 being for girls), and there are 5 elementary schools for boys which have added the first secondary-school class.

The only four-year secondary schools open to girls are those in connection with the two schools of teacher training—the Teachers Training College for Women, in Jerusalem, and the Rural Training Center for Women, in Ramallah. The school in Jerusalem has a five-year program, four of secondary education and one of professional training to prepare teachers for urban elementary schools. The Ramallah Training Center was a three-year course above the elementary school at the time of the visit of the American Council Commission, but a fourth year was to be added in 1946–47. The Center prepares teachers for rural schools for girls. Two-year secondary courses for girls existed in Jerusalem, Jaffa, and Nablus.

Secondary education for Arabs in government schools is limited to a highly selected group. The selective principle begins to function at the

end of the fifth elementary grade and becomes increasingly rigid at the end of the seventh grade. Selection is based upon age and class standing. All the secondary schools, except the one at Jaffa, have boarding departments and receive pupils from other parts of the country. Tuition and boarding fees are low, and exemptions from all or part of the fees are made for bright pupils without financial resources. A few of the town elementary schools include one or two years of the secondary course, from which the best pupils are transferred to a complete secondary school.

The secondary program of studies

The secondary school program is designed primarily to prepare pupils for the Palestine matriculation examination, previously described. Those

TABLE 42

Program of Studies for Arab Secondary Schools, Palestine, 1945–46

Subjects	Periods per Week					
	1st Year	2nd Year	3rd Year		4th Year	
			Literary Section	Scientific Section	Literary Section	Scientific Section
Muhammadan law and religion	1	1	2	2	2	2
Arabic	7	7	5	5	5	5
English	8	8	8	8	8	8
Elementary mathematics	...	...	5	5	4	4
Arithmetic	2	2	...	...	...	...
Geometry	2	2	...	...	...	...
Algebra	3	3	...	...	...	...
Additional mathematics	...	...	...	5	...	5
Physics	3	3	5	5	5	5
Chemistry	1	1	...	3	...	3
Botany	1	...	...	...	...	...
Zoology	...	1	...	...	...	...
Latin or Greek	...	...	4	...	4	...
History	3	3	3	3	4	4
Geography	2	2	3	...	3	...
Drawing	1	1	...	...	...	...
Physical training	1	1	...	...	...	...
Manual training	...	...	2	2	2	2
Preparation	...	...	2	1	2	1
Total	35	35	39	39	39	39

who pass with distinction are awarded the Palestine Matriculation Certificate; those who pass at a somewhat lower standard receive the Palestine Secondary-School Certificate. Minor variations in program exist in different schools—for instance, the course for girls is modified to permit study of the domestic arts and sciences—but the general pattern is shown in Table 42.

Arabic and English, the courses for which the most time is allowed, in-

clude the study of composition and précis writing, grammar, translation, and literature of appropriate difficulty and content.

In *English literature,* the students study Shakespeare's *Hamlet, Macbeth, Richard II, Henry IV, Henry V,* and *King John;* selections from A. S. Collins' *Treasury of English Prose,* including works of Ascham, Sidney, Jonson, Milton, Dryden, Addison, Burke, Hazlitt, De Quincey, Huxley, Chesterton, and Churchill. Selections from *Essential Poetry* by A. A. Mendilow and D. Melitzky (published by Aaronson in Jerusalem) are studied, including poems by Milton, Dryden, Pope, Gray, Wordsworth, Byron, Keats, and Tennyson.

Mathematics is studied in parallel classes rather than in sequence. In arithmetic the elementary-school subjects are reviewed, and more difficult problems and irregular figures in mensuration are added. Topics in algebra include quadratic equations, graphs of functions of first and second degree, roots, maxima and minima, fractional and negative indices, and logarithms to the base 10. The scope in geometry is equivalent to the first four books and book six of Euclid, including loci and areas of triangles and parallelograms of which the bases and altitudes have commensurable lengths. Work in trigonometry includes the functions of simple angles and their application to the solution of right-angle triangles. Additional mathematics for the third- and fourth-year students of the scientific section provides more advanced study in algebra, geometry, trigonometry, coordinate geometry, and calculus.

General physics includes the usual topics in mechanics, heat, light, sound, electricity, and magnetism; both qualitative and quantitative aspects are studied, and laboratory work is emphasized.

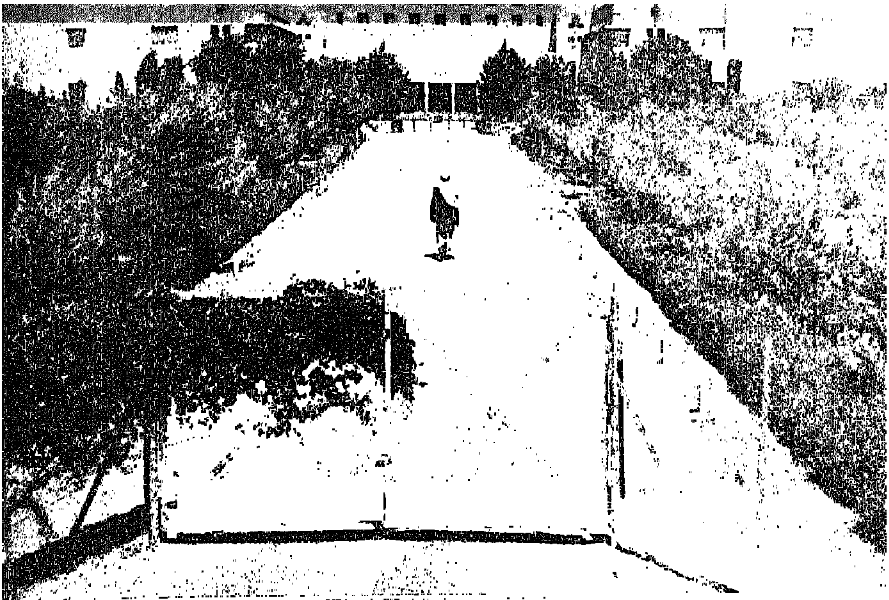
Chemistry covers elementary inorganic chemistry, and laboratory work and practical applications are stressed.

Botany ranges through morphology, physiology, and classification and uses of plants, and students are expected at the end of the course to be able to recognize at least 100 of the common plants of Palestine, including 30 trees.

The year of *zoology* includes general principles of animal life, growth and metamorphosis, structure and mode of life of types within the different orders with their distinguishing features.

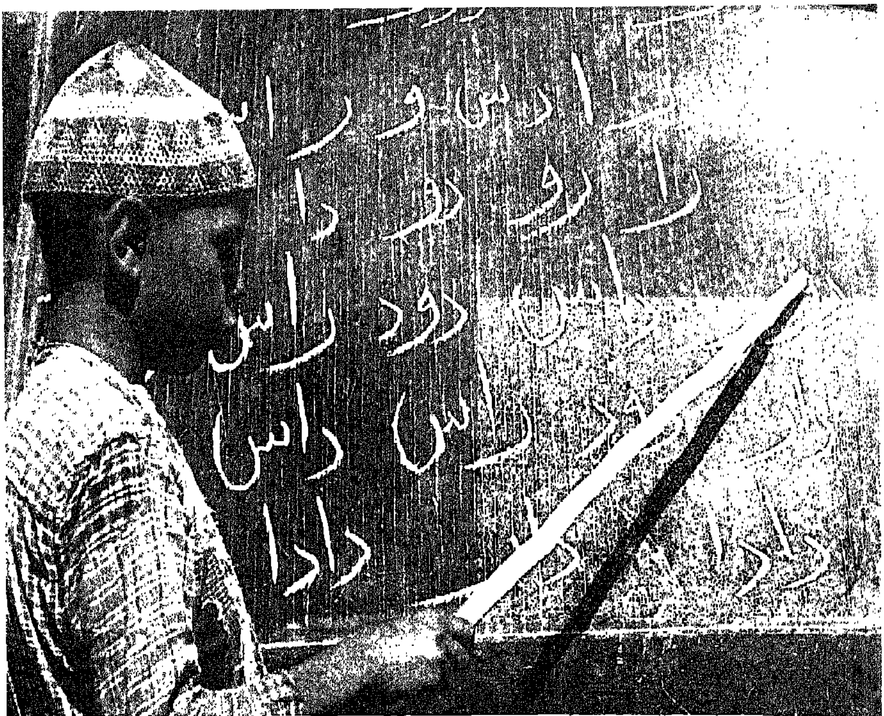
In *Latin* the students progress through the elementary study of the language to reading selections from Lucretius, Catullus, Vergil, Horace, Seneca, Ovid, and Martial.

Elementary *Greek* is followed by the reading of Plato's *Apology* and Euripides' *Hippolytus.*





Above: The Arab College, Jerusalem, Palestine. (Photo by Schwartz. Courtesy of Public Information Office, Government of Palestine.)
Below: The Kadoorie Agricultural School (Arab), Tulkarm, Palestine

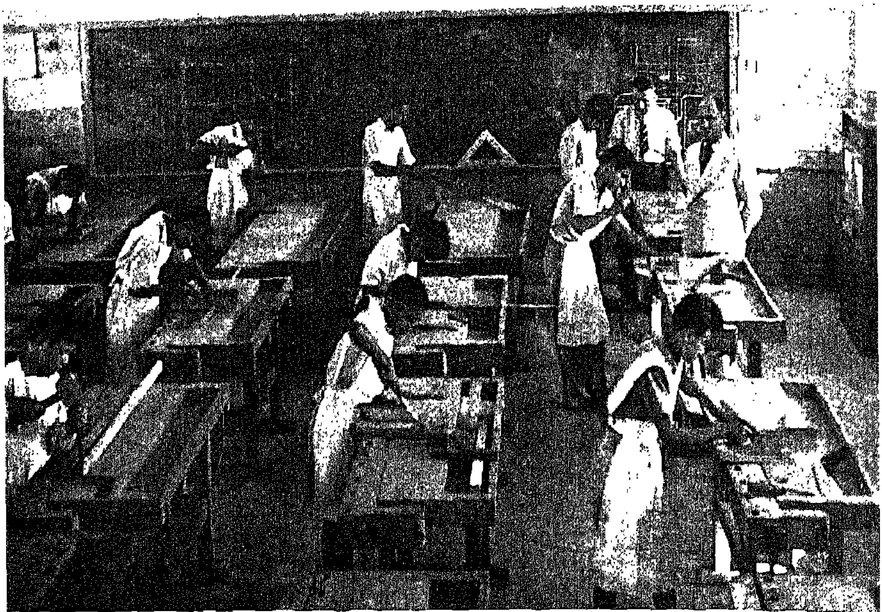


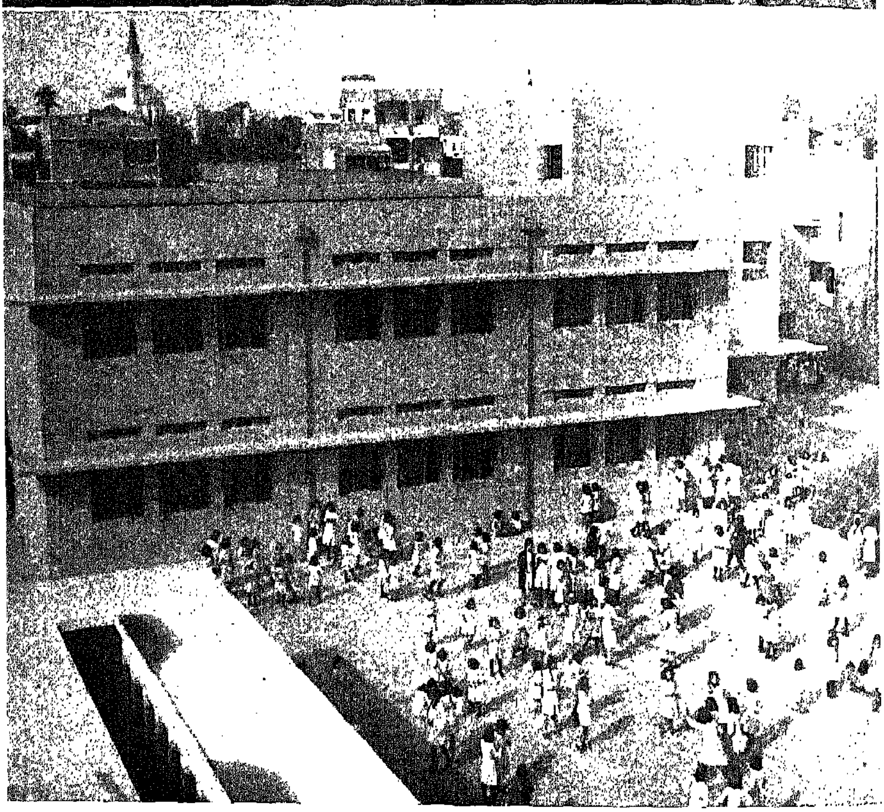


Above: Arab boy at blackboard in a primary school, Palestine. (Photo by Schwartz, Jerusalem.)
Below: A Government village school (Arab), showing part of the school garden, Palestine. (Photo by Schwartz, Jerusalem.)



Between Classes at a Government Village School (Arab), Palestine





Above: A class in industrial arts, Government secondary school for boys (Arab), Jaffa
Below: Recess at the Government primary school for girls (Arab), Jaffa

Although the *history* program emphasizes Arab history in its proper chronological order, it takes up ancient, medieval, modern, and English history in successive years.

Geography, which is correlated as much as possible with history, deals with sea basins, their coasts and hinterlands rather than with land masses.

Postmatriculation Study

Qualified students are provided with two years of postsecondary study at the Arab College and at Rashidiyah School (both in Jerusalem), the course being divided into literary and scientific sections. At the Arab College all postmatriculation students study Arabic language and literature, English, theoretical and practical pedagogy, logic, philosophy, hygiene, the elementary-school syllabus, and manual training. In addition, literary-section students take special courses in history, Latin or Greek, and philosophy, and those in the scientific section take pure and applied mathematics and the history of science. After this two-year program the student is prepared to teach in the elementary and lower secondary schools of Palestine or to proceed to English universities, Egyptian universities, or the American University of Beirut. The program at the Rashidiyah School omits professional preparation of teachers and includes premedical and pre-engineering subjects. In 1945–46 the Arab College had 19 students enrolled in its postmatriculation course, Rashidiyah School, 26; total enrollment for each school in that year was 88 and 310 respectively.

The Teachers Training College for Women, in Jerusalem, provides a fifth year of professional training for teachers after the four-year secondary course. Fifth-year study includes psychology, principles of education, history of education, methods of teaching the different elementary-school subjects and review of the subject matter of such subjects, and practice teaching. The total enrollment of the College in 1945–46 was 104 girls, 15 of whom were registered in the fifth-year course.

The Rural Training Center for Women,[7] at Ramallah, originally a three-year course above the elementary school, was to add a fourth year in 1946–47. Tuition and board are free, though a small fee is charged for school activities. Pupils are accepted from all parts of Palestine. In 1945–46 the total enrollment was 35. Each year the girls study the following subjects at increasingly higher levels: Arabic and English language and literature, mathematics, history, geography, science, hygiene, child welfare, religion, agriculture, drawing, sewing, theoretical and practical

[7] Not of postmatriculation standard but included here because it is a parallel institution in function.

housecraft, cooking, laundry, physical training, and singing. In the second and third years the program includes psychology and methods of teaching. It was planned that the fourth year, which had not been introduced at the time of the American Council Commission's visit, would provide professional training, history of education, special methods of teaching elementary-school subjects, and practice teaching, as well as additional work in academic fields. In this school the practical aspects of subjects are emphasized, and special attention is given to agriculture and poultry-raising.

Nursing Education

Training for nurses is provided for both Arab and Jewish girls under government auspices in seven government hospitals and seven mission hospitals. Instruction in the government hospitals is in English, and ability to speak, read, and write English is the only academic entrance requirement, although girls are expected, but not required, to have completed the elementary-school course. The nursing course is three years in length. The nursing profession has not developed any great popularity in the country, and applicants are few in spite of the fact that students receive a small stipend in addition to maintenance. Only 18 girls were in training in 1945–46 in the Government Hospital in Jerusalem. The training is largely practical, with five hours a week devoted to lectures. There are lectures on principles and practices of nursing each year. In addition the first-year program includes anatomy, physiology, and hygiene; the second, anatomy, physiology, infectious fevers, spread of infection, tropical diseases, and bacteriology; and the third, medicine, surgery, obstetrics and gynecology, and infant and child care. A fourth year provides opportunity to specialize in midwifery, mental diseases, child welfare, or ophthalmology.

Vocational Training for Boys

The Haifa Technical School has had an interrupted career. The physical plant, relatively well equipped and with sufficient land for expansion, was established in 1936. Almost immediately, however, all facilities were taken over by the military during the disturbances of 1936–39 and were retained during World War II. The School was returned to the Department of Education in 1945. All pupils are boarders. They pay a total fee of £P12 ($48) a year for tuition, board, room, and laundry. The study program includes Arabic and English languages and literatures, technology and trade theory, freehand and mechanical drawing, workshop mathematics, science, and workshop practice. The course is three years in length, each year having

forty-five periods per week. Workshop practice consumes eighteen periods the first year, twenty-seven the second, and thirty-three the third. Boys are selected on a basis of class standing in the elementary school and a personal interview by the director of the Technical School. Approximately one-sixth of those considered acceptable in terms of their elementary-school record were approved for admission in 1945. The School offers elementary trade training in fitting and machinery, carpentry and joinery, blacksmithing and welding, and automobile repair and maintenance. There were plans to extend the program to include training of electricians and builders. It is expected that graduates will eventually reach the foreman status in industry. Of recent graduates about one-third are working in the oil refinery, one-third in War Department workshops, and the remainder are teaching or are in private employment.

TRAINING IN AGRICULTURE

The Kadoorie Agricultural School at Tulkarm provides a two-year course for Arab boys who have completed two years of secondary school; at the time of the visit of the American Council Commission in 1946 it provided a third year for training men teachers of agriculture, but the teacher-training course was subsequently discontinued. The School was occupied by military forces during the disturbances of 1936–39 and World War II, and some parts of the School farm had not yet been released in the spring of 1946. Originally under the government Department of Agriculture, the School was transferred in 1944 to the Department of Education. It was planned to convert the general course to a three-year program, with a fourth year for teachers, beginning with 1946–47. In 1945–46 the first-year program included botany, chemistry, physics, zoology, physiology, Arabic, English, agricultural mathematics, horticulture, vegetable-growing, agriculture, poultry-raising, animal husbandry, agricultural economics, and drawing. Second-year students took field and fodder products, farm management, cooperatives, animal husbandry, plant protection, soils and fertilizers, irrigation, drainage and terracing, botany, horticulture, vegetable-growing, chemistry, surveying, bookkeeping, and poultry-raising. The year of professional training for teachers consisted of general methods of teaching, classroom management, model lessons, drawing, study of the syllabus of the elementary school, methods of teaching agriculture, and practice teaching. Five afternoons a week are devoted to practical agriculture in each of the three years.

In 1945–46 there were 11 in the class for teachers and 51 in the first two classes. All pupils are boarders and are selected on the basis of their

records in the secondary schools. In 1945–46 it was necessary to refuse admission to two-thirds of the qualified applicants because of lack of accommodations. Total annual fees amount to £P24 ($96), but approximately 30 percent of the pupils are exempt. The school has 150 acres of land, 110 of which are being farmed. Of the 27 graduates in 1945, 23 are teaching, 1 is employed by the Department of Agriculture, 2 had formed a partnership to operate a dairy, and 1 was unemployed in 1946. It was reported that out of a total of 120 graduates, only 2 were working as agriculturists. The small number engaged in farming is attributed to the difficulty in raising capital to purchase land and equipment.

Law Classes

Aside from the two-year courses of postmatriculation study at the Arab College and at Rashidiyah, the only opportunity for higher public education is provided in the Law Classes, which are administered by a board of fourteen members called the "Law Council." The council is responsible for appointing examiners, forming a disciplinary court for lawyers, approving credentials of foreign lawyers, and registering Muhammadan law counselors.

The course is five years in length, with examinations at the end of the second, fourth, and fifth years. Applicants with a London or Palestine Matriculation Certificate or the Secondary-School Certificate with credit in five subjects or the equivalent are admitted. Some officials of the police department, general administration, and courts are admitted on the recommendation of their department heads and without the minimum requirements; however, such students must pass the matriculation examination before they are permitted to practice as lawyers.

Classes are held from five to eight in the evening, four nights a week. Fees are £P12 ($48) a year. In 1945–46 there were 553 students enrolled, including 20 Jewish girls. Lectures are in English, Arabic, and Hebrew. Subjects studied in the first two years are civil law, criminal code, jurisprudence, law contracts, constitutional law, Ottoman land law, law of religious endowments (*waqf*), political science, and religious (*shari'ah*) law (optional). Third- and fourth-year students take law of evidence, commercial law, private and public international law, law of torts, forensic medicine, and legal history. Successful candidates in the intermediate examination, given at the end of the fourth year, are permitted to work as solicitors, but are not permitted to plead before the courts. The Diploma examination at the end of the fifth year is on civil and criminal procedures, Palestinian ordinances, legal drafting, and bookkeeping. Graduates must

practice with a lawyer for two years before being permitted to plead before the courts.

Private and Foreign Schools

Since private schools for Jews are part of the Hebrew system, they are included in the description of that system and will not be discussed here. Private schools, whether for Jews, Christians, or Muslims, may be classified as "assisted" and "nonassisted" schools.

In 1942–43, the latest year for which detailed statistics were available, there were 236 private schools, Muslim and Christian, enrolling 20,334 pupils—13,071 boys and 7,263 girls—which were receiving small grants-in-aid from the government. There were 322 schools with 20,141 pupils—11,942 boys and 8,199 girls—which did not receive aid. Most of the unaided schools were kindergartens and elementary schools, and those of Christian denominations were in the majority. Private schools have considerable freedom to develop their own programs, but tend to follow the government pattern quite closely, since most private-school pupils prepare for the government examinations. Increasingly, however, foreign-school pupils are substituting the London matriculation examination for the Palestine examination.

Most private and foreign secondary schools include elementary classes, and foreign schools usually begin a foreign language (the native language of the country of origin of the founders) in a lower grade than is the case in government schools. In many of the foreign secondary schools this foreign language becomes the language of instruction for much of the work in the upper grades.

Foreign schools have been established by missionary groups of many nationalities including British, American, French, German, and Russian. Usually they were started to emphasize religious education, but some, such as the Syrian Orphanage, were started to provide practical training in preparation for earning a living in a trade. The contribution of both private and foreign schools has been significant. Limitations of time made it impossible for the American Council Commission to visit many examples of either type.

The Friends Schools for boys and girls at Ramallah are providing a somewhat freer type of education on an American model. Buildings and grounds are designed for school activities. The programs of the schools follow the government plan, but instruction in most of the classes of the secondary school, other than Arabic, is in English. Many of the students are preparing for advanced work in the American colleges at Beirut. Work

in the boys school begins with the fifth grade of the elementary school and ends with the fourth year of the secondary. Boys in grades one through four are taught in the school for girls. The girls school had, in 1946, a kindergarten, seven elementary grades, and three years of secondary school. There were 95 boarders in the girls school, 3 of whom were from Ethiopia, while the boys school had 100 boarders. A number of the boarders in each school were from Transjordan.

The Terra Sancta College for boys in Jerusalem is administered by American Franciscans. It has a kindergarten, seven elementary grades, and four secondary years. In 1946 there were 335 boys in the kindergarten and elementary school and 170 in the secondary school. The building, erected in 1926, was constructed for use as a school and is well equipped. Instruction is in Arabic in the elementary school and in English in the secondary school. French and Hebrew are offered in addition to the government program. The school prepares boys for the Palestine matriculation examination, which they usually take in English. The majority of the boys are Christians, but a considerable number of Muslims and Jews are also enrolled.

The Najah College at Nablus and the Rawdat al-Ma'arif in Jerusalem are two private schools which the American Council Commission visited. Both are schools for boys and offer kindergarten, seven years of elementary school, and four years of secondary. They have boarding departments with approximately 100 boarders each. Instruction is in Arabic, and emphasis is placed upon the literature and history of the Arabs and the Muslim religion. They were established, partly, at least, to provide an alternative opportunity to the foreign missionary schools. Their objective is to provide education of a high standard for leaders with strong national aspirations.

Two more agencies provide educational opportunities on a more informal basis. The Young Men's Christian Association in Jerusalem has a beautiful physical plant, centrally located, which serves as a cultural center for Jerusalem. Excellent equipment is available for an extensive physical-activity program, and a large auditorium is popular for many types of activities. There were 423 public programs held in the auditorium in 1945. The facilities of the building are used by 125 different organizations. Classes are held in languages, including English at six levels, Arabic, French, Hebrew, German, Spanish, Russian, and Italian; matriculation classes in mathematics, physics, and chemistry; commercial subjects—shorthand, typing, and bookkeeping; lecture courses in art and modern history; music, with classes in fundamentals of music and a chorus; tutorial classes for adults, organized by Edwin Samuel; and a school for government

messengers. There are 1,900 members of the Association from thirty-four different national backgrounds. The second agency, the British Council, has institutes in the principal cities of Palestine where instruction in English and other matriculation subjects is given in the late afternoon and evening. The Institute of Higher Studies in Jerusalem, also sponsored by the British Council, prepares students for the London intermediate examination.

The Department of Social Welfare of the government of Palestine supervises education and care of children and young persons in 28 institutions for Arabs enrolling a total of 1,940 pupils, and 102 institutions for Jews having a total of 5,136 pupils. Approximately 40 percent of the pupils in both Arab and Jewish institutions are girls. The institutions for Arabs provide for social cases (delinquents), orphans, and physical defectives (largely the blind) and are administered by voluntary societies, religious bodies, and by the government. A relatively small number of the pupils (136) receive their education in schools outside the institutions. The institutions for Jews provide for social cases, immigrant children (mostly orphans), orphans, mental and physical defectives, and neglected children. These are maintained by voluntary lay and religious groups and societies, private individuals, the Jewish community (through the Vaad Leumi), and municipal agencies. Slightly more than one-third (1,731) of the children receive their education in schools outside the institutions.

Chapter 16

THE HEBREW EDUCATIONAL SYSTEM

MODERN HEBREW education in Palestine was initiated in the second half of the nineteenth century by European Jews who became interested in the welfare of Palestinian Jews, numbering about 25,000 at that time. Schools were founded by individuals, Jewish philanthropic societies, and, significantly, by Jewish national organizations that sprang up in tzarist Russia during the eighties and aimed at Jewish colonization in Palestine and the revival of the Jewish tradition there.

While most of these schools used the language of their founders' country, some—notably those fostered by societies of Russian origin, the Hovevei Israel and the Bilu, which were interested in bringing about a revival of the Hebrew language—began to teach school subjects in Hebrew. As Hebrew up to that time had been the language of religious liturgy and literature, but not that of everyday speech, its revival required considerable effort. Textbooks had to be written and terms for scientific concepts had to be coined before Hebrew could become the medium of instruction. It was natural that the advocates of teaching in Hebrew should sooner or later come into conflict with some of those who taught in the vernacular languages. Such a conflict, developing shortly before World War I, led to the foundation of a Jewish Board of Education (Vaad Hachinuch), which in 1914 assumed control of 12 schools in which all instruction was in Hebrew. Financial support was shared by Jewish settlers in Palestine and the Zionist Organization. From this nucleus the present Zionist school system developed.

At first only elementary schools were established, but in 1905 the world's first Hebrew secondary school, the Hertzliah Gymnasium, was opened in Tel-Aviv. Soon a second, the Hebrew Gymnasium, opened in Jerusalem, and in 1912 foundations were laid for the Haifa Technion.[1]

[1] Much of the information on the Hebrew educational system in Palestine is based on the following references: Executive of the Vaad Leumi, *Memorandum Submitted to the Commission of Enquiry into the Jewish Education System* (Mimeographed; Jerusalem: Vaad Leumi, 1945), pp. 1–4; Noah Nardi, *Education in Palestine, 1920–1945* (Washington, D.C.: Zionist Organization of America, 1945), pp. 17–19; Isaac B. Berkson, "Zionist School

After World War I and the promise of the Balfour Declaration to facilitate the establishment of a National Home for Jews in Palestine, the Zionist schools increased rapidly in number. Many schools controlled by other associations transferred to the Zionist Executive, which now established a Department of Education in Palestine. In 1918–19 Palestine had 94 Jewish schools enrolling a total of 10,172 pupils. Thus, it happened that the Zionist Executive assumed responsibility for the majority of Jewish schools in Palestine while the government took over administration of the Arab public-school system which had previously been maintained by the Ottoman government. Out of this situation developed Palestine's dual educational system.

In the early days of the mandate the Palestine government classed schools administered by the Zionist Executive with private schools and allowed them the small grants it allowed other private schools on the basis of 200 mils per pupil per year, a sum equal at that time to little more than a dollar. The Jewish community, however, claimed the right under Article 15 of the mandate to maintain its own schools in its own language and secured governmental recognition of the Zionist educational system as the Jewish public-school system. As a result the grant was substantially increased, to £E20,000 ($80,000) annually. In 1932 the Jewish school system was transferred from the Jewish Agency—which had taken over from the Zionist Executive—to the Vaad Leumi, the National Council of Palestine Jews. Thus, the main responsibility for the control and support of the Jewish public-school system, after it had been borne for some years by international Jewry, was assumed by the Palestinian Jews.

Administration

In theory the Government Department of Education has supreme authority over all education in Palestine; in practice the government has no direct administrative control over Jewish educational institutions. The Education Ordinance of 1933 authorizes the Government Department of Education to inspect and supervise schools, and the Department includes a Jewish Assistant Director of Education to advise the Director of Education on Jewish school matters and five (to be increased to seven) Jewish inspectors who may visit grant-aided Jewish schools. The government grants the Vaad Leumi Department of Education an annual lump sum for the support of Jewish public schools, and the Vaad Leumi controls the

System," in I. L. Kandel, ed., *Educational Yearbook of the International Institute of Teachers College, Columbia University, 1928* (New York: Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, 1929), pp. 177–79.

distribution. The Government Department of Education, empowered by the Education Ordinance to license teachers, rarely exercises this right with respect to Jewish teachers.

Actual responsibility for the Jewish public education system rests with the Vaad Leumi as the executive council of the Elected Assembly representing the registered Jewish community of Palestine (Kneseth-Israel). However, the Jewish Agency, which handed over that responsibility to the Vaad Leumi in 1932, declared that it would continue, as the representative of world Jewry, to share responsibility for the Jewish educational system in Palestine and to give financial assistance within the limits of its ability. Accordingly, the Jewish Agency makes a substantial annual grant to the Vaad Leumi and has one representative on the Executive Education Committee of the Vaad Leumi. In addition, the Zionist Organization of America, one of the Jewish Agency's most active sections in the Jewish National Home movement, maintains its own education committee, which concerns itself with Jewish education in the United States and elsewhere, including Palestine.

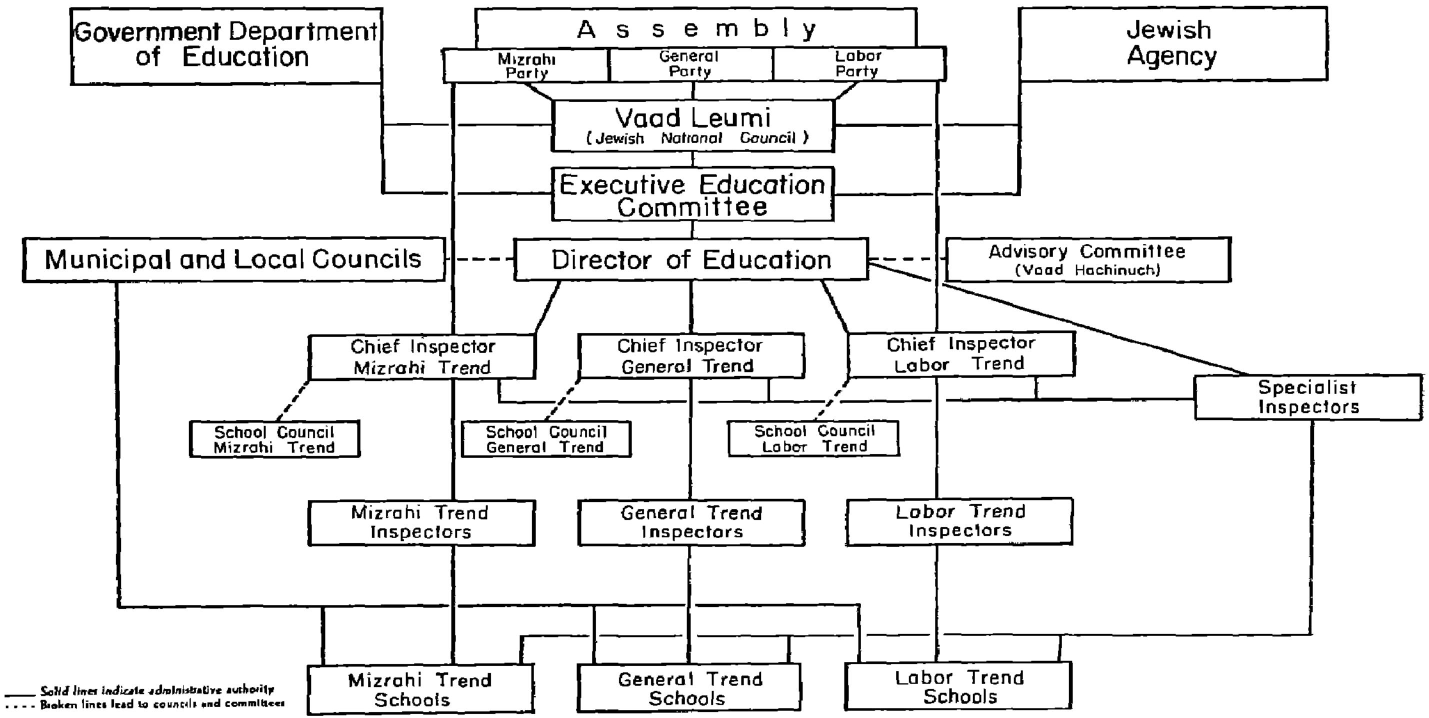
The administrative organization of the Jewish public-school system is shown in Chart VII. Supreme authority rests with the Vaad Leumi, which is responsible to the Elected Assembly representing Palestinian Jews. Three distinct parties are represented in the assembly: the General Party, a middle-of-the-road group; the Labor Party, the leftists; and the Mizrahi Party, composed of Orthodox Jews who have agreed to join the Zionist movement. It is important to bear these parties in mind, as the political divisions and ideologies within the community are reflected in the educational organization and in the curriculum of the school system.[2] Control of the administration is in the hands of three other bodies, the Executive Education Committee, the Board of Education (Vaad Hachinuch), and the Government Department of Education. In addition, there are three school councils—one for each of the political trends—and the local education authorities.

The Executive Education Committee of the Vaad Leumi consists of six members; three are representatives of the Vaad Leumi (one for each party or trend); one representative of the Jewish Agency; one representative of the Tel-Aviv municipality; and one representative of the central administration of the rural schools. A representative of the Government Department of Education is an advisory member, but he has no vote. This Committee decides all matters of policy and finance, but its important decisions, such as the approval of the budget and the appointment of the Director

[2] For further description of the differences between the schools, see p. 278.

Chart VII

PALESTINE: ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF THE HEBREW PUBLIC SCHOOL SYSTEM, 1946



of Education, are subject to the approval of the Vaad Leumi. The Director's appointment must be approved also by the Jewish Agency.

The Board of Education (Vaad Hachinuch) was formed in 1914 to administer Zionist schools, which had at that time begun to teach all subjects in Hebrew. Since its administrative functions were assumed by the Executive Education Committee (in 1932), its functions have been advisory, dealing with questions of curriculum, teaching, and purely educational affairs common to the three trends. It is composed of thirteen members including the Director of Education as chairman. Other members are: four from the General Trend, two each from the Mizrahi and Labor Trends, three from the Teachers Organization, one nominated by the Hebrew University, and one by the Executive Education Committee.

The Department of Education is the executive body responsible for conducting the school system. Its Director has the over-all administration and supervision of the Jewish public education system; appointed by the Vaad Leumi with the concurrence of the Jewish Agency, he answers to both bodies for carrying out their policies and those of the Executive Education Committee. The Director has three chief inspectors, one for each trend, who organize inspection within their trends and deal with school affairs therein, including appointment of headmasters, teachers, and inspectors subject to the approval of the Director. The chief inspectors have both administrative and supervisory duties and are in effect assistant directors. In another sense, however, they are more than assistants, for in matters affecting any one of the trends, the Director may not take action without first consulting the chief inspector of that trend. Conversely, the chief inspector may not take action without the approval of the Director. In cases of disagreement the matter is referred to the Executive Education Committee for decision. Decisions in matters affecting all the trends are made in a meeting of the Director and the three chief inspectors, and in case of disagreement the Director's decision prevails.

Each trend has, for the further protection of its interests, a school council made up of nine members, with the chief inspector as chairman. Members are appointed by the trend organization concerned. Aside from the chief inspector there are the three trend representatives on the Executive Education Committee and the Advisory Education Board, three teachers from schools of the trend, a representative of parents in urban areas, and a representative of parents in rural areas. Through their chief inspectors these councils submit recommendations to the Executive Education Committee for the appointment of trend inspectors and to the Director of Education for the appointment and dismissal of teachers. In addition,

they decide on curriculums to be used in the trend schools after securing the approval of the Advisory Education Board and the Director of Education.

The Vaad Leumi employs thirty inspectors, eight of whom are women. Six of the women are kindergarten inspectors, the other two are inspectors of special subjects. Of the twenty-two men inspectors, two are inspectors of secondary schools for the General Trend, thirteen are trend elementary-school inspectors, and seven are specialist inspectors. Trend inspectors visit only schools of their own trend, but specialist inspectors visit schools of all trends. The Mizrahi and Labor inspectors visit both elementary and secondary schools of their trends. The inspectors not only supervise teaching, but also make recommendations regarding teachers and principals and perform various administrative duties. There are no district inspectors. All inspectors report to the central office. The municipality of Tel-Aviv employs its own inspectors who function apart from those of the Vaad Leumi. The Government Department of Education has its own Jewish inspectors who visit Jewish schools regularly. Thus, there is a dual inspection system of Jewish schools.

It may be recalled that the Education Ordinance of 1933 set up procedures for creating local education authorities and empowering them to register land in their names for school purposes and to levy an education rate, or tax. In cities and villages of mixed population, two education committees may be set up, one for the Arab and one for the Jewish schools. The local Jewish authorities own most of their school land and buildings, and the number of such authorities levying local education rates is on the increase. Concerning other educational functions of the local authorities there is no standard practice. In Tel-Aviv, for instance, where the city pays most of the cost of education and receives a comparatively small grant from the Vaad Leumi, the local education committee exercises considerable authority, maintaining and inspecting schools and appointing and dismissing teachers with the approval of the Vaad Leumi Department of Education. However, in newly established small settlements, the community may furnish a school building, and the Vaad Leumi or the community may provide the teachers and pay them. In some communal settlements teachers who are members of the settlement are treated as other residents and receive no pay; in such settlements the school is usually an integral part of all phases of community life.

The general organization of the Jewish public-school system is marked by a good deal of flexibility. Local education authorities are taking an increasing share of responsibility, and the three trends enjoy considerable

freedom and, indeed, authority to recommend their own inspectors, principals, and teachers and to decide curricular matters. In contrast to the Arab public-school system, the Jewish system is rather thoroughly decentralized and allows freedom for individual and group initiative without much interference from above. Only on this basis was it possible, in the last twenty-five years, to induce the conservative Mizrahi and the leftist Histadruth (Labor organization) to bring their schools within the Jewish public-school system.

This system has not escaped criticism from various sources. Some Jewish educators, feeling that a more unified curriculum is desirable, regard with disfavor the reflection of factional differences in the schools.[3] The Government Director of Education stated his criticisms and recommendations in two messages addressed to the chairman of the Executive Education Committee of the Vaad Leumi.[4] His contentions are summarized in the following paragraph.

The three-party system prevents the Vaad Leumi Director of Education from being master in his own house. It is a wasteful system in which inspectors may inspect only schools of their own category and in which the effective voice in the appointment of teachers is that of the party councils whereas the teachers are supposed to be employees of the Vaad Leumi, which is responsible for their salaries and pensions. Moreover, teacher training under the three trends is not as efficiently carried out as it should be, and a sound financial policy for the system cannot be followed as long as trend councils, with or without connivance on the part of trend inspectors, open unnecessary schools and classes, financially committing the Government Department of Education to expenditures in excess of its funds. To quote the Government Director: "All important matters in the Department are decided by a committee of four persons, the Vaad Leumi director with three inspectors, each of whom owes primary allegiance neither to the director nor through him to the Vaad but to the 'category' which he represents. Unity has one certain vote only, and whatever the inspectors may feel about each other's distinctive views, two at least are almost inevitably supporters of separation." He contended that variation of the curriculum to suit the convictions of the three parties could be accomplished without prejudice to a unified and efficient system of administration, proposing an administrative cadre in which inspectors should be weaned from their party affiliations and in which sole responsible administrative authority in the central office would rest with the Director of Education and his deputy, subject to the instructions of the Executive of the Vaad Leumi. At the same time safeguards could be established to maintain the special character of the sectional schools.

[3] Nardi, *op. cit.*, pp. 235–44.

[4] Jerome Farrell, "Jewish Educational Administrative Reform," *Palestine Review*, Vol. IV, No. 35 (Jerusalem), March 29, 1940, pp. 431–35; *Memorandum of the Director of Education on Organization of the Hebrew Public School System, Delivered to the Chairman of the Vaad Leumi Executive Education Committee on 1st July, 1940* (Jerusalem: Government Press, 1940), 11 pp.

The Commission of Enquiry sent by the British Colonial Secretary to investigate the Jewish system of education in Palestine agreed in general with the views of the Government Director of Education. The Commission was headed by Sir Arnold McNair, a well-known English educational leader, and included among its four other members Sir Leon Simon, a prominent English Jew who stands high in Zionist circles. In its report the Commission deplored the fact that education, which in most countries is a unifying force, is in Palestine "separatist" in its effects. "The two main systems—the Jewish and the Arab, or Government, system—have no contact with one another."[5] Moreover, partisan influences within the Jewish system went beyond separatism in the form of the three trends and tended to develop "sub-trends within some of the trends. Recent history has shown the danger of enabling political parties to control or influence curriculum and teaching in the schools, and the Jewish public-school system stands in this danger today."[6] On the subject of administration, the Commission recommended a system of checks and balances created to satisfy mutual lack of confidence rather than one of individual personal responsibility. It considered that local education authorities, as a rapidly developing factor, should occupy a more prominent position in the administrative set-up. It made recommendations designed to weaken the influence of the trends and to strengthen that of the local authorities, and to put more effective control in the hands of the Director of Education.

Educational Finance

At the close of World War I the Zionist Organization bore the brunt of the cost of the Jewish system of education; in 1918–19 it paid £P65,844 ($273,376), or 88.7 percent, of the total expenditure on Jewish education, while the Jewish community together with other sources paid only £P8,348 ($33,392), or 11.3 percent. The sum paid out by the Zionist Organization increased annually until 1922–23, when the Palestinian Jewish community had recovered sufficiently from the war to increase its contribution to the support of the schools. From that point on the share of the Zionist Organization decreased. At about the same time the government began to contribute small sums toward the maintenance of the school system, gradually increasing the grants as the years passed. These facts are revealed in Table 43.

[5] Great Britain, Colonial Office, *The System of Education of the Jewish Community in Palestine*, Report of the Commission of Enquiry Appointed by the Secretary of State for the Colonies in 1945, Sir Arnold McNair, Chairman (London: H.M. Stationery Office, 1946), Colonial No. 201, pp. 6–7.

[6] *Ibid.*, p. 16.

TABLE 43

SOURCES OF INCOME FOR THE MAINTENANCE OF THE JEWISH PUBLIC-SCHOOL SYSTEM, PALESTINE, 1918–45*

Year	Zionist Organization (Jewish Agency)			Palestinian Government			Jewish Community and Other Sources			Total	
	£P	Dollars	Per-cent	£P	Dollars	Per-cent	£P	Dollars	Per-cent	£P	Dollars
1918–19..	£P 65,844	$263,376	88.7	...	...	...	£P 8,343	$ 33,372	11.3	£P 74,187	$296,748
1920–21..	113,539	454,156	77.0	£P 2,238	$ 8,952	1.5	31,796	127,184	21.5	147,573	590,292
1930–31..	75,271	301,084	40.8	19,175	76,700	10.4	90,177	360,708	48.8	184,623	738,492
1940–41..	35,000	140,000	6.8	56,000	224,000	10.9	421,500	1,686,000	82.3	512,500	2,050,000
1944–45..	116,760	467,040	7.9	127,082†	508,328	8.5	1,245,721‡	4,982,884	83.6	1,489,563	5,958,252

* Executive of the Vaad Leumi, *Memorandum Submitted to the Commission of Enquiry into the Jewish Education System* (Mimeographed; Jerusalem: Vaad Leumi, 1945), p. 63, except for 1944–45, figures for which are taken from Great Britain, Colonial Office, *The System of Education of the Jewish Community in Palestine,* Report of the Commission of Enquiry Appointed by the Secretary of State for the Colonies in 1945, Sir Arnold McNair, Chairman (London: H.M. Stationery Office, 1946), Colonial No. 201, p. 49.

† Includes £P55,000 ($220,000) cost-of-living allowances.

‡ Includes £P15,412 ($61,648) paid by the government as arrears from previous years.

From a position of virtual dependence upon the Zionist Organization for maintenance of its public-school system in 1918, the Palestinian Jewish community has, in the course of twenty-seven years, traveled a long way toward self-support in education. In that period it has increased its share from 11.3 percent of the total cost of education to 83.6 percent. The contribution of the Jewish Agency, although greater now than that of the Zionist Organization in the peak year of 1920–21, represents only 7.9 percent of the total cost, while the government's substantial grant constitutes only 8.5 percent of the total.

The 1944–45 contribution of the Jewish community can be traced to the following sources:

Sources	Contribution	
Vaad Leumi (general funds)	£P 4,000	($ 16,000)
Deficit to be met by Vaad Leumi Department of Education*	37,721	(150,884)
Local authorities and local Jewish Communities	556,000	(2,224,000)
School fees	584,000	(2,336,000)
Unclassified	64,000	(256,000)
Total	£P1,245,721	($4,982,884)

* Including £P16,412 ($65,648) arrears from previous years paid by the government.

The contributions of the local authorities and communities and the school fees provide the greater share. The fees, which constitute the largest item of all, are collected for every type of school, including the elementary, with the exception of the elementary schools in Tel-Aviv which are tax-supported and collect only a registration fee. The schools in the communal settlements charge no fees except to outsiders. Otherwise the elementary-school fees constitute from 25 to 32 percent of the elementary-education expenditure; and, in the elementary classes attached to secondary schools, 94 percent.

Both the Vaad Leumi and the Jewish community have protested the system's heavy reliance upon the collection of fees, especially in elementary schools, which in most civilized countries are free and tax-supported. The McNair Commission suggested that the burden of the fees for elementary education, now borne by individual parents, should be more generally distributed by rates collected by local authorities, and it commended the municipality of Tel-Aviv for the step it had taken in that direction.[7] However, the Jewish educational authorities argue that the fee

[7] *Ibid.*, pp. 50–51.

policy is necessitated by the inadequacy of the government's grants-in-aid,[8] and challenge the governmental allocation of funds between the Arab and the Jewish systems.

Allocation of expenditure within the Jewish public education system for 1944–45 was estimated as follows:[9]

Allocated to	Expenditure	
Central (Vaad Leumi) and local administration	£P 89,563	($ 358,252)
Kindergartens	150,000	(600,000)
Elementary schools	850,000	(3,400,000)
Secondary schools	270,000	(1,080,000)
Teachers colleges	40,000	(160,000)
Vocational schools	50,000	(200,000)
Continuation classes	30,000	(120,000)
Evening classes	10,000	(40,000)
Total	£P1,489,563	($5,958,252)

Further study of Table 43 on sources of income for the Jewish educational system reveals that the budget has grown to twenty times its 1918–19 size and ten times its 1920–21 size. This growth is attributable to three principal factors: (1) the rapid increase in Jewish population, largely the result of immigration, until it was in 1944–45 about ten times its 1918 figure; (2) the affiliation with the public-school system of a large number of schools that were formerly outside it; and (3) wartime inflation, which was mainly responsible for the trebling of the budget between 1941–45.

However, the budget of the Vaad Leumi Department of Education does not cover the entire cost of the schools for which it is more or less responsible. In fact, it was estimated that the budget actually provides £P340,000 ($1,360,000), or less than 25 percent of the estimated total cost for 1944–45, and that it receives most of this sum from the government Department of Education (£P127,082, or $508,328) and from the Jewish Agency (£P116,760, approximately $467,040), the rest of the income being derived from fees from schools (£P584,000, approximately $2,336,000), contributions by local authorities (£P556,000, or $2,224,000), the Vaad Leumi general funds (£P4,000, or $16,000), and miscellaneous sources (£P64,000, or $256,000). A deficit of £P37,721 or $150,884 was expected. The major portion of funds provided in the budget is handled by the local authorities.

For budgetary purposes, schools are divided into three categories: (1)

[8] Executive of the Vaad Leumi, *op. cit.*, p. 3; Nardi, *op. cit.*, pp. 227–33.
[9] Great Britain, Colonial Office, *op. cit.*, p. 49.

schools owned and supported by the Vaad Leumi—most of the public schools in Jerusalem, Haifa, Tiberias, and Safad, the Mizrahi teachers colleges in Jerusalem, and schools for workers' children in Tel-Aviv and Petah-Tikvah belong in this category; (2) schools nominally owned by Vaad Leumi but actually supported by local authorities, although the Vaad Leumi is the ultimate guarantor for the payment of teachers' salaries and makes grants-in-aid to the local authorities; and (3) schools owned and supported by newly founded settlements and receiving only minor grants from the Vaad Leumi, which does not guarantee salaries of the teachers—after a period of trial (usually not more than two years) these schools are transferred into category 2. There is an additional group of schools which are owned and maintained privately with no financial assistance from the Vaad Leumi, but which have affiliated themselves with the Vaad Leumi and are supervised by it.

The relative strength of these four categories of schools is indicated by pupil enrollment in each in 1942–43.[10]

Schools	Enrollment
Maintained by Vaad Leumi	10,630
Maintained by local authorities	36,340
Assisted	2,206
Private affiliated	17,563
Total	66,739

Relative expenditure of the categories—grouped somewhat differently—was as follows in the same year, 1942–43:[11]

Category	Expenditure		Enrollment
Vaad Leumi	£P138,000	($ 552,000)	10,630
Local education authorities	465,000	(1,860,000)	43,953
Private affiliated	217,000	(868,000)	12,156
Total	£P820,000	($3,280,000)	66,739

For the last few years the Jewish educational system has been operating on an increasing financial deficit, which in 1944 amounted to £P49,111 ($196,444). Moreover, the Jewish Department of Education has been obliged to borrow from the Teachers Pension Fund a sum which, with

[10] *Ibid.*, p. 47. Quoted by the McNair Commission from a report by A. Ulitzer and L. Kroner, presented to the Vaad Leumi, on the financial and administrative situation in the Jewish school system.

[11] Government of Palestine, "The Social Services," *A Survey of Palestine*, Report for the Anglo-American Committee of Enquiry (Jerusalem: Government Printer, 1946), chap. xvi, p. 669.

interest, totaled £P53,041 ($212,164) in 1943–44. In all, the Department's indebtedness came in that year to £P102,152 (about $408,000). At one time in the late twenties, teachers went without pay for as long as six months, and during the recent war failure to adjust teachers' pay to rising prices led to strikes which resulted in raising the salary scale of teachers throughout the system and increasing the financial burden of the Department of Education.

Jewish educational leaders have been urging the government to increase its grant to Jewish education to ease this financial strain. They have challenged the formula on which the government bases the apportionment of funds for the schooling of children between five and fifteen years of age. In 1945–46 it was estimated that there were about 300,000 Arab children as compared with about 100,000 Jewish children in this age group. The Jewish leaders argue that hardly more than a third of the Arab children are actually in school, while the Jews make every effort to approximate universal elementary education for their children, and that government grants should, therefore, take into account the number of children actually in attendance.

The Government Department of Education maintains that such a basis for calculation would be unjust to the Arabs, whose yearning for education remains unsatisfied because of inadequate budgetary provision. Thousands of Arab children are denied admission to primary schools yearly—10,079 in 1945–46—in localities that have schools. An unknown number do not apply for admission simply because no schools exist in their localities. There are instances of villages gathering contributions and building a school only to be told that no teachers are available because of budgetary limitations. Therefore, the government maintains that any additional sums available should go to provide places for Arab children who are being refused, and the Jewish system benefits in the meantime from the increased allotments in the ratio of Jewish to Arab children of school age.

The McNair Commission recognized the financial problem of the Hebrew educational system, admitting that the Jewish community bore a heavy burden of school fees in addition to taxes, but did not see its way to suggesting any amendment to the formula. Given the assumption that Palestine's paramount educational need is universal literacy, the Commission concluded, "the logical method of distributing the money available for education is to divide it between the two communities in the ratio of their school-age population." It went on to point out that the chief problem was posed, not by the formula, but by the inadequacy of the government's budgetary provision for education.[12]

[12] Great Britain, Colonial Office, *op. cit.*, pp. 51–58.

TEACHERS' SALARIES AND PENSIONS

The scale of salaries for Vaad Leumi teachers which was in force at the beginning of World War II classified elementary-school teachers into three groups with maximum and minimum monthly salaries as follows:

Elementary-School Teachers	Minimum		Maximum	
Teachers in grades one to four	£P 8	($32.00)	£P14.4	($ 57.60)
Graduates of teachers colleges	10	(40.00)	18.0	(72.00)
University graduates with training in education	14	(56.00)	26.0	(104.00)

With wartime inflation these salaries became inadequate, but financial difficulties of the Vaad Leumi Department of Education and its differences with the government Department of Education over the salary scale prevented adjustment of the salary scale until 1943–44, when a special wages commission, one member of which was a government representative, was appointed to draw up proposals for a new scale. The commission recommended raising the salaries of the groups of teachers to minimums of £P10, £P12, and £P16 and maximums of £P17, £P20, and £P28 respectively and increasing family allowances from £P1 to £P1.5 per dependent. In addition, it recommended a special qualifying examination to raise salaries of teachers of long service to £P24 instead of the customary £P20. Delay in the application of this new scale led to a teachers' strike at the beginning of the school year 1944–45. The strike lasted for more than a month and was settled by the acceptance of the recommended scale with an alteration in the maximum basic salary of graduates of teachers colleges (the largest group of teachers) to £P21 with a special allowance of an additional £P1 a month. Cost-of-living allowances were on the same scale as obtained for officials of Jewish national institutions. In addition, salaries for the previous year of 1943–44 were amended by a special grant of £P2 a month and a two weeks' salary plus family allowances. This scale was to be in force for the year in progress, 1944–45. For 1945–46 further amendment of the scale was made by raising the special allowance from £P1 to £P2 a month. As it now stands, the scale starts with an initial monthly salary for a teachers-college graduate of £P12 plus £P2 special allowance and leads to £P21 plus £P2 for a teacher of nineteen or more years of service. In addition, a married teacher gets £P1.5 for his wife and also for each child, so that a teacher of nineteen years or more of service who has a wife and three children receives £P29 ($116) a month. Additional cost-of-living allowances may reach up to £P16.218 ($64.87) for a teachers-college graduate who has a wife and two children.

Recent salary scales have been agreed to only on a year-to-year basis.

The Teachers Organization is pressing for a basic salary scale of £P15–£P30 plus family allowances of £P2 for each dependent and a cost-of-living allowance equal to that of other employees of Jewish national institutions. The teachers are showing determination to be treated as other Vaad Leumi officials are treated, and it is probable that other revisions of the scale will result in yet higher pay, despite the deficit in the Vaad Leumi educational budget.

Secondary-school teachers have in general fared better than elementary-school teachers. The Vaad Leumi maintains no secondary schools; and owing to the fact that all secondary schools are private, fee-charging institutions, there is no standard scale for the teachers. Most schools, however, have accepted the demand of the Teachers Organization for a scale beginning with a basic salary of £P20 and rising to £P35, plus a family allowance of £P2 per dependent and a cost-of-living allowance of 50 percent of the salary if such an allowance is higher than the rate paid to officials of the Vaad Leumi.

A pension fund has been set up to which teachers contribute 5 percent of their salaries and the Vaad Leumi a matching sum. For the last few years, however, the Vaad Leumi has not only ceased making its own contributions to the fund, but also has been financially pressed into borrowing the pension deductions from the teachers salaries.[13] By 1943–44 the indebtedness of the Department of Education to the pension fund had mounted to £P53,041 ($212,164). However, it was making payments to pensioners out of its current budget, including cost-of-living allowances, and an actuarial study of the pension fund was being conducted with a view to establishing a solvent pension plan.

The Hebrew Educational Ladder

In the broadest sense, the Hebrew educational system in Palestine comprises kindergartens, elementary and secondary schools, teachers colleges, vocational schools, the Hebrew University, and the Haifa Technion, and, in addition, continuation evening classes for workers and elementary evening classes for underprivileged boys and girls who are obliged to work during the day. Some of these schools have affiliated themselves with the Vaad Leumi system and are subject to departmental inspection, while others maintain a strictly private character and have to rely largely on fees for support. It is only by taking account of the Hebrew educational institu-

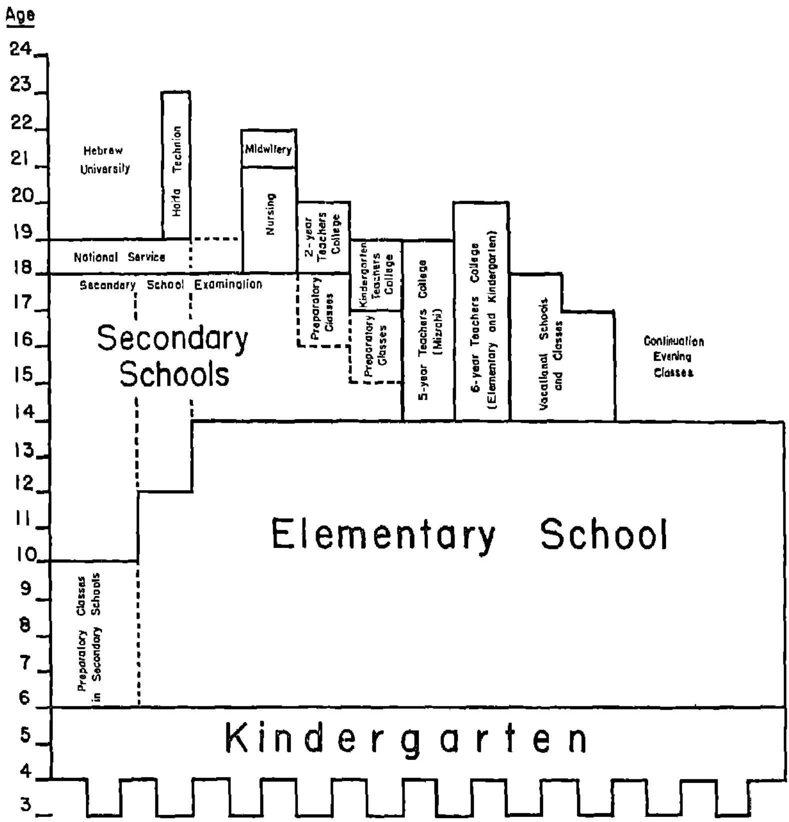
[13] *Ibid.*, p. 84, quoting the report by Ulitzer and Kroner on the finances of the Department of Education of the Vaad Leumi.

tions in all their variety that it is possible to give a meaningful picture of the educational ladder.

The ladder of Hebrew education is shown in Chart VIII. At the bottom is the kindergarten, usually a two-year course for children of four to six years of age, but sometimes accepting children of three, and at least one kinder-

Chart VIII

PALESTINE: HEBREW SCHOOL SYSTEM, 1946



garten in Tel-Aviv takes children of two. Kindergartens are neither maintained nor assisted by the Vaad Leumi Department of Education. Most of them are separated from elementary schools and charge fees that may run as high as £P30 ($120) a year. Tel-Aviv, some other municipalities, and communal settlements, however, maintain kindergartens and kindergarten classes in connection with elementary schools.

The fact that more than 17,000 children were attending Jewish kinder-

gartens in 1944–45 suggests the popularity of the kindergarten with the Jewish population. The number enrolled constitutes the great majority of children of kindergarten age in Jewish Palestine.

The combined length of elementary and secondary education is twelve years for children between the ages of six and eighteen. In general, the elementary school maintains an eight-year course, and the secondary school is of four years' duration. However, there are secondary schools which begin at fifth-grade level, maintaining the first four grades as a preparatory course, and a few which begin at seventh-grade level. Thus, there are three types of school organization—the 8-4, the 4-8, and the 6-6.

The pupil who finishes the eight elementary grades and is able to continue his education may enter either a secondary school, or one of the teachers colleges, or a vocational school.

To graduate from secondary school, the student must pass a combined school and external (Vaad Leumi Department of Education) examination, which will be described later. To the graduate Palestine offers further education in one of the Faculties (colleges) of the Hebrew University, in the Haifa Technion, or in a two-year teachers college. The Hebrew University and the Haifa Technion will not admit him, however, unless he agrees to spend at least six months in national service at the end of his course.

If the secondary-school graduate takes and passes the Palestine matriculation examination, he may enter the Law Classes in Jerusalem, for which the Vaad Leumi Department of Education examination is not recognized.

Vaad Leumi Examinations

The Vaad Leumi Department of Education, like the Government Department of Education, conducts a variety of examinations for the school system under its jurisdiction.

Scholarship examinations

In the last few years the Vaad Leumi Department of Education has been conducting scholarship examinations for graduates of elementary schools to assist superior students of no financial resources to continue school. Candidates are admitted to the examination upon recommendation of their principals if they have achieved an average of 80 or higher in their eighth-grade work. The examination is in Hebrew composition, the Bible, mathematics, and English. Students are ranked according to the total number of marks obtained in all four subjects, and scholarships are awarded to the top-ranking students.

SECONDARY EXAMINATIONS

Students completing their secondary-school studies take a combined internal and external examination: internal in that it is conducted within the school, external in that the questions are set and the papers read by committees set up by the Vaad Leumi Department of Education. Secondary-school inspectors, together with perhaps as many as sixty outsiders drawn from the Hebrew University, teachers colleges, and other sources, are grouped into subject committees, each with its chief examiner. Questions are usually set by the chief examiner, approved by the committee, and finally approved by the Jewish Director of Education. The examinations are held simultaneously in all the larger schools and in centers created for smaller schools. The papers for each subject are distributed among the members of the appropriate committee, each member reading his share, and the chief examiner rereading all.

The final secondary-school examination is in seven subjects, four being mandatory: Hebrew composition, the Bible, English, and mathematics. In addition, literary-course students take examinations in the Talmud, Hebrew literature, and history; and science students take examinations in higher mathematics, physics, and chemistry; students interested in biology may substitute it for physics. Certain schools require an additional paper in Arabic, French, economics, or Palestinography. At the agricultural secondary school at Pardes-Hannah, the examination in mathematics is taken at the end of the eleventh grade, while biology, chemistry, and agriculture examinations are held at the end of the twelfth.

The passing mark is 60 percent, but a student may pass with 50 in one subject—as long as it is not Hebrew. Those who fail in one or two subjects in the June examinations are given a chance to repeat those subject examinations at midyear. Results of the 1945 Hebrew secondary-school final examinations were as follows:

Section	Entered	Passed	Failed	Percentage Failing
Humanities	358	296	62	17.3
Science and biology	254	228	26	10.2

In addition to the final secondary-school examinations, the Department sets an earlier examination at the end of the tenth grade, consisting of three papers: in the Bible, Hebrew grammar, and English grammar. In schools recognized by the Department, the papers are corrected by the local teachers; in others they are read by the local subject teacher in conjunction with an external examiner appointed by the Department.

TEACHERS COLLEGE EXAMINATIONS

The Vaad Leumi Department of Education also examines students graduating from teachers colleges. In colleges providing a two-year course above the secondary school, students are examined in Hebrew composition, Hebrew grammar, education, and actual teaching. The passing grade is 60 except in Hebrew composition and actual teaching, in which it is 70. The examinations are more comprehensive in the colleges which accept elementary-school graduates and give five- or six-year courses: students are examined in Hebrew grammar, Hebrew composition, the Bible, English, history, literature, education, and practical teaching, and those planning to go to the Hebrew University must take mathematics also. Mizrahi teachers colleges substitute the Talmud for literature. Kindergarten teachers take additional examinations in hygiene, kindergarten theory, and psychology. The examining committees are composed of internal and external examiners with an inspector from the Department on each.

Expansion of Jewish Education

Tables 44 and 45 offer statistical summaries of the development of the Jewish educational system in the last quarter-century.

Table 44 gives an idea of the quantitative growth of the Jewish public and private schools, the number of pupils in them, and the number of pupils in non-Jewish schools. The public schools increased from 137 in 1920–21 to 651 in 1944–45, their teachers from 533 to 3,652, and their pupils from 12,830 to 79,441; in other terms, public schools multiplied 4.7 times, teachers 5.8 times, and pupils 6.2 times in that period. Since 1930–31 the schools have multiplied 2.8 times, teachers 4 times, and pupils 3.5 times. These figures show that there are on the whole more pupils per school than formerly. In the case of private schools, lack of figures for 1920 prevents comparison with that year; in 1922 there were 5,689 pupils in Jewish private schools. Compared with 1930–31, private schools have increased from 117 to 324, their pupils from 11,447 to 24,858 (1943–44 figures), and their teachers from 632 to 1,593 (1942–43 figures). Thus, schools have multiplied 2.7 times and pupils 2.1 times (4.4 times since 1922). The rate of increase in number of private schools has kept pace with that of the public schools, but in number of pupils it has fallen behind. The number of Jewish pupils in non-Jewish schools has doubled in fourteen years. No comparable number of non-Jewish pupils attend Jewish schools; the number fluctuated between 21 and 26 pupils a year between 1939 and 1943.

TABLE 44

Number of Jewish Schools, Teachers, and Pupils, Palestine, 1920–45, According to Type of Control*

Year	Public Schools			Private Schools			Jewish Enrollment in Non-Jewish Schools	Total		
	Schools	Teachers	Enrollment	Schools	Teachers	Enrollment		Schools	Teachers	Enrollment
1920–21	137	533	12,830	...	...	...	...	...	...	...
1930–31	230	897	22,533	117	632	11,447	725	347	1,529	34,705
1940–41	403	2,296	58,692	298	1,690	23,880	1,022	701	3,986	83,594
1941–42	437	2,367	62,807	309	1,693	23,961	1,277	746	4,060	88,045
1942–43	483	2,615	66,739	297	1,593	23,649	1,366	780	4,208	91,754
1943–44	579	3,324	73,104	324	...	24,858	1,478†	903	...	99,440
1944–45	651	3,652	79,441	...	...	...	...	...	...	...

* Statistics for the public schools, teachers, and pupils, from Executive of the Vaad Leumi, *Memorandum*, Appendix 8, p. 69. Those for the number of schools supplied by the Vaad Leumi Department of Education. Statistics for private schools and Jewish pupils in non-Jewish schools are taken from Government of Palestine, Department of Education, *Statistical Tables and Diagrams for the Scholastic Year 1942–43* (Jerusalem: Government Press), p. 25 except those for 1943–44 which were taken from Great Britain, Colonial Office, *The System of Education of the Jewish Community in Palestine*, Appendix II, Tables A and B, pp. 100–1, and from Government of Palestine, *A Survey of Palestine*, Report for the Anglo-American Committee of Enquiry (Jerusalem: Government Printer, 1946), p. 668.

† Includes a few non-Jewish pupils, probably no more than from twenty to thirty pupils.

TABLE 45

Number of Teachers and Pupils in Jewish Public Schools, Palestine, 1920–45, According to Level of School*

Year	Kindergartens		Elementary Schools		Secondary Schools		Vocational Schools		Teachers Colleges		Total	
	Teachers	Enrollment	Teachers	Enrollment	Teachers	Enrollment	Teachers	Enrollment	Teachers	Enrollment	Teachers	Enrollment
1920–21	127	2,713	305	8,368	63	992	10	532	28	225	533	12,830
1930–31	177	5,000	544	15,031	86	1,489	45	513	45	500	897	22,533
1940–41	228	6,211	1,569	44,818	382	6,307	39	539	78	817	2,296	58,692
1941–42	267	7,398	1,510	46,690	474	7,335	41	609	75	775	2,367	62,807
1942–43	308	8,485	1,638	49,181	528	7,846	47	603	94	624	2,615	66,739
1943–44	410	11,049	2,175	51,672	567	8,929	65	734	107	720	3,324	73,104
1944–45	469	12,490	2,422	55,471	613	9,527	41	1,067	107	886	3,652	79,441

* From Executive of the Vaad Leumi, *Memorandum*, Appendix 8, p. 69.

Totaling all categories of Jewish schools and pupils, there were, in 1943–44, 903 Jewish schools with 99,440 Jewish pupils in Palestine. The latter number represents 19 percent of the Jewish population of the country as compared with 22 percent in 1922. The principal reason for the steady increase in schools, teachers, and pupils is, of course, the growth of the Jewish population, chiefly by immigration. Whether the decline in the percentage ratio of school pupils to general population is due to a decline in birth rate or to a larger proportion of adults among the new immigrants, or to a lag in school attendance, or to a combination of all these factors cannot be determined. Secondary schools show the greatest expansion, with approximately a tenfold increase of teachers and pupils. Elementary schools are next with teachers increasing 7.9 times and pupils 6.6 times since 1920–21. Roughly speaking, kindergartens and teachers colleges show a fourfold increase, and enrollment in vocational schools has doubled. Most of the vocational-school enrollment is in private vocational schools.

TABLE 46

JEWISH PRIVATE-SCHOOL ENROLLMENT, PALESTINE, 1943–44*

Type of School	Enrollment	Percentage
Kindergarten	4,534	18.2
Elementary: grades one through seven†	13,163	52.9
Secondary: grades eight through eleven†	1,565	6.3
Teachers colleges, including twelfth grade†	329	1.3
Vocational	4,521	18.2
Special	746	3.0
Total	24,858	99.9

* Figures are from Government of Palestine, *A Survey of Palestine*, p. 668.

† Statistics for elementary and secondary schools and teachers colleges are not quite comparable with those of the Jewish public schools because the government uses a different classification from Vaad Leumi, counting the eighth grade as first-year secondary and including the twelfth grade with the teachers college.

Teacher increase has kept pace with enrollment in secondary schools and teachers colleges, so that the teacher-pupil ratio has not changed materially during the period covered. The lowest pupil-teacher ratio, 8, is in the teachers colleges, with that of the secondary school, 15.5, next. The increase in number of teachers in the elementary and vocational schools has outstripped enrollment, reducing pupil-teacher ratio from about 27 to 23 in the former and cutting it in half (from 50 to 26) in the vocational schools. In the kindergartens the increase in number of teachers has lagged behind the enrollment with the result that there are 5 more children per teacher, 26 instead of 21, than formerly.

Average class size has increased substantially in both teachers colleges,

20 to 34, and secondary schools, 24 to 31. The rise for kindergartens is more moderate—22 to 26. Elementary-school classes have stayed about the same on the average, while vocational-school classes have been cut drastically in size—an indication of less crowded conditions in workshops.

Enrollment in private Jewish schools in 1943–44 is shown in Table 46.

Private-school enrollment is about 25 percent of the total enrollment in all Jewish schools in Palestine. Kindergartens and vocational schools occupy a relatively higher position in the private than in the public schools, having 18.2 percent each of the total enrollment. Indeed, enrollment in private vocational schools is more than 4 times that in public vocational schools. Elementary-school enrollment is 52.9 percent of the total as compared with 59.8 percent in the public schools, while private secondary schools have only 6.3 percent as compared with 11.9 percent in the public secondary schools.

Chapter 17

THE JEWISH SCHOOLS AND THEIR PROGRAMS

THE DISTINCTIVE feature of Jewish schools in Palestine is the use of the Hebrew language as the medium of instruction in all subjects except English, French, and Arabic. At all levels much emphasis is given religious instruction and the background and development of Zionism.

As previously stated, schools of the Hebrew system are classified in three categories, or trends, in accordance with the party membership of the parents: General, Mizrahi, and Labor. These trends differ in educational, religious, and political ideals. Supporters of the General Trend believe that the spirit of the Jewish religious tradition should guide educational work, but that the observance of religious commandments should be left to the parents and home. The aim of the General-Trend schools is to give pupils a nationalist-Zionist education combined with progressive humanitarian ideals. About 53 percent of Jewish pupils are in schools of the General Trend. Schools of the Mizrahi (Orthodox-Zionist) Trend provide their pupils with a general education, but stress religious education. The children are taught to carry out the precepts of the Jewish religion, and all teachers are required to be Orthodox. About 24 percent of the pupils in the Jewish public-education system are in Mizrahi schools. Labor-Trend schools synthesize general national ideology and the principles of the Jewish labor movement in Palestine. Besides providing general and religious studies common to schools of all trends, Labor-Trend schools seek to inculcate a love of manual work in the children; many offer special training in handicrafts and agriculture. Much attention is given to developing knowledge and understanding of the history and philosophy of the labor movement in other countries as well as in Palestine, and also to creating an understanding of the importance of expanding Jewish activity to include work in the soil and in factories, and of counteracting the traditional overcrowding of commercial, banking, and professional fields. About 23 percent of Jewish public-school pupils are in these schools.

Kindergartens

In Jewish Palestine, where parents have come from such diverse cultures and backgrounds and speak so many languages, the kindergarten has special significance as a unifying force in the lives of small children. It bridges the gap between home and school and has been especially effective in accustoming children from homes where languages other than Hebrew are spoken to the language in which they will receive instruction for the rest of their school days.

There are kindergartens of every description, ranging from crowded rooms that are poorly equipped and inadequately ventilated in the old city of Jerusalem to well-arranged, extensively equipped modern institutions in Tel-Aviv. Some are little more than day nurseries which solve child-care problems for working mothers and may represent an improvement over the home environment of the child. The highest type is a model school used in training kindergarten teachers. Some kindergartens are attached to elementary schools; most of them are separate institutions. In 1944–45 there were 339 kindergartens associated with the Vaad Leumi Department of Education, with an enrollment of 12,490 children; other kindergartens not supervised by Vaad Leumi had an estimated enrollment of about 5,000.

In communal settlements, babies are placed in the nursery of the children's section (commonly called the "children's village") soon after birth to remain until their formal education is completed—normally at the end of the eighth grade. Parents are permitted to visit their children at certain hours each day, but the care and training of the children from birth to adolescence are provided by the trained personnel of the children's village.

Elementary Schools

Elementary education is not compulsory for either Jews or Arabs in Palestine. Although great effort is made to insure that all Jewish children have at least eight years of schooling, and the percentage of school-age children attending school is undoubtedly higher among the Jews of Palestine than among any other people of the six countries studied by the American Council Commission, it is estimated that there are about 3,000 Jewish children in Palestine who do not go to school. Most of these are in the oriental Jewish communities, principally in Jerusalem. In 1944–45 there were 269 Jewish public elementary schools with 55,471 pupils.

The lack of a compulsory-attendance law also results in curtailing school

life for many children, as is shown by the enrollment by grade in the public elementary schools for 1942–43 and 1944–45:[1]

Grade	Enrollment 1942–43	Enrollment 1944–45
A	9,025	9,863
B	7,953	9,082
C	7,037	9,567
D	6,131	8,511
E	5,601	7,228
F	5,261	5,952
G	4,921	4,957
H	4,219	4,596
Total	50,148	59,756

Eighth-grade enrollment diminishes to less than one-half of first-grade enrollment. This phenomenon is common to elementary education in all of the six countries studied. Normal retardation, of course, accounts for part of this decrease in number of pupils, but there is no doubt that the decrease is largely due to pupils dropping out of school for one cause or another. While it is impossible to analyze all factors that cause children to leave school prematurely, it is safe to say that the economic status of the family is a major factor, especially as fees are charged in most elementary schools.

In general, the elementary school maintains an eight-year course, with classes designated by the letters A through H in the Hebrew alphabet. As previously stated, schools of the Hebrew system are classified in three categories or trends in accordance with the party membership of the parents: General, Mizrahi, and Labor.

The elementary program of studies

Table 47 presents the program of studies for boys in General-Trend elementary schools.

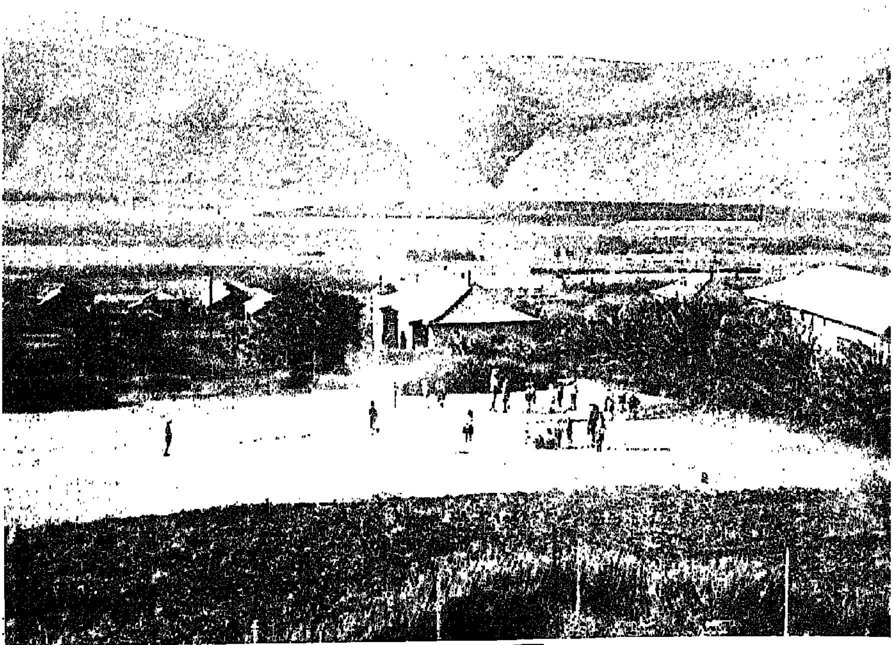
In girls schools the program includes three hours of handwork and sewing in each grade beginning with the third. Time for these subjects is obtained by slight reductions in time allowed for Bible, Hebrew, arithmetic, drawing and modeling, singing, and gardening. The Mizrahi schools for boys add two periods to the school week in grades five and six and three in grades seven and eight, and devote almost three times as many

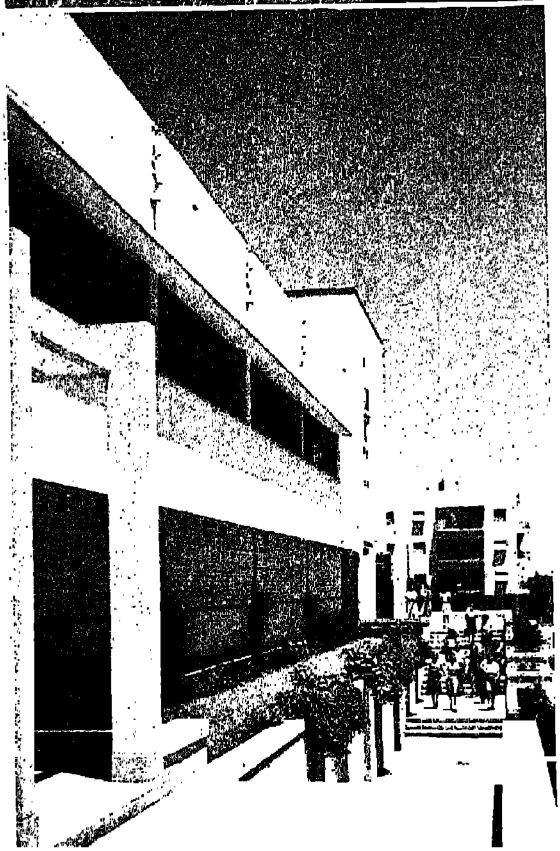
[1] Data for 1942–43 from Government of Palestine, Department of Education, *Statistical Tables and Diagrams for the Scholastic Year 1942–43,* pp. 14–15; data for 1944–45 supplied by Vaad Leumi Department of Education.





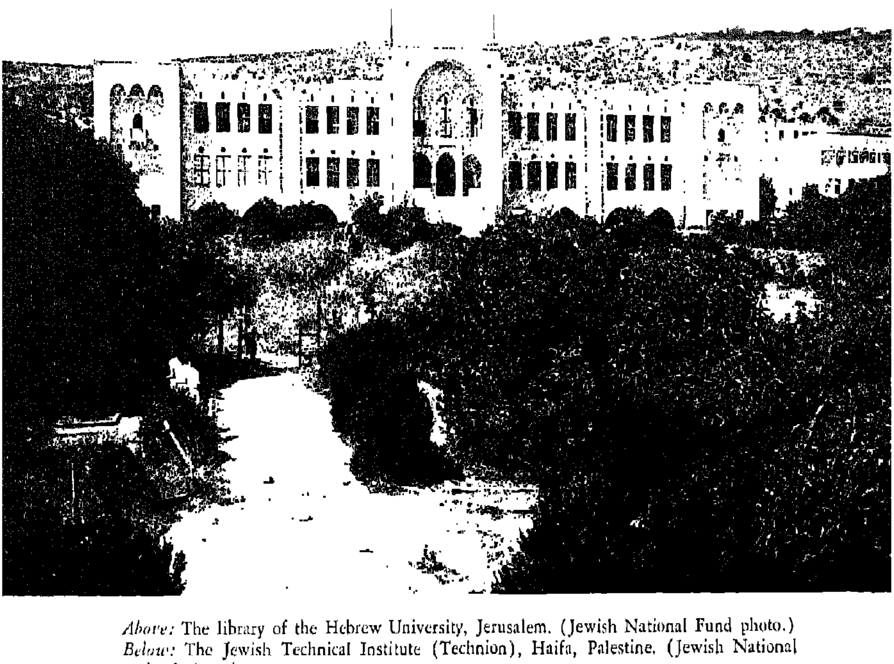
Above: Jewish school children planting trees during Arbor Day celebration, Beisan, Palestine. (Jewish National Fund photo.)
Below: A class out-of-doors in a Jewish colony, Tel Joseph, Palestine. (Jewish National Fund photo.)



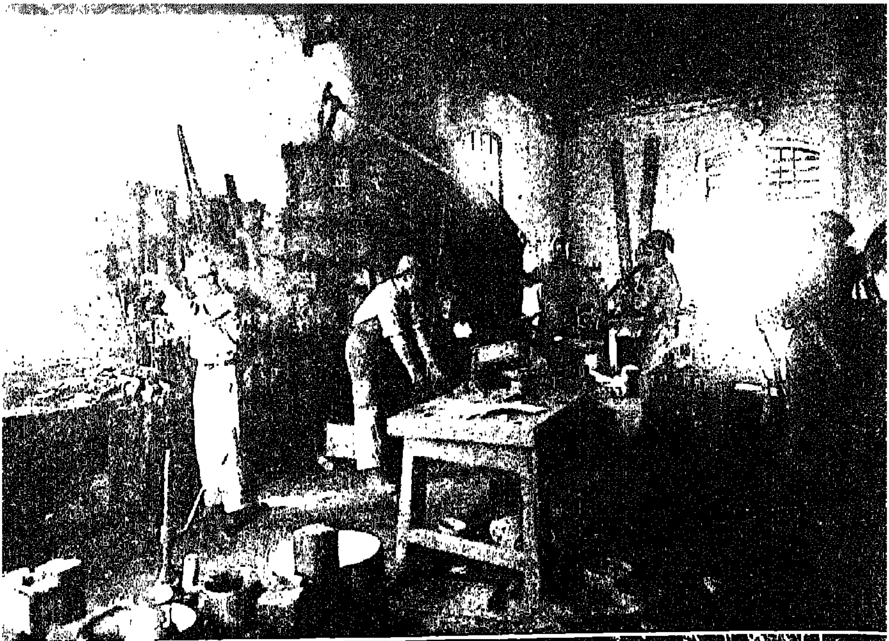


Above: The playground of a primary school in a Jewish colony, Palestine (Jewish National Fund photo.)
Below: The seminary for the training of Jewish teachers for schools of the General Trend, Tel-Aviv, Palestine. (Jewish National Fund photo.)





Above: The library of the Hebrew University, Jerusalem. (Jewish National Fund photo.)
Below: The Jewish Technical Institute (Technion), Haifa, Palestine. (Jewish National Fund photo.)





Above: A class in farm machinery repair, School of Agriculture, Mikveh Israel, Palestine. (Jewish National Fund photo.)
Below: A demonstration in a course in bee-keeping in a Jewish school, Palestine. (Photo by Schwartz.)

TABLE 47

PROGRAM OF STUDIES IN HEBREW BOYS ELEMENTARY SCHOOLS, GENERAL TREND, PALESTINE, 1945–46

Subject	Periods per Week							
	1st Grade*	2nd Grade*	3rd Grade	4th Grade	5th Grade	6th Grade	7th Grade	8th Grade
Bible	...	...	6	5	6	5	5	4
Hebrew	...	...	6	7	5	4	4	5
Mishnah	...	...	...	...	...	...	2	2
Palestinography: geography and nature study	...	...	6	4	4	4	4	4
History	...	...	...	...	2	2	3	3
Arithmetic	...	...	4	4	5	5	5	5
Drawing and modeling	...	...	...	2	2	2	2	2
Singing	...	...	2	2	2	2	1	1
Gardening	...	...	...	2	2	2	1	1
Physical training	...	...	2	2	2	2	2	2
English	...	...	...	...	5	5	4	4
Total	24*	24*	26	28	33	33	33	33

* Assignment of periods in the first two grades is determined by each school.

TABLE 48

PROGRAM OF STUDIES IN ELEMENTARY SCHOOLS OF THE LABOR TREND, PALESTINE, 1945–46

Subject	Periods per Week							
	1st Grade*	2nd Grade*	3rd Grade	4th Grade	5th Grade	6th Grade	7th Grade	8th Grade
Reading (literature)	...	...	7	7	4	4	3	3
Language (grammar, writing)	...	...	...	...	2	2	2	2
Ancient literature	...	...	...	...	...	...	1	1
Bible	...	...	3	4	4	4	3	3
Talk on social matters	...	...	...	...	1	2	2	2
Palestinography	...	...	4	2	1	...	...	...
Jewish affairs, Zionism, labor movement	...	...	...	...	...	...	1	2
Geography	...	...	...	...	2	2	2	2
Nature study	...	...	...	3	3	4	4	4
Jewish and general history	...	...	...	...	...	2	3	3
History of Culture and ancient history	...	...	...	1	1	...	...	...
Arithmetic and algebra	...	...	5	5	6	5	4	4
Physical labor: sewing, handwork, gardening, and farming	...	...	5	5	6	6	7	7
Drawing and modeling	...	...	2	2	2	2	2	1
Singing	...	...	2	2	1	1	1	1
Physical training	...	...	2	2	2	2	2	2
English	...	...	...	...	5	5	4	4
Total	29	29	30	33	40	41	41	41

* Assignment of periods in the first two grades is determined by each school.

hours to religious subjects as do schools of the General Trend. Mizrahi girls schools have the same number of hours in the school week as General-Trend schools for girls, but devote more time to religion.

Nearly all Labor-Trend elementary schools are coeducational, and the only differentiation made on the basis of sex in the program of studies shown in Table 48 is in handwork.

The Labor-Trend schools average slightly more than six hours above General-Trend schools in length of work-week, and the former devote less time to religion and much more to manual work.

The course of study for each trend is developed by a central education committee of the trend under the general supervision of the Vaad Leumi Department of Education. Subjects common to all schools follow, in general, the same course and use the same textbooks.

Palestinography, or study of the "Homeland," is stressed in all schools. The early grades study geographical features of home, school, and the immediate environment. Festivals, memorial days, and religious customs are discussed and celebrated. Communications, population distribution and characteristics, climate, location of offices of public services, plant and animal life of the vicinity, local history and legend, map-reading, and important characteristics of naturally defined areas of Palestine, are studied in detail. In more advanced grades a similar approach is made to the Arab countries surrounding Palestine and to the countries of the Mediterranean. This course is designed to develop an intelligent understanding of and a support for the Zionist ambitions in regard to a National Home in Palestine.

In *history,* major stress is on the activities of the Jews through the ages. Bible study begins with simple stories told or read in the first two grades and progresses to the more difficult books, including the study of commentaries in the higher grades. Mishnah includes the study of the sayings of religious leaders in the first few centuries of the Christian era. The course in Hebrew contains much study of religious literature.

Nature study is planned as a practical course. Much of the work is based upon direct observation, and there is correlation with the course in Palestinography. Attention is given to good health habits and to acquiring an understanding of the functions and care of the human body. Practical work in school gardens and on farms is correlated with the course in nature study, and there are frequent trips to points of educational significance.

To increase opportunity for practical *manual work* for boys without resorting to uneconomical shops in individual schools, handicraft centers have recently been established in Jerusalem. Boys in the upper grades of

various schools go to these centers for an entire morning or afternoon of work in wood or sheet metal. Sewing for girls provides training in making and repairing simple clothing. In the upper grades some attention is given to design, knitting, and embroidery for decoration of blouses and frocks.

In some schools, especially in localities of mixed population, the study of *Arabic* is introduced in the two upper grades. Spoken, rather than written or classical, Arabic is emphasized to provide the pupils with a basis of communication with Arab neighbors.

Although cooking is not named in the program of studies, it receives much attention of a very practical and effective kind. Instruction is provided in connection with the Hadassah (Women's Zionist Organization of America) school-luncheon projects started by Miss Henrietta Szold in 1925. Since 1939 they have been carried on by the combined efforts and support of the Hadassah and the social-service department of the Vaad Leumi. The primary purpose of the project was to provide hot lunches for needy and undernourished children, but the educational value appears no less important. Nearly every school that has an adequate number of pupils in the three highest grades to warrant the provision of a cooking teacher has its own kitchen where each day a different group of eight pupils—boys and girls in coeducational schools—work under the direction of the cooking teacher and prepare a school meal for from 150 to 250 fellow-pupils. The heavy work in the kitchen is done by paid workers. Notebooks of recipes and menus are kept by all pupils who work in the kitchen. Rotation of duty brings each group into the kitchen about once in every three weeks. Kitchen squad members are held responsible for making up all work missed because of absence from regular classwork. During their last three years in elementary school, pupils spend approximately thirty-six school days in the kitchen where, guided by the teacher, they acquire considerable knowledge of cooking. In addition, about half of the pupils are taught the theory of nutrition for an hour a week by the cooking teacher. More than 29,000 children are receiving a wholesome, balanced, and nourishing noonday meal. Some nonneedy children are permitted to have these meals on a paying basis. Schools which have no kitchens have meals sent in either from a nearby school kitchen or from one of the four central kitchens located in different parts of Palestine: these provide daily lunches for 8,300 children. Since 1940–41, the teaching of domestic science in centers equipped by Hadassah has been provided for eighth-grade girls. Girls in 24 schools are now receiving such instruction.[2]

[2] Much of the description of the cooking course is taken from a memorandum prepared by Mrs. S. Bavly, present director of the Hadassah school-luncheon project.

A special department of the Hadassah provides doctors and nurses who give annual physical examinations, provide treatments and medical care, give or assist with health instruction, and inspect general health and sanitary conditions in the schools. A milk project provides a daily glass of milk at very low cost during one of the recesses to every child in schools supervised by the Vaad Leumi. This special attention to the health of school children has paid dividends, especially in the marked drop in the incidence of trachoma.

There is great variety in the physical facilities of the schools. Some schools are housed in rented private dwellings, dark, poorly ventilated, and ill-suited to school purposes; others are in large, airy, attractive modern school buildings such as one finds in Tel-Aviv or in the settlements. City schools are crowded so that in some schools multiple shifts are arranged to provide space for all the children. In most settlement schools classes are small and physical facilities adequate. Newer schools in cities and settlements have space available for play areas and stress physical activity and development of healthy bodies. School furniture and equipment, especially in newer schools—except for certain shortages caused by the war—are, in general, adequate. Individual desks or tables and chairs are common.

In recent years a number of clubs have been formed to care for children of working parents. These children have quarters in school buildings or in rented houses under the supervision of leaders—frequently students in higher institutions. Provision is made for supervised study, games, handicrafts, and recreational reading, and a nourishing meal is furnished in the evening before the children go to their homes. Playing fields under the supervision of trained physical-education leaders provide additional facilities for healthful recreation. Summer camps provide similar accommodations in the holiday period.

To provide for boys and girls who are obliged to work for a living before completing their elementary education, evening classes have been established in the cities, especially in Jerusalem and Tel-Aviv. Such classes usually begin at six and continue until nine in the evenings. There is an intermission during which a meal which the pupils have helped to prepare is served. Approximately 1,600 boys and girls are taking advantage of this opportunity to complete an elementary course.

Secondary Schools

Secondary schools of the Jewish system in Palestine usually include a full elementary section, making a twelve-year program. The first four

grades are called a "preparatory section," and the secondary section has eight grades, its first grade corresponding to the fifth grade in an ordinary elementary school, and its fifth grade corresponding to the first year of the usual secondary school. Pupils who complete the eight-year elementary school may enter the fifth year of this eight-year secondary school, but it is reported that there are some difficulties in adjusting to the program. Some secondary schools are four years in length, admitting graduates of the eight-year elementary school. A recent tendency has been to classify the first six years of the twelve-year secondary school as preparatory and the last six as secondary, and to complicate things still further, at least one communal settlement central school (Mishmar HaEmek) has a five-year secondary program, based on principles of progressive education, above a six-year elementary school.

With the exception of one public secondary school recently opened by the Tel-Aviv municipality and not yet complete, all secondary schools in the Jewish system are independent and charge fees. There are 28 secondary schools affiliated with the Vaad Leumi and thus subject to its inspection. Twenty were classified as General Trend, 4 as Labor, and 4 as Mizrahi. Fees averaged £P28.5 ($114) in 1943–44, but are sometimes as high as £P55 ($220) per year. Many students are partially or totally exempted from fees. In recent years and at the suggestion of the Government Director of Education,[3] the Vaad Leumi Department of Education started giving scholarships of £P20 to worthy students who stand high in a competitive examination (the scholarships are discontinued if the student fails to maintain a high standing in school). About 400 students sit for this examination each year. These scholarships are for both secondary and vocational schools. The total number of scholarships awarded between the years 1942 and 1945 was 278, and in 1945–46, 120 were added to this number. These scholarships constitute the only financial link between the Vaad Leumi Department of Education and the secondary schools. With the exception of the scholarship students and certain students exempted from payment of fees by the schools, secondary-school pupils pay substantial sums for the privilege of attending school.

Of the 28 secondary schools affiliated with the Vaad Leumi Department of Education, 17 maintained preparatory classes. In 1944–45 secondary-school enrollment was 9,527 pupils, of whom 4,205 were in the lower eight elementary grades attached to the schools, and 5,322 were in the

[3] Farrell, *Memorandum of the Director of Education on Organization of the Hebrew Public School System, Delivered to the Chairman of the Vaad Leumi Executive Education Committee on 1st July, 1940* (Jerusalem: Government Press, 1940), p. 10.

upper four years of secondary school. The 15 private secondary schools not affiliated with the Vaad Leumi Department of Education had a total enrollment in 1942–43 of 3,169, with 1,796 enrolled in elementary and 1,373 in secondary classes. It may be said that of approximately 100,000 pupils in all types of public and private Jewish schools in Palestine about 7 percent are in the four-year secondary course.

The student has some choice of program in his final two years of secondary education. Most of the schools divide into literary and scientific sections at this point. Some are developing a biological section. One secondary school at Pardes-Hannah offers theoretical and practical training in agriculture, and Tel-Aviv has a commercial secondary school.

The program of studies of the Hertzliah Gymnasium (secondary school), founded in 1906, is given in Table 49. This school is reported to be the first modern Hebrew secondary school in the world. Its program is not presented as a typical program, but as an early attempt to harmonize the demands of Western academic training with the peculiar requirements of the Zionist program in Palestine. The program of the first four years is not included since it is similar to the program of the elementary schools of the General Trend.

The only exception to the general rule that all instruction is in Hebrew is the Evelina de Rothschild School for Girls, where instruction is in English.

Examinations which must be passed by secondary-school students have been described in chapter 16. Since the Palestine government does not recognize the Hebrew Secondary-School Certificate, it is necessary for students who wish to continue their education in the Government Law Classes to pass the Palestine matriculation examination and receive the Palestine Matriculation Certificate. In 1945 there were 115 Jewish candidates for this certificate, 28 of whom received it, and 44 who did not reach this highest standard were awarded the Government Secondary-School Certificate.

At the end of the secondary-school course all physically fit boys and girls spend a year in Jewish national service. This custom was established to relieve the labor shortage in the settlements and to provide the young with a practical introduction to life in the colonies.

Vocational Schools

Vocational education for Palestinian Jews began with the establishment of the Mikveh-Israel Agricultural School in 1870. This school was founded by the Alliance Israelite Universelles (a French organization for the extension and improvement of modern education for Jews throughout the world) to train Jewish agricultural workers for Palestine before the Jews

TABLE 49

PROGRAM OF STUDIES OF HERTZLIAH SECONDARY SCHOOL, TEL-AVIV, 1945–46

Subjects	Hours per Week													
	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year	6th Year			7th Year			8th Year		
						A*	M*	L*	A*	M*	L*	A*	M*	L*
Bible	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Talmud	2	2	2	2	2	...	2	2	...	...	2	...	...	4
Grammar	...	...	...	...	2	2	2	2	...	...	...	...	...	...
Hebrew	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6
General literature	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	2
Algebra and geometry	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	6	4
Physics	...	...	...	...	3†	2	2	2	2	5‡	2	2	5	1
Chemistry	...	...	...	...	...	2	2	2	2	4‡	1	2	2	...
History	...	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	4
Geography	2	2	2	2	...	...	2	2	2	2	2	...	3	2
Natural science	2	2	2	2	2	2	...	...	2	2	2	4	1	1
Drawing	2	2	2	2	1	...	1	1	...	...	...	...	...	...
Descriptive geometry	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	...	...	...
English	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6
Arabic or French	...	...	...	...	3	3	3	3	3	3	3	...	...	...
Music	2	2	2	2	1	...	1	1	...	...	1	...	...	...
Handicrafts	4§	3§	3§	3§	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Physical training	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
Soil science	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4	...	...
General agriculture	...	...	...	...	...	6	...	...	6	...	...	3	...	...
Total	33	33	33	33	34	36	34	34	36	36‡	35	36	35	36

* *A* refers to agriculture specialization, *M* to mathematical, and *L* refers to literary.
† Includes 1 hour of mathematical geography.
‡ Includes 2 hours combined laboratory, physics and chemistry.
§ Handicrafts include sewing, binding, carpentry, and horticulture.

had acquired a single agricultural settlement in the country. Instruction for the first fifty years was in French, but after World War I changed to Hebrew. Although fees are charged, nearly half of the students are exempted from half of all tuition. About 650 acres (2,600 dunums) of land given by the Turkish government provides opportunity for instruction, production, research, and experimental programs. At the time of the American Council Commission's visit (1946) approximately 450 students, including 250 refugees, were enrolled in the three-year course of the School. The regular course accepts boys and girls who have completed the eight-year elementary school or its equivalent. There is a special two-year course for students who have completed two years of the secondary school.

The first two years of the regular course offer a common training in general and technical subjects. Third-year students may specialize in field crops, vegetables, poultry, fruit trees, landscape gardening, nurseries, bee-keeping, dairying, or sheep-raising. In general, half of each day is spent in class and half in practical enterprises.

Other important agricultural schools for Jewish students are the Kadoorie School at Mount Tabor, founded with funds from a bequest of Sir Eli Kadoorie, a wealthy Baghdad Jew, an agricultural school for girls at Nahalal, and an agricultural secondary school at Pardes-Hannah. The last named offers a complete secondary-school education in addition to vocational education. In 1943–44 there were 17 agricultural schools for Jews in Palestine with a total of 2,019 students; some of these schools are of elementary-school standard.

There are 16 trade or vocational schools in the Jewish educational system, but only 9, with 1,067 students, are affiliated with the Vaad Leumi. Schools offering technical training are in Tel-Aviv, Jerusalem, Haifa, Safad, and other communities. These schools admit elementary-school graduates to a three-year course that allows boys to specialize in the metal trades, carpentry, building, and seafaring, and girls to specialize in domestic science, sewing and weaving, and commercial subjects. Most of these schools belong to the Labor Trend and are supported in part by the Histadruth, the Jewish labor organization.

The Max Pine Vocational School for boys in Tel-Aviv started as an evening school in 1928 and opened day classes in 1933. In 1945–46 there were 324 boys enrolled in its three-year course. The course is common in the first year, but in the second and third specialization is offered in fitting, electricity, and auto mechanics. In 1945–46 there were 57 third-year students specializing in fitting, 28 in electricity, and 18 in auto mechanics. There are evening classes to accommodate 300 apprentices. Approximately

half of a 45-hour week is devoted to general and theoretical work and one-half to shopwork. General subjects include Hebrew, history, sociology and demography of the Jews, mathematics, physical training, and hygiene. Of 313 boys graduated up to the time of the American Council Commission's visit, 158 were working in city factories in Palestine, 41 in settlements, 87 were in the army in technical jobs, 7 were studying engineering, and 20 were either dead or their occupations were unknown. The school is supported chiefly by tuition fees, but receives some income from the Histadruth, the municipality of Tel-Aviv, sale of its shop products, and a small grant from the Government Department of Education. Applicants are subjected to a battery of psychological aptitude tests used as a basis for admission and also as a basis for selection of specialization.

The Hadassah founded a similar school for girls in Jerusalem in 1942. A four-year course above the elementary school is provided for about 200 girls. They have a choice of three fields of specialization—cooking and domestic science, sewing (including arts and crafts, and weaving), and commercial training. The first graduating class (1946) was divided 11, 16, and 13 among these specializations. The school is housed in buildings formerly occupied by the Hadassah Hospital. Somewhat more than half of the school week—which is forty-two periods for sewing and domestic science specialists, and thirty-eight for those in the commercial course—is spent in vocational or technical subjects and practical work, the remainder on general subjects, which include Bible, English, Arabic—for commercial pupils—civics, gymnastics, and singing. This school is a unit in the Brandeis Vocational Center, which includes, in addition, the Julian Mack School and Workshops, a progressive elementary school for underprivileged children, the Vocational Guidance Center, and the Apprenticeship Training School (precision instruments). The Vocational Guidance Center is a service center for school children, working youth, and returning soldiers. General intelligence and performance tests are administered to individuals and groups, and professional guidance is given. A general testing program is administered to all eighth-grade children in Jewish schools in Jerusalem. The Center conducts entrance examinations for a school for backward children, two vocational schools, a school of nursing, a social-service school, and a secondary school. It is engaged in standardizing original and translated tests in Hebrew. A similar center has recently been established in Tel-Aviv.

Technical vocational training is provided in two schools for Jews at Haifa—one high school and one higher institution. The Technical High School offers three- and four-year courses above the elementary school in

metal-work, electrical work, auto mechanics, and woodwork, and a special two-year course is open to boys who have finished two years of secondary school. The school week is divided about evenly between general courses and practical work in the shops of the Haifa Technion, the higher institute of technology (described on page 295). The Nautical School trains navigators and marine engineers in a four-year course above elementary school. External examinations are administered under the auspices of the London Board of Trade. In 1945–46 there were 275 enrolled in the Technical High School and 90 in the Nautical School.

Nursing Education

Training of Jewish nurses takes place chiefly in Jewish hospitals, the largest of which is the Hadassah Hospital in Jerusalem. There are 4 Jewish training centers in Palestine, but the program of only one, the Henrietta Szold Hadassah School of Nursing, will be described here.

The course is three years in length for girls who have graduated from an approved secondary school or who hold a Matriculation Certificate or who have successfully completed a seven-year course in the gymnasium type of school. Instruction is in Hebrew, and a small tuition fee is charged, although students receive maintenance. The minimum age for admission is nineteen, and applicants are selected on the basis of a questionnaire, personal interview, and physical examination. Student nurses are exempted from the year of national service. Representatives of the school canvass graduating classes in secondary schools to recruit for the training program. In 1945–46 there were 87 girls training in this School of Nursing, distributed about equally among the three classes. The capacity of the school is 90, although this number was exceeded during the war years. The working day consists of two-and-one-half hours of lectures and class discussions and eight hours of practical work. Every effort is made to correlate the practical work with classroom work. Opportunities for specialization are provided in six-month graduate courses in midwifery, public-health nursing, and physiotherapy. External examinations for graduates are supervised by the Government Department of Health. The School of Nursing has the modern and extensive facilities of the Hadassah Hospital for practical work.

Teacher-Training Colleges

Of Palestine's 5 teacher-training colleges for Jews, 2 are for teachers in the General Trend, 2 for Mizrahi, and 1 for Labor. In 1944–45 the total enrollment in teacher-training classes was 886. Three of the colleges offer

five- or six-year courses above the elementary school. The first four years approximate the work of the secondary school and the additional years provide professional training. The other two colleges admit secondary-school graduates to a two-year course that is designed to give professional training and to extend the students' knowledge of Hebrew language and literature. Schools of the General and Labor Trends are coeducational; the Mizrahi Trend segregates its students. There are two special schools, a General Trend and a Mizrahi, and a special section of the Tel-Aviv Training College for the training of kindergarten teachers. Recently a preparatory class was added to the Beth HaKerem Training College in Jerusalem for the benefit of applicants from abroad or from the smaller schools of Palestine who have deficiencies to make up. The deficiencies are usually in Hebrew or English. Model schools for demonstration and practice teaching are attached to or associated with each of the training colleges. These teacher-training institutions of Jewish Palestine have assumed a much more important role in supplying teachers since Nazi persecution of European Jewry arose. Previously many, if not most, of the teachers in Jewish Palestine received their preparation in European institutions.

Final external examinations are a condition of graduation in all the teacher-training institutions. Students are examined in pedagogy, psychology, and hygiene and are required to teach model lessons before an external board of examiners. In addition, graduates of the seminary at Beth HaKerem are required to submit an essay on an educational subject. The preparation of this essay usually requires a year or more after graduation. In 1945 a study of the activities of all graduates of this institution from 1936 to 1945 showed that of 329 graduates, 226 were teaching or doing closely related work in Palestine, 44 were in the armed services, 6 were on leave from teaching, 20 had shifted to other occupations, 3 were dead, 24 had never taught, 2 were teaching in other countries, and the present occupations of 6 were unknown.

Higher Education

Above the secondary school and apart from teacher-training schools there are 2 institutions of Jewish higher education, the Hebrew University at Jerusalem and the Technion at Haifa.

The Hebrew University

Hebrew University, the capstone of Hebrew education for the entire world, was formally opened on April 1, 1925. The idea of such a university was first advanced by Dr. Hermann Schapira, professor of mathe-

matics at the University of Heidelberg, in 1882. Legal restrictions placed upon attendance of Jewish students at higher institutions in some eastern European countries helped to rally supporters for Dr. Schapira's idea. The foundation stone was laid in July 1918. Instruction began in 1923 with the establishment of a Chemistry Institute. Before the formal opening of the University in 1925, the Microbiological Institute and the Institute of Jewish Studies also were started. It was realized that a complete university of high standard does not spring up overnight and that it would be wise to limit first efforts to a few research institutes. Emphasis was placed upon research to solve problems of major importance in the development of the Jewish community in Palestine. These problems have been concerned with health, agriculture, irrigation, Jewish history, language and literature, sanitation, economics, and geology.

Increase in anti-Semitism, reduction in educational opportunities for Jews in Europe, and increased pressure from Palestinian Jews who desired higher education caused the authorities to inaugurate regular instruction for students. At present such instruction is provided in a Faculty of Humanities, a Faculty of Science, and a School of Agriculture. A Pre-Faculty of Medicine provides opportunities for postgraduate study and research, and in the near future it is expected to develop into a complete School of Medicine.

The Faculty of Humanities has three divisions—the School of Oriental Studies, the group of general humanities, and the department of education—and in addition, the Institute of Jewish Studies. The School of Oriental Studies offers three major subjects: Islamic culture, Arabic language and literature, and Semitic philology; and two minor subjects: archeology of the Near East and Egyptology. General humanities includes four major subjects: archeology, history, classics, and philosophy; and four minor subjects: Palestinian archeology, French civilization, Romance philology, and cultural sociology. The department of education gives courses in three principal subjects: principles of education, educational methods and administration, and psychology. The Institute of Jewish Studies provides for instruction in six major subjects: Hebrew philology, Bible, Talmud, Hebrew literature, Jewish philosophy and mysticism, and Jewish history and sociology.

The Faculty of Science offers instruction in seven major subjects: mathematics, physics, chemistry, biochemistry, zoology, botany, bacteriology and hygiene. Minor subjects are parasitology and geology, and additional lecture courses are given in meteorology, climatology, and physiology.

The School of Agriculture, in cooperation with the Agricultural Research Station of the Jewish Agency in Rehovoth, has a five-year course.

After studying principally natural sciences for two years in the University proper, the student spends a year in practical work in the settlements under the supervision of the Research Station and the last two years of the course at Rehovoth in specialized laboratory work.

The Pre-Faculty of Medicine offers advanced research opportunities to doctors in the following fields: bacteriology and hygiene, parasitology, physiology, pathological physiology, cancer research, hormone research, pathological anatomy, and, in cooperation with the Rothschild-Hadassah University Hospital, seven clinical subjects: internal medicine, surgery, pediatrics, obstetrics and gynecology, dermatology and venereology, ophthalmology, and X-ray and radiotherapy. The projected complete School of Medicine will include two years of premedical work, five of medical study, and a year or two of internship.

The University's four-year courses in the humanities and science lead to the Master of Arts and the Master of Science degrees. Candidates must satisfy examiners in one major and two minor subjects, presenting a thesis in the major subject and passing both oral and written examinations. The Ph.D. is granted to the holder of the master's degree in either field after two additional years of study. A special five-year course provided through cooperation of the Faculties of Humanities and Science and the department of education admits graduates of approved secondary schools in Palestine or equivalent accredited foreign schools and candidates who pass entrance examinations to become teachers in upper elementary and secondary schools. Successful completion of this course is recognized by a diploma. The department of education has a three-year graduate course for holders of the master's degree from either Faculty and upon completion of the course confers the Certificate of Pedagogical Studies. Tuition fees vary from £P20 ($80) in the Faculty of Humanities to £P70 ($280) in the Faculty of Science.

Hebrew University is located on the beautiful Mount Scopus site where extensive acreage is available for expansion. Buildings are planned to give maximum utilization for efficient study and instruction. The modern and well-equipped Hadassah Hospital is easily accessible to the students. The Jewish National and University Library, a collection of more than 400,000 volumes, is housed in a large modern building centrally located on the campus and provides extensive collections of botanical, zoological, geological, and archeological materials. The Museum of Biblical and Talmudic Botany and Jewish and Arab Plant Lore is housed in the large hall of the open-air theater.

All instruction, except in some aspects of the study of foreign languages,

is in Hebrew. The University has contributed heavily to the simplification and to the extension of vocabulary of the Hebrew language to meet modern conditions. The faculty, in 1944–45 consisting of thirty-seven professors, thirty-eight lecturers, twenty-three assistants, and sixty instructors, had been recruited from European countries, England, and the United States. The variety of points of view represented in the faculty has been productive of a unique organization and favors the development of a dynamic philosophy of higher education.

The Hebrew University is an independent institution administered by a board of governors representing the following elements: the Jewish community of Palestine, Societies of Friends of the Hebrew University throughout the world, the Zionist Organization, the Jewish academic world, and the University's principal financial supporters. Most of the money for capital and current expenses has come from foreign contributions. The direct administration of the University is the function of the Executive Committee, which consists of a group of men of public standing and experience in business, an administrative group appointed by the board of governors, and an elected group from the staff of the University. The chairman is appointed by the board of governors and is head of the University administration. The University president, elected by the board of governors, presides at the annual opening ceremony and at the graduation ceremony and acts as director of the Hebrew University Press Association. The administrator (chairman of the Executive) is the chief official of the University administration. Academic affairs of the University are in the hands of the senate, consisting of the professors and the representatives of lecturers and assistants. The rector, who is academic head of the University and represents it in all academic matters, is elected by the senate for a period of two years with the possibility of one re-election; he is chairman of the senate and of its standing committee and is an ex officio member of the Executive Committee. The Faculty of Humanities, the Faculty of Science, and the Pre-Faculty of Medicine have boards composed of the professors of each Faculty and all the lecturers who are engaged in teaching. The Faculty boards deal with all matters relating to instruction and particularly with the syllabuses.

In 1945–46 there were approximately 650 regular students registered at the University—350 in the Faculty of Humanities, 250 in the Faculty of Science, and 50 in the School of Agriculture. Since its founding the University has conferred about 500 master's and 50 Doctor of Philosophy degrees. The latest available analysis of the student body, made in 1940–

41, showed 72 percent to be men and 28 percent women. In that year more than half of the students had entered from secondary schools in which the language of instruction was not Hebrew, and about a third were graduates of Hebrew secondary schools in Palestine. The countries from which most students had come were: Poland, 20 percent; Germany and Austria, 18 percent; Czechoslovakia, 11 percent; Rumania, 6 percent; and Hungary, 5.5 percent. The average age of students was 23.64 years.

The Technion at Haifa

The Technion, Hebrew Institute of Technology, which was founded in 1912 but not opened until January 1925, is the only higher technical school in Palestine. In 1946 technical training was offered in civil engineering, architecture, industrial engineering (with specialization in mechanical or electrical engineering in the last two years), and chemical engineering. The four-year course admits graduates of secondary schools or holders of certificates of matriculation standard. Instruction in all specializations is in Hebrew. Diplomas with the degree of engineer are granted to candidates who pass an external examination which is set and marked by a board made up of government officials and representatives of the Jewish Agency and local professional societies. Questions and problems are selected by the board from a collection submitted by the teaching staff. The examinations are usually held in March of each year for students who completed their formal instruction the previous June.

The Technion is financed largely by tuition fees, although small grants have been made by the Palestine government and the Jewish Agency. Fees and income from property, workshops, and laboratories provide about 65 percent of the total budget. The annual tuition fee is £P45 ($180), plus an additional fee of £P5 ($20) charged for chemical engineering.

In 1945–46 the Technion (exclusive of the Technical High School and the Nautical School) operated on a budget of £P56,000 ($224,000). In that year the total registration was 459: 175 first-year students, 130 second, 105 third, and 49 fourth. Industrial engineering is the most popular course, with 208 students; civil engineering is next with 130. Extensive opportunities for practical training and research are provided in the fourteen laboratories and workshops of the Technion. A testing laboratory for building materials is used for instructional purposes but also serves the government departments and private construction firms. The workshops, which produce a variety of needed articles, contributed important products for the armed forces during World War II.

Other Hebrew Schools and Cultural Associations

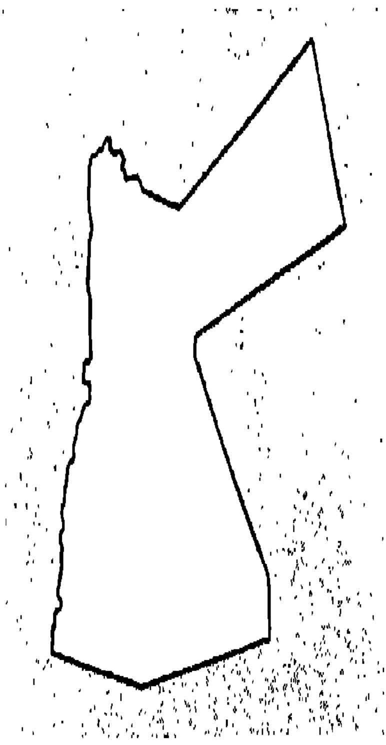
The Talmud Torahs, private schools which emphasize instruction in religion and private elementary education for religious leaders, are the most conservative and orthodox of Jewish educational institutions. The language of instruction may be Yiddish, Arabic, or Hebrew. In recent years some of these schools have received government grants and have reorganized on a more modern basis and raised their standards. In 1944 there were 73 of these schools with 8,234 pupils; 28 of these schools (enrolling 4,826 pupils) were receiving government grants. Such schools are comparable to the Muhammadan *kuttabs.*

Art and music education for relatively small groups is provided by art schools and conservatories in Jerusalem and Tel-Aviv. Dramatic arts are encouraged by the Habimah Theater, a cooperative society of actors, and the Ohel Theater. The Matate, a satirical theater of the European type, engages in candid commentary on social and political problems touching the Jewish community. The Art Theater of the Kindergarten Teachers Society brings the drama to the educational system.

A notable Jewish cultural institution is the Palestine Symphony Orchestra, which is managed by the Palestine Orchestra Trust and employs some seventy musicians. From time to time it has been conducted by some of the world's greatest conductors. The Palestine Folk Opera produces works of both Jewish and non-Jewish composers. Other organized bodies of note are the Palestine Oratorio Society, the "Music for the People" Association, and the choir of the Great Synagogue in Tel-Aviv. There are numerous small musical groups, many specializing in chamber music.

Cultivation of distinctively Jewish qualities is perhaps most pronounced in the literary field. There are associations concerned with the structure of the Hebrew language, notably the Hebrew Language Committee, and the Vaad Halashon, a body dedicated to modernizing the Hebrew vocabulary. Many famous literary works have been translated into Hebrew, and there is a substantial output of original works of distinction. Numerous literary prizes have been founded, among them the Bialik and Tchernokowsky prizes for poetry and the Dizengoff, Rabbi Kook, and Professor Clausner prizes for other forms of literature.

Part Four



TRANSJORDAN

TRANSJORDAN

Population: *400,000 in 1946 (estimated).*

Area: *33,750 square miles (estimated).*

Form of government: *A constitutional, hereditary monarchy. Legislative power is vested in the National Assembly and the King. The National Assembly consists of the Councils of Notables (the Senate), appointed by the King, and the Chamber of Deputies, composed of elected representatives.*

For purposes of general administration, Transjordan is divided into the Desert Area and four divisions, known as "liwas," each under a governor.

Principal occupations: *Agriculture, animal breeding, industry (limited).*

Principal exports: *Wheat, barley, raisins, skins, hides, wool, sheep, goats, cattle.*

Principal imports: *Manufactured articles, especially textiles, foodstuffs, benzine, kerosene, animals.*

Monetary unit: *Palestinian pound (£P) equivalent to approximately $4.03.*

Chapter 18

ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

THE PUBLIC educational system of Transjordan is largely a development of the period between the two World Wars. Before the First World War, the Turks had no more than a handful of elementary schools of five grades for boys in the larger towns. No school for girls existed. Transjordan was at that time an outlying part of the vilayet of Damascus and as such received even less attention in the matter of education than the neglected vilayets of the Ottoman Empire.

With the rise of the amirate of Transjordan in 1921, there gradually developed a small school system which now comprises 73 schools and 9,874 pupils. Nine of the schools are for girls, all elementary, with 1,956 pupils; 1 is a technical school for boys; and 4 schools are for boys, combining secondary with elementary classes. The rest are elementary town and village schools for boys.

Administration

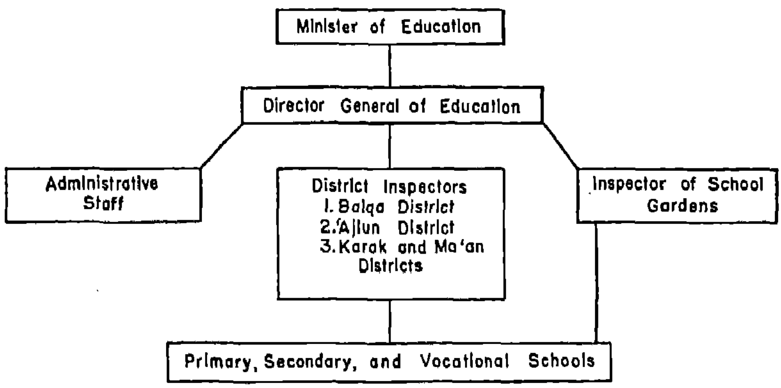
The public educational system of Transjordan is administered by the Ministry of Education, which is charged with the direction, supervision, and inspection of all government schools, and with the supervision and inspection of nongovernment schools. The Minister is a member of the Cabinet. He is assisted by a Director General of Education who is the executive head of the public-school system. Under the Director General are three district inspectors, one of whom has the rank of senior inspector. These inspectors correspond to the three districts of 'Ajlun, Balqa (in which 'Amman is situated), and the combined southern districts of Karak and Ma'an. Although assigned to these three districts, the inspectors actually have their headquarters at the capital, 'Amman. They are charged with inspecting the public and private elementary schools of their districts and share among themselves the inspection of secondary schools, each taking certain

subjects. The senior inspector supervises the teaching of Arabic and religion, the second inspector visits English and social-studies classes, and the third has charge of science and mathematics. The duties of the inspectors, however, are not confined to class visiting, but also involve general administrative inspection of schools, including the application of the education laws, registers, school premises, distribution of pupils by grades, the timetables, the register of marks, and other similar duties. Inspectors are also charged with presenting confidential reports about school principals and teachers, giving their opinions about reports sent by school principals about their teachers, presenting recommendations concerning the appointment, promotion, transfer, and discipline of teachers, the opening of new schools, and the composition of the staff of each school under their jurisdiction.

A special fourth inspector supervises the school gardens. The central office has in addition, a chief clerk, an accountant, a storekeeper, and some clerks. The administrative organization is shown in Chart IX.

Chart IX

TRANSJORDAN: ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF MINISTRY OF EDUCATION, 1946



Educational Finance

The financial support of public education in Transjordan is borne almost wholly by the central treasury. Table 50 shows the financial provisions in the annual budgets for the span of twenty-two years.

It is clear that as the general budget rose during the war years there was no corresponding increase in the budget for education, and that, therefore, the proportionate amount spent on education declined sharply. The whole educational provision is no more than £P35,248, which represents 1.1 per-

cent of the general budget. It is not too much to say that had the proportion remained at about 6 percent, as it was over several years, the sum would have been nearly sufficient to provide for universal elementary education.

TABLE 50

TOTAL BUDGET AND ESTIMATES FOR EDUCATION, TRANSJORDAN, 1924–46

Financial Year	Total Estimates	Education Estimates	Percentage
1924–25	£P 274,868*	£P14,771	5.4
1928–29	318,950	22,582	7.1
1930–31	350,532	23,482	6.7
1939–40	599,338	28,911	4.8
1941–42	1,183,155	29,542	2.5
1942–43	1,423,349	31,432	2.2
1943–44	2,062,290	33,366	1.6
1944–45	3,252,334	33,478	1.0
1945–46	3,249,000	35,248	1.1

* A Palestinian pound is equivalent to slightly more than $4.00.

A 1937 amendment to the Turkish Elementary Education Law of 1329 A.H. (1914) provided for a municipal education tax. This has so far been imposed in seven municipalities, and a total of twenty teachers has been appointed in the public schools and paid from municipal revenues derived from this tax. The appointment of these teachers made it possible to add sixth and seventh grades to many of the local schools.

According to the old Turkish law, the school building in the rural districts must be provided by the village authorities. The Ministry of Education must provide the rest—school furniture, equipment, cost of upkeep, and teachers' salaries. In the cities the cost of rental is borne by the Ministry of Education. All of the school buildings in Transjordan, except five, are rented.

Teachers are employed on the same basis as other civil servants. The Transjordan civil service is divided into four classes and ten grades as follows:

Class	Grade	Monthly Salary Range
I	1	£P58–64
	2	48–56
	3	38–46
	4	32–36
II	5	26–31
	6	21–25
III	7	17–20
	8	13–16
IV	9	9–12
	10	6–8

In addition, there is a temporary grade to which a salary of £P5 or less is attached. Appointment to this grade is upon the recommendation of the Director General of Education and the approval of the Minister. Officials and teachers in classes three and four are appointed upon the recommendation of the Director General, but with the approval of the Prime Minister. Officials of classes one and two are appointed upon recommendation of the Ministry concerned, with approval of the Council of Ministers and the King. At the time of the visit of the American Council Commission, the post of Director General of Education was scheduled on grade two of the civil service, the senior inspector was in grade four, and the other inspectors were in grade five.

Teachers with the degree of B.A. or its equivalent are first appointed in grade seven. Those who have finished the junior year at the American University of Beirut are appointed in grade eight; students who have finished the sophomore year of the American University of Beirut and graduates of the American Junior College for Women, in Beirut, and of the Arab College of Jerusalem are appointed in grade nine. Holders of the Transjordan Matriculation Certificate are put in grade ten on first appointment.

Promotions of teachers have lately been so rare that out of thirteen teachers with B.A. degrees who were teaching in the secondary schools, only four remained. The other nine left teaching for more lucrative jobs.

Educational Legislation

Until recently education in Transjordan was legally subject to the provisions of the education laws of the Ottoman regime. These were superseded, however, by the new regulations passed in 1939. Education Regulation No. 1 for the year 1939 concerning the organization of the educational system provides that the administration of the educational services must be conducted with the knowledge of the officials of the central office, the inspectors, the local administrative officials, the municipal committees in towns, and educational committees in the villages. The Departments of Health, Public Works, and Agriculture are enjoined to cooperate with the Ministry of Education, each in its own field. Regulations further prescribe the administrative framework for education already described. They stipulate that students for the educational missions are to be chosen by a committee of inspectors under the chairmanship of the Minister (later changed to the Director General) of Education. The Minister may also select specialists and principals of secondary schools to assist inspectors in work within their districts.

Education Regulation No. 2 for the year 1939 laid down the fundamental lines of educational organization. The functions of the Ministry of Education are defined as "the foundation, administration, and inspection of public schools, general supervision over private schools, encouragement of scientific and literary activities and of scouting and physical education in the schools, promoting fine arts, control of public morals, and concerning itself with all that pertains to public education and culture." Schools are classed as rural elementary, elementary, primary, secondary, and specialized.

The regulations set down the main features of elementary, secondary, and specialized education. Rural and town elementary education is free, and elementary education is compulsory for boys and girls in localities defined by the government. The conditions for admission to each type of school and for the granting of certificates are specified. Private schools cannot be opened without the permission of the Minister of Education. Private-school teachers must be licensed to teach by the Ministry. The teaching of Arabic and of the history and geography of the Arab world, including Transjordanian history and geography, are obligatory. Arabic lessons must be no less than five periods a week in elementary classes, and four periods in secondary classes. Teachers of elementary schools must be graduates of elementary- and primary-teachers colleges, while those of secondary schools must be graduates of a higher-teachers college (neither type of teachers college exists in Transjordan and, therefore, teachers must be prepared in neighboring countries). However, in case of lack of qualified teachers the Minister is empowered to choose people from a lower grade on a temporary appointment. Such temporary appointees cannot be confirmed in the service unless they spend three years in teaching during which they study special educational courses, and unless the Director General deems them worthy for teaching. Similarly, teachers of physical education and other special subjects may be appointed if deemed competent in their subjects without regard to other requirements.

The regulations provide for a public secondary examination, while an amendment passed in 1944 sets up a similar examination at the end of the primary school leading to the primary-school certificate. The abovementioned Regulations Nos. 1 and 2 for the year 1939 abolish all previous Turkish laws on education.

Regulation No. 1 for the year 1945 for private schools defines these schools as those founded by a Transjordanian or foreign individual, group, or sect and supported by their owners from their own funds or from fees, donations, or religious endowment. Private schools may be opened only by

permission of the Ministry of Education. The list of teachers, the courses of study, and the books must first be approved. The Ministry, also, is to endorse the diplomas and certificates of the teachers. Teachers are not to encroach on the freedom of religion and are to refrain from teaching beliefs which contradict the beliefs of the children who do not belong to the religion or sect of the school; nor are they to teach beliefs in opposition to the constitution of the state. No coeducational school may be opened beyond the third elementary grade, and no men may be appointed as teachers in girls schools even on a temporary appointment. Corporal punishment is prohibited. Schools are subject to examination by inspectors, doctors, and architects of the Ministry of Education. Authorities of the school must present to the inspectors all information required, and send to the Ministry of Education within three months after the opening of each school year statistics of the distribution of pupils by classes, ages, and religions. A full personal register for each pupil must be kept. The program for any ceremony, public meeting, or graduation exercises must be submitted to the local authorities for approval at least a week before the meeting.

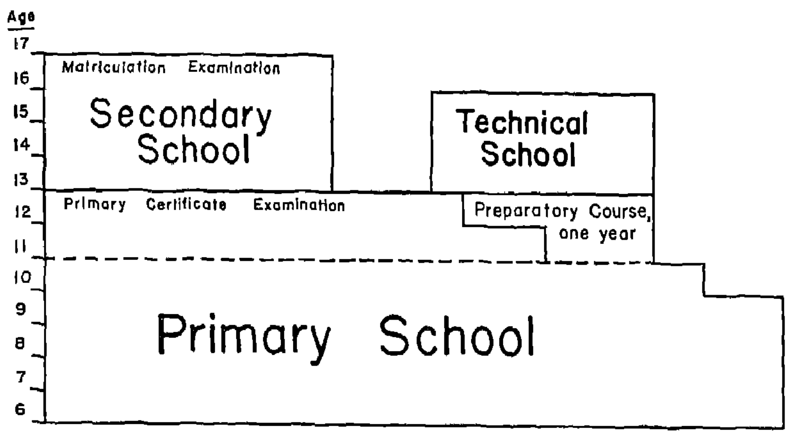
The Educational Ladder

The educational ladder in Transjordan is very similar to that of Palestine, although somewhat simpler. The two countries were in the last quarter of a century under the same mandatary; thus, it is to be expected that similarities should exist.

Chart X shows the design of the system. The primary schools are of

Chart X

TRANSJORDAN: PUBLIC SCHOOL SYSTEM, 1945-46



seven grades, divided into a lower cycle of five grades known as the elementary cycle and a higher cycle of two grades. Schools in the towns are either complete primary with seven grades or elementary with five grades. In the villages most schools are of four grades (as in Palestine) and are known as village elementary schools. In 1945–46 there were in Transjordan 12 complete public city primary schools of seven grades and 7 city elementary schools of four or five grades. In the same year there were 44 village schools of which 1 was of two grades, 1 of three, and 42 of four grades. In addition, there was 1 school for Bedouins.

To be admitted to the first grade, a pupil must have completed his sixth year of age, and not exceeded his eighth. A pupil is not allowed to repeat a grade more than twice and is dropped from a primary or elementary school if he has completed his fifteenth year of age. Previously pupils were graduated from the primary school on the basis of school examinations, but beginning with 1944–45 the primary-school certificate was granted only after a public examination.

Secondary schools are of four years in two stages—an intermediate stage and an upper stage, each of two years. Annual fees of £P2 for the intermediate stage and of £P3 for the upper stage are charged. Students are not admitted if they have completed their sixteenth year of age, and no student is allowed to repeat a year more than once. Secondary education ends with the Transjordan matriculation examination conducted by the Ministry of Education. In 1945–46 there were 4 public secondary schools, 1 of two years at Karak, 2 of three years (one at 'Amman and one at Irbid), and 1 complete school of four years at al-Salt. It was hoped that at least the 'Amman school would be extended to four years by 1946–47.

There is no public secondary school for girls in Transjordan, and the education of girls in the public schools, therefore, reaches only to the end of primary school. There is, however, 1 secondary school for girls, reaching to the third secondary year, which is maintained by the Church of England Missionary Society.

Parallel with the secondary school, is the Technical School at 'Amman. Here pupils may pursue a four-year course in carpentry (including upholstery), and blacksmithing.

No postsecondary schools exist. Students either are sent by the government to study outside Transjordan or go at their own expense. Educational missions have been sent to the American Universities at Beirut and Cairo. The British Council helped send 5 students to universities in England and Scotland. Some have been sent to Palestine to the Arab College and the Teachers Training College for Women in Jerusalem, to the Agricultural

School at Tulkarm, and to the English Girls College and the Schmidt College in Jerusalem. Twenty-three have been sent for agricultural training at the Near East Foundation Farm at Tha'labayah, Lebanon. Two boys were sent to the Higher Teachers College in Baghdad. Students may also go at their own expense to the American University of Beirut, the Syrian University in Damascus, the Egyptian universities, and other institutions abroad. In addition, the government has sent students for short courses in village welfare service in Lebanon, or in scouting in Palestine. During the period from 1927 to 1946 a total of 103 mission students, including 5 sent to England and Scotland by the British Council, have been sent to other countries to study for varying lengths of time. Of this total at least 12 were girls.

The Development of the System

Table 51 shows statistically the development of the public educational system in Transjordan between 1922–23 and 1945–46.

TABLE 51

Number of Public Schools, Teachers, and Pupils, in Transjordan, 1922–46

Year	Number of Schools	Number of Teachers	Enrollment			Average Number of Pupils per Teacher
			Boys	Girls	Total	
1922–23	44	81	2,998	318	3,316	43.4
1930–31	54	122	4,110	588	4,698	40.5
1940–41	74	184	8,255	1,895	10,150	56.7
1941–42	74	184	8,365	1,999	10,364	56.1
1942–43	74	186	7,955	1,897	9,852	52.3
1943–44	73	188	7,750	1,857	9,607	50.0
1944–45	73	197	7,645	1,844	9,489	47.7
1945–46	73	199	7,918	1,956	9,874	49.2

In the first nine years, schools increased by less than 25 percent, or at the rate of approximately one school a year, while the number of teachers increased by 50 percent and pupils by slightly less than that. In another ten years, by 1940–41, schools had increased by 37 percent over the previous decade, teachers by 50 percent, while the number of pupils had more than doubled since 1930–31. It is to be noted that the number of girls increased at a more rapid rate during the decade. Since 1940–41 the number of schools has been at a standstill, the number of teachers has increased slightly, and the number of pupils showed some drop during the war years. Evidently the number of pupils has been increasing at a more rapid rate than that of schools or teachers, so that the number of pupils per teacher has correspondingly risen from 43.4 in 1922–23 to 56.7 in

1940, and had come down to 49.2 in 1945–46. Some classes are too large for efficient teaching.

In 1945–46, there were 73 public schools of all types, with 199 teachers (including 38 women), and 9,874 pupils, of whom 1,956 were girls. In the same year there were 100 nongovernment schools of which 64 were for boys; 21, for girls; and 15, coeducational. These were manned by 251 teachers, of whom 95 were women, and attended by 6,472 pupils, of whom 2,640 were girls. Thus, the total number of pupils in both public and private schools was 16,346, of whom 4,596 were girls. It is noteworthy that there were more private than public schools and that more girls were in private than in public schools.

TABLE 52

ENROLLMENT BY GRADES IN PUBLIC SCHOOLS, TRANSJORDAN, 1945–46

Grade	Enrollment	
	Primary and Secondary Schools	Technical Schools
Elementary		
1	2,254	...
2	2,064	...
3	1,815	...
4	1,576	...
5	795	...
Primary		
6	575	...
7	357	...
Secondary		
1	138	26
2	99	20
3	93	19
4	36	7
Total	9,802	72

It is not possible to give accurately the ratio between children attending schools and the total number of children of school age. A rough calculation on the basis of a five-year school shows it to be between 26 and 28 percent. This ratio is higher for boys than for girls. Among the Christian communities there is approximately universal attendance in elementary schools for children of school age.

Distribution of pupils according to classes in public schools shows the same tendency of gradual elimination of pupils as in the other Arab countries. Table 52 shows the enrollment by grades for public schools for 1945–46.

A sharp decline in numbers occurs between the fourth and fifth grades, largely due to the fact that half the public schools do not go beyond the fourth elementary grade. As in Palestine, very few pupils reach the top

secondary classes, but, unlike Palestine, there seems to be no express policy of strict selection of pupils after the fifth grade. The process of elimination seems to take place naturally, partly due to the small number of complete primary and secondary schools.

An analysis of the statistics of attendance by types of schools reveals the following:

Type of School	Enrollment
City primary and elementary schools	6,321
Rural elementary schools	3,099
The Tribal School	16
Secondary schools	366
The Technical School	72
Total	9,874

Attendance in primary and elementary schools is divided in the proportion of two in the cities to one in the villages, although the ratio for the general population is more nearly the reverse. The number of secondary-school pupils is 3.8 percent of the number of primary- and elementary-school pupils.

Public Examinations

The public primary-school examination was instituted for the first time in 1944–45. This examination is open to all those who wish to sit for it. Application of pupils are sent through the schools, while independent applicants send their applications direct to the Ministry of Education. A fee of £P2 is charged. A committee is appointed by the Minister with the Director General of Education as chairman and with its membership made up of the inspectors and selected members. The committee chooses those who are to formulate the questions and those who are to be supervisors of the examinations and readers of examination papers. It sets down the rules for the examinations and summarizes the results. The results are not considered final until approved by the Minister.

The examination covers the topics taught in the upper two classes of the primary schools and is comprised of Arabic, English, arithmetic and geometry, history, geography, and science. Muslim boys take an examination in religion, while non-Muslims take an examination in agriculture. Girls take domestic science and child care instead of science, and non-Muslim girls take nursing instead of religion.

The passing mark is 60 for each subject. Pupils failing in more than one subject are considered failures. Those failing in one subject must, in order

to pass, have secured a mark near the passing mark in that subject. The examination is held only once a year. A student who has failed, therefore, may present himself again only in the following year. Pupils passing the examination are granted the Transjordan Certificate of Primary Examinations. Only holders of this certificate may be admitted to the public secondary schools.

In 1944–45, 224 boys and 42 girls took the primary-school examinations. Of these, 118 boys (52.6 percent) and 26 girls (61.9 percent) passed, and 106 boys and 16 girls failed. Reference to Table 52 reveals that a large number of pupils eligible to take the examination did not attempt it.

The Transjordan examination for the secondary-school certificate is conducted, in the same way as the primary examination, by a committee under the chairmanship of the Director General of Education. It is based on the program of the four years of secondary school. It comprises five

TABLE 53

Results of Public Secondary-School Examinations, Transjordan, 1940–45

Year	Number Entering	Number Passing	Number Failing	Percentage Passing
1940–41	64	59	5	92.2
1941–42	57	57	0	100.0
1942–43	41	33	8	80.5
1943–44	66	12	54	18.5
1944–45	55	14	41	25.4

required subjects—Arabic, English, mathematics, physics, and history. Muslim students are, in addition, required to take an examination in religion and one other of the elective subjects. Non-Muslims have to take two of these electives. The electives are botany and zoology together, general geography, and geography of the Mediterranean Sea.

The examination is held only once a year. The passing mark is 60 for each subject. A student failing in more than one subject is considered to have failed the examination, while one failing in one subject may be considered to have passed if his mark in the subject is not much below the passing mark. Successful students are granted the Transjordan Certificate of Secondary Examinations.

Table 53 shows the results of the secondary-school examinations for the five years 1940–45.

The proportion of passing students fluctuates considerably from year to year, having varied from 18 to 100 percent in the five-year period 1940–45.

Chapter 19

THE SCHOOLS OF TRANSJORDAN

THE PUBLIC, or government, education system of Transjordan consists of a seven-year primary school and a four-year secondary school leading to a public matriculation examination. There are no kindergartens in the public-school system as yet, although children younger than six may go to *kuttabs* (traditional religious schools, not included in the public-school system, which teach beginning reading and writing, but which emphasize religious instruction). In some villages the schools are incomplete, offering courses which vary from two to five years in length and frequently combining classes. In 1945–46 there were 44 such schools, all for boys, with 3,115 pupils registered. Girls are sometimes permitted to attend the first three grades of the elementary school for boys.

Elementary schools are housed in rented buildings, usually former dwellings. The increase in interest in school attendance during the last few years has been paralleled by increases in the size of classes so that at present most rooms are crowded. Most of the classes in primary schools in cities have more than 60 boys in each class and in at least 1 school there are 91 enrolled in one class in the second grade. Playground space is limited. Thirty-four of the village schools have school gardens varying in size from one and one-half to five acres.

Secondary schools are in rented or government buildings. The new building at Irbid is modern in design and construction and is surrounded by ample playground space. Classes are not large, and rooms are not crowded in secondary schools.

The Primary Course of Study

The Program of studies for primary schools for boys is given in Table 54. Slight differences appear in the distribution of periods in girls schools to provide one period per week in domestic science in the sixth and seventh grades, one period per week in child care in the seventh, and one period per week for nursing instruction in the sixth and seventh grades, and a total of thirteen hours for handwork distributed over grades

two to seven. The total number of periods per week for girls is the same as for boys except that the girls have two additional periods in grades two and three and one additional period in grades four and five. In the program for five-year village schools, the length of the periods assigned to religion, Arabic, English, and geography is reduced slightly in order to provide theoretical and practical agriculture for six periods per week in the third, five in the fourth, and four in the fifth grade. If no garden is available, the periods assigned to practical agriculture are distributed to the basic subjects.

TABLE 54

PROGRAM OF STUDIES IN PRIMARY SCHOOLS FOR BOYS, TRANSJORDAN, 1945–46

Subject	Periods* per Week						
	1st Grade	2nd Grade	3rd Grade	4th Grade	5th Grade	6th Grade	7th Grade
Koran and religion	4	5	5	4	4	4	3
Arabic	12	12	12	9	9	9	8
English	...	...	...	7	7	7	7
Arithmetic	5	5	5	5	5	4	4
Geometry	...	...	...	...	...	1	1
History	...	{ 1	1	2	2	2	3
Geography	...	{ 1	1	2	2	2	2
Civics	...	...	...	...	...	...	1
Science	...	1	2	2	2	2	2
Agriculture	...	...	...	...	...	1	1
Physical training and singing	2	1	1	1	1	1	1
Drawing and handwork	1	1	1	1	1	1	1
Total	24	26	28	33	33	34	34

* Periods are of 45-minute length.

The course of study in the *Koran* and *religion* provides for the memorization of parts of the Koran, beginning with about 150 lines in the first grade and requiring the learning of complete chapters in the sixth and seventh grades. Simple stories of the life of the Prophet and a study of his sayings are begun in the first year and continue for the entire course. By the end of the seventh year pupils are expected to know all the requirements of the Muhammadan religion relating to prayers, fasting, ablutions, feast days, pilgrimage, and responsibilities to the poor. Character traits such as honesty, truthfulness, attitudes toward parents, obedience, self-control, and kindness to animals are discussed and emphasized. Attention is given to an elementary study of the history of Islam, personal status (such as marriage, divorce, and inheritance), beliefs, and the lives of the prophets, including Adam, Abraham, Moses, and Jesus.

The course of study in *Arabic* includes the study of colloquial and classical Arabic. Attention is given to reading, writing, memorization, grammar,

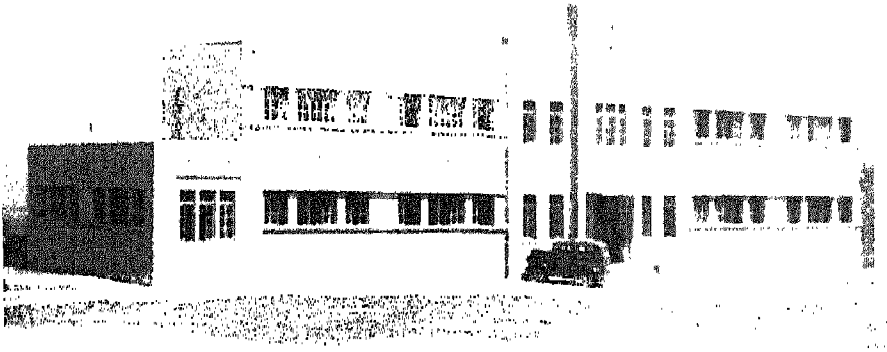
and composition, with materials selected which are considered appropriate for the age level involved. Dictation is frequently used as a method of instruction. Both personal and business letters are studied in the seventh year. Pupils are encouraged to read books and magazines and to use the library. Much of the material used in reading is derived from religious literature.

The study of *history* begins in the second grade and is correlated in that grade with geography. Simple stories of important figures during the early Islamic period serve as content in the second year. The lives of King Husayn and his sons are studied in some detail in this year. The course is continued in the third year with a more detailed study of the important events during the lifetime of Muhammad. From the fourth to the sixth years inclusive a systematic study is made of Arab history from the death of Muhammad to the period of the Crusades. In the seventh year a rapid survey is made of the history of the Near East from the time of the ancient Egyptians to the present.

Geography in the second year includes a study of the physical features of the pupil's village or city; definitions of such terms as mountain, valley, sea, lake, river; development of knowledge about day and night, the cardinal directions, the seasons, and means of communication in and between population centers. The earth and its movements are studied in the third year. Other topics include maps and the globe; definitions of such terms as island, peninsula, strait, canal, and cape; and the geographical features of Transjordan. The geography of Syria, Lebanon, Iraq, and Palestine is studied in the fourth year as well as such general topics as volcanoes and earthquakes, latitude and longitude, and phenomena of the atmosphere. Asia, Europe, and Africa are considered in the fifth year, and North, Central, and South America and Australia in the sixth. The emphasis in the seventh year is on the Mediterranean basin and a review of the geography of the Near East.

The course of study in *civics* in the seventh grade provides for the study of the family, the nation, development of government, the rights and responsibilities of citizens, and the constitution of Transjordan. Attention is given to both local and central organization and administration of the affairs of the country. The relationships between the executive, legislative, and judicial bodies are studied.

General Science begins in the second grade with observation and discussion of common animals and plants in the child's environment. The importance of cleanliness of body, clothing, and living spaces is emphasized. The relationship of wholesome food, fresh air, and exercise to good health is stressed. These topics are continued in the third grade with more details





Above: The new secondary school for boys, Irbid, Transjordan
Below: Recess at the secondary school for boys, Irbid

regarding good health habits and care of the eyes, nose, and ears. Discussion of common industries and occupations with attention to materials used is included in this grade. In the fourth grade domestic animals are studied, with special attention to their commercial value, and wild animals such as the lion, tiger, and elephant are discussed. Plants and trees of commercial value, including olive and almond trees, grape vines, wheat, and watermelon, are studied in this year. Rocks and minerals are identified, and their uses and importance explained. The skeleton and muscular, digestive, and circulatory systems of man are studied. Some common illnesses and their causes, and first-aid treatment are considered. The major topics of the fifth year are the less common animals of land and sea; structure of typical plants; introduction to elementary factors in agriculture such as function of plowing, importance of irrigation, and uses of common instruments or tools; and the human nervous system. In the sixth year more emphasis is placed upon physical principles, such as air pressure; size, weight, and density of substances; evaporation and melting; and meteorological phenomena such as fog, rain, hail, and snow. The human circulatory system is studied in considerable detail. Chemistry and its uses are introduced in the course of study in the seventh year. Differences between elements, mixtures, and compounds are explained. Chemical properties of common substances such as sulphuric acid, iron, lead, mercury, air, water, carbon are illustrated and explained. Respiratory systems in plants and animals are studied and compared. Importance of a balanced diet is stressed. Some of the elementary ideas about electricity together with such phenomena as lightning are included. Sound and light are also studied in this year. Contagious diseases, methods of transmission of disease, and further study of first aid are considered.

The course in *agriculture* for village schools from the third to the seventh years attempts to give modern theories together with much practice in the school gardens. Effort is made to make the course as practical as possible and to provide the basis for improvement of agriculture in the village areas. Vegetables, flowers, fruit trees, beekeeping, animal-breeding, poultry, plant and animal pests and diseases, grafting, pruning, and dairying are studied during the five-year period.

The Michael West series of New Method Readers is used in the course in *English* which begins in the fourth grade and continues through the seventh. The readers and companion books through reader five are expected to be completed by the end of the seventh grade. The introductory texts, however, are the *First Year English* by Morris and part of the second book by the same author.

The course in *arithmetic* for the first grade provides for learning to read

and write numbers up to 10, exercises in addition and subtraction of numbers to 10, and adding equal numbers as an introduction to the multiplication tables. By the end of the year pupils are expected to carry out the four fundamental operations with numbers up to 20. In addition to reviewing the first year's work, the second year's work includes operations with numbers up to 100, multiplication tables to 6 × 6, writing numbers to 500, and an explanation of the simplest fractions such as one-half and one-fourth. Multiplication tables, including 12 × 12, are learned in the third year. The decimal system is studied intensively in this year, and written problems are begun. Measures of time, length, and weight and more difficult and complex fractions are also studied in the third year. Reading and writing numbers up to 1,000,000 and multiplication and division by numbers with two or more digits are carried out in the fourth year. Problems involving units of time, the metric system, and Palestinian money are included. Addition and subtraction with compound numbers are studied in the fourth year. The fifth-year course includes a review of the four fundamental operations with whole numbers, fractions, and decimals; conversion of common fractions to decimals and vice versa; ratio and proportion; and areas of square and rectangular figures. In the sixth year, local, metric, and English measures, including money, are introduced, together with problems requiring conversion from one system to another. Problems involving simple, direct, and inverse proportion are solved. Commercial arithmetic involving percentage, simple and compound interest, profit and loss, insurance, and simple bookkeeping and elementary business practice comprise the content for the seventh year.

The relatively small amount of time allotted to *geometry* in the sixth and seventh years permits little more than an introduction to intuitive geometry and simple constructions. Elementary characteristics of circles, squares, rectangles, and parallelograms are discovered. Ability to compute the areas of these figures and the volume of the corresponding solids is developed.

At the end of the seventh grade of the primary school a public certificate examination is given to those pupils who have completed the course and who apply.

Since there are no teacher-training institutions in Transjordan, most of the elementary-school teachers in schools for boys are holders of Matriculation, or secondary-school, Certificates, although some have not completed their secondary-school course. In the schools for girls, especially in the smaller cities, most of the teachers have completed only the elementary-school course. In the larger cities, teachers in girls schools have received additional training, usually in Jerusalem or in Beirut.

Secondary Education

Secondary education for boys was provided under government auspices in 4 schools in Transjordan in 1945–46. These schools were located at al-Salt, 'Amman, Irbid, and Karak. Only the school at al-Salt provided the complete four-year program, but it was expected that the schools at Irbid and 'Amman would offer complete programs in 1946–47, and the one at Karak, in the following year. The total enrollment in the 4 schools in 1945–46 was 366 boys. There are no government secondary schools for girls. Preparation for government employment or higher education is the primary objective of the secondary schools. Government employment includes teaching, as well as clerkships in government departments. A determined effort has been made during the last few years to avoid the development of a group of unemployed secondary-school graduates.

The program of studies

The program of studies is comprised of a uniform course of four years' duration, upon successful completion of which the student presents himself for the public government Matriculation, or secondary-school, Certificate examination. The details of the program of studies are given in Table 55.

Somewhat detailed courses of study have been prepared for each of the subjects. A brief summary of the more important topics is given below.

Reading of the *Koran* forms the basis of the study in religion during

TABLE 55

Program of Studies for Secondary Schools for Boys, Transjordan, 1945-46

Subject	Periods* per Week			
	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year
Koran and religion....	2	2	1	1
Arabic..............	7	7	8	6
English†............	7	7	7	7
Arithmetic..........	2	2	...	...
Algebra.............	3	3	2	2
Geometry...........	3	3	2	3
Trigonometry........	...	...	1	...
History.............	3	3	3	3
Geography..........	2	2	2	2
Physics.............	2	3	5	5
Chemistry...........	1	...	3	3
Botany..............	...	...	...	1
Zoology.............	...	...	...	1
Agriculture..........	2	2	...	...
Total...........	34	34	34	34

* Periods are of 45-minute length.
† Between 5 and 10 minutes are taken from reading lessons for dictation.

the first three years. Directions relative to ablutions, prayer, fasting, charity, and pilgrimages are reviewed and emphasized. The four important sects of Islam are described and their differences explained. Quotations from the Koran are used to explain standards of behavior and relations to others. In the fourth year, major emphasis is placed upon developing an understanding of personal status (marriage, divorce, inheritance, and family relationship) as provided for in Muslim law. The bases of good government as found in the Muhammadan religion are studied.

The study of *Arabic* continues to improve the quality of written and oral expression, in addition to which attention is given to furthering knowledge of the historical development of Arabic literature, with special emphasis upon the 'Abbasid Period. An analytical study of the contributions of the Arabs to literature is made. Memorization of selections from poetry and prose is required.

In *English*, the sixth and seventh readers of the Michael West series form the basis of the work in the first year of the secondary school. More attention is given to silent reading of simplified or abridged editions of standard prose such as *Don Quixote, Ivanhoe, The Cloister and the Hearth*, and to anthologies of English poetry in the last three years. Systematic study of grammar is carried out in all four years.

The course of study for *history* in the first year provides for the study of ancient times up to the invasion of the barbarians, with special emphasis on the development of civilization in Egypt, the Near East, Greece, and Rome. Study of the Middle Ages from the barbarian invasion to the French Revolution is indicated for the second year, special attention being given to the part which the Arabs played in this period. Modern history from the French Revolution to the present is studied in the third year, and an intensive study of the history of the Arabs from earliest times to the present is made in the fourth year.

In the first year of *geography*, after a brief review of the material studied in the elementary school, attention is directed to the geographical features of Asia and especially the Middle East. Such topics as location, climate, natural resources, size, population, important cities, agriculture and industry, exports and imports, transportation, and government are considered for each political division. Europe and Africa are the regions studied in the second year, North and South America and Australia in the third year, while in the fourth year Syria, the Arabian peninsula, Iraq, and the Mediterranean basin are studied intensively.

The history of *agriculture* receives some attention in the first year, but major emphasis is upon such topics as forests, beekeeping, milk produc-

tion, water supply, irrigation, plants and their requirements for growth, field crops, and rabbit-breeding. Gardening, cattle- and sheep-raising, insects and their control, fertilizers, fruit trees, experimental agriculture, and floriculture are the topics receiving most attention in the second year.

In *arithmetic,* written problems involving the four fundamental operations, determination of the highest common factor and the lowest common multiple, ordinary and decimal fractions including conversion of one to the other, and ratio and proportion are included in the first-year course. Some business arithmetic involving percentage, profit and loss, insurance, and simple interest is studied in the first year also. In the second year the course includes a review of ratio and proportion, English and metric systems of measure, English and Palestinian monetary systems, square and cube roots, area and volume of common surfaces and solids, compound interest, and stocks and bonds.

In *algebra,* the major topics in the first year are fundamental operations with algebraic expressions, factoring, fractions, and problems with three unknown quantities; in the second year, simple and complex fractions, factors of the sum and difference of quantities to the third power, and quadratic equations; in the third year, more difficult factoring, theory of exponents, indices, logarithms and graphs; and in the fourth year, solution of equations by the use of graphs, and a review of the work of previous years with more difficult problems.

Trigonometry is taught for one hour a week during the third year. Elementary facts are studied regarding measurement of angles, relationships of length of sides to angles in triangles, trigonometric ratios for angles of 0, 15, 30, 45, 60, and 90 degrees, and problems involving the computation of sides and angles of right triangles are solved.

The course of study for *physics* for the first year includes measurement using the metric system, density, mechanics of liquids and gases, atmospheric pressure, temperature and laws of expansion; second year, magnetism, static and current electricity, batteries, electricity in the atmosphere, electric bells, telephone, telegraph and microphone, elementary principles and applications of sound and light; in the third year, simple machines, force and motion, work and energy, freezing, evaporation, humidity, and advanced work in sound, magnetism, and electricity; and in the fourth year, nature and characteristics of light, optics, analysis of light, electric current and its magnetic, mechanical, and chemical effects, electrons, radio, and a review of previous work in physics.

Chemistry is studied in the first, third, and fourth years. The introduction in the first year includes the study of differences between physical

and chemical changes, compounds and mixtures, oxidation and combustion, composition of air, production and characteristics of oxygen, hydrogen, and nitrogen, composition and properties of water, and the study of nitrogen, carbon, acids, and salts. In the third year the topics studied are atomic weights, Dalton's Theory, important chlorides, nitrogen and the production of ammonia, manufacture of ice, nitric acid, fertilizers, sulphur and its compounds, silica, and carbon. The topics studied in the fourth year are: chemical theories and laws; characteristic properties and compounds of sodium, potassium, calcium, magnesium, copper, silver, iron, and aluminum; preparation and properties of cement, steel, alcohol, ether, sugar, and starch. An introduction to the chemistry of photography is given.

Relatively little attention is given to the *biological sciences* in the secondary-school program. Only two periods per week in the last year are provided for the study of botany and zoology. The course in botany includes the study of the cell, germination of seeds and growth of plants, respiration, food requirements, storage of food, reproduction, grafting and pruning, and method of classification. In zoology the topics studied are: general characteristics of animals, the cell, food and nutrition, digestive, circulatory, respiratory, and nervous systems of animals, reproduction, classification, and a detailed study of the skeleton of the rabbit.

Laboratory work does not seem to have an important place in the teaching of science in the government secondary schools. Supplies and equipment are limited partly because it has been difficult to secure needed material during the war. Proper rooms for laboratories were not available in most of the schools, and existing equipment did not appear to be used extensively.

Informal student activities take the form of Boy Scout organizations, literary societies (usually limited to Arabic), cultural societies, and sports including soccer and basketball.

Since there is no institution of higher education in Transjordan, most teachers who have received training beyond the secondary school have studied in Palestine, Lebanon, Egypt, or Iraq.

Vocational Education

The only vocational education in Transjordan is given in the Technical School in 'Amman. There were 72 boys enrolled in this School in 1945–46, of whom 40 were boarding students. No fees are charged although boarding students must furnish their own clothing and their beds and bed-coverings. The vocational course is three years in length for those who have completed the primary-school course of seven years. Since in many

towns and villages only five years of elementary school are offered, a preparatory year is given for those who have completed only five or six years of the elementary school. In 1945–46, 26 of the 72 students were in the preparatory class.

The program of studies for the preparatory years includes Arabic (nine periods per week), arithmetic (six), geometry (three), physics (four), geography (two), general drawing (five), and shop orientation (five). The courses in these subjects are selected from the corresponding courses for the sixth and seventh grades of the elementary school and are designed to give in one year what is most necessary in the preparation for work in the Technical School.

There are two specializations in the Technical School—blacksmithing, including turning and fitting, and carpentry, including upholstering. Blacksmithing was more popular in 1945–46, having an enrollment of 30 boys, as compared to 15 in carpentry. Prior to the war a third specialization in bamboo-chair making and basketry was offered, but it had to be discontinued when materials were not available.

Instruction is carried out largely in the shops, with only one or two hours a day given over to mechanical drawing and theory. A series of practical projects of graduated difficulty is used as the basis of instruction. An exhibit of the students' work is held annually, at which time the objects are sold and the income is used for the support of the School. It was reported that graduates have little difficulty in finding employment with the Iraq Petroleum Company, the army, or in local repair shops.

Nongovernment Schools

Public education in Transjordan is supplemented by provision for education under private, usually religious, auspices. Catholic schools under the Latin Patriarchate of Jerusalem have the largest number of pupils, 2,731; Muslim schools have 1,429 pupils; Greek Orthodox, 1,247; Protestants, 843; and other religious groups or individuals provide for 222. Of the total of 6,472 pupils in nongovernment schools, 3,832 are boys and 2,640 are girls. Approximately two-thirds, 4,345, of the total in nongovernment schools are Christians. All but two of the schools are elementary or primary schools which follow more or less closely the government program of studies and prepare for the public primary-school certificate examination. Some have kindergartens and accept pupils below the age of six. Fifteen of them have boys and girls in the same classes for the kindergartens and first three grades. Most of the schools are housed in buildings constructed as private dwellings or in parts of church build-

ings or adjacent quarters. Some, such as the Catholic School and the Church of England Missionary Society School for Girls in 'Amman, begin the study of a foreign language, English, as early as the kindergarten.

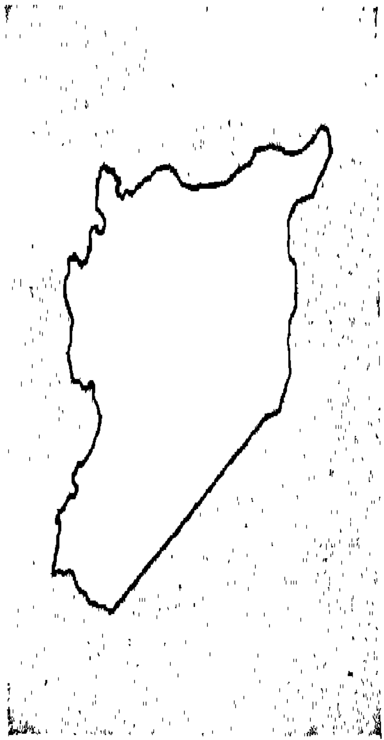
The only secondary education for girls in all Transjordan is provided in the Church Missionary Society School for Girls in 'Amman. This School, founded as an elementary school in 1927, is now providing three years of a secondary-school program. In 1945–46 there were 9 girls in the first year, 6 in the second, and 4 in the third. Girls who wish to continue their education after finishing the third year usually go to the American Junior College in Beirut or to schools in Palestine. In addition to the secondary school, there is a kindergarten and seven grades of elementary education which provided for 225 pupils in 1945–46. There were 75 boys enrolled in the kindergarten and the first three grades. The program of studies in the elementary school is not greatly different from the program in government schools except that the study of the Scriptures takes the place of the Koran and Muslim religion, and English is studied from five to seven periods in each year, including the kindergarten. In the program for the secondary years the major change consists of substituting domestic science, sewing, singing, biology, games, and Scriptures for the physics, chemistry, and Koran in the government course. The school week is forty-three periods including three periods for games, as compared to thirty-four periods in public schools. The study of Arabic is emphasized throughout the entire elementary- and secondary-school course. Extraclass activities include a fortnightly cinema provided by the British Council, a Christian Endeavor Society, and a literary society, each of which meets weekly, and an annual school outing. Fees for day pupils vary from £P12 ($48) in the kindergarten to £P18 ($72) in the secondary school. There were 14 boarders in 1945–46 who paid an additional fee of £P48 ($192). The School has an attractive building and site in a residential section of 'Amman. Recent additions to the original building have reduced the congestion, but many requests of boarding students have to be refused because of lack of space. A large playing field adjacent to the school building is much used. The student body is divided into six houses which compete in intramural games.

The Bishop's School, located a short distance from the Church Missionary Society School for Girls on the same ridge high above the city of 'Amman, was founded in 1936 to provide elementary and secondary education for boys. The present program (1946) begins with the fourth grade of the elementary school and finishes with the fourth year of the secondary school—a total of eight years. The total enrollment in 1945–46

was 212 boys, of whom 97 were in the secondary school. There is a tendency for boys to leave at the end of the third year to enter as freshmen at the American University of Beirut. Boys who complete the fourth year and pass the Transjordan matriculation examination are accepted as sophomores at A.U.B. Tuition fees vary from £P18 ($72) in the elementary classes to £P24 ($96) in the secondary classes. Boarding students pay £P66 ($264) in addition. The program of the School is similar to the government program although some of the subjects are taught in English instead of Arabic. Much emphasis, however, is laid on a high standard in Arabic. Students prepare for the London, as well as the Transjordan matriculation, examinations. In addition to the regular program of the School, informal activities include a literary society, Boy Scout troops, the YMCA, a hiking club, Sunday school, and a choir. A magazine containing articles in English and Arabic is published at the end of each school year. Of the 10 graduates of the class of 1945, 4 continued their work at the American University of Beirut, 1 is teaching in a government secondary school, and 5 are employed in government offices or in business.

The Bishop's School has attractive stone buildings which were constructed for the School. Classrooms are not large, but since classes are restricted in size they seem quite satisfactory. An area adjoining the buildings has been leveled off to form a football field and tennis courts. The boys seem much interested in sports activities. A cooperative society of present and former pupils operates a shop where sweets, stationery, and other requirements of boys are met.

Part Five



SYRIA

SYRIA

Population: *3,300,000 at the end of 1946 (estimate).*

Area: *171,104 square kilometers (66,063 square miles).*

Form of government: *Republic. President is elected for five years by the Chamber of Deputies (unicameral). Members of the Chamber of Deputies are elected by universal male suffrage. The Prime Minister is selected by the President. The Prime Minister nominates members of his Council of Ministers (cabinet), who are appointed by the President but responsible to the Chamber of Deputies.*

Principal occupations: *Agriculture, trade, professions, industry.*

Principal exports: *Cereals, fruits and nuts, meats, wool and hides, textiles.*

Principal imports: *Manufactured wares, mineral and chemical products, fuels, cotton goods, woolen textiles, foodstuffs (meats, fruits, rice, sugar, spices).*

Monetary unit: *Syro-Lebanese pound (£S) equivalent to $0.4576.*

Chapter 20

ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

EDUCATION in Syria underwent a process of radical change in the years 1943–46. As Syria was under French mandate prior to World War II, the educational system had been gradually shaped after the French model with a twelve-year ladder of general education involving a primary-certificate examination, an examination for the *brevet,* and examinations for the *Baccalauréat,* First and Second Parts, the former divided into scientific and literary sections, and the latter into mathematics and philosophy sections. While instruction was in Arabic, French occupied a prominent place in the curriculum. The French adviser to the Ministry of Education wielded decisive influence over the educational decisions of the Ministry. Almost all educational missions were sent to France, and French-trained Syrians held the key positions in administration and teaching.

With the declaration of the independence of Syria in 1941 and the holding of new elections which resulted in a nationalist victory, it was natural that the new Syrian government should wish to pursue a national policy in education, free from French influences, and calculated primarily to develop a Syrian-Arab type of education.

In order to do this, the Syrian government procured the services of the well-known Arab educator, Sati' al-Husri, a man of outstanding ability who, after making a special study of Swiss, French, and Belgian education, had become the most prominent educator in Turkey prior to 1914. After the separation of the Arab provinces from Turkey he joined the short-lived Arab government of the late King Faysal in Syria as its Minister of Education. Upon the fall of this government he accompanied King Faysal to Iraq where he became Director General of Education, laying the main foundation of the Iraqi educational system and continuing to exercise considerable influence on that system until 1936. He left Iraq in 1941 to reside in Lebanon, and since he was of Syrian origin, he was invited by the Syrian government to study its educational system and report on

possible reforms. He brought to his task a decided nationalist outlook and considerable experience with the problems of education in the Near East. His sixteen reports, written between March and July 1944, have been published in one volume.[1] The recommendations of these reports served with very slight changes as the basis for the new educational organization in Syria, and inspired the laws and regulations which are now in force. The new policies constituted a sharp turn from French educational policies as they had been applied in Syria and caused considerable controversy and some armed conflict as late as 1945.

One of the causes of contention was the new education law (No. 121, "Embodying the Organization of Public Education") which was passed in December 1944. It provided, among other things, that no foreign language was to be taught in elementary schools. This meant the abolition of French from elementary schools, where it had formerly been required. The new law provided that a first foreign language was to be taught beginning with the first secondary year and a second foreign language beginning with the fifth year. Students were given their choice, thus putting French on an equal footing with any other foreign language—notably English, which was becoming increasingly popular.

The Franco-Syrian clash of May 1945, when the French bombarded Damascus, resulted in the boycotting of French schools by the Syrian population, and they were compelled to close. As the year 1945–46 approached, French schools were told that to be allowed to reopen they would be required to register with the Ministry of Education, submit to supervision by the Ministry, follow the syllabuses of the Ministry in the teaching of the Arabic language, Arab history and geography, and comply with certain other conditions. Almost all French schools failed to do this and, therefore, remained closed. A few schools formerly registered as French now registered as national schools, put a Syrian citizen at the head of the school, and were allowed to open. These were usually schools run by Syrian monks or sisters.

The closing of the French schools, which had an enrollment of 19,503 in 1944–45, created a serious situation for the Ministry of Education. Thousands of students were confronted with the possibility of not being able to attend school, at the same time that the demand for education was increasing rapidly. The government, therefore, took drastic measures. A special budget annex was passed. Six new secondary schools and 52 new

[1] Sati' al-Husri, *Reports on the State of Education in Syria and Recommendations for Its Reform* (Damascus: Ministry of Education, Republic of Syria, Dar al-Hilal Press, 1944) 304 pp. (In Arabic.) Most of the statistical data on education in this chapter come from the al-Husri reports unless otherwise identified.

elementary schools are opened throughout the country. In addition, new classes and divisions were opened in the existing schools. Private schools were encouraged to open new classes, and special financial aid was offered for the opening of new private schools. Naturally, most of this effort was spent in the larger cities where most of the French schools had existed. Public secondary-school enrollment increased by 1,930 students in the six cities of Damascus, Aleppo, Latakia, Homs, Hama, and Tartus. Public primary schools had an increase of 6,718 pupils in the same cities, excepting Tartus. Private schools also registered large increases, an increase of 2,458 pupils taking place in the private primary schools of Damascus alone.

It is claimed that these measures dealt with the situation effectively enough to accommodate almost all the children who applied. Some secondary-school students, uncertain of being admitted to schools in Syria, arranged early to go to school in Lebanon. Because many of the measures were hastily improvised, they left something to be desired, but the emergency created by the closing of the French schools was met. It is with this state of emergency and the radical departure from French methods and influence in mind that the following description of the Syrian school system should be read.

Administration

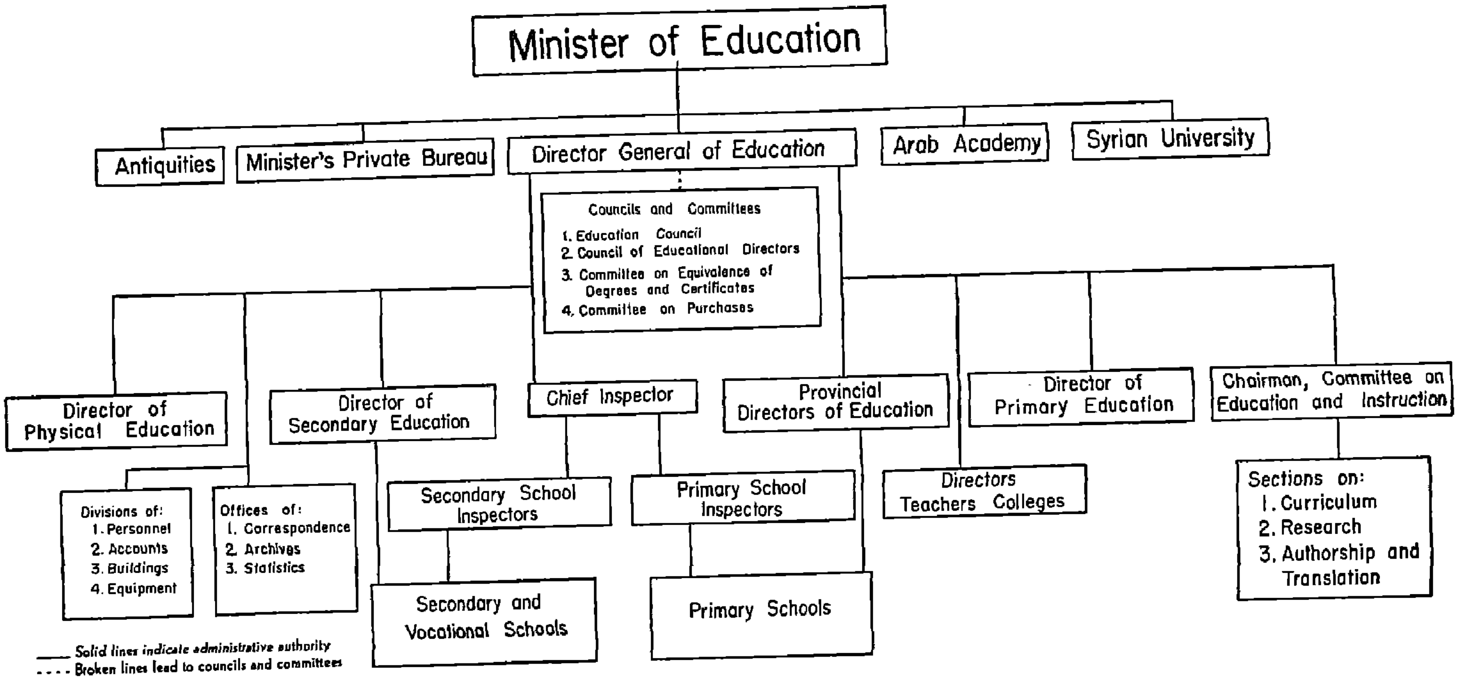
The administration of public education in Syria, as in the other Arab countries, is centralized and is controlled by the Ministry of Education. The Ministry provides almost all the money for public schools, educates and appoints the teachers, establishes the curriculum, prescribes the textbooks, and holds public examinations at the end of the primary, intermediate, and secondary courses.

The organization of the Ministry of Education and its departments is set down in a special decree (No. 224, "Embodying the Organization of the Ministry of Education") and a special law (No. 202, "Limiting the Number of Officials of the Ministry of Education"), both of which were issued in 1945. The organization is shown in Chart XI. At the head is the Minister of Education, who is a member of the Cabinet and is responsible to Parliament for the educational policies of his Ministry, and, with the aid of the Director General of Education, for the proper execution of the laws and regulations. All decisions and instructions are issued in his name and executed under his supervision. The Minister has his own Private Bureau which handles his appointments, correspondence, and controls all papers and documents entering or leaving his office.

Next in authority to the Minister is a Director General of Education,

Chart XI

SYRIA: ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF THE MINISTRY OF EDUCATION, 1946



who is the administrative head of all the departments of the Ministry and supervises the work of all the department officials and the proper operation of the schools. He appoints the officials of the central office and specialists in secondary and vocational education belonging to the second and third grades in the salary scale, and recommends to the Minister the appointment of officials of the higher grades. He is empowered to issue general notices and administrative instructions to help clarify ministerial instructions and to facilitate the running of his departments.

The Director General is assisted by three directors: the Director of Secondary Education who has charge of the affairs of all intermediate, preparatory, and vocational schools; the Director of Primary Education, who supervises primary and elementary schools; and the Director of Physical Education, who assists the Director General in organizing physical education, including scouting activities, sports, and organized games in and out of school.

Seven divisions and bureaus conduct the everyday business of the Ministry. The Division of Personnel keeps a complete register of all that pertains to the officials and teachers of the Ministry of Education. The Division of Accounts supervises the accounts of all departments, prepares budget estimates and is responsible for the execution of the budget law. The Division of Buildings, headed by an architect, draws the plans for school buildings and supervises all construction, repairs, and maintenance work in schools belonging to the Ministry. The Division of Equipment has charge of the central stores of the Ministry, of keeping textbooks and school furniture and equipment until they are distributed to the schools. In addition, there are the three bureaus of Correspondence, Archives, and Statistics, the functions of which are sufficiently indicated by their titles.

There are ten provincial directors of education, one each for the city of Damascus, Damascus Province (excluding the city), Hawran, Jabal Druze, Homs, Hama, Latakia, Aleppo, Jazirah, and Euphrates Provinces. These directors have charge mainly of primary education in their provinces and of supervising private schools. They are under the double jurisdiction of the Ministry of Education, from which they receive their instructions and approval of their proposals, and of the governor of their province, through whom they issue their orders and conduct their correspondence with higher authorities. The powers of the provincial directors of education during the regime of the French mandate were very limited. They were then called inspectors of education. Even the appointment of a janitor to a post already provided for in the budget needed to be referred through the governor to the Ministries of Education and Finance and was not final

until taken cognizance of by them and published in the Official Journal. Even the salary of the janitor was not paid until this publication took place, which sometimes stretched into months. This procedure resulted in delays in the appointment of teachers and was detrimental to their financial position and their morale. Efforts are now being made to expedite this procedure.

Side by side with the administrative machinery stands the inspectoral staff. Headed by a chief inspector, it consists of two types of inspectors—secondary and primary. The basic duties of inspectors are defined as supervising the work of principals and teachers of schools, guiding them into the better interpretation and application of programs and curriculum, showing them better methods of teaching, correcting their mistakes, and orienting their activities. They are further charged with keeping the Ministry informed of the conditions of teaching in the schools, the needs of the schools, and the activities and abilities of teachers and principals. They study the educational needs of the cities and villages and do publicity work for education among the people.

Secondary inspectors are appointed on the basis of the subjects in which they have specialized. They have their headquarters in Damascus and are sent to inspect schools according to a plan worked out by the central office. At the time of the visit of the American Council Commission, the inspectors of secondary schools were visiting schools as a team, each inspecting his own subject or subjects in the same school.

Primary inspectors are not expected to be specialists in any one school subject. One or more are attached to each province and inspect the schools of that province according to a program worked out with the director of education of the province. Special inspectors may be appointed for the special subjects—for example, physical education, manual arts, agriculture—and for private and foreign schools in the larger towns where these abound. Inspectors' reports are submitted in two copies, one for the provincial director of education, and one for the chief inspector's office at the Ministry. The provincial director then takes such action as he sees fit, based upon the report.

A third department of the Ministry under the Director General is the Committee on Education and Instruction. It is made up of a chairman and three permanent members, with power to elect other workers from among the officials, inspectors, and teaching staff of the Ministry. The committee is a professional body which is put in charge of making school curriculums, laying down educational policies and plans as well as school regulations; selecting suitable textbooks and books for school and public libraries;

writing and translating books and articles and issuing educational periodicals; collecting information about educational systems abroad for the benefit of the Ministry and the school system and for the purpose of establishing the equivalence of degrees and diplomas; preparing and studying statistics about the school system; preparing plans and courses for teachers institutes and conferences; conducting educational experiments; and, finally, studying any professional question laid before it by the Ministry. The committee is supposed to include a representative of each of the important fields of specialization, each mastering "one of the languages of world culture to ensure that the committee shall have access to the most important cultural and educational publications appearing in Europe or America." Each member is required to teach no more than four periods a week in one of the teachers colleges and is empowered to visit schools. The committee is divided into three sections: one on curriculum, one on educational research, and one on translation and authorship.

In addition to the three main divisions of the Ministry of Education there are two councils and two committees provided for in the decree, with other committees to be formed by administrative order when necessary. These are the Education Council, the Council of Directors of Education, the Committee on the Equivalence of Degrees, and the Committee on Purchases.

The Education Council is composed of the Director General of Education as chairman, the chairman of the Committee on Education and Instruction, the Inspector General, and the section Directors of Primary, Secondary, and Physical Education. Its function is to pass on proposals coming from the appropriate departments with regard to curriculum, textbooks, the budget, proposed laws and regulations, and any other matter submitted to it by the Minister.

The Council of Directors of Education meets under the chairmanship of the Director General of Education and is made up of the Inspector General, the Directors of Primary, Secondary, and Physical Education, and the provincial directors of education. It meets once a year to discuss the school staffs and the educational needs of the provinces, to pass on proposals for opening new schools and expanding existing ones, distribution of teachers, and allocation of the budget among the provinces.

The Committee on the Equivalence of Degrees meets under the chairmanship of the Director General, and has as its members the chairman of the Committee on Education and Instruction, the Inspector General, the Director of Secondary Education, and a representative of the Syrian Uni-

versity. The committee makes its decisions on the basis of reports submitted to it by the Section of Educational Research of the Committee on Education and Instruction.

The Committee on Purchases is under the chairmanship of the accountant of the Ministry, with two other members appointed by the Director General of Education. It has charge of all buying of equipment, of receiving bids, and of preparing the contracts of the Ministry.

Beside the Directorate General of Education and its branches covering the system of public education for the entire country, three other institutions and agencies are connected directly with the Minister of Education:

1. The Department of Antiquities is headed by a director who is under the jurisdiction of the Minister. It has charge of the museum of antiquities, supervises all excavations, and preserves archeological sites. Its regulations are incorporated in Decree No. 352 (1945) "Embodying the Regulations of the Directorate of Antiquities."

2. The Syrian University, which until 1946 consisted of the Faculties of Medicine and Law, was in the process of reorganization at the time of the visit of the American Council Commission. It is described in chapter 22.

3. The Arab Academy, which was founded during the Arab government regime following World War I, is a body of learned Arabists, which has its own assembly of members in Syria and corresponding members in other Arabic and Islamic countries as well as among orientalists. It holds public lectures, issues a magazine known as the *Review of the Arab Academy* which appeared first in 1920 and in which are published the researches and studies of its members. It also maintains a public library which contains about 20,000 printed books and more than 4,000 Arabic manuscripts. The Academy has at times attempted to lay down Arabic equivalents to modern scientific terms.

Educational Finance

Educational finance in Syria is centralized. The bulk of the expenditure on the schools and their equipment, on the salaries of teachers and janitors, comes from the budget of the Ministry of Education, which is a part of the general budget of the Syrian Republic. The Ottoman Education Laws of 1869 and 1913, which had remained the basic education laws during the French-mandate period, had provided that the expenditures of elementary schools should be borne by the local authorities. This, however, remained more a theoretical than a practical possibility in most of the Ottoman Empire. In Syria, some school buildings were provided—in Turkish, as in French, days—by the central governments, some by the localities or

municipalities, and the majority were, and are still, rented buildings, the rent being paid from the central budget. Salaries and other expenses are also paid from the funds of the Ministry of Education.

Table 56 gives a picture of the growth of the educational budget since

TABLE 56

GROWTH OF THE EDUCATIONAL BUDGET, SYRIA, 1923–46

Year	General Budget	Educational Budget	Percent of General Budget	Number of Government Schools	Enrollment in Government Schools
1923*......	£S 3,970,640†	£S 361,914	9.1	310	22,443
1931*......	11,932,693	1,170,892	9.8	479	45,491
1941†......	13,603,100	2,272,623	16.7	...	...
1945‡......	103,678,000	9,953,568	9.6	694	93,727
1946‡......	129,704,000	14,127,388	10.9	...	...

* Actual expenditure. Figures from the annual *Rapports sur la Situation de la Syrie et du Liban* (published by the French Government).
† The rate of exchange of the Syro-Lebanese pound was £S2.18 to the dollar in 1946.
‡ Estimates. Figures from the Ministry of Education.

the early days of the French mandate. Although the table shows a very large increase in budget allotments for education from £S361,914 in 1923 to £S14,127,388 in 1946, these figures should not be taken at their face value. The Syro-Lebanese currency, being based on the franc, had fluctuated in value along with the franc until 1943. Moreover, the increased amounts for 1945 and 1946 show clearly the influence of inflation. The budgetary provisions, therefore, are not based on the same rates of value. For this reason it would not be correct to say that the budgetary provision for education in 1946 was about thirty-nine times that of 1923. About the only thing that can be said is that the Syrian government, anxious in this era of independence to expand public education, is giving generously to the Ministry of Education. A budget of about £S16,000,000 was planned for 1947.

It will be seen from Table 56 that the percentage of the educational budget to the general budget has fluctuated from 9.1 to 16.7. In spite of the rapid increase in the general budget, the educational budget, while growing remarkably in the last four years, did not keep pace with the general budget. The percentages declined from 16.7 in 1941 to 9.6 in 1945 and picked up somewhat in 1946. This is a phenomenon that has been common in most of the other Arab states in the last few years. The 1945 budget was supporting 694 public schools of all types and 93,727 pupils in these schools, representing respectively 2.2 and 4.2 times the number of public schools and number of pupils in 1923.

The distribution of the budget over the various fields of public education in 1945 is shown in Table 57.

In the year 1944–45 there were 85,540 pupils in the public primary schools and 6,331 in the public secondary and teacher-training institutions. Thus, the average per pupil cost of a public primary school was £S61 (about $28) while that for a secondary or teachers-college pupil was £S278.6 (about $127.30). The latter figure includes the expenditure for boarding students both in some of the secondary schools and in the teach-

TABLE 57

BUDGET OF THE MINISTRY OF EDUCATION, SYRIA, 1945

Allocated to	Amount	Percent
Administration	£S 402,052	4.0
Primary education	5,220,000	52.5
Secondary and teacher education	1,763,720	17.7
Vocational education	630,596	6.3
Higher education and other cultural institutions	1,937,200	19.5
Total	£S9,953,568	100.0

ers colleges. Primary education is free. In secondary education fees are charged at the rate of £S48 for intermediate schools and £S60 for secondary schools (upper two classes) with exemptions to be detailed later. Boarding students pay a fee of £S300 in addition. In vocational schools no tuition fees are charged, but boarding students pay a boarding fee of £S240 per year, although some students receive free board and lodging. Education in the teachers colleges is entirely free, students not only receiving free board and room, but also £S15 a month for pocket expenses. Day students receive £S50 a month toward their board and lodging and £15 for pocket expenses. In the Syrian University tuition fees of £S120 are charged, but with about 25 percent of the students exempted. Additional fees are levied for the library and for physical education.

Revenue from fees goes to the Treasury and cannot be used directly by the schools or the Ministry of Education. Expenditure follows strictly the provisions of the budget.

The financial problem which public education in Syria faces is the same as that of the other Arab countries—to find the funds necessary to put into effect a program of universal education. So long as almost total reliance is placed on the central government budget, little hope can be entertained of reaching that goal. With the budget of the central government so pressed by the requirements of the various departments and agencies of the state, it is not possible to expect more than a limited increase in the budget provisions for education. The proposal, therefore, has been made that the way out of this situation is by the imposition of a

special education tax levied by the local authorities.[2] This could be done in two stages, first by making the local communities pay for the erection of school buildings and later by making them bear all other expenses, including the salaries of teachers. Steps were being taken in 1946 to put the first stage into operation.

Teachers' salaries

At the time of the visit of the American Council Commission in April 1946 the decree law governing the appointment, promotion, and salaries of teachers was on the point of being superseded by new decrees which were then in the making. A short sketch of the old decree law (No. 163, dated August 11, 1943) will be presented here in order to give an idea of the kind of practice which prevailed under French auspices and which is bound to leave its effect on the grading of teachers for some time. This will be followed by a summary of the new decrees defining the new cadres of the Ministry of Education.

The old decree law differentiates between the categories of teachers and of principals of schools, giving the latter a separate scale which was higher than that of the teachers. Teachers proper were divided into two categories: secondary (called professors) and primary teachers.

Secondary teachers were classified into six groups: head professor, group one professor, group two professor, group three professor, associate professor, and assistant professor. Each of these groups was further subdivided into four grades —distinguished, first, second, and third. This made a total of twenty-four grades for secondary-school teachers, for which the monthly salaries of the lowest grade ranged from a minimum £S60 ($27.50) to a maximum of £S75 ($34.40), and of the highest grade, a minimum of £S185 ($84.80) to a maximum of £S215 ($99). Grades and professorial groups overlapped in the salaries assigned to them to such an extent that the maximums and the minimums of three out of four grades in every group were the same as those of three grades in the next higher or lower group. This made a very complicated system.

Secondary teachers' salaries and their classification were closely linked with French degrees and diplomas. Each of the types of professors had to have one or more of the certificates of higher education leading to the *Licence ès Lettres* or *ès Sciences*.[3] In order to be appointed to the lowest secondary-school teaching post—that of associate professor—a candidate had to possess one certificate. One additional certificate was added for each of the four higher posts mentioned above until five certificates and a state or university doctorate were required for the head professors. As no colleges of arts and sciences existed at the Syrian Uni-

[2] Al-Husri, *op. cit.*, pp. 263–65.

[3] The *Licences ès Lettres* and *ès Sciences* are the first French university degrees. An undergraduate student had to secure certificates in four fields before he became eligible automatically for the *licence*.

versity, the medical and law degrees of this institution were equated to four and three certificates respectively. In order to occupy the three higher ranks of secondary-school teaching, therefore, a candidate had to go to France to secure the required certificates. Degrees from other countries were equated, by a special committee if necessary, but holders of French or Syrian degrees or certificates were given an advantage. Although the decree law was extremely detailed and explicit, it gave no bases for the equation of well-known degrees from other countries. The degree of Bachelor of Arts of the American University of Beirut (an institution recognized in America as a Class A institution) was recognized as equivalent only to the secondary-school *Baccalauréat,* Second Part, a fact which barred its holders from teaching in the public secondary schools.

The same method of classification and assignment of salaries was followed in the case of primary teachers. These teachers were grouped into seven groups of four grades each. The upper three groups were reserved for graduates of primary-, elementary-, and "practical" teachers colleges in descending order, while the lower four groups were open to candidates who had only the second *baccalauréat,* first *baccalauréat,* or the primary-school certificate with four years of secondary work, again in descending order. Each grade had its minimum and its maximum. The lowest grade carried a minimum salary of £S33 ($15) and a maximum of £S42 ($19), and the highest grade carried a minimum of £S97.5 ($44.70) and a maximum of £S120 ($55). Salaries of women teachers were fixed consistently one grade lower than those for the men even though they had the same qualifications.

A special cadre was drawn up for secondary- and primary-school principals, the former in four groups of four grades each, and the latter in two groups of four grades each. As in the case of the teachers, each grade for the principals had a maximum and a minimum. The lowest grade for a secondary-school principal carried a minimum of £S97.50 ($44.70) and a maximum of £S130 ($55), while the highest grade of principals received a minimum of £S205 ($94) and a maximum of £S247.50 ($113.50). Differentiation among principals was not on the basis of academic or professional qualifications, or on experience and length of service, or on tested ability, but on the type of school administered—whether a primary-, elementary-, or vocational-teachers college, a secondary or a vocational school, and whether it was a day or a boarding school, and if a day school whether it had more or less than 300 students.

Primary-school principals were classified into two groups of four grades each. The higher group was for principals of large schools of ten or more classrooms and the lower group was for smaller schools of at least five classrooms. The range in salaries was £S70 to £S100 ($32 to $45.80) for the lowest grade, and £S112.50 to £S150 ($51.60 to $68.80) for the highest grade. Like the grades and the salaries of the secondary-school teachers, those for primary teachers and for principals greatly overlap one another.

It would take too long to give even a summary of the rest of the decree law, the details of which fill seventeen large pages, each of two columns of small print, dealing with conditions of choice of teachers, the types of studies and combinations of studies recognized, the conditions and emoluments of part-time teaching and supervising of students in the schools, and so on.

In his *Reports on the State of Education in Syria*[4] Sati' al-Husri levels a number of criticisms at the decree summarized above and makes certain recommendations. As his criticisms and suggestions point the direction which reform of this phase of the Syrian educational system is taking, a summary is given.

1. Exception is taken to the close tying-up of grades and salaries to the French type of diplomas and degrees on the ground that the French practice of accumulating certificates toward the degree of *licence* is not found in most other countries; indeed, it is the exception. To base teachers' appointments on it, therefore, is to create unnecessary difficulties in the way of dealing with degrees secured from other sources. Moreover, the certificates in French higher education have value only as leading to the degree of *licence* and should not be considered as separate entities or stages which would entitle a person to take teaching positions as laid down in the decree. In another connection the writer warns against blind imitation of one system of education (in this case the French) and declares that Syrian education had been for a quarter of a century under the monopoly of the French type of educational organization. He advocates a diversification of the sources of educational ideas from different countries with the idea ultimately of creating "a special Syrian-Arab type of educational organization."[5]

2. The decree, in overemphasizing certificates, gave little if any weight to the teacher's length of service and experience and to his ability and enthusiasm in his teaching. This tends to discourage the good teacher and creates a current of dissatisfaction among teachers. Any arrangement for the service of teachers should take account of these factors.

3. It makes a special classification for principals, distinct from teachers, with a considerable difference in salaries. This is not based on a sound educational principle and would tend to draw the best teachers toward school administration, to the detriment of good teaching and scholarship. Besides, to base the classification of principals on the sizes of the schools and not on ability and qualifications is not in the public interest, for a small but important school may require the appointment of one of the ablest men among principals.

4. There is no justification for setting the salaries of women teachers at a lower rate than those of the men. Salaries should be according to qualifications regardless of the teacher's sex. Otherwise, an injustice would be done to women at a time when more women are needed in teaching and should be encouraged to get into the profession.

5. The practice of promoting primary-school teachers into the field of teaching in secondary schools under the title of "assistant professors" is one of the main factors of weakness in this field, particularly when these are confirmed in their new positions. A better practice would be to keep them as teachers "delegated" from the primary schools until such time as the need for them ceases, or until special courses and classes are opened to enable them to raise their level.

6. Finally, the system of overlapping groups and grades is very confused and

[4] Al-Husri, *op. cit.*, pp. 11–32.
[5] *Ibid.*, pp. 47–49.

confusing and should be replaced by a simpler system where the various grades meet end-on, providing a consecutive scale.

Sati' al-Husri's criticisms have provided some of the bases for the new cadres of the Ministry of Education. These were passed shortly after the Commission of the American Council on Education left the Near East.[6] They were based on the *Basic Officials' Law* which had been passed earlier in the year and which lays down a new basic salary scale for all officials.

The new law divides state officials into twelve levels, from the eleventh at the lowest to the first, with a "distinguished" level on top. Each of these levels is divided into three grades with a minimum and a maximum salary. The minimums and maximums for each level, however, usually do not overlap, but meet end to end. Thus, the lowest level, the eleventh, is divided into three grades as follows:

Grade	Monthly Salary	
Grade 3 (minimum)	£S30	($13.76)
Grade 2	35	(16.05)
Grade 1 (maximum)	40	(18.35)

This increment continues at the rate of £S5 for each grade up to the sixth level, then at the rate of £S10 through the fifth, at the rate of £S15 through the third, of £S25 in the second, of £S30 in the first, and £S40 in the "distinguished" level. The salaries for this last level are:

Grade	Monthly Salary	
Grade 3 (minimum)	£S420	($192.66)
Grade 2	460	(211.00)
Grade 1 (maximum)	500	(229.39)

Thus, the lowest official in the state receives a basic salary of £S30 ($13.76) a month, and the highest receives £S500 ($229.39) a month.

According to the new decrees embodying the education cadres mentioned above, primary-school teachers are classified into five ranks, of which the tenth level (minimum salary, £S45) is their lowest appointment, and they may reach up to the fourth level (maximum salary, £S175). Graduates of the primary-teachers colleges are first appointed in the middle grade of the eighth level (£S75), graduates of secondary schools in the lowest grade of the ninth level (£S55), and graduates of intermediate and vocational schools in the lowest grade of the tenth level (£S45). Only graduates of teachers colleges may be promoted beyond the eighth

[6] Legislative Decree No. 61, dated October 20, 1946, "Embodying the Cadre of the Officials of Primary and Secondary Education"; and Legislative Decree No. 62, dated October 21, 1946), "Embodying the Cadre of the Officials of Secondary and Vocational Education," *Official Gazette of the Syrian Republic,* Vol. XXIV, No. 44, October 21, 1945, pp. 1479–83.

level without taking competitive examinations. The others must pass theoretical and practical professional examinations before they may be promoted beyond the eighth level. Salary scales are the same for men and women, and for teachers and principals. A principal, however, is given an additional allowance.

Secondary- and vocational-school teachers are classified into seven ranks and may be appointed, depending on their qualifications, at the bottom of the seventh level (minimum salary £S85) and may reach up to the second level (maximum salary £S290). To be appointed to the secondary or vocational schools, a candidate must hold a university degree beyond a secondary-school certificate. The bearer of a doctorate in literature or in science based on a *licence,* or master's degree, in arts or science may be initially appointed in the middle grade of the fourth level (£S150). The holder of a *licence,* or a master's degree, in arts or science may be appointed in the lowest grade of the fourth level (£S145), while the holder of a B.A. honors degree from an American university is first appointed at the highest grade of the fifth level (£S130). Candidates without these qualifications may be appointed when need arises after passing a competitive examination, provided they are either graduates of secondary schools who have had at least two years of university studies or are graduates of primary-teachers colleges who have had at least five years of experience in teaching, or are secondary-school graduates with at least six years of teaching experience. These may be first appointed only in the lowest grade of the seventh level (£S85) and cannot be promoted beyond the sixth level except after passing a further examination. The same salary schedule prevails for men and women, and for principals and teachers. Principals of boarding schools and their assistants, however, receive an allowance for their added responsibilities.

Both primary- and secondary-school teachers may receive leave for study without pay in order to improve themselves professionally. Any diploma or degree which they might receive as a result entitles them to corresponding increases in salary. The two decrees provide for commissions which will study the individual cases of every teacher and regrade him or her according to the new scale.

Owing to the wartime inflation, however, teachers, like all government officials, were given cost-of-living allowances. In 1946 these were 180 percent for £S40 or below, 120 percent for salaries between £S41 and £S80, 90 percent for salaries between £S81 and £S150, and 45 percent for any salary of £S151 or above. In addition, there were allowances for a wife and children. Thus, the salary of £S40 rises to £S112, while the highest

salary paid, £S500, becomes £S912.5 ($418.57), not including allowances for the wife and children.

A system of pensions for government officials provides for a pension amounting to half the average final salary after thirty years of service. Teachers automatically fall under this plan.

Educational Legislation

Five articles of the Syrian Constitution (Articles 19–23) deal with education. The freedom of education is guaranteed in so far as it is not contrary to public order and good morals and is not detrimental to the dignity of the country or of religion. Education is directed to raise the moral and intellectual standard of the people on lines best suited to the national characteristics, and to promote concord and a fraternal spirit among all citizens. Primary education is compulsory for all Syrians of both sexes and is free of charge in the public schools. The curriculum for public education is laid down by law in order to insure educational uniformity. All schools are placed under government supervision.

The provisional Ottoman Education Law of 1913 had never been completely superseded during the French mandate. The law of July 6, 1933, "Fixing the Orders and Stages of Public Education," and the various decrees and orders (*arrêtés*) issued during the mandate regime had determined the educational ladder, set down the curriculum, the public-examinations regulations, the internal administration of schools, the supervision of private and foreign schools, the sending of educational missions abroad, and various other aspects of education, repealing in each case the corresponding sections of the Ottoman law.[7]

The 1943 education law represents a somewhat radical departure from the law of 1933 and the collection of decrees and orders (*arrêtés*) which governed education under the mandate. Since it sets down the main provisions upon which the new educational structure has been and is being laid, a summary of it is given here.

The law defines the basic function of the Ministry of Education as "giving a good education to the new generation—in all aspects, physical, moral, and intellectual—in order that each of its individuals will grow with

[7] Excepting the orders regulating archeology (1933), the Syrian University (1926), and the Arab Academy (1943) which are to keep their force in so far as they do not conflict with the new law, until changed in their turn. The order regulating archeology was later superseded by Decree No. 352, "Embodying the Regulations of the Directorate of Archeology" (1945), while that regulating the University was superseded by Law No. 269 (1940) and Decree No. 40 (1945).

a strong body, good character, and sound thinking, loving his country, proud of his nationality, conscious of his duties, equipped with the knowledge which he needs in his life, capable of serving his country with his mental and physical powers, and with his productive efforts."

The activities of the Ministry of Education are defined as: (1) establishing and administering public educational institutions of all types and grades; (2) supervising private and foreign educational institutions and directing their activities toward the basic aims of public schools; (3) fighting illiteracy, and disseminating culture among all the people; (4) stimulating the energies of youth and organizing their affairs by encouraging sporting and scouting activities in and out of school; (5) stimulating scientific and literary movements through the founding and expanding of public libraries, scientific museums, publishing old and new books, organizing broadcasts, public lectures, pageants, founding and encouraging academies, societies and clubs, and aiding individual efforts in science and literature; (6) fostering economic education by strengthening the love of work and production in students and youth; (7) fostering fine arts in and out of school; (8) preserving the national antiquities and directing all matters of archeology; and (9) strengthening cultural ties between Syria and its sister-Arab countries with a view to creating a unified culture for the Arab world.

The law divides education into three main levels: primary (five years), secondary (six years), and higher education. Provision is made for special schools for children who have not attained primary-school age. Higher education is to be at the Syrian University and its colleges, the proposed Higher Teachers College and its branches, and any other specialized institutions. The organization of the University is laid down in a special law. The education law of 1943 provides that the Ministry of Education may found higher colleges independent of the University.

Schools are further divided, according to aim, into schools of general culture and specialized schools, such as schools of agriculture, industry, commerce, and fine arts. Vocational education is to be provided in special classes or schools of all levels, some being complementary to primary education, others parallel to intermediate or secondary schools, while still others would be higher institutions.

Three kinds of institutions for the education of teachers are contemplated in the law: elementary-, primary-, and higher-teachers colleges. The first would prepare teachers for elementary and rural schools; the second would prepare them for primary schools; and the third would prepare them for intermediate schools. In addition, the Ministry of Education may

create special classes or courses annexed to the teachers colleges, or above vocational schools, for the preparation of teachers of special subjects—for example, art, physical education, manual arts, and home economics. No teachers may be employed in elementary and primary schools unless they are graduates of elementary- and primary-teachers colleges. In case of need, however, secondary-school graduates may be employed on a temporary basis, but may not be confirmed in their posts unless or until they have had the required teachers training and have passed a special examination in subjects of education and methods of teaching. Only graduates of the Higher Teachers College or of higher institutions in which they specialized in the subjects they are to teach may be appointed to intermediate and preparatory schools, except in case of emergency need, when temporary appointments may be made. Only candidates who have received a doctor's degree may be appointed to teach in higher institutions. Teachers of special subjects, such as physical education, art, music, home economics, manual arts, may be appointed regardless of the academic level they have reached provided they pass a special examination of aptitude in their subjects.

Teachers are prohibited from disseminating teachings leading to the corruption of character and to dissension, or teachings which are an affront to the dignity of the Syrian people and the Arab nation, or which make of education a means for political or partisan propaganda.

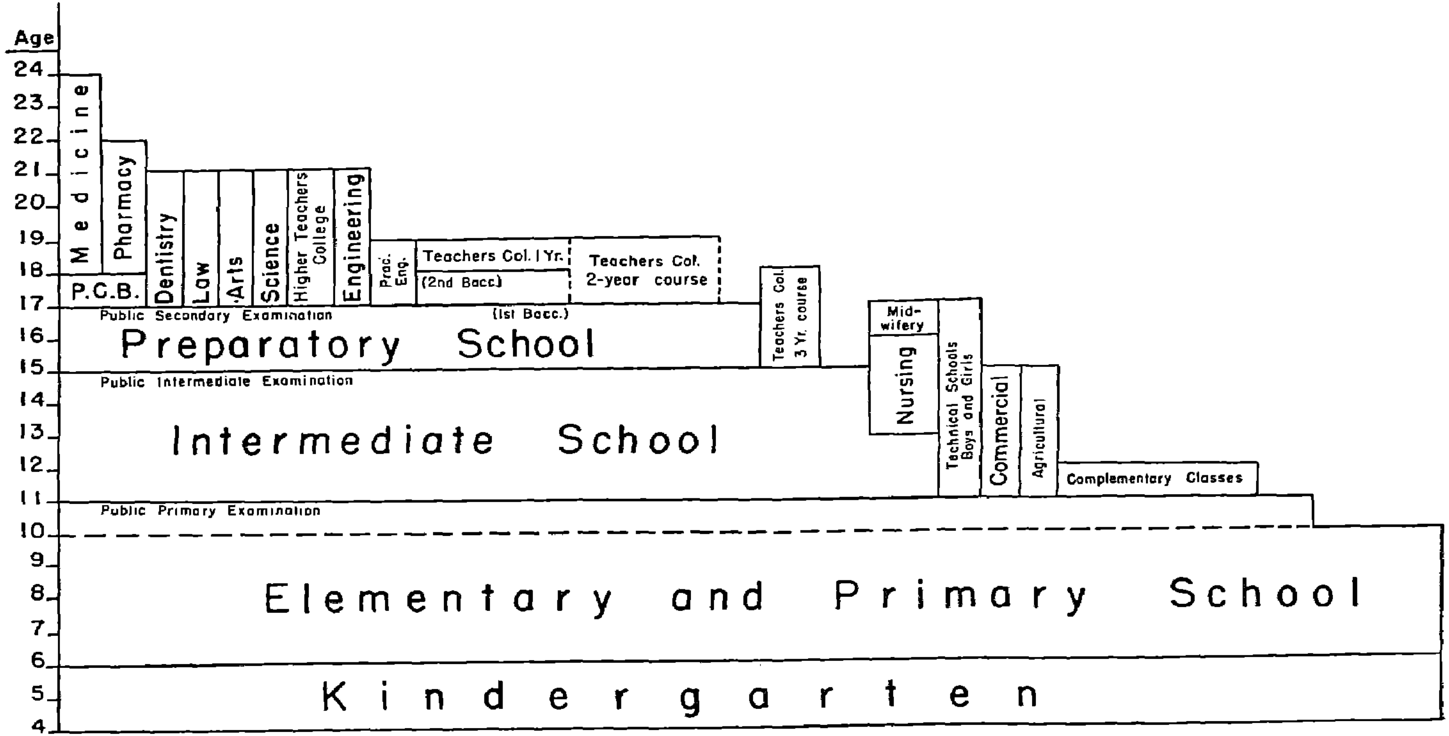
Finally, the law sets down the provisions for private and foreign schools of any kind or at any level, as follows: Written permission of the Ministry of Education is required before any such school may be established; all such schools must submit to the supervision of the Ministry of Education from all points of view—hygienic, educational, and moral; classes opened by individuals or groups for the teaching of one or more subjects (including languages or technical subjects) are regarded as schools, must secure permission, and are subject to supervision. The teaching of the Arabic language, Arabic history, and the geography of the Arab world, according to the course formulated by the Ministry of Education, is compulsory in all private and foreign primary and secondary schools. Private schools are forbidden to receive assistance from foreign sources except with the knowledge and approval of the Ministry of Education.

The Educational Ladder

The educational ladder in Syria, built upon the new education law, is shown in Chart XII. A comparison of certain features of the old 1933 law and the new 1943 law will help to bring out the salient points of the

Chart XII

SYRIA: PUBLIC SCHOOL SYSTEM, 1946



Abbreviations used above: P. C. B for Physics, Chemistry, Biology; Bacc. for Baccalaureate

reorganization. Both laws provide that primary education shall be compulsory and free.

The total period of primary education under the 1943 law is five years, the first four of which constitute a special cycle known as "elementary." While the old law differentiated between an elementary school of four years without French and a primary school of five years with two years of French, the new plan abolishes the teaching of French in the primary grades and makes the curriculum of the first four grades of both types of schools identical. The pupil finishing elementary school under the old regime had to repeat the fourth primary year if he wanted any further education; now he may transfer from the fourth elementary to the fifth primary grade without loss of time.

To enter the first grade of the elementary school, a pupil must have completed his sixth year of age. A basic curriculum is set down for elementary and primary schools, but this is to be adapted to the needs of the different sexes, on the one hand, and to the needs of urban and rural localities on the other. Although no foreign language may be taught in primary schools, the Ministry of Education may annex to any school in the cities a complementary class in which a foreign language and principles of keeping accounts are taught for the benefit of children who do not intend to proceed to secondary education.

Secondary education has been made more accessible. Formerly, a pupil was required to have attained a grade of *assez bien* (fairly good) in the primary-school certificate examination, or must have gone through an additional (sixth) primary year. Now, admission to a secondary school is open to all bearers of the Certificate of Primary Studies without regard to grade. A wide system of exemption from fees adds further to the accessibility of secondary education. This exemption may be made for as many as one-third or more of the student body, and may involve free board and lodging for promising out-of-town students.

Secondary education has been shortened from seven to six years, making the total of primary and secondary schooling eleven years, which is in line with the rest of the Arab countries studied in this report except Lebanon, which has kept its twelve-year system.

The six-year secondary school is divided into two stages: the first four years constitute the "intermediate" stage, the last two years, the "preparatory" stage. The preparatory stage is divided into literary and scientific sections, with different curriculums. Both stages lead to public examinations, which, if passed by the student, entitle him to the Certificates of Completion of Intermediate or Preparatory Studies respectively. The Minis-

try may add commercial, agricultural, and technical classes to any intermediate school if the need arises.

Under the French mandate, postprimary education was a two-ladder system. In addition to the secondary-school program which led to the University, two types of complementary courses were provided: a general complementary course of four years without a second foreign language, and professional complementary courses. The first led to the *Brevet* of General Complementary Education, after public examination. The professional complementary courses were of two types: one provided for a preparatory year followed by a program of from one to three years, leading to a professional (vocational) *brevet.* The other, following the four-year elementary school, gave a practical training of one to four years, ending in a Certificate of Practical Complementary Education. Holders of the two types of *brevets* and of the certificate were eligible for admission to technical schools, which usually gave a course of three years.

In practice, however, many of the "general complementary" schools were in reality incomplete secondary schools, having a curriculum identical with the corresponding secondary-school classes. The new law does away with the complementary courses.

A primary-school graduate may, therefore, either pursue a single-track secondary education or may enter one of the vocational schools.

The abolition of the teaching of French from the primary school has naturally affected foreign languages in the secondary school. Previously French was taught throughout the secondary school in continuation of its teaching in the last two primary years. A second foreign language was begun in the third secondary year. The new law gives the student the freedom to choose his foreign languages, one beginning in the first and the other in the fifth year of the secondary school, with the result that the overwhelming majority are now choosing English as a first language. Out of 1,000 pupils entering the first secondary year in Damascus in 1945–46, it was reported that only 37 chose French, the rest English. There arose, therefore, a great demand for teachers of English, a demand which cannot be satisfactorily met for the present.

Under the 1933 law there was a first *baccalauréat* examination at the end of the sixth year and a second *baccalauréat* examination at the end of the seventh; under the 1943 law there is an intermediate examination after four years, and a further examination after another two years upon the completion of the preparatory stage.

The division of studies into literary and scientific sections in the fifth and sixth years is maintained, but the sections of philosophy and mathe-

matics in the seventh year disappear with the abolition of that year in the shortening of the total secondary program from seven to six years.

There are two outlets for the graduate of the intermediate stage who does not go on to complete the full secondary-school program: (1) teachers colleges for both boys and girls, or (2) the School of Nursing, connected with the Faculty of Medicine of the Syrian University, for girls.

The situation in teachers colleges is in a state of transition. Previously a one-year course was offered for elementary-school teachers open to holders of the *brevet* or first *baccalauréat*, and another one-year course for primary-school and complementary-school teachers open to students holding the second *baccalauréat*. Later each of these courses was lengthened to two years. With the reorganization in 1943, three types of teacher-training courses are being maintained: (1) One year of professional education after the second *baccalauréat*. This was expected to disappear with the graduation of the last class of philosophy and mathematics in June 1946. (2) Two years after the first *baccalauréat* or after the sixth-year secondary course, offering a professional education for prospective teachers. (3) A three-year course after the intermediate-school certificate (old *brevet*). It is hoped that the latter type will become the standard course for the education of teachers, although the second course is likely to be continued for some time, owing to the shortage of teachers.

Finally, graduates of the full secondary program may go into the various colleges of the Syrian University, pursuing academic courses or one of the professional or technical fields—medicine, with its branches of dentistry, pharmacy, and nursing; law; engineering; or teacher-training. Requirements for admission, course of study, and examinations are discussed in chapter 22.

The reorganization of Syrian education did not come to pass without dissenting voices, mainly from individuals with a French educational background. Fear was expressed that the shortening of the secondary school from seven to six years would result in lowering the standard of Syrian general education. The fear was also expressed that, in attempting to preserve the main body of the seventh-year course (philosophy, mathematics), the new provisional course had introduced these subjects into the lower years, thus unduly crowding the course in these years, making it hard, if not impossible, for the teachers to cover all the ground adequately.

In answer to these criticisms it was pointed out that the former twelve-year combined-primary-and-secondary educational system in Syria is one year more than in Egypt, Palestine, and Iraq, among the Arabic countries,

and Turkey, Denmark, Rumania, Spain, Brazil, and a number of other countries. The twelve-year period in France and thirteen in Germany are due to the great attention paid there to the classics, the teaching of which is equal to more than a year. Moreover, the seventh-year course gave eleven out of twenty-four hours to the study of philosophy, a subject not given in secondary schools in many countries because it is believed to be beyond the capacity of most secondary-school students. Even where it is given, the time for it is much less than eleven periods a week, and Syria needs to give to the subject no more than three or four periods a week.[8]

The abolition of French from the primary-school curriculum, although it has had a much more favorable reception, has also been criticized. It is pointed out that the teaching of French in Syria is already much weaker than in Lebanon, where French is taught beginning in the first grade (even in the kindergarten), and many subjects, notably science and mathematics, are taught in French. Even in the period when French was required in the primary school, it was not begun until the fourth grade, and since the teaching was entirely in Arabic, students had little practice in the use of French.

A number of reasons are given for the abolition of French in the primary schools. The primary curriculum is very crowded and needs to be lightened. As the teaching of a foreign language at such an early age is considered by some to be educationally unsound, it is only natural that thought should be directed toward postponing its beginning to the later, more logical stage of secondary education. It is pointed out that few countries teach a foreign language in the primary school.

Public Examinations

Before the recent reorganization of education in Syria, there were four main public examinations held by the Ministry of Education. These were the examinations leading to the Certificate of Primary Studies, the *Brevet* of General Complementary Education, the *Baccalauréat,* First Part, and the *Baccalauréat,* Second Part. These were regulated by decrees and orders (*arrêtés*)[9] setting down the rules of the examinations. In addition, there were ministerial examinations for the vocational complementary education leading to the Industrial and Commercial *Brevets* and examinations for

[8] Al-Husri, *op. cit.,* pp. 113–20.

[9] Arrêté No. 29, "Certificat d'Etudes Primaires," of February 28, 1927 (in French and Arabic); Decree No. 68 of January 25, 1941, "Règlement du Brevet d'Enseignement Complémentaire Général" (in French); and Decree No. 242, "Regulations of the Syrian Baccalauréat of Secondary Education," dated March 9, 1938, supplemented by Decree No. 244 dated March 10, 1938.

the certificate of aptitude for primary and elementary teachers and for graduation from teachers colleges.

Examinations were both oral and written. There were six written and four oral primary examinations. Four of the written and two of the oral had to do with the Arabic and the French languages. No student was admitted to the oral examination unless he had passed the written examinations. Marks were on the basis of 10 for each subject; and, in order to pass, the student had to obtain half the total marks of all the subjects together and not receive a zero in any subject.

For the general *brevet* there were five written and six oral examinations. For the first *baccalauréat* there were four written and eight oral examinations for the literary and for the scientific sections. Examinations were weighted 1, 1.5, 2, or 3, depending upon the subject and the section. In the second *baccalauréat* there were three written and six oral examinations for the philosophy and for the mathematics sections. In all three secondary examinations marking was on the basis of 0 to 20. In order to pass, a student had to get an average of 50 percent and not receive a zero in any subject.

This examination system had been criticized[10] in that it gave too important a place to oral examinations, a fact which made strict evaluation of the students' work difficult, if not impossible, particularly since so many committees in various localities examined in the same subject, with all the differences in standards and tastes of the committees and the individuals composing them. The public examination is supposed to be an objective check on the work of the schools and the learning of the students; yet such a system made objectivity extremely difficult to achieve. Furthermore, the marking system was such that a student might be extremely weak in one, two, or even three subjects—receiving marks only slightly above zero in them—and yet through high marks in the other subjects reach the 50 percent required to pass. This gave the opportunity to many students, particularly in private and foreign schools, to pass in spite of their extreme weakness in the national language—Arabic.

The weighting of the subjects also followed a strange pattern. The total number of marks for oral and written primary examinations was 110, of which 35 were given to Arabic and 35 to French; 20 to mathematics; only 10 to object lessons, agriculture, and hygiene combined; and 10 to history and geography combined. In the written examinations for the *brevet,* 60 marks were given to Arabic, 40 to French, 40 to arithmetic, and nothing

[10] Al-Husri, *op. cit.,* pp. 233–42.

to science and history. Yet, in the oral examinations for the same stage the total mark for all the sciences was not equal to that of drawing, while that for history and geography was equal to drawing.

Accordingly, the new regulations for public examinations have attempted to eliminate these features and others besides.[11] Three, instead of four, examinations were prescribed—the primary, the intermediate, and the secondary. All examinations are to be written. The primary examination comprises six papers—Arabic grammar and dictation, Arabic composition, civics and ethics, history and geography, arithmetic and elements of geometry, and object lessons and hygiene.

The intermediate examination includes eight papers—Arabic grammar and literature, Arabic composition, first foreign language, civic and legal information, history and geography, mathematics, physics and chemistry, and biology and hygiene.

The secondary-school examination (given to three different sections) comprises eight papers. Each section has papers in the first foreign language, the second foreign language, and logic and psychology. In addition, the literary section has Arabic literature, history, geography, science, and general mathematics. The section for girls combines history and geography in one paper and adds child care and nursing. In addition to the subjects common to all, the scientific section has Arabic composition, history and geography, mathematics, physics and chemistry, and biology and hygiene. The papers are marked on the basis of 100. A student receiving a total of 60 and a mark of at least 40 in each subject passes.

Only one primary-school examination is held each year. Two are held each year for the intermediate and secondary stages, one in June and one in September. Students failing in two subjects or in the total may be re-examined in September, but students failing in more than two subjects or in one subject and the total have to repeat the year. In order to avoid too sudden a change from the old system to the new one, a transitory arrangement was worked out whereby lower standards were set for 1945 and 1946, the new standards going into effect in 1947. Thus, in 1945 the passing mark was to be 15 percent for each subject, and 40 for the total, while in 1946 it was to be 30 for each subject and 50 for the total.

[11] Decree No. 149, "Embodying the Public Examinations Regulations for the Certificate of Primary Studies"; Decree No. 150, "Embodying the Public Examinations Regulations for the Certificate of Intermediate Studies"; and Decree No. 151, "Embodying the Public Examinations Regulations for the Certificate of Secondary Studies," all dated February 6, 1945.

The questions are set by the Committee on Education and Instruction of the Ministry of Education and remain confidential to the day of the examination. The papers are marked by committees.

The public-examination results for 1943 and 1945 are given in Table 58. It will be noticed that the results for 1945 follow the same

TABLE 58

RESULTS OF PUBLIC EXAMINATIONS, SYRIA, 1943 AND 1945

TYPE OF EXAMINATION	1943			1945		
	Entered	Passed	Percent Passing	Entered	Passed	Percent Passing
Primary examination....	6,033	3,743	62.0	7,042	4,011	56.9
Brevet (intermediate)....	1,661	554	33.3	1,517	810	53.3
Baccalauréat, Part I.....	1,222	267	21.8	976	558	57.2
Baccalauréat, Part II....	744	125	16.8	604	370	61.1

classification that prevailed previously, as the new regulations did not come into full force until 1947.

It will be noticed that in the old system the percentage of those passing decreased steadily as the level of the examination rose. Whether this will be true under the new policy it is impossible to tell. The examinations in 1945 took place under exceptional circumstances; owing to the Franco-Syrian clash in May of that year, no examinations were held in June but were postponed until the fall.

Development and Extent of the Educational System

Table 59 shows the relative growth of public, private, and foreign schools and enrollments during the past quarter of a century. It was not possible to secure statistics for the years prior to 1923, nor were separate figures for boys and girls available for the early years. Information about the number of men and women teachers was not available for the years prior to 1943–44. In spite of these gaps, however, the table gives a fairly accurate idea about the expansion of education in the period following World War I, up to and including World War II.[12]

Table 59 shows that the schools increased from 562 to 1,165, and the enrollment from 53,403 to 162,818 between 1924 and 1945. Thus, while the schools are only two times their original number, the enrollment

[12] In their annual reports to the League of Nations, the French had kept separate statistics for Syria, Latakia, Jabal Druze, and Alexandretta. The latter has since been lost to Turkey. As the present Republic of Syria includes all the first three, the statistics for them have been combined throughout.

has nearly trebled. As compared with 1931, the schools increased 31 percent and the pupils 88 percent.

Of the three categories of schools, the public schools had the highest rate of increase. Compared with 1924 the number of public schools has more than doubled, while the pupil enrollment has almost quadrupled

TABLE 59

GROWTH OF SYRIAN EDUCATION, 1923–45*

YEAR	PUBLIC SCHOOLS		PRIVATE SCHOOLS		FOREIGN SCHOOLS		TOTAL	
	Number of Schools	Enrollment	Number of Schools	Enrollment	Number of Schools	Enrollment	Number of Schools	Enrollment
1923........	310	22,443†	190†	22,584‡	Not available		...	...
1924........	334	25,045	206‡	26,455‡	22§	1,903§	562	53,403
1931........	479	45,491	246	25,318	160	17,038	885	87,847
1941–42.....	626	76,852	331	42,213	168	22,950	1,125	142,015
1943–44....	664	83,186	311	40,983	155	22,529	1,130	146,698
1944–45.....	694	93,717	311	45,214	160	23,887	1,165	162,818

* Data for 1923, 1924, and 1931 from French annual reports to the League of Nations (1926, p. 34; 1931, p. 203). Data for 1941–42 from Conseil Supérieur des Intérêts Communs, *Recueil de Statistiques de la Syrie et du Liban, 1942–43* (Beirut: Imprimerie Catholique, 1945), pp. 24–25 and 38.
Data for 1943–44, from Sati' al-Husri, *Reports . . . , 1944*, pp. 63–66.
Data for 1944–45 supplied by the Ministry of Education.
† Not including the Syrian University.
‡ Including French schools.
§ Not including French schools. In later years French schools were included in the foreign group.

(374 percent). Compared with 1931, the public schools have increased by almost half their number (145 percent), while the number of pupils has slightly more than doubled.

It is not possible to determine accurately the growth of private and foreign schools separately, owing to the fact that, in the early years of 1923 and 1924, the reports of the French authorities included the French schools among the native private schools, and included only non-French schools in the foreign category. This was changed later. Taking the private and foreign schools together, we find that there were 228 such schools enrolling 28,358 pupils in 1924, compared with 471 schools and 69,101 pupils in 1944–45, an increase to 206 and 243 percent respectively. Comparing 1944–45 with 1931, the number of private schools increased by 65, bringing them to 126 percent, and by 19,896 pupils, raising the enrollment to 178 percent. The number of foreign schools has remained static, while enrollments have increased by 6,849, an increase to 140 percent. Compared with 1941, however, enrollments in foreign schools have only slightly increased. With the closing of the French schools in 1945–46, the number of foreign schools must have declined sharply because in 1944–45 the French schools constituted 74 percent of the foreign schools, and 82 percent of foreign-school enrollment. Thereafter most pupils went to public schools.

In 1924, enrollment in the public schools constituted less than half (46.9 percent) of the total enrollment in all schools. Enrollments in private and foreign schools together were more numerous, constituting 53.1 percent. This situation was reversed in 1944–45 when public schools enrolled 57.5 percent of the total; private schools, 27.8 percent; and foreign schools, 14.7 percent. The preponderance of the public-school enrollment was probably even more accentuated after the closing of the French schools in 1945–46, with the private schools also gaining considerably. This lead of both public and private schools will probably continue even if the French schools reopen, since many so-called "foreign" schools have joined the ranks of the private schools, and a large proportion of pupils who have transferred to government or native private schools are likely to stay there.

Distribution of schools by types

Table 60 gives the latest available data about the number of schools and of pupils distributed according to the types of schools—primary, secondary, vocational, teacher training, and higher—and according to the authority controlling the schools—public, private, and foreign.

There were in 1944–45 as many as 1,072 primary schools, of which 658 were public, 287 private, and 127 foreign schools. The public schools were attended by 85,540 children as against 43,010 in the private and 19,878 in the foreign schools. These represented 57.6, 29.0, and 13.4 percent respectively of the total primary-school enrollment. Of the total enrollment in all types of schools and educational institutions, that in primary schools represented 91.1 percent. In other words, less than one-tenth of the enrollment were in secondary schools, vocational schools, teachers colleges, and the University. It will be noticed that in the government schools boys and girls were taught in separate primary schools, while in the private and foreign schools there were two practices, separate schools and coeducational schools. There were 128 coeducational primary schools in existence during the year. Foreign schools on the whole were the larger, having an average enrollment of 156 pupils, closely followed by the private schools with an average enrollment of 153. Public primary schools had an average enrollment of 130. This is because private and foreign schools are situated in the larger urban centers for the most part, while many of the public schools are in sparsely populated rural districts.

There were 69 secondary schools in Syria in 1944–45, of which 22, or fewer than one-third, were public, 17 private, and 30 foreign. Nevertheless, the public schools accounted for more than half the student body (6,047 students, or 52.2 percent), while private schools had 1,743 stu-

TABLE 60

SYRIAN SCHOOLS CLASSIFIED ACCORDING TO TYPE OF SCHOOL AND TYPE OF CONTROL, 1944–45*

Type of School	Number of Schools				Enrollment			
	Boys	Girls	Coeducational	Total	Boys	Girls	Total	Percent
Primary and intermediate:								
Public	542	116	...	658	63,755	21,785	85,540	57.6
Private	158	40	89	287	28,800	14,210	43,010	29.0
Foreign	50	38	39	127	9,942	9,936	19,878	13.4
Total	750	194	128	1,072	102,497	45,931	148,428	91.1
Secondary:								
Public	14	8	...	22	4,557	1,490	6,047	52.2
Private	8	7	2	17	1,283	460	1,743	15.0
Foreign	9	14	7	30	2,639	1,163	3,802	32.8
Total	31	29	9	69	8,479	3,113	11,592	7.2
Vocational								
Public	4	1	...	5	812	199	1,011	60.2
Private	6	1	...	7	444	17	461	27.4
Foreign	2	1	...	3	101	106	207	12.3
Total	12	3	...	15	1,357	322	1,679	1.0
Teachers College (public)	2	2	...	4	153	131	284	0.2
Syrian University (public)	4	1	...	5	766	69	835	0.5
GRAND TOTAL	799	229	137	1,165	113,252	49,566	162,818	100.0
Summary:								
All public schools	566	128	...	694	70,043	23,674	93,717	57.5
All private schools	172	48	91	311	30,527	14,687	45,214	27.8
All foreign schools	61	53	46	160	12,682	11,205	23,887	14.7

* Figures supplied by Ministry of Education.

dents (15 percent), and foreign schools, 3,802 (32.8 percent). Public schools were either for boys or for girls, but a few private and foreign schools were coeducational. Government schools, with an average enrollment of 275, were larger on the whole than either private schools (with an enrollment per school of 102 students), or foreign schools (with an enrollment of 127 per school). One of the reasons for that situation is probably that the public schools charge much lower fees and have a substantial percentage of exempted students.

A further scrutiny of Table 60 shows an interesting fact about the relative number of boys and girls in public, private, and foreign schools. In the public schools the ratio of girls to boys is roughly 1 to 3, while in the private schools it is approximately 1 to 2, and in foreign schools the two sexes are almost equally represented. It is interesting to speculate

upon the reason for this phenomenon. One reason is the fact that there are a number of French Catholic orders of nuns which maintain schools patronized by Christians and non-Christians owing to the strict education and discipline exercised over the girls. Another reason lies in the fact that most of the pupils of foreign schools (77 percent) in 1942–43 were Christians and Jews, and it is a well-known fact that the education of girls is the more popular among these two groups—primary education among them is, in fact, almost universal, particularly in the cities where most of the foreign schools are located. This fact is further supported by the figures for foreign primary schools, which show that 19,878 pupils are almost equally divided between the two sexes—the difference is only six pupils—a phenomenon familiar where universal education prevails. Secondary education for girls, however, is much less popular, the girls forming only 30 percent of the total number of students in foreign secondary schools.

In addition to the regular graded schools, there were in Syria, according to Ministry of Education statistics, 1,229 ungraded schools, or *kuttabs*, enrolling 34,440 children. Of these 292 were for girls, enrolling 6,190 pupils. Presumably these figures are for the year 1943–44.[13]

In the vocational-education field the public schools lead with 1,011 students, or 60.2 percent, in 5 schools. Of the 7 private schools with a total enrollment of 461, or 27.4 percent, 5 schools are not, strictly speaking, vocational. They are religious and Muhammadan law schools, enrolling 424 students. This leaves 2 vocational schools with a total enrollment of 37 pupils. Three foreign schools give vocational training to 206 pupils, or 12.3 percent of the total.

There were 4 teachers colleges for educating teachers for the primary and elementary schools—2 for men and 2 for women—enrolling 284 students. This is a great advance over the previous year when there were only 78 students.[14]

Finally there is the Syrian University with its Schools of Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing, and Law, with 834 students, of whom 69 are women in the School of Nursing.

Teachers

As has already been mentioned, statistics for teachers are difficult to secure. Only figures for primary public-school teachers in the year 1944–45 were available to the American Council Commission. These numbered 2,140 and were distributed as follows:

[13] Al-Husri, *op. cit.*, p. 65.
[14] *Ibid.*, p. 54.

Teachers	Full time	Part time	Total
Men	1,411	95	1,506
Women	585	49	634
Total	1,996	144	2,140

Some figures were available, however, for the year 1943–44. There were in that year 2,239 teachers in all types of public schools except the University, distributed as follows:

Distribution of Teachers	Number of Teachers
Delegated to the central administration	50
Primary-school teachers	1,856
Secondary-school and teachers-college teachers	255
Vocational-school teachers	78
Total	2,239

Evidently the number of primary-school teachers gained considerably in one year, although it is difficult to determine accurately the amount of gain owing to the fact that some teachers, both primary and secondary, were delegated to the central administration, while others taught only part time.

Chapter 21

PUBLIC PRIMARY, SECONDARY, AND VOCATIONAL SCHOOLS

The Kindergarten

KINDERGARTEN education in Syria is still in its infancy. In 1944–45 there were 267 children—all girls—in the *classes enfantines* in connection with girls primary schools. These were in 4 schools, thus making an average of 47 children in each school.

In 1945–46 the Ministry of Education opened 2 new kindergartens, in Damascus and Aleppo. Both were visited briefly by the American Council Commission. They take children usually from four to six years of age, although the one at Aleppo was accepting children of two and one-half years of age. The children are kept busy with toys, singing and dancing, games, drawing, and similar activities. Care was being taken to teach the children habits of cleanliness. Some Montessori material, or an imitation of it, was being used. Some rudiments of reading without formal class teaching are included in the program. Each of the kindergartens had one teacher trained in France. The others were trained as primary teachers in the Teachers College for Women at Damascus.

Primary Education

Primary education is free in the public schools. It is also supposed to be compulsory, although this is more of a hope than a reality. The new education law, in setting down the principle of compulsion, provides that the principle may be applied in places decided upon by the Ministry of Education when adequate facilities exist. In his *Reports* Sati' al-Husri says that in drafting the new education law he was obliged to write the principle of compulsion into the law out of deference to the constitution which declares that primary education shall be compulsory. He knew, however, that the present number of schools is far from being adequate for requiring compulsory attendance in primary schools. Because the government budget will not be able to bear the expenses of compulsory primary schooling, he

therefore exhorts the government to embark upon a program of local taxation for the maintenance of primary schools.

But how far is Syria from compulsory attendance? Only a rough estimate can be made as there is no census showing the various age groups in Syria. If it is assumed that the ratio of children of school age (in Syria, age six to eleven) is the same as that in Egypt, then the total number of children of school age would be about 13 percent of the total population, which was estimated in 1942–43 at about 3,000,000 people including the tribes.[1] This would give a total of about 390,000 children between the ages of six and eleven. As there were in 1944–45 about 148,000 children in primary schools of all kinds, this would leave 242,000 children without regular graded schooling. Children in primary schools therefore represent roughly 38 percent of the total number of children of school age. Even if the 34,000 children in the ungraded *kuttabs* were to be taken into account, this would bring the total number of children attending schools to 182,000, or 45.6 percent of children of school age. There will still be 208,000 children left who are growing up in illiteracy, and for whom schools are needed.

Primary education is offered either in primary schools of five years or in elementary schools of four years. The former are largely in the cities and larger centers, while the latter are mostly in the rural districts. Five-year primary schools do, of course, exist in the rural areas as well, particularly in the larger villages. In practice, however, schools of from one to five classes exist, as is shown by the following tabulation (figures supplied by the Ministry of Education):

Type of School	Boys	Girls	Total
Schools of one grade	11	2	13
Schools of two grades	55	8	63
Schools of three grades	177	30	207
Schools of four grades	97	14	111
Schools of five grades	202	62	264
Total	542	116	658

Thus, only 264 public schools out of 658, or 40 percent, are complete with five grades. Another 111, or about 17 percent, could be considered *complete* elementary schools, bringing the total of complete primary and elementary schools to 375, or 57 percent. The remaining 43 percent have from one to three grades. The average number of grades in Syrian public primary schools is 3.8 grades.

[1] Conseil Supérieur des Intérêts Communs, *Recueil de Statistiques de la Syrie et du Liban, 1942–43* (Beirut: Imprimerie Catholique, 1945), pp. 9, 14, 15.

It is, therefore, to be expected that pupil registration in the various primary grades would show a drastic decline as one moves up the grades, and, indeed, such is the case. Statistics are not available for grade registration over a period of years which would enable us to calculate the amount of yearly elimination from grade to grade. The number of pupils in each of the five grades in 1944–45 are given in Table 61:

TABLE 61

ENROLLMENT BY GRADES IN PUBLIC PRIMARY SCHOOLS, SYRIA, 1944–45*

Grade	Enrollment			Number of Sections	Pupils per Section
	Boys	Girls	Total		
Classe enfantine....	...	267	267	4	47
First grade........	27,221	9,871	37,092	1,017	36
Second grade......	13,703	4,670	18,373	721	25
Third grade........	10,588	3,287	13,875	629	22
Fourth grade......	7,347	2,247	9,594	441	21
Fifth grade........	4,896	1,443	6,339	315	20
Total.........	63,755	21,785	85,540	3,127	27†

* Supplied by the Ministry of Education.
† Average.

Forty-three percent of the children are in the first grade, as compared with only 7 percent in the fifth. Children in the second grade number one-half of those in the first. From the second grade on, the number of children is cut in half every other grade. This phenomenon, which seems to be the rule wherever universal education is not enforced, has been observed with various degrees of intensity in all the countries studied in this report.

Table 61 brings out another characteristic—the declining size of classes from first to fifth grade. The average size of a class declines from 36 in the first grade to 20 in the fifth grade. This shows that not only do classes become fewer as we move up the grades, but they are attended by fewer pupils. The American Council Commission found classes that were as large as 91 in the lower grades and as small as 3 in the higher.

The primary program of studies

The primary course of study was in process of change at the time of the visit of the American Council Commission. A detailed new syllabus had been worked out only for history, geography, civics and ethics, and object lessons. Presumably these were considered the subjects most urgently in need of revision, while the other subjects were to follow the lines prescribed by the old course of study.[2]

[2] Detailed description of the content of subject courses will not be given here, except as attention will be called to the differences between the old and the new program in the

Table 62 gives the new distribution of periods assigned to the various subjects, which had been in effect since November 1945, the date of the delayed opening of the schools. All periods are of forty-five minutes each. The school day consists of four periods in the morning and two in the afternoon, with a half-holiday on Thursday and a full holiday on Friday.

It will be noted from Table 62 that under the old course of study *history* did not begin until the third grade. The new program provides for incidental teaching of history in the first two grades. In the third grade, the

TABLE 62

PRIMARY COURSE OF STUDY FOR SYRIAN PUBLIC SCHOOLS, 1945–46

Subject	Periods per Week				
	1st Grade	2nd Grade	3rd Grade	4th Grade	5th Grade
Religion and Koran	4	4	4	3	3
Arabic	13	13	9	8	8
Arithmetic and geometry	5	5	5	5	5
Object lessons	4	4	4	4	4
History	...	...	2	2	2
Geography	...	...	2	2	2
Civics and ethics	...	...	...	2	2
Handwriting	...	2	2	2	2
Drawing and handwork	3	2	2	2	2
Physical education and singing	3	2	2	2	2
Free activities	2	2	2	2	2
Total	34	34	34	34	34

children are introduced to modern Arab heroes and other great men through short biographies and work back to the Prophet Muhammad and the famous men and women of early Arab history. A few non-Arab kings and statesmen of ancient and modern times are included. With the biographies, a description of life in Babylon, Syria, Arabia, and Egypt is woven in. Systematic teaching of history begins in the fourth grade with generalizations about primitive society, the beginning of civilization, the domestication of animals, early human inventions, the rise of the family, the tribe, and the state. History of the Arabs through the Umayyad period is taken up in the fourth grade and is completed to modern times in the fifth. In the fifth grade reference is made to the rise of modern nations and imperialism and the development of democracy, and this is connected with modern Arab history.

The teaching of *geography* has also been advanced a grade. Under the new course of study incidental teaching of geography begins in the second

revised syllabuses for the four subjects mentioned. In general, the content of courses in the lower grades is similar in all the Arab countries except that the history and geography of each country is given special attention in the schools of that country.

grade, dealing with the school, the quarter, the village or town, and the surrounding plains, mountains, and rivers. Systematic geography begins in the third grade, with some study of the sun, moon, and earth. Maps of the class, the school, and the locality are made, showing the roads connecting the community with the outside. Actual trips are sometimes made to the surrounding country and imaginary trips to the rest of the Arab world in Asia and Africa. In the fourth grade, fundamental concepts of physical geography are given, with a brief study of outstanding countries on each continent. The fifth grade is devoted to a more detailed study of the geography of Syria, Lebanon, Palestine, and Transjordan, and a less detailed study of the rest of the Arab world.

Civics and ethics begin in the fourth grade and include man's duties to himself, his family, to others, to his country and countrymen, and to animals. In the fifth grade a study is made of the machinery of government, and the administrative divisions of Syria, Syrians abroad and foreigners in Syria, and the main types of government.

The new courses on Observation of the Environment and Object Lessons are a compound of two parts—the observation of nature (*science and hygiene*) and the observation of the environment (social and civic). It begins in the first grade with simple topics on personal cleanliness, the home and the school, and continues through the fifth grade, each year adding more complex subjects. Fifth grade subjects include physics, physiology, zoology, and botany and agriculture.

In general, the content of courses in *arithmetic*, *home economics*, *manual arts*, *drawing*, *music*, and *physical education* is similar to the primary course of study for Egypt, previously described.

An adaptation of the course of study for a three-year rural school cut down the periods for religion, civics, drawing, manual arts, and object lessons, adds more time for Arabic and arithmetic and prescribes six hours of practical agriculture a week. The American Council Commission visited a rural school of this kind near Homs, which had a garden of about one and a half acres. No special training in agriculture was given, and the teacher relied on his readings in a textbook and on the experience of the school janitor who was a farmer.

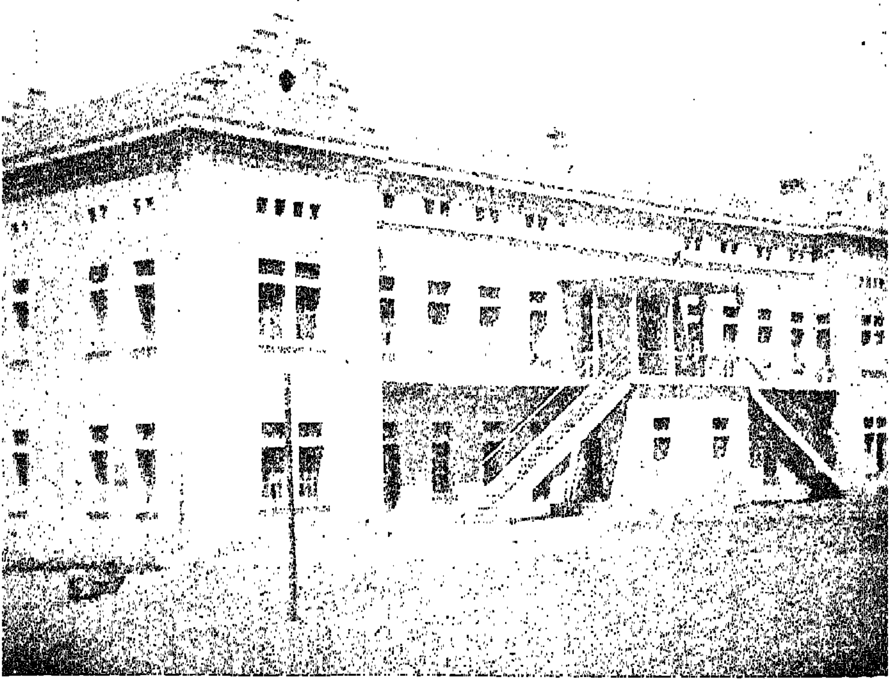
Teaching, textbooks, and school activities

It is difficult to give an adequate idea about classroom teaching in a whole country which has hundreds of schools. Some very good teaching was witnessed in a number of schools, such as in the practice school of the Teachers College for Men in Damascus, among others, while teaching in



Class in Arabic at Damascus College, Damascus, Syria





Above: Teacher (at right) and part of the top class of the primary school for girls, Suwayda, Syria
Below: A former French army barracks now used for a government school for boys, Suwayda

other schools, particularly in the villages, left much to be desired. The American Council Commission is under the impression that most of the better teachers are concentrated in the larger centers, while the tendency is to push the indifferent teachers to the outer regions.

Teaching is conducted mainly through inductive and deductive development lessons and through questions and answers. Through the use of readers and textbooks and discussion in class, subject matter is methodically imparted to the children. The teacher is the prime mover, and few, if any, classroom activities are initiated by the children. Children often write summaries down in their notebooks, and care is taken in true French style that the notebooks are kept clean and orderly. Occasionally, as in object lessons, material is brought in for observation, and charts and maps are used. Homework is assigned beginning in the first grade.

Readers and textbooks for the various subjects have been written in Arabic by Syrian authors, most of whom are in the public-school system. These follow mainly French models. Only textbooks approved by the Ministry of Education may be used in the public schools, and these are published by their authors. High prices prevailed during World War II and the period immediately following. Pupils buy their own books, although poor pupils are often helped by a cooperative society in the school.

The prevailing practice is to have the teacher responsible for his or her own class. In many schools, however, work in the fourth and fifth grades (and some in the third) is distributed among teachers by subjects. In village schools a teacher may have to take more than one class, or even a whole school. In this case, however, the school rarely exceeds three grades. The art of simultaneous teaching of more than one class is far from being perfected, and in most schools the Commission found the teachers teaching one group while the other students sat idle. Occasionally a teacher would give one item to one group, move to the next group for a few minutes, and then move back to the first group, the other group being idle in the meantime. Thus, the teacher would go back and forth many times in a period of forty-five minutes. Clearly, training in the use of simultaneous teaching would greatly improve the efficiency of the village schools.

A check-up conducted in a number of schools revealed that a majority of the children in the first grade, notably in the smaller centers, spent more than one year in that grade. The class is often unofficially divided into two or more sections, usually studying in the same room, and an advanced section may be reading in the first-grade reader in a place thirty to fifty pages ahead of a lower group. It seemed to be taken for granted that most of the pupils

of the lower group would not be promoted to the second grade at the end of the year, while a check-up of the advanced group showed that most of the children had been in the lower group the previous year.

Another quick check-up in the fifth grade of a few schools showed that children take from five to seven years to finish the primary school. Among 88 fifth-grade boys in one school the age range was eleven to seventeen. One school principal estimated that 25 percent of the children spend more than five years in the primary school. Others put it at a higher figure.

The school year now begins on October 1 and ends in mid-June, although the schools did not open in 1945 until late in November, owing to the emergency created by the closing of the French schools. The daily timetable is as follows:

8:00–11:45 A.M. Morning session of four periods of forty-five minutes each, with recesses of fifteen minutes between
11:45 A.M.–1:45 P.M. Lunch
1:45–3:30 P.M. Afternoon session of two periods and one recess

In the fasting month of Ramadan certain lessons are cut down and only a morning session is held.

Attendance in village schools increases gradually from October to January, usually remains high in January, February, and March, and begins to decline in April, and in some schools may be extremely low in the last two months of the school year when children may be working in the fields with their parents.

As regards extracurricular activities, many schools, especially in the cities, have cooperative welfare societies to which children make voluntary contributions to help the poorer pupils. Some schools have Scout troops. Many schools make excursions to the cities or to the surrounding country, while celebrations, parties, and dramatic performances are held in many of the larger schools.

TEACHERS

There were 1,996 full-time teachers in 658 public primary schools in 1944–45, compared with 1,856 in 639 schools in the previous year. This makes an average of three teachers per school for the whole country in 1944–45, compared with 2.9 teachers per school in the previous year. The following is the distribution of schools according to the number of teachers in them.[3]

[3] Figures supplied by the Ministry of Education.

Type of School	Number of Schools
Schools with one teacher	345
Schools with two teachers	90
Schools with three teachers	40
Schools with four teachers	17
Schools with five teachers	42
Schools with six teachers	38
Schools with seven teachers	24
Schools with eight teachers	16
Schools with nine teachers	10
Schools with ten teachers	6
Schools with more than ten teachers	30
Total	658

More than half of the schools (52.4 percent) are one-teacher schools, while the number of schools with a full complement of teachers (five or more) is 166, or 25.2 percent.

Light may also be shed upon primary education by an examination of the qualifications of primary-school teachers. The following data are for 1943–44:[4]

Qualification	Number of Teachers
Graduates of teachers colleges or holders of teaching diploma	820
Law College graduates	10
Agricultural School (Salamiyah)	13
Higher School of Literature	18
Baccalauréat, Second Part	93
Baccalauréat, First Part	225
Brevet (General, Technical, or Commercial)	159
Total	1,338

As the number of teachers was 1,856 in 1943, this leaves 518 teachers unaccounted for, presumably because their qualifications were even lower than the *brevet* (roughly equivalent to a junior-high-school certificate).

Buildings and Equipment

A large number of primary schools, particularly in the cities, are in rented buildings. Most of these are houses built to accommodate families, although some of the old-style houses are spacious and have large courtyards. Ordinarily the rooms planned as lodging quarters are too small for

[4] Sati' al-Husri, *Reports on the State of Education in Syria and Recommendations for Its Reform* (Damascus: 1944), p. 132.

a class of thirty or forty, and classes either become crowded or have to be adjusted to the rooms. Rented buildings range from the large houses that may be found in Damascus, Homs, Hama, and Aleppo, to the small village houses which are little more than huts. Primary-school buildings may be owned by the government, but the number of these is comparatively small. Many schools in cities and in villages are owned by municipalities or are rented by the municipalities as their contribution to the maintenance of the schools. Sanitary conditions, lighting, and ventilation may be fair in government-owned buildings and in some of the rented ones, but they are often inadequate.

The usual classroom desk is built with seats attached to accommodate two children, and is frequently a local product. The seats may or may not have backs, and in the latter case the children rest their backs either against the wall or against the desk immediately behind them. In a crowded school a desk for two may be occupied by three or even four pupils. The desks are in various degrees of preservation, some being new, while others appear to have been in use a long time.

Some of the larger primary schools in the cities are well stocked with instructional materials and equipment such as maps in French or Arabic, natural-history charts imported from Egypt, story pictures. In some schools there is a variety of instructional materials made by the teachers. The village schools are not so well supplied.

Libraries, when they exist, are very small and little used by the children. Very little money is given by the Ministry of Education for the purchase of library books. Occasionally books are sent to the schools by the Ministry.

The schools are run on the most economical lines. Very little money is allowed for the everyday running of the schools. The principal or head teacher has to spend out of his own pocket or borrow from the welfare society's fund. Only after receipts for the expenditure are presented and approved by higher authority is the money refunded by the Treasury.

Secondary Education

As has already been stated, secondary education was shortened from seven to six years under the new plan of organization. In the earlier course the first four years led to the examination for the *brevet* certificate, and were followed by two years in the scientific or literary section, which ended in the first *baccalauréat* examination. The new plan calls simply for an intermediate stage of four years leading to the intermediate examination, and a preparatory stage of two years divided into a scientific and a literary

section and leading to the Secondary-School Certificate examination.

New regulations for secondary schools were issued between February and December 1945.[5] The regulations declare that the aim of education is (*a*) to develop a cultured élite by inculcating on adolescents and youth the fundamental information and general culture which they need in their life; and (*b*) to prepare these adolescents and youth for vocational studies, on the one hand, and higher studies, on the other. Admission of students to the first year of the intermediate stage requires the possession of the government primary-school certificate. A student must be of good character and must be no less than ten and no more than fifteen years old. Admission to the preparatory stage requires the possession of the government intermediate-school certificate. The student must be of good character and no less than fourteen and no more than twenty years old. The school year begins on October 1 and ends on June 15. Schools are in session five and a half days a week, Thursday afternoons and Fridays being holidays. In addition, schools are closed on official holidays and for two weeks after midyear examinations.

A new plan for school examinations provides for three kinds—daily oral or written quizzes, midyear, and final examinations. The midyear examination papers are to be corrected by the class teacher, but final examination papers are to be read by a committee of which the class teacher is a member. All midyear and final examinations are written except those in languages, which are oral as well. Marks are on the scale of 100. The results of the quizzes for the first and second terms are averaged separately, added to the results of the midyear examination, and divided by three. The resulting mark is added to that of the final examination and divided by two. In order to pass, a student must have a general average of 50 or more, and a grade of 50 in each subject. If he has a general average of 50 and less than 50 in one or two subjects, he may be re-examined in those subjects. Otherwise he fails. As these passing marks are much higher than those previously prevailing, a transitional scheme of passing marks higher than those previously set but lower than the new marks was to be used until the end of 1945–46.

[5] These are contained in *Regulations for Intermediate and Secondary Schools and Teachers Colleges* (Damascus: Government Press, 1945), 51 pp., and comprise Decree No. 1415, dated December 17, 1945, "Embodying the Secondary School Regulations"; Decree No. 183, dated February 20, 1945, "Embodying the Futuwah Regulations for the Preparation of Secondary School Students for Military Life"; Law No. 201, dated September 19, 1945, "Embodying the Organization of Secondary Schools"; Decree No. 1304, dated November 13, 1945, "Embodying Fixing the Maximum Teaching Load for Intermediate, Secondary, and Vocational Schools, and the Fees Thereof." (In Arabic.)

These are the highlights of the new secondary-school regulations. In addition, the regulations give detailed provisions for admission of pupils and their transfer from one school to another, duties of students, absences, courses of study, and methods of teaching. The teachers are exhorted to use "active" methods in teaching and not to have students be mere listeners, and to encourage them to engage in free activities, such as reading, art, sculpture, music, and dramatics, in order to promote initiative and creativeness. In girls schools, studies are directed toward home needs and the "duties of motherhood." The regulations also set down provisions for the discipline of pupils, for the guidance of the administrative and teaching staffs as well as school committees and councils, and for relations with the parents. A staff council must meet at least three times a year, and subject committees must meet once a month. A disciplinary committee and a purchasing committee are also provided for.

A special decree prescribes compulsory military training for boys in the fifth and sixth years, and empowers the Ministry of Education to arrange for military training groups in nonpublic schools requesting it, and in the University.

Another decree abolishes the posts of special monitors (*surveillants*) for keeping order and discipline in the schools, which hitherto had been the practice borrowed from France, and puts the responsibility for discipline and order on the principals, their assistants, and the teachers.

Another decree fixes the maximum teaching load for teachers in secondary and vocational schools. Teachers of the special subjects, such as art, music, manual arts, physical education, domestic science, penmanship, and typing, teach up to twenty-four periods a week. Teachers of the other subjects in intermediate and vocational schools have a maximum load of twenty periods a week, while those teaching in preparatory classes and teachers colleges have a load of eighteen periods. Principals and their assistants are also required to teach a minimum ranging from three periods a week for a principal of a boarding school to ten periods for an assistant principal in a day intermediate or vocational school.

THE SECONDARY COURSE OF STUDY

The time allotment for the various subjects of the secondary course of study is given in Table 63. A total of thirty-four periods a week is maintained throughout the six years. Each period is forty-five minutes. The program for the first four years is the same for all students except that girls receive instruction in domestic science whereas boys are allowed periods for free activities. A choice between French and English is allowed in foreign languages.

TABLE 63

THE NEW PROGRAM OF STUDIES FOR SECONDARY SCHOOLS, SYRIA, 1945–46

SUBJECT	PERIODS PER WEEK									
	Intermediate				Preparatory: Boys				Preparatory: Girls	
					Literary Section		Scientific Section			
	1st Year	2nd Year	3rd Year	4th Year	5th Year	6th Year	5th Year	6th Year	5th Year	6th Year
Religion and Koran	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Arabic language and literature	7	6	6	6	6	6	4	4	5	4
First foreign language*	8	7	7	6	5	4	5	4	5	4
History	3	3	3	3	4	4	...	3	4	4
Geography	...	2	2	2	2	3	2	...	2	...
Ethics and legal and civic information	...	...	...	3	...	...	...	...	...	...
Mathematics	4	4	4	5	3	3	6	6	3	3
Science	4	4	6	6	3	4	6	7	3	4
Second foreign language*	...	...	...	...	5	4	5	4	5	4
Principles of science and logic	...	...	...	...	2	...	2	...	2	...
Psychology	...	...	...	...	...	3	...	3	...	3
Child care and nursing	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3
Drawing	2	2	2	...	...	...	...	...	...	...
Physical education	2	2	1	1	...	...	...	...	1	1
Music	1	1	...	...	...	...	...	...	1	1
Free activities for boys / Domestic science for girls	2	2	2	1	...	...	...	...	2	2
Futuwah (drill) and military information	...	...	...	...	3	2	3	2	...	...
Total	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

* Choice is made between English and French. The language chosen in the intermediate stage becomes the first foreign language for the preparatory stage.

In the preparatory stage boys and girls have different courses. Boys may choose either a literary or scientific course, in which the subjects taught are the same but with a difference in the amount of time devoted to them. Both sections take the same courses in foreign languages, logic, and psychology. The literary section emphasizes and gives more time to Arabic, history, and geography, while the science section takes more mathematics and science. Military training and lectures on military subjects are given to the boys. All girls take the same course, which includes two hours of domestic science each week in each year, with a correspondingly smaller amount of time devoted to geography and science than is given the boys. A second foreign language is introduced for all students in the fifth year.

A brief summary of the courses of study in the secondary school is given below, and the most important differences between the old and the new courses are indicated.

In *Arabic*, reading and literature are made the center around which the other subjects revolve. A smaller number of poets and writers are studied than in the old course, but more of the works of each are studied. Composition is stressed throughout the six years, while grammar is meant to be simpler and more practical than under the old course. Prosody, rhetoric, and elocution are given in the fifth and sixth years of the literary section; in the scientific section, emphasis is laid upon scientific reading material in these years.

In *geography*, Asia and Oceania are taught in the second year, and Europe and America in the third year. In the fourth year, Africa and the Arab countries in Africa and Asia are studied in detail. In the fifth year, general physical, human, and economic geography is taken up by both the literary and scientific sections, while in the sixth year, the literary section studies the Arab world again as well as the geography of the great powers.

History begins with prehistory and ancient history in the first year; the second and third years are entirely devoted to the history of the Arabs; the fourth year is devoted mainly to European history to the present time, although some time is given to Arab civilization at its height, the downfall of the 'Abbasid Empire, and to the Arab countries between the two World Wars. In the preparatory years, the fifth-year literary section studies the history of civilization with emphasis upon Arab and modern civilizations, and in the sixth year both sections take modern history and the history of the movement for independence in the Arab world.

In the field of *science*, the first year is devoted entirely to a general

course aimed at building a common foundation for the later study of physics, chemistry, zoology, botany, and physical geography. In the second year, mechanics and sound are studied in physics in two periods, while elements of zoology and botany are taken up in the other two. Heat and light are taken in third-year physics, and nonmetals are studied in chemistry. Finally, in the fourth year, electricity and magnetism are taken in physics, metals and organic compounds in chemistry, and anatomy and physiology. In the scientific section of the preparatory stage, the physics and chemistry studies of the intermediate stage are expanded and completed in the fifth year, while, in the sixth, advanced studies in the vibratory and periodic motions and in the theories behind modern inventions complete the physics course. In the literary section, also, the fifth-year class studies an expanded course in physics and chemistry. The study of science in the secondary schools is largely theoretical—the laboratory equipment is generally deficient. The students rarely do experiments by themselves, even in the advanced classes; whatever laboratory work exists is usually in the form of demonstrations by the teacher.

In *mathematics* the first year is given entirely to arithmetic, while the second, third, and fourth years are taken up with algebra and plane geometry. In the fourth year, elements of logarithms, trigonometric functions and graphs and their applications to surveying and statistics are included. In the preparatory stage, the literary section has a course in general mathematics which includes elements of trigonometry, further applications to statistics and surveying, and astronomy. The scientific section completes the study of algebra and geometry by taking advanced topics in each, including solid geometry. It also takes mechanics, trigonometry, the elements of analytical geometry, and astronomy.

The courses in the principles of *science* and *logic* and in *psychology* in the old course of study for the philosophy section (seventh year) are transferred to the fifth and sixth years. In the old course the philosophy section took eleven periods a week of philosophy (logic, psychology, ethics, and metaphysics); the mathematics section took four hours a week of philosophy, which included only logic and ethics. The new course of study provides for only logic and psychology, together with principles of scientific method to be taken by both the literary and the scientific section.

The details of the courses for *English* and *French* had not been made public at the time the American Council Commission was in Syria.

The new course of study for secondary schools has been criticized in certain quarters because it has attempted to condense a seven-year program into six years, with a consequent crowding of the curriculum which will

make it difficult for the teachers to finish the course and for the students to digest the subjects. To this criticism it is answered that some subjects—philosophy, for example—have been abolished and others reduced. The second foreign language has been abolished for the last three years of the intermediate school and now only begins in the fifth year. It is claimed that formerly a disproportionate amount of time was taken by the examinations at the beginning and the end of the year. Much less time is now taken by the examinations so that somewhere between a half and a full academic year is saved and is available for teaching purposes.

Admission and educational opportunity

Admission to the secondary school was formerly open to holders of the primary-school certificate provided they had passed their examination with a grade of *bien* (good) or *assez bien* (fairly good). In this way admission to the secondary school was limited. Under the reorganization these limitations have been abolished, and the way is open to all who wish to enter, provided they can pay the fees. The fees are not exorbitant, being £S48 ($21.60) in the intermediate, and £S60 ($27.27) in the preparatory schools. Even here, however, there is a wide range of exemptions. Children of teachers or of government employees receiving less than £S50 a month are exempt. Students are also exempt if their marks are high enough in the public examinations. A reduction of 30 percent of the fees is made to children of officials having a monthly salary of £S50–£S100. By order of the Ministry of Education no fees were charged in the two secondary schools of the Jabal Druze. In practice, about one-third of the student body receives exemptions. In addition, brothers pay less. One additional brother pays two-thirds of the fees, two additional brothers pay one-half each, and three additional brothers pay one-fourth each.

Students coming from localities where there is no secondary school, or the local school is incomplete, go usually to Damascus or Aleppo where boarding departments are maintained in both the boys and the girls secondary schools. Here, again, help is given to the deserving poor student through provision for free board or free lunches. In Aleppo, out of 247 boarding students in the public secondary school for boys, 92 received free board; and out of 140 students who ate only lunch at school, 58 received it free. The proportions were even higher in the Aleppo public secondary school for girls, where 24 boarders received their board free as compared with 29 girls who paid. Twenty-two had free lunch as compared with 10 who paid.

It is clear that an effort is being made to help the underprivileged child

to pursue his education further, and to equalize educational opportunity. How far these efforts are effective in the rural communities is another matter. Inquiry at some of the village schools showed that very few pupils from them had gone on to secondary schools.

TEACHERS, CLASSES, AND SCHOOL ACTIVITIES

There were 255 secondary-school teachers in the Syrian public schools in 1943–44. The following is a tabulation of their qualifications.[6]

Qualifications	Number of Teachers
Doctorates (of which 7 were in medicine)	17
Licence ès Lettres or *ès Sciences* from France	35
Licence in Letters from Fuad I University, Cairo	5
Master of Arts from the American University of Beirut, or from America	14
Licence in Law	17
Higher School of Letters	11
Teachers College at Istanbul	2
Total	101

The remainder (154 persons) have varied qualifications. It will be noticed that while many teachers of the secondary cadre hold higher degrees, few of them are professionally trained. Many teachers have formerly been in primary schools and were promoted to teach in secondary classes.

The same phenomenon of the decrease in the number of students as they rise in their grades which was noticed in the primary school is noticeable in secondary and vocational schools, as is shown by the figures for 1944–45 (Table 64) which were supplied by the Ministry of Education:

TABLE 64

DISTRIBUTION OF PUPILS IN CLASSES IN SECONDARY AND VOCATIONAL SCHOOLS, SYRIA, 1944–45

Class	Boys	Girls	Total
Preparatory class (vocational)	340	93	433
First year	1,863	604	2,467
Second year	1,103	393	1,496
Third year	742	291	1,033
Fourth year	446	193	639
Fifth year	356	52	408
Sixth year	234	47	281
Philosophy and mathematics	285	16	301
Total	5,369	1,689	7,058

[6] Al-Husri, *op. cit.*, pp. 131-34.

While there were 2,467 students in the first year, there were only 301 in the seventh year. Most classes have between 30 and 40 pupils, but classes with as low as 11 students and as high as 70 students were seen by the American Council Commission. Crowded classes, however, are rare in the secondary schools.

Attendance is quite regular, but it tends to drop sharply toward the end of the year, the students preferring to prepare for their final examinations at home.

School activities are on the whole encouraged, although schools differ in this respect. In addition to the regular athletic classes and the compulsory *Futuwah* (military training), schools engage in a number of organized games, mainly football, basketball, volleyball, and in some cases tennis. A number of schools have Scout troops. School groups also conduct picnics and excursions. Student clubs are more numerous in larger schools than in the smaller ones. The most common is the cooperative welfare society, which gathers contributions from students, teachers, and occasionally from the general public, for the help of poorer students. There are also clubs for Arabic, music, dramatics, and other such activities. Some schools and their clubs issue student magazines. The teachers usually play a leading role in these activities, serving as sponsors and in some schools as chairmen.

Perhaps a word regarding the opportunities open to the secondary-school graduate will be in order. In Syria proper a graduate may go to the Syrian University or to the two-year course in teacher training. The latter is the course most of the girls follow. However, a number of opportunities exist outside Syria where the second *baccalauréat* was considered to be of a high standard. Previously it was accepted in France and students holding it were permitted to enter French higher institutions. Whether the new certificate, with one less year of schooling, will be considered of the same level remains to be seen, although it is hardly likely under the circumstances. Both the American University and the Université St. Joseph in Beirut accepted it; the former required an examination in English but admitted students to the sophomore and even to the junior year. The latter accepted it for the purposes of entrance to its Faculties of Medicine, Law, and Engineering. The Egyptian Ministry of Education also recognized it for entrance to the Universities of Fuad I and Faruq I and other higher institutions.

Buildings and equipment

Secondary schools are more fortunate than primary schools with regard to their buildings. The boys schools are usually more favored as to build-

ings than are the girls schools. Of 14 secondary schools visited by the American Council Commission, 7 were government-owned, including 2 confiscated French barracks at Suwayda in Jabal Druze; 2 belonged to local municipalities; and 5 were rented. Undoubtedly, the best secondary-school buildings seen by the Commission in Syria were those of the Damascus and Aleppo boys schools. A fine new building for the boys secondary school at Homs was in the process of construction.

In libraries, also, the secondary schools are more favored. There is a wide range, however, in the number of books—from about 25 or 30 books in the library of the intermediate school for boys at Suwayda to about 7,000 volumes in the library of the secondary school for boys in Damascus. The books are almost entirely in French and Arabic. Large collections of French literary works and French textbooks exist at both Damascus and Aleppo boys schools. A number of Arabic magazines are subscribed to, and formerly a number of French magazines as well. The British Council recently gave small collections of English books to the libraries of some of the schools. The Damascus school for boys has a full-time librarian. Usually there is little space for reading in the libraries, and students borrow books at specified times, sometimes paying deposits for the books borrowed. More freedom in the system of borrowing, more space for reading in the libraries, and more encouragement by teachers and all concerned seem to be necessary for making the school library play a more important part in the educational programs of the schools.

The situation with regard to desks and furniture is much the same as that in primary school except that the quality of the desks is better, and few, if any, desks accommodate more than two pupils.

Vocational Schools

There were 6 public vocational schools in Syria at the time of the visit of the American Council Commission: the Technical (trade) School for boys, the Technical School for girls, and the Commercial School for boys, all in Damascus; the Technical School for boys, and the Commercial School for boys, both in Aleppo, and the Agricultural School at Salamiyah, east of Hama. The last named is under the jurisdiction of the Ministry of National Economy. Four of the six schools were visited by the Commission —the Technical School for boys and the Commercial School for boys at Damascus were not visited.

All of the vocational schools (except the school of agriculture) give a course of four years above the primary-school certificate. Formerly they

formed part of the plan for complementary education, which was of two kinds: general complementary, restricted to general cultural courses, and vocational complementary, combining cultural and trade education. A certificate known as the general *brevet* was given at the end of the general course after the student had passed a public examination, and "vocational *brevets*,"—Technical, Commercial, or Agricultural—were given at the end of the vocational courses after public examinations.

The attempt to make the vocational schools a part of the complementary education had resulted in a heavy overloading of the course of study, and the students were working and studying for forty-six periods a week in the technical schools besides which there were additional study periods that were compulsory for boarding students. After the abolition of the complementary system in the new educational organization the vocational schools were considered as independent schools, and an attempt was made to lighten their programs.

The number of students in the public vocational schools in 1943–44 was 1,024, and in the following year, 1,011. A summary description of the schools visited by the Commission will perhaps give the best picture of public vocational education in Syria.

The technical school for boys

The Technical School for boys at Aleppo dated back to 1900 when it was founded in connection with an orphanage, with the idea of providing trade education for orphans. Its connection with the orphanage was severed in 1924–25.[7] It had 148 students in 1945–46, of whom 73 were boarders. Eleven of these paid annually a sum of £S240 (about $108.00) for their board, and the other 62 had free board at the expense of the state. The boarding students come from the outer districts of the governorate of Aleppo as well as from the governorates of Homs, Hama, Latakia, and Dayr al-Zur. Thus, about one-half of the student body is from outside Aleppo, and an attempt is being made to give opportunity for vocational education to students from the smaller towns. No tuition fee is charged.

The new program of study, issued in November 1945, covers four years and combines general cultural with vocational work. It includes religion, civics, Arabic, a foreign language, mathematics, physics, history, geography, physical education, industrial drawing, technology, and shopwork. In the first year, which is a preparatory year, the shopwork is common for all

[7] This conception of technical education as primarily suited to orphans is of long standing and has persisted until lately in the Damascus technical schools for boys and for girls. In recent years steps have been taken to separate the orphanages from the technical schools in that city.

students. Specialization begins in the second year. Eight lines of specialization are provided: turning, fitting, foundry, auto and motor mechanics, blacksmithing, carpentry, wood-carving, and weaving. All students in the first six sections take welding as well. The auto-mechanics section is the most popular with the students, and most of them would take it up if allowed. Wood-carving is the least popular. In order to keep a balance between the various sections, therefore, the School has to apply some pressure on some of the students. Shopwork ranged from fourteen periods a week in the first year to twenty-two periods a week in the fourth year.

The School occupies a government building originally built as an elementary school by the Turks. It has fairly well-equipped fitting, turning, and carpentry shops. Most of the equipment was acquired twenty years ago, and few, if any, additions or replacements have been made. The new budget provided £S40,000 (about $18,200) for new equipment and raw materials. In addition, £S25,000 (about $11,400) was provided as working capital. Out of the profits from products sold or services rendered, it is planned to add a certain proportion to capital and to credit the remainder to the students. This would accumulate during their stay in school, and would be given to them at the time of their graduation to serve as their working capital. A law legalizing this procedure (Law No. 254) was passed on June 4, 1946.[8] In this way it is hoped to put the school and its other sister schools on a profit-making basis as far as that is compatible with instructional purposes.

Of the 12 students who were graduated from the Aleppo school in the previous year, 1 was working in the railways, 1 in the fire department, 1 in the Department of Supplies, 3 were primary-school teachers, 2 were working independently, and 4 were unemployed.

The Technical School for Girls

The Technical School for girls in Damascus was also originally started as an orphanage primary school. The Technical School proper began in 1938–39, and the first four of the primary grades were removed elsewhere. It was hoped to remove the fifth grade in 1946–47. Most of the students of the School still come from the orphanage, after having received their primary-school certificate. In 1945–46 the School had 118 students of whom 20 were free boarding students, and 2 were paying boarders. No

[8] Sati' al-Husri, *Reports on the Conditions of Education in Syria during the Year 1945* (Damascus: Government Press, 1946), p. 133. This is a sequel to his earlier reports already referred to, which were published in 1944. They attempt to show the progress made in the reorganization of Syrian education.

tuition fee is charged. The boarding fee is the same as in all other boarding public schools.

The course of four years provides instruction in religion, Arabic, a foreign language, mathematics, general science, physics, chemistry, biology (including hygiene), "industrial science," history, geography, civics, music, physical education, and drawing. In addition, courses in home economics, nursing, and child care are given. As many as thirteen subjects may be given in one year in a program that totals forty periods a week. Practical work ranges from ten periods in the first year to eighteen periods in the fourth. Specialization is afforded in any one of five departments—dress-making, embroidery, lacework, decorative art, and rug-making. In the first year the students make the round of all the five trades. Specialization begins in the second year. Dressmaking is the most popular trade chosen, followed by embroidery. Decorative art is the least popular.

Most of the students provide their own materials and are allowed to keep the product. If the material is provided by the School, the work is kept by the School.

No information was available on the activities of graduates.

The commercial school for boys

The Commercial School for boys in Aleppo (like its sister-school in Damascus, which was not visited by the Commission) was founded in 1933. Fittingly enough it occupies part of an old *khan* (inn) built in 1740 for foreign merchants trading in Aleppo. It had an enrollment in 1945–46 of 65 students. In contrast with the Technical School, it has only 4 students from outside Aleppo and is entirely a day school for which no tuition is charged. Only 2 new students had applied for admission at the beginning of the year; accordingly, there was no first class. A first-year secondary was opened in connection with the School, and students who are not exempt pay tuition as in the rest of the secondary schools. The reasons given for the lack of new applicants for the Commercial School were two: (1) the opening of the secondary schools virtually to all graduates of the primary school and a wide range of exemption from fees make students prefer to go to the secondary schools; (2) the benefits for the graduates have been limited and not encouraging. As the students are graduated young, firms are not usually inclined to employ them at such an early age.

The program of studies is of four years' duration, and is comprised of religion, Arabic, foreign language and translation, history, geography, mathematics, science, civics (including ethical, legal, and economic information), drawing, penmanship, and physical education. The commercial

studies, which start in the second year, range from eight subjects in the second year, to thirteen in the fourth year, and include commercial law, merchandising, typing, bookkeeping, and practical work in business firms. The total number of periods is thirty-four per week.

The school has a small library of commercial books and some Arabic and French typewriters.

Of the 5 students who were graduated in the previous year 3 were in the Department of Supply, 1 was studying in secondary school, and 1 was teaching in a primary school.

THE SALAMIYAH AGRICULTURAL SCHOOL

The Salamiyah Agricultural School is situated on a farm near the village of Salamiyah to the east of the city of Hama. The School was founded by the Turks in 1910, but had been closed in 1932 and was reopened in 1943 by the Ministry of National Economy, which now administers it.

Minimum preparation for admission is completion of the primary school, but between 30 and 40 percent of those admitted have held the *brevet*. Fifty-four students were registered at the school in 1945–46—23 in the first and 31 in the second year. All students are boarders. Of these, 33 are free boarders, paying nothing for tuition or board. The other 21 each pay £S300 a year (about $136.40).

The course of study extends over two years. It is comprised of civics, history, geometry, topography, hygiene, agricultural geography, agricultural and business arithmetic, mechanics, agricultural bookkeeping, physics and chemistry applied to agriculture, botany, zoology, and agriculture. The last mentioned includes general agriculture, agriculture of special crops, vegetable gardening, domestic animals, farm machinery, farm buildings, agricultural law, political and agricultural economy, geology, poultry, forestry, aviculture, silkworm raising, plant diseases, entomology, and veterinary science. To each of these, a certain number of lectures is allotted, ranging from ten to forty-five.

The School owns two plots of farm lands of 1,000 and 2,500 *dunams* (a *dunam* is a Turkish unit of land measurement). It has a number of buildings and barns, most of which were erected in the period of Turkish rule. It seemed to be fairly well equipped with farm machinery, including a harvesting and threshing combine and a cotton gin. It provides its own electric power. The farms have extensive fields for raising grain, vegetables, and fruits. There is also an extensive nursery and a variety of shade trees. Irrigation is provided from underground canals bringing water from a distance, a system which has come down from ancient times and which

abounds in the district. They are similar to the *kahrizes* of northern Iraq.

Practical agricultural training takes place every day, the first- and second-year students alternating in the mornings and afternoons. Students, working in groups of four or five, are assigned a specific type of work, such as nursery or vegetable gardening, each day. Thus, they go the round of each type of activity during the week and come back to the same activities the next week. No individual plots are assigned to the students.

Chapter 22

HIGHER EDUCATION AND THE EDUCATION OF TEACHERS

Syrian University

UNTIL OCTOBER 1946 the Syrian University consisted of the Faculties of Medicine and of Law. The Faculty of Medicine was founded in 1901 and the Faculty of Law in 1912, both by the Ottoman government. Both Faculties were closed toward the end of the First World War, but were reopened by the Arab government in 1919 as separate schools. In 1923 they were joined to form the Syrian University which also included the Arab Academy and the Antiquities Department. These latter two institutions were separated from the University in 1928, and a Higher School of Letters, offering a three-year course, was added in the same year. The Higher School of Letters was abolished in 1933. This left the original two Faculties of Medicine and of Law as the only branches of the University.

At the time of the visit of the American Council Commission, the reorganization of Syrian education was beginning to affect the University. A former Egyptian Minister of Education, Dr. Abd al-Razzaq al-Sanhuri Pasha, who had previously been dean of the Faculty of Law at Fuad I University, was responsible for developing plans for the reorganization of the University, which include the founding of new Faculties. It was planned to open initially Faculties of Letters, Science, and Engineering, and a Higher Teachers College. The Faculty of Engineering was to be in Aleppo while the others were to be in Damascus. Faculties of Agriculture and Commerce may be opened later. The reorganization plan was established by Decree No. 40, dated September 11, 1946, "Embodying the Cadre of the Syrian University." The first students were admitted to the new Faculties in October 1946.

The administration of the University is entrusted to a president who is appointed by a decree of the Council of Ministers acting upon the recommendation of the Minister of Education. The president presides over the University council unless the Minister of Education, who is the supreme head

of the University, is present. The University council consists of the deans of the Faculties and the directors of independent institutes, of one professor representing each Faculty (chosen by the respective Faculty councils for a term of two years), a representative of the Ministry of Education appointed for a term of two years, and three members with experience in higher education appointed by the Minister of Education for a term of two years. The University council acts upon the annual budget and the final accounting, the granting of degrees and diplomas recommended by the Faculty councils, the granting of honorary degrees, the setting down of the regulations for the University's educational missions as well as approving of the students chosen to go abroad and the conditions under which they are sent. The University council further acts upon the appointment, promotion, or transfer of any of the members of the teaching staff or their delegation to another university or department inside or outside the country.

The Faculties are administered by deans appointed for three years by presidential decree upon the recommendation of the Minister of Education who in turn avails himself of the advice of the Faculty council concerned. The dean is chosen from the professors occupying chairs of the Faculty and may not be removed until his term expires unless a special presidential decree is issued for removing him at the request of the Minister of Education after consulting the University council. The dean presides over the Faculty council which consists of professors occupying chairs, other full professors, assistant professors, and three members from outside the Faculty who have special knowledge of the subjects taught at the Faculty. These latter members are appointed for a term of two years by the Minister of Education acting upon the recommendation of the University council after due consultation with the Faculty council. The Faculty council is entrusted with the running of all affairs of the Faculty except those specifically entrusted to other bodies. It usually meets once a month.

The members of the teaching staff are classified as professors occupying chairs, professors, assistant professors, and lecturers. Teaching assistants, laboratory assistants, and demonstrators are not considered as members of the teaching staff. In addition, visiting professors and part-time lecturers may be employed by decision of the University council acting upon the recommendation of the Faculty council concerned. If foreign visiting professors or part-time lecturers are needed, the approval of the Council of Ministers must be secured.

To be appointed as an assistant or a demonstrator, a candidate must hold a *licence*, a bachelor's, or an M.D. degree. He must have gained these degrees with honors; otherwise, he must pass a competitive examination before his appointment. A year after his appointment he may be sent by

the University on a mission for study abroad. While on the mission he receives his full salary and, for purposes of promotion and pension, is considered in the service of the University.

Lecturers must hold a doctorate. For the Faculty of Medicine a diploma of specialization as designated by the University council must be added to the qualifications. Assistant professors and professors must, in addition, have made significant contributions in their fields and have served for at least four years as lecturers and assistant professors respectively.

Such is the new plan for the administrative organization of the Syrian University. As is to be expected, it shows in most points the influence of the organization prevailing at the public universities of Egypt.

The Faculty of Medicine

The Faculty of Medicine, the oldest of the institutions included in the Syrian University, is situated a short distance from the right bank of the Barada River which flows through Damascus. Here one University administration building, including a lecture hall, has been built in the same compound with the hospital and the public clinics. The School of Dentistry and some of the laboratories of the Faculty, together with the University library, are situated on the premises of the old religious school of Sultan Sulayman.

The Faculty of Medicine is made up of four schools: Medicine, Pharmacy, Dentistry, and Nursing. The Schools of Medicine and Pharmacy require for admission, in addition to the second *baccalauréat* or its equivalent, a year of science study known as the P.C.B. year (physics, chemistry, biology). This is borrowed from the French plan of medical education, as indeed are the main features of medical education in Syria. The School of Dentistry admits students directly after graduation from the secondary school, while the School of Nursing requires three years of secondary schooling, but if not enough girls apply, a lower standard is accepted.

The Faculty of Medicine gives a course of five years leading to the degree of Doctor of Medicine. A further year of internship in the University hospital or another approved hospital is required before a candidate is allowed to practice. This makes a total of seven years beyond the secondary school.

In the first two years the curriculum consists of the usual basic subjects—anatomy, physiology, histology and embryology, medical physics and chemistry, and elementary diagnosis. In accordance with the French plan of medical education, clinical work begins with the first year. In the third and fourth years, pathology, parasitology, internal medicine, surgery, experimental medicine, obstetrics, minor surgery, therapeutics, and materia medica are given. Practical work in the clinics and the hospital continues

and includes bedside study of the specialized subjects in medicine—skin and venereal diseases, psychiatry, diseases of the nose, ear, and throat, children's diseases, and tropical and infectious diseases. In the fifth year, hygiene, legal medicine, medical ethics, therapeutics, and materia medica are studied.

Examinations are written, oral, and clinical, given at the end of every year and prior to the granting of the degree. The examinations are conducted by committees of professors, which included French professors in the days of the mandate. Most of the professors of the Faculty have been educated or have had their specialization in France.

The course in the School of Pharmacy requires, in addition to the P.C.B. year, a year of practical apprenticeship in an approved pharmacy prior to admission to the School. Here the apprentice takes notes on all prescriptions filled and methods used, and before entering the School of Pharmacy has to pass a written and practical examination based on his experience of the previous year. He then enters a three-year course of theoretical and practical subjects in pharmacy and allied sciences, leading to practical and theoretical examinations at the end of every year and at the end of the third year.

The course in dentistry requires no P.C.B. preparatory year and consists of four years of study above the secondary-school studies. The course includes a study of "descriptive" anatomy, anatomy of the teeth, physiology, histology, bacteriology, inorganic, organic, and analytical chemistry, biochemistry, dental surgery and minor surgery, crowns and bridges, fillings, anesthesia, X-ray, and other allied subjects. Yearly and final examinations are both theoretical and practical and lead to the degree of Doctor of Dental Surgery.

The School of Nursing and Midwifery as envisaged in the decree embodying its new regulations accepts unmarried girls between the ages of seventeen and thirty who have finished the third secondary year, or, if sufficient applicants are not available with this preparation, girls who have had some study beyond the primary school and who pass an entrance examination. The course for nurses is of three years. Students may be day or boarding students. A fourth year is provided for those interested in midwifery. Students in midwifery must be boarders. Six hours a day of practical nursing and, later, midwifery are required throughout the four years, plus five to seven hours a week of study in anatomy, physiology, hygiene, bacteriology, parasitology, pharmacology, chemistry, the anatomy of the female genital organs, midwifery, legal medicine and ethics, and brief courses in the various types of diseases. Practical and theoretical

yearly and final examinations lead to the diploma in nursing or in nursing and midwifery.

The Faculty of Medicine has one hospital of 160 beds and another with 60 beds in obstetrics. It has also an outpatient clinic. The School of Dentistry has 13 dental chairs. Laboratories in chemistry, physics, anatomy, biochemistry, histopathology, and other subjects are located mostly in the nearby old building of the religious school of Sultan Sulayman. The laboratories on the whole are of modest proportions and the building is unfit for them.

THE FACULTY OF LAW

The Faculty of Law gives a course of three years above the second *baccalauréat.* With the shortening of the secondary course it is hoped to lengthen the course to four years. Students are prepared to be lawyers, judges in civil courts, and judges in Shar' (Muslim law) courts. Many of the graduates become government officials. The examinations leading to the degree of *Licence* in Law are conducted by committees consisting usually of two professors and a prominent judge, lawyer, or government official for each of the subjects. These external examiners are appointed by the Minister of Education. Graduates must work in a law office for two years before being licensed to practice before the courts. The government when endeavoring to fill a legal office holds its own special examinations which in the case of filling a vacancy in the Shar' courts include examinations in Muslim law.

Study at the Faculty of Law relies heavily on lectures. A student is permitted to absent himself from up to 50 percent of the lectures. A long period is allowed at the end of the year for the final examinations. Naturally, cramming at the end of the year is the prevailing practice.

The University library consists of 12,000 volumes, mainly in Arabic, French, and English. Books may be read in the library and are lent outside the library only to members of the teaching staff.

Student registration in 1945–46 was as follows:

Faculty	Enrollment
Medicine	256
Pharmacy	59
Dentistry	32
Nursing and midwifery	49
P.C.B. class	103
Law	541
Total	1,040

About one-third of the student body was from other countries, mainly Arab.

Teaching at the Syrian University is conducted entirely in Arabic. The Faculty of Medicine is the only such faculty in the Arabic world which teaches in Arabic.

Educational Missions

Educational missions were sent chiefly to France prior to World War II. With the French government as mandatary power, with French advisers to the Ministry of Education, and with the Syrian educational system following French educational methods and ideas, this was to be expected. As has already been said, graduates of French universities and institutions were shown a decided preference in appointments to posts in the Ministry of Education. The situation was not different in other departments of the government. It was only natural, therefore, that even students going abroad for study at their own expense usually preferred to go to France.

Even in 1943–44, when the French grip on Syria had loosened, 58 out of a toal of 101 students on educational missions were studying in France; most of them had begun their study in the prewar period. Of the other 43, there were 37 in Egypt and 6 in Beirut.

For the year 1946–47 it was planned to send 120 students abroad. None of these was being sent to France, partly because of the aversion to the French that has developed in Syria, and partly because the new Secondary-School Certificate is no longer recognized in France. Most of the students were being sent by the Ministry of Education. The remainder were being sent by other ministries. The countries to which the students are being sent are Belgium, Switzerland (evidently taking the place of France), Great Britain, the United States, and Egypt. Only a few are destined to study in Great Britain or the United States largely because of the difficulty of securing admission to American and British universities. The subjects to be studied cover a wide range and include the various branches of engineering, architecture, technical education, agriculture, irrigation, mathematics, the sciences, finance, medicine, public and school health, law, archeology, Semitics, history, English, education, commerce, and Arabic literature.

The Education of Teachers

The education of teachers in Syria has gone through a number of stages. In the latest of these, two kinds of teachers colleges were maintained: the

elementary-teachers college, which accepted students holding either the first *baccalauréat* or the *brevet* and gave them a course of one year; and the primary-teachers college which accepted holders of the second *baccalauréat* and gave them a course of one year. Later each of these courses was lengthened to two years. In addition, special examinations were held for the granting of the Certificate of Efficiency in Teaching. A total of 809 men and 242 women had been graduated from the teachers colleges or had received the Certificate of Efficiency in Teaching between 1919 and 1943. During the latter year there were 35 students in the Primary Teachers College for Men in Damascus, 13 in the Teachers College for Women in the same city, and 16 in the Elementary Teachers College for Men in Aleppo—a total of 64 students. In view of the great need for teachers, these numbers were wholly inadequate.[1]

Steps were therefore taken to increase the enrollment and to open a Teachers College for Women in Aleppo, bringing the total number of teachers colleges to four. Enrollment in 1944–45 increased to 153 men and 131 women students, a total of 284, and in the following year the American Council Commission found 162 men and 215 women in the four colleges, a total of 377 students.

At the present time the education of teachers is in the transition stage. As indicated before, three types of courses are being offered.[2] A professional course of one year is given, to which holders of the second *baccalauréat* are admitted. This course which is given only in the Damascus teachers colleges for men and women is expected to disappear with the disappearance of the second *baccalauréat*. In 1945–46 there were 17 men and 16 women registered in this course.

The second course is one of two years above the first *baccalauréat* or above the new Secondary-School Certificate. This is also a professional course which was started in 1944–45, with the first class graduating in June 1946. It was hoped that this course would attract more students than the previous one, since holders of the second *baccalauréat* are in demand in various fields which normally they would prefer to teaching. With the offering of a two-year education at the expense of the state it was thought that this course would attract more students. In 1945–46, the enrollment

[1] Sati' al-Husri, *Reports* . . . 1944, pp. 132–34 and 137–38.

[2] See Decree No. 1144, dated October 23, 1944, "Embodying the Amendment of the Regulations of Teachers Colleges for Men and Women," and Decree No. 182, dated February 20, 1945, "Embodying the Regulations for Primary Teachers Colleges for Men and Women," both in Ministry of Education, *Regulations for Intermediate and Secondary Schools and Teachers Colleges* (Damascus: Government Press, 1945), pp. 34–51.

in the two-year course was 41 men and 47 women, all in the Damascus teachers colleges.

The third type is a three-year course admitting students from the intermediate school. This was also started in 1944–45 and was in its second year at the time of the visit of the Commission. The first class was to be graduated in June 1947. It was hoped that the course would attract an even larger number of students. In 1945–46 there were 263 students (104 were men and 159 women) taking the three-year course in the 4 teachers colleges. As this course promises to be the most extensive, and possibly the permanent, plan, its program of studies is given in Table 65.

TABLE 65

PROGRAM OF STUDIES OF THE THREE-YEAR COURSE FOR THE EDUCATION OF TEACHERS, SYRIA, 1946

Subject	Periods per Week		
	1st Year	2nd Year	3rd Year
Academic:			
Religion	1	1	...
Arabic language and literature	5	3	...
French and translation	5	3	...
History	3	2	2
Geography	2	2	...
Mathematics	4	4	...
Physics and chemistry	3	3	2
Biology, agriculture, and hygiene	3	3	3
Sociology	...	...	3
Professional:			
Psychology and logic	...	3	2
Methods of teaching	...	3	4
Practice teaching	...	...	8
Practical or artistic:			
Drawing	2	2	2
Manual arts	...	2	2
Physical education	2	...	...
Music	2	...	...
Arabic penmanship	2	...	...
Agricultural activities	...	3	6
Total	34	34	34

The course of study is divided into three parts: the academic subjects, the professional subjects, and the practical or artistic subjects. The academic subjects are largely concentrated in the first two years and aim at rounding out and replenishing the student's fund of knowledge gained in the intermediate school. The professional subjects begin in the second year. In the theoretical and practical teaching of agriculture, as well as in hygiene, some recognition seems to have been given to the possible needs of the rural-school teacher.

Practice teaching takes place in a special practice school. Individual

lessons are given by each student with his classmates observing him. These lessons are later criticized by the students and the teacher of method. In the second half of the year the student spends fifteen days in full-time teaching.

Admission of students is controlled by a committee consisting of the principal as chairman and two lecturers as members. Students are admitted on the basis of their standing in the previous public examinations, a medical examination, and an interview.

Education in the teachers colleges is free, including board and lodging. Day students are reimbursed for the value of board at the rate of £S50 ($22.70) a month. All students receive £S15 ($6.80) a month for expenses. All the four colleges have boarding departments. The following was the number of day and boarding students in each college for the year 1945–46:

College	Day	Boarding	Total
Damascus Teachers College for Men	62	67	129
Damascus Teachers College for Women	130	22	152
Aleppo Teachers College for Men	13	20	33
Aleppo Teachers College for Women	45	17	62
Total	250	126	376

Three of the colleges were housed with the secondary schools in government buildings, while the fourth, the Teachers College for Women in Damascus, was in a rented building. The 2 colleges at Aleppo are headed by the principals of the public secondary schools in that city.

Most of the staff of the teachers colleges also teach in the secondary schools. Their qualifications are generally the same as those of the secondary-school teachers, already mentioned. The lecturers in education, practice teaching, and psychology in most cases have been educated in France, although some have been educated in Germany and at the American University of Beirut.

Chapter 23

PRIVATE AND FOREIGN SCHOOLS

PRIOR TO the Franco-Syrian political crisis of May 1945, private and foreign schools provided for the education of approximately 42 percent[1] of the school enrollment of Syria, excluding the *kuttabs*, or ungraded Koran, schools. These schools include primary (with kindergarten), secondary, and vocational schools. No private or foreign teachers colleges or higher institutions exist, except the American Junior College at Aleppo. As this last was recognized as an institution equivalent to those institutions preparing for the second *baccalauréat*, it was not classified as a higher institution. Table 66 shows a comparison for 1944–45 of the number of institutions and enrollment in private and foreign schools with the public schools of their level.

In 1944–45 there were 685 public primary, secondary, and vocational schools with an enrollment of 92,598 students, compared to 306 private schools with an enrollment of 44,790 students, and 160 foreign schools with an enrollment of 23,887 students. Thus, public-school enrollment accounted for 57.4 percent of the total enrollment in these three types of schools, private schools accounted for 27.8 percent, and foreign schools for 14.8 percent.

One feature brought out by Table 66 is that, while the total enrollment of girls as compared with boys in the public schools was approximately in proportion of one to three, it was one to two in the private schools and nearly one to one in the foreign schools. Private and foreign schools were educating more girls than were public schools (25,892, as compared with 23,474). They were, however, educating considerably fewer boys (42,785, compared with 69,124). Not only was the proportion of girls schools to boys schools greater in the private and foreign schools, but there were a comparatively large number of coeducational private and foreign schools. None of the government schools, except the University, is coeducational.

Comparative figures are shown in the following tabulation:

[1] This is the second highest proportion of private- and public-school enrollment in the six Arab countries studied here, the first being Lebanon.

Administrative Control	Number of Schools Boys	Girls	Coeducational	Total
Public schools	560	125	..	685
Private schools	167	48	91	306
Foreign schools	61	53	46	160
Total	788	226	137	1,151

Another fact brought out by Table 66 is that while foreign schools occupied third place in number of institutions in the field of primary education, accounting for 13.5 percent of the enrollment as compared with 39 percent by the private schools, the situation was reversed in the field of secondary education where the foreign schools occupied second place with 32.9 percent of the secondary-school enrollment, while private schools held third place with only 15 percent. The same thing is true of the vocational schools, where foreign schools have 16.4 percent of the enrollment and private schools only 3 percent.

Most of the foreign schools were French schools as shown in Table 67. Thus 120 out of 160, or 75 percent of the schools, were French. These schools had an enrollment of 19,710 out of 23,887 pupils, or 82.9 percent of the total foreign-school enrollment. A number of the schools registered as foreign however, are in effect private schools registered as French by the French authorities in the days of the mandate. Of such a character are the schools of Alliance Israelite Universelle, which are locally supported and are occupying buildings built by the local Jews, and some of the local Catholic sectarian schools which for various reasons previously preferred to be classed as French schools. Similarly, but in a reverse way, some of the so-called "American" schools had first been established by American missionaries, but have now been transferred to the local Protestant communities, though they are still registered as American schools.

Such was the situation as regards private and foreign schools up to the Franco-Syrian crisis of May 1945. It was then that the French schools were boycotted and closed. They remained closed throughout the following year of 1945–46, except for a few schools which declared themselves to be really native schools, willing to accept the conditions set by the new education law, and appointed Syrian principals. They were then registered as private schools and allowed to open. The closing of the French schools naturally caused a rush on the public and private native schools. The measures taken by the Ministry of Education to deal with the situation have been indicated previously (pages 326–27). Here it is sufficient to say that the loss of the French schools meant the gain of the public and private schools. Accordingly, there was a sharp drop in the enrollment in foreign schools

TABLE 66

Public, Private, and Foreign Schools and Their Enrollments on Various Levels, Syria, 1944–45

Type of School	Public Schools				Private Schools				Foreign Schools				Grand Total, Enrollment
	No. of Schools	Enrollment			No. of Schools	Enrollment			No. of Schools	Enrollment			
		Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total	
Primary	658	63,755	21,785	85,540	287	28,800	14,210	43,010	127	9,942	9,936	19,878	148,428
Percent				*57.5*				*29.0*				*13.5*	*100.0*
Secondary	22	4,557	1,490	6,047	17	1,283	460	1,743	30	2,639	1,163	3,802	11,592
Percent				*52.1*				*15.0*				*32.9*	*100.0*
Vocational	5	812	199	1,011	2	20	17	37	3	101	106	207	1,255
Percent				*80.6*				*3.0*				*16.4*	*100.0*
Total	685	69,124	23,474	92,598	306	30,103	14,687	44,790	160	12,682	11,205	23,887	161,275
Percent				*57.4*				*27.8*				*14.8*	*100.0*

TABLE 67

Foreign Schools and Enrollment Classified According to Nationality of Governing Body, Syria, 1944–45*

Nationality	Primary Schools				Secondary Schools				Vocational Schools				Total	
	No. of Schools	Enrollment			No. of Schools	Enrollment			No. of Schools	Enrollment			No. of Schools	Enrollment
		Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total		Boys	Girls	Total		
French	96	8,179	8,655	16,834	21	1,921	748	2,669	3	101	106	207	120	19,710
American	18	1,273	699	1,972	6	678	312	990	...	...	...	...	24	2,962
British	6	344	203	547	2	40	94	134	...	...	...	...	8	681
Danish	6	136	359	495	1	...	9	9	...	...	...	...	7	504
Greek	1	10	20	30	...	...	...	...	...	...	...	...	1	30
Total	127	9,942	9,936	19,878	30	2,639	1,163	3,802	3	101	106	207	160	23,887

* Data supplied by the Ministry of Education. See also Sati' al-Husri, *Reports on the Conditions of Education in Syria during the Year 1945* (Damascus: Government Press, 1946). pp. 52 and 56.

in 1945–46 with a corresponding drop in the percentage of foreign-school enrollment compared with the total primary- and secondary-school enrollment. This is clearly brought out in Table 68.

TABLE 68

COMPARISON OF ENROLLMENT IN PUBLIC, PRIVATE, AND FOREIGN SCHOOLS, SYRIA, 1944–45 AND 1945–46*

CONTROL	PRIMARY-SCHOOL ENROLLMENT				SECONDARY-SCHOOL ENROLLMENT			
	1944–45		1945–46		1944–45		1945–46	
	Pupils	Percent	Pupils	Percent	Pupils	Percent	Pupils	Percent
Public schools...	85,540	57.5	99,703	66.5	6,047	52.1	8,276	65.3
Private schools...	43,010	29.0	47,224	31.5	1,743	15.0	3,322	26.3
Foreign schools..	19,838	13.5	3,207	2.0	3,802	32.9	1,063	8.4
Total.......	148,388	100.0	150,134	100.0	11,592	100.0	12,661	100.0

* Figures from Sati' al-Husri, *Reports . . . , 1945*, pp. 136–38.

Enrollment in public primary schools increased by 14,163 in 1945–46 and its percentage of the total enrollment rose from 57.5 percent to 66.5 percent. The private-school enrollment increased by 4,214 pupils, and its percentage rose by 2.5 percent to 31.5 percent. At the same time the foreign schools lost 16,631 pupils, their percentage declining from 13.5 percent to 2 percent.

Similarly, the public secondary schools show an increase of 2,229 students and a rise in their percentage of 13.2, while the private secondary schools almost doubled their enrollment by adding 1,579 students and raising their percentage from 15 to 26.3. The foreign secondary schools lost 2,739 students, their percentage going down from 32.9 to 8.4. It is to be noted that in spite of the closing of more than 100 French schools, the total school enrollment in 1945–46 increased over the previous year. Primary schools show a net increase of 1,746 pupils, and secondary schools increased by 1,069 students. This would tend to show that as far as student registration is concerned, the crisis created by the closing of the French schools was fully met.

It is interesting to note that the decrease in the enrollment of the foreign schools is almost entirely due to the closing of the French schools. The schools of other nationalities remained largely unaffected as shown by the following figures of enrollment in non-French schools:

Year	Primary	Secondary
1944–45	3,044	1,133
1945–46	3,207	1,063
Gain or loss	+163	−70

The non-French primary schools increased by 163 pupils, while the secondary schools decreased by 70. It can, therefore, be said that enrollment in the other foreign schools remained substantially the same and that these schools were unaffected. The reaction was entirely against the French schools.

As all three foreign vocational schools had been French and had closed, there were no foreign vocational schools in 1945–46.

The future of the French schools remains uncertain. It is probable that those French schools which were originally Syrian schools will be registered as private schools, as indeed some have already been. The others, or at least some of them, will probably reopen, but with much less prestige and with reduced enrollment. It is reported that a few French schools were allowed to reopen in 1946–47.

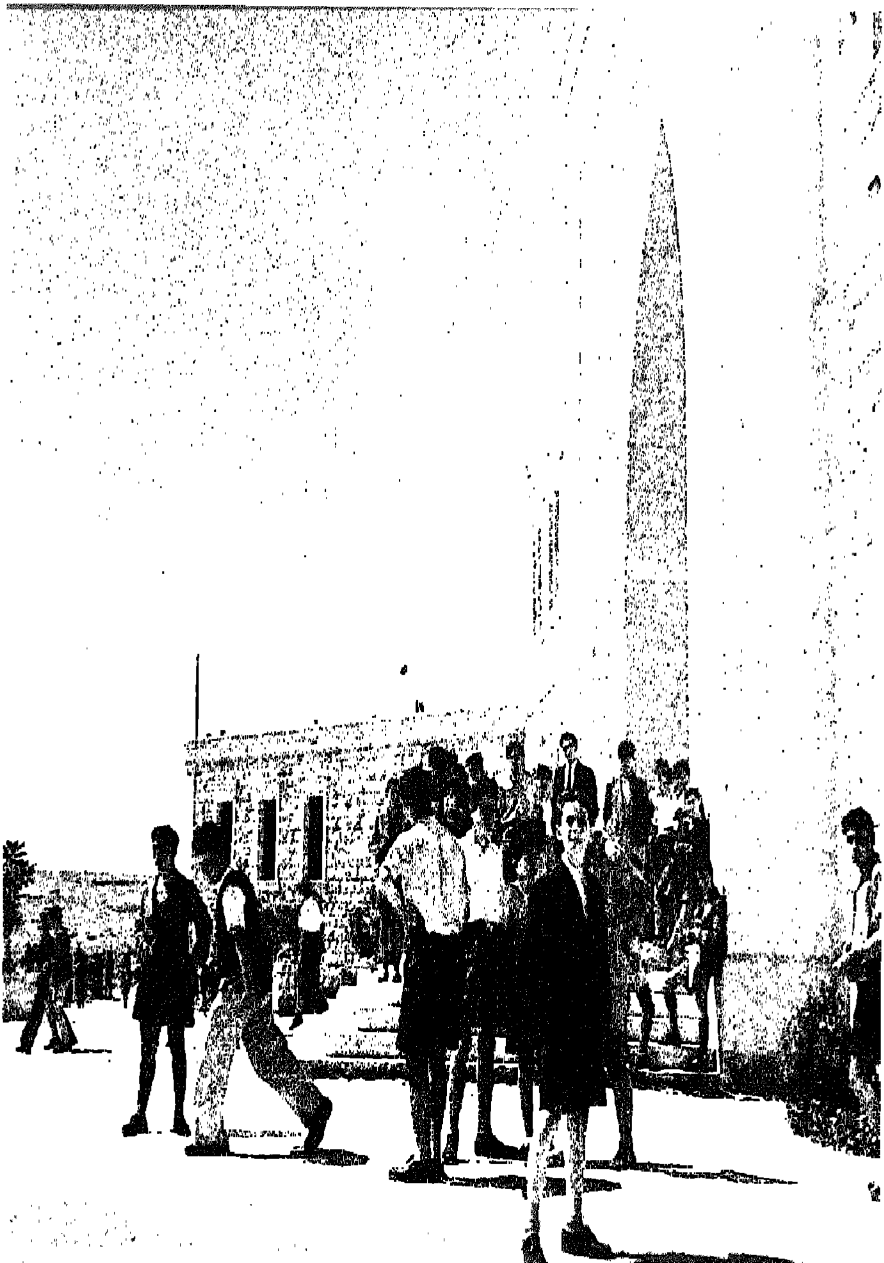
The Franco-Syrian crisis and the new plan of the Ministry of Education to abolish the teaching of a foreign language in the primary schools created a problem for some of the private schools. Christian schools especially, largely in response to the demands of parents who are usually keen on their children's learning foreign languages, frequently start the teaching of French in the first grade and often even in the kindergarten. This they did even at the time when government schools started French in the fourth grade.

With the coming of the new regime of independence and the abolition of the foreign language from the primary-school curriculum, pressure was brought to bear upon the private schools to follow the lead of the public schools—or at least to postpone the teaching of the foreign language until the two upper grades. This, however, would put the private schools at a disadvantage with the foreign schools, almost all of which begin the teaching of the foreign language, usually French or English, very early. Representations were, therefore, made by some schools that if such a course were followed, the private schools would lose a large number of their pupils to the foreign schools, owing to the insistence of parents on their children's learning a foreign language. The representations of the schools were successful, at least temporarily. How permanent such an arrangement can be, and how far there will be a shift from French, which prevailed in most of the private Christian schools, to the English language is a matter of the future.

Grants-in-Aid

A decree was passed in March 1945 setting down the conditions for giving grants-in-aid to private schools and other cultural institutions.[2] This

[2] Decree No. 261, dated March 25, 1945, "Embodying the Regulations for Grants-in-Aid to Private Schools and to Cultural, Artistic, and Sporting Institutions."



Aleppo College, Aleppo, Syria
This view shows the Arabic arched façade of the main classroom building





Above: One of the classroom buildings of the secondary school for boys, Homs, Syria
Below: A village primary school with a school garden, near Homs

decree, designed to encourage private individual and group effort "in the service of science, letters, fine arts, and physical education," provides that financial aid is to be given to private schools and educational institutions in proportion to their service to education and to their financial needs. Criteria are established to serve as a basis for the distribution of funds: (1) the level of the school and the number of its classes and pupils; (2) the standard of education provided; (3) the number of teachers, their qualifications and teaching ability; (4) the curriculum and the degree of its agreement with the public-school curriculum; (5) the number of students participating in the public examinations and the percentage of those passing; (6) the income and expenditures of the school; and (7) the fees levied upon students and the number of students exempted from the payment of fees.[3] Grants are to be allotted annually by the Education Council in the first half of August. The council's decisions in this matter must be based upon the reports of the inspectors and directors of education concerning each school. If necessary, the Ministry of Education may pay the grant in the form of salaries paid to teachers which it selects or appoints to the schools.

Bases are also laid down in the 1945 decree for the distribution of grants to cultural, artistic, and sporting societies and clubs.

This provision as to grants-in-aid was of great help to the Ministry of Education in its attempts to meet the crisis created by the closing of the French schools. The budgetary provisions for the grants were trebled by being increased from £S100,000 (about $45,450) to £S302,500 (about $137,500). Private schools were encouraged to open new classes to take in more pupils, and grants were given to stimulate the opening of new schools.

Private Schools

Private primary schools are usually classified in Syria by the denomination of the authorities controlling them. Table 69 shows the denominational distribution of private primary schools in Syria for 1944–45.

The data for the 9 private secondary and 8 intermediate schools, which have an enrollment of 1,743 students, are not given by denominations.

It does not, however, follow that all the schools classed as controlled by denominations are actually so. Many of them are really secular and are simply classified according to the sect of the controlling authority, following a custom started during the French mandate which emphasized sectarian matters as a policy. In actual fact private schools are of three main categories:

[3] Compare with Iraq, pp. 128–29.

sectarian schools, schools controlled by societies and groups, and schools controlled by individuals.

The first class of schools is that maintained by religious groups, the clergy, or by lay organizations having a religious motive. The second are conducted by groups having a philanthropic or national aim, often without regard to religious affiliation, and the last, those conducted by individuals, may be philanthropic or national in aim, but are often established to secure a livelihood or personal gain for the founder.

TABLE 69

DISTRIBUTION OF PRIVATE PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO RELIGIOUS CONTROL, SYRIA, 1944–45*

Denomination of Controlling Authority	No. of Schools				Enrollment		
	Boys	Girls	Coeducational	Total	Boys	Girls	Total
Muslim	53	15	9	77	11,146	3,518	14,664
Catholic (Greek, Syrian, Chaldean, Maronite, and Armenian)	49	12	10	71	5,128	2,673	7,801
Orthodox (Greek, Syrian, and Armenian)	50	11	50	111	10,129	6,542	16,671
Protestant (Syrian and Armenian)	2	...	15	17	942	754	1,696
Jewish	3	...	1	4	822	24	846
Miscellaneous	1	2	4	7	633	699	1,332
Total	158	40	89	287	28,800	14,210	43,010

* Figures from Sati' al-Husri, *Reports . . . 1945*, pp. 43–44.

In the sectarian category fall the schools maintained by the Waqf department for the training of Muslim religious teachers as well as judges and clerks for the Muhammadan law courts. There are 5 of these schools, enrolling 424 students. Such schools are, however, actually public schools since they are supported by Waqf funds. The Ministry of Education pays nothing toward their maintenance and consequently classes them as private.

Some of the schools are of hardly more than primary standard. Two, however—1 in Damascus and 1 in Aleppo—are of a higher standard. The *Sharī'ah* college in Damascus was founded by the Body of 'Ulama in 1942. It is still in the process of development. In 1945–46, it had 140 students, of whom 85 were boarders from the various parts of Syria. Admission is from the primary school, and the plan is to have a series of three courses, one above the other. The first course of six years would be a kind of religious secondary course to prepare clerks for the Muhammadan law courts and teachers of religion for the elementary schools. A higher course of four years would aim at training higher clerks for the courts, preachers, minor judges, and teachers of Arabic and religion for secondary schools. Finally,

a special course of two years would prepare full judges and *muftis*. Eight of the proposed fourteen classes were in existence in 1945–46. The Aleppo school follows the same program. At the end of the first and second courses a public examination is held for which the questions are set by the professors of the 2 schools at Aleppo and Damascus sitting together.

The Damascus school is run by a board composed of the *qadi* (a judge of the canon law of Islam) as chairman, the *mufti* of the Republic, the *naqib* (dean or registrar), the directors of Waqf of the Republic and of Damascus, two representatives of the Ministry of Education, and finally the director and the secretary of the school. Education is entirely free, including the board and lodging of the boarding students.

A sectarian Muslim school of a different kind is the Islamiyah College in Aleppo maintained by a society of Muslims who support the idea of a modern education but who also believe in a sound Islamic religious education. Its sponsors believe that the curriculum of the modern schools errs in giving too little attention to Muslim religious education and to Muslim character. At the same time it is felt that it is necessary "to counteract the effects of foreign schools." A group of citizens mostly connected with the Muslim Orphanage of Aleppo got together and solicited the help of a devout Aleppo lady who gave them the funds for erecting a large building for the school on the outskirts of the city in 1943. The school in 1945–46 had 238 boys enrolled in fifth primary through the sixth secondary. It had 30 boarding students of whom 8 were from the Orphanage and were given their education and living free after passing a competitive examination. The remainder came from the districts of Aleppo province and paid for their tuition, food, and lodging at the rate of £S700 (about $318.00). Tuition for day students ranges from £S50 to £S160 ($22.70 to $72.00) with full exemption for 10 boys and half-exemption for another 51 boys.

The curriculum of the government schools is followed with the addition of more hours for the study of the Koran, religion, and Muslim character. The school is supported by contributions from the public, by grants from the central government and the municipality of Aleppo, and by fees.

The Christian sectarian schools follow two main types—the Greek Orthodox and the Roman Catholic.

The Orthodox schools are exemplified by the Greek Orthodox school in Damascus which was visited by the American Council Commission. This school and 5 other schools in Damascus are conducted by the denominational council of the Greek Orthodox church—a council which has control

of the property, the finances, and the philanthropic and educational activities of the church. A board of five men, all laymen, is chosen by the council to have charge of the schools. These 6 schools make a complete kindergarten, primary, and secondary ladder by themselves, consisting of 2 boys primary schools, 2 girls primary schools (1 of which is topped by an intermediate section), a coeducational primary school, and a complete secondary school for boys. Girls leaving the girls intermediate may join the secondary classes at the boys secondary school, and in 1945–46 there were 5 girls who had done this.

The schools are supported by fees, by income from the church endowment and property, by grants from the government, and by contributions. The buildings are owned by the Greek Orthodox church and community. The student body, though predominately Greek Orthodox, has students from other denominations. The boys secondary school, for example, has about 40 Muslims, 25 Jews, and 20 Catholics. The teaching staff of the school is also mixed: 16 Greek Orthodox, 5 Muslims, 2 Jews, and 3 Catholics. Fees are £S6 to £S90 in the primary schools and £S20 to £S200 in the secondary schools.

All pupils whose families receive help from the welfare society of the Greek Orthodox community are exempt from fees. Other pupils pay according to ability after inquiry by the priests and the committee.

In general, the curriculum follows that of the government, but with two important differences. French is begun in the first primary grade, and English in the first secondary grade. Arabic reading is begun toward the end of the first kindergarten year and continued in the second kindergarten year. By the time the children enter first grade, they know how to read. The first grade is, therefore, in reality equivalent to the second grade of the government schools; and, although the primary school is nominally five years, it is in actual fact six years. The first-grade children appear to be above the average age. This procedure may perhaps have been necessitated by the early teaching of French.

The problem of teaching a multiplicity of languages in primary schools is found in an extreme form in Armenian schools. The largest Armenian community in Syria is in Aleppo where Armenians took refuge after the Armenian massacres in Turkey during the First World War. Anxious to preserve their national language and to know the language of the country of their adoption, they have had to teach both Arabic and Armenian. At the same time the advantages that accrued to those who knew French under the mandate made them introduce that language into their schools, while the fact that most Armenian youth who wanted to continue their

education preferred an American school forced them to teach English as well.

This situation is well illustrated by the 2 Giligian primary schools in Aleppo—1 for boys and 1 for girls. Both are under the same principal. The boys school had in 1945–46 an attendance of 254 boys, while the girls school had 228 girls. The kindergarten department in connection with the latter had 240 boys and girls in four sections, one section of which had 72 children. Naturally, the teacher could do little more than watch over the children. In these schools Armenian is begun in the upper section of the kindergarten, Arabic in the first grade, English in the second grade, and French in the third. Previously, however, it was the practice to begin French in the first grade.

In order to provide for a program so heavily loaded with languages, each grade has an average of thirty-six to thirty-seven periods a week. The program also extends over six years instead of the usual five years of the public schools. The schools are housed in rented houses, and are supported mostly by fees ranging from £S30–£S60 a year. About 65 boys and girls are exempted. The government pays a grant of £S750 a year and the salary of one teacher which it supplies. The other teachers are graduates of American secondary schools, holders of the second *baccalauréat,* or women who have had some secondary studies. Two are from the Armenian secondary school in Istanbul, Turkey, while five men and women are graduates of the Armenian teachers college in Nicosia, Cyprus. This is an institution offering a course of three years above the secondary school for the education of teachers for Armenian schools.

While Orthodox schools are mostly controlled by laymen's councils of the community with the clergy in the background, the Catholic schools are controlled to a considerable extent and often directly by the clergy. The 3 Catholic private schools visited by the Commission in Syria were of this nature. A Catholic primary school in Aleppo was under the supervision of the Bishop of Aleppo and supported by him. The Maronite school for boys is headed by a priest and housed in a building belonging to the church. Its deficit is met by the Maronite welfare committee. A Maronite girls school in Latakia is conducted by the Maronite nuns of the Holy Family commonly known as the "nuns of 'Ibrin," a village in Lebanon where the mother convent is located. In all these schools French is stressed, except that the latter school by agreement with the government begins the teaching of French in the fourth grade.

The final type of private school is the nonsectarian school maintained either by groups and societies or by individuals.

An example of the former is the Dawhat al-Adab school for girls in Damascus, maintained by the society of the same name. It is a school founded by a group of society women of Damascus who thought that a school for society girls was needed. Hitherto such schools were mainly in the hands of nuns, while the government schools were open to all classes. An organization was, therefore, established in 1928 which opened the school in 1931. The school, which began in a small way, now has a kindergarten, a primary section, and a secondary section leading to the second *baccalauréat*. Although established for society girls, many girls from poorer homes are accepted. Comparatively high fees are charged, but 30 girls are fully exempt, and another 40 are partially exempt. Fees range between £S120 and £S200 a year. The school has a large budget of £S120,000 (about $54,550), toward which the government contributes £S20,000. The program followed is that of the government, with the addition of the English language. Special attention is paid to home economics, sewing, and embroidery. A number of student societies exist. An Arab society follows up the news of the Arab world; a cultural society holds lectures, invites speakers from outside, and takes care of the library; a cooperative society of the type found in many schools helps poorer students; and social committees help the needy in the city.

The individual private school is exemplified by the Scientific National College at Damascus, founded in 1907 by Dr. Munif Aidi, a professor of the Faculty of Medicine of Syrian University, and now administered by his son. It consists of a boys primary and secondary school, a girls primary and secondary school, and a coeducational kindergarten. These schools together have an enrollment of more than 1,000 students, of whom 109 are boarders. The schools have a budget of more than £S200,000. About 70 percent of the revenue is from fees, the government pays a subsidy of £S12,500, and contributions are solicited from the public. The Syrian government contributes five teachers without charge, while the Egyptian government contributes three.

The school has tried to fit its program to the demand. Prior to 1939, a section preparing students for the French *baccalauréat* examination existed side by side with the section preparing for the Syrian *baccalauréat*. Recently, with the disappearance of the French and the ascendance of the English, a section organized along the lines of the preparatory school of the American University of Beirut has been opened.

The school pays some attention to sports and games and has its own teams which play against other schools. It has a Boy Scout troop and a recently established Girl Guide troop. Student societies also exist.

In summary, it may be said that, while there are some good private schools, the general impression left on the visitor is one of precarious finance leading to makeshift arrangements, such as poor accommodations, small rooms, crowded classes, and, often, poorly qualified teachers. On the other hand, they make a more determined effort to keep in touch with the parents than do the public schools and are more careful about the teaching of languages. There is little, if any, original or creative planning being done in the private schools with regard to curriculum, methods, or organization. If they are not following the government curriculum, they are usually imitating one or the other of the foreign-school systems in the country, generally either the French or the American schools.

Foreign Schools

Foreign schools in Syria belong to five different nationalities: French, American, British, Danish, and Greek, named in the order of their numerical importance. Greek and Danish schools could not be visited by the Commission, the latter lying in eastern Syria outside of the Commission's itinerary. French schools were entirely closed during the whole year of 1945–46 and could not, therefore, be visited. The visits of the Commission were confined to 5 American schools in Damascus, Aleppo, and Latakia, and to a British school at Idlib, which lies between Aleppo and Latakia.

One originally French school, the Lazarist school for boys in Damascus, was visited. It is one of the oldest, if not the oldest existing school in that city. The Lazarist mission had been founded in Damascus in 1755, and the school had followed about two decades later. After a very long service of a century and a half, it had become part of the Catholic community of Damascus. When the Franco-Syrian crisis of 1945 took place, therefore, it had been registered as a native school and allowed to remain open. (A separate school for girls was also open, which included boys in the first grade.) The school, however, was running on a reduced scale, as it had opened late and many students had gone elsewhere. The morale seemed to be low, and there was an atmosphere of uncertainty about future developments.

The school consisted of five primary and four secondary grades. It had fourteen teachers, of whom eight were brothers. This is rather typical of French missionary schools in Syria and Lebanon run by the various Catholic orders of monks. In this way cost is reduced to a minimum. Teaching was being conducted in Arabic, except in science and mathematics in the upper classes, which were taught in French. The teaching of French started from

the first primary grade. Otherwise, the school was following the government program. Fees of £S30–£S40 in the primary grades and of £S50–£S150 in secondary grades were being charged. About 100 students did not pay any fees, while others made partial payments. As the school was in intimate touch with the community, it had no difficulty in knowing the poorer pupils who needed to be exempted from fees. Fifteen students were boarders as compared with 73 in the previous year.

Most of the French schools are conducted by the various orders of monks or nuns such as the Jesuits, the Lazarists, or the teaching order of the Christian Brothers. There are, however, schools that belong to the French secular mission known as the Mission Laïque which had a number of schools in Syria, particularly in Aleppo, Damascus, and Tartus, on the seacoast between Tripoli and Latakia. Since the French schools almost invariably follow the French type of program, together with the government program, they are not usually different from the other French schools in Lebanon. A further description of them will, therefore, be found in chapter 26.

The British school for boys and girls at Idlib was founded in 1927 by the Irish Mission Board of the Reformed Presbyterian Church. It consists of one kindergarten and seven primary classes and in 1945–46 enrolled a total of 136 children, of whom 92 were boys and 44 were girls. The fees range from £S45 to £S108, paid in nine monthly installments. All teaching is done in Arabic, except in the seventh grade, where it is done in English. Previously, both French and English were taught, the former beginning with the second grade, and the latter with the fourth grade. French is being gradually eliminated, the seventh grade in 1946 being the last class to take it. English now begins informally in the kindergarten, and formal teaching of it begins in the second grade. The school was staffed with four full-time and two part-time teachers of whom one full-time woman teacher was British. She was the principal.

Five American schools were visited by the Commission: Damascus College, the American High Schools for Boys and Girls in Latakia, the American High School for Girls in Aleppo, and Aleppo College, which includes a high school for boys.

Damascus College was opened in the fall of 1945 by the American University of Beirut, on the basis of an understanding with the government, which was anxious, because of the closing of the French schools, to provide the best educational facilities possible. Accordingly, a high school was started in a rented building, the high rent being contributed by the government. Only the first two secondary classes were opened rather late in the

year—after many likely students had registered elsewhere. The school had a staff of four full-time and two part-time teachers and a registration of 33 full-time day students in the first two classes. In addition, there were the two special English classes, one of which was for adults. It is hoped that this school will eventually develop into a junior college, drawing away from the University at Beirut some of the pressure of student applications. Teaching is conducted in English, and the program is the same as that of the preparatory school of the University in Beirut.

The two American schools, one for boys and one for girls, in Latakia are maintained by the Reformed Presbyterian Mission of North America and are under one administration. They were founded in 1860 and occupy buildings belonging to the Mission erected in the late eighties. The boys school had an elementary section of six grades enrolling 332 boys and a secondary section with four grades enrolling 74 students. The eleventh grade, which is the highest grade, was missing in 1945–46. The school had twelve teachers, of whom two were American. The government contributes two teachers but no financial aid. The girls school had a kindergarten with 121 boys and girls, and a school ordinarily of eleven grades of which only eight existed during 1945–46, enrolling 313 girls. Girls finishing the eighth grade may continue in the boys school. Three girls were doing so. The girls school had twelve teachers, of whom one was American. Fees ranged from £S36 to £S180 a year. Boarding fees were £S500. There were 24 boarders in the boys school, but none in the girls school.

The program is a modified American program of the college-preparatory type. English is begun in the fourth grade, and French in the third grade. All teaching is in Arabic in the first six grades and is changed to English at the beginning of the seventh grade. General and European history is taught. The schools have always prepared students for the government primary-school certificate examination. At one time they also prepared for the *brevet,* but this has been discontinued. The two schools aim to prepare students for Aleppo College and the American University of Beirut. The latter accepts their students upon examination. The schools have no laboratory. The boys school has a small library. A chapel service is held once a week. The student body is drawn from many of the religions and sects in Syria. Greek Orthodox students were the largest group (139), followed by Protestants (54), Muslims, Alawites, Maronites, Greek Catholics, Druzes, and Isma'iliyas.

The American High School for Girls in Aleppo is the combination of a Congregational Mission school at Marash, Turkey, before the First World War, and another Presbyterian school at Aleppo. Its educational policies

are controlled by the educational committee of the Syrian Mission with headquarters in Beirut. The School has a kindergarten and classes from the first to the eleventh grade, with an elementary school of six years and a high school of five years. The total registration is 501 pupils. Boys are accepted in the kindergarten and the first two grades. A class in special English, which in 1945–46 enrolled 53 pupils, prepares students coming from other schools with little or no knowledge of English to be fitted into the proper grade. This is a provision found in many of the larger American schools in Syria and Lebanon. The School has twenty-eight teachers, of whom four are American. There are eight boarding students. Fees range from £S60 to £S200 a year. The student body stems from twelve denominations, the largest number of students being Muslim (174), followed by Armenian Orthodox (122), Greek Orthodox (52), Armenian Protestants, Greek Orthodox Protestants, Jews, Syrian Orthodox, Greek Catholic, Roman Catholic, Syrian Catholic, Armenian Catholic, and Maronites.

The language of teaching is Arabic in the elementary school and English in the high school. English is informally taught in the first grade, but regular teaching of it begins in the third grade. French is now begun in the fifth grade. Graduates of the School may go to the American Junior College for Women in Beirut and thence to the American University of Beirut. Some go into teaching.

The highest American institution in Syria at the present time is Aleppo College, situated in Aleppo, the largest urban center of Syria. Founded as Central Turkey College at 'Ayntab (Gaziantep), Turkey, in 1876, its work was cut short by the First World War. It was transferred to Aleppo and reopened as a high school in 1924. Another American high school, known as the North Syria High School for Boys, was established in 1927. These two institutions were combined as Aleppo College in 1937, occupying their two new buildings on the present site on the outskirts of Aleppo in 1940–41. Aleppo College consists of an elementary school, a secondary school, and a junior college.

The elementary school consists of four grades, from the third through the sixth. By an agreement with the American High School for Girls, boys are admitted to the kindergarten and the first two grades of that school, after which they are transferred to the boys school. The latter is not on the College campus, but is situated in the city. Teaching is conducted in Arabic.

The high school for boys consists of five grades (seven through eleven), each in two or three sections, and a special class designed to help students with a meager knowledge of English to fit themselves into the regular

school and college classes. Only students with such intentions are admitted to it. These classes combined had an enrollment of 479 students, of whom 135 were in the special class. Instruction is entirely in English, except for the classes in the three languages of Arabic, French, and Armenian. The textbooks, except for those used in language instruction, are usually American. The Michael West series[4] of readers for foreign students with its accompanying simplified classics is used in the lower secondary classes. The program of studies is shown in Table 70.

TABLE 70

PROGRAM OF STUDIES, HIGH-SCHOOL SECTION, ALEPPO COLLEGE, SYRIA, 1945–46

Subject	Periods per Week				
	7th Year	8th Year	9th Year	10th Year	11th Year
English	5	5	4	4	3
Arabic	5	5	5	5	5
Arabic for Armenians	(5)*	(5)*	(5)*	(5)*	(5)*
Armenian	3	3	3	3	2
French	4	4	3	3	3
Algebra	...	...	4	...	4
Geometry	...	...	...	4	...
Arithmetic	4	4	...	...	...
Physics	...	...	...	...	6
Biology	...	...	...	4	...
Science	2	2	4	...	...
Geography	3	3	...	...	1
History	...	...	3	4	4
Bible	2	2	2	2	2
Home room	1	1	1	1	1
Athletics	2	2	2	2	2
Study period	8	6	6	5	6
Music	...	2	2	2	...
Total	39	39	39	39	39

* Omitted from totals.

It will be noticed that the program is quite heavily loaded with languages. Armenian is, however, compulsory only for Armenians. For the rest the course is of the college-preparatory type, but with an emphasis upon the teaching of the Bible, which is compulsory for all students whatever their religion or denomination. Special provision is made for the teaching of Arabic to Armenians, using classes in colloquial conversation and readers and books of a considerably lower grade than those used for Arabic-speaking students.

The junior college has 35 students in the freshman year and 27 in the sophomore year, all men. Teaching is in English. The course for freshmen

[4] A carefully graded series of readers, language books, and simplified supplementary readers written by the British educator Michael West and published by Longmans, Green & Co.

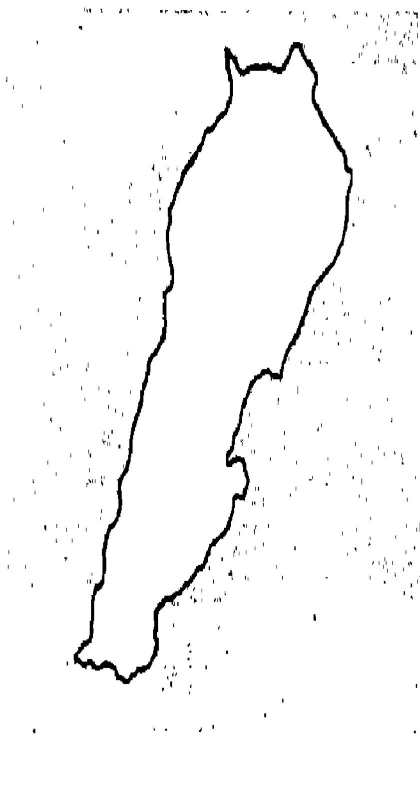
is the same for all students and consists of the study of English, Arabic, and Armenian (for Armenians), literature, a course in introductory college mathematics using an American text, a course in the history of the Arabs, and a course in religion.

The sophomore year is divided into three sections: arts, science, and engineering. All take philosophy and literature. The arts section takes, in addition, economics, political science, history (modern Europe), and religion. The science section takes mathematics (calculus), physics, and biology, the latter two with extensive laboratory work. The engineering section takes descriptive and solid geometry, calculus, physics, and drawing. The total number of hours are eighteen for the arts, twenty-three for science, and twenty-five for engineering.

The College occupies two fine buildings, one of which is for administration and instruction and the other for boarders. The campus, only recently established, affords a view of the city of Aleppo from the edge of the plateau on which the College is situated. Tuition fees, including health and laboratory fees, range from £S85 ($38.53) to £S455 ($206.82). The boarding fee is £S700 ($318.18). The College is considered to have the best science laboratories of any school in Syria. It has a library of 8,000 volumes which is extensively used by the students and friends of the College.

The College encourages athletics and extracurricular activities. It has its own teams for football, basketball, and volleyball, and fosters tennis and swimming. A Scout troop has existed for some time. A choir and a small orchestra provide mediums for the development of student talent in music and singing. Many student clubs function on the campus—a fine-arts club, international-relations club, and a Christian Endeavor Society. Literary evenings are held. A campus paper, the *College Herald,* and two class papers are issued in English. A literary review is printed once a year in Arabic, English, and Armenian.

Part Six



LEBANON

LEBANON

Population: *1,200,000 at the end of 1946 (estimate).*

Area: *10,170 square kilometers (3,926 square miles).*

Form of government: *Republic. President is elected for six years by the Chamber of Deputies (unicameral). Members of Chamber of Deputies are elected by universal male suffrage. The Prime Minister, selected by the President, nominates members of his Council of Ministers (cabinet) which are appointed by the President but are responsible to the Chamber of Deputies.*

Principal occupations: *Trade, agriculture, professions, industry.*

Principal exports: *Olive oil, oranges and other fruits, silk, textiles, wool and hides.*

Principal imports: *Manufactured wares, mineral and chemical products, fuels, foodstuffs (wheat, meats, vegetables, rice, sugar, spices), cotton goods, woolen textiles.*

Monetary unit: *Syro-Lebanese pound (£L) equivalent to $0.4576.*

Chapter 24

ORGANIZATION AND ADMINISTRATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM

TWO UNIQUE features of education in Lebanon distinguish it from education in the rest of the Arab world. Lebanon has the highest rate of literacy among the Arab states. It is estimated that between 70 and 75 percent of the children of primary-school age are attending school—a considerably higher rate than in the neighboring countries. This rate would have been higher had it not been for the addition to Lebanon after World War I of some regions which were much less advanced educationally than the original Mount Lebanon. Many village communities in Lebanon have what amounts to or approximates universal literacy.

The second remarkable fact is that this comparatively advanced stage has been accomplished largely through the efforts of private and foreign schools rather than through publicly supported schools. Indeed, before World War I, autonomous Lebanon had only one public school, the Daudiyah at 'Abay, which was supported by the Lebanese government for the education of the children of that predominantly Druze region.[1] The private and foreign schools were largely sectarian. This gave education in Lebanon a predominantly sectarian character, emphasizing sectarian differences, the remnants and effects of which are felt to this day.

Even in 1945–46 the number of pupils enrolled in the public schools was smaller than the number of those enrolled in either private schools or foreign schools. Higher education is conducted entirely in foreign institutions. Secondary education is shared between private and foreign schools, the Lebanese Ministry of National Education having no complete secondary schools. Primary education is conducted in all three types of schools—public, private, and foreign—with the public schools in the third place in enrollments. In addition to primary schools, the Ministry of Na-

[1] Government schools existed in those parts of the present Lebanese Republic which were parts of the neighboring Ottoman provinces. Among these were the cities of Beirut (now the capital of Lebanon), Tripoli, Sidon, and Tyre, as well as such districts as 'Akkar, Buqa', and Marju'yun.

tional Education conducts a few schools with complementary classes, two normal schools (one for men and one for women), a School of Arts and Crafts including a course in agriculture, and a conservatory of music.

The Lebanese public educational system, therefore, is by itself incomplete. Only by relating it to the systems of private and foreign schools—which roughly fall into two types, the French and the American-British—does it become a complete, though diversified, system. The description of education in Lebanon will have to follow a somewhat different pattern than the one used for the other school systems. A description of the organization, administration, and finance of public education will be followed by a description of the public primary and special schools and the public examinations. Next, there will be a description of the French, American, and British schools, which set the pattern for most if not all private schools, and the account will end with a consideration of the various types of private schools.

The Administration of Public Education

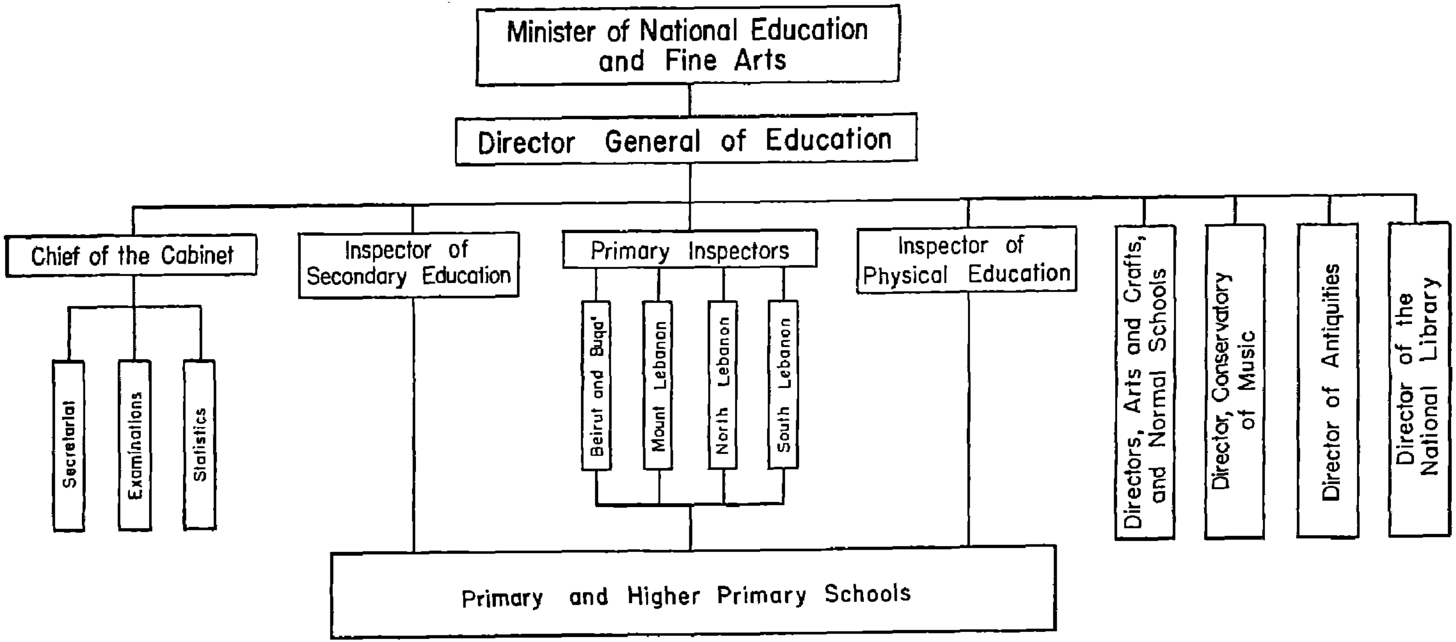
The administration of public education in Lebanon is centralized and is entrusted to the Ministry of National Education and Fine Arts. This is sketched in Chart XIII. The head of the Ministry is a member of the Council of Ministers and is responsible to the Lebanese Parliament. For the last few years the Minister of National Education has also occupied another ministerial chair, usually that of foreign affairs. He has, therefore, been able to give only part of his time to the Ministry of National Education.

Under the Minister is the Director General of Education, who is the permanent executive. At the time of the visit of the Commission of the American Council on Education, the Director General was also occupying an administrative position in the executive department of the Republic, and was giving only part of his time to his functions at the Ministry of Education.

The burden of the work of the Ministry of National Education, therefore, fell on the shoulders of the Chief of the Cabinet of the Ministry of Education who seemed in effect to be doing the main work of the Director General. During several visits by the Commission to the office of the Ministry in an effort to secure material for the present study, it found him in the process of supervising the preparation, administration, and correction of the public examinations, and working on the new decree concerning private schools and the passage of the decrees embodying the new

Chart XIII

LEBANON: ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND FINE ARTS, 1946



programs of study. His office was usually full of inspectors, heads of schools and other establishments of the Ministry, and of teachers and others who were trying to transact business with him in his official capacity.

The Chief of the Cabinet's office consists of three sections: (1) the Secretariat, which includes clerks and typists, one of whom acts as an accountant, while another has charge of the files and archives of the Ministry; (2) the Examinations Section, with two clerks, one of whom has charge of the stores; (3) the Statistical Section, with two clerks in charge.

Such is the constitution of the purely administrative side of the comparatively small central office of the Ministry in Beirut. The regional administration is in the hands of the four primary inspectors who have charge of the four regions into which Lebanon is divided for purposes of educational administration. These are: North Lebanon with Tripoli as a center; Mount Lebanon, which is the central portion of Lebanon facing the sea, with Ba'abdah, the old capital, as a center; Beirut and Buqa', which includes those sections of the country lying on the east side of the mountain range, with a center at Mu'allaqah Zahlah; and South Lebanon, which includes the southern provinces on both sides of the range, with a center in Sidon. Each region is headed by a chief, who, in addition to his duty of inspecting public and private schools, is in charge of all the administrative work. These regional offices are small, with the result that the administrative work of the inspector tends to reduce his inspectorial or supervisory work to a minimum.

Two other inspectors have their headquarters at the Ministry of National Education—the Inspector of Secondary Education and the Inspector of Physical Education. Since there are only a few incomplete public secondary schools, which in reality are upper primary schools (*écoles primaires supérieures*), the work of the Inspector of Secondary Education is primarily the inspection of private and foreign secondary schools. As in the days of the French mandate, when the foreign schools enjoyed a privileged position and were inspected by officials from the High Commissioner's Department of Education, the duties of an Inspector of Secondary Education have not been heavy. However, with the adoption of the new decree concerning private and foreign schools emphasizing the right of supervision by the Ministry of Education, the duties of the Inspector of Secondary Education are likely to grow. As his title implies, the duties of the Inspector of Physical Education are to supervise and encourage physical education and games, Scout activities, and various forms of sport inside and outside the schools.

Four schools, situated in Beirut, are directly connected with the Ministry. These are the School of Arts and Crafts which includes a section on agriculture, the Normal School for Men, the Normal School for Women, and the National Conservatory of Music. The Directorate of Antiquities and the Directorate of the National Library complete the list of the institutions directly connected with the Ministry of National Education.

Educational Finance

The support of public education comes almost entirely from the central budget of the government. Table 71 shows the growth of the educational budget in selected years of the last quarter of a century. This budget, which includes that of the Directorate of Antiquities, has ranged between 5.6 to 8.4 percent of the total budget of the state. The influence of wartime inflation can be seen from the almost sevenfold jump in the educational budget between 1941 and 1945, while in the corresponding period the number of schools increased from 267 to 308 and the enrollment from 21,056 to 30,113.

It was not possible to obtain the salary scale for public-school teachers. A scale set down by a government decree to serve for private and foreign schools fixes salaries at figures probably not very different from those paid in the public schools. The system of classifying teachers as instructors, assistant instructors, and teachers is almost identical with the public-school system. Instructors must be holders of university degrees, assistant instructors must have the *baccalauréat* or the Lebanese teaching certificate, and teachers must hold the Lebanese *brevet* or its equivalent. Monthly salaries for instructors range from £L75 to £L135 ($34 to $61), for assistant instructors from £L45 to £L85 ($20 to $39), and for teachers from £L35 to £L55 ($16 to $25). Salaries are paid for twelve months.

During World War II, cost-of-living allowances were added for government officials and teachers. These ranged from 250 percent for salaries that were £L40 a month or less, to 45 percent for the highest salaries paid by the state. In addition, married teachers received £L14 each for the wife and first child, and £L10 for each additional child up to five children.

A pension plan for government officials allows half the average salary for the last three years after thirty years of service. A person who has been in government service for thirty years and who has attained the age of fifty-five may ask to be retired or may be sent to retirement by the government after due investigation by a committee. Sixty-five is the latest age for retirement, though under special circumstances a person may be allowed to serve on a yearly basis up to the age of seventy.

TABLE 71

GROWTH OF THE EDUCATION BUDGET, LEBANON, 1921–45*

ALLOCATED TO	1921	1932	1939	1941	1945	1946 Budget	1946 Percent of Total Educational Budget
				Education Budget			
Administration	£L 14,559	£L 19,510	£L 20,924	£L 14,180	£L 111,060	£L 150,433	3.2
Primary education	*164,721*	*218,923*	304,019	335,761	2,215,820	3,018,319	64.6
Technical education	...	...	74,399	83,027	325,336	*309,741*	6.6
Agricultural education	...	...	...	...	40,305	33,955	0.7
Fine arts education	...	3,750	4,327	5,315	25,204	25,204	0.5
Teacher education	...	...	...	...	...	121,556	2.6
Antiquities	...	17,716	84,373	55,439	439,901	479,133	10.2
National library	...	8,447	9,180	11,199	49,292	58,000	1.3
Grants and awards	...	20,500	42,000	44,925	324,200	475,100	10.2
Total education budget	£L 179,280	£L 288,846	£L 539,222	£L 549,946	£L 3,531,118	£L 4,671,441	99.9
				State Budget			
Total state budget	£L2,438,000	£L5,109,000	£L6,369,000	£L6,635,000	£L43,314,500	£L60,046,000	
Percent allotted to education from state budget	*7.3*	*5.6*	*8.4*	*8.3*	*8.1*	*7.7*	

* In Lebanese pounds (£L); one pound equals $0.45.

Educational Legislation

Article 10 of the Lebanese Constitution of May 23, 1926, guarantees freedom of teaching provided it does not transgress upon public order or morals and is not disrespectful of any religion or sect. It also guarantees the rights of the religious denominations to establish their own schools provided they are established in conformity with the regulations laid down by the state. This is the only article in the constitution dealing with education. Decrees regulating both public and private education are issued, as the need arises, by the President of the Republic acting upon the decision of the Council of Ministers. The main provisions of three of these decrees which were made available to the Commission of the American Council by the Ministry of Education will be summarized here. A fourth decree set up the administrative organization of the Ministry of Education, as already stated. The decrees establishing the new courses of study and the procedures governing examinations will be given in chapter xxv.

Legislative Decree No. 295, dated December 17, 1942, prescribes the conditions for the selection of the teaching staff of the Ministry of National Education and Fine Arts. This staff is divided into two parts: the staff for primary education and the staff for secondary and technical, or vocational, education. Primary-education staff members are classified upward as practicing teacher, teacher, assistant instructor, and inspector. The personnel of secondary and vocational education are classified as instructors and inspectors.

To be appointed a practicing teacher, a candidate must hold the *Baccalauréat,* Part II, or the *brevet.* Before he may be appointed to the grade of teacher, he must have passed through a probationary period of two years, or if he holds the Lebanese teaching diploma,[2] he may be appointed a full teacher after only one year of probation. The regular requirement for promotion to the sixth grade of teaching, which is the beginning grade for a full teacher, is that the candidate must have passed the two parts of the examination for the Lebanese teaching diploma.

To be appointed an assistant instructor, a candidate must be the principal of one of the higher primary schools, or hold the teaching diploma and have had five years of teaching in complementary classes, or have taught eight years in the classification of practicing teacher.

A secondary- or vocational-school instructor must hold a *Licence* in

[2] This is given either to students of the normal schools or to practicing or probationary teachers who have passed the two parts of the diploma examinations. The first part is the same as the examination for the first-year studies of the normal school, and the second part is the same as that for the second year.

Letters, Science, or Teaching, or an engineering diploma. He must spend one year on probation.

A primary-school inspector is chosen either from secondary-school instructors who have spent at least five years in service, or from assistant instructors of primary schools who have served for at least ten years.

Finally, secondary- and vocational-school inspectors are chosen from among the professors of higher institutions, or from secondary- or vocational-school instructors who have spent not less than ten years in service, or from primary inspectors who have spent not less than ten years in service and who have taken a higher degree.

Legislative Decree No. 212, of August 31, 1942, fixes the conditions of employment of private-school teachers. As already indicated, it classifies the teaching staff as instructors, assistant instructors, and teachers, and fixes the grades and salaries of each. Further, it specifies the principles of appointment, promotion, discipline, leaves of absence, and compensation upon dismissal. It fixes the teaching load for primary-school teachers at no less than thirty hours a week, for teachers of the upper primary or equivalent secondary classes at no less than twenty-four hours a week, and for upper secondary classes (*deuxième, première, philosophie et mathématique*) at no less than eighteen hours. It also specifies the cost-of-living allowances for teachers in private schools. These changed progressively with the rise of prices during the war.

Perhaps the most important educational legislation in Lebanon of recent years is Decree No. 7,000, of October 1, 1946, issued only a few days before the last member of the American Council Commission left Lebanon. It is concerned with the opening, running, and supervision of private schools and is based on a previous similar decree (No. 7,962, of May 1, 1931), though with a number of significant new features.

This decree defines a private school as any educational institution founded or administered by an individual, a society, or a mission. To open a school, an official permit must be secured in the form of a decree which is issued upon the recommendation of the Minister of National Education and Fine Arts. Only persons who have attained the age of eighteen and who hold an official school certificate may teach in a private school at any level. Only persons who hold at least the *Brevet Primaire Supérieur* or its equivalent may direct a primary school; and only those who hold at least a complete *baccalauréat* or a higher degree may direct a secondary school. These heads of schools must be at least twenty-one years of age.

An individual or a recognized association wishing to open a school must submit the name of the proposed principal, his qualifications, his

certificate of good behavior, and the places of his residence during the last five years, as well as a plan of the building to be used, a certificate from the county doctor as to its sanitary arrangements, and another certificate from an architect (or master-mason in outlying villages) as to the soundness of the building. The principal must give an affidavit stating that the school will follow the official course of study. Before granting the permit, the Minister considers whether there is a need for the school. Any changes in the plan of organization of the school require repetition of all the processes indicated above. A school which does not open within two years of the date of issue of its permit has its permit withdrawn. Any school whose proprietor has no permit is closed.

Coeducation is permitted up to the age of eleven. Although the private and foreign schools are required to follow the official courses of study, the principals have a choice of methods of teaching. Only textbooks approved by the Minister of Education may be used in the teaching of history, geography, and moral, civic, and patriotic subjects, and any private school that uses a textbook banned by the Ministry is subject to the penalty of being closed.

Private schools, whether native or foreign, are subject to supervision by the Ministry of National Education. At the end of November of each year private-school principals must submit a register of the school staff and their qualifications, a detailed report on the condition of the school, and the number of pupils and the denominations to which they belong. Schools already having permits at the time of the issuance of the decree of October 1946 were required to register them before April 1947, after which date an unregistered school was subject to being closed.

The Educational Ladder

Schools in Lebanon, as already intimated, belong mainly to one of two types of educational organization: a French or an American type. The French type prevails in the government schools, in the large majority of foreign schools, and in some of the private schools—all culminating in the French Jesuit university known as the Université Saint-Joseph. The American type is found in the next largest group of foreign schools, the schools of the Protestant Synod, and in some of the private schools. These culminate in the American University of Beirut, the oldest existing institution of higher education in Lebanon (founded in 1866). A third type of organization comprising a small number of schools may be called the "British" type and is exemplified by the British-Syrian Training Col-

lege for girls and the elementary schools for boys and girls attached to it.[3]

Which one of the types a particular pupil is likely to choose depends to a large extent upon his community background—more specifically his religious community background. A Catholic parent is likely to place his child in a Catholic foreign or native private school, which means that he receives the French brand of education. Greek or other Orthodox children, when they do not go to their own schools, are as likely to pick a French type as American or British types of school. When picking a French type, they usually prefer a lay-mission (Mission Laïque) school where they are not subjected to the intense religious teaching of the Catholic-mission schools. Most Protestant children go to Protestant schools which, with one notable exception (Le Collège Protestant Français) are of the American or British types. A Muslim parent usually would prefer to send his child to a Muslim school, which may be following plans of any of the types. The poorer Muslims often send their children to the government schools, which follow the French type of organization, or to the French lay-mission schools, or to the American or British types of school. The deciding factor is the absence or minimum of proselytization. Druzes, when they do not send their children to their own schools, usually send them to government schools, but they may choose American or British schools; the latter have had long-standing relations with the Druze community. Druzes also send their children to French schools and to some of the Muslim and Christian denominational schools. Thus, the choices of schools are to a large extent determined by sectarian considerations. This situation is a perpetuation of the status prevailing in the days of the Ottoman Empire, which was accentuated even further in the days of the French mandate. It is not likely to change appreciably until the government assumes greater responsibility for public education than it has hitherto.

Chart XIV attempts to depict the various educational systems in vogue in Lebanon. In general, two systems—the American and the French—go their own ways, using their own curriculums, their own methods, and, indeed, are guided by two distinct philosophies.[4] About the only link between the two types is the establishment by the American University of Beirut of a *Section Secondaire,* in which an adaptation of the French secondary program is followed and where the teaching is in French. Those who finish this program present themselves for the French or Lebanese

[3] There are, in addition, 1 Danish, 1 Swiss, and 1 Greek school. The American Council Commission was unable to visit any of these schools and, therefore, is not in a position to describe the type of organization they follow.

[4] For a description of French schools, see chap. xxvi; for American and British schools, chap. xxvii.

baccalauréat examinations (Parts I and II) and then become, as are other holders of the French or Lebanese *baccalauréat,* eligible for admission to the junior year of the School of Arts and Sciences of the University. The French and Lebanese authorities recognize the B.A. degree of the American University as only equivalent to the complete *baccalauréat.* As a rule the French schools give English as their second language. American and British schools give French as their second language: until recently they even started teaching French earlier than they did English.

PUBLIC SCHOOLS

In constructing Chart XIV, the new government course of study, which was announced in October 1946, was used. Until the new course is gradually put into operation in the next few years, however, the former course will still prevail in the public schools. This consists of a six-year primary school and a three-year higher primary school. The primary school is divided into three courses of two years each—the preparatory, elementary, and middle courses—and leads to the primary-studies certificate examination. If successful, a pupil may enter the higher course *(cours supérieur)* of one year, followed by the complementary course *(cours complémentaire)* of two years. This ends in the *brevet* examination. As the government maintains no complete secondary schools, a pupil who wishes to finish his secondary education has to transfer to a French-type secondary school, where he spends six to seven years, depending upon the class to which he is admitted. Though having no secondary schools, the Ministry of Education set a secondary course of study modeled after the French, but with the addition of Arabic, local history and geography, and Arabic philosophy. This course serves as the basis for the Lebanese *baccalauréat* examinations, Parts I and II. The course is uniform for all students until the ninth grade (called *classe de troisième*). It then divides into two sections—scientific and literary—for the two classes which follow, tenth and eleventh grades, after which the first *baccalauréat* examination takes place. In the final secondary year the students may enter either of two sections—the *classe de philosophie* or the *classe de mathématique*—and finally present themselves for the second part of the *baccalauréat* examination. The course also provides for a classical section starting with the *sixième* (sixth grade) in which an oriental or Western classical language is required.

The new course of study provides for a kindergarten of two years to which children may be admitted at as early an age as three, followed by a primary school of five, instead of six, years ending in the primary-studies certificate examination. Having passed that examination, a pupil may

proceed either to the seven-year secondary school or the four-year higher primary school, or to the School of Arts and Crafts, which gives a course of four years. The program of the first two years of the higher primary school has been made identical with that of the first two years of the secondary school in order to facilitate transfer from one school to the other. Those students who pass the *brevet* examinations may enter one of two other government schools or courses. These are the agricultural course, which is now under the same administration as the School of Arts and Crafts, and the normal school for men or that for women. Entrance is by competitive examination. Students who have passed the first *baccalauréat* examination may also apply for admission to the agricultural course, while those who have passed the first or first and second *baccalauréat* examinations may apply for admission to the normal schools. These more advanced students are allowed 10 or 20 marks for their certificates, thus giving them an advantage in the total score which forms the basis of admission.

Education in the public schools is entirely free, the pupils providing their own books. Students in the School of Arts and Crafts, the agricultural course, and the normal schools may be boarding students at the expense of the government.

French schools

The organization of the French schools in Lebanon is not very different from that of the public schools because the latter schools have been modeled after them. The French schools constitute a complete system from kindergarten to university. As a rule, a French institution has both the primary and secondary schools as one continuous school on the same premises.

The kindergarten class for three- and four-year-olds leads to a prefirst grade (called twelfth class—*douzième*), where some very rudimentary elements of reading and arithmetic are taught. The real first grade, however, is the eleventh class (*onzième*). The primary school extends from the eleventh through the seventh class, and is divided into a preparatory course of one year, an elementary course of two years, and a middle course (*cours moyen*) of two years. If the pupil remains in the same school to continue his secondary education, he need not take the primary-certificate examination. If he decides to take this examination, he usually has a choice of the French examination, formerly given by the Haut Commissariat and now by the Œuvres Françaises, or of the Lebanese examinations already mentioned. He may take these examinations after his seventh class or a year later, after the sixth class. If he passes these examinations, he may continue his education in the same school (the customary procedure)

or transfer to some other French or Lebanese school, or even to an American- or British-type school.

The secondary course which follows is of seven years, and prepares for the first and second *baccalauréats,* both French and Lebanese, and also for the *brevet* examination, both French and Lebanese. Some schools also prepared for the Syrian *baccalauréat* up to a very recent date.

After graduating from the secondary school and becoming a *bachelier,* the student has several choices for continuing his education. He may enter one of the two higher institutions in Lebanon—the French Jesuit Université Saint-Joseph or the American University of Beirut, or he may go abroad, especially to France, where both the Lebanese and French *baccalauréats* are recognized for admission to higher institutions. Comparatively few graduates of French secondary schools transfer to the American University.

The usual course for the graduate of a French or French-type secondary school is to enter the Université Saint-Joseph. Here he may pursue studies leading to the degree of *Licence ès Sciences* (though the University itself does not grant that degree), or he may enter one of the professional schools—the Faculty of Theology, Institute of Oriental Letters, Law School, Engineering School, or Faculty of Medicine with its divisions of pharmacy, dentistry, nursing, and midwifery. The requirements and courses are described on pages 473–78.

AMERICAN SCHOOLS

The American-type schools also constitute a complete ladder from kindergarten to university. The term is applied to the system of American nonsectarian and mission schools, together with the native private schools which follow the American pattern. At the top of the ladder is the American University of Beirut.

The ladder starts with a kindergarten of one year, which exists mainly in the girls schools. This is followed by an elementary school of six years, which may be for boys alone, or girls alone, or coeducational. Sometimes the lower classes are coeducational, the children separating after the second or third grade. The elementary school is followed by a five-year high, or preparatory, school which follows a uniform program throughout. The combined normal duration of the elementary and high school is eleven years, instead of the twelve of the French ladder. Some of the schools, however, have twelve grades, with the better students skipping directly from the sixth to the eighth grade, while the slower ones stay in the school for the entire twelve years.

A girl graduate of an American-type high school who wishes to con-

tinue her education may enter the American Junior College for Women situated in Beirut. Though included for convenience in Chart XIV under the American University of Beirut, it is an independent institution with a separate board of trustees. It offers a two-year course, which, if of an approved sequence, is accepted for admission to the junior year of the School of Arts and Sciences of the University. A woman student may enter the School of Nursing of the University, where, after a three-year course she receives the Nurses' diploma. An additional year of study leads to the diploma of midwifery. A graduate of the School of Nursing who is also a graduate of the American Junior College for Women may receive the B.A. degree by studying for one more year in the School of Arts and Sciences.

A male graduate from high school may enter the intermediate section (freshman and sophomore classes) of the School of Arts and Sciences. Here he may continue his college studies in the academic subjects, or take up farm management, pursue a business course, or, after the freshman year, enter the School of Pharmacy.

After finishing the intermediate section, the student may enter the junior year of the University where he is joined by the graduates of the American Junior College for Women and by the higher-ranking graduates of the *Section Secondaire* (the French-type secondary school established by the American University) or other holders of the French or Lebanese *baccalauréat*. Here he may take courses in the arts, the sciences, commerce, or engineering, or pursue an honors course. If he intends to study medicine, he enters the School of Medicine after his junior year.

The University Institute of Music has no specific requirement for admission beyond a practical examination to determine the class into which the student fits. The course is of seven years' duration, including a preparatory year for beginners. It is described further on pages 496–97.

British schools

British schools are comparatively few in number. They are described on pages 499–501.

The ladder consists of two years of kindergarten followed by a course of ten years covering the elementary-, middle-, and high-school standards (grades). The high-school certificate is recognized for entrance into the American Junior College for Women and to the School of Nursing of the American University of Beirut.

Such is the present situation with regard to the educational ladder of Lebanon—if ladder it can be called. It is a situation where two, or per-

haps three, educational outlooks and philosophies emanating from abroad dominate the scene. Native schools, whether public or private, follow one or the other of these educational ideologies and systems. Owing to the policies followed by the French mandate between the two World Wars, the French type of school and curriculum is by far the most prevalent. nevertheless, the American type enjoys a certain vogue, largely owing, perhaps, to the prestige of the American University of Beirut, for which many a private school prepares its students.

The Growth of Education

The former autonomous province of Mount Lebanon had only one public school and relied on private and foreign schools to educate its children. The other parts of the present Lebanese Republic, which were parts of the vilayets of Beirut and Damascus and subject to the direct rule of the Ottoman government emanating from Istanbul, had public schools maintained by the Ottoman government through its departments of education in the provinces. These schools formed the nucleus of the new Lebanese public-school system when the former Ottoman cities and districts were added to Lebanon after 1920.

It was not possible to secure statistics of schools and attendance in Lebanon in the same detail as for the other Arab countries. All that could be secured from the Lebanese Ministry of Education was the total number of schools, teachers, and pupils for 1944-45 in the public, private, and foreign schools, together with the distribution of the pupils in the public schools according to sect. For the rest the American Council Commission had to glean whatever data it could find in the statistical annual for 1942–43, which was issued by the Council of General Interests for Syria and Lebanon, in the *Bulletin de l'Enseignement,* a periodical previously published by the Education Department of the Haut Commissariat, and the annual reports of the French Republic to the League of Nations on the situation in Syria and Lebanon. Even these, however, gave no figures as to the distribution of teachers and pupils by grades, or the number of complete and incomplete schools, and other useful figures which would permit a more intimate study of an educational system. Both the government and the Haut Commissariat's figures emphasize the sectarian distribution of schools and their pupils.

Table 72 shows the growth of education in Lebanon between 1924 and 1945 in public, private, and foreign schools.

It is evident from Table 72 that the public schools are in the minority. In 1944–45, there were only 308 public schools, in which 30,113 pupils

TABLE 72

NUMBER OF SCHOOLS AND PUPILS CLASSIFIED ACCORDING TO CONTROL, LEBANON, 1924–46

Year	Public Schools		Private Schools		Foreign Schools		Total	
	No.	Enrollment	No.	Enrollment	No.	Enrollment	No.	Enrollment
1924....	117	8,064	762*	52,705*	98†	6,614†	977	67,383
1930....	129	13,632	767	49,197	410	36,153	1,306	98,982
1941–42.	267	21,056	986	73,608	326	43,654	1,579	138,318
1944–45.	308	30,113	963	71,524	326	43,065	1,596	144,702
1945–46.	451	40,926	...	...	...	...	...	...

* Including French schools.
† Not including French schools. In later years French schools were included among the foreign schools.

were enrolled. This represents 19.3 percent of the total of 1,596 schools, and 20.9 percent of the total of 144,702 pupils. In sharp contrast, there were 963 private schools, enrolling 71,524 pupils, a percentage of 60.3 and 49.4 respectively. In other words, more than one-half of the schools were private schools, accommodating one-half of the school population of Lebanon. Foreign schools numbered 326 (20.4 percent) and enrolled 43,065 pupils (29.7 percent).

It is to be noticed, however, that the public schools have been increasing at a more rapid pace than the other schools owing to the vigorous policy followed by the Ministry of Education in opening new schools. In 1945–46 the number of schools reached 451 and of pupils 40,926, an increase of 143 schools and 10,813 pupils in a single year. This brought the number of public schools to approximately 4 times what they were in 1924, and the number of pupils to about 5 times. During the same period private and foreign schools reached 1.5 times their former number (860 to 1,289) while the number of pupils approximately doubled (59,319 to 114,589). It is to be noted that private and foreign schools have been at a standstill in the last few years. This may be due to the difficulties of the war period. It may, however, be possible that they have reached a saturation point; and with the end of the French mandate, which encouraged foreign schools (especially the French), and with a more vigorous educational policy by the Lebanese government, the next few years may witness a spurt in public education and a comparative lull in the numerical expansion of private and foreign schools.

The distribution of pupils according to sex is available only for public and foreign schools. No comparable figures of recent date have been found for private schools. The figures are as follows:

	Public Schools			Foreign Schools		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
1942–43	17,051	5,803	22,854	22,316	24,410	46,726
1945–46	30,361	9,965	40,326	...	...	...

In the public schools one out of every four pupils is a girl. In the foreign schools, including the large number of girls schools maintained by orders of nuns, the number of girls is greater than that of boys. The ratio of girls to boys in the private schools probably stands somewhere in between these two extremes.

In 1944–45 there was a total of 5,092 teachers in all types of schools in Lebanon. Of these, 887 were in public schools, teaching an average of 34 pupils each; 2,167 were in private schools, teaching an average of 33 pupils each; and 2,037 were in foreign schools, teaching an average of only 21 pupils each. The average number of pupils per teacher was markedly lower in the foreign schools partly because of the presence of higher institutions among them, and partly because many of them were run by orders of friars and nuns who received no salaries and cost only their maintenance. Such schools, therefore, could afford greater numbers of teachers.

Table 73 shows the distribution of schools and pupils according to types of schools in 1941–42, the latest year for which such figures could be obtained.

TABLE 73

Distribution of Schools and Pupils by Type of School, Lebanon, 1941–42

Type of School	Public Schools		Private Schools		Foreign Schools		Total	
	Schools and Units	Enrollment	Schools and Units	Enrollment	Schools and Units	Enrollment	Schools and Units	Enrollment
Primary and complementary	266	20,761	1,164	69,422	435	35,671	1,865	125,854
Normal and secondary	3	295	37	4,186	48	6,295	88	10,776
Higher institutions	...	...	...	...	25	1,688	25	1,688
Total	269	21,056	1,201	73,608	508	43,654	1,978	138,318

Public and private Lebanese schools were of the primary and secondary types. No public or private higher institutions existed. All public schools, except 3, were primary and complementary. The 3 exceptions were the 2 normal schools (1 for men and 1 for women) and the School of Arts and Crafts, all at Beirut. There were 37 private secondary schools, having an enrollment of 4,186 pupils; and 1,164 private primary units, enrolling 69,422 pupils. Among the foreign schools, there were 435 primary sections, enrolling 35,671 pupils; 48 secondary sections, enrolling 6,295 pupils; and 25 units of higher education (the American and French universities and their component schools and departments), enrolling 1,688

students. There were more foreign secondary schools than public and private secondary schools combined, with three-fifths of the total secondary-school enrollment.

The distribution of foreign schools according to nationality, and the number of boys and girls enrolled in them in 1942-43 (the latest figures available), are shown in Table 74.

TABLE 74

DISTRIBUTION AND SIZE OF FOREIGN SCHOOLS BY NATIONALITY, LEBANON, 1942–43

NATIONALITY	NO. OF SCHOOLS	ENROLLMENT		
		Boys	Girls	Total
French..........	273	17,789	21,724	39,513
American........	36	3,462	1,581	5,043
British..........	14	847	946	1,793
Danish..........	1	18	110	128
Greek...........	1	170	...	170
Swiss...........	1	30	49	79
Total.......	326	22,361	24,410	46,726

The largest group of foreign schools was the French, constituting 83 percent of all foreign schools and enrolling 84 percent of the total foreign-school enrollment. Far behind them trail the American schools, which constitute 11 percent of all foreign schools and educate about the same proportion of pupils. They are followed by the British schools, which constitute 4 percent of the total of foreign schools with the same percentage of the total enrollment. Denmark, Greece, and Switzerland are each represented by one school.

Finally, owing to the great stress laid in Lebanon on the sectarian distribution of school children and of the population in general, it seemed worth while to study the sectarian composition of the school population of

TABLE 75

SECTARIAN COMPOSITION OF THE SCHOOL ENROLLMENT OF LEBANON AS COMPARED WITH THE COMPOSITION OF THE GENERAL POPULATION, 1941–42

RELIGIOUS AFFILIATION	ESTIMATED POPULATION	PERCENT	ENROLLMENT					PERCENT OF ENROLLMENT TO POPULATION
			Public Schools	Private Schools	Foreign Schools	Total	Percent	
Christian....	585,443	53.0	6,783	53,274	36,606	96,663	69.9	15.8
Muslim.....	434,705	39.3	13,208	16,997	3,999	34,204	24.7	7.8
Druze.......	72,842	6.6	1,002	2,799	1,117	4,918	3.5	6.7
Jews........	5,567	0.5	10	262	1,775	2,047	1.5	36.8
Miscellaneous	6,112	0.6	53	276	157	486	0.4	8.0
Total...	1,104,669	100.0	21,056	73,608	43,654	138,318	100.0	12.5

Lebanon and compare it with the composition of the general population of the country. The matter is not without both educational and sociological interest. This is shown in Table 75.

Although the Christians of Lebanon constitute slightly more than one-half of the population, they have 70 percent of the total school enrollment of the country. The ratio of children in school to the Christian population is 15.8—which seems to show that the Christians are closely approaching universal literacy. It tends to confirm the statement made earlier, based on personal observation, that many a Christian village in Lebanon has achieved almost complete literacy. The Muslims, who make up 39.3 percent of the population, have 24.7 percent of the school enrollment. Their children constitute 7.8 percent of the total Muslim population. They seem to be half-way on the road to complete literacy. They are closely followed by the Druzes who have 6.7 percent of their population in the schools. As a community the Druzes make up 6.6 percent of the total population and have 3.5 percent of the total enrollment. The abnormal proportion of Jewish children in school compared with their population (36.8 percent) may be attributed either to the possibility that the figure given for the Jewish population is an underestimate or that Jewish students are coming from neighboring countries to study in Lebanon in such numbers as completely to upset the ratio. The Jews seem to have no problem of illiteracy.

Taking the total school enrollment and the total population of Lebanon, it is found that the former constitutes 12.5 percent of the latter—the highest percentage among the Arab countries.

Chapter 25

PUBLIC EDUCATION

To DESCRIBE the public schools of Lebanon is essentially to describe its primary and higher primary schools. At the time of the visit of the American Council Commission in 1945 the public primary school consisted of six grades. These were divided into three courses in the French fashion, the first two grades making up the preparatory course; the next two grades, the elementary course; and the last two grades, the middle course (*cours moyen*). The higher primary school consisted of three years, the first year of which was called the higher class, and the remaining two years were called the complementary classes (*classes complémentaires*). French was the only foreign language taught in the public schools and began with the first grade. The medium of instruction in the first four grades was Arabic, but children were required to study in French the arithmetic they learned in Arabic. In this way they were gradually inducted, from the first grade, into the study of subject matter through the medium of French. Beginning with the first year of the middle course (fifth grade), the study of object lessons was shifted to the medium of French, while arithmetic was carried through in both languages. Much the same pattern was kept in the classes of the higher primary school, science taking the place of object lessons. Drawing, manual arts, and physical education were allied to French, while singing was conducted in both languages.

The new course of study, issued in October 1946, shortens the length of the primary school from six to five years, gives the pupils the option of either French or English as the foreign language, and makes Arabic the language of instruction throughout the primary school. The teachers, however, are to "Habituate the pupils, beginning with the fourth year, in the understanding and use of scientific terms in French or English—according to the choice of the pupil—in arithmetic and object lessons." In the public examination at the end of the five-year course, the pupil may choose whether he will be examined in French or English.

Kindergartens

The kindergarten is of two years. In the first year special attention is paid to the cleanliness of the children and to teaching them games in the open air. They are given picture books and taught music and singing. They are taught the numbers from 1 to 10 and told moral stories relating to the members of the family.

In the second year, attention to cleanliness and the teaching of games, music, and singing are continued. A beginning is made in reading, and the children write the letters and words they learn. Elementary arithmetic is continued with objective practice on the four fundamental operations with numbers from 10 to 25. In object lessons short discussions of the pupils' environment are held, including such topics as furniture, equipment, clothing, and food. Moral precepts and love of one's country (taught by means of stories and conversations), patriotic songs, the Lebanese flag, the national anthem, and pictures portraying views of Lebanon, the president of the Republic, and famous Lebanese men, are included in the second year.

Primary Education

Education in the primary stage is said to have two functions: preparing pupils for life, and preparing them for the next stages of education. Though these may appear contradictory they have a common basis which is viewed as the real aim of primary education, namely, preparing the whole man, the thoughtful citizen, and the active member of society by providing him with spiritual, intellectual, and physical education. Spiritual education is based on the idea of God and His relation to creation, on respect for the human personality, on acceptance of the "hierarchy of values, rising from matter to mind to spirit," on the practice of noble virtues, and on the understanding of the duties and rights of man. Intellectual education is based on accustoming the pupil to correct thought and deduction, good observation and close attention, together with a body of information and practical methods which will enable him to deal with the everyday affairs of life. Finally, physical education aims at strengthening the body and helping it to grow through athletics. All these are to be accomplished by means that fit the level of the student, using tangible examples and avoiding going into abstractions and debatable issues in any detail.

Higher primary education is said not to differ in general aim from primary

education except that orientation toward the more practical side of life becomes a fundamental aim. Students are prepared in this stage for vocational schools and professional schools for teachers and for entry into life. During the first two years, therefore, the teacher is to watch the interests of the pupil in order to direct him toward that line of specialization for which he is best suited.

THE PRIMARY PROGRAM OF STUDIES

The program for the first two years of the higher primary school is made identical with that of the first two years of the secondary program to allow the pupil to transfer without loss of time, and presumably to give him enough time to mature and for his abilities and interests to show themselves before he chooses his career. The last two years, however, differ from those of the secondary school in giving greater emphasis to the practical side of the studies. Translated into time distribution, this means one hour more to drawing and manual arts, and to science (physics, chemistry, and biology), and two hours more to mathematics in the higher primary course, while in the secondary course emphasis is laid on languages, history and geography, and morals and civics.

Table 76 shows the primary and higher primary program of studies which together make up a program of nine years.

A summary of the primary and higher primary courses of study, though separate units, will be given here in a combined form, partly to avoid repetition and partly to show the evolution of each subject through the grades.

Arabic

In the teaching of Arabic special attention is paid to the difference between the colloquial and the classical languages, and an effort made to bridge the gap between them by selecting, as far as possible, vocabulary from the colloquial and incorporating it in correct sentences in the classical style. Care is taken not to choose difficult and rare words far from the pupil's environment. In the higher primary school special emphasis is laid on composition and style on living topics, and on the development of taste in literature.

Arabic begins in the first grade with reading of elementary words and simple sentences in a method that seems to be a combination of a spelling and a phonetic method. Reading is accompanied by penmanship based on the lessons and by memorization of simple poems. In subsequent years read-

ing of pieces with explanation of the meaning of words and comprehension is emphasized. The pieces are at first voweled to insure correct reading, but later unvoweled pieces are introduced. Selections from contemporary writers are chosen in the first two years of the higher primary school, while in the last two years selections from various periods of Arabic literature are chosen. Memorization continues throughout with poems and, later, prose

TABLE 76

PROGRAM OF STUDIES FOR PRIMARY AND HIGHER PRIMARY SCHOOLS, LEBANON, 1946

SUBJECTS	PERIODS PER WEEK				
	Primary School			Higher Primary School	
	1st Year	2nd and 3rd Years	4th and 5th Years	1st and 2nd Years	3rd and 4th Years
In Arabic:					
Religion	1	1	1	1	1
Moral and national lessons	1½	1	1	1½	1½
Reading, memorization, penmanship copying*	6	3½	2	3	}
Composition, grammar, dictation	...	3	...	3	} 5
Grammar, dictation	...	...	2	...	}
Composition, penmanship	...	...	2	...	}
Object lessons, conversation, hygiene†	2	1½	2	...	...
Arithmetic	5	5	5	...	...
History, geography	...	2	2	2½	2½
Drawing, manual arts	2	2	2	2	3
Music, singing	2	1	1	1	1
Physical education	2½	2	2	2	2
In the foreign language:					
Reading, memorization, penmanship	}	}	2	3	}
Grammar, composition, dictation	} 5	} 5	...	3	} 5
Grammar, dictation	}	}	1½	...	}
Composition, penmanship	}	}	1½	...	}
Optional in Arabic or the foreign language:					
Physics, chemistry, biology	...	...	...	4	4
Mathematics	...	...	...	4	5
TOTAL	27	27	27	30	30

* Penmanship shifted to composition after third year. Copying eliminated.
† Periods assigned to conversation only in first year, hygiene added in fourth and fifth years.

pieces and proverbs of increasing difficulty. Dictation starts in the second grade with exercises already studied and continues later with unstudied selections through the third year of the higher course, with emphasis on the writing of the *hamzah*. Written composition starts in the second grade with exercises in sentence construction, leads to the writing of descriptions of simple events, stories, and letters; develops in the higher course into longer stories, writing about descriptive and moral topics, essays, development of themes, and translation. Conversation lessons are given in the second and

third primary years and are based on the observation of the immediate environment of the children—the home, the school, familiar animals, flowers and plants, fairy tales, school picnics, and trips—and in the third grade on such topics as the seasons, the story of bread, the various trades, the mail, the cleaning of the streets, transportation, and dramatized stories. In the fourth and fifth years conversation is merged with the preliminary discussion of composition topics.

Grammar begins in the second grade with the parts of speech, the singular, dual, and plural, the masculine and feminine, proper and common nouns, the adjective, the pronoun, simple conjugation, and the subject and object. In each subsequent year these topics are expanded and new topics brought in, for example, the root verb and the derivative verb, the past, present, and imperative, and their conjugation, the verbal and the nominal sentences, the active and the passive, the adverbs of place and time, number, the demonstrative nouns, and types of nominal sentences. By the end of the third year of the higher primary school almost all the topics of grammar have been studied, and some of them repeatedly emphasized.

The Arabic course culminates in the fourth year of the higher primary course with a study of Arabic literature, heroic and lyric poetry, dramatics, philosophical poetry, the story, and description. Selections from the works of two prose writers and one poet of the 'Abbasid period are studied.

History and Geography

In teaching history and geography, the teacher is reminded that these subjects are of great use in developing patriotism and national spirit, that the two subjects are intimately related, that full use should be made of maps, particularly in the study of Lebanon's economic wealth and possibilities, and the lines of communication within Lebanon and between it and the Arab and other countries of the world. Special detail is to be given to the countries which have received Lebanese emigrants.

History and geography start informally in the first grade by reference to village life, the earth, the stars, and atmospheric phenomena. In the second and third years historical pictures and stories about Lebanon and the Arab countries are taken up. Beginning with the fourth year, history is divided into two parts: history of Lebanon and history of the rest of the world. In the fourth grade, early history of Lebanon is brought down to the end of the Byzantine period, and the history of the world to the discovery of America and the beginning of the Western nations is studied. In the fifth year Lebanese history to the present day is studied including

relations with the Arab countries, while world history takes up the modern period including the French Revolution, the attempt at the unification of Europe, and modern discoveries.

In the higher primary course the history of the ancient peoples having relations with Lebanon is studied, including the Egyptians, the Babylonians, Assyrians and Chaldeans, the Aegeans, Hittites, Hebrews, Persians, Greeks, and the Romans; the growth of Christianity and the Byzantine empire. The ancient history of the Phoenicians—the early inhabitants of Lebanon—is then studied, with emphasis on their invention of the alphabet, their seafaring and trade, their founding of Carthage and other colonies around the Mediterranean. In the second year the course is divided into three parts: history of the Arabs down to the Mamluks, the invasions of Europe and the states growing out of these invasions, and Lebanon during the Arab period down to the Fatimids, the Crusades, and the final expulsion of the Crusaders. In the third year the Renaissance and the rise of the modern states in Europe are studied, together with the Ottoman conquest in the early 1500's, and the situation in Lebanon in Ottoman days down to the seventeenth century. Finally, in the fourth year European history is brought down to the First World War, the history of Lebanon in the Shihabi period, and during its autonomous regime after 1864, during World War I, the French mandate, and finally the establishment of the independent Republic of Lebanon in 1943.

Geography is taught informally through stories and pictures in the first two grades to develop basic concepts about the earth, the stars, the villages, mountains, plains, rivers, and many of the geographical features which are in the immediate environment. In the third year, physical geography of the five continents and the important nations in each are studied. The fourth year is given to brief survey of Lebanon, the Arab countries, and Turkey, Cyprus, and Greece, while in the fifth grade a more extended study of Lebanon is made, with brief studies of Italy, France, Spain, North Africa, and other important countries of the world. Lebanese migration to various countries is noted.

In the higher primary school, physical geography of the continents of Asia and Oceania is studied in the first year; in the second year, Europe and Africa with emphasis on the Mediterranean basin, noting physical and climatic characteristics, agricultural, mineral, and industrial regions, as well as political divisions; in the third year, North and South America; and in the fourth year, astronomical geography, a review of the five continents, a detailed study of Lebanon, and lines of communication, especially among the Arab countries, conclude the course.

Morals and Civics

The primary course in morals covers personal traits and general virtues such as cleanliness, good manners, obedience, justice, charity, moral courage, sacrifice for others, honesty, love of parents, respect for teachers, and cooperation with others. In civics, a beginning is made from the first grade by explaining words such as citizen, soldier, flag, state, minister, and similar familiar terms. In the second and third years such concepts as nation, people, administration, customs duties, public projects, prosecutor general, and juries are explained, while in the fourth and fifth years general principles about the form of the state, the distribution of powers to legislative, executive, and judicial branches, parliament, the courts, military service, taxation, elections, banks and currency, and similar topics are studied.

In the higher primary course a more rationalized study of morals is made with emphasis on the place of the mind, the will and discipline, the conscience, cooperative living and what it implies in respect for others, mutual aid and philanthropy, division of labor, the family in general and family life in Lebanon, and Lebanese society. The course in civics gives in much more expanded form the ideas about the state, the division of power, and the parliamentary system, which were touched upon in the primary school. In the third year, principles of freedom and equality are discussed in detail: personal freedom (inviolability of home and property), freedom of work, conscience, belief, assembly, teaching and of thought, speech, writing and publishing, equality in civic and political rights and public duties, and equality of men and women. In addition, the duties of the citizen, such as obedience to law and authority, paying taxes, and military service, are studied together with the Lebanese Constitution, its development and its latest amendments. In the fourth year, an extensive study of Lebanon is made, the elements constituting it, its international position before World War I and after, its relations with the states of the Arab League and the United Nations. A review is made of the forms of government in the modern history of Lebanon from the seventeenth century to the present day. The program ends with a study of the aims of education, the contribution of the Lebanese people to culture, and Lebanese emigration, its causes and effects, and some of the famous emigrants.

Foreign Languages

Foreign-language teaching in the primary grades is justified by the fact that Lebanon's geographical position is that of a bridge between East and

West, and that archeological excavations have shown Lebanon to have been multilingual from the very dawn of history. With present-day shortening of distances and mixture of cultures, Lebanon should not abandon its role in world culture which it has acquired by virtue of being open to both East and West. A foreign language must then be taught side by side with the Arabic language—and taught well, bearing in mind the cultural benefit accruing from such teaching. In the modern world, French and English have the greatest vogue and potential usefulness, and the student is given the choice of one of these languages. The teaching of both starts with the first grade.

In French, the children are supposed to learn to read simple material fluently by the end of the first grade. Vocabulary and language exercises are based on familiar topics, and simple conjugations are stressed. The writing of letters of the alphabet and familiar words is taught by dictation. In subsequent grades the students are taught the derivation of words and the construction of sentences, and are gradually introduced to new topics in grammar—conjugation of regular and irregular verbs, parsing and logical analysis—and they read selections from French literature. Written exercises are assigned regularly throughout the entire four years. By the end of the fifth grade the pupil is supposed to be able to write simple narratives, descriptions, and letters.

In the higher primary school, a review of grammar is followed by systematic study, including logical and grammatical analysis, and culminating in a study of prosody. Reading begins in the first year with literary selections from twentieth-century French writers and poets; in the second year, selections from the eighteenth- and nineteenth-century writers are studied; in the third year, writers of the seventeenth century; and in the fourth year all periods are studied, including the complete works of such authors as Corneille, Racine, Lamartine, Chateaubriand, Molière, and Victor Hugo. In the fourth year, selections for reading keep pace with a course in the history of French literature. Composition starts with narration, description, and letters and ends with literary analysis, criticism, imitation of literary pieces, the writing of themes and expansion of proverbs and maxims. Texts written for French children are used throughout.

English starts in the first grade with conversation about the immediate environment, the study of the sounds and the alphabet, and memorization of simple songs and poems. Both oral and silent reading from texts are emphasized beginning with the second grade. Special attention is paid to pronunciation, fluency, dramatization, and meanings of words in their context. Supplementary reading material is introduced in the fifth grade and

conversation in English in class is encouraged. Composition ranges from answering questions on texts and using words in sentences in the third grade, to reproducing material read, telling and writing simple stories, and writing short compositions on easy subjects in the fifth grade. Grammar includes conjugation with emphasis on the verbs "to be" and "to have," the third person singular, plurals, the possessive case, affirmative, negative, interrogative, degrees of the adjective, irregular verbs, and all types of pronouns including the use of the relative pronoun. Throughout the course selections for memory work and dictation are based on the texts used. The books recommended are to be selected from those specially written for foreigners, viz., those by Michael West (in use also in Egypt and parts of India), by Morris (in use in Palestine), and by Leavitt (developed and used at the American University of Beirut and schools allied to it).

Mathematics

Arithmetic in the first grade starts with reading and writing numbers from 1 to 20 and then to 100, simple addition of numbers of one digit, subtracting numbers below 100, counting by twos, threes, fours, and fives as an introduction to multiplication, and the reverse of this process as an introduction to division. Second-grade teaching covers reading and writing numbers up to 1,000 and then to 10,000, adding and subtracting numbers of three digits, multiplying these numbers by 3, 4, and 5, and later by 6, 7, 8, and 9, dividing whole and decimal numbers by numbers from 2 to 9, exercises and problems on the four fundamental operations. In the third grade are taught addition of numbers of five or more digits, multiplication by numbers of three, four, and five digits, the multiplication table, division of whole and decimal numbers by two digits, introduction to the metric system of measures of length, weights, and capacity, the Lebanese currency up to 100 piasters, simple operations on buying, selling, and profit, and simple proportion. In the fourth and fifth grades are taught reading and writing of whole and decimal numbers, augmenting and diminishing numbers 10 and 100 times, the four fundamental operations with emphasis on mental arithmetic, divisibility by 2, 3, 4, 5, and 9 and the corresponding multiplication table, the highest common factor and lowest common multiple of two numbers only, common and decimal fractions, squaring numbers and the square root of whole numbers and fractions, a fuller study of the metric system; units of length, area, volume, and weight, density and specific gravity, the units of work and energy, compound numbers, measures of time, changing compound numbers to

fractions, distance and speed, ratio and proportion, percentage, interest and discount, compounds and mixtures. Some notions of geometry are included in the fourth and fifth grades, including the various types of lines and angles, the circle, the compass and the protractor, the triangle and its parts, the right triangle, quadrilaterals, the areas of triangles and quadrilaterals, regular and irregular polygons. Arithmetic is continued in the four years of the higher primary school with a more extensive treatment of the primary-school topics and the addition of graphs, direct and inverse proportion, and practical applications.

Geometry is taught in each of the four years of the higher primary school. The first year is taken up with elementary geometry, finding the areas of geometrical figures, and the volumes of solids. The second year deals with the kinds of lines, angles, triangles, and quadrilaterals, their properties, their drawing, and some operations on them. The third year includes the following topics: the relationship between the circle and the straight line including the tangent, the arc, and the chord; the relationship between angles and circles, angles inside and outside the circle, arcs corresponding to an angle, quadrilaterals and polygons drawn within a circle; two tangents drawn from a point outside the circle; similar figures, triangles, and polygons. The fourth-year course is divided into plane and solid geometry. Plane geometry comprises metric relationships in the right triangle, in any triangle, and in the circle; the areas of polygons and the relationships between areas. In solid geometry are studied lines and planes, the intersection of planes, parallel and perpendicular lines and planes, solid angles, solid figures, their areas and volumes, the plane diameter, and the plane tangent to a sphere.

Algebra begins in the second year with elementary definitions, numerical values, negative numbers, the use of parentheses, reduction of terms, the four fundamental operations on one term and on many terms, equations of the first degree with one and two unknowns involving no fractions. In the third year the study of algebra is continued with fractions, their simplification and their addition, subtraction, multiplication, and division; the square roots, their simplification, and the four fundamental operations on them, changing a square root denominator to a nonsquare root denominator; equations of the first degree with one or more unknowns and with denominators; algebraic measures of vectors on a directed straight line; theory of Thales, finding the position of a point in a plane with rectangular coordinates; notions of variable, and function; the relations of $Y = ax$ and $Y = ax + b$ where a and b are numerical values. In the fourth year, study is given to equations of second degree with numerical coefficients,

the relation between roots and coefficients, graphic representation of the functions $Y = ax^2$ and $Y = \frac{1}{x}$, and problems the solution of which leads to equations of the first or second degrees.

Object Lessons and Sciences

Object lessons begin in the first two grades with conversations about familiar objects in the environment and such topics as air, water, time and its divisions including the seasons, months, weeks, days, and reading the hours of the clock. In the third year, an elementary study is made of the body of man, of the domestic animals and the main differences among them, of common plants, of food and drink, of raw materials and the chief local manufactured products, and of the three elements of nature—air, water, and fire. These topics are reviewed and expanded in the fourth year with the addition of a study of useful and harmful animals and insects, the main families of plants, agricultural operations, types of rock; kinds of fuel, the common minerals, air, respiration, combustion, atmospheric pressure, and water, its uses and its three states. In the fifth year the subject is divided into topics in physics, chemistry, zoology, botany, and elementary notions of agriculture.

In the higher primary school this division into subjects is maintained under the headings of physics, chemistry, and natural science. The course outlines cover about twenty pages, and considerations of space make it impossible to summarize them in any detail. First-year physics consists of a brief survey of the subject. Mechanics of solids and liquids are studied in the second year, gases and heat in the third year, and light, magnetism, electricity, and sound in the fourth year—the whole having a practical bent with emphasis on the various instruments which show the application of physical laws (barometer, manometer, balance, thermometer, voltmeter, etc.).

In chemistry the first year is taken up with simple experiments on air, oxygen, hydrogen, water, carbon, with the preparation of oxygen, hydrogen, and carbonic gas, a brief study of sulphur, common salts, calcium carbonate and the main acids, bases and salts; properties of metals and alloys. In the second year systematic study is begun of physical and chemical phenomena, kinds of matter, chemical nomenclature, formulas and equations; combustion, oxygen, oxides, phosphorus, sulphur, carbon, calcium, sodium, acids and bases, iron, zinc, magnesium, water, hydrogen. In the third year some of the commonly used compounds of the elements

mentioned above are studied while in the fourth year organic chemistry and the main organic compounds are taken up.

In natural science the first year is devoted to a general survey of the study of man, animals, plants, and geology. In the second year, botany and zoology are studied in greater detail, together with the classification of animals and plants. The third year is given to an extensive course in hygiene and another in geology, including the types of volcanic and sedimentary rocks, the influence of air, glaciers, rain and sea water, and living beings, the movement of the soil and earthquakes, volcanoes, geological strata and fossils, the geological ages, and finally, applications of geology to mining, public works, agriculture, and hygiene. The fourth year is given to a study of animal and plant anatomy and physiology.

Beginning with the fourth primary grade, the courses in science and mathematics may be given in either Arabic or French; schools have the option of teaching these subjects in either language and presumably in English as well.

Physical Education, Music, Drawing, Manual Arts

In physical education, the usual program for boys and girls in the primary and higher primary schools includes marching and running exercises, Swedish and gymnastic exercises, group games, ball games, dances, and corrective exercises.

Music consists of songs in Arabic and the foreign language, elements of musical notation and reading, the scales and the keys, culminating in the higher primary school in songs for one voice or in group songs with parts; recorded classical music with explanations by the teacher, the history of music and stories of the lives of famous composers, information on types of instrumental and vocal music, and types of musical instruments: string, brass, woodwind, and percussion instruments. With the training and equipment of the average Lebanese teacher it is doubtful if this program can be applied—indeed, it is the exceptional teacher that can apply it even in part.

Drawing in the primary school includes the drawing of geometrical figures, objects, animals, flowers, and some wooden or clay models. In the higher primary, three types of drawing are mentioned: artistic, decorative, and geometrical. The student is to be directed to whichever type he likes best.

The course in manual arts follows the traditional lines of paper-folding, cutting and pasting, and work in straw and clay. The girls learn to em-

broider, knit, weave a small rug, and do some needlework. Boys in the villages may take a course in agriculture and girls a course in home economics and elements of home nursing. The course in agriculture covers soils, irrigation, the raising of cereals, vegetables, and trees, and the care of animals. Theoretical and practical work are provided for. However, since the time allotted for drawing, manual arts, and agriculture combined is only two hours a week, and since very few if any schools have facilities for agriculture, the course is more an expression of a hope than a practical reality.

Description of Primary Schools

Of 23 government primary and higher primary schools in Lebanon visited by the American Council Commission, 10 were housed in buildings belonging to the government, 11 were in rented buildings, and 2 had been contributed by individuals or communities. Some of the government buildings, mostly those in the cities, had been built under the Ottoman regime, while others were built during the French mandate regime. In two instances in northern Lebanon modern buildings were being erected by the government. Rented buildings and some of the government buildings in the villages left much to be desired, their rooms being too small for the classes, which often were large.

The schools were poorly equipped. A few maps and charts were found in some schools, and one school had a very small laboratory. Libraries were noticed in two schools; these two libraries were being developed through the efforts of the principals and contributions from the pupils, the government sending a few books occasionally. Desks were of the fixed-seat variety designed to accommodate from two to four pupils. Often, however, they were used by from three to six or even more pupils. Most of the furniture showed signs of long use. Playing space was small, especially where the buildings are rented.

The school year of nine months begins about October 1 and lasts until the end of June. The school day consists of a morning session from 8 A.M. to 12:15 P.M., and an afternoon session from 2 to 4 P.M. Classes usually run in half-hour units.

THE TEACHERS

Schools in the cities are largely staffed with graduates of the 2 teachers colleges of Beirut—1 college exclusively for men and 1 for women. Some of the teachers—a small number—have passed the teachers qualifying examination. In the smaller towns and villages of the mountains, however,

graduates of the teachers colleges are few. Here the qualifications of a teacher may vary from hardly more than the primary-school certificate to the *Baccalauréat,* Part II. The Commission found very few of the latter. There are a few teachers from Turkish days and a few teachers of Arabic who had their studies under *shaykhs*. The rest of the teachers were former students or graduates of private and foreign schools who had had one to six years of secondary or complementary education, but no professional training.

Teaching consisted almost entirely of imparting knowledge and skills to the pupils, the initiative being largely that of the teacher, pupils taking the passive, receptive role. Stress was laid on homework and the working-out of exercises. These were corrected by the teacher. The larger schools had special supervisors for maintaining discipline, keeping records of attendance, and watching that pupils went in and out of classes promptly and in an orderly manner. The pattern of teaching follows in general that of the French schools, though efficiency in its application varies with the schools. Usually the resemblance grows fainter as one moves farther out into the smaller villages.

The teachers' load in primary and higher primary schools varies from twenty-seven periods in the lower grades to twenty-four in the middle grades and twenty-one in the upper grades. A teacher is usually responsible for teaching all subjects to a primary class except when a school has one or more teachers who do not know French, in which case some adjustment is made in subject distribution. In the higher primary school the distribution of work is by subjects.

Government statistics showing the distribution of pupils in the grades were not available. The American Council Commission, however, was able to secure data on this point from 19 of the 23 schools visited, a summary of which follows.

Registration was progressively smaller in the upper grades. This is a phenomenon which was found in the public primary schools of all the six Arab countries studied. Pupils in the first grade constituted 30.4 percent of the total in the primary schools visited, while those in the sixth grade made up only 6.8 percent of the total. In the absence of adequate facts one can only speculate as to the factors bringing about such a situation. One reason is probably the incompleteness of some of the schools. Of the 19 schools studied, which it is believed constitute a fair sample, 7, which enrolled 565 pupils, were incomplete village primary schools having less than six grades. Another possible explanation is the removal of pupils to private and foreign schools which on the whole have a better

Grades	Enrollment
Primary Classes	
First	1,374
Second	909
Third	910
Fourth	593
Fifth	422
Sixth	307
Total	4,515
Higher Primary Classes	
Seventh	196
Eighth	127
Ninth	64
Total	387

reputation. A third reason is probably retardation, some examples of which the Commission was able to observe. In a check-up in a village boys school in northern Lebanon and in a girls school in Tripoli the average age of sixth-grade children was found to be 14.8 and 14.4 respectively, with a range from 12 to 17 years. Another check-up in 2 schools showed that children in the first grade were grouped into an advanced group and a retarded group. Most of the children in the retarded group usually had to spend another year in the first grade. In one school 30 out of 45 children in the first grade had been in that grade the year before. This tendency of many children to repeat the first grade is somewhat confirmed in the sharp decline in numbers between the first and second grade shown in the figures above.

The current view among the people seems to be that the government schools are surpassed in quality and efficiency by most foreign and private schools, though in the villages there may not be much to choose from. Here an occasional government school may be better than its private or foreign neighbor.

Public Primary-School Examinations

The Lebanese primary-certificate examination is given after the sixth grade at the present time but according to a new decree issued on the same day as the decree setting forth the new primary course of study, beginning with the year 1949 it is to take place at the end of the fifth

year. The new examination system is summarized here, and reference to the current one is made only for the sake of comparison.

The public primary examination takes place once a year in June and is controlled by a committee headed by the Director General of Education, with members drawn from the public-school system. The Minister of National Education and Fine Arts, however, may appoint state officials of culture and experience to serve on the committee. The chairman makes the final selection of the questions and is responsible for their secrecy until the time of the examination and for keeping the identity of the pupils' examination papers unknown to the members of the committee.

The pupils taking the examinations are not only pupils of the public schools, but may come from private and foreign schools as well.

To be admitted to the examination, a pupil must be no less than ten years old and must present a certificate of identity and a certificate from the principal of his school that he had attended the fifth primary year in full.

Under the current system (up to 1949) the examination is written, but an oral examination also is held for both the Arabic and French language; examinations in Arabic language, history, and geography are conducted in Arabic; those of the French language and object lessons, in French; and the pupil is given the choice of answering arithmetic in Arabic or French. The new examination (beginning 1949) is to be entirely written, and all examinations are to be taken in Arabic except the foreign-language examination. Marking is on the basis of 10 for each subject. The subjects of the examination are shown in Table 77.

In Arabic composition the student writes a letter, a story, or a description. There must be three questions in history and geography, one of which involves the drawing of a map. In arithmetic at least one problem must show the method of its solution. The examination in object lessons

TABLE 77

SUBJECTS FOR THE PRIMARY-CERTIFICATE EXAMINATION, LEBANON

Subject	Time Allotment	Weighting	Total Marks
Arabic composition	1 hour	3	30
Arithmetic	1 hour	2	20
Geography and history	45 minutes	2	20
Object lessons	30 minutes	1	10
Drawing for boys or sewing for girls	1 hour	1	10
Foreign-language dictation	1 hour	3	30
Total		12	120

consists of three questions to be answered briefly. In the foreign language, dictation must consist of at least ten lines and there must be three questions on the text, one of which involves comprehension and the other two grammar and vocabulary.

A pupil fails if he receives a zero in any subject or less than 2 in Arabic. In order to pass, a pupil must secure 60 out of the total of 120 possible marks. The following were the results of the public primary certificate examination in 1944–45:

	Entered	Passed	Percent Passing
Boys	2,077	999	48.1
Girls	1,046	704	67.3
Total	3,123	1,703	54.5

The Higher Primary Certificate examination is administered by a committee of public-school personnel under the chairmanship of the Director General and with competent government officials assisting when necessary. The pupil must be at least fourteen years of age, must hold the primary certificate, must pay a fee of £S3 ($1.38), and must present a certificate showing that he had attended the third and fourth years of a higher primary school.

The examination is both oral and written, and a pupil is admitted to the oral only after he has passed the written. The examination is held

TABLE 78

SUBJECTS FOR HIGHER PRIMARY CERTIFICATE EXAMINATION, LEBANON

Written Examination			
Subject	Hours	Weighting	Total Marks
In the Arabic language:			
Arabic composition	2	2	40
History and geography	1	2	40
In the foreign language:			
French or English composition	2	2	40
In Arabic or one of the two foreign languages:			
Mathematics	2	3	60
Physics, chemistry, biology	2	3	60
Total marks			240

Oral Examination		
Subject	Weighting	Total Marks
In the Arabic language:		
Arabic	2	40
History and geography	1	20
Civics	1	20
Physical education	1	20
Drawing or sewing	1	20
In the foreign language:		
French or English	2	40
In Arabic or one of the two foreign languages:		
Mathematics	2	40
Science	2	40
Total marks		240

twice a year, in June and October. The subjects of the examination and their time allotments and weighting are shown in Table 78. Papers are marked on a scale of zero to 20.

In order to pass the written examination, the pupil must receive a total of 120 marks. In both the written and oral examinations he fails if he receives a zero in any subject or less than 5 in Arabic composition and reading. In order to pass the whole examination he must receive a total of 240 marks.

Following is a tabulation of the results of the *brevet* examination for 1944–45:

	Entered	Passed	Percent
June session	360	135	37.5
October session	61	10	16.4
	421	145	34.4

The new decree prescribing the conditions of this examination, which was issued simultaneously with the new course of study on October 1, 1946, will come into effect beginning with the June session of 1953, that is, four years after the first application of the new primary-certificate examination system. In the meantime the old system for the *brevet* examination will be continued. The most important difference between the two is that of the language of the examination. While in the old system the examination in all subjects except Arabic could be taken in Arabic or French, in the new system all subjects except the foreign language, science, and mathematics, *must* be taken in Arabic, and in the latter two the student has the choice of using either Arabic, French, or English.

Secondary Education

Although the Lebanese government has no secondary schools, it acts as an examining authority and for that purpose has issued a detailed secondary course of study. The new secondary course was issued in October 1946 simultaneously with the primary course of study and is based on the latter. It is to be applied immediately after the pupils who follow the new primary course finish the fifth grade, that is, in 1949, and the first new-style secondary-school examination is to be held in 1955.

Secondary education is, as indicated in the preamble to the course, essentially different in aim and method from primary education. The aim is to train and select the youth of the country for the right orientation in

matters of the mind, for carrying the major responsibilities of public life, and for enlightened specialization in the branches of higher education. Method is directed to the quality rather than the quantity of teaching, to theoretical proof more than to practical test, and to allowing time for the opening out of all man's gifts into a well-rounded personality that will assimilate the subject matter and transmute it into his own cultural existence. It has aptly been said that the ideal secondary culture is "what remains in man's make-up after he has forgotten what he learned."

In secondary education, therefore, the scientific-mathematical section will guide the select youth of Lebanon to deep insight, logical thinking, and right judgment, while the literary-philosophical section will guide them to a sensitiveness, disciplined imagination, good taste, holding in esteem the hierarchy of values and the universality of man.

THE SECONDARY PROGRAM OF STUDIES

The new secondary program of studies is given in Table 79. The distribution of periods in the first two years and the details of the syllabuses are exactly the same as those for the first two years of the higher primary school. In the third and fourth years, one-half hour is added to morals and civics and to history and geography, one hour to the foreign language, and two hours to Arabic. Correspondingly, one hour is taken from drawing and manual arts and from science, and two hours from mathematics.

As far as the details of the courses for the third and fourth years of the higher primary and the secondary schools are concerned, the difference is rather slight. In the secondary schools there is slightly more emphasis upon literature in fourth-year Arabic, and upon the reading of French authors in third- and fourth-year French. The course for French grammar is somewhat different, and grammar is reviewed in its entirety in the fourth year. In mathematics some topics are delayed to a later year and the details of solid geometry are omitted, while in science some topics in physics and chemistry are dropped. The program, uniform for all students in the first four years, is divided into literary and scientific sections in the fifth and sixth years, and into philosophy and mathematics sections in the seventh or last year.

Students may, however, select a classical-languages section in which they study Syriac, Hebrew, Latin, or Greek in addition to their regular program. Such study is planned to begin with the first year and last through the sixth year. This innovation, not yet in operation in 1946, is described hereafter.

TABLE 79

NEW PROGRAM OF STUDIES FOR SECONDARY SCHOOLS, LEBANON, 1946

First to Fourth Years

Subject	Hours per Week: 1st and 2nd Years	Hours per Week: 3rd and 4th Years
In Arabic:		
Religion	1	1
Morals and civics	1½	2
Arabic	6	7
History and geography	2½	3
Drawing and manual arts	2	2
Music and singing	1	1
Physical education	2	2
Foreign language*	6	6
*In Arabic or the foreign language:**		
Physics, chemistry, and biology	4	3
Mathematics	4	3
Total	30	30

Fifth and Sixth Years

Subject	Hours per Week: Literary Section	Hours per Week: Scientific Section
In Arabic:		
Religion and ethics	2	2
Arabic language and literature	8	5
History and geography	4	3
Drawing	1	1
Music and singing	1	1
Physical education	2	2
Foreign language and literature*	6	5
*In Arabic or the foreign language:**		
Physics and chemistry	3	6
Mathematics	3	5
Total	30	30

Seventh Year

Subject	Hours per Week: Philosophy Section	Hours per Week: Mathematics Section
In Arabic:		
Religion and ethics	2	2
Philosophy	7	3
History and geography	4	3
Physical education	2	2
*In the foreign language:**		
Philosophy	8	3
*In Arabic or the foreign language:**		
Physics, chemistry, and biology	5	9
Mathematics	2	8
Total	30	30

* French or English.

The Fifth and Sixth Years

Arabic literature.—Arabic is given in the fifth and sixth years and is entirely devoted to literature. After an introduction in general principles and a quick survey of the main periods in the history of Arabic literature, a somewhat full course is given. Literature is divided into two parts, prose and poetry, and each is taken in part in the two years. In prose are included the story and the novel, proverbs and maxims, scientific, historical, geographical writings, and travel, oratory, the *maqamat* (formalized stories in rhymed prose), moral and social "lessons," and literary criticism. Under poetry are included the categories familiar in Arabic poetry—lyric poetry, elegies, heroic poetry, philosophical and moralistic poetry, maxims, romantic poetry, Bacchic poetry, description, eulogies and diatribes, political and religious poetry. At least one selection from each of two to five poets from each of the periods is studied in each category. An extended study of three poets is made in the fifth year and of five in the sixth year. Composition involving moral, literary, and critical essays, translation, and the study of Lebanese literary figures in other languages completes the course.

Foreign languages.—French is given in the fifth and sixth years with emphasis on the evolution of the language and literature. The sixteenth and seventeenth centuries are well covered, with some attention given to the eighteenth and nineteenth. Special attention is paid to the works of Corneille, Racine, Molière, and La Fontaine among the poets, and to Voltaire, Rousseau, Bossuet, La Bruyère, and Pascal among the prose writers. Selections are studied from the nineteenth-century novelists and historians. The Orient in French literature as depicted in works by Volney, Chateaubriand, Lamartine, De Nervel, and Barrès, is discussed, and Romanticism, Realism, and Symbolism as schools of literature are defined. Essays on moral and literary topics and on literary analysis are written.

In English, a review of grammar and an outline history of English literature are studied. In the sixth year two prescribed texts, of which one is to be a Shakespeare play, are required. In both years, compositions on general topics and on literary subjects connected with the course are written.

History and geography.—The history course in the fifth year gives a general survey of the history of Lebanon from ancient times to the Mamluk period and in the sixth year extends to the middle of the nineteenth century. The European-history course includes the discovery of America, the Renaissance, the Reformation, the religious wars, the rise of Great Britain, France, the United States, the problem of Poland, and scientific discoveries and their influence on the social structure of the West.

Fifth-year geography centers around the economic geography of the Americas. In the sixth year a detailed study is made of the economic geography of Lebanon, Syria, and Palestine, and a summary study of the economic geography of the countries of the Mediterranean basin including Iraq, Sa'udi Arabia, and Yaman.

Mathematics.—Fifth- and sixth-year mathematics includes a review of algebra, expanded study of the four fundamental operations, fractions, equations of the first and second degrees with graphic representation, and graphic solution of equations, rectangular coordinates, the parabola and the hyperbola, arithmetical and geometrical progression, compound interest, and definition and use of logarithms with 4 or 5 decimal places. A beginning of trigonometry is made in the sixth year. In geometry, the course in plane geometry begins in the fourth year and is completed in the sixth year. This is about the only important difference between the science and literary sections in the field of mathematics.

Science.—Science in the fifth and sixth years is confined to physics and chemistry. A rather extensive course in physics comprises mechanics, hydrostatics, heat, magnetism and static electricity in the fifth year, light and optics, and electricity in the sixth year. No mention is made of sound. The two-year course in chemistry comprises, aside from some general principles, the experimental study of air, oxygen and nitrogen, water and hydrogen, acids, bases and salts, sulphur and its compounds, phosphorus, carbon, silicon and their compounds, sodium, potassium, chlorine, calcium and their compounds, the three metals, iron, aluminum and copper, and their compounds. The difference between the science course for the literary and scientific sections of the sixth year is slight.

Physical education, music, drawing, and manual arts.—The courses in physical education, music, drawing, and manual arts are about the same as those for the higher primary course, with the exception that no courses in agriculture for boys and home economics for girls are given.

The Year of Philosophy and Mathematics

The syllabus for the philosophy and mathematics sections—the seventh year—lists the same subjects for both: religion and morals, philosophy, history and geography, science, mathematics, and physical education. The basic difference is that while the philosophy section takes fifteen hours of philosophy, five hours of science, and two hours of mathematics, the mathematics section takes six hours of philosophy, nine hours of science, and eight hours of mathematics. Certain of the courses are common, or almost so, including history and geography, biology, cosmography, Arabic

philosophy, logic and ethics. The main difference is that the mathematics section takes a wider program of physics, chemistry, and mathematics, while only the philosophy section takes psychology and metaphysics.

Philosophy.—The course in Arabic philosophy starts with a brief survey of the intellectual development in Muslim countries, and is accompanied by a similar survey of Greek philosophy: Socrates, Plato, Aristotle, Plotinus, and Neoplatonism. This is followed by the study of the translation movement into Arabic and the role of the Christian Jacobites and Nestorians and of the Sabeans in this movement. A survey is made of the introduction and development among the Arabs of medicine, pharmacy, chemistry, mathematics, music, and logic. The interaction of culture in the 'Abbasid period is touched upon, together with its effects on Muslim thought in the growth of Muslim scholasticism, the new schools, especially the Mu'tazilite,[1] the reaction to the schools (Ash'ari[2] and Ghazzali[2]) and mysticism in Islam. Muslim philosophy in the East is then studied through Ikhwan al-Safa[3] and Ibn Sina[2] (Avicenna), and in Andalusia through Ibn Tufayl and Ibn Rushd[2] (Averroes). To these is added Ibn Khaldun and his sociology. Finally, the effects of Muslim philosophy on medieval Europe are studied including the translation of philosophic works into Hebrew and Latin by Maimonides and Albertus Magnus, and the effect of Muslim philosophy upon the theology of Saint Thomas Aquinas. This extensive program is accompanied by selected readings from eleven Arab philosophers. The whole is studied in Arabic.

Philosophy studied in the foreign language includes psychology, metaphysics, logic, and ethics. In psychology the treatment of the subject is typically French: After a discussion of preliminary topics, definitions, and methods, the course takes up (1) cognitive life including sensation, perception, the conscious and the unconscious, memory, association of ideas, imagination, conception, judgment, reasoning, symbols, and language; (2) affective life: pleasure and pain, tendencies, emotions, and passions; (3) active life: tropisms, irritability, instinct, the will, and liberty. An appendix to the course of study treats of spirituality and immortality of the soul. The whole is intertwined with the various theories of Descartes, Freud, Janet, Jean-Paul Sartre, Henri Bergson, H. Delacroix, and William James, as well as materialist and spiritualist theories.

[1] A school of comparatively liberal thinkers which grew up in Baghdad beginning with the ninth century A.D.

[2] Prominent Arab scholars and philosophers who lived between the seventh and fourteenth centuries.

[3] A group of thinkers during the 'Abbassid period, best known for their essays on philosophical subjects.

The study of metaphysics deals with (1) the problem of criticism, reason, and the origin and value of rational principles, the idea of truth; (2) rational cosmology: realism, idealism, space and time, matter, and life, with careful distinction drawn between the scientific and metaphysical points of view in the last three items; (3) theodicy, the origin of religion, the knowledge of God through experience as expounded in the theories of Hindu, Muslim, and Christian mystics, reasons for believing in the existence of God, the nature of God and His attributes, relation of the world to God: monism, pantheism, dualism, creationism, providence, liberty, and evil.

Logic deals with science and method. The distinction between science and the sciences is made, the scientific spirit, objectivity, the contributions of the Arabs to science, classification of the sciences, general mental processes (intuition, deduction, induction, analogy, analysis, and synthesis) are discussed. Under method are included the various types of sciences, their methods and their roles: mathematics, experimental sciences including history and sociology, and the theories of Tarde, Durkheim, and other contemporary writers in sociology.

Ethics is divided into theoretical and practical. Under theoretical are treated the various ethical doctrines, the rational bases of ethics (conscience, the good, duty, responsibility, social sanction, law, justice, charity, and equality). Under practical ethics are included: (1) duties of man to himself; (2) ethics of the family including theories on the origin and function of the family, children, and population and a critical treatment of the Malthusian theory, birth control, eugenics, racism, and the "crime of abortion"; (3) social ethics; property, capital, profit, work, division of labor, relation between capital and labor with liberal and socialist theories and directed economy; (4) civic and political ethics: political society, nation, country, state, government, the three powers of government, origin of political society and of power, civic and political rights and duties; (5) ethics and international relations: humanity.

History and geography.—In history, Lebanon from the middle of the nineteenth century to the present is studied in detail, together with the following topics in modern history: the unification of Germany and Italy, the American states, evolution of social ideas, and commerce and industry.

The economic geography of Great Britain, Germany, Russia, Iran, India, China, Indo-China, and Japan is studied.

Mathematics.—Mathematics for the philosophy section consists of a supplement to algebra in which a review is made of trigonometry already studied, with the addition of a study of the derivatives, speed as derived

from space in its relation to time, and of cosmography which deals briefly with the Copernican system, the sun, the planets, the earth, the moon, comets and shooting stars, stars and nebulae, and the Milky Way.

The program in physics and chemistry is a shorter version of that given to the mathematics section which will be described later. However, the two sections take the same program in biology. This consists of a study of the anatomy and physiology of man, the anatomy and physiology of plants, and hygiene and prevention of disease. In this last, a brief study is made of infectious diseases, including malaria, smallpox, cerebral meningitis, pulmonary tuberculosis, typhoid and paratyphoid fevers, and amoebic dysentery. The topics of immunity, vaccines, and serums are touched upon.

Although no hours are specifically allotted to the teaching of a foreign language, a syllabus is set out for English précis work and for advanced composition on general, abstract, and literary topics. In literature, one play by Shakespeare, one prose work, and an anthology of poetry are studied. This program is identical for both sections.

Only a summary of the courses in physics, chemistry, and mathematics, therefore, which distinguish the mathematics section from that of philosophy, need be given here.

The course in physics comprises certain special topics in mechanics, sound, light and electricity, and ends with a study of the constitution of matter. In chemistry, elements of qualitative and quantitative (volumetric and gravimetric) analysis and of physical chemistry are given, but most of the course is devoted to a rather extensive treatment of organic chemistry.

The course in mathematics comprises arithmetic, algebra, trigonometry, geometry, mechanics, and cosmography (astronomy). In arithmetic some basic theories are taken and a more extended treatment is given to such topics as divisibility, highest common factor and lowest common multiple, ratio and proportion, common and decimal fractions, the metric system, the square of a whole or a fractional number, and relative and absolute error. The course in algebra begins with a treatment of whole, fractional, negative and positive indices, arithmetical and geometrical progression, and compound interest. The main part of the course, however, deals with analytical geometry. Trigonometry reviews what was taken in the sixth year, and completes plane trigonometry. Geometry comprises moderately detailed treatments of the transformation of figures (translation, rotation, similitude, inversion, projection), conics, and descriptive geometry. Mechanics takes up kinetics (rectilinear, curvilinear, and circular motions) and the simple motion of a solid body; to this is added a fairly extensive treatment of statics. The course in cosmography is the same as that given in the philosophy section.

THE CLASSICAL-LANGUAGES SECTION

This is a novelty in the Lebanese course. As stated in the official course of study, this program is meant to "help bring up scholars in languages and archeology, for it is obvious that thorough study of the Arabic language requires a thorough study of ancient Semitic languages and especially Syriac and Hebrew, just as the science of archeology cannot be mastered except by him who prepares for it by studying Greek and Latin." Courses for these four languages are outlined, extending over the first six years of the secondary school.

The course for each of the classical languages is planned to start with the alphabet (except Latin) and the teaching of reading. Grammar and literature are to go side by side after that, with a study of masterpieces of poetry and prose.

The classical-languages section is still largely a project for the future. It is not indicated where the time will be found to include it in the studies of those who choose it. Nor is it known how much of a demand there will be for it. It is, however, an interesting experiment, unique in Lebanon and the Arab world.

Public Secondary-School or Baccalauréat Examinations

The *baccalauréat* examinations of the Lebanese government are held in parts: Part I, at the end of the sixth year of the secondary school; and Part II, at the end of the seventh year of the secondary school. Each is held in two sessions, in June and July, and in October of each year. The examinations are held in much the same way as the primary examinations previously described, except that the Minister of National Education himself is chairman of the examining committee which is made up of professors of higher institutions, with the help of competent government officials and teachers in public secondary schools, if necessary.

The student must be at least sixteen years of age and must present his school record for the fifth and sixth years in order to be allowed to sit for Part I, and for the seventh year in order to be allowed to sit for Part II. A fee of £L4 (about $1.80) is charged for Part I, and £L10 (about $4.55) for Part II.

The details of the examinations are given in Table 80. A study of the table shows that the difference between one section and another is a matter of emphasis rather than an important difference in subject matter, except for special papers in physics and chemistry for the scientific section (Part I), translation from a classical language for the classical-languages section (Part I), and a special paper in philosophy for the philosophy section (Part II). For example, the literary section of Part I has a weighting

TABLE 80

SUBJECTS FOR LEBANESE BACCALAURÉAT EXAMINATIONS: PART I

Subject	Literary Section			Scientific Section			Classical-Languages Section		
	Hours	Weighting	Total Marks	Hours	Weighting	Total Marks	Hours	Weighting	Total Marks
Written examinations:									
Arabic composition	3	3	60	3	2	40	3	2	40
Mathematics	3	2	40	3	3	60	...	...	...
Arabic literary criticism, or translation, or translation from Latin	3	2	40	...	...	...	...	...	..
French or English composition	3	3	60	3	2	40	3	2	40
Translations from and to a classical language	...	...	...	...	...	...	3	3	60
Physics and chemistry	...	...	...	3	3	60	...	...	..
Oral examinations:									
Explanation of an Arabic text	...	3	60	...	2	40	...	2	40
History and geography	...	2	40	...	1	20	...	3	60
Mathematics	...	1	20	...	3	60	...	1	20
Physics and chemistry	...	1	20	...	3	60	...	...	...
Explanation of a French or English text	...	3	60	...	1	20	...	2	40
Explanation of a classical language text	...	...	...	...	...	...	...	3	60
Total	...	20	400	...	20	400	...	18	360

TABLE 80—*Continued*

SUBJECTS FOR LEBANESE BACCALAURÉAT EXAMINATIONS: PART II

Subject	Philosophy Section			Mathematics Section		
	Hours	Weighting	Total Marks	Hours	Weighting	Total Marks
Written examinations:						
Arabic composition in philosophy	4	3	60	3	2	40
Physics, chemistry, and biology	3	2	40	...	...	...
Physics and chemistry	...	...	...	4	3	60
Mathematics	...	...	...	4	3	60
French or English composition in philosophy	4	3	60	...	...	...
Oral examinations:						
Explanation of Arabic text in philosophy	...	2	40	...	1	20
History and geography	...	2	40	...	2	40
Physics and chemistry	...	1	20	...	3	60
Mathematics	...	1	20	...	3	60
Biology and hygiene	...	2	40	...	1	20
Philosophy in French or English	...	1	20	...	...	...
Explanation of French or English text in philosophy	...	2	40	...	1	20
Total	...	19	380	...	19	380

of 3 on Arabic and foreign language compositions, but a weighting of only 2 on mathematics. Inversely, the scientific section has a weighting of 3 on mathematics and science, but a weighting of only 2 on Arabic and foreign-language composition.

A candidate for the *baccalauréat* certificate is given a choice of an additional examination in modern foreign language, for which only the marks that are in excess of the passing mark of 50 percent are credited to his total marks.

In Arabic literature, Arabic philosophy, philosophy in the foreign language, mathematics, physics and chemistry, three questions in each are asked, out of which the student answers only one. In mathematics and science, however, an additional required question is set.

Papers or oral examinations are marked on the basis of zero to 20. In order to pass, a student must not receive a zero in any subject, and must get no less than 5 marks out of 20 in Arabic. The student must receive at least one-half of the possible marks in the written examination before he is allowed to enter the oral examination. He must aggregate at least 50 percent of the total marks in written and oral examinations before he finally passes and becomes eligible for the certificate. Students failing the oral examination in June may present themselves for oral examination in October. If they fail again, they must pass both the written and the oral examinations in subsequent years. A student gets a mention of "good" if he has received 14 out of 20 marks, and of "very good" if he has received 16 out of 20. A certificate signed by the Minister of National Education is given the student who passes the first part of the *baccalauréat* examination, while the diploma of the second part of the *baccalauréat* is signed by the President of the Republic.

The following are the results of the *baccalauréat* examinations in 1944–45 for the June and October sessions combined:

	Entered	Passed	Percent
Part I			
Literary section	329	188	57.1
Scientific section	437	249	57.0
Total	766	437	57.0
Part II			
Philosophy section	380	228	60.0
Mathematics section	96	60	62.5
Total	476	288	60.5

The Education of Primary Teachers

The education of primary-school teachers is undertaken in 2 rather small schools, 1 for men and 1 for women. The school for men is housed in a rented house, while that for women shares the same premises with a girls primary school which serves as its practice school. The 2 schools have essentially the same program of two years for which students are eligible after having secured their *brevet*. Students who have passed Part I or Part II of the *baccalauréat* examinations are also eligible. Admission is by a competitive examination. Holders of the *baccalauréat* certificate, Part II, are given an allowance of 20 marks, while those who have passed Part I are allowed 10 marks. No fees are charged. Allowances of £L90 (almost $41) a month are given to better students, and 44 out of a total of 85 students in both schools received such scholarships in 1945–46. It is hoped to grant scholarships to all out-of-town students in order to attract students from the villages.

TABLE 81

PROGRAM OF STUDIES FOR PREPARATION OF PRIMARY-SCHOOL TEACHERS, LEBANON, 1946

Subject	Periods per Week	
	1st Year	2nd Year
Psychology*	2	...
Ethics and civics*	2	...
Professional ethics and school administration*	...	1
Education*	...	1
Education†	...	1
Practice teaching*	1	3
Practice teaching†	1	3
Mathematics*	3	2
Science*	3	3
Arabic literature	5	2
French literature	5	2
History†	3 (History and Geography together)	1
Geography†		1
Sociology†	...	1
Manual arts	...	2
Drawing	2	2
Music	1	1
Physical education	1	1
Hygiene	...	1
Agriculture or home economics	1	2
Total	30	30

* Language of instruction is French.
† Language of instruction is Arabic.

The program of studies is shown in Table 81. Some of the courses are

given in Arabic, others in French, while some, such as education and practice teaching, are conducted in both French and Arabic.

The course is designed to prepare teachers who could, if need be, teach some subjects in French. Practice teaching takes place in both the first and second years and is supervised by the teachers of education. A summer course of one month is held for practical work and some lectures in agriculture and physical education. After graduating, students may enter the second year of the agricultural course in the School of Arts and Crafts, and upon graduation be appointed as teachers with an addition of £L15 ($6.82) per month to their salary.

The final examination for each year of the normal school is laid down by the Ministry of Education. It is also the qualifying examination for noncertificated teachers. The examination is in two parts corresponding to each year of study. Part I consists of Arabic literature, French literature, history and geography, ethics and civics, mathematics, psychology, and science. The examinations in Arabic, history and geography, and ethics and civics are conducted in Arabic; the others, in French. Part II comprises examinations in education (in Arabic), education (in French), history and geography (in Arabic), professional ethics (in French), and Arabic literature, French literature, and science and hygiene (in French). Three practical examinations are also held in which a candidate teaches one lesson in Arabic, one in French and one in physical education. In addition to the normal-school students, 20 candidates took the qualifying examination, Part I, and 12 took Part II in 1944–45. A new appointee has to stay on probation for at least one year before he is confirmed as a full-fledged teacher.

In 1945–46 there were 33 students in the first year and 17 in the second year of the normal school for men, and 22 in the first year and 13 in the second year in the normal school for women. It is evident that in view of the large number of primary schools now being opened, not enough teachers are being prepared.

The School of Arts and Crafts

The School of Arts and Crafts at Beirut was founded during the Ottoman regime, and, as was usual at that time, started as an orphanage. It occupies a large building erected by the Turkish authorities and is well equipped with workshops, particularly in the mechanical section. Students who hold the primary-school certificate, the certificate of the first *bac-*

calauréat, or the *brevet,* are admitted on the basis of the results of a competitive examination which is both written and oral. The written examination comprises French, Arabic, arithmetic, handwriting, and drawing, while the oral examination comprises geometry, geography, history, biology, and object lessons. The School had a total of 317 students in 1945–46, of whom 265 were boarders. Instruction and board were free, and day students received free lunch.

The School has three main courses: a mechanical course of four years' duration, a weaving course of two years' duration, and an agricultural course which has been lengthened from two to three years. The mechanical and weaving sections admit holders of the primary-school certificate, and the agricultural section admits holders of the *brevet* or first *baccalauréat.*

The mechanical section gives instruction in the first two years in carpentry, blacksmithing, and fitting. Students get practical and theoretical instruction in these three specialties. Specialization begins in the third year, and the student may take one of the following seven specialties: auto mechanics, turning, blacksmithing, welding, foundry, woodcarving, and electricity. The latter includes radio, telegraph, and telephone. In addition, students receive throughout the course instruction in the following "theoretical" courses: arithmetic, geometry, algebra, physics, chemistry, general and applied mechanics, industrial drawing, technology as applied to machines, French, Arabic, history, geography, and industrial bookkeeping.

Instruction in the mechanical section is divided almost equally between theory and shopwork, except for the last year when shopwork is predominant. In each of the first two years approximately 600 hours of shopwork are divided among carpentry, blacksmithing, and fitting. In the third year each subject of specialization is allowed 800 hours, while in the fourth year the total shopwork for each specialization is 1,100 hours. Laboratory work is given in both physics and chemistry. The mechanical section is the most popular among the students, accounting for 246 out of a total of 317 students.

In the weaving section, the program is less theoretical and more practical. In the first year about 50 hours are given to theoretical work in weaving, while in the second year the total of theoretical work is 150 hours. Shopwork receives 1,100 hours in each of the two years. Only 38 students were registered in the course in 1945–46.

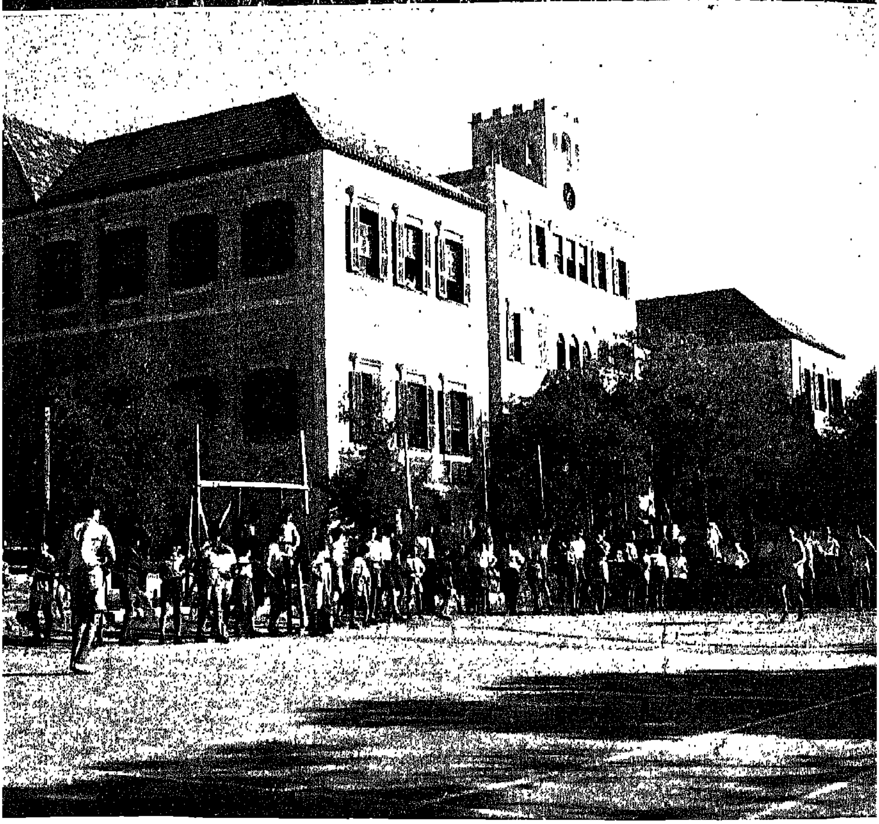
The agricultural section, giving a two-year course, was only two years old in 1946. At that time 33 students were registered, and the course was





Above: Some of the students in the preparatory department of the American University of Beirut, some in native costumes, some in Western clothes. These youths come from various parts of the Arabian peninsula
Below: Students approaching Rockefeller Hall of the American University of Beirut. This building, erected in 1910, was the gift of John D. Rockefeller, Sr.





Above: This view of the campus of the American University of Beirut shows the natural beauties of its location. At the left is the observatory, and at the right College Hall
Below: American School for Boys, Tripoli, Lebanon. Upper classmen in a tennis match. Outdoor sports are prominent in this school; all students participate in some sport

being reorganized into a three-year course. Some teachers and graduates of the normal schools have been encouraged to enter the second year in order to become teachers in the rural schools. The school has no land for practical work.

Students of all three sections take an examination given by the School at the end of their study. Graduates of the School of Arts and Crafts are in demand, and are employed by the army, aviation workshops, the railroads, and electrical plants.

Chapter 26

FRENCH SCHOOLS

AMONG FOREIGN schools in Lebanon, French schools are the most numerous, in 1942–43 numbering 273 schools out of a total of 326. These had a total student registration of 39,513 out of 46,726 in all foreign institutions during that year.[1]

French missionary and educational activities have a long history in Lebanon. Late in the sixteenth and early in the seventeenth centuries Franciscan, Capucin, and Jesuit missionaries came to Syria and began to establish missionary posts in various parts of the country. The Jesuits were perhaps the most active. They established their first mission in Aleppo in 1628, which was followed by other missions in Damascus, Tripoli, Sidon, and 'Anturah. The latter, founded in 1636, still has a well-known college which will be described later. The fact that Lebanon had a large community of Maronites, who had centuries before acknowledged the authority of the Church of Rome, facilitated the entry of Catholic missions to Lebanon, and connection with the Maronite community is intimate up to the present day.

The early missionaries usually established a small school at each of their stations. They taught the rudiments of reading, writing, and arithmetic, catechism, and liturgy, occasionally teaching also French or Latin. At the same time some of the brighter pupils were sent to the Oriental Seminary in Rome where they took advanced studies in philosophy and theology, and sometimes became well-known scholars. At one time Louis XIV, upon the advice of his minister Colbert, brought at state expense oriental Christian children to Paris to study in the Collège Louis-le-Grand which was then under the direction of the Jesuits. It was these activities that eventually led to schisms among the oriental churches resulting in the establishment of a Catholic branch of each of the existing oriental churches.

The activities of Catholic missions were mainly missionary in the first

[1] See Table 74, p. 424.

two centuries, and it was not until the nineteenth century that educational work of an advanced sort began to be given. The college at 'Anturah was perhaps the first to be established along modern lines. It was founded in 1834 under the Lazarist order, which had taken over the station upon the closing of the Jesuit order in the middle of the eighteenth century. Not long afterward the Jesuits established a Catholic seminary (1846) and a secondary school (1855) at Ghazir to the northeast of Beirut in the same general region as 'Anturah. This seminary was later moved to Beirut and formed the nucleus of the present secondary school, the Oriental Seminary, and the Faculty of Theology at the French Jesuit Université Saint-Joseph. The University itself was founded in 1875. Other missionary orders also began to come in, and their activities increased particularly when the French mandate over Syria and Lebanon was established after World War I. Feeling that French missionary activity was giving a colored impression of France abroad and that it did not express the true spirit of modern France, some French laymen established a lay mission (Mission Laïque) which opened a school for boys, and a school for girls in Beirut in 1909. Other similar schools were later established in Damascus, Aleppo, and Tartus, all in Syria. The French mandatary government, anxious to spread the French language and culture and to bring up a generation which would sympathize with France and its position in Syria and Lebanon, encouraged French missionary activities to a large extent and gave subsidies to the large number of orders active in Syria and Lebanon. Among these may be cited the Jesuits, who have the largest number of schools, the Lazarists, the Capucins, the Franciscans, the Christian Brothers, and the Frères Maristes. Among the orders of nuns may be cited les Filles de la Charité, les Dames de Nazareth, les Sœurs de la Sainte Famille, les Sœurs de la Charité, les Sœurs de Besançon, and the Franciscan nuns of Mary. All these orders had schools, not only in the large cities such as Beirut and Tripoli, but some, especially the Jesuits, had (and still have) elementary schools even in remote villages. These schools did not come under the authority of the Lebanese government Department of Education (later Ministry of Education). They communicated directly with the Office of the French Adviser in the Haut Commissariat Français. Indeed, the Lebanese government had no authority over foreign schools in the days of the mandate. During World War II, financial resources from the mother country were cut off. French schools, therefore, had to rely very largely upon their income from tuition and upon some help from the Œuvres Françaises, a semiofficial organization which tried to keep up French

cultural work abroad. This was still the situation at the time of the visit of the American Council Commission to Lebanon.

It was not possible for the Commission to visit even one example from each type of French schools in Lebanon. Aside from the schools of the Mission Laïque and the Collège Protestant Français, however, the pattern of the French missionary schools is substantially the same. The success of their work is shown by the large number of Lebanese men and women, especially Catholics, who speak French fluently, and some of whom think, speak, and write in French even more easily than they do in their native Arabic.

The large French schools usually have primary and secondary departments combined on the same premises so that the primary grades are actually preparatory to the secondary, or *lycée,* sections, in much the same way as is the general practice in France. They are usually fee-charging institutions, the fees ranging from £L100 ($45) to £L350 ($160) for tuition, on an ascending scale from the lowest primary to the highest secondary grade. Boarding fees may range between £L600 and £L750 ($275 to $344). Some of the orders, however, maintain special primary schools for poor children where instruction is free. This separation of the poor children from those who can pay seems to be a fairly prevalent practice.

The staffs of the schools are usually both French and Lebanese, the proportion varying. The number of Frenchmen may constitute as many as one-half and sometimes as low as one-third. A large part of the staff of missionary schools consists of monks or nuns who receive no pay for their services and cost only their maintenance. The rest are laymen, usually Lebanese. In spite of this, fees are usually higher than those charged in native schools. Some of the money seems to be spent on the schools for poor children, as well as on maintaining the work of the mission. Some missions have been known to save some money for future expansion of, and building programs for, the schools. At one time the Jesuits had their own normal school for the training of teachers for their village schools. This, however, has been discontinued.

The schools visited by the Commission were housed, on the whole, in good buildings, with spacious quarters, usually large classrooms, and more or less adequate yard-space for recreation periods, though not enough provision had been made for playgrounds for athletic activities. The better schools were usually well equipped with libraries, and some of them had laboratories and natural history museums. Boarding facilities

were usually in large dormitories. Naturally, village schools were not so well equipped.

On the whole the schools enjoy great prestige, particularly among the Christians and those of higher economic status. This is especially true of the schools maintained by the nuns for the education of girls. About seven-eighths of the students in French schools are Christian. Out of a total of 39,513 students in French schools in 1942–43, 34,758 were Christian, 2,507 were Muslim, 1,544 were Jews, 631 were Druze, 73 were of other religions. Among the Christian students the majority were Catholic.

Program of Studies

The program of studies is primarily that used in France, preparing students for the French certificate of primary studies, the French *brevet,* or the French *baccalauréat.* As the schools must prepare a certain section of their students for the Lebanese examinations as well, certain modifications are introduced to adapt it for that purpose. The difference lies mainly in Arabic language, Lebanese and Arab history and geography, and in the introduction of a course in Arabic philosophy. For the rest the two programs are largely similar. Indeed, the comparison of the new secondary courses of study of the Lebanese government with the French program of secondary education shows great similarity, and some subjects, such as logic and ethics, are identical. In the days of the mandate, the Education Department of the Haut Commissariat issued a magazine, the *Bulletin de l'Enseignement,* in which it published regularly the decrees and *arrêtés* of the French Minister of National Education dealing with courses of study, examinations, and other school matters, so as to keep the French schools informed on developments in France. As educational practices were gradually modified in France, the French schools in Lebanon and Syria followed suit as a matter of course.

Some of the schools take children at the early age of four or five and put them in a *classe enfantine.* As they begin to learn the letters of the alphabet, they promote them to a prefirst grade (called the twelfth class —*douzième*). The formal first grade is the *onzième.* The primary school consists of five grades divided into three courses, the preparatory course in the first grade, the elementary in the second and third grades (*dixième* and *neuvième*), and the middle course (*cours moyen*) in the fourth and fifth grades (*huitième* and *septième*). After this, a student in good standing may pass to the secondary grades of his own school without hav-

TABLE 80

SUBJECTS FOR LEBANESE BACCALAURÉAT EXAMINATIONS: PART I

Subject	Literary Section			Scientific Section			Classical-Languages Section		
	Hours	Weighting	Total Marks	Hours	Weighting	Total Marks	Hours	Weighting	Total Marks
Written examinations:									
Arabic composition	3	3	60	3	2	40	3	2	40
Mathematics	3	2	40	3	3	60	...	...	...
Arabic literary criticism, or translation, or translation from Latin	3	2	40	...	...	...	...	...	..
French or English composition	3	3	60	3	2	40	3	2	40
Translations from and to a classical language	...	...	...	...	...	...	3	3	60
Physics and chemistry	...	...	...	3	3	60	...	...	..
Oral examinations:									
Explanation of an Arabic text	...	3	60	...	2	40	...	2	40
History and geography	...	2	40	...	1	20	...	3	60
Mathematics	...	1	20	...	3	60	...	1	20
Physics and chemistry	...	1	20	...	3	60	...	...	...
Explanation of a French or English text	...	3	60	...	1	20	...	2	40
Explanation of a classical language text	...	...	...	...	...	...	...	3	60
Total	...	20	400	...	20	400	...	18	360

TABLE 80—*Continued*

SUBJECTS FOR LEBANESE BACCALAURÉAT EXAMINATIONS: PART II

Subject	Philosophy Section			Mathematics Section		
	Hours	Weighting	Total Marks	Hours	Weighting	Total Marks
Written examinations:						
Arabic composition in philosophy	4	3	60	3	2	40
Physics, chemistry, and biology	3	2	40	...	...	...
Physics and chemistry	...	...	...	4	3	60
Mathematics	...	...	...	4	3	60
French or English composition in philosophy	4	3	60	...	...	...
Oral examinations:						
Explanation of Arabic text in philosophy	...	2	40	...	1	20
History and geography	...	2	40	...	2	40
Physics and chemistry	...	1	20	...	3	60
Mathematics	...	1	20	...	3	60
Biology and hygiene	...	2	40	...	1	20
Philosophy in French or English	...	1	20	...	...	...
Explanation of French or English text in philosophy	...	2	40	...	1	20
Total	...	19	380	...	19	380

of 3 on Arabic and foreign language compositions, but a weighting of only 2 on mathematics. Inversely, the scientific section has a weighting of 3 on mathematics and science, but a weighting of only 2 on Arabic and foreign-language composition.

A candidate for the *baccalauréat* certificate is given a choice of an additional examination in modern foreign language, for which only the marks that are in excess of the passing mark of 50 percent are credited to his total marks.

In Arabic literature, Arabic philosophy, philosophy in the foreign language, mathematics, physics and chemistry, three questions in each are asked, out of which the student answers only one. In mathematics and science, however, an additional required question is set.

Papers or oral examinations are marked on the basis of zero to 20. In order to pass, a student must not receive a zero in any subject, and must get no less than 5 marks out of 20 in Arabic. The student must receive at least one-half of the possible marks in the written examination before he is allowed to enter the oral examination. He must aggregate at least 50 percent of the total marks in written and oral examinations before he finally passes and becomes eligible for the certificate. Students failing the oral examination in June may present themselves for oral examination in October. If they fail again, they must pass both the written and the oral examinations in subsequent years. A student gets a mention of "good" if he has received 14 out of 20 marks, and of "very good" if he has received 16 out of 20. A certificate signed by the Minister of National Education is given the student who passes the first part of the *baccalauréat* examination, while the diploma of the second part of the *baccalauréat* is signed by the President of the Republic.

The following are the results of the *baccalauréat* examinations in 1944–45 for the June and October sessions combined:

	Entered	Passed	Percent
Part I			
Literary section	329	188	57.1
Scientific section	437	249	57.0
Total	766	437	57.0
Part II			
Philosophy section	380	228	60.0
Mathematics section	96	60	62.5
Total	476	288	60.5

The Education of Primary Teachers

The education of primary-school teachers is undertaken in 2 rather small schools, 1 for men and 1 for women. The school for men is housed in a rented house, while that for women shares the same premises with a girls primary school which serves as its practice school. The 2 schools have essentially the same program of two years for which students are eligible after having secured their *brevet.* Students who have passed Part I

TABLE 81

Program of Studies for Preparation of Primary-School Teachers, Lebanon, 1946

Subject	Periods per Week	
	1st Year	2nd Year
Psychology*	2	...
Ethics and civics*	2	...
Professional ethics and school administration*	...	1
Education*	...	1
Education†	...	1
Practice teaching*	1	3
Practice teaching†	1	3
Mathematics*	3	2
Science*	3	3
Arabic literature	5	2
French literature	5	2
History†	3 (History and Geography together)	1
Geography†		1
Sociology†	...	1
Manual arts	...	2
Drawing	2	2
Music	1	1
Physical education	1	1
Hygiene	...	1
Agriculture or home economics	1	2
Total	30	30

* Language of instruction is French.
† Language of instruction is Arabic.

or Part II of the *baccalauréat* examinations are also eligible. Admission is by a competitive examination. Holders of the *baccalauréat* certificate, Part II, are given an allowance of 20 marks, while those who have passed Part I are allowed 10 marks. No fees are charged. Allowances of £L90 (almost $41) a month are given to better students, and 44 out of a total of 85 students in both schools received such scholarships in 1945–46. It is hoped to grant scholarships to all out-of-town students in order to attract students from the villages.

The program of studies is shown in Table 81. Some of the courses are

given in Arabic, others in French, while some, such as education and practice teaching, are conducted in both French and Arabic.

The course is designed to prepare teachers who could, if need be, teach some subjects in French. Practice teaching takes place in both the first and second years and is supervised by the teachers of education. A summer course of one month is held for practical work and some lectures in agriculture and physical education. After graduating, students may enter the second year of the agricultural course in the School of Arts and Crafts, and upon graduation be appointed as teachers with an addition of £L15 ($6.82) per month to their salary.

The final examination for each year of the normal school is laid down by the Ministry of Education. It is also the qualifying examination for noncertificated teachers. The examination is in two parts corresponding to each year of study. Part I consists of Arabic literature, French literature, history and geography, ethics and civics, mathematics, psychology, and science. The examinations in Arabic, history and geography, and ethics and civics are conducted in Arabic; the others, in French. Part II comprises examinations in education (in Arabic), education (in French), history and geography (in Arabic), professional ethics (in French), and Arabic literature, French literature, and science and hygiene (in French). Three practical examinations are also held in which a candidate teaches one lesson in Arabic, one in French and one in physical education. In addition to the normal-school students, 20 candidates took the qualifying examination, Part I, and 12 took Part II in 1944–45. A new appointee has to stay on probation for at least one year before he is confirmed as a full-fledged teacher.

In 1945–46 there were 33 students in the first year and 17 in the second year of the normal school for men, and 22 in the first year and 13 in the second year in the normal school for women. It is evident that in view of the large number of primary schools now being opened, not enough teachers are being prepared.

The School of Arts and Crafts

The School of Arts and Crafts at Beirut was founded during the Ottoman regime, and, as was usual at that time, started as an orphanage. It occupies a large building erected by the Turkish authorities and is well equipped with workshops, particularly in the mechanical section. Students who hold the primary-school certificate, the certificate of the first *bac-*

calauréat, or the *brevet,* are admitted on the basis of the results of a competitive examination which is both written and oral. The written examination comprises French, Arabic, arithmetic, handwriting, and drawing, while the oral examination comprises geometry, geography, history, biology, and object lessons. The School had a total of 317 students in 1945–46, of whom 265 were boarders. Instruction and board were free, and day students received free lunch.

The School has three main courses: a mechanical course of four years' duration, a weaving course of two years' duration, and an agricultural course which has been lengthened from two to three years. The mechanical and weaving sections admit holders of the primary-school certificate, and the agricultural section admits holders of the *brevet* or first *baccalauréat.*

The mechanical section gives instruction in the first two years in carpentry, blacksmithing, and fitting. Students get practical and theoretical instruction in these three specialties. Specialization begins in the third year, and the student may take one of the following seven specialties: auto mechanics, turning, blacksmithing, welding, foundry, woodcarving, and electricity. The latter includes radio, telegraph, and telephone. In addition, students receive throughout the course instruction in the following "theoretical" courses: arithmetic, geometry, algebra, physics, chemistry, general and applied mechanics, industrial drawing, technology as applied to machines, French, Arabic, history, geography, and industrial bookkeeping.

Instruction in the mechanical section is divided almost equally between theory and shopwork, except for the last year when shopwork is predominant. In each of the first two years approximately 600 hours of shopwork are divided among carpentry, blacksmithing, and fitting. In the third year each subject of specialization is allowed 800 hours, while in the fourth year the total shopwork for each specialization is 1,100 hours. Laboratory work is given in both physics and chemistry. The mechanical section is the most popular among the students, accounting for 246 out of a total of 317 students.

In the weaving section, the program is less theoretical and more practical. In the first year about 50 hours are given to theoretical work in weaving, while in the second year the total of theoretical work is 150 hours. Shopwork receives 1,100 hours in each of the two years. Only 38 students were registered in the course in 1945–46.

The agricultural section, giving a two-year course, was only two years old in 1946. At that time 33 students were registered, and the course was

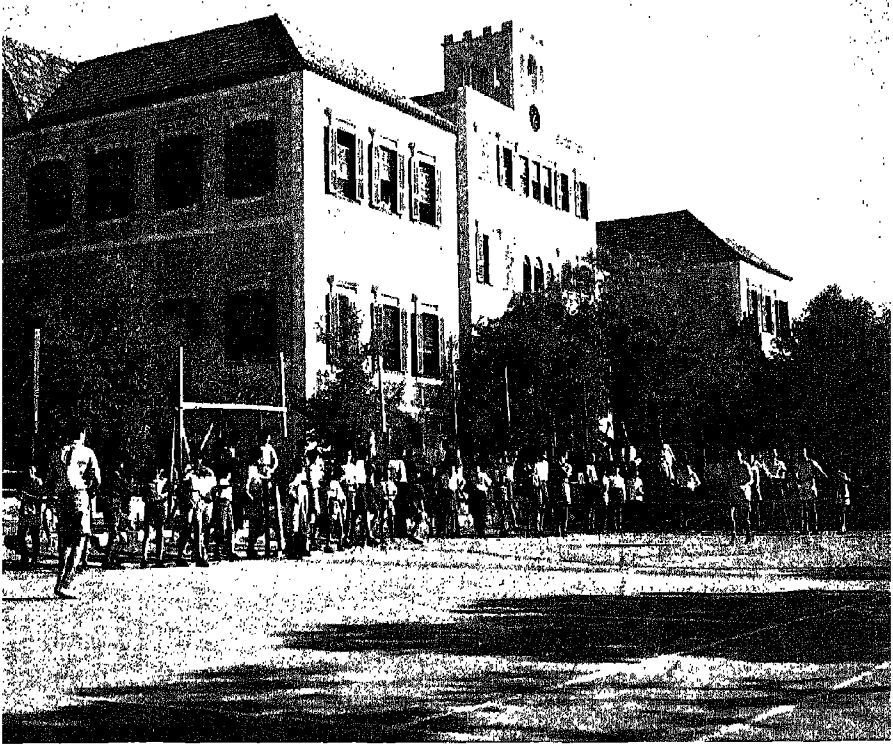




Above: Some of the students in the preparatory department of the American University of Beirut, some in native costumes, some in Western clothes. These youths come from various parts of the Arabian peninsula

Below: Students approaching Rockefeller Hall of the American University of Beirut. This building, erected in 1910, was the gift of John D. Rockefeller, Sr.





Above: This view of the campus of the American University of Beirut shows the natural beauties of its location. At the left is the observatory, and at the right College Hall
Below: American School for Boys, Tripoli, Lebanon. Upper classmen in a tennis match. Outdoor sports are prominent in this school: all students participate in some sport

being reorganized into a three-year course. Some teachers and graduates of the normal schools have been encouraged to enter the second year in order to become teachers in the rural schools. The school has no land for practical work.

Students of all three sections take an examination given by the School at the end of their study. Graduates of the School of Arts and Crafts are in demand, and are employed by the army, aviation workshops, the railroads, and electrical plants.

Chapter 26

FRENCH SCHOOLS

Among foreign schools in Lebanon, French schools are the most numerous, in 1942–43 numbering 273 schools out of a total of 326. These had a total student registration of 39,513 out of 46,726 in all foreign institutions during that year.[1]

French missionary and educational activities have a long history in Lebanon. Late in the sixteenth and early in the seventeenth centuries Franciscan, Capucin, and Jesuit missionaries came to Syria and began to establish missionary posts in various parts of the country. The Jesuits were perhaps the most active. They established their first mission in Aleppo in 1628, which was followed by other missions in Damascus, Tripoli, Sidon, and 'Anturah. The latter, founded in 1636, still has a well-known college which will be described later. The fact that Lebanon had a large community of Maronites, who had centuries before acknowledged the authority of the Church of Rome, facilitated the entry of Catholic missions to Lebanon, and connection with the Maronite community is intimate up to the present day.

The early missionaries usually established a small school at each of their stations. They taught the rudiments of reading, writing, and arithmetic, catechism, and liturgy, occasionally teaching also French or Latin. At the same time some of the brighter pupils were sent to the Oriental Seminary in Rome where they took advanced studies in philosophy and theology, and sometimes became well-known scholars. At one time Louis XIV, upon the advice of his minister Colbert, brought at state expense oriental Christian children to Paris to study in the Collège Louis-le-Grand which was then under the direction of the Jesuits. It was these activities that eventually led to schisms among the oriental churches resulting in the establishment of a Catholic branch of each of the existing oriental churches.

The activities of Catholic missions were mainly missionary in the first

[1] See Table 74, p. 424.

two centuries, and it was not until the nineteenth century that educational work of an advanced sort began to be given. The college at 'Anturah was perhaps the first to be established along modern lines. It was founded in 1834 under the Lazarist order, which had taken over the station upon the closing of the Jesuit order in the middle of the eighteenth century. Not long afterward the Jesuits established a Catholic seminary (1846) and a secondary school (1855) at Ghazir to the northeast of Beirut in the same general region as 'Anturah. This seminary was later moved to Beirut and formed the nucleus of the present secondary school, the Oriental Seminary, and the Faculty of Theology at the French Jesuit Université Saint-Joseph. The University itself was founded in 1875. Other missionary orders also began to come in, and their activities increased particularly when the French mandate over Syria and Lebanon was established after World War I. Feeling that French missionary activity was giving a colored impression of France abroad and that it did not express the true spirit of modern France, some French laymen established a lay mission (Mission Laïque) which opened a school for boys, and a school for girls in Beirut in 1909. Other similar schools were later established in Damascus, Aleppo, and Tartus, all in Syria. The French mandatary government, anxious to spread the French language and culture and to bring up a generation which would sympathize with France and its position in Syria and Lebanon, encouraged French missionary activities to a large extent and gave subsidies to the large number of orders active in Syria and Lebanon. Among these may be cited the Jesuits, who have the largest number of schools, the Lazarists, the Capucins, the Franciscans, the Christian Brothers, and the Frères Maristes. Among the orders of nuns may be cited les Filles de la Charité, les Dames de Nazareth, les Sœurs de la Sainte Famille, les Sœurs de la Charité, les Sœurs de Besançon, and the Franciscan nuns of Mary. All these orders had schools, not only in the large cities such as Beirut and Tripoli, but some, especially the Jesuits, had (and still have) elementary schools even in remote villages. These schools did not come under the authority of the Lebanese government Department of Education (later Ministry of Education). They communicated directly with the Office of the French Adviser in the Haut Commissariat Français. Indeed, the Lebanese government had no authority over foreign schools in the days of the mandate. During World War II, financial resources from the mother country were cut off. French schools, therefore, had to rely very largely upon their income from tuition and upon some help from the Œuvres Françaises, a semiofficial organization which tried to keep up French

cultural work abroad. This was still the situation at the time of the visit of the American Council Commission to Lebanon.

It was not possible for the Commission to visit even one example from each type of French schools in Lebanon. Aside from the schools of the Mission Laïque and the Collège Protestant Français, however, the pattern of the French missionary schools is substantially the same. The success of their work is shown by the large number of Lebanese men and women, especially Catholics, who speak French fluently, and some of whom think, speak, and write in French even more easily than they do in their native Arabic.

The large French schools usually have primary and secondary departments combined on the same premises so that the primary grades are actually preparatory to the secondary, or *lycée,* sections, in much the same way as is the general practice in France. They are usually fee-charging institutions, the fees ranging from £L100 ($45) to £L350 ($160) for tuition, on an ascending scale from the lowest primary to the highest secondary grade. Boarding fees may range between £L600 and £L750 ($275 to $344). Some of the orders, however, maintain special primary schools for poor children where instruction is free. This separation of the poor children from those who can pay seems to be a fairly prevalent practice.

The staffs of the schools are usually both French and Lebanese, the proportion varying. The number of Frenchmen may constitute as many as one-half and sometimes as low as one-third. A large part of the staff of missionary schools consists of monks or nuns who receive no pay for their services and cost only their maintenance. The rest are laymen, usually Lebanese. In spite of this, fees are usually higher than those charged in native schools. Some of the money seems to be spent on the schools for poor children, as well as on maintaining the work of the mission. Some missions have been known to save some money for future expansion of, and building programs for, the schools. At one time the Jesuits had their own normal school for the training of teachers for their village schools. This, however, has been discontinued.

The schools visited by the Commission were housed, on the whole, in good buildings, with spacious quarters, usually large classrooms, and more or less adequate yard-space for recreation periods, though not enough provision had been made for playgrounds for athletic activities. The better schools were usually well equipped with libraries, and some of them had laboratories and natural history museums. Boarding facilities

were usually in large dormitories. Naturally, village schools were not so well equipped.

On the whole the schools enjoy great prestige, particularly among the Christians and those of higher economic status. This is especially true of the schools maintained by the nuns for the education of girls. About seven-eighths of the students in French schools are Christian. Out of a total of 39,513 students in French schools in 1942–43, 34,758 were Christian, 2,507 were Muslim, 1,544 were Jews, 631 were Druze, 73 were of other religions. Among the Christian students the majority were Catholic.

Program of Studies

The program of studies is primarily that used in France, preparing students for the French certificate of primary studies, the French *brevet,* or the French *baccalauréat.* As the schools must prepare a certain section of their students for the Lebanese examinations as well, certain modifications are introduced to adapt it for that purpose. The difference lies mainly in Arabic language, Lebanese and Arab history and geography, and in the introduction of a course in Arabic philosophy. For the rest the two programs are largely similar. Indeed, the comparison of the new secondary courses of study of the Lebanese government with the French program of secondary education shows great similarity, and some subjects, such as logic and ethics, are identical. In the days of the mandate, the Education Department of the Haut Commissariat issued a magazine, the *Bulletin de l'Enseignement,* in which it published regularly the decrees and *arrêtés* of the French Minister of National Education dealing with courses of study, examinations, and other school matters, so as to keep the French schools informed on developments in France. As educational practices were gradually modified in France, the French schools in Lebanon and Syria followed suit as a matter of course.

Some of the schools take children at the early age of four or five and put them in a *classe enfantine.* As they begin to learn the letters of the alphabet, they promote them to a prefirst grade (called the twelfth class —*douzième*). The formal first grade is the *onzième.* The primary school consists of five grades divided into three courses, the preparatory course in the first grade, the elementary in the second and third grades (*dixième* and *neuvième*), and the middle course (*cours moyen*) in the fourth and fifth grades (*huitième* and *septième*). After this, a student in good standing may pass to the secondary grades of his own school without hav-

ing to pass a government examination. Pupils coming from other schools are examined by the school they are entering, for the purpose of placing them in the appropriate grade. The secondary course is of seven years, divided into a first cycle of grades one to four (*sixième* to *troisième*), and a second cycle, the first two years of which (*seconde* and *première*) lead to the *baccalauréat* examination, first part, and the third year (*classes de philosophie et de mathématique*) leads to the second part of the *baccalauréat* examination.

The French program followed is generally that of *Série B*, which is the program without classical languages and with some emphasis upon foreign languages and the sciences. The only exception to this is the pro-

TABLE 82

DISTRIBUTION OF PERIODS IN TWO GRADES OF THE LYCÉE FRANÇAIS OF THE MISSION LAÏQUÉ, BEIRUT, 1946

Fifth Primary Grade		Fourth Secondary Year	
Subject	Hours per Week	Subject	Hours per Week
Arabic	8	Arabic	8
Moral and civic education	1½	Morals and civics	1
French language	6½	French	6
General history and geography	2	Foreign language	4
Arithmetic and the metric system	4	History and geography	3
Object lessons	2	Mathematics and drawing	4
Drawing and manual arts	2	Physiology and natural sciences	3
Physical education	1½	Physical education	1
Singing	1		
Total	28½	Total	30

gram of the Collège Secondaire of the Jesuit Université Saint-Joseph which follows *Série A*, including Latin and a foreign language, but no Greek. The same school, however, also gives the other courses of *Série B*. The foreign language taught is usually English and is begun in the first secondary grade (*sixième*), but it may also be German, Italian, or some other modern language. It is not necessary to give full details of the French program here. Adaptation to the local needs of Lebanon is well exemplified by the Lebanese program of studies. As far as the French schools themselves are concerned, however, this differs from school to school. Table 82 shows an example of the adaptation worked out in one primary and one secondary class.

It is interesting to note that the differences between complementary classes (the last two years of the higher primary school) and the lower secondary classes have been virtually obliterated, and the complementary classes are often referred to as secondary. More than one school refers

to the first cycle of the secondary school as ending with the *brevet* examination, which originally was the examination ending the higher primary studies. This is in accord with the new tendencies in French education, but seems to have been easier to apply owing to the much less complicated situation in Lebanon, where class distinctions are not as marked and the tradition of classical studies has not developed.

A number of schools such as the schools of the Christian Brothers, in Beirut and Tripoli, and the Lycée Français and others maintain a commercial course beyond the fourth secondary year which extends from two to three years and leads to the higher diploma of commerce, and a certificate of bookkeeping. Table 83 gives the program given at the school of the Christian Brothers.

TABLE 83

PROGRAM OF STUDIES FOR THE COMMERCIAL SECTION, LYCÉE FRANÇAIS, TRIPOLI, LEBANON, 1946

Subject	Length of Period (Minutes)	Periods per Week		
		1st Grade	2nd Grade	3rd Grade
French	45	6	6	6
Commerce and bookkeeping	75	6	6	6
Commercial and financial mathematics	60	6	6	6
Arabic	60	6	6	6
English	60	5	5	5
Economic geography and history of commerce	60	3	3	3
Merchandising	60	2	2	2
Stenography	30	6	(*)	(*)
Typewriting	30	(*)	(*)	(*)
Commercial law	20	1	1	1
Political economy	20	1	1	1

* Practice as much as possible out of class.

Students are supposed to practice outside school hours, especially on Thursday afternoons. Some of the better students do the work in two years. Others take an additional year in order to prepare for the *baccalauréat* examinations.

Methods

Methods of administration and teaching are the same as those prevailing in France. Beside the director of the school, there is usually a supervisor *(surveillant)* who has charge of the discipline, attendance of students, and the entrance and leaving of classes. The major subjects usually have directors of studies; this is particularly true of the two languages, French and Arabic. Their job is to see that teaching in their subjects is properly planned and executed. The teaching is essentially subject-matter

teaching. Point by point, and topic by topic, the subject matter is systematically imparted to the students, reviewed and reviewed again, particularly in the teaching of languages and of arithmetic. Extensive use is made of exercises and homework. Much attention is given to penmanship and to the neatness of notebooks. Notebooks are collected almost daily, graded by the teacher (usually on the basis of 1 to 10), and returned to the children, after which the children take them home. Parents are constantly requested to take an interest in the marks the children receive and in the work they are doing, and are entreated to encourage diligence and to spur them on to better work. About once a month the average of the marks is taken and the students' standing in the class is worked out.

School examinations take place usually three or four times a year, and the results are made known to the parents through the student's report card. This is sent to the parents for their inspection, and they are sometimes asked to sign it in order to make sure that they have examined it. Irregular attendance, tardiness, and negligence result in lowering the marks and standing of the student. In some schools what is known as the *cahier d'honneur* is kept in each class. In this notebook the best achievement by any student in the class and in every topic studied is registered. By the end of the year this book would represent the ground covered by the class and the highest achievements attained.

Great attention is given to the teaching of French. The program is comparable to that given in France, and essentially the same standards of achievement are required. The fact that a large number of students pass the French primary and *baccalauréat* examinations is the best testimony that such a result is achieved. Instruction in French begins with the *classe enfantine*. Gradually the children build up a speaking vocabulary and learn to recognize the letters of the alphabet. Regular reading begins usually with the first grade *(onzième)*. Almost everything is taught in French except the lessons in Arabic and in local geography and history. Conversation in the classes and on the school grounds is in French. In some schools the speaking of French on the school grounds is obligatory and the speaking of Arabic is an offense. Thus, in both formal and informal ways, in work as in play, the students cannot help absorbing French from the very atmosphere of the schools. Before they are graduated from secondary school, students learn not only the basic structure of the language and acquire a good reading knowledge of it, but also speak it fluently and are able to write essays in French in a good style. Some of the outstanding students have been known to write French poetry and some artistic pieces of prose.

The French schools are usually accused of giving less attention to Arabic, and their graduates are said to be less at home in the knowledge of Arabic literature and composition than in French. The accusation is made that the nature of the French examinations tends to encourage this weakness, for as long as a student receives the sum total of marks required for the examinations, he can pass, provided he does not receive a zero in any subject. Theoretically it is possible, therefore, for a pupil to get 1 mark out of 20 in Arabic and still pass. This criticism, however, is too general to apply to all schools. Some of the better schools maintain a high standard of Arabic and have produced a number of Arab poets and writers. Much the same criticism is made with regard to the history and geography of Lebanon and the Arab world. The students are said to know more about the history, geography, and literature of France than of their own country.

While the laboratories of some of the schools are fairly well equipped they do not seem to be adequately used. The Commission did not see a laboratory class in any of the French schools they visited, although this might have been an accident. The apparatus did not look as if it was regularly used. Better use is made of charts, especially for the study of zoology, botany, geology, and human anatomy and hygiene. The texts in use, except for the subjects taught in Arabic or for local subjects, are the same as those used in France. When the supply of books was cut off during the war, special editions were printed by the Œuvres Françaises in Cairo and Beirut and distributed to the schools.

In the French Catholic missionary schools, discipline is very strict. The students are constantly supervised, and boarders are allowed to go out only with their parent or guardians. Only their parents or persons authorized by the parents may visit them at school. The school may take an outing about once a week, usually on Sundays, under the supervision of the director and teachers. No student is allowed to bring into the school any book, magazine, pamphlet, or paper except the books directly in use at the school. In this way an attempt is made to shut out outside influences as much as possible. A long timetable keeps the day students at school from early morning until the late afternoon. The atmosphere of the Catholic schools is decidedly religious. Students are required to attend Mass every morning. Classes usually begin and end with prayers, and Sunday Mass and religious teaching are obligatory. Irreligion, insubordination, immorality, or even habitual laziness are reasons for expulsion.

The following daily timetable for boarding and day students at ʻAnturah, although perhaps not universal, shows the type of daily disposition of work current in the Catholic missionary schools:

Hour	Activity: Boarding Students	Activity: Day Students
5:00 A.M.	Get up	. . .
5:30	Mass	. . .
6:00	Study period	. . .
7:00	Breakfast	Obligatory Mass
7:15	Recess	
7:30	Class	Class
9:00	Recess	Recess
9:15	Study period	Study period
9:45	Class	Class
10:45	Recess	Recess
11:00	Study period	Study period
11:55		Lunch period
12:00	Lunch	
12:30 P.M.	Recess	
1:20		Assembly in the court yard
1:30*	Study period	Study period
2:00	Class	Class
3:00	Recess	Recess
3:15	Study period	Study period
4:15	Recess and *goûter*	Recess and *goûter*
4:45	Study period, classes	
5:45		Middle and lower grade students go home
7:25	Evening prayer in chapel, dinner	Secondary students go home
8:00	Required study period for *baccalauréat* classes	

* Outings on Thursdays, 1:30 to 4:15, and on Sundays, 1:30 to 4:30.

Other French schools, such as those of the Christian Brothers, maintain a somewhat shorter day for the day pupils, starting at 7:15 or 7:30 and ending about 4:30 or 5:00. It is evident that the daily timetable is so long that the students are kept busy throughout the day and that supervision of their activities is constant and unwavering. Attendance on Thursdays and Sundays is in the morning only. On Sundays students attend Mass and also attend classes in religion and, in some schools, classes in drawing and singing.

A different disciplinary atmosphere prevails in the non-Catholic French schools, such as those of the Mission Laïque, and the French Protestant missions. In the words of the director of the French Lycée for boys in Beirut, "Our methods of discipline are inspired by a reasoned indulgence toward those faults which are due more to spontaneity than to premeditation. We repudiate brutal repression because it kindles the fire which has to be quenched, and we find ourselves satisfied with a frank and active supervision which finds nothing to note beyond a laziness proper to certain adolescents. Moreover we know, because we have experienced it for a long time, that it is clumsy and futile to wish to suppress temperament and character. The good method consists rather in foretelling their excessive manifestations, and trying to soften them by a persevering effort at persuasion."

Examinations

French schools prepare their students for at least two types of examinations: French and Lebanese. They also prepare for examinations of the French Delegation which has succeeded the old Haut Commissariat. The new Lebanese examinations have already been described.[2] The French examinations are the same as those given in France; they are those for the Certificate of Primary Studies, for the *Brevet Élémentaire,* and for the *Baccalauréat,* Parts I and II. The *baccalauréat* examination is usually based upon *Série B* which offers a choice of a foreign language—English, German, Italian, Spanish, Russian, Armenian, Turkish, Persian, modern Hebrew, or modern Greek. A modified program of examinations has been set down by the French Delegation which gives more attention to local needs. In this examination Arabic is required of all Arabic-speaking students. French Delegation examinations are given in various centers, not only in Lebanon and Syria, but also in Jerusalem, Haifa, Baghdad, and Larnaca in Cyprus. The Commission was not able to secure information on the latest results of these examinations.

Description of Some French Schools

Having given a generalized account of French education in Lebanon, it may be worthwhile to present short descriptions of some of the schools visited by the American Council Commission which would show how this education works in practice and some of the features peculiar to each school.

'Anturah College is perhaps the oldest existing French school in Lebanon. It occupies a beautiful site in the village of the same name in the heart of the Maronite district of Kasruwan to the northeast of Beirut. Occupied for the first time in 1656 by the Jesuits, the site was taken over by the Lazarists in 1775 after the abolition of the Jesuit order. The present school was founded in 1834 upon the request of the French consul, and later received the patronage of Guizot, the famous French Minister of Education, who gave the school some money for scholarships. It has been carrying on its work constantly for the last 114 years, except for temporary stoppages during the disturbances of 1860 in Lebanon and during World War I. During this long history it has produced many prominent men, some of whom play an important role in Lebanese life today.

The school admits pupils at the age of seven, starting with the equiva-

[2] See pp. 440–43, and 451–53.

lent of the second grade *(dixième)*, and continuing through the courses of philosophy and mathematics. It is essentially a boarding school and had 380 boarders in 1945–46. It has a large building which contains a theater seating 450 persons. The school year begins about October 1, and ends about the end of June. The classes attended by members of the Commission showed a high order of work in French, Arabic, and mathematics. The school is well equipped with laboratories for physics and chemistry, mainly for demonstration work. It has a large art room, and a music room in which individual lessons in piano and violin are offered at special rates. Music lessons, however, are said to be not too popular, mainly because they are not included in the official examinations. The teaching of English is started in the sixth grade and is continued until graduation. Students are given the average of their marks every month in the large theater in the presence of the whole school. They include marks in conduct and industry, and outstanding students have their names inscribed on the honor roll. The program of study is worked out in detail. The title of each composition for every class is indicated in the handbook which each student receives at the beginning of the year. These compositions fall into three categories: those in French have to do with philosophy, mathematics, geography, history, literature, physics, chemistry, biology, and religious instruction, and *explication de textes;* those in Arabic are mainly on the Arabic language, history and geography of Syria and Lebanon, and translation and literary criticism; a third set is in English covering the various phases of English work. A detailed calendar for every month is also included in the student's handbook and informs him about workdays and holidays, dates compositions are due, examinations, handing out of marks, religious retreats and communions, and various other activities of the school. The College is staffed with nine Lazarist brothers, two Maronite brothers, and twenty lay teachers. It has a Scout troop of about 100 scouts, and a dramatic society. A motion picture is shown to the students every Sunday evening. It has an active association of former students which publishes an attractive annual dealing with the school and its activities throughout the year. The annual is published largely in French, but it also has some Arabic articles and poems. Contributions are by professors, students, and alumni.

The Christian Brothers, popularly known as *"les Frères,"* have two large colleges, one in Tripoli founded in 1881, and one in Beirut founded in 1889. In addition they have six other schools in these two cities, and in Brummana, a Lebanese village and resort to the east of Beirut. These schools had approximately 4,000 boys in the year 1945–46. They are fee-charg-

ing schools except for one school in Tripoli and another in Beirut for poor children. The fee-charging schools pay for themselves. The free schools are paid for partly with money given by the French Delegation and partly with funds saved by the other schools. The Collège de-la-Sainte Famille in Tripoli, visited by the Commission, occupies a large site, and had 888 students ranging from the five-year-olds in the *classe enfantine* to the students in the classes of philosophy, mathematics, and commerce. There were 145 students who were boarders, drawn from Lebanon and Syria, and from some of the British and French colonies in Asia and Africa. The pupils in the Collège were distributed as follows: 507 in the primary school, 352 in the secondary school, and 29 in the commercial course. In addition an annex had 250 students, and another annex, 145. Both annexes were primary schools. The school year begins on October 11 and ends July 1. The school was staffed by thirteen Christian Brothers and thirty-three lay teachers. All the Brothers have French university degrees.

The large college of the Christian Brothers in Beirut, the Collège Français du Sacré Cœur, also ranges from the *classe enfantine* to the classes of philosophy, mathematics, and commerce. In 1945–46 it had 695 pupils in the primary school, 634 in the secondary school, and 49 in the commercial course, making a total of 1,378, of whom 110 were boarders. Three other schools exist in Beirut, the best known of which is the Collège La Salle. The school is staffed by twenty Brothers, all but seven of whom act as directors of studies, and by seventy-three lay teachers. It is housed in a large building which includes a spacious and beautiful chapel. In addition, it has an auditorium seating 360, laboratories of physics and chemistry, and a biology museum with an extensive herbarium. The school also has a good library of French, English, and Arabic books. It has a Scout troop affiliated with the Scouts of France, and a youth organization for its students known as Jeunesse Étudiante Chrétienne (Student Christian Youth). In addition, it has French and Arabic literary societies. The French society publishes an annual magazine with contributions by teachers and pupils. The Collège also has an alumni association that maintains a meeting place with provisions for games, reading rooms, and even a bar for soft drinks. The schools of the Christian Brothers pride themselves on the results in the public examinations, both French and Lebanese. The results are made public as part of the campaign to gain students. Discipline is strict, and the work day is quite long. Attendance is required even on Sunday mornings.

The schools of the Mission Laïque Française represent a different orientation from the usual French missionary school, and have a distinctly more

liberal and free atmosphere. The Lycée Français de Garçons occupies a large modern building on the Damascus road in the southern part of Beirut. In 1946 it had a total enrollment of 950 students; the Lycée des Jeunes Filles, in another quarter of the city, had 630 students. The boys Lycée takes students from the age of four. It consists of a kindergarten of two years combined with a primary school of five years, a secondary school of seven years, and a commercial section. The girls Lycée has the same organization, but has no commercial classes or classes in philosophy or mathematics. Girls wishing to prepare for the second part of the *baccalauréat* come to the boys Lycée. There were 239 girls in attendance in the boys Lycée during the year. The Mission Laïque not only has schools in Syria, in Damascus, Aleppo, and Tartus (the latter coeducational), but it also has important schools in other parts of the Near East, in Cairo, Heliopolis near Cairo, Alexandria, Mansurah, and one *lycée* in Teheran.

The boys Lycée in Beirut had sixty teachers of whom thirty-three were French; of the remaining twenty-seven of Lebanese nationality, seventeen taught Arabic. The girls Lycée had thirty-six teachers of whom eighteen were French; and of the remaining eighteen of Lebanese nationality, ten taught Arabic.

These schools have a reputation for excellent teaching of Arabic, as well as of French. In order to achieve this purpose, students are classified according to their ability in Arabic and French. Considerably more freedom is also given to the students, and the Laïque schools pride themselves on the spirit of critical insight which they try to impart to their students. "Our methods of teaching," says the director of the boys school in a memorandum for the Commission, "are methods of thorough scrutiny. Far from wishing to anesthetize the critical sense of their pupils, our professors, themselves jealous for the independence of spirit so dear to the French university, search for it and sharpen it. Our teaching is not inspired by any system of intellectual conquest or by any mysticism. Our grown-up students can testify to the scruples which animate us in the exposition of all points of view and our frequent appeals to that control of thought which makes for intellectual honesty. . . ." The schools try to keep in touch with the parents, and invite their collaboration by visits to the school. The parents are kept in touch also through the homework given to their children (*cahiers de textes*) and by the marks and observations which are inscribed in their *carnets de notes*. Monthly examinations are held for the primary classes, and trimestrial examinations for the secondary classes. These are also reported to the parents, together with the

remarks of the professors and of the disciplinary council with regard to the aptitudes, diligence, and progress of the student.

The Collège Protestant Français for girls in Beirut, founded in 1927, was the only French Protestant school visited by the Commission. It is situated in the heart of Beirut in a building that formerly belonged to German nuns, but was given to the Protestant French mission several years after World War I. Like the others, it consists of a primary and a secondary school, and has students from the age of three upward. In 1945–46 there was a total of 546 students. Among these the largest single group of students was the Muslim, followed by the Jewish, Greek Orthodox, Catholic, and Protestant. It had a staff of thirty-nine teachers of whom nineteen are French, four European, and sixteen Lebanese. The school is one of the more popular schools for girls in Beirut and is imbued with a progressive spirit. Considerable freedom is allowed the girls. In the primary school the work is organized on the basis of centers of interest, one for each month. The school accepts boys up to the age of ten.

The Jesuits are educationally the most active of the Catholic orders in Syria and Lebanon. Having re-established themselves in Lebanon in 1831, they opened a small school, and, as already mentioned, followed it with a seminary, and a secondary school at Ghazir. This was followed by the establishment of the Université Saint-Joseph, in 1875, and a large number of schools in various parts of Syria and Lebanon. It was not possible to secure recent data on the number of Jesuit schools in Syria and Lebanon, but it is known that in 1928 Jesuit schools numbered 145, with a total of 10,890 students. Of these 9,000 were in Lebanon, making up almost 10 percent of the total number of students in the schools of all kinds in that country. Of these schools, 48 were for girls.

The crowning work of the Jesuit mission in Syria is the Université Saint-Joseph which was founded partly to create leadership among the Christians of Lebanon, and partly to offset the influence and teaching of the Syrian Protestant College, which is now the American University of Beirut.

Starting with a Faculty of Theology and the secondary school, the Université added a Faculty of Medicine in 1883, and the School of Pharmacy in 1889. Later a School of Dentistry and a School for Midwives were opened. The Oriental Faculty for the teaching of oriental languages, history, and archeology was opened in 1902; it has since reduced its program and is today called the Institute of Oriental Letters. The Institute has a large library, the Bibliothèque Orientale. In 1913, the French

School of Law and the French School of Engineering were added. The Université also has under its administration the Catholic Press, first founded in 1847, and the observatory at Ksara on the Buqa' plain between the Lebanon and the Anti-Lebanon ranges.

The Université is administered by a rector who is a Jesuit priest. Each

TABLE 84

Number of Students and of Faculty Members, Université Saint-Joseph, Lebanon, 1945–46

School and Subject	Enrollment	Professors
Faculty of Theology		
Theology	48	
Philosophy	28	
Total	76	13
Institute of Oriental Letters	129*	11
Law School		
Law	570	
Political science	180	
Total	750	24
Engineering School		
Engineers	138	
Licence	49	
Total	187	31
Faculty of Medicine		
Medicine	344	
Pharmacy	57	
Dentistry	76	
Mechanical dentistry	6	
Applied chemistry	11	
Midwifery	24	
Visiting nurses	31	
P.C.B. preparatory	36	
Total	585	44
Grand Total	1,727	123

* Of the 129 students in the Institute of Oriental Letters, 49 were registered students and 80 were free auditors.

Faculty of the institution is also headed by a Jesuit priest. The teaching personnel is comprised of Jesuit priests, other religious men, and lay teachers. Some of the Jesuit Fathers in the past, as in the present, have been scholars of international standing, particularly in the field of oriental studies.

The Université maintains 3 primary schools in the city of Beirut which had a total registration of 741 pupils and twenty-nine teachers in 1945–46. Instruction is free for most of the students. The Collège Secondaire

of the Université had a staff of ninety-nine and a student body of 1,131. This school was not visited by the Commission due to the fact that the classes were not open to inspection by visitors.

The number of teaching personnel and of students in the higher schools and Faculties of the Université are shown in Table 84.

The majority of the student body belong to the various Catholic oriental rites, as well as to the Latin church, but there are a large number belonging to the orthodox rites, Protestants, Jews, and the various Muslim sects.

With regard to nationality, eight of the Near Eastern countries are represented, thirteen countries of Europe, six of Central and South America, and two of Africa.

The Faculty of Medicine gives a course of six years exclusive of the preparatory year of P.C.B. The preparatory year consists of courses in physics, chemistry, geology, and animal, cellular, and plant biology. Each of these except geology is accompanied by laboratory work. The program of medicine naturally follows French lines.

The first and second years are given to elementary physiology, histology, embryology, biological chemistry, and biological physics with laboratory work in each subject. One difference from the American course is that the physics laboratory is limited to ten demonstrations each year. Clinical training in surgery and medicine begins with the first year and attains its full proportions in the second, third, and fourth years. In the fifth year it is divided among dermatology, pediatrics, obstetrics, and contagious diseases.

In the third year, medico-surgical anatomy, operative medicine, and pathological anatomy are given, together with bacteriology, experimental medicine, parasitology, radiology, and surgical and medical pathology.

The studies of the fourth year comprise more bacteriology, obstetrics, parasitology, surgical and medical pathology, as well as ophthalmology, otorhinolaryngology, pharmacology, and therapeutics.

The fifth year comprises medical ethics, dermatology, syphilology, hygiene, legal medicine, pediatrics, pharmacology, physiotherapy, stomatology, and therapeutics.

The sixth year is for internship.

Admission is granted to holders of secondary-school certificates after a competitive examination in physics, chemistry, and biology. Students from other countries of the Near East who hold a secondary-school certificate also are admitted to the examination, but are on a different priority list.

The course leads to the French state degree of Doctor of Medicine, after a final examination by an official French government jury. The students practice in the French hospital and, by agreement with the Lebanese health authorities, in the government hospitals and clinics. The Faculty is well supplied with laboratories. Connected with the Faculty of Medicine are four Institutes: the Physiotherapy Institute, Antirabic Institute, Institute of Bacteriological Research, and the Institute of Chemical Research.

The School of Pharmacy admits students after the same kind of competitive examination as for entrance to the School of Medicine, but requires a preliminary year of practical work in a pharmacy, after which a student must pass an examination known as the Examination for the Validation of the Practice Period *(stage)*. The course in pharmacy is of four years, the first consisting of preparatory courses in general physics and chemistry, botany, and animal and plant biology, including laboratory work in chemistry and physics.

The second-year course consists of human anatomy and physiology, analytical chemistry, botany, hydrology, materia medica, micrography, pharmacy, and toxicology, with laboratory work in general and analytical chemistry, physics, and pharmacy.

Third-year work comprises human anatomy and physiology, biology, botany, analytical and biological chemistry, hydrology, materia medica, parasitology and toxicology, with laboratory work in biology, general biological and analytical chemistry, micrography, parasitology, and pharmacy.

The fourth-year course includes biological chemistry, professional ethics, hydrology, hygiene, materia medica, parsitology, pharmacy, and toxicology, with laboratory work in bacteriology, biology, chemistry, micrography, parasitology, and pharmacy.

The probationary examinations toward graduation are given by an official jury of the French government beginning with the end of the third year. Students passing these examinations are awarded the French State Diploma of Pharmacist.

Admission requirements for the School of Dentistry are the same as for the Faculty of Medicine. Two courses in dentistry are given: a two-year course for dental mechanics working under dentists, ending in a certificate; and a course of four years which, after examination by the School, leads to the degree of Doctor of Dental Surgery of the French Faculty of Medicine in Beirut.

The first-year course for the preparation of dentists comprises general

anatomy, dental anatomy, embryology, dental histology, oral pathology, dental terminology, dental therapeutics, hygiene, and operative dentistry.

The second-year course includes physiochemistry, topographic anatomy, anesthesia, prosthetic dentistry, operative dentistry, dental surgery, oral pathology, stomatology, and physiology.

The third year includes bacteriology, histology, metallurgy, materia medica, dental bridges, dental pathology, general and internal pathology, oral pathology, and stomatology.

The fourth-year course comprises pathological anatomy, maxillo-facial surgery, prosthetics, dental equipment and clients, clinical courses and conferences, electrology, materia medica and therapeutics, orthodontia, dental pathology, and radiology.

Clinical work takes place regularly from 9:00 to 11:30 A.M., every day throughout the four years, and for the fourth year another period of special work takes place after five o'clock. There is also work in hospitals and prisons.

The course in midwifery admits only oriental women students and daughters of European families living in the Near East. They must be at least eighteen years of age and must pass an examination designed to test their knowledge of French. The course is of two years' duration, and comprises in the first year, anatomy, hygiene, and care of the sick.

The second year covers pathology, puericulture, obstetrics, and professional ethics. The course leads to a diploma of the School of Midwifery.

The course for visiting nurses admits students under the same conditions as the School of Midwifery. Students who have had that course may be admitted directly to the second year. The course is of two years' duration—eight months for the first year, and nine months for the second. It comprises courses in medicine, surgery, hygiene, prophylaxy, hygiene of the mother, and nursing of the child. Courses are also given in the battle against social scourges, sanitary organization, and professional, social, urban, and rural hygiene. Rudiments of sociology, political economy, labor legislation, pedagogy, history and functioning of the social services, professional ethics, domestic economy, and physical education are also given. Practice work in the wards takes place five afternoons a week. The course ends with a diploma of Visiting Nurse from the French Faculty of Medicine in Beirut.

The Faculty of Medicine has a special library with about 500 volumes for the use of students, and 10,000 volumes for the use of professors. Before the war it received about 75 periodicals.

CERTIFICATES OF HIGHER STUDIES

Recently the Université Saint-Joseph began to offer courses for preparing students for certificates of higher studies leading to the degree of *Licence ès Sciences.* Courses are offered in physical chemistry, biology, and geology. There is also an extensive course of two years in applied chemistry.

The School of Law comprises an undergraduate course of three years, an Institute of Lebanese Law, and the Center of Social Studies and of Preparation for Careers. Students admitted to the School must hold the *baccalauréat,* or an official secondary-school certificate in the case of countries other than Syria and Lebanon. Students are admitted by competitive examination which includes a written examination of three hours on a subject of general culture designed to show the ability of the student to think and write in French. Two oral examinations, one in philosophy, and one in history and geography, are also required from those who pass the written examination.

The undergraduate course includes in its first year civil law, Roman law, history of French law, political economy, constitutional law, and an introduction to juridical studies. In the second year are given civil law, administrative law, penal law and penal procedure, political economy, and Roman law. Studies of the third and final year are civil law, commercial law, civil procedure, private international law, public finance, and financial legislation, and one of the seven following courses: Muslim law, comparative law, social legislation, social science, public international law, maritime law, and ways and means of execution.

Examinations are held by a special jury at the end of each of the three years. Each examination is both written and oral. The degree of bachelor is given at the end of the second year. The *Licence ès Droit* is given at the end of the third year. Both are French state degrees. Examinations are held in June and October. Failure in the written examination eliminates the student from the oral.

In order to secure a doctorate, a student must acquire at least two diplomas and write a thesis. The diplomas may be secured in private law, public law, and political economy. The diplomas are granted after an oral examination of an hour's duration before a jury of four examiners. The time for study for each diploma usually takes a year or more. The thesis is written under the supervision of a *président de thèse* who approves it. The student has to defend it before a jury of three members for an hour and a half.

The Institute of Lebanese Law includes studies in public and administrative law and in financial law in the first year, on professional status,

and on legal codes of obligations and procedures in the second year. These courses may be taken during the undergraduate studies for the *licence*. They lead to a diploma countersigned by the Lebanese Minister of National Education.

The Center of Social Studies and of Preparation for Careers is divided into two sections: The judicial section gives courses in judicial instruction, criminology, special penal law, and exercises in judicial technique; the administrative section gives courses in public law, social science and social legislation, Lebanese administrative law, public finance and Lebanese fiscal legislation, personal status, land laws, history of local public law, economics, and geography of the Levant states. The courses in each of these two sections are of one year's duration and lead to a special diploma after an oral examination. The School of Law is under the jurisdiction of the University of Lyons in France, which exercises control over the studies, appointing a director chosen from the law professors of that University.

The School of Engineering is also a subsidiary of the University of Lyons, which controls its studies by appointing a director from among its professors. Admission is based upon: (1) the Certificate of Higher Studies in Mathematics, Physics, and Chemistry (M.P.C.) or in General Mathematics, or (2) a competitive examination for holders of the French, Lebanese, or old Syrian *baccalauréat* in Philosophy or Mathematics, or equivalent official certificates from the neighboring countries. The course is of four years' duration. Specialization begins in the fourth year. Two choices are offered: civil engineering and industrial engineering. The course ends with a Diploma of the French School of Engineering in Beirut, on which are inscribed the words "Industrial Engineering," or "Civil Engineering," as the case may be.

Special courses for Certificate of Higher Studies based on the *baccalauréat* in preparation for the *Licence ès Sciences* were opened in 1942 for the duration of the war. The students could prepare for a certificate in mathematics, physics, and chemistry (M.P.C.) as well as certificates in each of the following: general mathematics, general physics, general chemistry, industrial physics, and applied mechanics. The first two certificates admit the student to the School of Engineering without examination.

The Institute of Oriental Letters gives courses to all those interested who hold the *baccalauréat*. Lectures are also open to the public without reference to certificates or diplomas. Courses change from year to year. The Institute offers courses in three departments: (1) Semitic Philology and Literature, including Arabic philology, history of Arabic literature,

institutions of the Arab peoples, Islamic sociology, and history of Arabic philosophy. In some years, courses in the Aramaic languages (biblical Aramaic, ancient Aramaic epigraphy), and Syriac language and history are given; (2) archeology and history of Syria and Phoenicia; (3) Armenian language and culture. Completion of studies ends in an examination for certificates comparable to the certificates of the *Licence ès Lettres* in a French Faculty of Letters. The Université, however, is not entitled to grant this degree, and those students who receive four certificates are granted a Diploma of Oriental Studies of the Université.

The Institute publishes an Arabic review, *al-Mashriq,* first published in 1898, and a series of monographs known as *Les Mélanges de l'Université Saint-Joseph* which are studies in Semitics, archeology, history, and philology of the Near East.

French education and French culture have deep and long-established roots in Lebanon. They have exerted a tremendous influence on the thoughts, attitudes, and habits of the Lebanese, particularly the Catholics. When Lebanon attained its independence in 1943, the French government attempted to insure the ascendance of French cultural influence by proposing a cultural treaty which would have given it almost a monopoly on cultural and educational influence in Lebanon. This was, with slight modifications, the same treaty which was offered to Syria and rejected by it. It proved to be also unacceptable to the Lebanese government. The French, having lost Lebanon, are still exerting great efforts through the Œuvres Françaises and through their schools to maintain their cultural influence. There is no doubt that in this they have the support of a section of the Christian population which has been brought up along French lines and is loath to see that influence weaken. Already, however, a perceptible shift toward English and a demand for it are noticeable. Nevertheless, if what has happened in Egypt in the last century is any measure, French cultural influence will probably remain strong for a long time to come.

Chapter 27

AMERICAN AND BRITISH SCHOOLS

American Institutions

AMERICAN missionary connection with Syria began in 1822 with the arrival in Beirut of two American Protestant missionaries. By 1825 they had opened a small school for boys enrolling about 85 pupils. The American Press, which had been founded in Malta about the same time, was transferred to Beirut in 1831 and began publishing books in Arabic. A school for girls was started shortly before 1830 by the wife of one of the missionaries, Dr. Ely Smith, and a building for it, the first one of its kind in Syria, was erected on the grounds of the present mission. This school continued until the death of Mrs. Smith in 1843. Later another missionary school for girls was opened in the home of another missionary, and did not close until 1854 when that missionary family returned to America. In 1860 the foundations of the present American School for Girls were laid; it has been in operation ever since, continuing the work of its two predecessors.

In the meantime, another boys school was founded in 'Abay which acquired considerable fame as a school giving a modern type of secondary education and preparing Protestant ministers. In this school, books were prepared in Arabic by one of the greatest American missionaries who ever came to Syria, Dr. Cornelius V. A. Van Dyck. Having become a master of Arabic, he soon produced books in geography, algebra, geometry, logarithms, plane and spherical trigonometry, navigation, and biology. These books were printed at the American Press and remained standard works almost until the end of the century. It was Doctors Van Dyck and Ely Smith who worked for more than a decade on the translation of the Bible into Arabic. After the death of Ely Smith, Dr. Van Dyck brought the work to completion with the assistance of a great Syrian scholar of the time, Butrus Bustani.

It was not until after the troubles of 1860, however, that the firm foundations of American and British Protestant missionary work were laid

and began to flourish and expand. After that, schools began to spring up, mainly in Lebanon, but also in Syria: in Sidon and the surrounding villages, in Tripoli and its outlying districts, in the Alawite Mountains, and in the northern and eastern part of Syria.[1] At one time in the late nineteenth century the number of schools was 123. Great stress was laid upon education of girls, and in a number of places, girls schools preceded those for boys. Many of the village schools were coeducational. Boarding schools were established in some of the larger localities. Among these can be counted the American schools for girls in Beirut, Tripoli, and Sidon, and the boys schools in Tripoli, Sidon, Suq al-Gharb, and Shuwayr,[2] and the preparatory school of the American University of Beirut, which took the place of the ʿAbay seminary closed in 1878.

It was also after 1860 that the need was felt by the American Presbyterian Mission for a college to help prepare youth for leadership in the life of Syria and the Near East. The mission therefore entrusted to one of its prominent members, Dr. Daniel Bliss, the task of preparing the road for the foundation of an American college. After appeals were made in England, Scotland, and America, Dr. Bliss succeeded in opening the first college class in 1866, preparatory classes having been opened in 1863. The college was named the Syrian Protestant College.

The following year a medical course was started. From the very beginning it was decided to have the College outside the Mission with a separate board of trustees. The College operated under a charter granted by the legislature of the state of New York in 1863. The preparatory school was started in 1870, and fully organized in 1880. The School of Pharmacy was founded in 1872, the School of Commerce in 1900, the School of Nursing in 1905, and the School of Dentistry in 1910. The last mentioned was discontinued in 1939. In 1920 the charter of the College was amended, and the institution thereafter was named the American University of Beirut. In 1926 the French *Section Secondaire* was organized, and in 1929 an Institute of Music was established. In 1936 International College was transferred from Izmir in Turkey and became affiliated with the University. A year later a course in agriculture was begun, and within the last two years a complete course in engineering has been organized as part of the School of Arts and Sciences. The University became a coeducational institution in the year 1921–22. It is now a nondenominational institution.

[1] Syria is here used to include Lebanon which in the early nineteenth century had not yet had the clear-cut boundaries it acquired after 1860.

[2] This school was first started by the Scottish Mission and was later transferred to the American Presbyterian Mission.

Finally the Syrian Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church of North America established the American Junior College for Women in 1924. Its buildings now stand not far from the site of the American University of Beirut on the promontory known as Ras-Beirut.

After World War I, with the growth of French schools, the establishment of many native schools, and the demand for French education which made easier entry to government jobs, American schools in the villages, though not in the larger cities, began to dwindle. In 1945–46 they numbered only 26, enrolling 1,902 pupils. Almost all the village schools have been transferred since 1939 from the Mission to the Evangelical Synod of Syria. The Mission contributes only a small sum toward their maintenance. Two of the well-known Mission secondary schools for boys, those at Suq al-Gharb and Shuwayr, have been closed. The village elementary schools are now under the control of the education committee of the Syrian Evangelical Synod, although the government permits for their direction are still in the name of the Presbyterian Mission. Education was formerly provided by them free of charge, but financial stringency has dictated that small fees be charged the students. In many places they are under the direction of the Protestant minister, and provide partial support for him. In other places they are conducted by one or more teachers. They are almost all coeducational. The two or three that were visited by the American Council Commission left much to be desired, although in one place the girls and boys seemed to be quite advanced in both Arabic and English.

The main educational work of the American Mission in Lebanon as distinct from the American University of Beirut is carried on in its boarding secondary schools which usually include elementary grades as well. These comprise girls schools in each of Beirut, Tripoli, and Sidon, and schools for boys in the last two cities. These occupy well-built and generally well-lighted buildings. They are usually well supplied with libraries as well as with other equipment. All 5 schools were visited by the Commission of the American Council on Education. At the time of the visit each of the schools had an American principal and a few American teachers while the rest of the staff were Syrian and Lebanese. For the higher classes they are generally, although not always, graduates of the American University of Beirut, while for the lower classes they are the products of the American high schools, or individuals who have not finished their college work at the University. Almost all the American members of the staff are college or university graduates.

PROGRAM OF STUDIES

The program of studies is distributed over eleven grades, six in the elementary school and five in the high school. The program laid down in 1940 is in process of modification. At first these schools started English in the fourth or fifth grade but started French from the first grade. With the withdrawal of the French from Lebanon that arrangement is being gradually reversed. English starts in the first grade, and French begins in the fourth. The program of studies given in Table 85 shows this transition as witnessed by the fact that no French was given in the first grade in 1945–46, but was still being given in the second and third grades; and while English was begun in the first grade during that year, it was not given in the second grade.

TABLE 85

ELEMENTARY- AND HIGH-SCHOOL PROGRAMS OF STUDIES, AMERICAN PRESBYTERIAN MISSION SCHOOLS, LEBANON, 1945–46

Subject	Hours of Classwork per Week					
	Elementary School					
	1st Grade	2nd Grade	3rd Grade	4th Grade	5th Grade	6th Grade
Elementary program:						
Arabic	5	5	5	5	5	5
Arithmetic	5	5	5	4	4	4
English	2½	...	3	5	5	6
French	...	2½	4	5	4	4
Correlated studies: religion, social and nature studies, agriculture, hygiene, elementary science, history, geography, drawing, music, games, handwork	10	10	6	6	6	4
Study and games	...	...	...	...	2	2
Total	22½	22½	23	25	26	25
	High School					
	7th Grade	8th Grade	9th Grade	10th Grade	11th Grade	
High-school program:						
Arabic	4	4	4	3	3	
Mathematics: arithmetic, algebra, geometry	4	4	4	4	4	
English	4	3	4	4	3	
French	4	4	3	3	3	
History and geography (in Arabic and English)	3	4	3	3	3	
Religion (in Arabic and English)	2	2	2	2	2	
Science (in French and English)	2	2	2	3	5	
Music	...	...	1	1	...	
Art	1	1	1	...	...	
Athletics	...	...	...	1	1	
Bookkeeping	...	...	1	1	1	
Penmanship	1	1	...	...	...	
Total	25	25	25	25	25	

Most of the American schools receiving students from other schools where no English is taught have a special class for the teaching of English in which unclassified students are registered; and later they are distributed among the various classes if they make satisfactory progress in their study of English.

The program just outlined reflects clearly the difficulties under which American schools labored during the days of the French mandate. As Americans they naturally wanted to teach English well and to follow more or less American methods in education. On the other hand the presence of France in the country as a mandatary power, the importance of French types of examinations which led to government employment, and the demand of the parents that their children should learn French made it inevitable that the program of the American schools should be adapted to that situation. Moreover, the country being an Arab country, and Arabic being the mother-tongue of the children, it was desirable that, especially in the elementary schools, Arabic should be the medium of instruction and that due care should be taken in teaching it both in the elementary and secondary schools. The program of the American schools was, in actual fact, therefore, a compromise. In their attempt to satisfy these three demands, these schools went so far as to start the teaching of English three or four years after starting the teaching of the French language. Had they not done so, they might have found themselves handicapped and missed a great many of their clientele. They admittedly could not maintain the same standards in French as the French or Lebanese schools, but they—at least the good ones—managed to teach all three languages with a fair measure of proficiency. In their care for Arabic, American schools have largely escaped the criticism leveled against the French schools.

Considerable reliance is placed on the discretion of the teacher who in most cases is given a wide choice in the use of books and methods. The methods of discipline in American schools are also much freer than elsewhere. Not only is there a freer relationship between teacher and student, but students enjoy a great deal of freedom in their daily rounds in and out of school. Boarding students are allowed to leave the grounds at somewhat frequent specified times and on their own responsibility. They are not required to be accompanied by parents or guardians. Censorship of their correspondence, books, magazines, and papers is not even thought of. On the contrary students are encouraged to read their own books and magazines. Chapel attendance and religious teaching seem to be compulsory in most, if not all, mission schools.

Description of American Schools

The American School for Girls in Beirut is the oldest of the existing American institutions in the country, having been started about 1830 and with two interruptions continued to the present day.

The School consists of a kindergarten, elementary school, and a high school, plus a special class in English for unclassified students. In 1945–46 it had 373 pupils, of whom 60 were boarders. The boarding department has been in operation since 1862. Tuition fees range from £L60 to £L220 (approximately $27 to $100). Boarding fees are £L700 ($318). The School is self-supporting except for the salary of the principal. The Mission provides the building. The School has for a long time drawn students from various countries, and during 1945–46 had students from Lebanon, Syria, Iraq, Palestine, Iran, and Turkey. Instruction is in Arabic up to the eighth grade; thereafter most subjects are taught in English. Forty-five percent of the girls are Christian and an equal percentage Muslim. The remaining 10 percent are Jews. The School is of the academic college-preparatory type, and most of the graduates go to the American Junior College for Women. Indeed, the first classes of that College were started in the American School for Girls in 1924 so that the College may be considered as an outgrowth of the School. Extracurricular activities include a Girl Reserves, a choir, and a student society called the Loyal League. The School does not prepare directly for government examinations. Like the other American schools, it started the teaching of French from the kindergarten and first grade, but delayed the teaching of English until the fifth grade. This plan is now being gradually changed and informal work in English was begun in 1945 both in the kindergarten and first grade. It is planned to delay the teaching of French until the fifth grade.

The American School for Girls in Tripoli was founded in 1872 and for a long time was the only boarding school for girls serving northern Lebanon and Syria. It consists of a kindergarten, an elementary school, and a high school. In 1945–46 it had 356 pupils, of whom 60 were boys. The boys are admitted in the kindergarten and the first two grades, after which they are transferred to the Boys School. Tuition fees are £L70–£L220 (approximately $27–$100) and boarding fees are £L550 ($250).

The school is staffed with fifteen full-time and four part-time teachers. It had no principal, but was under the same direction as the other American school, the Tripoli Boys School. Instruction in the elementary and first secondary grades is in Arabic, shifts partially to English in the eighth and ninth grades, and is entirely in English in the last two grades. English is

now begun informally in the kindergarten, and a visit to the first grade showed that most of the conversation in the class was being done in very simple English helped by some Arabic. Arabic reading is started in the advanced kindergarten group. Of the 17 graduates of the high school of the previous year, 6 entered the American Junior College for Women in Beirut, 2 entered the Nursing School of the American University of Beirut, 1 was married; there was no information about the other 8. The School occupies its own building, erected in 1928.

The Tripoli Boys School is under the same administration as that of the girls school. It occupies a fine site on the hill adjoining old Tripoli. The buildings were erected in 1912. The School had 343 students in 1945–46, of whom 116 were boarders. Fees are the same as those in the girls school. The School comprises an elementary school of six years, and a high school of five years, and accepts students not only from Tripoli, but from the surrounding districts of northern Lebanon and Syria. Fifty percent of the students are Greek Orthodox, 35 percent are Muslims, and 15 percent are Protestants or Catholics. It was staffed by fifteen full-time and two part-time teachers, of whom two were women. Four of the teachers had university degrees as compared with two in the girls school. The rest were men who had not finished their studies at the American University of Beirut or who were graduates of the Near East School of Theology in Beirut, holders of the French *baccalauréat,* and, the largest group, high-school graduates. The staff at the girls school had been similarly prepared, with the addition of graduates of the American Junior College for Women (eight), and graduates of the British-Syrian Training College in Beirut (two). The Boys School was founded in 1909, thirty-seven years after the girls school.

The American School for Girls in Sidon was founded in 1862 and now occupies a good site on the outskirts of that city. It is composed of a kindergarten, an elementary school, and a high school. In 1945–46 it had 238 students, of whom about 70 were boarders. Tuition fees ranged between £L80 to £L250 (approximately $36 to $114), and boarding fees were £L550 ($250). All girls in the last two years of the School must be boarders. The School is making a determined effort to teach home economics to all the girls. This is done by reducing the program of mathematics and replacing science with household chemistry and dietetics. Beginning with the seventh grade, about five to six periods each week are given to home economics. This program comprises sewing and cooking each year with the addition of family life, child care, dietetics, household chemistry, and similar subjects distributed over the various years. The

School has a small home-economics laboratory, sewing room, child-care room, a cooking laboratory, and a household-chemistry laboratory. It occupies a set of buildings so designed as to enable it to follow the "house" system. There are six houses, each occupying a floor. A "house" accommodates 12 girls of various ages under the supervision of a teacher who lives in the house. The girls do all the housework by dividing it among themselves and changing tasks every two weeks. While some would be in charge of cooking, others would take care of the cleaning. Each group is headed by an eleventh-grade girl. Light chores are given to the younger girls. Provisions are issued to each house for a period of one month, and the menu is planned in such a way to keep within the limits of the provisions supplied. At one time during the year the girls are given money for the purchase of provisions for a specified period, and they are required to budget it so as not to exceed the allowance.

The Gerard Institute for Boys in Sidon was founded in 1881 and for a time gave practical vocational training in the trades. When a site for the school was built on the hill outside Sidon, its distance from the city was too great a hardship for the students, and the school therefore moved back to its old premises in the city. The school comprises a kindergarten, an elementary school, and a high school. In 1945–46 the school had 422 pupils, of whom 160 were boarders. The student body was almost evenly divided between Christians and Muslims, the latter element almost evenly divided between Shi'ites, and Sunnites. The tuition fees are the same as those for the girls school. The staff included twenty teachers, of whom two were American and one British. Five of these had university degrees, the others were high-school graduates and holders of the *baccalauréat*. The school still emphasizes practical work, but this is no longer of a vocational, but rather of an educational, nature. The authorities of the school would like to include more practical work for the trades in their curriculum, but the desire of the parents to send their children to postsecondary schools counteracts that. Like the rest of the American schools, the school attempted to change its policy with regard to French, but the protests of the parents made it begin the teaching of French in the first grade. English is now also started in the first grade so that the teaching of all three languages—Arabic, English, and French—starts simultaneously. All students are required to study religion and to attend chapel.

Besides the schools described above and the village schools turned over to the Protestant synod, the American Mission operates a residential school for teen-age girls in a village near Tripoli, a school at Nabatiyah east of Sidon, and a small school in a village near Baalbak. These were not visited by the Commission.

THE AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT

The leading American institution in Lebanon, and, indeed, in the whole Arab world, is the American University of Beirut, founded in 1866 as the Syrian Protestant College. The name was changed in 1920. Though an outgrowth of the activities of the Presbyterian Mission, the University is a lay institution with a separate endowment and board of trustees. It draws its students not only from all the countries of the Near East, but also from Asia, Africa, Europe, and a few from North and South America. As a rule, some twenty-five or thirty nationalities are enrolled, representing most of the Christian, Muslim, and Jewish sects. Many of its graduates have occupied and now occupy leading positions in the political, economic, and cultural life of the Arab world.

Starting with 16 students in 1866, its enrollment in all its departments in 1945–46 was 2,399, as shown in Table 86. The total number of its graduates since its foundation was 6,167, of whom 4,348 hold university

TABLE 86

ENROLLMENT IN THE AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT, 1945–46

School		Enrollment
School of Art and Sciences		
Final year, engineering	15	
Graduate class	22	
Junior and senior classes	301	
Special students	79	
Total		417
School of Medicine		
First, second, third, fourth, and fifth years		172
School of Pharmacy		
First, second, third, and fourth years		91
School of Nursing		
First, second, and third years		59
Total, University proper		739
Institute of Music		91
Intermediate Section		
Freshman and sophomore classes	367	
First and second years, farm management	27	
Special students	3	
Special form	75	
Total		472
Preparatory Section		409
Section Secondaire		446
Elementary School		242
Total, International College		1,569
TOTAL NUMBER OF STUDENTS		2,399

degrees, the others, lower certificates or specialized certificates. Approximately four-fifths of its students are Arabic-speaking.

The University has a beautiful campus on the promontory of Ras-Beirut overlooking the Mediterranean Sea and the city of Beirut, with a view of a large part of the Lebanon Mountains. The campus comprises no less than thirty buildings of major size and a large number of smaller buildings, the whole interspersed with groves, wooded slopes, and playing fields. The University comprises a School of Arts and Sciences, a School of Medicine, a School of Pharmacy, a School of Nursing, and an Institute of Music; the lower division of the University is known as International College,[3] and is separately administered and financed. International College comprises: the intermediate section, covering the first two college years; the preparatory section, an American-type high school; the *Section Secondaire*, a French-type secondary school established in 1926; and an elementary school. Each section of International College has its own director and committee. International College admits boys only. Girls are admitted to all other departments of the University.

The elementary school has six grades and is under the administration of a professor of education in the University. Most of the children are day pupils, but boarding accommodations are available for twenty-five boys. Pupils must be six years of age, and each grade has an age range limit of about two years. Teaching is entirely in Arabic. English is begun in the fourth grade. French, however, is still begun in the first grade as was required under the French mandate. In the school year 1945–46 the elementary school had a total enrollment of 242 pupils. The school was staffed by fourteen teachers, of whom four were women; three teachers held the B.A. degree. Two of the women teachers were graduates of the British Syrian Training College, one was a graduate of the British school in Jerusalem, and one was a graduate of the Collège Protestant Français for girls. The other teachers were former students of the University of freshman or sophomore standing. The elementary school is used for practice teaching for students of education in the University.

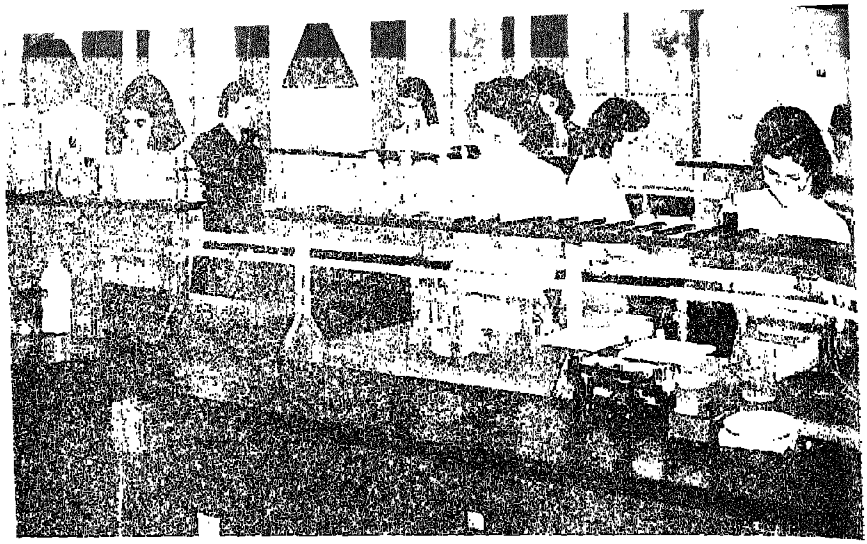
The preparatory section, or American-type secondary school, is a counterpart of the American schools for boys in Tripoli and Sidon. It receives students not only from Lebanon and Syria but from other countries, including Palestine, Transjordan, Iraq, India, Bahrayn, Iran, and Ethiopia. In 1945–46 it had 405 students, of whom about 160 were boarders. Tuition fees range from $119 to $179, and boarding fees from $465 to $525 a year. It

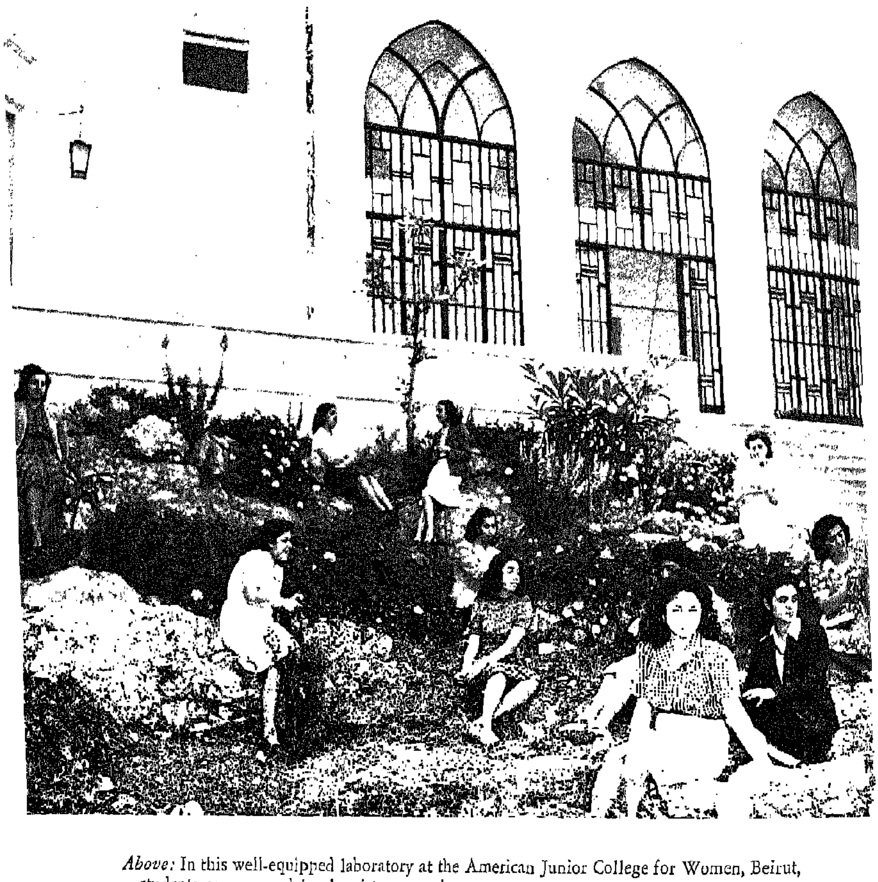
[3] International College was formerly a high school at Izmir, Turkey. It moved to Beirut and became affiliated with the American University in 1936.





Above: A reading class in a village primary school, Bishmizzin, Lebanon
Below: A village primary school, Bishmizzin





Above: In this well-equipped laboratory at the American Junior College for Women, Beirut, students are engaged in chemistry experiments
Below: Undergraduates of the American Junior College for Women relax between classes in the rock garden in front of the dormitory

was staffed by twenty-five teachers, two of whom were American. Almost all of them had university degrees. The program of studies in both the elementary and secondary schools is similar to that of American mission schools. Instruction in the preparatory section is entirely in English except for the classes in Arabic and French languages. The preparatory section program extends over six years, called the seventh grade, eighth grade, first year, second year, third year, and fourth year. The best pupils of the sixth grade of the elementary school are often admitted directly to the eighth grade of the preparatory section. The seventh grade is treated as a flexible arrangement whereby the slower pupils are helped to catch up. Most of the graduates of the preparatory section enter the University classes. Students coming from other schools have to pass an entrance examination which is used in classifying them. Those weak in English may be asked to go to summer school in the mountains to make themselves more fluent in the language.

The *Section Secondaire* is the answer of the University to the imposition of French and French-designed Lebanese examinations during the period of the mandate. It is also an answer to the demands of those parents who wanted their sons to learn French well, but preferred some advantages of the American schools to other schools. In 1945–46 the school had 446 students distributed from the *classe de septième* to the *classe de philosophie et mathématique;* 30 were in the two-year commercial course, which starts after the *troisième* (ninth grade). The language of instruction is French, but special attention is given to Arabic and English. Students graduating from the school are admitted to the sophomore or junior year of the American University, and also to the French university, Université Saint-Joseph.

Table 87 gives the program of studies for the school and shows the type of adaptation of the French program which has been made.

With the passing of the French mandate the fate of the *Section Secondaire* was somewhat uncertain. When the new Lebanese program and the new law regulating private schools were issued, however, tentative ideas were being entertained of turning the *Section Secondaire* into a school following the new Lebanese program, and keeping the preparatory school with its present program. The first foreign language would then become English, and courses now taught in French would be taught in English. French would become simply the second foreign language. Under these circumstances the *Section Secondaire* would be attended almost entirely by Lebanese students, while the preparatory school would be attended largely by students coming from other countries.

TABLE 87

Program of Studies for the Section Secondaire, Regular Course, American University of Beirut, 1946

Subject	Periods per Week										
	Primary Instruction	Classes of First Cycle				Classes of Second Cycle					
	7me	*6me*	*5me*	*4me*	*3me*	*2de* L*	*2de* F*	*1re* L*	*1re* F*	*Philosophie*	*Mathématique*
Philosophy	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10	3
French literature	...	...	...	...	...	6	6	6	6	...	...
French	9	7	7	7	7	...	...	...	...	...	...
Arabic philosophy	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5	4
Arabic literature	...	...	...	...	...	5	5	6	...	...	...
Arabic and Arabic translation	6	6	6	6	5	...	...	2	5	...	...
English literature	...	...	...	...	...	4	4	3	3	2	2
English and English translation	...	6	5	5	5	1	1	2	2	...	...
History	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Geography	1	1	1	1	1	1	1	1	...	1	1
Lebanese history	...	...	...	1	1	1	...	1	...	1	1
Lebanese geography	...	...	...	1	1	...	...	1	1	1	1
Mathematics	5	3	3	4	4	5	5	5	5	2	10
Physics	...	...	1	2	2	3	3	3	3	2	3
Chemistry	...	...	...	1	1	2	2	2	2	2	3
Biology	2	2	1	1	1	...	...	...	...	3	3
French writing	1	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...
Arabic writing	1	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...
Drawing and singing	1	1	1	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	28	30	29	30	30	30	29	34	29	31	33

* F, for students preparing for French examinations; L, for students preparing for Lebanese examinations.

The program of the commercial course, which starts after the *classe de troisième*, is shown in Table 88.

The intermediate section, for men, composed of freshman and sophomore classes, although administratively and financially a part of International College, is under the supervision of the School of Arts and Sciences of the University as to curriculum and academic standards. For admission to the intermediate section, a student must be at least sixteen years old, and have fifteen units of credit from an approved secondary school, or pass entrance examinations.

TABLE 88

Program of Studies for Section Secondaire, Commercial Course, American University of Beirut, 1946

Subjects	Periods per Week	
	1st Year	2nd Year
French	3	3
Arabic	3	3
English	5	4
History	1	1
Geography	2	1
Business mathematics	3	2
Correspondence	2	1
Commerce	2	2
Bookkeeping	5	5
Mathematics	...	2
Commercial law	...	3
Political economy	...	3
Stenography and typing	5	4
Total	31	34

The following certificates are accepted for admission to the freshman class: Certificate showing graduation from an approved secondary school, provided the candidate has spent at least two years in the school; the government secondary-school certificates of Egypt (general section), Palestine, Greece, Iraq, Transjordan, and the Iranian *Baccalauréat,* Part I, provided candidates pass an entrance examination in English; and the London Matriculation, and Oxford and Cambridge School certificates (without mathematics, history, and science).

Entrance examinations are held in four groups of subjects. Group I comprises English, Arabic, and French. English and either Arabic or the vernacular language of the student are required; French is required of Lebanese and Syrians only. Group II requires examination in geography, and one examination in history in one of the following fields: ancient history, medieval and modern history, modern history, general history. Group

III includes arithmetic, algebra, and plane geometry, all required. Group IV includes elementary science as a required subject, and either biology, chemistry, or physics.

Completion of the freshman year of the University or other officially recognized American institutions entitles students to admission to the sophomore class. Certain certificates are accepted for admission provided the student passes an examination in English: the Egyptian *baccalauréat;* French *Baccalauréat,* Part I; Iranian *Baccalauréat,* Part II; Lebanese *Baccalauréat,* Part I; Syrian *Baccalauréat,* Part I; the Iraq Government Secondary Certificate if the student has an average of 75 or more; the Palestine Matriculation Certificate; the Transjordan Matriculation Certificate if the student is in the upper half of the group taking the examination; the London Matriculation, and the Oxford and Cambridge School certificates if the candidates passed examinations in history, mathematics, and science. Those who hold the English certificates or the Palestine Matriculation Certificate are not required to take an entrance examination in English.

The freshman program is uniform, with Arabic or French (the former required of Arabic-speaking students), English, history of the Arabs, mathematics, science, sociology, and physical education required. A choice is given of engineering, music, or political science.

The sophomore class is divided into two sections: the arts section, which takes courses in Arabic or English, economics, history, philosophy, and political science; the science section, which takes required courses in chemistry, mathematics, physics, and philosophy, with a choice of biology, further mathematics, or engineering.

The intermediate section offers a special two-year course in farm management, consisting entirely of courses in agricultural subjects and taught in Arabic. There is also a "special form" for students who qualify for admission to the intermediate section, to the School of Arts and Sciences, and to the Schools of Medicine and Pharmacy *except for English.* The special form is divided into three divisions according to proficiency in English, and only courses in English are taught.

Regulations of the intermediate section with regard to examination and promotion are very much like those in American colleges. A certificate known as the Intermediate Certificate of the Arts (or Science) Program is given to those students who finish the regular course, while a Farm-Management Certificate is given to students pursuing the farm-management course. The certificates are given by International College.

The School of Arts and Sciences.—The School of Arts and Sciences covers the junior and senior college years. Two types of academic pro-

gram are offered: (1) the general course, designed to provide a "liberal" education in which there is very little specialization, and which leads to a "Pass" degree granted on the basis of a passing mark of 60 in all courses, and an average of 65 or above; or (2) the honors course, which aims to train the student to do independent work in a specialized field, and which leads to an honors degree, which, among other things, requires a general average of 70 or above. The honors degree is awarded with first-, second-, or third-class honors. For first-class honors the student's average must be 85 or above in the senior year; for second-class honors, an average of 75 to 84.99 is required; for third-class honors, an average of 70 to 74.99. For first-class honors the student must also be recommended by his major department.

Both general and honors courses are given in the arts and sciences, and in commerce and economics. Engineering, however, is offered only in the honors program.

Work in the arts or sciences in the general course leads to the Bachelor of Arts Pass degree. Students completing the commercial course of the general course receive the degree of Bachelor of Business Administration —Pass. A two-year honors program in commerce and economics leads to the degree of Bachelor of Business Administration, with first-, second-, or third-class honors.

To be admitted to the honors course, students must hold the Intermediate Certificate, first- or second-class; graduates of Aleppo College or the American Junior College for Women must have an average of 70 and a minimum of 70 in at least two year-courses; other students must pass an examination in prerequisite subjects.

The course in engineering is a completely required curriculum, including surveying and practice courses during the summer. Graduates receive the Bachelor of Arts degree, with first-, second-, or third-class honors; an additional year of required courses leads to the Bachelor of Science in Engineering.

Students pursuing honors courses in arts and sciences have to take a major and a minor according to the following schedule:

Major	Minor
Arabic	Education—English—philosophy
Arabic Studies	Arabic—history
Biology	Chemistry—education—philosophy
Chemistry	Biology—education—physics
Economics	Commerce—philosophy—political science
Education	Arabic—biology—chemistry—English—Arabic history—mathematics—sociology

English	Arabic—education—history
Arabic history	Education—philosophy—political science
European history	Economics—philosophy—political science
Mathematics	Astronomy—education—physics
Philosophy	English—history—political science
Physics	Astronomy—chemistry—mathematics
Political Science	Economics—history—philosophy
Sociology	Economics—education—political science

Upon completion of the two-year course, the degree of Bachelor of Arts is awarded, with first-, second-, or third-class honors. Students who major in education—that is, complete a minimum of eight semester courses in education, with a minimum grade of 75 in each course—are awarded the Normal Certificate.

In addition to the regular course, described above, the School of Arts and Sciences offers three special courses: (1) the P.C.B. (physics, chemistry, biology) course, which is a preparatory year for entrance to the School of Medicine and is intended for holders of the Lebanese, Syrian, or French *Baccalauréat,* Part II; (2) the Bachelor of Science in Nursing course, open to graduates of the American Junior College for Women, or its equivalent, who are also graduates of the School of Nursing; (3) the combined course in theology and arts which may be taken either as a general course or as an honors course. This last-named program requires the completion of a minimum of twenty semester courses—fifteen in the Near East School of Theology and at least five in the University—and leads to the Bachelor of Arts Pass degree or honors degree, depending upon grades.

It would be impracticable to detail the courses offered in the various departments of the School of Arts and Sciences. Suffice it to say that the system followed is very similar to that in American universities and colleges. The following are the departments of the School: agriculture, Arabic, astronomy, biology, chemistry, commerce, economics, education, engineering, English, French, history, mathematics, music, philosophy, physical education (offering a freshman course only), physics, political science, psychology, religion (in the Near East School of Theology), science (offering courses in general science, world geography, and geology), and sociology. The number of courses in a single department ranges from one to twenty-nine.

An extensive study of the organization and curriculum of the School of Arts and Sciences has been made in recent years. While no final action had been taken up to the time of the American Council Commission's visit

in 1946, the trends are toward establishing a three-year honors course after the sophomore year, leading to the degree of Master of Arts. The general course of the junior and senior years leading to a pass degree would remain.

Graduate Study.—Graduate work is offered in the School of Arts and Sciences leading to the degree of Master of Arts (for work in all departments *except* commerce), Master of Business Administration (for work in the department of commerce), and Master of Science (for students in the medical sciences preliminary to entering the School of Medicine). Graduation with first- or second-class honors is customarily required for admission to graduate classes, and the student must also pass a written comprehensive examination in his major field of study. Studies usually extend over an academic year except where students have a teaching fellowship, in which case two years may be required. A thesis and a final oral examination are required.

Division of Medicine.—The Division of Medicine is composed of the School of Medicine, School of Pharmacy, School of Nursing, and a course in midwifery.

To be admitted to the School of Medicine, the student must have satisfied the premedical-education requirements of his own country, and must have completed the junior year of the School of Arts and Sciences. Admission is selective and is restricted to 40 students a year. The five-year course meets the standards of schools rated "Class A" by the American Medical Association. Upon the successful completion of the course the degree of Doctor of Medicine and Surgery is awarded. The required hours range from 1,102 to 1,214 a year. The first two years are preclinical years. Beginning with the third year, students spend about two-thirds or more of their time in hospital or clinical work. The University hospital has a total of 214 beds, and a branch maternity and prenatal clinic is maintained in the city of Beirut. Students also get practice training in the Lebanon Hospital for Mental Diseases, which accommodates 365 patients; in two hospitals for tuberculosis, which accommodate 186 patients; and in the Kennedy Memorial Hospital in Tripoli, with accommodations for 52 patients. Plans were being drawn in 1946 for a big medical center near the present University hospital, which would add considerably to the bed space for patients as well as provide facilities for more laboratories and research.

The School of Pharmacy has a four-year course leading to the degree of Pharmaceutical Chemist. In addition, one year of practical work in an approved pharmacy is required, which is recommended to follow the first

year of pharmacy study and in any event must be completed before the student enters the second year; occasionally a practice year spent immediately before entering the first year of the School is acceptable by special permission of the director of the School. Admission is selective and limited to 30 students a year. Candidates must have satisfied the official requirements of their own country regarding preliminary education and must have completed the freshman class of the intermediate section of the American University. Students who wish to practice pharmacy in Lebanon or Syria must have obtained the Lebanese *Baccalauréat*, Part II, or its equivalent, in addition to the degree of Pharmaceutical Chemist. The total hours required range from 794 to 880 a year. Graduates of the School of Pharmacy may take a one-year course (chiefly laboratory work in the analysis of foods, oils, waters, drugs, and industrial articles) leading to the Public Analyst Certificate.

The School of Nursing gives a course of three years comparable to the standards of the New York State requirements for registered schools of nursing. Admission is based on a high-school certificate or its equivalent, and students must be between the ages of eighteen and thirty. The first semester is devoted chiefly to class instruction in theoretical subjects; during the remainder of the two and one-half years, students are on hospital duty for eight hours daily in addition to class work. Students satisfactorily completing the course are granted the Nurses' Diploma. Graduates of the American Junior College for Women who subsequently graduate from the School of Nursing are eligible to enter the senior year of the School of Arts and Sciences for a special one-year course leading to the degree of Bachelor of Science in Nursing. A home for nurses is provided on the hospital grounds.

The course in midwifery extends over nine months for graduates of recognized schools of nursing. Students attend deliveries in the University maternity center, and after they have assisted in twenty-five cases they are allowed to assume responsibility alone. Most of the practice work is done in homes. Abnormal cases are observed in the delivery room of the University hospital. Upon completion of the course a Diploma of Midwifery is granted.

The Institute of Music.—The Institute, founded in 1928, is recognized by the Ecole Normale de Musique de Paris through the courtesy of the director, M. Alfred Cortot, the well-known pianist. The program is divided into three main stages: lower, intermediate, and higher. There is also a one-year preparatory course for beginners preceding the regular

course. Instruction is given in piano, violin, viola, cello, voice, ensemble, theory of music, solfeggio, harmony, history of music, and musical forms. Although the normal duration of the regular course covers six years (two years for each stage), advancement depends upon proficiency and may be more or less rapid. Graduates receive either a certificate or a diploma; the certificate is awarded for satisfactorily meeting the standard requirements of the curriculum, the diploma for satisfying the following requirements in addition: (1) giving an instrumental recital; (2) playing in ensemble; (3) completing specified required courses; and (4) giving a specific performance, the exact type depending upon the instrument used.

The Institute of Rural Life.—In addition to its regular schools and courses, the University maintains an Institute of Rural Life in conjunction with the Near East Foundation, an organization which succeeded the Near East Relief after 1928. The work includes teaching improved agricultural methods to school children and farmers in five villages in the Buqa', health work among the farmers, work with village girls, extension activities, and a program of scholarships. The Institute issues pamphlets on agricultural and health subjects, and a reader for illiterates written by a professor at the University has been in use for some time. Summer camps in the Buqa' region are held every year by volunteers from the faculty and students from the University. This provides experience for students in rural life and problems. The health service employs a full-time doctor and some nurses. The sociology and agricultural departments of the University have played an active role in conducting the Institute. Recently some scholarships have been offered to students from Iraq and Syria for study at the Sanitary Inspection Institute in Cyprus, and a nurse from Iraq was given a scholarship to study public health and home welfare in Jerusalem.

The University issues various series of research studies in archeology, Oriental studies, social science (including economics), the medical sciences, and natural sciences. It has a main library of about 50,000 volumes. There are branch libraries at the International College and the intermediate section. There are also the Nickoley Library in economics and political science, the extensive Islamic library, the philosophy seminar library, and the medical library, the latter comprising about 14,000 volumes, of which more than 9,000 are bound volumes of medical journals. The medical library subscribes to 218 different journals.

The University has a museum with sections of archeology, geology, botany (including an extensive herbarium), and zoology.

THE AMERICAN JUNIOR COLLEGE FOR WOMEN

The American Junior College for Women was established by the Syria Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States. It began in 1924 as classes attached to the American School for Girls and later moved into temporary quarters in Ras-Beirut. It now occupies a campus comprising two fine buildings and the president's house. One of the buildings is a dormitory and the other an administration and classroom building. In 1945–46 it had 187 women students, of whom 88 were boarders. The students belonged to twelve nationalities and thirteen religious sects.

The purpose of the College is to provide general education for family life and for teaching positions and to prepare students for entry into the professional schools of the American University of Beirut. No women students are admitted to the University in the freshman and sophomore years so that in actual practice women desiring an American higher education must first pass through the American Junior College for Women. The College was staffed with twelve full-time and four part-time instructors besides the president. Of these, ten are holders of A.B. degrees from American universities or the American University of Beirut, four have the M.A. degree, one the Ph.D. degree, and one a Nurses' Diploma. Tuition fees are $225 a year, boarding fees $400, and room rent ranges from $50 to $125. In addition, some laboratory fees and fees for music, stenography, and examinations are charged. A limited number of students may earn money by doing some work at the College. Some full-tuition scholarships are offered.

Admission to the Junior College is on approximately the same conditions outlined for the American University of Beirut.

The two-year course consists, in the freshman year, of religion, sociology, Near East history, hygiene, English, and Arabic or French. These courses are all required. In addition, a student must take either mathematics or a basic course in the field of euthenics. In the sophomore year, four courses are required: euthenics, psychology, religion, and athletics, with the addition of another course each semester chosen by the student according to her interests. These courses are chosen from the following: English II, Arabic II, European history, political science, art appreciation, child psychology, social psychology, adolescent psychology, religion, home nursing, mathematics, educational methods, economics, family relations, philosophy, zoology, botany, chemistry, stenography, bookkeeping, typewriting, and music.

Students wishing to enter the American University of Beirut must include mathematics in the freshman year and must rank in the upper half of the students graduating. The College has affiliations with the Near East School of Theology whereby students who have completed their freshman year may receive their diploma in a combined course of the College and the School of Theology. The Institute of Music of the American University of Beirut provides instruction in music at the College for those interested.

The College is equipped with good laboratories for biology, chemistry, and hygiene. A special building houses the laboratories for the courses in euthenics and child psychology. Student activities include a student council, an Arabic club, an international relations club, a crafts club, and student-cooperative clubs. There are also class organizations. The construction of a special auditorium is planned.

British Schools

The British-Syrian Mission has had schools in Syria and Lebanon since 1860 when Mrs. J. Bowen Thompson opened her school in Beirut which is now the British-Syrian Training College. At one time these schools, scattered over many villages of southern Lebanon and in Damascus, reached the number of 40 schools, enrolling about 3,000 pupils. The Mission is nondenominational. Today British-Syrian Mission schools comprise schools in 'Ayn Zhalta, Damascus, Hasbayyah, Tyre, a Bible Training Institute at Shimlan, a boys school, a girls school, and a school for blind boys in Beirut, and the British-Syrian Training College in the same city. These are all elementary schools except for the Training College in Beirut, the school at Damascus which has two secondary classes, and the school at 'Ayn Zhalta, which has had the seventh and eighth grades added to it with a view to training rural teachers. Thus, the British-Syrian Mission by opening teachers training courses and a school for the blind is attempting to work along different lines from the other missions.

The most important institution is the British-Syrian Training College for girls located at Beirut in the heart of the city, not far from the headquarters of American Mission. This school now has a kindergarten of two years, an elementary and secondary course of ten years, and a teacher-training course of two years. In 1945–46 it had 352 students of whom 61 were boarders. Boys are admitted up to the age of nine. The school is primarily intended for Arabic-speaking students. Others may be accepted in the higher classes only, unless they are prepared to study Arabic. Teach-

THE AMERICAN JUNIOR COLLEGE FOR WOMEN

The American Junior College for Women was established by the Syria Mission of the Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church in the United States. It began in 1924 as classes attached to the American School for Girls and later moved into temporary quarters in Ras-Beirut. It now occupies a campus comprising two fine buildings and the president's house. One of the buildings is a dormitory and the other an administration and classroom building. In 1945–46 it had 187 women students, of whom 88 were boarders. The students belonged to twelve nationalities and thirteen religious sects.

The purpose of the College is to provide general education for family life and for teaching positions and to prepare students for entry into the professional schools of the American University of Beirut. No women students are admitted to the University in the freshman and sophomore years so that in actual practice women desiring an American higher education must first pass through the American Junior College for Women. The College was staffed with twelve full-time and four part-time instructors besides the president. Of these, ten are holders of A.B. degrees from American universities or the American University of Beirut, four have the M.A. degree, one the Ph.D. degree, and one a Nurses' Diploma. Tuition fees are $225 a year, boarding fees $400, and room rent ranges from $50 to $125. In addition, some laboratory fees and fees for music, stenography, and examinations are charged. A limited number of students may earn money by doing some work at the College. Some full-tuition scholarships are offered.

Admission to the Junior College is on approximately the same conditions outlined for the American University of Beirut.

The two-year course consists, in the freshman year, of religion, sociology, Near East history, hygiene, English, and Arabic or French. These courses are all required. In addition, a student must take either mathematics or a basic course in the field of euthenics. In the sophomore year, four courses are required: euthenics, psychology, religion, and athletics, with the addition of another course each semester chosen by the student according to her interests. These courses are chosen from the following: English II, Arabic II, European history, political science, art appreciation, child psychology, social psychology, adolescent psychology, religion, home nursing, mathematics, educational methods, economics, family relations, philosophy, zoology, botany, chemistry, stenography, bookkeeping, typewriting, and music.

Students wishing to enter the American University of Beirut must include mathematics in the freshman year and must rank in the upper half of the students graduating. The College has affiliations with the Near East School of Theology whereby students who have completed their freshman year may receive their diploma in a combined course of the College and the School of Theology. The Institute of Music of the American University of Beirut provides instruction in music at the College for those interested.

The College is equipped with good laboratories for biology, chemistry, and hygiene. A special building houses the laboratories for the courses in euthenics and child psychology. Student activities include a student council, an Arabic club, an international relations club, a crafts club, and student-cooperative clubs. There are also class organizations. The construction of a special auditorium is planned.

British Schools

The British-Syrian Mission has had schools in Syria and Lebanon since 1860 when Mrs. J. Bowen Thompson opened her school in Beirut which is now the British-Syrian Training College. At one time these schools, scattered over many villages of southern Lebanon and in Damascus, reached the number of 40 schools, enrolling about 3,000 pupils. The Mission is nondenominational. Today British-Syrian Mission schools comprise schools in ʻAyn Zhalta, Damascus, Hasbayyah, Tyre, a Bible Training Institute at Shimlan, a boys school, a girls school, and a school for blind boys in Beirut, and the British-Syrian Training College in the same city. These are all elementary schools except for the Training College in Beirut, the school at Damascus which has two secondary classes, and the school at ʻAyn Zhalta, which has had the seventh and eighth grades added to it with a view to training rural teachers. Thus, the British-Syrian Mission by opening teachers training courses and a school for the blind is attempting to work along different lines from the other missions.

The most important institution is the British-Syrian Training College for girls located at Beirut in the heart of the city, not far from the headquarters of American Mission. This school now has a kindergarten of two years, an elementary and secondary course of ten years, and a teacher-training course of two years. In 1945–46 it had 352 students of whom 61 were boarders. Boys are admitted up to the age of nine. The school is primarily intended for Arabic-speaking students. Others may be accepted in the higher classes only, unless they are prepared to study Arabic. Teach-

in Bsharri, northern Lebanon, now conducted by the Lebanese Carmelite sisters, was visited by the Commission. It had a kindergarten class and four elementary grades, and enrolled 60 pupils, of whom 24 were boys. It had a staff of four sisters and two lay women teachers. The school had a good building, evidently intended for a much larger school, and had some up-to-date furniture. The instruction in Arabic and French was indifferent.

Chapter 28

PRIVATE LEBANESE SCHOOLS

MODERN EDUCATION in Lebanon goes back to the end of the eighteenth century when a Maronite patriarch, formerly a student in one of the oriental seminaries of Rome, opened a school at the monastery of 'Ayn Waraqah in 1789. This school therefore precedes by thirty-five years the elementary American school opened in 1824, and precedes 'Anturah College by forty-five years. Inspired in its plan by the seminaries in Rome, it gave instruction in Syriac, Arabic, Italian, Latin, philosophy, theology, and civil law, combining in its student body lay students as well as those destined for clerical life. It has often been called the mother of the national schools of Lebanon, and produced a number of learned Lebanese men of the nineteenth century. Among its distinguished alumni may be cited the linguist-lexicographer-journalist-encyclopedist, Butrus Bustani, already mentioned as one of the translators of the Bible into Arabic, Ahmad Faris al-Shidyaq, another linguist and journalist, and Monseigneur Yusuf al-Dibs, later Maronite Archbishop of Beirut and author of an eight-volume history of Syria, and founder of the well-known al-Hikmah College, which will be described later.[1] This school remained open well into the nineteenth century. Other schools were founded later by Maronites, Greek Catholics, Syrian Catholics, and Greek Orthodox (of the latter, the Syrian School at Dayr al-Shurfah and the Greek Orthodox School of Three Doctors are the best known), but they did not seem to have had the same influence as the school at 'Ayn Waraqah. Bustani founded the National School in Beirut, which prepared students for the American University of Beirut during its early years.

The Greek Catholics founded a school in Beirut known as the Patriarchal School, which is still in existence as one of the prominent schools of Lebanon. Later the Muslim Charitable Purposes Association founded a school in Beirut, in 1876. Down to the present day, private schools have been founded by sects, associations, and individuals in such numbers that it is impossible to enumerate them.

[1] See pp. 506–9.

In 1944–45 private Lebanese schools were the largest single group of schools in the country, numbering 963 schools and enrolling 71,524 pupils, or 60.3 percent of the schools and 49.4 percent of the enrollments. The period following the First World War was a period of great development in private schools. These grew up in the larger cities as well as in the smaller villages and may be divided from the standpoint of control into three categories: (1) sectarian schools; these are the largest group and are maintained by the various denominations in order to keep the education of their children under their wing; (2) schools controlled by committees and associations for national or purely educational purposes; (3) schools controlled by individuals—many of these are simply commercial ventures of private individuals for private gain.

TABLE 90

Distribution of Private Schools and Pupils According to Denomination, Lebanon, 1941–42*

Denomination	Number of Schools	Enrollment					
		Christian	Muslim	Druze	Jews	Miscellaneous	Total
Muslim	122	92	15,408	162	...	97	15,759
Druze	26	41	45	1,452	5	2	1,545
Jewish	1	...	...	...	236	...	236
Christian							
Maronite	406	20,600	523	175	2	15	21,315
Greek Catholic	148	7,856	500	231	...	6	8,593
Syrian Catholic	4	945	40	29	...	...	1,014
Armenian Catholic	9	1,586	...	...	...	...	1,586
Chaldean	1	141	1	1	...	...	143
Greek Orthodox	186	10,479	252	131	2	...	10,864
Syrian Orthodox	5	328	3	...	...	...	331
Armenian Orthodox	37	7,062	...	...	...	...	7,062
Armenian Protestant	13	1,151	...	...	...	...	1,151
Protestant	2	187	14	3	...	...	204
Miscellaneous private schools	26	2,806	211	615	17	156	3,805
Total	986	53,274	16,997	2,799	262	276	73,608

* Conseil Général des Intérêts Communs, *Recueil de Statistiques de la Syrie et du Liban, 1942–43* (Beirut: Imprimerie Catholique, 1945), p. 31.

From the standpoint of government statistics almost all the private schools are classified under the denominational affiliation of their controlling authorities as is shown in Table 90, which gives the distribution of private schools and pupils according to denomination in the year 1941–42.

The largest single group of schools and of pupils is the Maronite with 406 schools and 21,315 pupils. Next comes the Greek Orthodox with 186 schools and 10,864 pupils. The Greek Catholics come third with 148 schools and 8,593 pupils. The Muslims, though fourth in the number of schools, are second in the number of pupils; they had 122 schools with

15,759 students. Armenian schools, both Orthodox and Protestant, come next with 50 schools and 8,213 pupils. They are followed by the Druzes, with 26 schools and 1,545 pupils.

A careful study of Table 90 shows that each denomination is catering almost exclusively to children of its own religion, though not necessarily of its own sect. Only 715 pupils out of the more than 21,000 in Maronite schools are non-Christian. Similarly, 385 pupils out of 10,479 in Greek Orthodox schools are non-Christian. Only 92 Christians, 162 Druzes, and 97 pupils from various sects attend Muslim schools out of a total of 15,759. Thus, the sectarian differences already existing among the people of Lebanon are paralleled in the composition of the student bodies of the various private schools. It can perhaps be safely said that the schools help to perpetuate these cleavages, if not to make them more pronounced.

As a group the private schools represent no special philosophy of education or any attempt to experiment with new curriculums or methods. It is the rare school indeed which is trying to strike out in a new direction. Rather, the private schools follow the lead either of the French, American, or British types of education. Naturally, since the government conducts primary and secondary examinations, some schools also follow the program of studies set down by the government.

These statements must be qualified by two considerations. The first is the attempt of each sect to draw to its own schools the children of its own community, and annoyance lest these children may go to schools of a different sect. This is particularly true of the Greek Orthodox and Catholic sects. The same is true of some of the private Muslim schools which were established to prevent Muslim children entering Christian missionary schools where another religion might be taught to them, sometimes compulsorily, and where they would have no chance of studying their own religion. Some of the sectarian schools provide children for religious services in their churches, and the children are, therefore, taught the liturgy and hymns of their own church. In a large portion of the Catholic schools, the clergy is in full control, with nuns or priests as principals, directors of discipline and studies, and as teachers. The same is not true of the Greek Orthodox schools, though there is a close affiliation with the church.

The second consideration is the new outlook advocated by some of the Lebanese that their culture should follow the lines of the so-called "Mediterranean culture." The protagonists of this theory maintain that Lebanon has always been a bridge between the East and the West and has always been influenced by Eastern and Western cultures alike. Whether in Phoenician, Greco-Roman, or Crusading times, Lebanon was always in direct

relationship with other parts of the Mediterranean world and was influenced by the cultures emanating from that world. At the same time since it was attached to the Eastern soil and populated by races of Semitic origin, it could not help being influenced by Eastern cultures as well. In this way "Mediterranean culture" seems to mean the present Arab culture of the East and its background of other Semitic cultures, as well as the present modern Western, particularly French-Catholic, culture and its background of Greco-Roman culture. It is further maintained by this group, made up largely of French Catholic sympathizers who have not taken easily to the participation of Lebanon in the Arab League, that Lebanon should not be swayed too far to the East, to the point of losing its identity in the Arab-Muslim majority and in the Arab-Muslim ideology. Rather, due care must be taken to keep in close touch with the West, the Christian Catholic West in particular, in order to have a balanced culture inside Lebanon.

Their antagonists, on the other hand, made up largely of sympathizers with the Arab cause who like to see the Arabic culture of Lebanon maintained, accuse them of not paying enough attention to Arabic and Eastern cultures, and assert that what is called "Mediterranean culture" is nothing more than a thin veil for the attempt to preserve French Catholic influence and education in Lebanon.

This controversy has come to the fore more specifically in the last several years with the end of the French mandate, the rise of the Arab League, and the declaration of Lebanon's independence. From the standpoint of the schools themselves, however, it has as yet made little difference either in the types of curriculum or methods followed. It is not necessary, therefore, to describe them further as a group. The descriptions which follow are of individual schools visited by the Commission.

Denominational Schools

MARONITE SCHOOLS

The outstanding Maronite school in Lebanon is the al-Hikmah College, a boys school founded in Beirut in 1876, by the Maronite Archbishop of Beirut, Monseigneur Yusuf al-Dibs, a learned man of his times. It is situated in the eastern part of the city in its own old building to which has been added a large new building constructed in 1938. It has a primary school, a secondary school, and a commercial course. It had an enrollment in 1945–46 of 1,565 students, of whom 350 were boarders. About 900 were in the secondary section. Students are drawn mainly from Lebanon, but about 100 boys came from Syria, a few from Palestine, while others

were children of Lebanese emigrants to Africa. The school was staffed with a director, a prefect of discipline, two directors of studies of Arabic and French (all of them priests), and 70 men instructors, 12 women instructors, and some nuns. In addition there were 12 supervisors, all priests. The school is under the authority of the Maronite Archbishop of Beirut who appoints the principal and receives from him a written report on the school annually. It is self-supporting, the fees being sufficient normally to pay all expenses. Any additional expenses are paid, when need arises, out of endowments of the Diocese of Beirut. The buildings belong to the diocese.

The College is well known for the equal care given to the teaching of Arabic and French. It has produced a large number of the leading men of Lebanon, among whom are writers, poets, journalists, and clergymen. Originally both a seminary and a college, it is now only a college for lay instruction, the seminary having been moved elsewhere. The authorities of the College have been among the leaders in the movement for the accession of what has been called "Mediterranean culture" and have taken the lead in founding the Cultural League of Free Education. This is an association of private Lebanese secondary- and elementary-school principals and inspectors which has the following aims:

1. Intimate cooperation and participation with the government in propagating the spirit of independence and patriotism in the hearts of youth, and the unification of education inspired by the Lebanese spirit.
2. The maintenance of the separation between cultural and political orientation and respect for the national Lebanese ideal and its cultural superiority.
3. Maintenance of the freedom of educational method in private schools within the public programs.

Table 91 shows the program of studies of the school beginning with the fourth primary year (*huitième*) as an illustration of the attempt to give more or less equal emphasis to Arabic and French.

It should be added that though the hours given to French are somewhat less than those given to Arabic, a number of subjects are taught in French. The Commission in its visit to the school was impressed by the fact that the general atmosphere seemed to be decidedly French. The school authorities spoke French among themselves and kept some of the records in French. English is begun in the fifth primary grade (*septième*).

The school has a literary society, physical-education society, a Scout troup, and a choir of 150 voices which sings church and Lebanese music. Dramatic societies are also active, giving both Arabic and French plays.

The College seems to be attempting to foster the introduction of harmony into Arabic and church music.

An illustration of the efforts by the Maronite clergy to provide education for girls are the schools of les Sœurs de la Sainte Famille, known as the Nuns of 'Ibrin, named after the village where the mother convent is situated. These Maronite nuns maintain about 40 schools for girls, to which the government pays a small contribution. Some of these schools are in Syria, but the majority are in Lebanon. Their girls school in Beirut

TABLE 91

PROGRAM OF STUDIES OF AL-HIKMAH COLLEGE, LEBANON

SUBJECTS	PERIODS PER WEEK BY CLASSES*							
	8me	*7me*	*6me*	*5me*	*4me*	*3me*	*2de*	*1re*
Arabic	12	8	7	7	7	7	7	6
French	10	6	6	6	6	6	7	5
Mathematics	5	4	4	4	4	5	5	6
Science	...	1	1	2	2	2	4	4
English	...	3	3	4	4	4	4	4
History and geography	3	2	2	2	2	2	2	3
History of Lebanon	2	2	2	2	2	2	2	2
Translation	...	...	...	...	...	...	...	1
Religious instruction	2	2	2	2	2	1	1	1
Drawing	1	1	1	1	1	...	...	...
Writing	1	1	½	½	½	...	...	...
Total	36	30	28½	30½	30½	29	32	32

* The names of classes follow the French system of having the first class have the highest number; for example, the first class is called "*huitième.*"

is perhaps the best illustration of the type of school for girls maintained by this order. It consists of the *classe enfantine,* a primary school, and a secondary school. In 1945–46 it had 450 pupils, of whom 110 were boarders. The students are mostly from Beirut and Lebanon though there are some from Damascus and Latakia. The student body, though largely Maronite, includes also other Catholics, Greek Orthodox, Druzes, Jews, and Muslims. In 1945–46 the school was staffed with forty teachers including fifteen nuns. Fifteen men and five women were part time. The school accepts boys up to the age of seven.

The program of studies shows no great differences from that of al-Hikmah College for boys. Home economics is taught on Saturday afternoon. On Sunday there is compulsory Mass and a lecture on ethics. School fees are £L50 to £L300 ($22.50 to $136) for day students and £L600 to £L800 ($273 to $354) including tuition for boarding students. Forty day students and 10 boarding students are exempted from paying fees.

Some of the boarding students come from immigrant families from Africa and America.

GREEK ORTHODOX SCHOOLS

Two Greek Orthodox schools, one for boys and one for girls were visited by the Commission.

The School of Three Doctors, founded in 1835, was at one time one of the prominent schools of Beirut, but has had an uneven career. It is situated in the eastern part of the city, where it has its own building belonging to the Greek Orthodox community. It is controlled by a committee of the denominational council of the Greek Orthodox Church which is responsible to the Greek Orthodox Archbishop of Beirut. At the time of the visit of the Commission in 1945–46 the School consisted of an elementary and a secondary section. The school was in the process of being rebuilt educationally after some years of low standards. There were 303 pupils in attendance, of whom 120 were in the secondary section. The School had up to that year not presented students for the second *baccalauréat* examinations, but had started a class in philosophy with 4 students during the year. It was headed by a lay principal, staffed by twenty-three men and two women teachers, of whom seven were part time. Two of the teachers had the French university degrees of *Licence ès Lettres,* two had B.A. degrees from the American University of Beirut, one was an engineer, four were students at higher institutions, and the rest had second *baccalauréats*. The program of studies does not differ radically from the other schools with the exception that English is begun with the third grade of the primary school (*neuvième*).

The Greek Orthodox School for Girls in Tripoli was founded in 1921 by the present Greek Orthodox Patriarch who was then Archbishop of Tripoli. It was later taken over by the ladies committee. The grounds and the buildings had been supplied by the diocese. The School building was requisitioned by the British Air Forces between 1941–45, and consequently the School suffered, and has been building itself up again since its return to its old quarters. It consists of a kindergarten, a primary school, and the first three years of secondary school leading to the *brevet* certificate. In 1945–46 it had 350 pupils, of whom 50 were boarders. One hundred fifty of the pupils either received full or partial exemption from fees. The student body, largely Greek Orthodox, had about one-third Muslim students. The staff included sixteen teachers, of whom four were men. The principal of the school has for some time been the head of the Girl Scout movement in Lebanon.

GREEK CATHOLIC SCHOOLS

The American Council Commission regrets that it was not able to visit the well-known Patriarchal College of the Greek Catholic denomination, founded in 1865, owing to a misunderstanding growing out of inaccurate reports of the purpose of the survey conducted by the Commission.

MUSLIM SCHOOLS

Three well-known Muslim schools were visited by the American Council Commission, in Beirut, Sidon, and Tripoli. The best known of these is the College of the Muslim Charitable Purposes (al-Maqasid al-Khayriyah) at Beirut. This is conducted by an association made up of Muslim laymen headed by a prominent, wealthy resident of Beirut. The association not only maintains schools, but has other charitable activities. Its schools are under two educational committees, one for the schools in Beirut, and the other for village schools. It draws its income of about £L250,000 ($136,000) a year from endowments made up largely of property and from fees, which range from £L110 to £L300 ($50 to $136.50) a year. The association maintains a secondary school for boys and another for girls in Beirut together with four elementary schools for boys and two elementary schools for girls in the city. A number of schools in the villages around Beirut and in Buqa' are also maintained.

The College of Muslim Charitable Purposes, in Beirut, for boys, was founded in the last quarter of the nineteenth century under Ottoman government auspices, but had an uneven history until after World War I when the Muslim community, largely under the leadership of a public-spirited man, put the College on a sound foundation and developed it from a primary school into a full secondary school. It includes a kindergarten which accepts children of nursery age, two primary schools, and a full secondary school presenting students for the second *baccalauréat*. The College is situated in the southern part of Beirut adjoining the great pine grove. In 1945–46 it had 996 students almost all of whom were from Beirut. The secondary school and what is known as the old primary school constitute a unit which enrolls 728 pupils and is staffed by the head principal and forty-two men teachers. Another unit known as the new elementary primary school and kindergarten enrolls 248 pupils and is staffed by a principal and eleven women teachers. The nursery and kindergarten follow some of the most progressive methods witnessed in any of the countries visited by the Commission. The authorities of the school are planning to add primary grades to the kindergarten which would follow more pro-

gressive lines than the old school. At the time of the visit of the Commission only the first grade of the new primary school had been started, and the Commission was told that other grades would follow gradually in subsequent years.

The College follows the government program by giving first place to Arabic and French, both of which are started in the kindergarten. English is begun in the first secondary year. Like many other schools, however, the College authorities are thinking of giving the students a choice between French and English beginning with the kindergarten. Teaching was being conducted in Arabic in the primary school and in the first secondary year. It was hoped to turn all of the teaching into Arabic gradually, teaching the French language simply as a language. A commercial course of two years after the third secondary year is planned. The College presents students for all four Lebanese examinations, and its secondary-school certificate is recognized by the Egyptian government and by the American University of Beirut for entry into the freshman year. It is hoped that when the teaching of English is improved, graduates, or at least some of them, will be able to go into the sophomore year. The College receives help from the Egyptian government in the form of four teachers, three of whom were delegated by the Egyptian Ministry of Education and one by al-Azhar. This delegation of Egyptian teachers was first begun in the year 1936–37. In 1945–46, 22 graduates of the College were studying in Egyptian universities, where they were receiving free tuition and board.

The College of Muslim Charitable Purposes in Sidon represents another institution of the same kind as that of Beirut, though it belongs to an independent organization. The College is made up of a kindergarten department of three years and a secondary school of eleven years, including the classes of philosophy and mathematics. The College is 1 of 4 schools in Sidon supported by this same organization. One is a boys primary school, enrolling about 450 children; 2 are schools for girls, both of which are primary, with about 600 girls in one and 350 girls and small boys in the other. It is planned to expand the first girls school into a full secondary school, leading to the second *baccalauréat.*

The boys College visited by the Commission had in 1945–46, 584 students of whom 139 were boarders. Girls are admitted in the kindergarten. The students come not only from Sidon and the rural districts surrounding it, but also from Buqaʿ, northern Lebanon, Beirut, and parts of Syria. About 35 boarders were children of Lebanese parents living in Africa.

The College is the only full public or private secondary school in southern Lebanon, and is, therefore, sought not only by Muslim children but by

Christians as well. Forty-five Christians were in the secondary section, which enrolled a total of 154 students. It is staffed by a principal, an assistant, and twenty-six teachers, not including nine women kindergarten teachers. Fees range from £L40 to £L325 ($18 to $148) with an addition of another £L500 ($228) for boarding students. The College is almost self-supporting and is said to charge the highest fees in Sidon. Children of teachers are accepted gratis in the primary school and on half-fees in the secondary school. Income from property is spent mostly on the other free schools.

The College has a library of about 2,000 books in Arabic and in French, a small chemical laboratory, and some maps in French and Arabic. It fosters a number of student activities including a literary and dramatic society, a lecture program, two library committees (one each for Arabic and for French books), a Boy Scout troop, and various athletic teams. A school magazine, edited largely by students, is published in Arabic.

The College is now preparing for first and second *baccalauréats,* as well as for the primary-school certificate and the *brevet.* Its diploma has been recognized by the universities in Egypt, and 4 students are already studying at Egyptian universities. At the time of the Commission's visit, English was started in the seventh grade, but it was planned to form a special English section by agreement with the American University of Beirut. In this section English would begin in the kindergarten and continue through the secondary school.

The leaders of the Muslim Charitable Purposes movement may be said to represent in their outlook the opposite pole of the ideology represented by the al-Hikmah College and the Cultural League of Free Education. To them there is nothing that can be called Lebanese culture, but there is an Arab culture, or rather a world culture. They believe that Arabic should be the language of instruction and of expression. They attack the idea of French as a language of expression for Lebanese and Arabs: foreign languages should be taught for purposes of opening the gateways for acquisition of Western thought, but the expression of thought, whether Western or Eastern, should be in Arabic.

They concede that the foreign-language situation in Lebanon is different from the rest of the Arab countries in that the Lebanese population is more urban, and a large part of the Lebanese villages are summer resorts frequented by people from abroad. The Lebanese, therefore, take more easily to the teaching of foreign languages because their environment fosters acquisition of languages. This, however, should not mean in any way the neglect of the Arabic language, and the use of a foreign language

for purposes of teaching or of expression. The aim, therefore, should be to turn all teaching into Arabic while at the same time fostering the teaching of foreign languages.

A third Muslim institution is the National College of Education and Instruction in Tripoli. This includes a kindergarten of three years, a primary school of five years reaching the sixth-grade standard, a secondary school of five years, a religious school of four years above the primary school, a commercial section, and an English section is being planned. In 1945–46 the College had 616 students, of whom 213 were accepted gratis. Students come from Tripoli and vicinity, while boarding students come from Homs, Hama, Latakia, and Aleppo. Fees range from £L90 to £L300 ($41 to $136.50) to which is added £L550 to £L700 ($251 to $318) for boarding students. Exemption from fees is based on economic need. The boarding section includes 130 orphans free and ten religious students who pay no fees and 55 paying students. A student accepted gratis in the primary school is given the option of entering the religious section or the secondary section. If he chooses to go into the secondary section, he receives one-half exemption only, but full exemption is accorded him if he chooses the religious section.

The program of the College is that of the government program leading to the primary-school certificate, the *brevet,* and the *baccalauréats,* but with greater emphasis on English, religion, and Arabic history. English is started in the fourth grade. Prior to 1945 it was started in the first secondary grade. The idea now is to have a separate English section preparing students for entry into the American University of Beirut. The religious section, formerly of four years, has been reduced to three years. It endeavors to prepare students for entry into al-Azhar in Cairo. Applicants, however, were few in 1945–46, only 22 students being registered in all three classes.

The College has its own building, owned by a society maintaining it. It has a laboratory and a lecture hall. It fosters a number of student activities and has a Boy Scout troop and various athletic teams. In addition to the College, the society maintains a primary school for girls, and a primary school for boys in the old quarter of Tripoli. The College is typical of the attempt of Muslim communities to give a religious education to the younger generation, and also to impress upon the pupils the principles of Arab nationalism. Non-Muslims are accepted, but, in contrast with many Christian mission schools, no attempt is made to enforce compulsory Muhammadan religious instruction upon them.

DRUZE SCHOOLS

These are maintained mainly by a Druze education committee under the leadership of a well-known Druze public figure. Fifteen schools are maintained, of which 4 are for girls. They enroll a total of 1,067 students. Four of these schools are complete primary schools. Another, the Daudiyah school in 'Abay, is a full primary and secondary school for boys; a girls primary school of six years is maintained in the same town. An orphanage in Beirut takes children up to the fourth grade after which the brighter pupils are transferred to 'Abay. The schools are supported mainly from fees, but also by income from property and endowment, and by a small government grant. Each village school charges its own fees and is administered by its own local committee. Any deficit is paid by the central committee, which has the academic and financial supervision of the schools.

The Daudiyah College for boys in 'Abay is undoubtedly the most important Druze educational institution. It was founded in 1862 by the Lebanese autonomous government and named for the first governor of Lebanon. It was for a long time the only public school maintained by the Lebanese government. Closed during World War I, it did not resume its activities until 1931, when it became a private denominational school. It consists of two sections: a French Lebanese section leading to the French and Lebanese examinations, and an English section preparing students for admission to the American University of Beirut. The French section comprises classes from the fourth grade to the class of philosophy; this section enrolled 124 students in 1945–46. There was no mathematics class at the time of the visit of the Commission. The English section, started only three years before, included classes from the fourth through the seventh grade, and it was planned gradually to develop it into a full high school. This section enrolled 62 students, making a total of 186 students, of whom 90 were boarders. Boys belonging to the first three grades were taught at the girls school in 'Abay, which had 120 pupils, of whom 30 were boarders; 40 pupils were boys. Students in the Daudiyah school were mainly from the villages of Lebanon as well as from Jabal Druze in Syria. The College is staffed by a principal and seventeen teachers, of whom three were contributed by the Egyptian government and one by the Œuvres Françaises.

The so-called French section follows the Lebanese government program while the English section is following the program of the preparatory school of the American University of Beirut. English is begun in the first secondary year in the French section, and, conversely, French is begun in the same

year in the English section. Present plans call for the English section to be completed in three years. The girls school is substituting English for French.

The Daudiyah College occupies a new building built by special contributions and from Druze endowments. It has a library of about 1,000 books and is receiving contributions of books from Egypt. Student committees for Arabic, English, French, science, and student welfare exist. A number of athletic teams are organized, and a school magazine is published.

Nondenominational Schools

Nondenominational schools fall mainly into two types: those controlled by boards and societies and operated on a nonprofit basis, and those owned and controlled by individuals for profit. The number of the nondenominational schools is rather large both in the cities and in the villages of Lebanon. It was possible for the Commission to visit only a few of them. Four schools and institutions will here be mentioned.

The National (al-Ahliyah) School for Girls was founded in 1916 by a former teacher at the British-Syrian Training College partly, at least, for the purpose of filling the gap created by the closing of that College during World War I. It is controlled by a board of trustees composed of prominent people, most of whom are from Beirut. A boarding department was opened in 1926.

The School consists of a kindergarten, a primary school open to both boys and girls, a secondary school of five years, and a college freshman year which was opened for the first time in 1945–46. A matriculation class was also being conducted during the same year. The School had a total of 440 pupils, of whom 110 were boarders. Tuition fees range from £L100 to £L250 ($45 to $114), except for the freshman class for which they are £L400 ($182). Boarding fees are £L650 ($296). Some of the intelligent girls receive scholarships for work done at the School. The School is staffed by a principal, an assistant, and twenty-two teachers, of whom six are men. Most of the staff are American-trained.

The program of the School follows closely that of the American schools. Instruction is in Arabic through the seventh grade, partially so in the eighth grade, and entirely in English in the ninth grade and above. French is begun with the kindergarten, English in the third grade. French instruction reaches the standard of the *classe de deuxième* (tenth grade), and no attempt is made to prepare students for the government or French examinations. The authorities of the School have a firm belief in the teaching of

foreign languages. Sectarian religion is not taught, and prayers are of a nonsectarian character. Study of the Bible in English is part of the teaching of literature in the upper grades. No rigid discipline is contemplated, and the authorities attempt to give the School a strong family atmosphere. Stress is laid on art and Western classical and sacred music. Some of the girl students are members of the choir of the Lebanese Academy of Fine Arts. The School receives no contribution from the government or any foreign source. It does, however, accept gifts of books.

As an example of a private school in a Lebanese village the school at Bishmizzin in northern Lebanon may be cited. This village has had private schools for a long time under various forms of control. For the last seven years, however, the school has been run by a committee of the citizens of Bishmizzin, most of whom are graduates of the American University of Beirut. The building occupied by the school was requisitioned during the war by the British military forces, and it was expected that it would be returned soon. At the time of the visit of the Commission the school occupied two rented houses. The school consists of an elementary school of six grades and a secondary school of four grades. It was planned to add an eleventh grade in 1946–47. By agreement with the American University of Beirut graduates recommended by the school would be accepted in the freshman class of the University provided at least two of the teachers have B.A. degrees and provided a laboratory is installed in the school.

In 1945–46 the school had 220 pupils, of whom 118 were boys and 102 were girls. Thus, the school is one of the outstanding examples of a coeducational primary and secondary school in Lebanon. It is staffed by a principal and eleven teachers, of whom six are women. The school follows the program of the government in the primary section, and that of the American University of Beirut in the secondary section. English is begun in the third grade and French in the sixth. The students come not only from Bishmizzin itself, but also from the various villages around it. The government gives an annual contribution of £L700 ($318). A deficit of £L1,500 ($682) in 1944–45 was paid by public-spirited citizens of the village.

The Lebanese Academy of Fine Arts was established in 1942–43 for the study of music. In the following year a course in architecture and another in art were added. These were scattered at first over three schools of the city. In 1944–45, however, the Academy rented its own building. It is maintained by a committee of Lebanese men and women and claims to be the only Lebanese institution of higher education.

Its course in architecture is of one preparatory year and four years of

architectural training. Entrance is by a competitive examination based on the second *baccalauréat.* The preparatory year is for students who do not pass the examination or for holders of the first *baccalauréat.* Its program is identical with the *classe de mathématique* with the addition of drawing and design. In 1945–46 the architectural course consisted of only three years; the fourth year had not yet been started.

The course in music is divided into three stages: a first stage of three years, a middle stage of four years, and a final stage of two years consisting largely of repertoire selections. Every student must study at least one instrument. Instruction is given in piano, violin, cello, flute, clarinet, oboe, brass, and voice. All students take courses in theory of solfeggio, theory of music, harmony, counterpoint, composition, and instrumentation. The Academy has a choir composed of some of its men and women students and of girls from the National School. An amateur orchestra is made up of the Academy students, and for major performances some professional musicians are hired. The Academy has given programs in choral and instrumental music, including Beethoven's *Missa Solemnis,* Haydn's *The Creation,* Bach's *Christmas Oratorio,* Mendelssohn's *Elijah,* and Handel's *Messiah,* all under the direction of the president of the Academy.

The art section has no definite length of time for study. It gives instruction in painting, water colors, wood engraving, photography, and sculpture, together with theoretical studies in anatomy, shading, and history of art (the last named in conjunction with the School of Architecture).

In 1945–46 the Academy had 43 students in architecture, 130 in music, and 30 in art. It was staffed by about forty-five teachers, most of whom were part time. Fees were £L120 ($54.50) for art students, £L140 ($63.50) for music, and £L440 ($200) for architecture. Gifted poor students are exempted from payment of fees, as are students studying the rare musical instruments such as the oboe. The Lebanese government in 1945–46 granted £L8,000 ($3,636) toward the support of the Academy.

The movement for the foundation of private schools controlled by boards and societies seems to be spreading in Lebanon. For example, the League of Lebanese Women, which is perhaps the foremost association of women in Lebanon, established a progressive kindergarten in Beirut which quickly attained popularity. The Commission, however, was unable to visit it. In the summer of 1946 plans were being laid for the foundation of two boys schools of secondary level in the two well-known Lebanese villages of Suq al-Gharb and Shuwayr on premises formerly occupied by American and Scotch mission schools. The movement was led by graduates of the Ameri-

can University of Beirut. Still another school was being started in Marju'yun with money collected from emigrants from that region now living in England, Australia, and the United States.

Finally, as an example of the private school controlled by the individual initiative of one person, the Universal National College (al-Jami'ah al-Wataniyah) for boys at Aley may be cited. This school, founded in 1907, now has grown to large proportions. It has a French section leading to the first *baccalauréat*, an English section preparing for the American University of Beirut, a commercial section taught in English, and an agricultural section. There was a total of 625 students in 1946, of whom about 200 were boarders. A girls school of about 250 students is maintained in another part of town; it, too, has an English section of three secondary years, and a French section of two years in the secondary school. A summer school is maintained for those who fail in the examinations of the College or of other schools, and for students who wish to prepare for examinations. The student body is composed of students from Lebanon, Syria, Iraq, Palestine, Transjordan, Iran, Hijaz, and West Africa. Graduates of the English section recommended by the College are admitted into the freshman class of the American University of Beirut.

The College has a number of student societies and student teams. It has a library of about 1,200 volumes and occupies a building owned by its founder. Fees range from £L60 to £L230 ($27 to $104.50), and in addition a boarding fee of £L650 ($294) is charged.

Part Seven

INTERPRETATION

Chapter 29

EDUCATION AND CULTURAL CHANGE IN THE ARAB WORLD

We have now come to the end of our journey. Our account of Arab education has been mainly factual and descriptive. No attempt was made to evaluate the systems described or to present suggestions or recommendations. Problems and trends were depicted with hardly any indication as to their ultimate solution or outcome. The reader was left to decide for himself about the merits of each educational system and the problems confronting it. For that, only the most meager of background material was provided.

Yet education is essentially a social process, intimately connected with the stream of life around it, with the currents and crosscurrents of events, with the heritage of the past and the hopes of the future. It is only appropriate, therefore, that after this lengthy account of education in the six Arab states visited, an attempt should be made to gather up the threads of our inquiry; to summarize the problems and trends, and in general to throw the educational picture against the background of political, social, and economic life in the Arab East.

To do this properly would require a separate investigation in itself. Here only a comparatively brief attempt can be made. What in general is the present situation in the Arab world? What are the main characteristics of life in it? Which way is the Arab world heading, and what are the problems it is facing? And, finally, what are the educational measures which have been taken to cope with the major problems and needs and changes in Arab life today? How adequate are they, and what can be done to improve the educational endeavors of the various countries? To these question only a partial answer can be given at present. Our remarks will apply only to the Arab systems of education, and, unless specifically stated, they will not apply to the Hebrew system of education in Palestine.

Background of Arab and Near Eastern Life

The Near East, of which the Arab countries are a part, lies at one of the most strategic points in the world. It provides the connecting link between three continents—Asia, Europe, and Africa—and in this way lies at the crossroads of world communication, by land, sea, and air. This fact has affected Near Eastern history from very early times and has made it an area coveted by many nations and races. At least two other factors have tended in the same direction: the benign temperate climate which, at its hottest, is semitropical, and the potential wealth of the country. In its early days its agricultural wealth was of prime importance; more recently, mineral wealth in the form of oil has attracted international competition. It is not, therefore, an accident that the first civilizations known to history had their birthplace in this region, more particularly in the valleys of the Tigris, the Euphrates, and the Nile. Even the comparatively scanty supplies of such minerals as copper helped very early in history to transfer man from the stone age to an age in which he began to use metal tools in his peaceful, as well as warlike, pursuits.

It is this geographical position of the Arab East which made it the center of trade routes and of paths of invading armies from the very dawn of history. Routes converge upon it from the east through the Iranian plateau; from the north through the Caucasus, the Hellespont, and Asia Minor; from the west through the Mediterranean Sea; and from the south through the Arabian desert and Egypt, the Persian Gulf, and the Red Sea. Along these routes came invading armies and wholesale migrations of peoples, and from this center armies moved in all directions. This fact partly explains the racial composition of the Near East. As far as the Arab world is concerned—especially the Arab world in Asia—the races can be roughly divided into two groups: the Semitic groups coming from the south and including among them such peoples as the Babylonians, the Assyrians, the Aramæans, the Canaanites, the Hebrews, and finally the Arabs. They have given the region its predominant character and provided it with its main cultural heritage. The second group of races are the non-Semitic peoples, which include the early Sumerians, the Kassites, the Hittites, the Medo-Persians, the Philistines, the Greeks, the Romans, the Mongols, the Kurds, and the Turks. Between these two groups a battle seems to have gone on throughout history, with the Semites seeming to win out in the plains of Iraq, and in Syria and Palestine, and the non-Semites preponderant in Asia Minor and in the northern mountains of Iraq and the Persian mountains to the east of it. The Semites never seemed to be at home in the

colder and the rougher mountainous regions, though they occasionally darted through them and controlled them for a while. The non-Semitic races, while getting a foothold every now and then in the plains, were usually driven out or assimilated.

Owing to this geographic determinism, the Near East has, in its long history, managed to be almost always in the center of the picture. The world does not seem able to leave it alone, nor can the Near East afford to remain isolated from world events. Events of the last century and a half and particularly of the immediate present seem amply to confirm this fact.

The welter of races invading the Near East, each leaving in it a stratum of racial deposit, has not only made of it a very ancient melting pot of races, but also a breeding ground of many cultures and the repository of foreign cultures introduced into it. With a clash of races there was also a clash of cultures, and as each race left its remnants in flesh and blood, so did it also leave its remnants in customs, moral standards, dress, religions, literature, art, architecture, languages, and many other aspects of life. Many of these are apparent even today, while many others exercise a more subtle influence. As the traveler or student goes through the Arab East, he cannot help realizing that many of the current practices and tools in use go back to very early times. The camel and the tent, the raft and the *gufa*[1] sliding down the Tigris and Euphrates, the *shaduf*[2] in Egypt or *chard*[2] in Iraq as methods of irrigation, the dress of the great majority of people, the religious beliefs, the superstitions, the customs of hospitality, the tribal and clannish feuds, the standards concerning women, and sundry other phases of life—these have their roots in the very remote past. To them are now being added, as has been done throughout the ages, new practices, new customs, new forms of dress, new tools, and new ideas and beliefs. The most superficial observer cannot fail to see that in any given spot in the Near East the old and the new stand side by side; the old never fully obliterated; the new not yet having its firm roots in the ground. The educator can only reflect that while education has to do with the present and the future, in the Arab Near East it cannot help being concerned with the past and the cultural heritage.

As far as the Arab world is concerned, for the last 1,300 years this racial and cultural heritage has been essentially a heritage from the Arab tribes that migrated into the Fertile Crescent, and established the Arabic language and the religion of Islam, with all the other components that go

[1] A round boat made of palm fronds and bitumen and propelled with paddles.

[2] Primitive device for lifting water from rivers and canals.

to make up culture. Yet, this Arab-Islamic culture is based on a firm foundation of the previous cultures that have nourished the Near East, Semitic or non-Semitic. A glance at the history of cultural migration shows that what is known today as Western or European civilization had its initial start in the Near East. Here it was born and through a few thousand years rose to a certain measure of maturity. Here were initiated so far as we know, advanced methods of agriculture and irrigation, of building and architecture, the wheel on land and the boat on the sea, the early geometrical and astronomical notions, the first phonetic alphabet, as well as the three important monotheistic religions of the world. This great cultural development was passed to the West, in the second and the first millenniums, B.C., largely through the travels and trading of the Phoenicians with the Greek and Italian shores, as well as through their colonies on the southern European shores, in Spain and in North Africa. The genius of the Greeks developed that culture to unheard-of heights, and gave the world its systematic philosophy, the systematizing of mathematics and astronomy, discoveries in medicine and some branches of science, and the great Greek literature, art, and architecture.

As the Greeks turned the tables on the Persians, and through Alexander the Great began to take the offensive, civilization began to go back to the East, which thereafter enjoyed the Hellenistic civilization reinforced later by the contributions of the Romans. For a thousand years the Near East was under the influence of Greek ideas, to which it added those of Christianity—an oriental contribution which spread far to the West. As the Arabs came into the scene in the seventh century, civilization had been for sometime on the decline. The Arabs in their turn, as representatives of the East, adopted certain phases of Greek civilization, merged them with some contributions of Persia and India, and with the religion of Islam, to constitute the great Arab-Islamic culture, which spread from India and Central Asia to Spain and the Atlantic. It was through Spain, southern Italy, and Sicily, through the Crusades and the traders of Venice and Genoa, that this civilization found its way into medieval Europe, and was a factor in bringing about the European Renaissance. As Europe took up the torch, the Near East fell a prey to a new wave of barbarian and semibarbarian invasions which obliterated its political and cultural life. Beginning with the nineteenth century, however, there has been a stream of cultural influence from the West back to the East, for the second time. And today the world is witnessing a new awakening in the Near East and the Arab world, owing to the impact of Western ideas.

Perhaps the best conclusion that can be drawn from this swift glance at

cultural migration is that the culture of the Near East and of the Arabs, while differing in some important respects from that of the West, falls essentially within the main cultural stream which has brought about the present Western civilization. In many fundamentals, therefore, the present Arab culture of the Near East is not entirely foreign to the culture or cultures of the West.

It is necessary to bear in mind these ideas about the racial and cultural heritage of the Arab East, and about the geographical location of the Arab countries, in thinking over the educational situation and problems in these countries. With this broad background it may be of use to survey briefly and pointedly the present situation in the Arab countries studied in this report and the main forces affecting their life and destiny.

Chief Aspects of Modern Arab Life

AN AGRICULTURAL ECONOMY

One of the most outstanding facts about Arab life is its fundamentally agricultural economy. The overwhelming majority of the people live on the land and subsist by agriculture. This is as true of Iraq as of Egypt, of Syria, of Arab Palestine, and Transjordan. Even Lebanon, which is proportionally the most largely urbanized because so many of its villages have been turned into summer resorts, is still largely rural. Built upon this agricultural economy is a system of trading and commerce whereby goods are exchanged within the country or exported and imported from and into the country. The farmer has to dispose of his produce in the towns and in return receives agricultural implements, clothing, tea, coffee, sugar, and a few other necessities and luxuries. The excess of the agricultural produce thus purchased in the towns is, naturally, shipped abroad, and in return goods are imported from abroad to meet the needs of the countries. A few industries exist which cater to the needs of the country districts. These industries, the remnants of a once-great past, have suffered a tremendous eclipse since the mass production of machine-made goods in the West. As a result most of the goods needed in the countryside are no longer produced locally but are imported from abroad, and the apparent balance of trade in almost all the countries surveyed shows an unfavorable balance of imports over exports. Thus, even the urban districts are to a great extent no more than marketing centers for the rural areas and live largely as mushroom growths on the countryside.

More recently, particularly after World War I, efforts have been made to revive industry and re-establish it on a modern machine basis. This move-

ment is still in its infancy and has so far succeeded in introducing only lighter industries, such as the making of cotton goods, woolen cloth, soap, cement, sugar, leather products, and the like. In this movement Egypt is now undoubtedly the leader, partly because of the greater wealth of the country and partly because it has had an organized modern government and a modern economy for a longer time than the rest of the Arab world. World War II in some respects encouraged the growth of industry, especially in Egypt, owing to the difficult transport situation, which virtually cut off the inflow of manufactured goods from the West. How far the industrial movement can develop in the face of great competition of mass-produced goods is a difficult question to answer. There is no doubt that such a development is needed in order to raise the standard of living in the Arab countries and to improve the adverse balance of trade. It would also help utilize in a better way some of the agricultural produce of the countries, such as cotton and wool, which are now largely exported and are brought back in the form of manufactured goods from the West. So far as is known at present, the Near East has the power necessary to motivate the wheels of industry in the form of plentiful petroleum and water power, but does not have sufficient quantity of metal for the creation of heavy industry. Rich deposits of iron are reported in southern Egypt, but so far have remained unexploited.

The predominance of agricultural economy in the Arab East is perhaps the most important determinant of its low standard of living. More accurately it is the low level of efficiency in agricultural exploitation of the land and the prevailing methods of land ownership and tenancy which are the main causes of the low standard of living. On the whole the lands are fertile in Iraq, in Egypt, and in Syria, and less so in rocky Lebanon and Palestine. There is, therefore, a potentiality of high productivity in the soil if well exploited. At present, with the exception of Egypt, agriculture is more extensive than intensive, and the variety of produce is limited mainly to those grains more immediately necessary for the subsistence diet of the people. The growing of cotton in Egypt and of oranges in Palestine for purposes of export are almost the only exceptions. There is a great need for teaching the farmers more modern methods of agriculture, such as the use of fertilizers, the sound methods of irrigation, the improvement of strains of agricultural produce, the introduction of a greater variety of crops, the fighting of pests and parasites, the methods of grading the produce, and cooperative buying and selling of such produce. With these must be coupled more scientific methods of raising livestock, of improving the breeds, and of protecting them from diseases and scourges. In addition,

there is need for the conservation of water resources and the better use of those resources, both for irrigation and for water power. Some of the lands of the Arab East today show many signs of better exploitation of water resources in the past than in the present. The remains of great canals in Iraq, of abandoned subterranean channels, and of wells in northern Iraq and Syria are the best testimony to that effect. At the same time the hillsides now largely denuded of trees, owing to centuries of cutting and little or no planting, are in crying need of reforestation. This will not only increase the timber wealth of the countries where timber is now largely imported, but will also help conserve the soil on the mountain slopes, and slow down the running of rain water in torrents, so that it could seep through the ground and be of more benefit to the vegetation. One might also add that in the great plains of Egypt, Syria, and Iraq there is an unlimited field for the use of agricultural machinery and improved farm tools.

The problem of land ownership

The systems of land ownership and land tenure are not such as encourage the development of agriculture and the improvement of the methods of farming. Indeed, they may perhaps be the greatest obstacle in the way of agricultural development. The prevailing system is either a situation where the government owns most of the land and leases it out to tribal chiefs and influential people, who in turn distribute it among individual farmers, or a system where large tracts of land are owned by wealthy landowners, usually living in the cities, who rent out the lands at comparatively high rentals to farmers, or exact from the farmers a more or less high share of the produce. Under such systems the individual farmer's annual income is very low and his interest in the improvement of the land is at a low level, with the result that in certain regions a deterioration of the land is manifest. As an added factor in Egypt, one must mention the fact that the amount of cultivable soil is limited as compared with the dense population of that country. While intensive farming is practiced, the exceedingly small plots exploited by each farmer, together with the payment of rent on them, make the income of the farmer sadly inadequate to take care of his usually large family. The net result is a very low standard of living and inability to support local institutions and social services, poor homes and clothing, the bare necessities of life, and barefootedness and disease. In some parts of the Arab world, notably in the Lebanon mountains, which form the original part of autonomous Lebanon, a system of individual land ownership prevails. Here one can readily see a more independent-minded farmer and at the same time a more prosperous one. Better and cleaner homes, better clothing for men,

women, and children, and healthier bodies fostered also by the mountain climate are apparent.

Of late the Arab world has been showing signs of awareness of its land problem and of its injurious influence on its national interests and economic, political, and social development. The Iraq government is experimenting with a new method of distribution of state lands by fixing a limit on the number of acres that can be alienated to an individual. In Egypt an active movement of social service is spreading for the purpose of fighting illiteracy and disease, teaching better methods of farming and of social organization to the farmers. These are promising trends which, if pursued, may eventually lead to healthier farming communities.

This description of agricultural and rural life in the Arab world has its obvious bearing upon education. The low level of production and the meager wealth eked out of the land impede the development of education and sometimes make it impossible, but conversely there is also the fact that education, whether general or vocational, can be a tremendous force for the enlightenment of the people, for the improvement of agricultural technique, and for increasing the wealth of the farmer.

The influence of Islam

Another outstanding fact about the Arab world is that it is predominantly Muslim. Islam is a religion preached by the Arab Prophet Muhammad and carried by Arabs and later their converts to the confines of the globe. It would be difficult here to do justice in describing Islam, as a system of faith, as a way of life, or as a world brotherhood. We are much more concerned here with the plain fact that Islam forms a predominant and substantial portion of the heritage of the Arab world. Not only has it influenced its beliefs and attitudes, its language, its expression and its mode of life to a very deep extent, but it has also literally brought the Arabs to a position of world dominion in the past and helped to preserve them as a nation, after the downfall of the Arab Empire. Largely though the Koran the classical Arabic language has been preserved as a living language centuries after Arab dominion disappeared. And as the Arab world reawakens, that same Arabic language regains a new vitality and a new force.

Muslim Arabs, whether they may be deeply religious or not, today are justly proud of their Muslim religion and heritage, and keep to it with an unshakable loyalty. This loyalty now manifests itself as an ally of Arab nationalism, and as a factor in the defensive struggle of the Arabs to maintain their identity in the face of Western imperialism. Often an attack from the West on the Arabs is pictured as a lurking danger, not only to the

Arabs, but to Islam, and forces are rallied for the defense of the cause of the Arabs, which is the cause of Islam as well. Thus today, as in the past, Islam is one of the forces that is helping to preserve the unity of the Arab peoples. In all of the countries studied, excepting Lebanon and Palestine, Islam is the official religion of the state, and its tenets are taught to Muslims in the public schools.

Today Islam, always a comparatively tolerant religion towards the adherents of other monotheistic religions, is becoming even more tolerant. There is a community of intercourse today between Christian and Muslim all over the Arab world, which is immeasurably greater than it was in previous centuries, in spite of the fact that religious lines still remain very distinct. In this movement the general enlightenment of the age, as well as the pressure of Western imperialism, have brought about a greater understanding among the adherents of the two religions engendered by a community of interests. This has been apparent in the national struggles of Egypt, of Palestine, of Syria, and of Iraq.

The Rise of Nationalism

A fourth aspect of life in the Arab world today is the resurgence of nationalism, which fills the air of the whole Near East and cannot be missed by even the most casual observer. Nationalism began in the Arab world in the latter half of the nineteenth century at the hands of literary men who rediscovered the beauties of Arabic literature and the glories of the old Arab Empire. Side by side with these were religious reformers who wanted to introduce reforms into the Ottoman government, which was then recognized as the successor of the Islamic Empire. As the two protagonists complained of the autocracy of the Ottoman sultans and the backwardness and corruption of their rule, the two voices tended to blend. Arab nationalism, however, did not begin to make rapid headway until the twentieth century when the overthrow of autocratic rule in 1908–9 brought to the fore the Young Turks as the ruling party in the Empire. The attempt of the Young Turks to pursue a pro-Turkish policy which did not give enough weight to the other national elements within the Empire brought a reaction amongst the Arabs, particularly their deputies in the Ottoman Parliament and their young students in the colleges of Istanbul. Open and secret societies began to be formed, some limiting themselves to internal reform, others asking for decentralized rule within the Empire, and still others calling for the independence of the Arabs. In its early aspects, therefore, Arab nationalism took the form of a struggle against the ruling Turkish element. In this it found encouragement from some of the foreign powers who entertained

ambitions of partitioning the Empire for their benefit. World War I brought matters to a head when some of the Arab elements were dissatisfied with the entry of Turkey on the side of the Central Powers, and when the Young Turks took the opportunity to eliminate some of the leaders of the Arab national movement. The hanging of a large number of Arab leaders in Damascus and Beirut and the banishment of others gave the signal for plotting the Arab revolt. Sharif Husayn, of Hijaz, and his sons secured promises from Britain for the independence of the Arabs and declared a revolt against the Ottoman Sultan in 1916, joining the Allied campaign, which led finally to the overthrow of the Turkish armies. Thus, came to a close the first phase of the Arab national movement which was the struggle for the liberation from Turkish rule.

It was soon found out, however, that the Allies had, through secret treaties, partitioned the northern Arab countries into zones of influence and zones of outright occupation. At the same time the Balfour Declaration promised the Jews a National Home in Palestine. Strategic considerations, oil and other economic considerations brought final agreement between Britain and France which gave Britain the ascendancy over Iraq, Palestine, and Transjordan, and France control over Syria and Lebanon. As the League of Nations began to take shape, the idea of the mandate was invented as the form which British and French authority was to take over the Arab provinces of the former Ottoman Empire. The whole idea of spheres of influence and of mandates was opposed strenuously by the Arabs, who vainly sought for the application of the principle of self-determination to support their claim for independence. The demands remained unheeded, the mandates were granted to Britain and France, the principle of the National Home for the Jews was written into the mandate for Palestine, and the second phase of the Arab national struggle for liberation of the Arabs from British and French dominion and Zionist ambitions began.

The course of the national movement in Egypt has a different history. Muhammad 'Ali Pasha, the great founder of the present ruling dynasty of Egypt, had succeeded early in the nineteenth century in establishing himself as the ruler of Egypt owing allegiance to the Ottoman Crown. He had toyed with the idea of establishing an Arab Empire carved out of the Arab provinces of the Ottoman Empire. He had waged war against the Sultan and his armies, had threatened even the capital, Istanbul, but the interference of foreign powers finally led to the withdrawal of the Egyptian armies from Asia Minor and Syria, and Muhammad 'Ali had to be content with Egypt. His successors were given the title of Khedive or Viceroy, and for a long time Egypt pursued its own course within the

nominal authority of the Sultan. The British occupation in 1882 gave an incentive to Egyptian nationalism which took definite form in the late nineteenth and earlier twentieth centuries by the establishment of the Egyptian Nationalist Party with the avowed aim of liberating the country from British rule. In their attempt to liberate Egypt from Britain, the Egyptian ruling class and the Nationalist party found a natural ally in the Ottoman Empire, a fact which created new ties with, and a new allegiance to, the Ottoman Sultan. It thus came about that Egyptian nationalism followed a different course from that of the rest of the Arab world which was trying to liberate itself from the Ottoman yoke. After World War I, however, the national struggle of both parts of the Arab world took the same direction, namely liberation from the two European powers dominating them, Great Britain and France.

The period between the two World Wars was largely occupied with the struggle for liberation which conditioned the attitudes and thought of the generation which went through it. A long series of demonstrations, boycotts, and revolts rose, now here, now there, in the countries under study. Slowly the nationalist movement made some headway. Egypt obtained some measure of independence and a constitution in 1922–23, and in 1937 secured the abolition of extraterritoriality and the promise of withdrawal of British forces to the Canal Zone. Iraq was finally declared independent and admitted into the League of Nations in 1932. Syria and Lebanon had a longer struggle, their independence being promised in 1941 by the de Gaullist regime, and put into effect in 1943. The withdrawal of French forces did not finally materialize until 1946. Transjordan was declared independent in 1946. In Palestine alone the struggle[8] of the Arabs against Britain and Zionism is still going on. A new nationalism, that of the Jewish Zionist immigrant, has sprung up. Though having conflicting interests, Arab and Jewish nationalism did not come into an open armed conflict except in isolated instances until 1948. Rather they have both, though at different times, directed their attacks at Great Britain, the author of the Balfour Declaration.

In the last few years Arab nationalism has taken a new direction, that of bringing together various Arab states into an Arab League which would try to bring some unity in their actions and policies and create a united front in the face of outside danger. The Arab League has also been trying to foster better communications among the countries of the Arab world, a more unified economic policy, bringing the various educational systems into

[8] The reader should keep in mind that this manuscript was completed in the summer of 1947.

closer relationships, encouraging Arab letters and science, and trying to bring about some sort of unified citizenship. All of these are still in their initial stages. Arab nationalism, however, seems to have the double task of bringing about internal reforms and of protecting the country from foreign intrusion. While Syria, Lebanon, Sa'udi Arabia, and Yaman are free from foreign armies, the other Arab states still have contingents of them.

Nationalism has not only been a potent force in the general life of the Arab world, but it has had an influence on its educational systems and practices. That influence is bound to continue for some time to come. The Arab educator usually thinks of schools as the main channel through which the Arab nationalist spirit can be spread and taught to the younger generation. Youth ought to be made proud of the nation's glorious past so as to be spurred to further action and to work for the revival of the Arab nation. They ought to be taught the geography of the Arab world and be made conscious of the possibilities of their land. There has gone into this phase of the struggle against Western imperialism an attitude of animosity toward any form of imperialism. This, naturally, has developed into some aversion toward some of the Western powers, though not against things Western in general. On the contrary, there is a general realization that acquisition of Western methods and techniques is in the national interest, although a dissenting voice may be heard here and there.

Western imperialism

A discussion of nationalism among the Arabs brings up the topic of its antithesis—imperialism. Western imperialism has been responsible to a large extent for arousing the spirit of nationalism in the East. Western imperialism with regard to the Arab world had its roots in the nineteenth century when most of the known European powers had ambitions for the acquisition of land in Arab countries. Turkey being on the decline, there grew up in the nineteenth century what was known as the "Eastern Question," which in effect was little more than the problem of partitioning the Ottoman Empire among the ambitious powers. World War I provided the chance for it. While some of the contestants were out of the struggle—namely Russia, Germany, and Austria—the others, Britain and France, partitioned among themselves the Arab provinces in Syria, Palestine, and Iraq. Britain had already occupied Egypt, and Italy had wrested Libya. Britain besides had made treaties with a number of the Arab principalities around the coast of the Arabian peninsula which brought these definitely under her influence. For two generations in Egypt and for one generation in

the rest of the Arab world, Western armies have been moving around in the Arab countries. There has naturally grown a desire for the withdrawal of these forces and for the realization of Arab independence in one state or in many states. This has created an attitude of defensiveness among the educated Arab class which is quite apparent in Arab youth and which has been nurtured by the press, the radio, the schools, and all other agencies.

It is difficult to predict the course of nationalism and imperialism in the Arab world. Most of the Arab states are now independent, but the conscious citizen of the Arab world has grown suspicious of any form of foreign influence, whether in the form of colonization, mandate, trusteeship, or economic developments. Even in cultural and educational activities Western efforts have now and then come under suspicion. The fact that the Arab world feels weak before the great force at the disposal of the Western powers aggravates this attitude. In some instances the attitude of aversion to imperialism has made students dislike the idea of learning a foreign language though the elders realize the benefits to be derived from that. In other instances, European powers have been accused of deliberately withholding facilities for education in the countries they occupied in an attempt to hold back the progress of those countries and keep them under their sway. In other cases they have been accused of intentionally spreading propaganda for their own countries through their own schools.

The coming of democracy

Political democracy came to the Arab world with the introduction of the constitutional reform in Turkey in 1908 and 1909.[4] Since then, with the rise of the new Arab states under the mandates of Great Britain and France and with the rise of independent Egypt in the twenties, all the Arab countries studied in this report except Palestine have developed their own democratic institutions which provide for elected representatives to meet in parliaments, either of one or two chambers. Cabinets are responsible to these parliaments, the king or president of a republic providing the final sanction for legislative and executive action. In theory therefore, the machinery exists for democratic rule by the majority.

In practice, however, this is limited by a number of considerations. In some of the countries, cabinets may be dismissed by the action of the chief of the state, without an adverse action by parliament, while in others the electoral system does not function as smoothly as is desirable. Elections may be by direct or indirect primary. At the same time, the fact that many of

[4] There had been an abortive attempt at constitutional government in the seventies.

the Arab states were under some form of foreign influence has meant, in some instances of conflict with the interest of the foreign powers, that democratic institutions have been maneuvered in order to sanction the interests of the outside powers.

Local and municipal councils also exist in most of the countries studied. These may be elected or appointed or both, so that the machinery for some measure of local government exists. However, it may be said that in a large number of cases, local councils are not strong enough to assert themselves in the face of the central government. Nor are their powers wide enough to respond fully to the wishes of the local population. The highly centralized forms of government naturally lead to policies being shaped more in the capitals than in the local communities. One justification for this is the widespread illiteracy and the lack of experience in handling local affairs with any degree of efficiency. Since the educated citizenry with its powers of progressive leadership is largely concentrated in the capitals, it naturally follows that progressive policies have to be formulated in the center and handed down to the provinces.

Thus, democratic institutions and ideas, though existing, have not yet taken firm root in the lives of the people. The average Arab is in his own way an inborn democrat. The old form of Arab tribal tradition, as well as the early Islamic tradition, is imbued with the ideals of equality among the members of the tribes or among Muslims, and matters are in the main decided not by individual autocratic methods but in council. The tradition of early Arab life, however, has throughout the ages been overshadowed by the autocratic rule of empires, so that the principles and ideals of modern democracies are not understood well enough at the present to insure the smooth running of democratic institutions. These are difficult enough to handle even in the most advanced countries. They will, therefore, need a long period of education before they take firm root. The Arab is an individualist by nature of his background, and democracy is in essence a cooperative method in which individuals act with due consideration to the will of the majority. Its essence is compromise between the conflicting points of view, a fact to which the extreme individualist does not take too easily.

Socialism and communism

Yet, another, though more recent aspect, of the Arab scene is the appearance in the last decade or two of socialistic and communistic ideas and theories. These are not derived only from propaganda, more particularly Russian communistic propaganda. They have also come in through reading of French and English socialistic and communistic theories. Interest in these

theories has also been developed by students studying in western Europe, particularly pre-Hitlerite Germany, France, and England. They represent a wide range of ideas from mild socialism to advanced forms of communism. The presence of widespread poverty among the masses of the people and the unequal distribution of land and of wealth provide a fertile field for socialistic and communistic propaganda, which can picture socialism as the natural and logical method of getting rid of all these evils. Another method used, especially by Communists, is to pose as an implacable enemy of imperialism and as a natural ally of the nationalist forces. The Western powers in Europe having been the aggressive powers occupying the Arab world, the net effect of communist propaganda would then be to discredit them and what they stand for in the eyes of the Arab public. It is in this way that the attitude taken by people sometimes takes the form of Communism *vs.* Democracy, Democracy being pictured as the ally of imperialism.

Socialism and communism are as yet too recent in the Arab world even to be considered as serious movements. The future spread of socialistic and communistic ideas will probably depend very largely on how the situation in the Near East is handled by the Western allies and how democratic the behavior of the so-called democratic powers is in the Arab world. It will probably also depend on whether the Western powers will be too busy looking after their interests and exploiting the resources of the country without giving due regard to the interests of the people themselves or whether they will ally themselves with the progressive forces in the countries working for reform and progress.

The changing scene

Finally, an atmosphere of change is one of the leading characteristics of modern life in the Near East and the Arab world. The habits, customs, attitudes of thousands of years are changing. The physical surroundings in the towns, as in the rural districts, are being gradually but surely changed by new forms of building and architecture, new methods of planting, of landscaping, and new ways of transportation. Along with these changes is coming a great change in ideas, values, and behavior, in art and literature, in character and moral affairs, and in political methods of organization. This change, which began in the early nineteenth century, has been gathering momentum with ever-increasing force. It is due almost entirely to the contact which modern communication has made possible between the East and the West. The invasion of things Western is not confined only to armies or to political predominance, but is also manifest in economic pene-

tration whether by investment of foreign capital or the dumping of Western products of all sorts on the markets of the Arab world. It has also taken the shape of schools where Western ideas are expounded and taught to the new generations. Travel has played its part as has the study of Arab students abroad. More recently, the radio and the increasing supply of Western books and periodical literature have also played their role.

As a result, life in the Near East can be said to be in the melting pot. The old ideas and concepts are being gradually mollified and whittled down. There is, therefore, what could be called an increasingly liquid situation. Will it take any mold, and what type of mold will it be? Can this process of change be controlled or at least directed into certain channels? Or should it be left to the haphazard happenings of time? And if it is to be controlled and directed, then by what means? It would seem obvious that part of this direction at least can be exercised through education, though education alone is not strong enough to shape the things that are to come. The forces at play are too big and too varied to be confined in the schoolroom.

A number of anxious questions may be asked and are being asked about this cultural change. What will happen to the cultural heritage of the East? What of the religious concepts that have grown in the East? What of the customs, of the literature, and of the art can be saved under the driving force of Western civilization? Will most of these be swept away, or can they be adjusted to the new spirit and be so modified as to fit themselves into the new pattern of life? Will the Arab world be able to maintain not only its political independence but also its entity as a cultural unit? In the past the Near East succeeded in maintaining and assimilating within itself the cultural influences that bore upon it from outside. Will it be possible to repeat the process even in this dynamic age where things happen in a bewildering succession and where assimilation, therefore, becomes extremely difficult? Will the Near East, therefore, be culturally swept off its feet, or will the new culture so blend with the old as perhaps to provide a new message and a new contribution by the Near East to world civilization?

And what about Western civilization itself? Is it to be taken in its totality, or is it to be studied and scrutinized so that its virtues and weaknesses may be ascertained? Is the Near East to benefit from the mistakes made by the West in order to avoid some of them, or is it necessary that these mistakes be repeated? And how can the pitfalls be avoided? How shall Western civilization be understood? There is at present a pronounced tendency to be so dazzled by the achievements of Western civilization in the

field of industry, of war and armament, and in the field of health and medicine that it is easy to overlook the other less apparent and more intangible forces that have made Western civilization, such as intellectual curiosity, freedom of thought and inquiry, the value of human life, the worth of the individual, his personality and ideas, the equality of woman with man, and many other ideals which have influenced the development of systems of government, economies, and social life. Will these more subtle aspects of Western civilization be appreciated well enough so that an intelligent attitude can be taken toward that civilization? And how is that going to be accomplished?

Moreover, Western civilization is coming to the East from many lands and national groups—from America, Great Britain, France, Germany, Russia, and many other sources. Naturally, the national rivalries of these countries tend to show themselves culturally also, and there is often a conscious or unconscious attempt by the protagonists to push themselves forward to the exclusion of the others. What shall the attitude of the Arabs be toward each of these particularized forms of Western civilization? With the many national rivalries shown in the various foreign schools in the Arab world and by persons studying in the various Western countries, there have grown advocates among the Arabs of this or that national culture, one discrediting the other. In this way there has developed culturally among the Arabs a house divided upon itself, and various schools of thought and even of behavior have shown themselves. How is it possible to make these groups with different cultural backgrounds cooperate with each other? Is there any way by which this difficulty can be obviated at its source? Is it possible or desirable for the Arabs to take an eclectic point of view and pick from each culture what appears to suit their needs? How can that be done without risking internal complications? In the face of international rivalries, can the channels of contact with the multitudinous cultural influences be kept open so that the new Arab culture will have the broadest bases for its development?

All these questions and a number more present themselves about the cultural situation and the future adjustment of the Arab world to this impact of Western civilization. But one more question is basic. Have the Arabs any choice in this matter of cultural adaptation, and how wide is this choice? Not only is the power of certain Western nations such as will force upon the Arabs certain courses of action and adaptation, but the forces at work in general are so varied and so great that the choice in many instances will be extremely difficult.

Finally, what does all this problem of cultural change in the Near East

mean when translated into educational terms? What does it mean in terms of schools, curriculum, and methods? How can education be so shaped as to help modify that Arab tradition without losing its essence? How can it help introduce the best in Western civilization while avoiding some of the pitfalls? And how can it work for the integration of the two so as to create a new whole which shall operate in the lives of the Arabs in the future? The problem can only be posed here by stating the need for an educational philosophy that will guide Arab educators in the future. Things so far have not progressed much beyond the mere raising of these questions, but as the Arab world and Arab educators attain greater maturity, they are likely to receive greater attention.

Summary

In summary the following points of significance to education in the Arab world are indicated.

The Arab world is now nationally conscious. This consciousness is increasing and in the past has taken the form of a struggle for the liberation of the Arabs from Turkish rule and later from Western domination. This objective, now largely achieved, is being directed toward establishing some unity of policy among Arab states, designed as a defense measure for the preservation of national independence. At the same time nationalism now has the constructive task of developing the resources of the countries and introducing widespread reform.

Democratic institutions have been established. They need to be strengthened by a more enlightened electorate which will be more conscious of its rights and responsibilities.

The Arab world can be said to have unlimited opportunities for economic development. Large tracts of cultivable land running into millions of acres remain unexploited and those parts that are now under cultivation can be exploited more efficiently by irrigation, the conservation and utilization of water resources, and the utilization of water power. There is a great opportunity for future development for generations to come. The same may be said of certain types of industrial development and of the development of oil resources. The small population, sparsely distributed (except in Egypt, Lebanon, and Palestine), may, for the time being, set limits to this development, but when health conditions are improved, a steady rise in the population is noticeable, which in the long run, may bring back to the Near East its concentration of human power. In the field of agriculture and industry, as in the field of health, education can play a great role.

Finally, the impact of Arab and Western cultures presents a problem of its own. This problem can be stated as: How to build up a new Arab culture which will have the broadest basis possible, one which will have its roots deep in Arab and Near Eastern culture, Western, and world cultures? In the present cultural change established standards are melting away, and there is a moral danger that youth may lose its balance; character education to help youth orient itself becomes, therefore, an imperative and crucial need.

It is against this background, however inadequately stated, that the problem of education must be projected; and in the light of this situation the achievements and potentialities of education must be gauged.

Educational Problems and Prospects in the Arab States

EDUCATIONAL PROGRESS BETWEEN THE TWO WORLD WARS

The student of education in the modern Arab world cannot help but be impressed by the great progress which has been achieved in the last quarter of a century. Judged by the absolute ideal of universal school attendance and literacy, this progress may, to the superficial observer, seem to fall short of the standard of the civilized world. Considered, however, from the standpoint of the starting point, about 1920, the advance, in spite of all the political struggles and economic hindrances, has been very great. In many instances school attendance has been trebled and quadrupled, and in some instances multiplied by ten and more times. This is true in all the countries surveyed, though in different degrees. Not only has there been a quantitative expansion of the educational systems, but also a rise in the standards, an establishment and advance of higher education, and some measure of qualitative change in the curriculum. One cannot ignore also the positive advance in the field of education of girls, a fact which holds great promise for the future. The sending of educational missions abroad has helped to educate a staff of specialists and leaders in the various fields, and all the countries are contemplating plans for increasing the number of missions. Coupled with all this is the rising demand for education among the people—a demand which cannot always be met with the resources at hand, resulting in a lag between demand and educational facilities provided. There has also been great improvement in textbooks, in equipment, and in school buildings. Before World War I governments were not fully conscious of their responsibilities in the educational field, and, therefore, education lagged far behind other activities of the state. Today all the governments in the countries visited are actively engaged in increasing

educational facilities so that tax-supported schools form the bulk of the school system except in Lebanon.

A break with the past

In building up their educational systems, most of the Arab states have abandoned the old form of common, ungraded school, the *kuttab,* and established new forms of schools modeled after the Western graded types. The only exception to this is Egypt, where, along with the modern European type, the former *kuttab* has been developed, improved, and graded to include all the usual studies of elementary education except a foreign language, and with a greater emphasis on religion and Arabic. In a way, therefore, the new educational development in the Arab world represents a break with the past and an orientation in a new direction. The reasons for this break are largely historical. The gap between Western progress and life in the Arab world was so great that in their anxiety to catch up with the advance in science and to establish colleges for the training of medical men, engineers, army officers, and the like, the governments had to establish modern schools to prepare youths for entry into these colleges. The old school, limited to the Koran and the three R's, was hardly adequate for this purpose.

Western influence and westernized schools

A contributing factor which brought about this trend was the influence of foreign individuals and groups operating in the Near East and the Arab world. The first educational council in Egypt, established in 1837, was made up almost entirely either of foreign persons in the employ of the Egyptian government, or of Egyptian students who had studied abroad, mainly in France. Later a foreign inspector was employed for almost twenty years, and after the occupation of Egypt by the British, British officials played a large role in the shaping of educational policies until 1922. In other parts of the Arab world—especially in Syria, Lebanon, and Palestine—foreign mission schools preceded any organized modern government schools established by the Turks and naturally served as models for both public and private schools established later. The public-school system of the Ottoman Empire, established in the latter half of the nineteenth century and improved in the early twentieth century, was largely influenced by Western models, notably the French. With the coming of the mandates of Syria, Lebanon, and Palestine, French and British educational authorities played a controlling influence in the shaping of education in the post-war period. In Iraq the new educational system was started in 1915 by the

British authorities and later was developed by Iraqi educators who had been influenced either by French or American types of education.

It is a source of no wonder, therefore, that education in the various countries studied shows many signs of imitation of Western models. Western curriculums and methods were borrowed. Western systems of examinations, mainly after the French model, were adopted, and today one of the main sources of pride in some of the countries is the fact that the standard of the baccalaureate is as high as the French, or that the standard of matriculation is higher or more difficult than that of the University of London. Things went so far even as to have the Arabic-speaking children in public schools taught in foreign languages. This was true in Egypt, for example, between 1885 and 1907, and of Lebanon during the French mandate. A high standard of proficiency in foreign language was required. The result was a high percentage of failures among those students who could not rise to the academic and linguistic standards set in elementary and secondary schools.

It was only natural that educators coming out of the West, or Easterners studying in the West, should fall to copying Western models, particularly at a time when educational research had not yet started in the Near East, and traditional forms of organization and of curriculums prevailed in the West. Transplanted from Europe and America to the East, methods and curriculums, however suitable they might have been to the needs of the Western countries because they had grown up within them, could not meet adequately the needs of Eastern countries. When large public-school systems began to be established, it became more and more a pressing problem to scrutinize critically these Western models and their suitability for the needs of the Arab countries. This has not been done to any marked degree. The reason is largely the fact that most of the educational systems are too recent to have had the long historical evolution which would make for their adaptation to their new environment.

Need for professionally trained personnel

But there is yet a second reason. It is the lack of educationally trained personnel in the various departments and ministries of education in the Arab world. For the most part, educational policies are being shaped by people who have had some form of education, now usually higher education, but who have had little acquaintance with educational philosophy, with educational psychology, with modern techniques of educational methods and curriculum construction, and the various problems of educational administration and organization.

This seems to be one of the outstanding needs of the educational departments of the various countries. Some are completely lacking in professionally trained personnel, others have a very inadequate number of them. Yet the problems to be studied scientifically are legion. There is need for social and educational theorists who will be able to deal with the educational problems in relation to the general social, political, and economic background of the countries, who would translate into educational terms the various currents and changes in Arab life. There is need further for a study of the multitudinous needs of the environment in order to lay down curriculums that will meet these needs. The simplification of the teaching of Arabic is a problem faced by almost every Arab educator, and upon its proper solution depends to some extent the success of campaigns for combating illiteracy.

No standardized mental and achievement tests as yet exist in the Arab world, so that it is difficult to follow scientifically the progress of students, to diagnose their abilities or defects, and to make adequate provision for their needs. Educational administration is carried on in an amateurish fashion, which often is wasteful of time, effort, and funds. New buildings are sometimes constructed so poorly that they fall into ruin within a decade or two, and there is hardly any computation of a standard cost per unit of classroom or school. A professionally trained staff would help avoid many mistakes and pitfalls, and would help lay down sound and broad plans for the development of education in the future. Hundreds of such trained men and women are needed throughout the Arab world to occupy key positions in educational administration, in the teachers colleges, and in important strategic schools.

Along with the steps that need to be taken for the training of such personnel, there is need for establishing research centers in education and psychology which will study specific problems facing each country. Such research will make it possible to base educational policy on scientific studies and to adapt education to the needs of the countries.

Centralized Systems

The present study has clearly shown that education in the Arab states is almost completely centralized. Policies, curriculums, textbooks, plans for expansion, examinations, and certificates are all handed down from the central offices in the capital of each country. Under the central office there are usually regional offices which take their orders from it and which exercise a limited influence on the shaping of educational policies. Their job is to execute the orders of the central office and to see that those sub-

ordinate to them apply them properly. The local communities have little to say about courses of study, books, methods, the appointment of teachers, and in actual fact contribute little money or effort towards the maintenance of their own local schools. Throughout the various states (except possibly in Lebanon) there is a certain dependence on the central government which leaves almost everything in education to it. Education is financed almost entirely from the central budgets, and little local taxation exists. This does not make for local interest in the schools, or local concern about them, or local cooperation in their proper running. The school is not conceived of as a part of the community, but as a part of government which is something different from the people.

The reason for this state of affairs is in part the fact that all government and public institutions are centralized in the same fashion, and in every department of the government orders are received from the center and applied in the provinces or localities. Even local councils and the municipalities in which they exist do not have the strength that they have in Western countries. But there is still a deeper reason. The best talents are usually concentrated in the capitals, and the idea prevails that it is up to the intelligentsia to lead the way in the regeneration and development of the country. People in the smaller centers cannot be depended upon to lay down constructive, progressive policies. Since centralization prevails in all the departments of the government, it is naturally difficult to decentralize educational administration. Yet this is greatly needed at least to a degree. It is needed to arouse more interest by the people in the education of their own children. It is needed for levying local taxes and providing local funds for the better and wider development of schools. Today schools have to secure almost everything from the central government—buildings, desks, salaries, as well as library books. Local responsibility is also needed in order to establish a bond between the school and the community, so that the school can better influence the life of the community and the community provide a stimulus for the activity of the school. The development of local institutions is also needed for better democratic living as well as for better running of social and educational services.

Attempts have been made in some of the countries toward throwing some of the responsibility for education on the shoulders of local authorities. In Egypt provincial councils were asked to bear the cost of the compulsory schools, but not enough taxing power was granted these councils to enable them to support the schools, and the main burden, therefore, fell again on the central treasury. In Palestine the government has insisted that the Arab villagers provide the buildings for the schools, and councils

have been empowered to levy taxes for the schools. In this way a large number of schools were built and even teachers employed by the local authorities. More interest in the schools by the people can be witnessed as a result, and while educational facilities are admitted to be inadequate by the government itself, throwing the responsibility on the local communities has had a beneficial effect in arousing in them a sense of responsibility for education. In Iraq the establishment of local councils has just been written into law, and it is not possible to predict how this scheme will operate. In Syria responsibility for village school buildings has also been laid upon the local authorities. These measures are still in their infancy and are far from being perfect. Why, for example, should villagers in some of the countries be required to provide the school buildings, while the government provides them in the cities—usually rich municipalities—is difficult to explain or justify.

LIQUIDATION OF ILLITERACY

Perhaps the most fundamental educational problem facing the Arab world today is the double problem of putting every child of elementary school age in school, and of liquidating illiteracy. The Arab states have arrived at various points along the road toward the solution of this problem. Table 92 gives a general idea of the relative educational progress in

TABLE 92

PROPORTION OF CHILDREN IN SCHOOL IN SIX ARAB COUNTRIES
(in the period, 1942–45)

Country	Estimated Population	Estimated Population of Elementary-School Age*	Number Attending Elementary Schools	Percentage of Appropriate Age-Group in School
Egypt	18,000,000	2,870,000	1,360,000	47.4
Iraq	4,500,000	675,000	135,000	20.0
Syria	3,000,000	375,000	148,000	39.4
Lebanon	1,100,000	165,000	120,000	72.7
Transjordan	400,000	50,000	14,000	28.0
Palestine (Arab)	1,250,000	207,000	107,000	51.6

* Estimates of the elementary-school-age population for all countries are based upon the age-distribution tables of the 1937 census for Egypt. Similar distribution figures were not available for the other countries. The estimates make allowance for a six-year range for Egypt, Iraq, and Lebanon, a five-year range in Syria and Transjordan, and a seven-year range in Palestine.

each country. The figures presented are only approximate, but they give some indication of the present situation and of the task ahead.

An examination of Table 92 shows that Lebanon has put in elementary school the largest percentage of its school-age population. Following in order are: Palestine, Egypt, Syria, Transjordan, and Iraq. It would seem that Lebanon has within its grasp the stamping out of illiteracy among the

rising generation, provided an active policy is pursued by its Ministry of Education. Palestine would come next, where it is estimated by a responsible authority that the present education budget would have to be doubled if compulsory attendance in elementary schools was enforced. Palestine can, therefore, be considered to have within its grasp the possibility of compulsory attendance if the authorities are willing to pursue that aim actively.

In the other countries the position is somewhat more difficult because of the long road that still is to be traveled and the lack of funds; it was estimated in Egypt, for example, that the most modest compulsory attendance at an elementary school would cost approximately twenty-four million Egyptian pounds ($96,000,000), or 25 percent of the present total budget of Egypt. Similar situations, though in different proportions, exist in the other Arab states. The main problem, therefore, is essentially financial, and its solution will depend on the rise of the standard of living of the common man in each country and the rise in his average income, so that he may be taxed sufficiently to support a complete educational system. This problem of educational expansion ties directly with economic development and reform in each of the countries. An agricultural economy running at a low level of productivity cannot support a system of universal education. Before that is possible, greater productivity and more extensive and intensive exploitation of the soil must be made, and perhaps more industrial development must take place in every country. It should be remembered that universal elementary education, long an aim in European and American countries, did not become a reality until the industrialization of these countries, or until an extremely efficient agricultural organization, such as that of Denmark, was achieved.

In some of the Arab countries universal education is hampered by other factors. The social organization of the large section of the population which is tribal and the sparcity of the population in many regions slow down the spread of education. The liquidation of illiteracy among adults is even a more difficult problem. In the preoccupation with the education of the young, not much effective work has been done for adults. In Iraq a vigorous movement for the liquidation of illiteracy started in 1922, had so slowed down by 1930 that it was taken over by the Ministry of Education as one of its routine activities in evening schools in towns and villages. Now some 10,000 students of all ages receive a small amount of instruction in these schools. In Egypt the Ministry of Social Affairs was launching a large program for fighting illiteracy in 1945–46. It is too early to judge its results. In other Arab states little was being done in this field.

WHAT TYPE OF ELEMENTARY SCHOOL?

The problems of universal attendance and liquidation of illiteracy are not the only ones connected with elementary education in the Arab world. Indeed, some internationally known authorities on education have been shifting the emphasis from the liquidation of illiteracy to the whole question of raising the standard of living of the masses. This is undoubtedly the basic issue, but it cannot be dealt with purely by means of education. It requires a much wider program which is at once political, economic, hygienic, and social, sponsored by progressive governments. Education would then be one of the chief agencies for the realization of such a program.

It must, therefore, be asked: What type of elementary school and what types of curriculums are best calculated to improve the life of the masses, and indeed of all the people? At the present time elementary schools in each country have one common course of study prescribed by the central authorities.[5] This is to a large extent bookish and academic, borrowed from abroad, and designed to prepare for the passing of examinations. For the most part the only adaptation to local needs seems to be the teaching of Arabic and of the history and geography of the Arab lands, particularly the land in which the school happens to be. To this is added some instruction in health, again of a bookish type, and, in the village schools, some instruction in agriculture. For this there is little practical application except in Palestine and more recently in a few schools in Egypt and Transjordan. The best development along this line has undoubtedly been in the Arab system in Palestine where school gardens have been established in 238 schools and practical instruction in agriculture is given to the pupils of grades five through seven. The practical training varies with the locality. While fruit-raising may be emphasized in one environment, vegetables, cereals, or beekeeping or a combination of these may be emphasized in another. There is, however, even in Palestine little sign of any attempt to tie up the activities of the school with those of the community. As in the rest of the Arab states the elementary school moves in a world by itself, divorced from the world around it.

The new development in Egypt is too recent for any accurate evaluation. There is certainly a need in all of the Arab world to examine carefully the type or types of elementary schools that fit the rural environment of the large majority of the population, that would help raise the standard of

[5] Egypt has several, one for each type of elementary or primary school, all prescribed by the Ministry of Education.

agriculture, of health, of social consciousness, of citizenship, and of character. Even though such an ideal has been spoken of before by some Arab educators who have studied abroad, it has not yet been translated into action.

The curriculum and the elimination of pupils

Another problem connected with elementary schools is an offshoot of the problem of compulsory attendance. In all the countries studied it was found that the number of pupils in the elementary schools eliminated in the successive grades was large. In some cases this elimination was so large that it raised a serious question about the effectiveness of the education given to the large majority of the children. In many places they did not average more than two or two and one-half years of school and, therefore, ran the danger of reverting to illiteracy after leaving school. In some cases, as in Egypt, while hundreds of thousands of pupils are registered in the first grade of the compulsory schools, only a few thousand were found in the fifth grade. In Iraq, Transjordan, and Syria, while the proportion was higher, no more than 5 to 10 percent of the total student body was in the upper grade. No figures are available for Lebanon, but, judging from some of the schools visited, a similar, but perhaps not as pronounced, situation seems to prevail. In Palestine elimination in the first four grades is comparatively limited, but registration begins to drop sharply after the fourth grade. Some of this is accomplished by design on the part of education authorities owing to lack of places in the schools. Some study of the phenomenon of elimination has been made in Iraq, but no thorough scientific investigation of it has been conducted with a view to analyzing its causes and prescribing some remedies. Such a study is needed in all the countries.

Elimination of pupils is due in part to social and economic forces, but it may also be due to the types of curriculums and methods followed. These are too dry and unattractive to the child and often to the parents. The courses of study are, as a rule, too filled with logically organized subject matter unrelated to the environment and too heavily loaded and difficult for the average student to be able to master them. This results in a large percentage of failure and retardation and tends to keep the lower grades overcrowded while depleting the number of pupils in the upper grades. The average age rises correspondingly in the upper grades so that pupils take an average of seven to eight years to complete an elementary school of six years. The problem of elimination and retardation, therefore, has its bearing not only on the measures to be taken to enforce attendance,

but also on the type of curriculum to be followed. The large number of failures in the public examinations at the end of the elementary-school stage seems to confirm this point.

Too often it is assumed that a high standard must be maintained in elementary schools. Those pupils who cannot attain that standard are consciously or unconsciously thought of as unworthy and, therefore, are weeded out. The idea of fitting curriculums and standards to the capacity of pupils, though often admitted in theory, does not find much application in practice. It happens, therefore, that those who pass through the sieve of examinations are the minority that go on for further education and present the justification for the maintenance of the so-called high standards. In most of the Arab countries these students pursue their secondary or higher education only to gravitate for the most part toward government and "white collar" jobs. The other students can be said to fall into three groups: (1) those students who will keep on trying and who therefore pass from grade to grade taking a longer time at their work and providing the laggards and the misfits in the upper elementary classes and the secondary schools; (2) those who drop out in the upper elementary classes or in the secondary schools but who think of themselves as too well educated to work with their hands; (3) those who drop out early in their school life, often to revert to illiteracy, and become farmers, laborers, and artisans. Thus, a certain stratification results where skilled, as well as unskilled, labor becomes the province only of the dullards who cannot go through school and attain a higher academic standing.

It would seem evident that the pursuit by educational authorities of a high academic standard in the elementary school takes into account neither the abilities, interests, and needs of individual peoples, nor the economic needs of the countries concerned. It would seem evident that this outlook needs to be so modified as to make the course of study more in agreement with the needs of the environment on the one hand and of the individual pupils on the other. While certain basic minimum essentials might perhaps be required, there certainly exists a need for more gradation and variation in the courses of study. It must be said that the practice of dictating curriculums by the central authority and of examinations by the same authority does not leave much room for this variation.

The uniformity of the elementary course of study for all children is, however, defended on national grounds. It is argued that the country is in urgent need of a united citizenry and that it is the business of the school to give a unified course of study that would help to produce it. While this aim is a legitimate one and while there is certainly a need for greater unity

among the citizens of the Arab world, it does not follow that this can be achieved by rigidly setting down courses. Some measure of uniformity may be legitimate in the so-called "national" studies, namely, Arabic, history and geography of the Arabs, and civics. But there is certainly room for variety in the other subjects of the curriculum which would facilitate fitting them to the needs of each locality and to the needs of individuals. Moreover, even in the national subjects there is possibility of variety of treatment, both in method and content. The insistence on uniformity may, in the long run, be injurious to educational advance in the Arab world because it stifles the possibility of experimentation and of trying to devise new curriculums and new methods.

Secondary education

In the secondary schools the same tendencies prevail. All over the Arab world the only type of secondary school that exists is the academic secondary school. Division of the course into scientific and literary and sometimes mathematical and biological sections is almost the maximum of variety attempted. These schools are, therefore, of the college-preparatory type. The only exception is a commercial secondary school in Baghdad, the certificate of which is accepted for purposes of admission to some higher institutions. For the rest, any schools for the same age level which give a different course of study or give a vocational education are not accepted for purposes of university education. In Iraq and in some other countries, graduates of some of the vocational schools, thought of as equivalent to secondary schools, may continue their education in higher schools of the same type. But this is not usually the case, nor is the way open to the students to change over to another type of higher education without loss of time.

There is thus some preferential treatment in favor of academic secondary education which creates an attitude in all concerned—whether school authority, parent, or student—that this is a superior kind of education which it is the ambition of every parent to give to his child. As a rule, therefore, it is students with lower abilities who are squeezed out of academic schools and who take refuge in the vocational schools. Vocational education thus carries a stamp which does not attract students to it. This is one of the factors which has operated to make it largely unsuccessful in the various countries of the Arab world. In some of the Arab countries this problem has received some thought, notably in Iraq, where for some time the creation of a number of parallel secondary courses with a vocational bias has been advocated. The suggestion first came from the Monroe Commission in 1932. It has, however, met with strenuous opposition by the

advocates of the unity of the courses of study. Recently this topic was again brought up, and it was thought that secondary courses with a commercial, agricultural, technical, and home-economics bias might be created. So far, this has not gone beyond the stage of preliminary thinking. Vocational education is given in separate schools. As yet the need has not been felt for vocational guidance of students after they graduate from elementary school. Since secondary education is of an academic type, it can readily be seen that hardly any grounds exist for raising the question.

Availability of secondary education.—Another aspect of secondary education—its availability to youth in general—needs some attention here. This problem has received some consideration in Iraq, Syria, and Egypt. In these countries a system of exemption from fees on the basis of economic need or academic achievement, or both, exists which may exempt wholly or partially from 25 to 40 percent of the student body. The annual fees at their highest are rather low: in Iraq,[6] $18, and in Syria, $27.30. They are considerably higher in Egypt, $80. In addition, Iraq has established for each of its fourteen provinces a system of complete scholarships with free board, lodging, and books for a number of brighter pupils. Thus secondary education may be said to be available to most of those who can graduate from elementary school, although the cost of maintenance away from home for village youth may be a barrier for many who are not at the top in the public examinations. Syria has recently established a system similar to that of Iraq. In Egypt, while a wider range of exemption has been allowed since 1943, it must be remembered that the division of the educational system into two ladders, primary and elementary, makes the secondary schools available only to the minority of the well-to-do who go through the primary schools, while the majority who graduate from elementary schools find the road to secondary education blocked before them. Not unless they can transfer to the primary schools and spend some additional time in study, can they hope to enter secondary schools.

In Palestine and Transjordan provision for public secondary education is extremely limited. Under a very stringent method of selection only the most capable of the students can finish their secondary education in the two or three public secondary schools that exist in Palestine. For the poorer of these students a system of scholarships exists, but the scope of secondary education is so limited as to make its availability to the youth of the country almost insignificant. In 1945–46 Transjordan maintained only one complete secondary school. Two others, however, were on the

Secondary school fees have since been abolished in Iraq.

point of being completed. In Lebanon, reliance has been laid on private and foreign secondary schools and the Ministry of Education maintains no complete secondary school. Any students, therefore, wanting to complete their secondary education must go to the private and foreign schools where high fees are charged with a minimum of exemptions. The poor boy or girl of Lebanon finds it exceedingly difficult to complete his secondary education. It is surprising how many sacrifices and privations Lebanese parents are willing to undergo in order to send their children through secondary school. A system of public secondary schools or at least of public scholarships for promising students is sorely needed.

Extension of the facilities for secondary education.—No clear-cut policy seems to have as yet emerged in any of the countries with regard to the expansion of secondary education. While Lebanon has thrown the responsibility for secondary education almost entirely on private and foreign schools, Palestine has followed the policy of restriction, apparently out of fear lest overproduction of secondary-school graduates would leave a large number of these graduates unemployed who would become a possible source of agitation. Students have, therefore, sought to enter private and foreign secondary schools in large numbers; and, as the demand grew, a larger number of private secondary schools were established to take care of it. It must be added that this restriction of facilities of public secondary education in Palestine is also attributed by the authorities to the lack of funds and to the preference to devote funds mostly to primary education. In the other countries expansion has been left to the pressure of circumstances. Ordinarily most of the graduates of primary schools in Egypt, Iraq, and Syria want to continue their education through secondary schools. Attempts by these countries to restrict entry into secondary schools have not been too successful. Iraq has wavered between what may be called the open-door policy and restriction with the former winning most of the time. The same may be said to be true of Egypt. As the provision for secondary education lagged behind the demand, there was a tendency for classes to become larger in Iraq and Egypt. Recently Iraq has been trying to base admission of pupils into public secondary schools on academic accomplishment in the public examinations. Students who fail more than once in any class are also eliminated. Exemption from fees has been linked with quality of achievement, so the beginnings of a policy seem to be emerging. However, if students fail to find a place in the public secondary schools, or if they are eliminated along the road, they have tended to enter the private schools, and a large number of these schools have been growing up in both Egypt and Iraq.

Up to the present the government authorities seem to take the attitude of being responsible only for the students capable of secondary education. What the governments can do to care for the education of those who are not so capable is a question that seems to have arisen very rarely, if at all. However, more recently under the influence of developments abroad, principally in England, Egypt has raised the question of other types of education parallel to secondary schools for the students of lesser ability. This attitude is still in its infancy.

Vocational education

Vocational education is perhaps the least successful aspect of education in the Arab world. On the whole it can be said that vocational schools are not popular, and in many instances there is difficulty getting recruits to fill the classes even moderately. The reasons for this are many, though no scientific study of them has been made. Perhaps the most fundamental among them is the fact that industry is still in its infancy in the Arab world. As the cottage hand trades have been waging a losing fight with modern Western industrial products, so has there been an industrial dislocation in the various Arab countries. The new industry based on machinery is beginning to make its appearance, but is still a struggling infant. Naturally the demand for skilled, industrial workers is not great, nor is the appreciation for the preparation of such workers. Rather, as small industries arise, the tendency has been to train skilled workers on the old apprenticeship basis, using illiterate boys as the principal source of supply. Workers so trained are willing to accept lower wages than are the graduates of trade or technical schools. As they have the more practical kind of training in the actual industry, they are usually more favored in finding jobs than the literate student who has combined theory with limited practice.

Among the reasons for the nonpopularity of vocational education is the fact that secondary-school graduates are reasonably sure of a steady income with no strenuous work to soil their hands. Since the government official in the past has enjoyed a great deal of prestige, government jobs are coveted. It follows that the academic studies leading their graduates to government jobs become the more popular. Even the educational authorities themselves have paid much less attention to vocational education, and have consciously or unconsciously held it in somewhat lower esteem, though often acknowledging the necessity for it.

Some other factors have impeded the progress of vocational education in some countries. In Iraq, a practice of discriminating against students in vocational schools in the form of nonexemption from military service has

acted as a factor contributing to the small number of applicants for vocational schools. Students would rather enter the secondary schools, in which case their military service is postponed until after graduation. They then receive reserve-officers training for nine months. Vocational-school students are not so favored and have to serve for two years as privates. In Palestine vocational education has been hampered by the unsettled conditions of the country which necessitated the occupation by the military of the physical plants of the agricultural and trade schools almost continuously from 1936 to 1945.

With regard to agricultural and commercial schools, similar forces are in operation. Many businesses are content to conduct their accounts in a primitive way rather than employ the services of what they think is an expensive clerk. In this respect the various countries of the Arab world are not of the same level. In centers such as Beirut or Cairo one finds a greater trend toward accepting modern business methods than in Damascus, Aleppo, or Baghdad. Appreciation of agricultural education follows the agricultural development of the country. It is more advanced in Egypt because of the great agricultural development in that country for the last half-century. The prevailing systems of land ownership and distribution are a great hindrance to agricultural development and agricultural education. Farmers are at best conservative; but when a farmer does not own his land and lives on a subsistence level, he is not likely to want to improve his land nor is he capable of supporting a son through a vocational school. A further hindrance to the development of vocational education is the lack of experts. There is a great need for well-trained teachers and leaders in the various branches of vocational education. The problem of vocational education is crucial in the Arab world because upon it depends very largely the development of the resources of the countries, the efficient exploitation of the land, and the training of skilled workers for industries. Of late, efforts have been directed toward developing vocational education as a variety of secondary education. American experience and developments in England have been influential in creating this trend both in Iraq and Egypt. These plans, however, are still in the realm of ideas, and the leadership to put them through is lacking. Some progress has been achieved in Egypt, where fairly successful vocational schools of various levels—elementary, intermediate, and higher—exist.

Public examinations

All of the Arab systems studied emphasize examinations at the end of each period of study. The Government (Arab) system in Palestine holds only one public examination, the Palestine matriculation examination. No

primary examinations exist, but a rigid system of selection of students on the basis of school records is practiced after the fifth grade. Transjordan has two public examinations—a primary and a secondary examination. Egypt, Syria, and Iraq have three—a primary, an intermediate (or general) examination, and a secondary (or special) examination. Lebanon has four examinations—a primary, a *brevet*, a *Baccalauréat*, Part I, and a *Baccalauréat*, Part II. Usually a pupil is not allowed to proceed to the next higher stage without first passing the examination at the end of the previous stage. Examinations thus serve the purpose of selecting students for the next step on the educational ladder and are often effective methods for eliminating pupils. Elimination may range in any examination from 25 to 50 percent, rarely less and rarely more. There is, therefore, a great fear of the examinations by students and teachers alike. Many schools have special classes outside regular school hours to help prepare students. The anxiety felt by the children, the cheating, and, rarely, a leaking of questions are part of the system.

Examinations also have an influence on the course of study. In government schools those who set the courses and the examinations are the central offices of the ministry of education. Students, whether in public or in private schools, are on the whole unwilling to pay much attention to studies that are not included in the public examinations, and school education becomes to a large extent a preparation for the examinations. Naturally education in its broad sense suffers. Private and public schools cannot venture very far in experimenting with new curriculums. Thus, examinations act as an obstacle to educational experimentation and progress. Public examinations are held under strict secrecy so that those who correct the papers cannot know the name of the pupil whose paper they are correcting. There is in the system, therefore, the element of mistrust of school authorities. Principals and teachers are not depended upon to judge the progress of their own pupils, and to base upon this judgment the recommendation for the granting of school certificates. It is said that teachers and principals if left to themselves become subject to pressures from parents and people in authority. The responsibility, therefore, is taken out of their hands and rests on the higher authorities. Naturally, this does not make for high morale or sense of responsibility among teachers, both badly needed in all the systems visited.

Examinations are further justified on two counts. It is said in the first place that they help raise the standards of teaching both in private and in public schools, but particularly in the commercialized private schools. Secondly, they are said to insure that private schools come under a certain

measure of control by the government in the interest of national unity. Public-school curriculums require certain subjects of national importance, such as Arabic and local history and geography. Examinations are useful in insuring that these subjects shall be properly taught. It is hardly necessary to point out that school standards are being maintained in many countries, without the help of public examinations, by raising the standard of educating teachers, by better-equipped schools, by better libraries and laboratories, and by systems of supervision which help keep the teachers alert and create in them a sense of professional pride and responsibility. Subjects of national importance can be required from private and foreign schools as, indeed, they are now being required. The proper teaching of them can also be insured by proper supervision without the necessity of rigid examinations which create mistrust in all the teaching body, hinder experimentation, and are a constant source of neurotic worry besides being detrimental to character in the incentive they give to cheating. An easing up of the examination systems, especially in the lower stages of schooling, is greatly needed, and would be the first step toward liberalizing the courses of study and toward educational progress in general. This is, however, going to be difficult to achieve owing to the prevailing ideas about centralization which are difficult to eradicate.

Education of teachers

The problem of the expansion of the elementary schools in the six Arab countries naturally creates the problem of the preparation of teachers in adequate numbers and training for the system. Radical differences exist among the countries in the level of preparation and the number of trained teachers that they produce. Transjordan has no teacher-training institution. In Palestine and Lebanon the number of teachers graduated from normal schools and teachers colleges is extremely small. Accordingly, recourse has been had to appointing as teachers, graduates of secondary schools and individuals with much less education, sometimes even elementary-school graduates. Syria has recently recognized the problem and increased the capacity of its teacher-training institutions, though the existing facilities are still short of the need. Egypt and Iraq are the only two countries that are training elementary- and primary-school teachers in more or less adequate numbers.

The level at which elementary- and primary-school teachers are being prepared also differs radically. In the dual system of primary and elementary education in Egypt, primary-school teachers have for many years been prepared on a four-year college basis and in certain instances on the

basis of two years of professional study beyond college work. More recently, a two-year course above the general secondary certificate has been instituted. This is now being lengthened to three years. On the other hand, elementary-school teachers receive an academic and professional training that is hardly equivalent to secondary education. In Palestine two years of academic and professional training beyond the secondary school are a standard practice for men teachers, while women teachers for city schools have thus far received a training of only one year beyond secondary school. Rural-school women teachers are of a much lower standard, and no school for the training of rural men teachers exists, except that those who have passed the matriculation examination could take a year at the Kadoorie Agricultural School at Tulkarm. The teacher-training course at this school, however, has not been in operation for some time.

In Lebanon, two years of training are given to both men and women students in a course that is hardly equivalent to Lebanese secondary education. In Syria, the new training scheme, which is likely to become general, is of three years above intermediate schools. In Iraq, rural teachers are trained in special institutions which are roughly equivalent to secondary schools, while city teachers receive a training equivalent to one or two years above secondary schools. Thus, the education of teachers in the Arab states ranges from a minimum of training that is less than a secondary-school certificate, to a maximum of two graduate years beyond college work.

The chief problems with regard to the education of teachers seem to be quantitative and qualitative. On the quantitative side it is the need for trained teachers in adequate numbers to meet the rising demand for elementary education. This has been met more or less well in Iraq and Egypt, although the rate of the education of teachers would prove inadequate once these countries embarked on a vigorous program of expanding their elementary education. In the other four countries supply is far short of the demand, and makeshift arrangements are resorted to which compel authorities to employ unqualified teachers in large numbers. A forward-looking policy is needed to prepare professionally trained teachers in numbers adequate to meet the demand for public elementary education. Private and foreign schools, however, are also finding some difficulty in recruiting professionally trained teachers. The teacher-training institutions are almost wholly public and prepare teachers for the public schools. The graduates of these institutions prefer to be in the public-school system because they are usually paid more adequate salaries, have more secure positions, and are usually protected by retirement plans. This leaves the private schools al-

most entirely without professionally trained teachers. The private schools are so heterogeneous that they cannot get together to establish teacher-training centers of their own.

The governments have not paid enough attention to this problem, being preoccupied with the problem of preparing their own teachers. Some measure of cooperation is needed between the government authorities and the private and foreign schools for the preparation of teachers for these schools. Such a cooperation will probably be hard to realize, partly because private schools will not have the resources, even with contributions from the governments, to maintain such an institution, and partly because the attitude of cooperation does not always exist between some of the government departments and some of the private and foreign schools, or among the private schools themselves. There is here certainly the opportunity for foreign institutions of higher education to render some real service in providing professional education for teachers of private schools. This has been done on a somewhat small scale in the field of high-school teaching. But there is a wide field in training for elementary-school teaching. So far, however, there has not been sufficient demand for such a course. The demand will probably not arise until a minimum of professional education is required by law from all elementary- (and secondary-) school teachers.

On the qualitative side, greater attention should be given to the preparation of rural-school teachers. The current practice of sending the poorest teachers to the countryside should be stopped. If it is true that the economy of all these countries depends largely on the development of their agricultural resources, then their rural life needs to be reconstructed. In this reconstruction a great role can be played by a special kind of rural school which pays adequate attention to the needs of its environment. Such a pioneering school needs well-prepared teachers. Teachers are needed for the rural districts who not only master the common subjects, but who also have an adequate acquaintance with agriculture and with the social and health problems of the countryside.

Iraq and Palestine are the only countries which have tried to grapple with this problem. Special rural-teachers colleges have been established in Iraq where agricultural and health training are given to the students along with academic subjects. Students are usually recruited from the countryside itself. The general plan seems to be correct, but it is feared that the way it is being handled, largely due to the lack of well-trained staffs in the teachers colleges, is not securing the quality of teachers that is wanted for the rural schools of Iraq.

The problem resolves itself into that of staffing the teachers colleges with capable men of vision and of adequate professional education. For the present, most of the staff of the teachers colleges are either former teachers of secondary schools or people who are academically but not professionally trained. Often principals of teachers colleges are men with no professional training and, therefore, have no conception of their task. Teachers-college instructors should be men and women who, in addition to experience in teaching in elementary schools, have had some graduate study in their field of specialization coupled with professional study in education. The teachers colleges need not only specialists in education, but also specialists in sociology who can conduct original research in the social problems of their country. In addition, there is a great need for teachers of the practical subjects such as agriculture, manual arts and crafts, physical education, and some of the fine arts, such as music, art, dance, and rhythm. Many of the teachers colleges are sadly lacking in this respect. The great potentialities of the people along these lines remain undeveloped.

One of the things for which rural-school teachers need to be specifically trained is the simultaneous teaching of more than one class. In the many rural schools visited in all of the six countries, the American Council Commission does not recall a single instance in which a teacher was able to conduct successfully the teaching of two groups, not to say three, at the same time. In almost all the instances one group remained idle while the other was being taught. Specific training in this technique is badly needed.

In the preparation of secondary-school teachers, Iraq has maintained a four- or five-year course above secondary school for men and women which combines academic training with the professional. Egypt followed the same system down to 1930 and later replaced it with the institutes of education which give two years of professional training beyond college work. For the rest, reliance in all the Arab world for recruiting secondary teachers has been on college or university graduates who are for the most part only academically trained. Graduates of the American University of Beirut and at Cairo have been a common source of recruiting, together with some graduates of French, British, and American universities. Many secondary-school teachers do not have a university training. Syria has just started a higher teachers college following roughly the lines of the Higher Teachers College in Iraq, while Egypt is re-establishing the higher teachers college for preparing teachers of science and mathematics.

Two schools of thought are current with respect to the professional education of secondary-school teachers. One is to postpone this training until after graduation from the university; this follows the Continental

and the British method. The other is to combine in one course both academic and professional training. Arguments for both have been given. Iraq and Syria and the American Universities at Beirut and Cairo have generally followed the second scheme. Egypt, acting upon the advice of the late Professor Édouard Claparède of the University of Geneva, has for the last seventeen years followed the Continental scheme. Here, as in the case of elementary-school teachers, the problem is largely one of producing enough teachers and of staffing the teacher-training institutions with able professors. In addition, one must again mention the need for research centers in education connected with the teachers colleges—elementary, secondary, and higher.

Another angle of the problem of the preparation of teachers is their training in service. Little organized, regular, and constant effort is being exerted in this direction in any of the countries studied. Here and there a summer training course or evening classes are held. The teachers, therefore, tend to sink gradually in their professional competence, easily fall behind the times, and lose morale. School inspection is rarely directed toward improving the knowledge of the teacher. Nor are school principals usually much better trained than their fellow-teachers. Plans are needed in all the countries for regular summer and full-year courses for teachers and for the training of capable principals who can help their teachers improve themselves. Publications for the benefit of teachers are also needed. The Iraq Ministry of Education and the Education Department of the Haut Commissariat of the former French government in Syria and Lebanon have been the only public education departments that have published educational magazines for the benefit of teachers. Some governments have maintained qualifying examinations for teachers, but these are more for the purpose of raising the level of the unqualified teachers than for improving the level of those already qualified.

Foreign languages

Foreign languages occupy an important place in the programs of modern schools of the Arab countries. The reason is not far to seek. The location of the Near Eastern countries on the world highways has forced upon them contacts with many peoples and cultures and, therefore, acquainted them with many foreign languages. It has made their people more sensitive to languages and more linguistically minded. Languages have been important for the relationships of the ruling and the ruled and for purposes of trade. Moreover, with the greater mobility afforded by modern communications, a large number of foreign tourists, travelers, and salesmen, as

well as armies, have appeared on the Near Eastern scene. Illiterate boys coming in contact with British tommies picked up English on the streets of Baghdad in 1917, as do the dragomans on the streets of Cairo. The fact that the Near Eastern countries are learning Western science, Western technology, Western philosophy, and all other branches of Western knowledge has necessitated also their learning many Western languages, not only French and English, but also German, Italian, and Russian. The appearance of a large number of foreign schools in Egypt, Syria, and Palestine, each teaching in its foreign language, has enhanced this tendency. Some of these schools made the teaching of their own language one of their primary purposes and insisted as much on fluent speech as on a high standard of writing in it. In this, the French schools probably were the most successful. For a large number of students in foreign schools, it became easier to think, speak, and write in a foreign language than in their own Arabic.

As national systems of education grew, sometimes under the control of foreign powers, foreign languages naturally occupied a prominent place and sometimes were even made the medium of instruction. This was true for a certain period in Egypt, and in Lebanon and Palestine. This could not have failed to arouse an antagonistic reaction among the nationalistic elements in the various countries, and as the countries began to be liberated from foreign rule, the question of foreign languages began to come to the forefront. The controversy centers around four points: (1) What foreign languages? (2) How much foreign language, and when to begin to teach it? (3) Is it necessary to use the foreign language as a medium of instruction? (4) What is the effect of the emphasis on the teaching of a foreign language on the teaching of the national language?

With regard to the first question, there has been a transition over the whole of the Near East from French, which was predominant in the nineteenth century, to English. This is as true of Egypt as of Syria and Iraq. The shift from French to English has been very abrupt in Syria and has assumed the proportions of a boycott of the French language. French is still favored in Lebanon, but there is a perceptible shift to English. The question is being decided more by the growing political and economic prestige of the Anglo-Saxon world than by any educational considerations.

The amount and time of beginning foreign-language teaching are questions on which there is a wide difference of opinion. Lebanon lies at one extreme, for there the teaching of foreign languages in public, as well as in private, schools begins in the kindergarten. At the other extreme lies the new reaction in Syria which has led to the abolition of the teaching of

foreign languages from all elementary schools. The middle position is taken in Iraq, Transjordan, Palestine, and Egypt, where a foreign language is generally begun with the equivalent of the fourth or fifth grade. A new movement in Egypt, however, advocates the postponement of the teaching of the foreign language to the first year of the secondary school. Two reasons are usually given for this stand. First, a student must be allowed to master the elements of his own language before being started on a different one, lest the teaching of the foreign language interfere with the mastery of the native language. The second is the difficulty of preparing enough teachers with a mastery of the foreign language to be able to give a good start to all children in the school system, that is, in remote rural districts as well as in urban communities. The advocates of the earlier teaching of foreign languages state that such early teaching insures learning the language with the least of trouble. It is said that starting a language at the age of eleven or twelve does not make for its mastery by most of the pupils. This point of view is taken in Lebanon, where it is pointed out with pride that foreign-language teaching, whether French or English, is most successful. There is general agreement, however, among all educational authorities that at least one foreign language is necessary in secondary education. All public-school systems give one foreign language in secondary schools, and some of them give two.

The national systems of Egypt, Palestine, Transjordan, Syria, and Iraq have decided against teaching through the medium of a foreign language in elementary and secondary schools, and all teaching in the public schools is done in Arabic. Most of the foreign schools, however, and some of the private schools, teach in a foreign language and not in Arabic, particularly in the secondary schools. We have seen that in Lebanon most of the teaching in elementary and secondary schools was formerly conducted in French, but that the new programs are giving greater place to teaching in Arabic, though allowing the teaching of some of the subjects in the foreign language. In higher education both practices are followed. Medical and technological schools, even the public ones, with the exception of the medical school of the Syrian University, teach in English or French while other schools usually teach in Arabic, but may give some courses in a foreign language.

This brings up the fourth point, namely the influence of teaching in a foreign language upon teaching the national language. The Arabs are anxious that their language shall be well taught to their children and shall become an adequate instrument for the expression of all kinds of ideas, whether social theory or scientific technology. They are, therefore, anxious

that their children shall use Arabic as a medium of learning and instruction to the fullest extent possible. It is true that, after centuries of darkness, Arabic was outdistanced as a medium of expression by the modern European languages. There is, therefore, today the problem of coining scientific terminology in Arabic, and in general of expressing scientific ideas and abstruse theories in Arabic. Arab intellectual leaders contend that their language will rise to the occasion as it did in the past, but can only do so if it is used as such in the schools as the medium for expressing scientific ideas. They complain that the insistence of foreign schools on teaching in their own languages retards the development of Arabic, and accuse some of the foreign schools, particularly the French, of deliberately neglecting the teaching of Arabic.

The Commission was not, of course, able to go into this question thoroughly within the very limited time at its disposal. It did, however, make some attempt to explore it in the schools and to ask opinions of various authorities and teachers about it. As a result, the Commission has formed certain impressions and conclusions which it presents for what they are worth.

It is, indeed, unfortunate that the neglect by certain foreign schools of the Arabic language and the emphasis on their own language has led to the general impression that the teaching of a foreign language may be detrimental to the teaching of the national language. It has also created such resentment as to help confuse the issue and make it appear that it is the national language versus the foreign language. But this need not necessarily be so. In inquiring about this question, the Commission was told by a number of experienced teachers, particularly in Lebanon, that it was quite possible, given a healthy and sympathetic attitude on the part of school authorities, to teach the two languages to a high standard. Indeed, a number of such schools are found teaching English or French, as well as giving adequate attention to Arabic. There is no scientific evidence to support the theory that the teaching of a foreign language is necessarily detrimental to the teaching of the national language. The main trouble has been the wrong attitude taken by some schools which favored the foreign language over the national language. The Commission, therefore, would put a question mark over the whole theory and would suggest that here is a fertile field for experimentation, which can be conducted by public-, private-, and foreign-school authorities. It may very well be that in certain aspects, such as some topics in grammar or sentence construction, there may develop some interference between the two languages, but it may also be just as true that in certain other topics they might reinforce each other.

With regard to the time to begin foreign languages there is some evidence to show that an early start is better than a late one. Such seems to be the case in a bilingual country such as South Africa. The experience in Lebanon, where foreign languages are more successfully taught perhaps than in any other Arab country, would tend to point in the same direction. It is not, however, possible to dogmatize on this question. Lebanon has been so much in contact with foreigners and the teaching of foreign languages has been going on for such a long time that an interest and an atmosphere favorable for foreign languages have been created. Parents insist on their children learning a foreign language and may speak it at home themselves. Another factor also is the fact that in many of the schools foreign languages are not only taught as languages, but are a medium of instruction, and it is precisely in schools where these languages are used for instruction that they are best learned. Here, again, there is need of scientifically controlled experimentation. In the meantime most school systems are taking a compromise position.

In view of the need for foreign languages in the Arabic-speaking countries, the Commission is of the opinion that it would be unwise to postpone the teaching of a foreign language until the secondary school. The age of twelve is a late age to start a foreign language, and it must be remembered that the age at which the average pupil leaves elementary school is higher than twelve, so that a large number of children would begin their foreign language at the age of thirteen or fourteen. For all except the brighter pupils such a late start would preclude proficiency in the language, not to say mastery of it. One of the serious objections to starting foreign-language teaching in the elementary school is the administrative one of providing enough teachers of foreign languages for the outlying village schools. Another objection is the lack of need or interest in a foreign language in the villages. It must be admitted that it would be very difficult to train foreign-language teachers for all the present and future rural schools of the Arab world. The Commission is of the opinion, however, that teachers can be trained for a sufficiently wide selection of them. Again, the experience of Lebanon is illuminating where some of the farthest outlying schools have been able to secure teachers of French or English who have attained a fair degree of proficiency. It is not necessary that a foreign language shall be taught in all elementary schools, but that it should be taught in the more important ones where there is a sufficient demand for it and in schools so distributed that pupils desiring a foreign language in one village may obtain it in a nearby larger village school. Another possibility is to give additional hours of foreign-language

teaching in secondary schools to those children who could not have it in their village elementary schools.

In considering the use of a foreign language as the medium of instruction, Arab educational leaders are undoubtedly right in wanting to develop Arabic as the medium of thought and expression for their own countrymen. They are, however, at the same time anxious to see their students master foreign languages well enough to be able to read foreign literature on all the subjects of specialization and on all aspects of life. The question of a new dynamic Arab culture is intimately connected with the problem of foreign languages, and it is necessary that the intellectual leaders of the Arab countries shall be masters of one, and perhaps more, foreign languages. This does not necessarily mean that content should be taught in a foreign language. Again, a compromise position may well be a solution. There is a good deal to be said for teaching certain subjects one year in the native language and another in a foreign language, and varying these subjects from year to year so as to give the student the experience of reading, thinking, and speaking about these subjects in the two languages. Some bold experimentation in this direction is needed.

FOREIGN SCHOOLS

Foreign schools have played an important part in the intellectual life of Syria, Lebanon, and Palestine in the last three-quarters of a century, and a somewhat lesser part in Egypt. Their influence in Iraq and Transjordan has been much less. Throughout this period, and particularly before the growth of the national systems of education, foreign schools did pioneering work in spreading education both in the cities and in rural areas. They spread the knowledge of foreign languages and acquainted the peoples of the countries with Western science and Western learning. They have been particularly strong in emphasizing character education. While their influence has been effective mainly among the minority groups of Christians and Jews, they nevertheless have influenced a considerable number of Muslims. Until 1920 almost the only worth-while higher education available in Syria, Palestine, and Iraq was at the American University of Beirut and at the French Université Saint-Joseph in the same city. Foreign missions have given special attention to the education of girls, often giving it precedence over the education of boys. This was clearly the case of the American schools for girls in both Beirut and Tripoli, which preceded the present American schools for boys. The French nuns also did, and still are doing, great and effective work in female education. Moreover, a number of the native leaders in the fields of politics, business, and medicine are

graduates of foreign institutions. Even the national movement may be said to have been enhanced to a certain extent by some of the more liberal foreign schools. A number of outstanding leaders of the Arab national movement have been graduates of the American University at Beirut. For a long time foreign schools enjoyed a special prestige and a somewhat privileged position in the Arab countries.

However, certain aspects of foreign education and some types of foreign schools have come under sharp criticism. One of the important criticisms is found in some resentment among non-Christians at the attempt of most foreign-missionary schools to require attendance in Christian religious classes and in Christian devotional services, even of non-Christians. A similar resentment, though much milder, is often felt by a Christian parent belonging to one denomination who sends his child to a school of a different denomination. This is branded as an attempt at proselytizing and is resented particularly by Muhammadan parents. It does not prevent many parents, however, from sending their children to foreign schools although it is quite apparent that the enrollment of Muhammadan students in foreign schools would have been much larger had not the fear of Christianization deterred many a parent from sending his children. It is not without significance that in countries where the overwhelming majority of the people are Muhammadans, the majority of students in foreign schools are usually non-Muhammadan.

Another accusation leveled at some, though by no means all, of the schools, is that of creating sympathies for their countries of origin. This is often branded as active propaganda for these countries, and, with the growth of national feeling throughout the Arab world, this propaganda has come to be resented more and more strongly. Along with this goes the criticism of the neglect of the Arabic language and of the teaching of the geography and history of the Arab and Near Eastern countries, while at the same time great pains are taken to teach the foreign languages and the geography and history of the foreign countries. The net result of all this has been to alienate the sympathies of a large section of the younger generation from their own country and to make them look toward the particular foreign country of the school in which they were educated. In this way the national movement was handicapped. This criticism is particularly leveled at French and Italian schools. American schools, it is fair to say, have been rather free of this outlook. In no American school did the Commission find any special emphasis being put on the history or geography of America.

A third criticism has been that the foreign schools belonging to various

nationalities have as a net result helped to divide the loyalties of the youth of the country among these nationalities. The different methods of education pursued in each have created different attitudes and different patterns of behavior which have tended to make cooperation among the graduates of the various institutions difficult. It is claimed, therefore, that this has been one of the principal obstacles in the way of the national movement. In catering largely to the minority groups, foreign schools have tended to sharpen the already wide cleavages between the various religious communities.

Finally, prior to the growth of the national systems, foreign schools were quite independent, and under the Ottoman rule were protected by the regime of the Capitulations. They were to a large extent a law unto themselves. During the autocratic rule of the Ottoman sultans, such a situation may have been helpful to more than one liberally minded teacher or student, but with the rise of national governments, the situation of the schools came to be more and more resented.

As a result there has been a gradual shift in the attitude toward foreign schools in the last twenty-five years. One factor in the new situation is the fact that the growth of the national school systems has made the various countries less dependent on foreign schools than they previously were. They are now subject to greater criticism than before, and some of them are under suspicion. The last two decades have witnessed the assertion by the various national governments of their authority in claiming and exercising the right of supervision of foreign schools. This right was first established by the mandate authorities in Iraq, Syria, Lebanon, Palestine, and Transjordan, but with the passing of the mandates it began to be exercised by the national governments. Along with the right of supervision, new laws have been passed in Egypt, Syria, Lebanon, and Iraq which set limits on the activities of foreign schools. Teachers and textbooks are to be approved by the governments, and in Iraq the right of elementary education for Iraqi children is given exclusively to the state and to the nationals of Iraq. In some of the countries the schools follow the same programs in the teaching of Arabic and Arabic history and geography and civics as those of the government schools, the government appointing the teachers. Foreign schools are in some countries definitely forbidden to spread foreign propaganda. Finally, the institution of public examinations has set definite limits on programs of studies which may be followed in private and foreign schools. Many of the parents are anxious that their children shall pass the government examinations. Entrance to government higher educational institutions as well as to government jobs and many other such privileges are

dependent upon achievement of this goal. Foreign schools have been obliged by the pressure of circumstances to prepare their students or a large portion of them for the public examinations. Many of them have adopted the procedure of maintaining their own course of study on the one hand, and the government course of study on the other. In some instances the schools are required to follow the official government program.

It is clear that this whole trend of setting limitations on the foreign educational activities is due partly to the abuses committed by some foreign schools, and partly to the rise of national feeling in the Arab world. The trend is becoming increasingly pronounced and has been giving considerable food for thought to the authorities of foreign schools. In some cases doubts have arisen in the minds of certain of them about the worthwhileness of continuing in the face of such restrictions. It is undoubtedly true that some of the schools which have been free of the criticisms leveled at foreign schools are likely to suffer through no fault of their own. It is contended that rather than subject all schools of whatever kind to the same restrictions, based on suspicion, a system of supervision should be devised whereby schools violating the provisions of the law about propaganda and weakening the national sentiment should be severely punished. In applying the same standard to both the innocent and the violating schools, useful activity is likely to suffer.

It may be said that this whole trend may be a passing one, brought about by national feeling of the Arab world asserting itself. As the Arab countries begin to feel more secure and sure of their national existence, they may feel that they can afford to take a more liberal attitude toward foreign schools. Leading men interviewed by members of the Commission were almost unanimous in their desire to keep and expand the activities of foreign, especially American, schools. It is asserted that these schools have values which could not be secured through public education. Many, however, stated categorically that they expected foreign schools to produce loyal citizens of the countries to which they owed allegiance, rather than to any foreign power.

At this point it is appropriate to raise the question of how foreign schools may be of use to the Arab world in the changing atmosphere and setting which now prevail in it. It is clear that the situation has materially changed from what it was in the nineteenth and early twentieth centuries. The old autonomy of the foreign schools is gone, however that fact may be bemoaned by some foreign school authorities. It is also clear that while in the nineteenth century foreign schools performed a unique function in countries which were virtually deprived of even elementary education, the

rise of the national educational systems in this century has now made foreign schools far outnumbered by both the public and the native private schools. In elementary and secondary education, and in some instances in higher education, the work of foreign schools is no longer unique. Some of the national systems may even claim to set higher academic standards. It may be said that foreign schools may supplement the educational provisions existing in each of the countries, which are admittedly inadequate at present to meet the needs of those countries. This is undoubtedly true, but it must be said that many a foreign school today, far from relying for financial support on its country of origin, is almost entirely self-supporting through the fees collected locally. In this respect, a foreign school may be no more than one more private school of the type increasingly being established by the natives of the country.

What, then, can be the place and function of foreign education in the Arab world today? What should be the attitude of foreign educators in the Arab world? What should be the attitude of Arab educational authorities toward foreign schools? There is certainly a need for rethinking this whole question. The following remarks are offered by way of suggestions:

1. If it is recognized that one of the main purposes justifying the existence of foreign schools is to help the people of the country to a better life, it follows that these schools shall have as their aim the education of useful and loyal citizens for the countries concerned. In this their aim should be the same as that of the national public schools. Schools undermining that aim and seeking to create a foreign allegiance should not be tolerated. This does not mean that foreign schools are called upon to create any chauvinism or extreme nationalism that finds itself at war with all other nations, but it does mean that a positive effort must be made to bring up an enlightened and loyal citizenry which is set to serve its homeland. If a certain sympathy toward the country of school origin should develop, this should be an unconscious by-product rather than a positive aim to be actively striven for. In return, and once confidence is established, foreign schools have a claim to a large measure of freedom in following their own curriculums and methods, once the government is assured that the national subjects—Arabic, national geography, history, and civics—as well as the national spirit are properly taken care of.

2. In view of the development of the national systems of education, foreign schools should, as far as possible, seek to break new ground and to do what the national public and private schools are not able to do. They should keep up their pioneering spirit either by supplementing the work of the public schools, or by showing the way for new and useful develop-

ments in education. In this they have a rich background of their own respective countries to draw upon. They can, therefore, serve as agencies for putting before the Arab countries the valuable experience gathered in their own home countries. They should try to study the needs of the field in which they are working and help meet those needs through their educational endeavors. The following are some of the fields in which particularly useful work can be done by foreign schools, aside from ordinary elementary and secondary education:

a) Vocational education. It has already been indicated that the public-school systems have not been particularly successful in their attempts at vocational education. Foreign schools coming from a background where considerable experience has accumulated in this field can be of particular help in passing it on to the Arabs.

b) Experimentation with newer methods of teaching and newer types of curriculums. This undoubtedly is going to be hindered by the present attitudes developing in the Arab world, but with greater confidence between the governments and the schools, it should be possible to make some developments along this line. The schools should, indeed, claim it as their right to break new educational ground and show the advantages that would accrue to the countries.

c) Along with experimentation foreign institutions have the opportunity of providing, especially in higher institutions, modern training and research in the field of education.

d) The pioneering work of foreign schools in the field of female education should be expanded. They also have a better knowledge of how to conduct coeducational institutions.

e) Foreign schools can do an outstanding job in character education, as they have done in the past. A real example can be set before the public schools in this field.

f) Along with character education can go education in citizenship and the working of democracy. American, British, and French schools, rising from democratic backgrounds, should be in a better position to teach the methods of cooperation and of democracy than the public or native private schools.

g) Foreign schools will always do useful and outstanding work in the teaching of foreign languages. While this should not be done in a way that would mean the weakening of Arabic, through the successful teaching of foreign languages foreign schools are outposts of contact between Eastern and Western cultures.

h) In spite of the development of native institutions of higher learning,

there is still a great field for foreign higher education, both liberal and professional. It will help to provide the intellectual, social, economic, industrial, and agricultural leadership for the Arab world. Foreign higher education, if well endowed, should share in graduate training in pure and applied research which would help the Arab world in the long run to share in contributing to the advancement of knowledge and to develop its vast, largely unexploited, material resources. There is, however, a still greater opportunity for foreign higher institutions. They can become centers not only of training Arab specialists, but of Western specialists in fields connected with the Near East. This part of the world is largely an unstudied field, and Western and Eastern specialists on all phases of its life are not many. Yet the Near East is a paradise for the archeologist, the ethnologist, the anthropologist, the sociologist, the linguist, and the historian. A great deal of work needs to be done on its geology, flora, and fauna, its economic, industrial, and agricultural problems and possibilities, its politics, government, and jurisprudence, its art, handicrafts, music, folk-dancing, and folklore. Foreign higher institutions provide the opportunity for bringing together Western and Eastern scholars and students to work on common problems. Each of the two groups would be the finest interpreter of its culture to the other. Here is intellectual and cultural cooperation at its best. The same should also be true, though to a smaller extent, of foreign elementary and secondary schools. In this way foreign schools can contribute to bringing about a better understanding between East and West.

Conflict of Ideologies

A frequent topic of comment in books and periodicals, as well as in private conversation, is the conflicting ideologies among the newly rising generation which is often ascribed to the influence of different foreign schools attended by students. The following, taken from a newspaper article in Beirut is typical:

> One of the catastrophies which has hit the rising generation of this country is the divergence of outlook and tendency resulting from the divergence of teaching and education. We are stating nothing new if we say that a family of three brothers has no cultural unity within it when each brother has been educated at a different private school.[7]

Although this is ascribed to the influence of schools, particularly foreign schools, a close scrutiny of it shows that it goes much deeper than that. In

[7] Hanna Ghusn, "Submitting Private Schools to Supervision," *Al-Diyar,* Beirut, October 6, 1946.

the first place, it is not confined to the younger generation or to the literate individuals, but differences of outlook exist among the older generation and the illiterates as well. This can be ascribed to two main sources. First, the old religious and racial cleavages in the Near East, and, secondly, to the influence of modern private- and foreign-school education stemming from various sources—American, British, French, German, Italian, and Russian.

It is hardly necessary to go into any detail to describe the differences between Arabs and Kurds, Christians and Druzes; and among the Muslims themselves the differences between Shi'ites and Sunnites. In recent years the project of the Jewish National Home in Palestine has injected into Arab life a racial and religious problem which has reached international proportions. Naturally, one can point out also the differences existing between the multitudinous Christian sects. These differences, which have lasted for centuries, have created special attitudes within each sect or race, and sometimes have meant intersectarian or interracial animosity or cleavage. These differences, however, are now gradually melting away. The groups are learning to work together in conducting their governments and in friendly relation one with the other, with the exception of the tension existing between Arabs and Jews over Palestine. The conflict of attitudes and ideas will probably be worked out, given a sufficient period of time.

On top of these differences have come new differences brought to the fore by foreign education. This influence has been exercised in a number of ways. The most important has been the foreign schools, and indirectly the private schools fashioned after them. These have transmitted to the Arab world their own versions of Western life and culture, differing from nation to nation. The picture given is usually a purified picture of this life and culture set somewhat as a model and something superior to be followed. This naturally had its advantages. Another fact is that they directed attention to the better side of Western life which made for the education of character and generally created an incentive to do as well as the Westerners are doing. Yet, on the other hand, it had its disadvantages. Most of the schools, being missionary schools, gave a narrow conception of Western life, sometimes imbued with extreme sectarian attitudes. France, for example, though decidedly nonreligious in its state government and education, has been pictured as a Catholic country and a protector of Catholics. This was supported by French colonial policy. Catholics and Protestants have been living more or less in two separate worlds. Moreover, most of these schools give little or no indication of the more businesslike and sometimes sordid aims and ambitions of Western powers in the Near

East. In this way a somewhat warped view of Western civilization was given by this second-hand type of Western education.

More recently a broader acquaintance with the West has become possible partly by students going abroad by the hundreds and living among Westerners for a number of years. They have naturally brought back a broader conception of Western life, sometimes well understood and perhaps more often only partially understood. Western books and magazines in different languages have had their effect, as have Western radio broadcasts. Finally, there have been Western armies and Western secular government officials of varying abilities to carry out their responsibilities.

This diversity of influences naturally makes for diversity of outlook. Students studying in France do not mix too well with those studying in England or America. Graduates of British universities have a tendency to scoff at students of American universities and the type of education they receive. Students studying in Germany, though not numerous, have been influenced by the events and philosophies current in that country in the last two decades. There is, therefore, a problem involved in trying to make graduates of such schools and institutions work together for a common cause. The problem is the more important because the better-educated class of citizens is involved. The influence of missionary schools and private sectarian schools in catering to minorities and to sectarian differences has already been mentioned.

Against this centrifugal influence, one may set two unifying agencies. First, some of these foreign schools, particularly the higher institutions, have been bringing together students from various backgrounds and exposing them to the same type of education. Muslims, Christians, Druzes, Jews, Arabs, and Kurds may meet on the same campus and in the same classrooms, societies, and groups, at the American universities in Beirut and Cairo, and a community of outlook is thus developed. The same may perhaps be true of the French University in Beirut, or some of the *laïque* schools in Syria and Cairo. Between the two groups, however, there remains the difference between American and French education.

The second, and perhaps the more important, of these agencies is the public schools that have been founded and greatly expanded during this generation. Here students of all creeds come together and follow a program unified for each country and sometimes are taught by teachers of various religious backgrounds. The point of view taught in the public schools is national, and friendships are developed among the students which may last for a lifetime. It is this that makes educational authorities in some of the Arab countries anxious to have the new generation acquire a unified

outlook. In the long run the public-school systems may be considered as the main agencies for the unification of the peoples of the Arab world and for the education of citizens who will have loyalties wider than those of the family, the tribe, the creed, or the race.

An Arab national system of education?

To say that the public-school system is to be the main unifying factor among the various elements of the Arab world is to raise the question, "What kind of a public school system?" What constitutes a national system of education? And how does one national system differ from other national systems? How far have the Arab systems of education progressed toward being national systems? Is there to be one system for all Arabs, or many systems, one for each country? If the latter, how far can they be coordinated so as to approximate a single Arab system? These are difficult questions to answer. The following remarks are meant to be a contribution toward an answer.

What constitutes a national system of education?

1. A national system of education obviously must cover a whole geographical region over which a certain nation is spread out, and must maintain most or all the types of schools and education needed in that region.

2. A national system of education is one which has grown and evolved with the country, adapting itself to its needs by continuous adjustment throughout its history.

3. A national system of education has its own peculiar organization, legal provisions, and means of support. Whether loosely organized or highly centralized, and whether entirely public or partly public and partly private, these are simply features which are peculiar to any particular environment and are probably in accord with, or influenced by, the organization in other fields of national life.

4. A national system of education usually lays special emphasis on the national language and national history and geography and on the bringing-up of citizens who owe allegiance to the country and are willing to do service for it, who are capable of exercising their rights as citizens and sharing in the responsibilities of running the country in all phases of life.

5. Along with this and as part of it, a national system of education cultivates native arts and crafts, dances, folklore, and music, some useful and fine customs and traditions and all that goes to create a local atmosphere, a general background—in brief, a national spirit and character.

6. A national system of education studies the problems and needs of

the country, whether political, economic, social, hygienic, cultural, or otherwise, and tries to meet those needs as far as is possible in the school system.

To sum it all up, a national system is one which reflects the genius and peculiar character of a nation and forms part and parcel of its past achievement, its present preoccupation and problems, and its future hopes.

How far have the Arab countries studied in this report progressed toward the realization of a national system of education as envisaged in the criteria just set down?

If by a national school system is meant that each country has developed a public-school system for the education of its children, then each of the Arab countries studied has in varying degrees made some progress toward a national school system of its own. All of them have founded a fairly large number of elementary schools. Most of them have a variety of secondary, vocational, and teacher-training institutions. Some have established institutions of higher education. All of them stress the teaching of Arabic and of local, if not national, history, geography, and civics.

Yet the description of the school systems embodied in this report and the analysis of this chapter should have made it quite clear by now that the Arab school systems still have to travel a long way in order to measure up satisfactorily to the above criteria. No Arab educator would claim that these criteria have been met. Most of them are conscious of the long task ahead of them and of the problems confronting them. To put every child of school age in school, to provide him with a curriculum that fits his needs and those of the country, and to open for him the possibilities for further study from which he is capable of profiting, are still to a considerable extent matters of the future. Except for Egypt, the systems of education are so recent that they have not had time to evolve properly so as to meet the needs of their respective countries. All of them have been at one time under the domination of foreign powers. This foreign influence has naturally left its impress on the systems, so that they cannot as yet be called indigenous with their roots firmly established in the soil.

The Arab countries are still experimenting with various methods of educational organization. The present types of organization resemble each other in the fact that they are highly centralized, but the happy medium of cooperation between local and central authorities in educational matters is still unrealized. Nor can the schools be said to meet the needs and the problems of the countries adequately; nor have these problems been consciously studied and analyzed with a view to adjusting the school systems and curriculums and orienting them toward a solution. While the various

school systems emphasize the teaching of Arabic and of national history and geography, not much has been done in the fields of native arts, crafts, music, dances, and folklore. Even in the national subjects, however, there is as yet little evidence of a clear conception of what the content and method of training for citizenship should be. In some countries, particularly Palestine, national history is treated merely as part of general history. In others, national history is little more than the teaching of the local history of the particular country, while in still others effort has been made to teach both local and general Arab history in conjunction with the history and the geography of the rest of the world. In some countries no more than a formal teaching of civics is offered, while in others, particularly in Iraq, an attempt is being made to deal in intermediate and secondary schools with current problems of the country. On the whole, however, a course dealing with current problems is looked at with suspicion, owing to the fact that it has to treat some burning and controversial issues of the day.

The fact that the Arab world has not yet arrived at an educational *modus vivendi* is hardly surprising. It is not only that in all the countries except Egypt any serious public educational effort is of rather recent date, nor is the educational leadership as yet adequate, but it must be conceded that the Arab world today is in a condition of profound change where the old is gradually being superseded by the new, with all the strains and stresses and confusion that such a change involves. The fact that the change is taking place more rapidly under the impact of world forces makes the problem even greater. The Arab world has not yet found itself and will not find itself for a long time to come. It is not surprising that its educational systems reflect the same unsettled and inadequate picture which its life in general presents to day. Not until a new level of cultural, political, and economic stability is brought about will Arab education find its rock bottom and will educators be able to build a system relatively adequate for Arab needs—a system which will express the genius and aspirations of the Arabs.

As regards the unity of Arab education some rather superficial discussions of it have been voiced occasionally in the press and in public pronouncements. It is glibly asserted that schools all over the Arab world should follow the same curriculum without realization of the stifling influence such a policy would have on the development of Arab education and Arab mentality. Already, however, there are signs that such a course would not prove satisfactory to the various educational and political leaders of the respective Arab countries. Each country has more or less struck out in its own direction, though often taking inspiration from the same source.

Certain patterns have been developed, and certain traditions, though recent, have begun to take shape. Moreover, there are local needs for each country which are bound to affect the education in that country and would, therefore, make for some measure of variety between the school systems.

In the opinion of the present writers, this variety will in the long run be a point of strength rather than weakness in Arab education because it will provide that freedom of experimentation and of striking out in new directions which is so vital to the growth of any educational system. The fact that French and American influences are so pronounced in Lebanon, British influence in Palestine, French and British in Egypt, and American and British in Iraq, however deplored by some, may provide one of the broad bases that are needed for developing in the future a well-rounded Arab national system. In the long run, it is the aspects of these foreign influences which meet the needs of the countries that are most likely to survive while the others will be discarded; and, in the long run, it is the steps that are taken by each country alone or in cooperation with the others to meet its problems as they arise that will finally result in a system that will be truly national.

Some measure of unity is undoubtedly essential, but care must be taken that the mold in which this unity is cast is not too rigid and will not fit Arab education into a strait jacket that will check its healthy growth. Unity should rather express itself in mutual recognition of diplomas, certificates, and degrees on the broadest possible basis, in exchange of views through publications and conferences, in exchange of teachers and professors, and in an anxious solicitude for the education of united citizens, conscious of the sense of kinship that ties them together. Unity should be that of spirit, of goals, and of basic principles rather than unity in all matters of detail. A unity with variety should be the motto of Arab education.

INDEX

INDEX

THE AMERICAN COUNCIL ON EDUCATION

GEORGE F. ZOOK, *President*

A. J. BRUMBAUGH, *Vice President*

The American Council on Education is a *council* of national educational associations; organizations having related interests; approved universities, colleges, and technological schools; state departments of education; city school systems; selected private secondary schools; and selected educational departments of business and industrial companies. It is a center of cooperation and coordination whose influence has been apparent in the shaping of American educational policies as well as in the formulation of American educational practices during the past thirty-one years. Many leaders in American education and public life serve on the commissions and committees through which the Council operates.